हमारी राजनैतिक समस्याएँ

[वैज्ञानिक विश्लेषण की दिशा में एक प्रयत्न]

समालोचनार्थ मकाशक की अंह से 🗮

> लेखक प्रोफेसर शान्तिप्रसाद वर्मा

इन्दौर नवयुग साहित्य सदन १९४६

•			

यह पुस्तक वर्त्तमान भारतीय राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियों के एक वैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में पाठक के सामने आ रही है, पर इसका आरम्भ इतने बड़े डीलडोल के साथ नहीं हुन्ना था। फरवरी १६४५ में कुछ न्यंग्रेज मिन्नों ने मुक्ते एक विशुद्ध स्रंग्रेजी सभा में 'भारतवर्ष स्रौर स्रंग्रेजी साम्राज्य' पर एक भाषण देने कें लिए निमंत्रित किया । उस शाम को एक घएटे के ऋभिभाषण ऋौर दो घएटे की हार्दिक बातचीत में इस पुस्तक की नींव पड़ी । उसके बाद दीवारें चिनी जाने श्रीर इमारत का शेष काम समाप्त होने के साधन अपने आए निकलते आये । फरवरी के ख्रंत में मेरठ कालेज की अध्यापक-समिति में 'राजनैतिक गत्यावरोध कैसे मिटे ?' पर एक प्रबंध पहुना पड़ा, श्रौर, उन्हीं दिनों, कुछ परिवर्तन-परिवर्धन के साथ स्थानीय स्टूडेंट्स-कांग्रेस की कार्य-समिति के सामने, वातचीत के रूप में, उसी विषय का विवेचन करना पड़ा । मार्च में, राजनीति के एम० ए० के अपने विद्यार्थियों के साथ प्रजातन्त्र, विभाजन त्र्यौर संघ-शासन, इन तीनों विषयों पर लंबी चर्चा करने का मौक़ा निकल आया, और इसके कुछ ही दिन के वाद 'इपिडयन त्रफ़ेयर्स फ़ोरम' के उत्साही मन्त्री, बैरी, के त्राग्रह पर फिर त्रंग्रेज़ों की एक बड़ी सभा में 'भारतवर्ष श्रीर प्रजातन्त्र' पर एक भाषण देने के लिए तैयार होना पड़ा ।

उन्हीं दिनों जब कि मैं भारतीय राजनीति संबंधी विषयों के ऋध्ययन-मननऋध्यापन ऋदि में लगा हुऋा था, विद्याभवन, उदयपुर, से भाई केसरीलालजी
बोर्डिया का ऋादेश-पत्र मिला कि मुभे उदयपुर पहुंचकर कई व्याख्यान देने
होंगे। मैंने 'भारतवर्ष ऋौर प्रजातन्त्र' विषय चुना, ऋौर उस पर विद्याभवन के
स्वस्थ शैक्तिक वातावरण में वैज्ञानिक ढंग से खूब चर्चा रही। इस पुस्तक की
वाह्य रेखाएं उदयपुर के उन चार भाषणों में ही स्पष्ट हो चली थीं। प्रत्येक भाषण
के वाद प्रश्नोत्तर की गुंजाइश रखी गई थी, ऋौर प्रायः प्रत्येक दिन, भाषण के
वाद, शाम के लम्बे भ्रमण में, जिनमें मुसलमान साथी भी शामिल होते थे, इन
विषयों पर खुल कर चर्चा होती थी।

उदयपुर से भाषण देकर लौटा भी नहीं था कि नवयुग-साहित्य-सदन, इन्दौर के उत्साही संचालक भाई गोकुलदास धूत का पत्र ह्या पहुंचा कि इन भाषणों को पुस्तक का रूप दिया जाना चाहिए। श्री वैजनाथजी महोदय ह्यादि अन्य मित्रों की श्रोर से भी उन्हें मुभपर दवाव डालने का आदेश मिला। ऐसी परिस्थिति में, सिवाय इसके कोई चारा ही नहीं था कि मैं वैठूं और पुस्तक को लिख डालूं। फिर भी निश्चिन्तता से वैठकर काम करने के अवसर कम ही मिले। एक वड़े व्यस्त और वहुधन्धी कार्यक्रम के वीच इस पुस्तक को लिखने का काम चलता रहा है। श्रीर बाद के दिनों में तो यह हुआ है कि मैं लिखता रहा हूं, श्रीर पुस्तक छपती रही है, और कई वार तो प्रेस का काम हका भी है।

पुस्तक की छुपाई श्रीर प्रकाशन श्रादि के निरीक्षण का भार भाई मार्तएड उपाध्याय पर रहा। उसके श्रांतरिक विषय श्रीर उसकी व्यवस्था श्रादि के संबंध में भी मैं प्रायः उनकी सलाह लेता रहा हूं। पुस्तक के लिखने में सभी मित्रों की श्रोर से मुक्ते लगातार प्रोत्साहन मिलता रहा है। इस प्रकार एक वड़े स्वस्य, सहान्त्रभूतिपूर्ण, श्रीर सीहाई पूर्ण वातावरण में उसकी रचना हुई है, श्रीर वैसे ही वातावरण में उसका प्रकाशन भी हो रहा है। फिर भी पुस्तक में मेरे श्रपने व्यक्तित्व की श्रापूर्णता की प्रतीक, श्रनेकों गलतियां श्रवश्य रह गई होंगी। उनका संपूर्ण दायित्व मुक्तपर है, श्रीर उनके लिए पाठक के सामने में सविनय क्तमाप्रार्थी हूं। मेरठ,

२० दिसम्बर '४५

शान्तिप्रसाद वर्मा

विषय-सूची

		पृ० संब
ξ.	विषय-प्रवेश	\$
	भाग १: समस्या: सांप्रदायिक पत्त	
ર્.	हिन्दू-मुस्लिम संबंध : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	3
	प्राथमिक सम्पर्क	3
	रचनात्मक प्रवृत्तियां	११
	सामाजिक सहयोग	१३
	धार्मिक सिंहष्णुता	१४
	राजनैतिक समभौता	१६
	सांस्कृतिक समन्यय	१७
	सत्रहवीं शताब्दी : मतभेद के चिह्न	3\$
	त्र्यंग्रेज़ी शासन का प्रभाव	२१
	नवयुग स्त्रौर प्राचीन का पुनर्निर्माण	२२
	राष्ट्रीयता का स्वरूप	२४
₹.	मुस्लिम राजनीति श्रीर सांप्रदायिकता	२७
	सर सैयद त्र्रहमद खां	२७
	सांप्रदायिकता का स्त्रपात	३१
	उदार प्रवृत्तियां	३३
	इक्तेत्राल	રૂપ્
	राष्ट्रीयता का विकास	३६
	सांप्रदायिकता की प्रगति	34
	राष्ट्रीयता का पुनरुत्थान	४१
8.	मुस्लिम-लीग श्रौर पाकिस्तान की मांग	४४
	इक्तत्राल का स्वप्न	४५
	कैम्ब्रिल : पाकिस्तान की जन्मभूमि	४६
	डाक्टर लवीफ़ की योजना	४७
	एक पंजावी के विचार	४८
•	सर सिकन्दरहयात्वां योजना	2∨

		80.40
	मुस्लिम-लीग का निर्ण्य	પ્ર
	पाकिस्तान का मनोविज्ञान 🛷 🕻	પ્ર૪
	भाग २ : समस्या : राजनैतिक पच	
¥.	अंग्रेजी शासन और हमारी वैधानिक प्रगति	६०
	भारत ग्रौर ग्रंग्रेज़	६०
	वैधानिक प्रयोगों का स्त्रारम्भ	ं ६४
	प्रजातन्त्र की जड़ों पर ग्राघात	ं ६६
	१६३५ की शासन योजना	ं ७२
	बैधानिक प्रयोगों की विशेषताएं : एक विश्लेपगा	ં હમૂ
ξ.	भारतीय राजनीति के प्रमुख तत्व	= 8
	हमारे राजनैतिक दलः कांग्रेस	5 3
,	कांग्रेस का विधान : एक दृष्टि में	5 8
	कांग्रेस श्रीर गांधीजी	ج. ح
	शिक्त का केन्द्रीकरण	ंद्रप्र
	सर्वेहर प्रवृत्ति (Totalitarianism)	<u>5</u> 8
	देशी राज्यों के प्रति कांग्रेस की नीति	ەع
	मुस्लिम-लीग पर प्रहार	. ६२
	कांग्रेस के उद्देश्य व त्र्यादर्श	,, €₹
	राजनैतिक दल : श्रान्तरिक प्रवृत्तियां	83
ড.	वर्त्तमान स्थिति ः राजनैतिक गत्यावरोध	33
	महायुद्ध की प्रतिक्रिया	. १००
	गत्यावरोध का सूत्रपात	11808
	मनोवैज्ञानिक पद्य	. १०३
	क्रिप्स-प्रस्ताव	१०६
•	निराशा की मध्यरात्रि	१०८
	समभौते की ऋनिवार्यता	१०६
	राष्ट्रीय त्रांदोलन की शक्ति	१ १०
	सांप्रदायिक समभौते की संभावनाएं	१११
	7 - 1 - 1	* 1

श्रन्तर्राष्ट्री	य उ	ननमत
समाधान	की	दिशा

भाग ३ : समाधान की दिशा : विभाजन

 पाकिस्तान : व्यावहारिक कठिनाइयां 	1 !	• • ;	. ११६
सीमात्रों का निर्धारण		•	ुं ११६
· ं सिक्खों की समस्या			११७
पंजाब का विभाजनः ऋन्य कठिनाइयां	·	•	१२०
उत्तर-पूर्व की समस्या			१२१
त्रावादियों की त्र्यदल-बदल			१२२
पाकिस्तान का स्त्रार्थिक पहलू	•		१२३
रचा-संबंधी व्यय			१२४
त्र्यार्थिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से		,	१२६
श्रन्य विरोधी तत्त्व : श्रंग्रेज़ी सरकार			१२ट
कट्टर हिन्दू दृष्टिकोण			३२१
यह-युद्ध की संभावना			· १३०
राष्ट्रवादी मुस्लिम-संस्थात्रों का मत			१३१
समारोप	•		१३२
६. पाकिस्तान : सैद्धांतिक विश्लेषण 🕝			१३४
दो राष्ट्रों का सिद्धान्त	•		१३४
राष्ट्रीयता के त्र्याधार तत्व		•	१३५
'राष्ट्रीय त्र्रात्मनिर्ण्य' का सिद्धान्त	•		१३८
'त्र्रात्मनिर्णय'ः रत्ता-संबंधी समस्याएं			१४१
'त्र्रात्मनिर्ण्य' : त्र्रार्थिक पद्म	•		१४३
भारववर्ष की भौगोलिक एकवा			१४४
विभाजन का मनोविज्ञान			१४५
मुस्लिम चिन्तन-धारा की प्रवृत्ति			१४६
श्रन्तर्राष्ट्रीय विचार-धारा का सुकाव			१४७
१० विभाजन की कुछ अन्य योजनाएं			१४०
इन योजनास्रों या ऐतिहासिक विकास	•		१५२
क्रिप्स-योजना	-		१५३

	पृ० सं०
कूपलॅंड-योजना	१५४
चेत्रीय-विभाजन के ग्राधारभूत सिद्धांत	१५६
योजना का राजनैतिक महत्व	१५७
चुेत्रीय शासन-विधान	१५८
योजना का ग्रार्थिक पच्	१६२
योजना का सांस्कृतिक पद्म	१ ६६
योजना का सांप्रदायिक पत्त्	१६७
योजना का राजनैतिक पद्म	१६८
भाग ४: समाधान की दिशा: संघ-शासन	•
११. (अ) भारतवर्ष और संघ-शासन	१७१
सांस्कृतिक त्र्राधार-भूमि	१७१
संघ-शासन के त्र्याधार-तत्व	१७६
ग्रन्य संघ-शासन : स्वीज़रलैएड ग्रौर रूस	१८२
(স্থা) प्रस्तावित संघ-शासन : স্থাधारभूत सिद्धांत	१मध
सत्ता का वंटवारा : रज्ञा ऋौर विदेशी नीति	१८८
त्र्यार्थिक पुनर्निर्माण का प्रश्न	१६२
केन्द्रीय सरकार के अ्रन्य ऋधिकार	१९७
केन्द्र श्रौर प्रांत के संयुक्त श्रिधिकार	२००
स्वायत-शासन भोगी प्रांतों के ऋधिकार	२००
१२. (ऋ) वैधानिक विकास की दिशा	२०३
वैधानिक विकास की स्राधार-भूमि	२०३
एक श्रस्थायी शासन-योजना का प्रश्न	२०७
विधान-निर्मातृ समा की मांग	२१२
संधि श्रौर स्थायी विधान	२२२
(त्र्रा) सममौते की दिशा में वैधानिक प्रयत्न	२२४
मूलभ्त ग्राधिकारों का प्रश्न	२२५
मूलभृत ग्रिधिकारों की रूपरेखा	२२७
राजनैतिक संरच्गों की समस्या	२२८
सांप्रदायिक चुनाव का प्रश्न	२३०
'वाह्य' ग्रौर 'व्यक्तिगत' तत्वों का निराकरण	२३१

	सांप्रदायिक-सद्भावना समिति		२३३
	सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व		२३४
	कार्यकारिणी का निर्माण		२३५
	सांस्कृतिक ग्राधिकार		280
१३.	सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के पथ पर		२४४
	शिद्धा श्रीर समाज-सुधार		288
	शिक्ता स्त्रीर स्त्रार्थिक पुनर्निर्माण		२४८
	सामाजिक समानता की सृष्टि	•	२५०
	राष्ट्रभाषा की समस्या		२५२
	हिन्दी बनाम उदू	,	ર્પૂપ્
	समाधान की दिशा		२५६
	माहित्य का परिवर्तित दृष्टिकोण		२६३
	कुछ सुभाव		२६४
	एक संगठित योजना की स्त्रावश्यकता		२६६
	काम की दिशा		२७१
	वेसिक हिंदुस्तानी का ऋान्दोलन		२७२
	परिशिष्ट		२७४
	कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र		२७५
	सेवा ऋौर त्याग का इतिहास		२७५
	समान ऋधिकार की पुकार .		२७६
	हमारे बुनियादी ऋधिकार		হ্ডড
	विपदा की कहानी		२७८
	हमारी समस्याएं ऋौर उनका हल		765
	वैरानिक विकास की स्रावश्यकता		र⊏१ र⊏२
	सत १६५३ व्या गाव्याच		1

·		

हमारी राजनैतिक समस्याएं

: ? :

विषय-प्रवेश

हमारा राष्ट्रीय ज्ञान्दोलन विश्व की ज्ञाज की प्रमुख प्रवृत्तियों में ते एक है- उसकी तुलना रूस की सामाजिक क्रान्ति श्रीर चीन के राष्ट्रीय . त्र्यान्दोलन से की जा सकती है। इस त्र्यान्दोलन की जड़ें देश के उस सांस्कृ-. तिक पुनरुत्थान में हैं जिसका त्रारम्भ, लगभग डेंद्र सौ वर्ष पहिले, भारत की ब्राध्यात्मिकता पर पाश्चात्य भौतिकवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुन्रा था। इस सांस्कृतिक पुनरोत्थान का आधार अपने प्राचीन धर्म और संस्कृति में हमारे श्रात्म-विश्वास का जागरण था । इस विचार-धारा के श्रादि-प्रवर्त्तक राममोहन राय स्त्रन्य समकालीन युवकों की प्रवृत्ति के विरुद्ध पश्चिमी सभ्यता के प्रवाह में वह जाने से ऋपने ऋापको रोक सके। उनके सामने उपनिषदों का महान तत्त्व-ज्ञान था। पश्चिमी सभ्यता के गुणों को समभते हुए भी वह ऋपनी प्राचीन संस्कृति के गौरव को भूले न थे। धार्मिक सुधार की यह प्रवृत्ति वाद में दो धारात्रों में बंट गई। एक का त्रापह केवल धर्म के व्यक्तिगत पत्त पर था, दूसरी समाज-सेवा के रास्ते ही धार्मिक जीवन की कल्पना कर सकतो थी-इनके प्रवर्त्तकों में देवेन्द्रनाथ ठाकुर स्त्रौर केशवचन्द्र सेन के नाम लिये जा सकते हैं। समाज-सेवा की यह धारा भी, जिसका पूर्ण विकास केशवचन्द्र सेन के प्रभाव में महाराष्ट्र में तथापित प्रार्थना-समाज में हुन्ना था, वाद में दो भागों में वंट गई। एक का त्रादर्श केवल समाज-सुधार में त्रापनी सारी शक्ति लगा देने का था,दूसरी का विश्वास हो चला था कि जब तक हमारी राजनैतिक दशा नहीं सुधरती. समाज का प्रगति की स्रोर स्रमसर होना स्रतंभव है-इन दो प्रवृत्तियों की स्रभि-व्यक्ति हम रानाडे स्त्रीर गोखले के व्यक्तित्व में पाते हैं। गोखले जिस प्रवृत्ति के त्राचार्य थे, गांधी उसी की चरम-सीमा हैं। गांधी को यदि हम अपनी राजनै-तिक गति-विधि ऋौर राष्ट्रीय ऋाकांक्ताऋों का मापदराड मान लें तो हमें यह समभने में देर न लगेगी कि किस प्रकार हमारा त्राज का राजनैतिक जीवन समाज-सुधार के रास्ते त्राने वाले धार्मिक त्रीर चांस्कृतिक पुनरोत्थान का ही विकसित रूप हैं । गांधी हिन्दुस्तान की त्राज़ादी के लिए प्रयत्नशील हैं. पर उनका मुख्य साधन समाज-सुधार है श्रीर इसके लिए उन्हें मूल-प्रेरेला धर्म ते प्राप्त होती है।

यह तो हुन्ना हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक पन्न-जो हमें प्राचीन धर्म श्रोर संस्कृति से संबद्ध करता है। हमारे राष्ट्रीय-जीवन का एक दूसरा पन्न भी है-जिसका सम्बन्ध भावी विश्व-व्यवस्था से है। संसार की राजनीति में हम ग्रापना स्थान पा लेने के लिए वेचैन हैं । हम ग्राज़ाद होना चाहते हैं । गुलामी की जिन जंज़ीरों में जकड़े जाकर हम विश्व की राजनीति से दूर फेंक दिए गए हैं उन्हें हम तोड़ फेंकना चाहते हैं। राष्ट्रीय ब्रान्दोलन का प्रारम्भ मध्यम श्रेगी के शिचित-वर्ग से हुग्रा, वाद में निम्न-मध्यम-श्रेगी की जनता ने उसमें प्रवेश किया श्रीर श्रव वह जन-साधारग-गरीव श्रौर पदवस्त, किसान श्रौर मज़दूर-के दैनिक जीवन का विषय होगया है। ज्यों-ज्यों ज्ञान्दोलन व्यापक होता गया, हमारे मानसिक चितिज का विस्तार भी बढ़ता गया है। शुरू में हमारी दृष्टि ऊंची सरकारी नौकरियों व शासन में कछ श्रिधकार पा लेने पर थी। वाद में 'स्वराज्य' का श्रस्पष्ट श्रौर धुन्धला रेखा-चित्र हमारे सामने श्राया, श्रीर तव पूर्ण स्वा-धीनता के ध्येय की स्थापना हुई-ग्राय धीरे-धीरे इस त्यादर्श की वाह्य रेखाएं श्रिधिक स्पष्ट होती जा रही हैं श्रीर उसके राजनैतिक, श्रार्थिक श्रीर सांस्कृतिक पत्तों पर प्रकाश डाला जाने लगा है। ग्रान्दोलन की व्यापकता ग्रौर ग्रादशों के विस्तार के साथ-साथ प्रयत्नों की गम्भीरता भी बढ़ती गई है। १६२०-२१ के वाद से ही हमारी राजनीति का मुख्य ग्राधार त्याग ग्रौर कप्ट-सहन पर स्थापित किया जा चुका है। तव से हमारे देश की वड़ी से वड़ी विभृतियों के जीवन का ग्रधिकांश समय ग्रंग्रेज़ी शासन के जेलख़ानों में बीता है, ग्रीर हज़ारों देशभक्त लाठी के ग्राधातों, घोड़ों की टापों ग्रीर गोलियों के प्रहारों में ग्रपने प्राणों की भेंट चढ़ाते रहे हैं। कई फांसी के तख्तों पर भूले हें, श्रीर कई श्रपने जीवन के लंबे वर्ष जेलखानों की चहारदीवारी में विताने पर विवश किये जा रहे हैं। इन्हीं के तप और साधना का परिणाम है कि हमारा राष्ट्रीय ग्रान्दोलन एक प्रवल शक्ति वन गया है।

पर, देश की त्राज़ादी के लिए प्रयत्न करने वाली क्रात्मात्रों ने सदा ही वड़ी वेचैनी के साथ महसूस किया है कि जैसे हमारे इस सशक्त राष्ट्रीय त्रान्दोलन की जड़ें लगातार एक घातक ज़हर से सींची जाती रही हों, जैसे उसकी त्राकाशगामी शाखाएं किसी शाप से प्रसित हों। राष्ट्रीयता के विकास के साथ सांप्रदायिकता का ज़हर भी बढ़ता गया है— त्रीर जब कभी हमने त्रापने लद्द्य की प्राप्ति के लिए हाथों को ऊंचा किया है, उसने वरवस उन्हें पीछे धकेल दिया है, त्रीर हमारी राष्ट्रीय-शिक्त को पैरों तले रोंदती हुई वह स्वयं त्रागे बढ़ती चली गई है। १६२०-२१ के वे दिन त्राज केवल एक मीटी स्मृति के रूप में ही हमारे सामने

रह गए हैं, जब कांग्रेस ऋौर ख़िलाफ़त के विद्रोही-भरखें एक साथ फहरा उठे थे, 🔍 गांधी स्त्रीर स्रली भाइयों की जय एक साथ बोली जाती थी, स्त्रीर हिन्दू स्त्रीर मुसल्मान त्राज़ादी की लड़ाई में, कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर, खड़े हुए थे। १६३० श्रीर '३२ के श्रान्दोलनों में भी. हज़ारों मुसल्मान जेल गए, पर सांप्रदायिक शक्तियां दिन व दिन सशक्त बनती जा रहीं थीं ! मुसल्मान राष्ट्रीयता के प्रति सशंकित होते जा रहे थे। राष्ट्रीय विचारों के मुसल्मान भी कांग्रेस में शरीक होने के स्थान पर अपनी अलग-अलग संस्थाएं बनाने लगे थे, बद्यपि कांग्रेस के त्रादशों के साथ इन संस्थात्रों की पूरी सहानुभृति रही। १६३७ के प्रान्तीय चुनाव से एक बार फिर त्र्याशा वंधी । यह चुनाव देश भर में प्रगतिशील शक्तियों की विजय का प्रतीक था। ऋषिकांश प्रान्तों में कांग्रेस की जीत हुई। पद्माव में यूनियनिस्ट-दल व वंगाल में कृषक-प्रजा-दल के सामने प्रतिक्रियावादी मुस्लिम लीग टिक न सकी । युक्तप्रान्त में मुस्लिम लीग खयं एक प्रगतिशील संस्था थी-वह नवाव छतारी ऋौर उनके ऋन्य प्रतिक्रियावादी साथियों पर त्रासानी से विजय प्राप्त कर सकी। सीमाप्रान्त में कांग्रेंस जीती, त्रीर सिंध में भी लीग सफल न हो सकी। पर, कांग्रेसी मंत्रिमएडल वनते ही सहयोग ऋौर प्रगतिशीलता की सारी प्रवृत्तियां न जाने कहां ख़त्म होगईं, ऋौर प्रतिक्रियावादी शिक्तयां, सांप्रदायिकता का जामा पहिन कर, दिन व दिन अपने को सशक बनाती चली गई । ऋन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कांग्रेस ने जब पद-त्याग किया, तव मुस्लिम-लीग ने देश भर में 'मुक्ति-दिवस, मनाकर ग्रापने हर्ष का प्रदर्शन किया । धीरे-धीरे वह पाकिस्तान, श्रीर हिन्दुस्तान के बंटवारे के, त्रादर्श की त्रोर वही। सन् ४२ का, त्रपने त्राप उभर उठने वाला, महान जन-म्रान्दोलन भी मस्लिम-जनवा को भ्रपनी राजनैतिक निष्कियता के राजमार्ग से डिगा न सका । मृह्लिम जनता उसमें भाग लेने के लिए व्यप्नथी, पर नेतास्रों का त्रादेश उनकी इस सहज इच्छा के विरुद्ध था। त्रानुशासन का यह एक शानदार उदाहरण था, पर, ऋांधी के थम जाने पर लोगों के मन में यह सहज-स्वाभाविक प्रश्न उठा कि क्या इसमें देश के प्रति ग्रहारी की भावना नहीं थी ?

साम्प्रदायिकता की इस समस्या ने हमारी राजनीति को एक ख्रजीय उलभन में डाल दिया है। हमारी राजनीति ख्राज एक विदेशी शासन के प्रति सीधी-सादी लड़ाई नहीं है। वह तो एक विकाणात्मक संघर्ष (Triangular fight) है। हम विदेशी शासन से मुक्त होने का जितना ही ख्राधिक प्रयत्न करते हैं, छपने को सांप्रदायिकता के दलदल में गहरा घंसते हुए पाते हैं। १६३७ में कांग्रेस के पद-ग्रहण करने की नीति के पीछे विदेशी शासन पर ख्राधिकाधिक प्रभाव डाल

कर शासन-योजना को प्रजातंत्र के ढंग पर विकसित कर लेने का उद्देश्य था, पर कांग्रेस द्वारा पद-ग्रहण के २७ महीनों में, मुस्लिम-लीग द्वारा प्रेरित, साम्प्रदायिक विरोध इतना तीव होगया कि कांग्रेस विदेशी शासन पर देश का संयुक्त-प्रभाव नहीं डाल सकी । कांग्रेस के पद-त्याग कर देने के वाद, मिस्लम-समाज के नेतृत्व का दावा करने वाली संस्था, मुश्लिम-लीग, ने वार-वार शासन में हाथ वंटाने की अपनी तैयारी प्रगट की । कांग्रेस के विरोध में चले जाने से सरकार को विवश होकर मुस्लिम-लीग का समर्थन करना पड़ रहा था। सरकार ने केन्द्रीय-शासन पर तो मुस्लिम-लीग को हाथ न रखने दिया, पर प्रांतीं में अन्य मंत्रिमण्डलों को तोड़कर मुस्लिम-लीगी मंत्रिमण्डलों की स्थापना में खुली सहायता पहुँचाई । सिंध ग्रीर बङ्गाल के वड़े मंत्रियों-ग्राह्मावखश ग्रीर फ़ज़ल़लहक़ को जिन परिस्थितियों में श्रलहदा किया गया--श्रीर उनके स्थान पर हिदायतुला ऋौर सर नज़ीमुद्दीन को विठाया गया-चह प्रांतीय स्वशासन के इतिहास का एक लज्जाजनक ग्रध्याय है। उधर देश में ग्रसन्तोष बढ़ रहा था। गांधी जी उसकी श्रिभिव्यक्ति रचनात्मक प्रवृत्तियों में करने की चेष्टा करते रहे. पर तीन साल की अवजा और उत्तीड़न के बाद जब मार्च '४२ में क्रिफ्स-प्रस्तावों के रूप में भारतीय राष्ट्रीयता का ग्रपमान किया गया तव उसका रोक सकना श्रसम्भव होगया । गांधी जी जानते थे कि मुसल्मान राष्ट्रीय-श्रान्दोलन के साथ नहीं हैं, पर यह यह भी जानते थे कि जब तक विदेशी शासन से हम छुटकारा नहीं पा जाते, सांप्रदायिक समस्या का कोई सन्तीष-प्रद इल निकालना मी असं-भव ही है,-दो वर्ष के बाद सितम्बर १६४४ में मि० जिन्ना से २१ दिन तक यातचीत करने के बाद भी गांधी जी इसी परिगाम पर पहुँचे।

इसी वीच पाकिस्तान की मांग सामने छाई। भावप्रवर्णता के स्तर से उठ-कर उसने हिन्दुस्तान के एक वहुत वहें तवके की क्रौमी मांग का रूप ले लिया। मुस्लिम-लीग द्वारा अपनाये जाते ही पाकिस्तान मुस्लिम जनता का इन्किलावी नारा वन गया। हज़ारों मुसल्मानों ने अनुभव किया कि उन्होंने अपनी छात्मा के अन्तरतम सत्य को पा लिया है। भारतीय मुसल्मानों का अन्तिम लद्द्य पाकिस्तान ही हो सकता है। पर, यह तो निराश-हृदय की एक चीज़ थी। यह परि-रिथितयों की कठोर वास्तविकता से भाग निकलने का एक आकर्षक मार्ग था—जिसका अन्त होता था विद्रेष, अविवेक और आत्महत्या की एक अधेरी गुफ़ा में। अंग्रेजी सरकार, परिस्थितियों के वश मुस्लिम-लीगका समर्थन कर रही थी। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर लीग के कुशल सर्वे-सर्वा मि० जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को एक वड़ा व्यापक रूप दे दिया। पर सम्बन्ध-विच्छेद की

इस चरम मांग से एक श्रन्छा परिणाम भी निकला । एक श्रोर तो यह प्रगटें होगया कि एक श्रल्प-संख्यक समुदाय की कहरता उसे किस सीमा तक ले जा सकती है, दूसरी श्रोर यह भी स्पष्ट होगया कि मुसल्मानों के विरोध के पीछे एक तीखापन श्रीर तीव्रता भी है, श्रीर उसके कारणों का विश्लेषण कर लेने, श्रीर जहां तक हो सके उनकी उचित मांगों को स्वांकृत कर लेने श्रीर श्रन्य शिकायतों के सम्बंध में उचित वैधानिक श्राश्वासन देने की श्रावश्यकता है।

प्रजातंत्र में तो पारस्परिक सहानुभूति ऋौर एक-दूसरे के दृष्टिकोण को सम-भने की चमता का होना बड़ा आवश्यक है। हम पर, जो इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना देखने के लिए उत्सक हैं, यह वाध्यता है कि हम मुसल्मानों की मांग से खीभ उठने के बदले उसके मनोविज्ञान की गहराई में जायं। पाकिस्तान पके फोड़े की तरह एक ग़लत और संघातक चीज़ हो सकती है, पर हमारी राजनीति के ब्रस्वांस्थ्य में हो तो उसका जन्म हुन्ना है न ? पाकिस्तान के सम्बन्ध में क्यों मुसल्मानों का इतना ऋधिक ऋाग्रह है, ऋौर क्यों यह ऋाग्रह प्रवलतर होता जा रहा है ? कौनसी शिक्तियां हैं जो इस आग्रह के पीछे काम कर रही हैं, ग्रौर उसे प्रेरणा श्रीर प्रोत्साहन पहुंचा रही हैं ? उन शक्तियों का जान लेना, यदि हम भारत की एकता के आधार पर एक प्रजातन्त्र की स्थापना करना चाहते हैं, नितान्त स्रावश्यक है । यह जानने के लिए हमें इतिहास की गहराई में जाना पड़ेगा । हिन्दू श्रौर मुसल्मान समाज क्या हमेशा एक दूसरे से इसी तरह खिंचे रहे या कभी उनमें मेलजोल भी होगया था। यदि मेलजोल हुन्रा था तो वह किस सीमा तक पहुंचा था, ग्रीर वह क्यों ग्रपने को क़ायम न रख सका ? कौन से ऐसे कारण थे जिन्होंने दो महान् संस्कृतियों को एक शानदार समन्वय से पथभ्रष्ट कर दिया ? उसमें विदेशी शासन की कूटनीतिशता का प्रभाव कितना था श्रीर कितना था हमारी श्रपनी सामाजिक कमियों का उत्तरदायित ? मुसल्मानों द्वारा पाकिस्तान की मांग ने इन सब प्रश्नों का वैज्ञानिक उत्तर ढुंढ़ निकालने पर हमें विवश कर दिया है।

कुछ लोग मुसल्मानों के इस रवैये से खीभ कर उनसे अपना राजनैतिक सहयोग ही खींच लेना चाहते हैं। वह राष्ट्रीय अपन्दोलन को ही इतना सशक्त बनाना चाहते हैं कि मुसल्मानों के सहयोग के बिना, अथवा जरूरी हुआ तो असहयोग के साथ भी, अंग्रेंजों के अनिच्छुक हाथों से शासन-सचा छीन ली जाय। यह विश्वास उस मनोवृत्ति से भी, जिसने पाकिस्तान की जन्म दिया, अधिक भयङ्कर है। पाकिस्तान यदि निराशा की पुकार है, तो यह धारणा एक बौखलाहट की अभिन्यित है। हमारी राष्ट्रीयता के विकास में

सव से वड़ी कमी यही रही है कि उसमें कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, जिनका विश्लेपण त्यागे के पृथ्ठों में मिलेगा, त्यारम्भ से ही मुसल्मानों का सह-योग बहुत कम रहा । इस कारण उसका हिन्दू संस्कृति के रंग में रङ्ग जाना स्वाभाविक होगया । वाद में एक ऋोर ते। राष्ट्रीयता की इस प्रवृत्ति के लिए श्रपना सारा परिधान एक साथ वदल डालना कठिन होगया, दूसरी श्रोर मुस्लिम संस्कृति के जीर्णोद्धार में लगे हुए कहर धार्मिक व्यक्ति जब राष्ट्रीयता के कार्यचेत्र में ग्राये तो उनसे ग्रासानी से ग्रपना ताल-मेल न जोड़ सके, पर हमें यह स्वप्रता से समभ लेना है कि भारतवर्ष की ग्रानेकानेक भौगोलिक ग्रौर ऐतिहासिक प्रवृत्तियों ग्रीर सांस्कृतिक जीवन-प्रवाहों की देखते हुए इस देश में समाज के लिए यह संभव नहीं है कि वह ग्रापनी डफली ग्रालग ले जाकर ग्रापना कोई त्रालग राग छेड़ सके। इस प्रयत्न का फल या तो त्र्यात्म-हत्या होगा या लाख-लाख चेष्टा करने पर भी उस डफली में से चिर-भारतीयता का वही राग निकलेगा जिससे चिढ कर मुसल्मान ग्रलहदगी के चकर में पड़ना चाह रहे हैं। दूसरी त्रोर इम यह भी न भूलें कि भारतीय समाज के एक जीवित त्रांग, मुसल्मानों को, जो पिछले हज़ार वपों में हमारे जीवन की धारा में वुलमिल गए हैं, काट फेंकना स्वयं हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं हो सकता।

पाकिस्तान ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के ख़िलाफ़ जाता है। ग्राज दुनियां छोटी होती जा रही है—देशों की सीमाएं ताश के पत्तों के महल की तरह गिर रही हैं। राष्ट्रीय सार्वभीमता ग्राज राजनीति के शब्द-कोष में एक निरर्थक शब्द-मात्र रह गया है। ग्राज की ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों में एक प्रमुख प्रवृत्ति यह है कि ग्रासपास के देश मिलजुल कर ग्रपने राजनैतिक, ग्रार्थिक ग्रीर सांस्कृतिक पुनर्तिर्माण का काम ग्रपने हाथ में ले रहे हैं।

हमारी सशक्त राष्ट्रीयता भी विश्व के इस पुनर्निर्माण में अपना उचित स्थान पा लेने के लिए वेचैन है। उसकी भौगोलिक स्थिति, असीम साधनों और अट्टूट जन वल को देखते हुए विश्व की आने वाली राजनीति में उसके आनिवार्य नेतृत्व का चित्र हमारी आंखों के सामने घूम जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हमारे देश को उकड़ों में वांट दिया गया, तो न केवल हमारी राष्ट्रीय महानता के इन स्वप्नों का अन्त होजायगा, विल्क एशिया भर की प्रगति को एक गहरी ठेस पहुंचेगी, और द्गा-च्गा में संकुचित होनेवाले इस विश्व में एशिया के लिए जो आहितकर होगा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका प्रभाव भी अच्छा नहीं पड़ सकता।

राष्ट्रीय प्रश्नों की इस अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि को हम अपनी दृष्टि से ओभल तहीं कर सकते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का वहाना

लेकर अथवा प्रजातंत्र के बहुसंख्यक शासन की आड़ में हम अपने यहां के अल्य-संख्यक दलों को कुचल दें। इस सम्बन्ध में तीन बातों पर हमें दृष्टि रखना है। पहिली बात तो यह है कि ज्ञान्तर्भारतीय प्रश्नों के समाधान में हमें वही नीति वर-तना है, जिसकी हम अपने राष्ट्र के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय-संघ से अपेन्ता करते हैं। राष्ट्र के लिए त्राज़ादी का ध्येय सामने रखते हुए हम त्रपने देश के किसी संगठित ग्रंग को भी उतनी ही श्राज़ादी का उपभोग करने से रोक नहीं सकते। सच तो यह है कि ग्राज विश्व में जहां एक त्रोर राष्ट्रीय सार्वभौमता को त्रम्तर्रा-ष्ट्रीय संगठन में मिला देने का प्रयत्न चल रहा है, दूसरी श्रोर राष्ट्र के भीतर के सांस्कृतिक विभिन्नता रखने वाले सभी संगठित वर्गों को श्रिधिक से श्रिधिक त्र्यांतरिक स्वशासन दिये जाने की प्रवृत्ति भी ज़ोर पकड़ रही है। दूसरी वात यह है कि प्रजातंत्र का सच्चा अर्थ यह कभी नहीं होता कि वहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग या वर्गों की, ऋपनी संख्या के वल से, सदा के लिए दवाये खे । प्रजातन्त्र का ऋर्थ, ऋब्राहम लिंकन के शब्दों में, जनता का शासन, जनता द्वारा शासन श्रीर जनता के लिए शासन है । श्रव्राहम लिंकन ने वहुसंख्यक वर्ग के शासन की वात नहीं कही। किसी एक वर्ग या दूसरे वर्ग पर शासन चाहे किसी नाम से पुकारा जा सके, प्रजातन्त्र-शासन नहीं कहला सकता। प्रजातन्त्र-शासन तो समस्त प्रजा द्वारा समस्त प्रजा का ऐसा शासन है जिसमें प्रजा के हितों को दृष्टि में रखा गया हो । तीसरी वात, जो हमें ध्यान में रखना है, यह है कि मुसल्मानों को श्रल्पसंख्यक वर्ग के नाम से पुकारना राजनीति की वस्तु-स्थिति का उपहास करना है। मुसल्मानों की स्रावादी ६ करोड़ से स्रधिक है—इंग्लैंड की स्रावादी चे दूनी ऋौर कनाडा से ६ गुनी । उनकी ऋपनी सभ्यता ऋौर संस्कृति, खान-पान श्रीरं पहरावा, भाषा श्रीर श्राचार-विचार हैं। यदि कुछ व्यावहारिक कटिनाइयां श्रीर कुछ सैद्धान्तिक उलभनें न होवीं तो उनके एक राष्ट्र मान लिये जाने में कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती थी। इतने वड़े समाज को सदा के लिए एक श्रल्य-संख्यक वर्ग में परिणत कर देना प्रजातन्त्र की भावना का खुला विरोध करना है। हमारी राजनैतिक समस्या निस्सन्देह एक गम्भीर समस्या है। पाकिस्तान की स्था-पना ऋसम्भव है, पर यदि हम ऋपने देश के लिए एक स्थायी वैधानिक योजना चाहते हैं तो उसमें मुसल्मानों को संपूर्ण सांस्कृतिक श्रिधिकार श्रीर श्रिधिक से ग्राधिक ग्राधिक सुविधाएं देनी होंगी, ग्रौर साथ ही मुस्लिम प्रांतों को पूर्ण स्व-शासन श्रीर केन्द्रीय शासन में मुसल्मानों को एक प्रमुख स्थान देना भी श्राव-श्यक होगा ।

पर, वैधानिक योजना उस समय तक सफल नहीं हो सकती जब तक ग्रंग्रेज़ी

सरकार भारतीय शासन पर से श्रपना नियंत्रण हटा लेने के लिए तैयार न हो । मैं जानता हूं कि देश में एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि अंग्रेज़ हिन्दुस्तान की श्राज़ादी देने के लिए कभी तैयार न होंगे । श्राज़ादी, सचमुन, कभी किसी एक क़ौम ने दूसरी क़ौम को नहीं दी है। पर एक क़ौम दूसरी की सदा के लिए गुलाम भी कव रख सकी है ? खेन का समस्त वल हॉलैएड की आज़ाद होने से रोक नहीं सका, फ्रांस इंग्लैएड के ग्राधिपत्य से निकल कर संसार के महान् राष्ट्रीं की श्रेणी में जा पहुंचा। इटली ख्रीर जर्मनी ख्रास्ट्रिया के प्राधान्य की टुकरा कर स्वतन्त्र हो गए । पहिले महायुद्ध में टकीं ग्रौर रूस के साम्राज्य टूटे । इस युद्ध में जर्मनी, इटली ग्रौर जापान के साम्राज्यों की धिजयां विखर रही हैं। स्वतंत्रता श्रजीव चक्करदार रास्तों से होकर श्राती है। राजनैतिक परिस्थितियों का एक ववरडर-सा उठ खड़ा होता है और तब, कल तक जो राष्ट्र गुलाम होते हैं वह श्रांख मल कर उठ कर खड़े होते हैं कि वह ग्राज ग्राज़ाद हैं। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय शक्ति का विकास, ऋन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां और शासक-देश की आंतरिक दुर्वलता प्रमुख हैं । परिस्थितियों का दवाव त्राज हिन्दुस्तान के पच्च में पड़ रहा है, इसमें तो संदेह है ही नहीं। हिन्दुस्तान को श्रधिक दिनों तक गुलाम नहीं रखा जा सकेगा । त्राज तो दूर चितिज पर स्वतंत्रता की एक-पताकाएं त्रास्पष्ट-सी चमक भी उठी हैं, श्रीर डर यह है कि स्वतंत्रता श्राये श्रीर कहीं हम श्रपने को तैयार न पाएं। यह पुस्तक ऐसी ही परिस्थित के लिए हमारी तैयारी की दिशा में एक विनम्र प्रयत्न है। -- ग्रौर यदि चितिज के ये रेखा-चित्र केवल काल्पनिक हों श्रीर श्राजादी के लिए हमारा एक श्रीर वड़े संघर्ष के वीच से गुज़रना ज़रूरी होजाय तो भी, मैं स्त्राशा करता हूं, स्त्राज की राजनैतिक प्रवृत्तियों का यह विश्लेषण हमें श्रागे का मार्ग निश्चित करने में कुछ सहायता ही पहुंचाएगा।

: ?:

•

हिन्द्-मुस्लिम संबंध : ऐतिहासिक एष्ठभूमि प्राथांमक संपर्क

मुसल्मानों के संपर्क में श्राने के पहिले हिन्दू-सभ्यता विकास के एक ऊंचे शिखर तक पहुंच चुकी थी। धर्म श्रीर संस्कृति, कला श्रीर विज्ञान, साहित्य श्रीर सदाचार, सभी में उसने एक श्रद्धितीय महानता प्राप्त कर ली थी। उधर, ऋरव में, इस्लाम की स्थापना के साथ, एक ऐसी सभ्यता का जन्म हुन्ना जो त्रापने जीवन की प्राथमिक शताब्दियों में ही, कई शतपाय संस्कृ-तियों को पुनर्जीवित करती हुई ऋौर स्वयं ऋपने में नये-नये तस्वों का समावेश करती हुई स्पेन के पश्चिम से चीन के दिस्त्र तक फैल गई। इन दी महान् संस्कृतियों का संपर्क, हमारे देश में, उत्तरी भारत की मुस्लिम-विजय से कई शताब्दियों पहिले न्त्रारम्भ होचुका था। इस संपर्क का सूत्रपात दिव्यग्-भारत में हुन्ना। दिव्यग्-भारत से ऋरव वासियों के व्यापारिक संबंध शताब्दियों पहिले से चले ऋारहे थे। उनके इस्लाम-धर्म स्वीकार कर लेने से इन संबंधों में किसी प्रकार की रुकावट नहीं पड़ी। दिच्या भारत के हिन्दू-निवासी उसी प्रेम श्रीर श्रादर से श्रास्व वालों का स्वागत करते रहे, जैसे वह पहिले किया करते थे। मुसल्मानों के लिए स्थान-स्थान पर मस्जिदें बना दी गईं। मलाबार के कई राजात्रों ने इस नये धर्म में दीचा ले ली थी। दिच्या के प्रायः सभी राज्यों में मुसल्मान उच्च पदों पर नियुक्त किये जाने लगे थे। ³ मालिक काफूर ने जब दिस्तिण

१—ससूदी ने, जो दसवीं शताब्दी के श्रारम्भ में दिच्छ भारत में श्राया था, मलाबार के एक ही नगर में दस हज़ार मुसलमानों को बसे हुए पाया। श्रवू दुलफ़ मुहाल्हिल, इब्न सईद व मार्को पोलो ने भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। इब्न बत्ता ने चौदहवों शताब्दी में समस्त मलाबार-प्रदेश को मुसल-मानों से भरा हुश्रा पाया। उसने स्थान-स्थान पर उनकी बस्तियों व मिस्जिदों का जिक्र किया है।

—इलियट श्रीर डॉसन, पहिला भाग।

र-लोगन: मलाबार, पहिला भाग. पृ० सं० २४४ । •

३-सुन्दर-पांड्य के शासन-काल में तक्नीउद्दीन की मन्त्रित्व का भार सोंपा गया श्रीर कई पीड़ियों तक यह पद उसी के कुटुम्ब में रहा। उसके पुत्र सिराजुद्दीन व पौत्र निजा़मुद्दीन द्वारा शासन-संचालन के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। -इलियट व डॉसन, तीसरा भाग। भारत पर त्राक्रमण किया तो वीर वल्लाल की जिस सेना ने उसका मुकाविला किया था, उसमें २०००० मुसलमान भी थे। इन संपकों का प्रभाव दिज्ण-भारत के धार्मिक ग्रौर सामाजिक जीवन पर पड़ना स्वाभाविक ही था।

उत्तरी-भारत पर मुसल्मानों ने कई शताब्दियों के वाद ग्राक्रमण किया। तव तक इस्लाम की दुनियाँ बदल चुकी थी। इन नये-नये त्र्याक्रमण-कारियों का उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं था-वे तो उन शिक्तात्रों को टीक से समभ भी नहीं पाते थे, जो पैगुम्बर ने श्रपने निकट के श्रनुयायियों को दी थीं। इस्लाम के उदय थ्रौर उत्तरी भारत के मुस्लिम श्राक्रमण के वीच कई शता-ब्दियां, जिन्होंने इस्लाम के इतिहास में कई उतार-चढाव देखे थे, उमय्यद-काल की प्रचएडता ग्रौर ग्रञ्चासी-काल का वैभव, सभ्य ईरान की धार्मिक कहरता ग्रौर वर्बर मंगोलों की पाशविक रक्त-पिपासा । ये ऋाक्रमगुकारी या तो लूटमार के उद्देश्य से हमारे देश में श्राये, या मध्य एशिया की श्रार्थिक श्रीर राजनैतिक परिस्थितियों से विवश होकर, ब्राश्रय की खोज में । महम्मद गुजनी का स्पष्ट उद्देश्य हमारे मंदिरों ऋौर तीर्थ-स्थानों में एकत्रित की गई ऋपार धन-राशि को लूट ले जाने का था। उससे वह गुज़नी की समृद्धि को वढ़ाना चाहता था, ग्रीर साथ ही सफल त्राक्रमणों से प्राप्त प्रतिष्ठा का उपयोग मध्य एशिया में ऋपनी · राजनैतिक रिथति को मज़बूत बनाने में लगाना चाहता था । भोहम्मद ग़ोरी श्रीर उसके साथियों के सामने यह श्राकांचा भी नहीं थी। मध्य-एशिया में उनके लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। हिन्दुस्तान की राजनैतिक दुरवस्था से लाभ उठा कर वह यहां श्रपने लिए छोटे-मोटे राज्यों की स्थापना कर लेना चाहते थे।

विजय का उद्देश्य चाहे कुछ भी रहा हो, पर उत्तरी भारत के मुस्लिम आक्रमण्कारियों ने जिन उपायों का सहारा लिया वे वर्धर और नृशंसतापूर्ण थे—श्रीर इस कारण इस प्रदेश की जनता के मन में इस्लाम की जो कल्पना प्रविष्ट कर सकी वह दिल्ला के अपने देशवासियों से विल्कुल भिन्न थी। इस्लाम धर्म के मूल-तत्वों से अधिक उसके मानने वालों के वहशी कारनामे उनके सामने आए। ऐसी परिस्थित में, यदि दोनों संस्कृतियों के वीच श्रविश्वास की भावना कुछ समय के लिए व्यवधान के रूप में आ खड़ी हुई, तो इसमें आश्रवं ही क्या था? हिन्दू अपने राजनैतिक संगठन की कमज़ोरी के कारण, मुसल्मानों की विजय के रास्ते में कोई स्कावट खड़ी न कर सके, पर उनकी वर्बरता और धार्मिक असहिष्णुता से खीम कर उन्होंने अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन

१-इटन बत्ता ने इस घटना का जिकू किया है। २-प्रो॰ हवीब: Mahmud of Ghazni. के चारों त्रोर एक मज़बूत क़िलेवन्दी कर ली। मुसल्मान तेज़ी से एक के वाद दूसरे प्रदेश को जीत सके, पर उनके निवासियों के सामाजिक जीवन में उनका प्रवेश विल्कुल निषिद्ध था । वह हमारे खान-पान श्रीर विवाह-सम्बन्धों से वहि-ष्कृतं थे । यह पहिला त्र्रावसर था जव हिन्दू-समाज ने त्र्रापने चारों त्र्रोर वहिष्कार श्रीर श्रसहयोग की इतनी मज़बूत दीवारें खड़ी करली थीं। इसके पहिले सदा ही वाहर वालों के लिए उनके द्वार खुले रहा करते थे। दूसरी त्र्रोर भी यह पहिला ही स्रवसर था जव मुसल्मान किसी देश में पहुंचे हों, वहां स्रपनी राजनैतिक सत्ता क़ायम कर सके हों, पर उस देश के सामाजिक जीवन से इस प्रकार त्र्यलहदा फेंक दिये गए हों । त्र्यसहयोग की जो मनोवृत्ति एक वार वनी, वह काफ़ी दिनों तक सामाजिक संगठन की जड़ों को सींचती-पोसती रही। कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों ने, जो बहुत कम दिन टिक सकीं, मुस्लिम-समाज में भी सामाजिक ऋसहयोग की इस भावना को दृढ़ बनाया । मुसल्मान बहुत थोड़ी संख्या में इस देश में आये थे, और थोड़े ही दिनों में आंधी की तरह चारों ओर फैल गए थे, श्रीर महासागर में फैले हुए द्वीपों के समान उन्होंने श्रपने छोटे-छोटे राज्य खड़े कर लिए थे। जनता के संगठित तिरस्कार के सामने उनके लिए भी यह ज़रूरी होगया कि वह मुस्लिम समाज के सभी तत्त्वों - उलमा, श्रमीर व जन-साधारण-को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करें। मुसल्मानों का राज्य में एक विशिष्ट स्थान वन गया-हिन्दुत्रों के प्रति ऋविश्वास की भावना प्रमुख थी। भारत में मुरिलम राज्य की स्थापना के पहिले के कुछ वधों-शायद दशाब्दियों तक-हिन्दू ऋौर मुसत्मानों में जो ऋापसी संबंध रहे, दुर्भाग्यवश,कुछ स्वार्थी ऋौर ग़ैरज़िम्मे-दार इतिहासकारों ने उन्हें ही एक हज़ार वर्ष के इतिहास में परिखत कर दिया है।

रचनात्मक प्रवृत्तियां

प्रारम्भिक-काल की ऋविश्वास और ऋसहयोग की यह प्रदृत्ति सर्वथा ऋस्वाभाविक थी, और ऋषिक दिनोंतक टिक नहीं सकती थी। दो जीवित, जागत, उन्नितशील संस्कृतियां इतने निकट संपर्क में रह कर ऋपने को एक-वृसरे के प्रभाव से बचा नहीं सकती थीं, और फिर मुसल्मान तो इतनी कम संख्या में इस देश में ऋाये थे कि विना जनता के सहयोग के वह किसी स्थायी राज्य की नींव डाल ही नहीं सकते थे। इसी कारण हम देखते हैं कि ईल्जुित्मश ने मुसल्मानों के ऋांतरिक संगठन की जिस नीति को जन्म दिया था, और जो प्रारम्भ में मुस्लिम राज्य की स्थापना में सफल भी हुई थी, वह उनकी मृत्यु के बाद कुछ दिनों भी न चल सकी। वलवन ने उनकी उपेक्षा की। झलाउदीन ख़िल्जी ने धर्म और राजनीति के भेद को कुछ ऋषिक स्वष्ट किया। मुहम्मद

तुग़लक ने एक विरोधी नीति को विकास की चरम सीमा तक पहुंचा दिया।

ये रचनात्मक प्रवृत्तियां राजनैतिक चेत्र में तो प्रगट हो ही रही थीं, परन्तु धार्मिक ग्रीर सांस्कृतिक तौर पर वे ग्रीर भी ग्राधिक सशक्त वनती जारही थीं, इसका कारण था मुसल्मान ज्ञाकमणकारियों के साथ ही साथ इस देश में प्रवेश करने वाले मुसल्मान संतों श्रीर सूफ़ियों की एक श्रमवरत श्रृङ्खला, जिसने हमें न केवल वाहर के मुस्लिम देशों की विचार-धाराश्रों के संस्पर्श में रखा. पर जो हमारी संस्कृति की जड़ों को अपनी आध्यात्मिकता से सींचती और पोसती भी रहीं। ग्राज जो हम ग्रपने देश की ग्रावादी का २४ फीसदी इस्लाम के ग्रनु-यायियों का पाते हैं, उसके पीछे न तो मुसल्मान शासकों की धर्मान्धता है, न मुसल्मान प्रचारकों की जुबर्दस्ती। उसके पीछे तो हमारे समाज की श्रान्तरिक विषमता श्रीर इन सन्तों के व्यक्तित्व का प्रवल श्राकर्षण है। दसवीं शताब्दी में मंसूर ग्राल हल्लाज, ग्यारहवीं में वावा रीहान श्रीर उनके दर्वेशों का दल व शेख इस्माईल बुखारी. बारहवीं में फरीदुदीन असार श्रीर तज़ाकिरत उल श्रीलिया, तेरहवीं में ख्याजा मुईनुदीन चिश्ती श्रीर शेख जलाल-द्दीन तबरेज़ी व सैयद जलालुद्दीन बुखाऱी श्रीर वावा फ़रीद, चौदहवीं में श्रव्दल करीम ऋलजीली--- ग्रीर इस सबके साथ ग्रसंख्य छोटे-मोटे प्रचारक----इन सब का एक तांता-सा बना रहा । उनके व्यक्तित्व ग्रौर प्रचार का हिन्द्-समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । मुसल्मान ग्रीर हिन्दू सभी सन्तों को श्रादर की दृष्टि से देखते थे, श्रीर उनके प्रशंसकों व भक्तों में सांस्कृतिक भेद-भाव ग्रापने श्राप कम हो चले थे । ज्याज भी हम उनकी दरगाहों पर लाखों की संख्या में हिन्दुच्चों को इकटा होते हुए पाते हैं। ऋजमेर में ख्वाजा मुइनुदीन चिश्ती की दरगाह पर हर रोज़ तीन घएटे नौवतखाना वजता है । हुसैनी ब्राह्मण् व मल्कान राजपूत भी हमारे वीच हैं, जो रमज़ान के दिनों में रोज़े भी उसी ख्रास्था से रखते हैं जिससे वह हिन्दू वर्तों का पालन करते हैं। सिन्ध के मशहूर संत करीमशाह के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने एक वैष्णुव साधु से 'ग्रोम्' मंत्र की दीजा ली थी। उनकी जीवनी में लिखा है कि यह मंत्र उनके लिए 'एक ग्रांधेरे कमरे में घूमते हुए दीपक के समान' बन गया था। इसी प्रकार भाक्ष के प्रसिद्ध साध बाबा साहना के सम्बंध में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने एक मुस्लिम संत से दीज्ञा ली, श्रीर तव महरवावा कहलाने लगे 13 इस प्रकार, दो महान संस्कृतियों की,

1-T. W. Arnold: Preaching of Islam.

२-वाराचन्द : Influence of Islam on Indian Culture.

३-चितिमोहन सेन : Medieval Mysticism.

विभिन्न दीखने वाली दो विशाल-धाराएं हमारे देश के प्रयाग में, गंगा श्रौर यमुना के समान, एक दूसरे से जा मिलीं —एक भारतीय संस्कृति के निर्माण में सतत श्रागे बढ़ते रहने के लिए।

सामाजिक सहयोग

यहां हमें यह भी भूल नहीं जाना है कि इस देश में मुसल्मानों की संख्या, जो लगातार बढ़ती गई उसका कारण यह नहीं था कि वे लोग बहुत बड़ी संख्या में बाहर से आये थे। बाहर से आनेवालों की संख्या नगर्प्य थी। उनमें से आधिकांश, ६० या ६५ फ़ीसदी, ऐसे थे जो इस देश की प्राचीन संस्कृति के प्रश्रय में पले थे। उन्होंने जब मुसल्मान धर्म स्वीकार किया तव वह अपने समाज के वे सब आचार-विचार, जो वह सिदयों से मानते आरहे थे, इस्लाम में ले गए। जो थोड़े से मुसल्मान बाहर से आये भी थे वे उनके सामाजिक आचार पर बहुत अधिक प्रभाव न डाल सके, क्योंकि स्वयं उनकी आत्माओं में इस्लाम का प्रवेश बहुत गहरा न था, वे तो भिन्न-भिन्न फिरक़ों में बंटे हुए साधारण व्यक्ति थे, जो एक अस्थायी लाभ की खोज में इस देश में चले आये थे। संत और सूफ़ी धर्म-प्रचारकों का उद्देश्य साधना के मार्ग पर लोगों को प्रवृत्त करना था—सामाजिक संगठन की विभिन्नता को सुरिच्ति रखने अथवा उनका निर्माण करने पर उनका आग्रह नहीं था। उनके प्रभाव में जिन लाखों व्यक्तियों ने इस्लाम की दीचा ली, वे उस समाज-व्यवस्था से तिनक भी परिचित न थे जिसका विकास मुसलमानों ने इस देश के बाहर किया था।

ऐसी परिस्थित में वही हुन्ना जो कि स्वामाविक था। इस देश के उन ग्रसंख्य त्रादिम निवासियों ने, जिन्होंने इस्लाम धर्म में दीना ले ली, न तो ग्रपनी सिंदियों से चली ग्राने वाली प्राचीन समाज-व्यवस्था को ग्राधात पहुंचाने की चेष्टा की, श्रीर न उसके मुकाविले में किसी ग्रन्य समाज-व्यवस्था का निर्माण किया। मुसल्मान धीरे-धीरे हिन्दू-संस्थात्रों को ही ग्रपनाते गए। इस प्रकार श्रादि-काल से चली ग्राने वाली ग्रामीण ग्रर्थ-व्यवस्था की छत्र-छाया में एक नये समाज का निर्माण हुन्ना, जिसमें विविध धर्मावलम्बी तो थे, पर जो एक ही समाज-व्यवस्था को मानते थे। शहरों में संगठन की दिशा कुछ भिन्न थी। पर वहां भी हिन्दू ग्रीर मुसल्मान सरकारी नौकरियों में श्रथवा वाणिज्य छोर व्यापार के सूत्रों द्वारा एक-दूसरे के निकट-संपर्क में ग्राते गए। शासन-व्यवस्था में हिन्दू ग्रीधकारियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई। चारों ग्रोर सहयोग, साह-

গ–बी॰ के॰ मल्लिक : Individul and the Group : A Study in Indian Conflict. चर्य ग्रीर सीहार्द्र की भावना ने ज़ोर पकड़ा। जो वर्बर विजेता के रूप में ग्राय थे, वह हमारे सामाजिक जीवन के एक ग्रंग वन गए। केवल एक चीज़ व्यव-धान वन कर हमारे वीच खड़ी रह गई थी। वह थी धार्मिक विभिन्नता—पर धर्म धीरे-धीरे व्यक्ति के निजी विश्वास ग्रीर ग्राचार की वस्तु वनता जारहा था। हिन्दू ग्रीर मुसलमान एक दूसरे के ग्राचार ग्रीर व्यवहार के प्रति सहिष्णु वनते गए, ग्रीर सामाजिक धरातल पर उन्होंने एक-दूसरे के धार्मिक कृत्यों में भी उदा-रता से भाग लेना ग्रारम्भ कर दिया।

धार्मिक सहिष्णुता

सामाजिक सहयोग के साय-साथ धार्मिक सहिष्णुता की भावना भी पवल होती चली । ऊपर से देखने से तो यह जान पड़ता है कि मूर्ति-पूजक हिन्दू-धर्म श्रीर मृत्ति-भंजक इस्लाम में कहीं तादात्म्य है ही नहीं। पर कई शताब्दियों पहिले से बौद्ध-धर्म ग्रीर हिन्दू वेदान्त के प्रचारक उन देशों में फैले · हुए थे, जहां बाद में इस्लाम का प्रचार हुआ। सूफ़ी मत के इतिहास के उत्तरी-काल में उनका प्रभाव बहुत स्पष्ट है—यद्यपि यह सच है कि स्फ़ी रहस्यवाद की बुनि-याद हमें कुरान-शरीफ़ की कुछ ग्रायतों में ही मिल जाती है। फ़ना, तरीक्ता, मराक्रवा त्रादि सुफ़ी-सिद्धांतों में निर्वाग, साधना, योग त्रादि की कल्पना स्पष्ट भलकती है। दूसरी ग्रोर, इस्लाम के सिद्धांतों का भी वहुत वड़ा प्रभाव हिंदू-दर्शन पर पड़ा । सुधार की नई धारा का प्रारम्भ दक्षिण भारत से ही हुन्ना था, जहां हिंदू-दर्शन पहिली बार इस्लाम के सिद्धांतों के संपर्क में ऋाया था। दिच्या-भारत में वौद्ध ग्रोर जैन धमों के रुखे ग्रध्यात्म की प्रतिकिया के रूप में शैव ग्रौर वैष्ण्व पंथों का प्रारम्भ हुन्ना। इनका त्राग्रह जीवन के उपासना-पद्म पर था। उपासना के ग्राधार के लिए सगुग् ब्रह्म की ग्रावश्यकता पड़ी। यह कहना कठिन है कि सगुण ब्रह्म की कल्पना के पीछे इस्लाम के नये सिद्धांतों का प्रभाव कितना था। पर शंकराचार्य के ग्राच्यात्म-दर्शन पर इस्लाम का प्रभाव, जो उनकी जन्मभृमि के त्रासपास प्रे ज़ोर पर था, चिल्कुल भी नहीं था, यह मानना भी कठिन है। मध्यकाल का हिंद-दर्शन ज्यों-ज्यों विकास पाता गया, इस्लाम का प्रभाव उस पर त्राधिक स्पष्ट होता गया। शंकराचार्य के ऋदौतवाद ने धीरे-धीरे रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वेत का रूप लिया, ग्रीर तद वह वल्लभाचार्य के द्वैतवाद में विकसित हुआ। द्वैतवाद की मनोरम कल्पना की कोमल भृपि पर, स्फ़ी-मत के त्राधिक सीधे संपर्क के परिणाम स्वरूप, भक्ति की धारा का फूट निकलना तो सहज स्वामाविक ही था।

उत्तरी भारत में तेरहवीं, चौदहवीं ग्रीर पन्द्रहवीं शताब्दियों में जो सिद्धान्त

फैले उन पर तो मुस्लिम-प्रभाव बहुत सीधा ही पड़ रहा था। रामानंद ने विष्णु की कल्पना को श्रौर भी सहज-सुलभ बना कर राम का रूप दिया, उन्होंने भक्ति की दीन्ना चारों वर्णों को दी-उनके ऋनुयायियों में से ऋधिकांश जुलाहे, चमार त्रादि ही थे। कवीर **ने** तो रीति-रिवाज श्रीर जात-पाँत को उठाकर एक श्रोर रख दिया, ग्रौर राम ग्रौर रहीम की एकता का संदेश जन-साधारण तक पहुंचाया। उनके सिद्धान्तों पर रूमी, सादी और दूसरे सुफ़ी कवियों और सन्तों का प्रभाव वहुत स्पष्ट है। नानक श्रीर दादू की साखियों में हिन्दू श्रीर मुसल्मान धर्मों के सामञ्जस्य के इस प्रयत्न को हम ऋौर भी बढ़ा हुऋा पाते हैं। नानक सूफ़ी रंग में इतने रंग गए थे कि हिन्दू धर्म का उन पर कितना प्रभाव था, यह जानना कठिन है। वैदिक श्रौर पौराणिक सिद्धान्तों की उन्हें कम ही जानकारी थी। दादू का भी यही हाल था। दो-तीन शताव्दियों तक समस्त देश भक्ति की उत्ताल तरंगों में, एक नई प्रेरणा से स्पंदित-विभोरित होकर ह्रवता-उतराता रहा। हिंदुऋों में भक्ति-त्र्यान्दोलन त्रपने पूरे ज़ोर पर था, त्रीर मुसल्मानों में सुफ़ियों की नई-नई जमातें—चिश्तिया, सुहरावर्दिया, नवृशवन्दी त्र्यादि—'प्रेम की पीर' का प्रचार कर रही थीं । भावना के इस व्यापक प्रदेश में हिन्दू श्रीर मुसल्मानों का एक-दूसरे के समीप से समीपतर त्राते जाना स्वाभाविक ही था।

उससे भी नीचे स्तर पर, जहां जनसाधारण के ब्राचार-विचार, रीाते-रिवाज श्रीर पूजा-मानता का सम्बन्ध था, हिन्दू श्रीर मुसलमानों का यह भाव प्रायः विल्कुल ही मिट गया था। हुसैनी ब्राह्मणीं श्रौर मल्कान राजपूतीं की चर्चा ऊपर त्राचुकी है। मुस्लिम संतों के हिन्दू साधुत्रों से, त्रौर हिन्दू साधकों के मुसल्मान फ़क़ीरों से ऋाध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करने व गुरु-दिव्यणा लेने के श्रनेकों उदाहरखों से मध्य-काल का इतिहास भरा पड़ा है । साधक हिन्दू श्रथवा मुसल्मान कोई भी हो उसके ऋनुयायियों में दोनों ही समाजों के ऋनेक व्यक्ति रहा करते थे। त्र्याज भी उनकी शव-समाधियों पर जो वार्षिक मेले लगते हैं उनमें हिन्दू ऋौर मुसल्मान सभी इकड़ा होते हैं। सिन्ध के प्रसिद्ध कवि-साधक शाह अब्दुल लुतीफ़ की समाधि पर प्रत्येक वृहस्पतिवार की आज भी असंख्य हिन्दू श्रौर मुसलमान मिल कर कवीर, दादू, नानक श्रौर मीरावाई के भजन गाते हैं। च्रेमानन्द के 'मानस-मंगल' में, जो सत्रहवीं शताब्दी में लिखा गया था, वंगाल के एक राजा के कमरे में कुरान शरीफ़ के मौजूद होने का जिरु है। 'तर उल-मुताखरीन में लिखा है कि नवाव मीरजाफ़र श्रपने सब शहरियों के साथ गंगा-पार होली खेलने जाया करते थे, श्रीर मरने के वक्त उन्होंने दिसी-तेश्वरीदेवी की मूर्ति को जिस पानी से नहलाया था, उसका श्राचमन किया

था। 'बेहुला सुन्दरी' नाम की एक वंगला-किवता में लिखा है कि जो ब्राह्मण नायक की यात्रा के लिए शुभ-दिन निर्धित करने के लिए इकटा हुए थे, उन्होंने कुरान में 'फ़ाल' देख कर अपना निश्चय बनाया था। एक दूसरे कान्य-प्रन्थ में हम मुसल्मान नायक का सप्तर्पियों से वरदान मांगने के लिए पाताल जाने का वर्णन पाते हैं। सत्य-पीर नाम के देवता में तो समस्त वंगाल की जनता, हिन्दू और मुसल्मान दोनों, का अखंड विश्वास था।

राजनैतिक सममोता

हृदय की इस एकता के आधार पर राजनैतिक समभौते की भावना का विकसित होना ऋनिवार्य था। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि भारतीय इतिहास समप्र मुस्लिम-काल में केवल दो मुसल्मान शासक, फ़ीरोज़ तुशलक त्यौर श्रीरङ्गजेव, ऐसे हए हैं जिन्होंने अपने शासन-काल में धार्मिक असहिष्णाता की नीति का पालन किया, ऋौर वह भी थोड़े वपों के लिए ऋौर विशेष राजनैतिक परिस्थितियों के कारण । अन्य शासकों ने, और इन दोनों शासकों ने भी श्रपने शासन-काल के शेष भाग में धार्मिक मामलों में हस्तत्त्रेप न करने की नीति का ही पालन किया। कुछ ने इस्लाम का पत्त लिया, पर हिन्दू धर्म के साथ दुर्भावना नहीं रखी । श्रकवर के बहुत पहिले काश्मीर का सुल्तान जैनुल-श्राविदीन श्रपनी धार्मिक सिंहप्णता की नीति के लिए प्रसिद्ध था । उसने जिज़या हटा दिया था, श्रीर संस्कृत के कई प्रन्थों का फ़ारसी में श्रनुवाद किया। वंगाल में सुल्तान त्रालाउदीन हुसैनशाह ने भी इसी नीति का पालन किया । शेरशाह हिन्दू-जनता में 'वर्फ़' वाँटा करता था। सम्राट श्रकवर के शासन-काल में यह प्रवृत्ति श्रपनी चरम-सीमा तक जा पहुंची । मुगल-सम्राटों के समस्त शासन का संगठन जिन सिद्धान्तों पर किया गया था वे भारतीय पहिले थे, सैरेसेनिक, ईरानी या मुश्लिम वाद में । संस्थात्रों में थोड़ा हेर-फोर हुत्रा, पर वह मूलतः वही रहीं जो सनातन-काल से चली त्रा रहीं थीं। धार्मिक-सहिष्णुता की नीति ने भारतवर्ष के मुस्लिम शासन में धर्म का स्थान ले लिया था।

राजनैतिक सम्बन्धों के निर्धारण में धर्म का कभी कोई विश्रेप हाथ नहीं रहा। चौदहवीं श्रीर पन्द्रहवीं शताब्दियों में गुजरात, मेवाड़ श्रीर मालवा में लगातार संघर्ष रहा, पर इस संघर्ष में गुजरात के सुल्तान प्रायः उतनी ही बार मेवाड़ के राणा के पक्त में, श्रीर मालवा के सुल्तान के खिलाफ़ लड़े जितनी बार वह मालवा के सुल्तान के पक्त में श्रीर मेवाड़ के राणा के खिलाफ़ लड़े थे। बावर

१-कालोकिकरदत्त : Studies in the History of the Bengal Subah.

श्रीर हुमायूं ने, पठानों के खिलाफ, राजपूतों का साथ दिया। मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद भी निज़ाम मराठा-साम्राज्य के श्रन्तर्गत था न कि मैसूर के सुल्तान के साथ, श्रीर राजपूतों की सहानुभूति मराठों के साथ कम श्रीर रहेलों के साथ ज्यादा रही। मुग़ल-साम्राज्य द्वारा स्वीकार की गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति का ही यह परिणाम था कि उसके पतन के डेंद्र सौ वर्ष बाद भी, १८५७ के विद्रोह में, मुग़ल-वंश के किसी उत्तराधिकारी को ही समस्त देश का शासक बनाने का प्रयत्न किया गया। बीच में भी इस प्रकार के प्रयत्न चलते रहे थे। उत्तर-भारत में १७७२ से १७६४ ई० तक महादजी सिन्धिया का श्राधिप्तय रहा, पर श्रपने शासन के लिए यथेष्ठ नैतिक वल प्राप्त करने की दृष्टि से उनके लिए यह श्रावश्यक होगया कि वह मुग़ल-वंश के शाह श्रालम को श्रं ग्रें जो की किद से छुड़ा कर दिल्ली की गद्दी पर विठाएं, श्रीर उसके नाम से शासन करें। किसी भी साम्राज्य के पतन के बाद उसके प्रति जनता की इतनी गहरी भक्ति का प्रदर्शन साम्राज्यों के इतिहास में एक श्रनहोनी-सी घटना है।

सांस्कृतिक समन्वय

राजनैतिक एकता का सहारा लेकर सांस्कृतिक समन्वय का विकास हन्न्या। इस प्रवृत्ति का त्रारम्भ तो एक सामान्य भाषा की उत्पत्ति के साथ ही हो चुका था। हिन्दी ब्रजभाषा त्र्रीर फारसी के सम्मिश्रग का परिगाम थी। उसका शब्दकोष, वाक्य-विन्यास, व्याकरण, सभी दोनों भाषात्र्यों की सामान्य देन हैं। हिन्दु च्रीर मुसल्मान दोनों ने इस भाषा को धनी बनाया। च्रमीर खुसरो हिन्दी भी उतनी धारा-प्रवाह लिख सकते थे जितनी फ़ारसी। ऋकवर ने उसे प्रोत्साहन दिया। खानखाना, रसखान त्र्रौर जायसी हिन्दी-साहित्य के गौरव हैं। जायसी तो मध्य-कालीन हिन्दी के तीन सर्व-श्रेष्ठ लेखकों में हैं, श्रीर हृदयकी सुदमतम भावनाश्रों की ऋभिव्यक्ति में कई स्थलों पर तुलसी श्रीर सूर से भी वाज़ी ले गए हैं। ऋन्य प्रांतीय भाषात्र्यों —मराठी, वंगला, गुजराती, सिंधी त्र्यादि—पर भी मुसल्मानों का उतना ही गहरा प्रभाव पड़ा । मराठी वहमनी-वंश के संरक्त्ए में ही साहि-त्यिकता की सतह तक उठ सकी । वंगला का विकास भी मुस्लिम-शासन की स्था-पना के परिणाम-स्वरूप ही हुन्ना। स्व॰ दिनेशचन्द्र सेन का मत है कि "यदि हिन्दु-शासक खाधीन बने रहते तो (संस्कृत के प्रति उनका ऋधिक ध्यान होने के कारण) वंगला को शाही दर्वार तक पहुंचने का मौक़ा कभी नहीं मिलता ।"" जायसी के ऋवधी-भाषा में लिखे हुए पद्मावत की फ़ारसी-लिपि की छनेक प्रतियां अराकान श्रीर चटगांव के ग्रामीण मुसल्मानों के पास से प्राप्त हुई हैं। पद्मावत का १-दिनेशचन्द्रसेन: A History of Bengali Literature.

वंगला श्रनुवाद भी एक मुसल्मान किन ने ही किया था। दारा-शिकोह ने हिंदुश्रों के उपनिपदों व श्रन्य धर्म-अन्थों का फ़ारसी में श्रनुवाद किया—इसी के इटैलि-यन भाषा के श्रनुवाद ने पश्चिम के विद्वानों का ध्यान हिन्दुश्रों के धर्म-अन्थों की श्रोर खींचा। फ़ैज़ी ने महाभारत का श्रनुवाद फ़ारसी में किया। हिन्दुश्रों श्रोर मुसल्मानों के साहित्य की साधना में एक रूप हो जाने के श्रनेकों उदाहरण मध्य-कालीन भारत के इतिहास में मिलते हैं।

सांस्कृतिक समन्वय की यह प्रवृत्ति वास्तु-कला ग्रौर चित्र-कला के चेत्रों में ग्रापनी चरम-सीमा तक पहुंची है। मुस्लिम वास्तु-कला का सर्वोच विकास इसी देश में हुया । क़ाहिरा की मिस्जदों में भी, फैंज़ पाशा के शब्दों में, "कला की सम्पूर्ण मनोरमता नहीं है । सामजस्य, ग्राभिन्यिक, सजावट, सभी में एक ऐसी ग्रपूर्णता है -जो वरवस ग्रपनी ग्रोर ध्यान ग्राकर्पित करती है।" ईरान की मुस्लिम-कला में भी हम यही वात —भन्य सजावट श्रीर वैज्ञानिक कौशल का श्रभाव -पाते हैं । ताजमहल हिन्दुस्तान में मुश्लिम वास्तु-कला का सर्वश्रेष्ठ उदा-हरण है। परन्तु, वह संसार की ग्रन्य इस्लामी इमारतों से विलकुल भिन्न है। उसके निर्माण में हिन्दू शिल्प-शास्त्रों के सिद्धान्तों का ग्राधिक पालन किया गया है। बीच के वड़े गुम्बद श्रीर उसके चारों श्रोर चार छोटे-छोटे गुम्बद पंचरत की कल्पना का स्मरण दिलाते हैं। गुम्बद की जड़ों में कमल की ख़ली हुई पंख-ड़ियां हैं, जो मानों गुम्बद को धारण किए हुए हैं। शिखर के समीप कमल की उल्टी पंखड़ियां हैं। शिखर के ऊपर त्रिशूल है। हैवल ने ठीक ही लिखा है कि सैंटपाल का गिर्जा ग्रीर वेस्ट मिस्टर एवे श्रंग्रेज़ी-कला के उतने सच्चे नम्ने नहीं हैं, जितना ताज हिन्दुस्तानी कला का । कितन हैवल के इस कथन से मैं सहमत नहीं हूं कि हि दुस्तान में मुस्लिम वास्तु-कंला इस कारण ही महान् हो सकी कि उसका विकास उन हिन्दू कारीगरों के हाथों हुन्ना जो हिन्दू-संस्कृति में डूवे हुए थे। इस देश में त्राने के पहिले ही मुसल्मान इस चेत्र में वहुत महत्व-पूर्ण, सफ-लता प्राप्त कर चुके थे। मुस्लिम-काल की भारतीय वास्तु-कला के पीछे इस्लामी प्रेरणा भी उतनी ही पवल है, जितना हिन्दू प्रभाव। सर जॉन मार्शल का मत है कि पुरानी दिल्ली की कुञ्जुल-इस्लाम मस्जिद ग्रीर ताज के पवित्र ग्रीर भन्य मक्तवरे की कल्पना मुस्लिम प्रभाव के विना नहीं की जा सकती। देश भारत की मुस्लिम-कला की महानता इसी में है कि वह दो महान् संस्कृतियों के संम्मिश्रण का परिशाम है।

- 9-E. B. Havell: Indian Architecture.
- R-Cambridge History of India, Vol III.

चित्रकला के च्लेत्र में भी हम यही वात पाते हैं। मुग़ल चित्रकारों के सामने एक ग्रोर तो ग्रजन्ता की पद्धित थी, दूसरी ग्रोर समरक्षन्द ग्रीर हिरात, इस्रहान ग्रीर वग़दाद के चित्रकारों की कृतियां थीं। दोनों के समन्वय से मुग़ल-कलाका जन्म हुग्रा। ग्रजन्ताकी कला में एक ग्रभ्त-पूर्व जीवनी-शक्ति थी, मध्य एशिया की कला में समन्वय, संतुलन ग्रीर सामञ्जस्य की भावना प्रमुख थी। दोनों के मिश्रण से रंग का निखार ग्रीर रेखा की संवेदनशीलता दोनों ने एक ग्रद्धुत प्रगति की। शाहजहां के प्रमुख चित्रकारों में हमें एक ग्रीर तो कल्याणदास, ग्रुन् चतर ग्रीर मनोहरके नाम मिलते हैं, ग्रीर दूसरी ग्रीर मोहम्मद नादिर समरक्षन्दी, मीर हाशिम ग्रीर मोहम्मद फ्रकीरुल्जा के। हिन्दू ग्रीर मुसल्मान कलाकारों ने मिलकर मुग़ल-चित्रकला का विकास किया था। डॉ॰कुमारस्त्रामी ग्रीर कुछ ग्रन्य लेखकों ने मुग़ल ग्रीर राजपृत कलाग्रों में कुछ मूलभृत भेद यताने की चेष्टा की है। पर गहराई से देखा जाए तो राजपृत-कला, एक विश्वेत्र वातावरण में, मुग़ल-कला के प्रयोग का ही एक उदाहरण है। व

सत्रहवीं शताब्दी: मतभेद के चिह्न

हिन्दू श्रीर मुस्लिम संस्कृतियों के सहयोग श्रीर समन्वय की जो धारा शंताब्दियों की सीमात्रों को लांघती हुई दिन पर दिन प्रवल होती जा रही थी, सत्रहवीं शताब्दी में उसके प्रवाह में कुछ रुकावट पड़ी। इसका मूल-कारण राजनैतिक था, यद्यपि उसके पीछे कुछ सामाजिक प्रवृत्तियां भी काम कर रही थीं । देश में स्थान-स्थान पर हिन्दुन्त्रों ने त्रपने स्वतंत्र-राज्य स्थापित करने त्रारम्भ कर दिए थे। मरा ठे स्रौर बुन्देले, राजपूत स्रौर सिख, सभी एक नई राजनैतिक त्राकांचा से उद्देलित से हो उठे थे। राजनैतिक त्राकांचात्रों को समाज-सुधार की उन प्रवृत्तियों से बल मिला था जो हिन्दू-समाज में इन दिनों न्यापक होती जा रही थीं। कवीर, दादू श्रीर दूसरे स्वाधीन-चेता संतों द्वारा रूद्धिपयता श्रीर कट्टरता पर जो त्राकमण किया जा रहा था त्रीर दूसरी त्रीर भिक्त के नाम पर जो उच्छुङ्खलता फैलती जा रही थी उसका प्रभाव सामाजिक संगठन पर ग्रच्छा नहीं पड़ रहा था.। इसी कारण महाराष्ट्र व उत्तर-भारत के नए सुधारकों - नुका-राम, रामदास, तुलसीदास त्रादि—समाज को मर्यादात्रों को निवाहने पर त्र्राधिक ज़ोर देने लगे थे। इस ग्रामह से समाज में ग्राचार की शुद्धता ग्रीर पवित्रता का विकास हुन्ना। जीवन की इस नई उत्क्रांति का राजनैतिक स्तर पर श्राजाना श्रनिवार्य इसलिए भी होगया कि मुस्लिम-शासन उन उदार प्रवृत्तियों के साथ,

१-P. Brown : Indian Painting. २-ए० के०-कुमार-स्वामी: Rajput Painting.

जिनका विरोध किया जा रहा था, इतना ग्रिधिक सम्बद्ध होगया था कि उन्हें एक दूसरे से ग्रालग नहीं किया जा सकता था। इसी कारण हिन्दू-समाज की नई सुधार-प्रकृतियां, जिनका ग्राधार दृष्टिकोण की उदारता नहीं, मर्यादाग्रों का पालन था, मुग़ल-साम्राज्य से जा टकराई।

दूसरी प्रतिक्रिया यह हुई कि मुग़ल-शासन में भी मुसलमानों का एक ऐसा दल उठ खड़ा हुन्ना जिसने उसे कहर मुसल्मानों की संस्था वनाने का प्रयत्न किया । इस विचार-धारा को शाहजहां के कमज़ोर शासन-काल में संगठित होने का ग्रावसर मिल गया । शाहजहां के जीवन के ग्रान्तिम वपों में उसके योग्य पुत्र ग्रीरङ्गज़ेव ने इस दल का नेतृत्व ग्रायने हाथों में ले लिया। ग्रीरङ्गज़ेव कद्दर मुसल्मान तो था ही, शासन के ऋनुभव छौर योग्यता में भी वह ऋपने सव भाइयों से ऋधिक बढा-चढा था। गद्दी पर बैठने के बाद कुछ वपों तक उसने, हिन्दू स्वत्वों का विरोध न करते हुए, इस्लाम के ऋादशों पर शासन का पुनर्निर्माण करने की चेटा की । ग्रोरङ्गजेव के वनारस वाले फ़रमान ग्रीर ग्रन्य ग्राज्ञापत्र इस बात के सान्ती हैं, पर विचारों का बेग, ग्रौर उसके प्रभाव में घटनात्रों का चक, इतना तेज़ी से चल रहा था कि 'ग्रौरङ्गजेव इस कठिन सिद्धाःत का पालन ग्राधिक दिनों तक न कर सका । ज्यों-ज्यों मराठों ग्रौर सिखों का संगठित विरोध ग्राधिक तीन्न होता गया, उसे विवश होकर हिन्दू-विरोधी नीति का पालन करना पड़ा । जिज़या फिर से लगा दिया गया। नये हिन्दू-मन्दिरों के वनने का निषेध होगया । परिस्थितियों, त्र्रोर कुछ व्यक्ति विशेषों ने, मुस्लिम शासन को फिर एक वार उसी स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसका प्रारम्भ हुन्ना था। उसने फिर एक कहर मुसल्मानों की संस्था का रूप ले लिया ।

इस संबंध में कई वार्ते ध्यान में रखना ज़रूरी हैं। मुस्लिम-शासन को भारतीय जीवन-धारा से ग्रालहदा कर देने का यह प्रयत्न बहुत थोड़े मुसल्मानों तक, श्रीर केवल राजनैतिक चीत्र तक, ही सीमित रहा, सांस्कृतिक जीवन का वह स्वर्श न कर सका। इसका तो इससे ग्राच्छा प्रमाण ग्रीर क्या हो सकता है कि धर्मान्धता के सबसे, ग्रांधकारमय युग में भी स्वयं ग्रीरङ्गज़ेव की लड़की हिंदी में कविता लिखती ग्रीर हिंदू कवियों को ग्रार्थिक सहायता पहुंचाती रही? राजनैतिक चीत्र में भी यह प्रयत्न ग़लत था, इसमें तो शक है ही नहीं। हिंदू ग्राथवा मुसल्मान किसी एक भी समाज के विरोध के ग्राधार पर इस देश में कोई शासन स्थापित नहीं किया जा सकता। १७०७ में ग्रीरङ्गज़ेव की मृत्यु के, साथ ही इस प्रयत्न का भी ग्रांत होगया। भारतीय जीवन की दोनों प्रमुख धाराए फिर एक साथ वहने लगीं। ग्रीरङ्गज़ेव के उत्तराधिकारियों के लिए हिंदू जनता का

समर्थन प्राप्त कर लेना ज़रूरी होगया । शासन को फिर उदारता की नीति वर-तनी पड़ी। इसी बीच कुछ कारण ऐसे हुए जिनके परिणाम-स्वरूप मुस्लिम-समाज में पतनशीलता के चिह्नं स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। बाहर के मुस्लिम देशों से उनका संपर्क प्रायः समाप्त ही होता जा रहा था। ईरान के सफ़वी-वंश के पतन के बाद भारतीय मुसल्मानों के लिए प्रेरणा का एक मुख्य स्रोत बंद होगया था। इधर हिंदुच्चों की निम्न-श्रेणियों में से जिन च्रसंख्य व्यक्तियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, वे भी ऋपने साथ बहुत ही निम्न-कोटि की सभ्यता लाए थे, उसका भी बुरा ऋसर पड़ रहा था । मुसल्मानों में ग़रीवी ऋौर शिचा का स्प्रभाव दोनों बढ़ रहे थे। राजनैतिक सत्ता हाथों से जा रही थी। सम्भव है कि मुगल-साम्राज्य यदि फिर श्रपने प्राचीन वल श्रीर वैभव की प्राप्त कर पाता तो दोनों संस्कृतियों के समन्वय की धारा एक बार फिर ऋपने प्रवल वेग से बह निकलती, पर राजनैतिक परिस्थितियां प्रतिकृत थीं । जो तार एकवार टूटा वह फिर जुड़ न सका। पर यह सोचना कि धक्का बहुत गहरा ऋथवा सांघातिक लगा, इतिहास की सचाई को ठुकराना है। समाज के ग्रन्तस्तल में शताब्दियों से जिस समन्वय की जड़ गहरी होती जा रही थी उसे ग्रासानी से उखाड़ फेंकना सम्भव नहीं था। डा॰ बेनीप्रसाद के शब्दों में ''निकट भृतकाल के अनुभव भुताए नहीं जा सके। हिंदू-मुस्तिम-संस्कृति का जो ढांचा पांच शताब्दियों के ज्ञात स्त्रथवा अज्ञात सहयोग-प्रयत्नों द्वारा वनाया गया था वह न सिर्फ़ क़ायम ही रहा, पर और मज़बूत बनता गया । वह कड़ी से कड़ी परीजा में खरा उतर चुका था, ग्रीर देश की पूंजी का ग्रंग वन चुका था।""

श्रंग्रेजी शासन का प्रभाव

पतन श्रीर श्रानिश्चय की उस संक्रमण घड़ी में श्रंग्रेज़ इस देश में श्राए, एक नई, सशक्त सम्यता की चकाचौंध के साथ। इस नई सम्यता के प्रति हिंदू श्रीर मुस्लिम समाजों की प्रतिक्रिया ने दो विभिन्न रूप धारण किए। हिंदु श्रों ने, विशेषकर वंगाल के नवयुवकों ने, पश्चिमी-कला श्रीर विशान, सम्यता श्रीर संस्कृति से श्रिधक से श्रिधक सीख लेने की प्रदात्त का प्रदर्शन किया। ईसाई-मिशनिरयों द्वारा खोले गए स्कूलों श्रीर छात्रावासों, कंपनी के नौकरों के लिए खोले गए फोर्ट-विलियम कालेज व शेलवर्न, हेरोज़ियो श्रादि विदेशी शिक्कों के संपर्क के परिणाम-स्वरूप, हिंदू-समाज में जीवन श्रीर जागित की एक नई चेतना लहर उटी। श्रंग्रेज़ी तहज़ीव के प्रति मुसल्मानों का हिंदिकोण इसते विलक्षल भित्न था। सैकड़ों वर्षों के शासन के गौरव को वह श्रासानी ते मुला नहीं सकते

९-वेनीश्रसाद: Hindu Muslim Questions.

थे। राज्य के वहें-वहें छोहदे उनके हाथ से चले ही गए थे। जो कला-कीशल उनके हाथ में थे, ईस्ट-इिएडया कम्पनी की भारतीय उद्योग-धंधों को ख़रम कर देने की नीति से उन पर वड़ा धक्का लगा। ग्रंगेज़ी शासक भी उनके प्रति संशंक ही थे। इन सब वातों का परिणाम यह हुआ कि काफ़ी लम्ये ग्रंमें तक मुमलमान ग्रंगेज़ी सम्यता से विमुख छोर ग्रंगेजी शासन से खिंचे रहे। इसी कारण हम देखते हैं कि एक ग्रोर हिन्दू समाज में जहां ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज ग्रादि धार्मिक ग्रोर सामाजिक प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, जो पश्चिमी सम्यता के श्रच्छे गुण ले लेने के पन्न में थीं, वहां मुस्लिम-समाज में फरेज़ी ग्रोर वहावी ग्रांदोलन, जो मूलतः ग्रंगेज़ी शासन के ख़िलाफ़ थे, फैले। मुसलमानों का ग्रंगेज़ी शासन के प्रति क्या रख़ था, इसका ग्रच्छा परिचय हमें मिर्ज़ा ग्रंगेज़ी शासन के प्रति क्या रख़ था, इसका ग्रच्छा परिचय हमें मिर्ज़ा ग्रंगेज़ी शासन के प्रति क्या रख़ था, इसका ग्रच्छा परिचय हमें मिर्ज़ा ग्रंगेज़ी शासन के प्रति क्या रख़ था, इसका ग्रच्छा परिचय हमें मिर्ज़ा ग्रंगेज़ी शासन की प्रति क्या रख़ था, इसका ग्रच्छा परिचय हमें मिर्ज़ा श्रंगेज़ी शासन की प्रति क्या रख़ था, इसका ग्रच्छा परिचय हमें मिर्ज़ा श्रंगेज़ी शासन की प्रति क्या रख़ था, इसका ग्रच्छा परिचय हमें मिर्ज़ा श्रंगेज़ी शासन की प्रांजेजी शासन की तिरा है।

नवयुग और प्राचीन का पुनर्निर्माण

नवीन जीवन की जो चेतना भारतीय समाज में, चाहे वह हिन्दू हो स्रथवा मुसल्मान, व्यापक होती जा रही थी, उसका मुख्य ग्राधार प्राचीन का ममत्व श्रीर उसकी छाया में नृतन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न था। प्राचीन संस्कृति में त्रात्म-विश्वास की भावना के साथ ही तो इस नवसुरा का प्रारम्भ हुन्ना था। हिंदु-समाज में जिन श्रानेक धार्मिक श्रीर सामाजिक सुधार प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, उनके पीछे प्राचीनता के पुनर्निर्माण की यह भावना स्पष्ट ही है। राजा राममोहन राय द्वारा १८२८ ई० में स्थापित ब्रह्म-समाज को मुख्य प्रेरणा भारतीय उपनिषदों की महानता में एक ग्रमर-विश्वास से ही प्राप्त हुई थी। स्वामी दयानंद का वेदों की महानता में उतना ही ग्राखण्ड विश्वास था—उन्होंने स्मृतियों श्रीर पुरागों को उस हद तक ग्रमान्य ठहराया जहां उनमें वेदों का विरोध पाया जाता था। ग्रॉल्कॉट की थियोसोफ़िकंल सोसाइटी ने ग्रात्म-विश्वास की इस भावना को श्रौर भी पुष्ट किया । उसकी दृष्टिमें हर वस्तु श्रौर हर विचार, जिसका विकास इस देश में हुआ था, शुद्ध-वैज्ञानिक ऋौर चिरन्तन-सत्य था। यह भावना नवीन-वेदान्तवाद का समर्थन करने वाली प्रगतिशील, ग्रौर सनातन-धर्म महामएडल त्रादि रूढिवादी, संस्थात्रों द्वारा त्रीर भी दृढ वनाई गई। सब जगह प्राचीनता की ग्रोर लौटने की पुकार थी-वीच के ग्रन्धेरे युग को चीरते हुए प्राचीनता के स्वप्नों को ज्ञात्मसात कर लेने की ललक !

भारतीय इस्लाम में भी, एक विभिन्न वातावरण के प्रभाव और एक विभिन्न नेतृत्व में इसी प्रकार के प्रतिक्रियावादी ग्रान्दोलन खड़े हो रहे थे। उनका ग्राधार भी प्राचीन की ग्रोर लौटने—क़ुरान, पैगुम्बर ग्रीर हदीस में ही त्रात विश्वास रखने—पर था। इन त्रान्दोलनों के नेता श्रों में से दिल्ली के शाह अव्दुल ग्रजीज़ ने इस्लाम को उन ग्रन्ध-विश्वासों श्रोर रूढ़ियों से मुक्त करने का प्रयत्न किया जो उसने हिन्दू-समाज से ली थीं ग्रीर इस्लाम के पैग़म्बर द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों का प्रचार किया। वरेली के सैयद ग्रहमदने 'तरीक एमोहम्मदिया' की स्थापना की, जिसके ग्रनुसार हिन्दुस्तान को 'दारुल हर्न' करार दिया गया था, जहां मुसलमानों को जिहाद करते रहना ग्रावश्यक था। जीनपुर के शाह करामत ग्रली इतने उप्र विचारों के न थे, पर उन्होंने भी ग्रसंख्य मुसल्मानों को शुद्ध इस्लामी जीवन की ग्रोर प्रवृत्त करने में बड़ी सहायता पहुंचाई। फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्ला व उनके पुत्र दूधूमियाँ द्वारा चलाये गए फरैज़ी ग्रान्दोलन का उद्देश्य केवल धार्मिक शुद्धता का प्रचार ही नहीं था, उसने राजनैतिक ग्रमंतोष को भी उकसाया। ग्रहले हदीस ग्रीर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ग्रनुयायियों में भी यही प्रवृत्ति काम कर रही थी।'

प्राचीन के पुनर्निर्माण की यह प्रवृत्ति प्रत्येक देश के नवयुग का एक मुख्य त्रंग है। यूरोप में भी पन्द्रहवीं शताब्दी में नये जीवन की जिस चेतना ने त्रपनी उत्ताल तरंगों के प्रवल त्राघातों से मध्यकाल के ध्वंस-चिहों को नष्ट-भ्रष्ट किया, उसके पीछे भी ईसा के पहिले की यूनानी सम्यता के जीणोंद्वार का प्रयल था। हिन्दुस्तान में भी इस प्रवृत्ति की उपस्थित स्वाभाविक थी। जब कोई राष्ट्र निराशा के गढ़े में गिरा होता है, तब प्राचीन महानता की स्मृति ही उसे भविष्य की नई त्राशात्रों व नये सपनों को जागत करने में सहायता पहुंचाती है। पर, हमारे देश में इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुत्रा कि एक त्रोर तो हिन्दुन्नां की दृष्टि त्रपनी उस प्राचीन संस्कृति की त्रोर गई जिसका विकास, गंगा त्रोर यमुना के किनारे, त्रार्थ-ऋपियों के द्वारा उन शताब्दियों में हुत्रा था जब भारतवर्ष मुस्लिम-संपर्क से विल्कुल त्राख्रुता था, दूसरी त्रोर मुसलमानों के मानसिक चित्रित पर उस सम्यता का रंगीन चित्र खिचा, जिसका विकास त्रारव के महस्थल में पैगम्बर त्रौर उनके खलीफ़ा-साथियों द्वारा हुत्रा था, त्रौर जो त्रपनी चरम-सीमा-रेखा का स्पर्श, त्रौर उसे पार, कर चुकी थी हिन्दुस्तान के संपर्क में त्रानेके

१—ये सब आन्दोलन प्राय: वहाबी आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध हैं. पर इनका मौलिक 'वहाबी' आन्दोलन से—जिसे मुहम्मद इटन अट्टुल वहाय (३७०७-२७) ने अरव में चलाया था—कोई सम्यन्ध नहीं था। इसमें में अधिकांश इनकी और शक्ती कान्नों को मानते हैं, और 'तसन्वुक्त' की वहाबी कल्पना का विरोध करते हैं। इन्हें 'कुरान की और लौटो' आन्दोलन कहना अधिक उपयुक्त होगा।

शताब्दियां पहिले । वे दोनों भूल गए—जैसे किसी दूर की वस्तु को देखने की तल्लीनता ग्रोर तन्मयता में हम कभी-कभी पास की वस्तु को भूल जाते हैं—िक उन दोनों ने इस देश के सैंकड़ों वपों के सामान्य जीवन में ग्रोर साथ में प्राप्त किये गए सुख ग्रोर दुःख के सहस्व-सहस्र ग्रानुभवों में, एक महान् सामान्य सम्यता का निर्माण किया था, सामान्य सामाजिक संस्थाग्रों, सामान्य धर्म-सिद्धान्तों ग्रोर कला ग्रोर साहित्य की सामान्य पृष्ठभूमि पर, जिसके लिए वे उतना ही गौरव ग्रानुभव कर सकते थे, जितना किसी ग्रान्य सम्यता के संबंध में।

क्या यह एक आश्चर्य में डाल देने वाली वात नहीं थी ? क्यों हिंदू श्रीर मुसल्मान दोनों अपने सैंकड़ों वधों के सामान्य जीवन श्रीर उसकी श्रद्भुत देन, एक सामान्य सम्यता, को भूल गए ग्रीर क्यों उन्होंने ग्रपने नये जीवन की नींव दर-पार की दो विभिन्न संस्कृतियों के ऋाधार पर डाली ? इस प्रश्न का वैज्ञानिक उत्तर देना कठिन नहीं है। वात यह हुई कि हमारे नये जीवन की चेतना का ग्राधार धर्म में था-उस एकाकी वस्तु में जो हिन्दू ग्रीर मुसल्मानों में भेद की रेखा वन कर खड़ी थी। सुधार की नई प्रवृत्तियों का आरंभ धर्म से हुआ, और यहीं प्रवृत्तियां, समाज-सुधार के रास्ते, राष्ट्रीयता में परिण्त होगईं। इसी कारण हमारे देश में हिन्दू व मुस्लिम समाजों में राजनैतिक जीवन का विकास भी दो विभिन्न रूपों में हुन्रा। जब तक यह प्रवृत्ति धर्म न्त्रीर समाज के सुधार तक सीमित रही, संघर्ष की गुंजाइशा नहीं थी। पर उसके राजनैतिक दोत्र में प्रवेश करते ही संवर्ष का प्रारम्भ होगया। फिर भी वस्तु-रिथित पर काबू पाया जा सकता था यदि भृतकाल के सामान्य अनुभव और वर्तमान जीवन की सामान्य गुलामी श्रीर कड़वाहट की तीखी श्रनुभृति—एक शब्द में, राष्ट्रीयता—श्रपने शुद्ध रूप में विकसित हो पाती। परन्तु, हमारे देश में राष्ट्रीय त्र्यांदोलन का विकास भी प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों का सहारा लेकर हुआ - इस कारण दोनों समाजों के वीच की खाई का वढ जाना स्वाभाविक ही था।

राष्ट्रीयता का स्वरूप

भारतीय राष्ट्रीयता की जहें हिन्दू-धर्म छ्रौर संस्कृति के पुनरोत्थान में निहित हैं। उसका छ्रारम्भ ब्रह्म-समाज छ्रौर प्रार्थना-समाज के नेताछों से हुछा जिनमें राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशवचंद्र सेन, रानाडें, मंडारकर, चन्दावरकर जैसे प्राचीन हिंदू-संस्कृति में डूचे हुए व्यक्ति थे। जिन विदेशी लेखकों की रचनाछों से हमारे उस छ्रात्मविश्वास को, जो राष्ट्रीयता का मूल छ्राधार था, पुष्टि मिली, उन्होंने भी हिंदू संस्कृति के प्राचीन गुणों को ही हमारे सामने रखा। देश मर में छार्य-संस्कृति की विजय-ध्वजा स्थापित कर देने का स्वप्न जिन दया- नन्द की स्रांखों में था, भारतीय राष्ट्रीयता के प्रवर्त्तकों में उनका बहुत वड़ा स्थान है। हिंदू समाज के ऋन्य ऋांदालनों ने भी, नाहे वे नव-वेदांत-वाद जैसे तर्क प्रधान रहे हों, चाहे सनातन धर्म महामण्डल जैसे रूढ़ि-प्रधान, राष्ट्रीयता की भावना को ही पुष्ट किया। उन्नीसवीं शताब्दी के त्रांत तक हमारी राष्ट्रीयता धर्म का जामा पहिन चुकी थी-या यों कहना चाहिए कि धर्म ने ही राष्ट्रीयता का रूप ले लिया था। इस धार्मिक राष्ट्रीयता के ऋाचार्य थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने त्र्यात्मविश्वास, त्र्राशा त्र्यौर शक्ति का एक नया संदेश हमारी नसीं में फूंका l शिकागो को 'वर्ल्ड कांफ्रेंस ब्रॉफ रिलीजन्स' पर उनके व्यक्तित्व का बहुत वड़ा प्रभाव पड़ा। पर विवेकानंद स्वयं त्र्यमरीका से पश्चिमी सभ्यता के लिए तिरस्कार की भावना लेकर लौटे थे। "एक बार फिर", उन्होंने ऋमरीका से लौटने पर कहा, ''संसार पर भारतवर्ष की विजय होगी''''। ''हमें विदेशों में जाना चाहिए ऋौर संसार को ऋपने ऋध्यात्मवाद ऋौर तत्त्वज्ञान से जीवना चाहिए। हमारे लिए यही एक रास्ता है। हमें चाहिए कि हम इसी पर चलते हुए मर मिटें। राष्ट्रीय जीवन, एक बार फिर सशक्त राष्ट्रीय जीवन, की एकमात्र शर्त यह है कि संसार पर भारतीय विचारों की विजय हो।" विवेकानंद का यह संदेश तभी से भारतीय राष्ट्रीयता का मूल-मंत्र वना हुन्ना है ।

भार्मिकता की इस ब्वापक-प्रवृत्ति की हम ग्रापने वीसवीं सदी के ग्रारम्भ के राजनैतिक जोवन की दोनों धारात्रों—क्रांतिकारी व कांग्रेस के उप्रदल—पर वरावर हावी पाते हैं। इन त्र्यांदोलनों का नेतृत्व देश भर में फैले हुए जिन व्यक्तियों के हाथ में था-महाराष्ट्र में तिलक, वंगालमें ग्रावंद वीप ग्रीर विपिन-चन्द्र पाल, पंजाव में लाजपतराय—उन सवका हिंदू धर्म में गहरा विश्वास था। क्रांतिदल के सदस्यों का तो मुख्य ग्रंथ गीता था, ऋौर उनके जीवन की मुख्य प्रेरणा श्रीकृष्ण का निष्काम कर्म का त्रादर्श । ऐसी परिस्थित में भएडे ग्रौर गीत, प्रतीक श्रीर उद्घोष जितने भी निकले, वे यदि हिंदू विचारधारा श्रीर हिंदू तत्वज्ञान में हूवे हुए थे, तो त्राश्चर्य ही क्या था ! महाराष्ट्र में तो त्राधिनक राष्ट्रीयता उन प्रवृत्तियों का ही पुनरोत्थान-मात्र थी, जो किसी समय मुस्लिम राज्य के विरोध में विकसित हुई थी। तिलक ने, जो जन-संपर्क में स्त्राने वाले पहिले राष्ट्रीयं नेता थे, गो-वध निपेध समितियों, हिंदू भ्राखाङ्गें व गण्यति श्रौर शिवाजी उत्सवों के द्वारा दिक्कण भारत में राष्ट्रीयता की भावना का संगटन किया था। शिवाजी के श्रफ़ज़ल-वध का समर्थन करते हुए लो॰ तिलक ने लिखा-"म्लेच्हों को ईश्वर ने ताम्र-पत्र पर हिंदुस्तान का पट्टा लिख कर नहीं दे दिया है। शिवाजी के जीवन का उद्देश्य यही था कि वह उन्हें ऋपनी जन्मभूमि से निकाल दाहर करें ""।"

मस्लिम समाज में राष्ट्रीयता की यह लहर काफ़ी लम्बे ग्रार्स के बाद पहुंची-क्योंकि मुस्लिम समाज ने उन मंजिली को पार करने में ग्राधिक देर लगा दी जिन पर होता हुन्ना हिंदू समाज राष्ट्रीयता की चेतना तक पहुंचा था। ग्रंगेजी शासन ग्रौर सम्यता के प्रति मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया का ज़िक ऊपर त्यांचुका है, पर दोनों समाजों की प्रगति के मूल में, मनोवैज्ञानिक प्रति-कियात्रों के ग्रलाया, टोस ऐतिहासिक कारण भी थे। हमें यह न भ्लना चाहिए कि नवयुग की यह चेतना समस्त देश में एक साथ नहीं फैली-वह, अंग्रेजी शासन के विस्तार के साथ, एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक वढती गई। हेमें यह वात भी मुला नहीं देना है कि मुस्लिम संस्कृति का प्रधान केन्द्र सदा से उत्तरी भारत के पंजाय, दिल्ली, युक्तपांत ग्रादि प्रदेश रहे हैं—इन तक पश्चिमी सम्यता का प्रभाव पहुंचने में ग्राधी शतान्दी से भी ग्राधिक का समय लग गया। समुद्र तट के प्रांतों में सुधार की प्रवृत्तियां जब ग्रापनी चरम-सीमा पर थीं, तब उत्तरी भारत में उनका ग्रारम्भ हुन्ना। प्रधानतः हिंदुन्त्रों के हाथों विकसित होने के कारण राष्ट्रीयता पर हिंदू धर्म ग्रीर हिंदू-संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ जाना स्वा-भाविक ही था--ग्रौर तत्र मुसलमान उसके संपर्क में ग्राये, ग्रौर उनसे उसे श्रपनाने की श्रपील की गई। मुसलमानों में भी राष्ट्रीयता की इस भावना के विकसित होने के पहिले धार्मिक ग्रौर सामाजिक दोनों चे त्रों में प्रतिकियावादी प्रवृत्तियां वैसे ही अपने पूरे ज़ीर पर थीं जैसे हिंदू समाज में । इस्लाम धर्म और मुस्लिम-संस्कृति में डूवे हुए मुसल्मान राष्ट्रीयता के इस हिंदू रूप को देखकर कुछ चेंकि, कुछ िममके, उनके इस्लाम प्रेम ग्रीर राष्ट्रीयता की भावना के वीच एक संघर्प-सा छिड़ा, श्रीर उनमें से जो एक कहर मुस्लिम संस्कृति के पचपाती थे, उन्होंने राजनीति के चेत्र में राष्ट्रीयता को छोड़कर सांप्रदायिकता का पल्ला पकड़ा । यहीं से हमारे राजनैतिक जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या—सांप्र-दायिक समस्या- का सूत्रपात होता है। पर, उसे ग्रीर भी ग्राधिक स्पष्ट रूप में समफने के लिए हमें मुस्लिम राजनीति के विकास की गहराई में जाना होगा, ग्रीर उसके ग्रानेक युगों पर पड़ने वाले ग्रार्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक ग्रीर सवसे ऋधिक व्यक्तिगत प्रभावों को कुछ विस्तार के साथ समम्भना होगा।

मुस्लिम राजनीति और साम्प्रदायिकता

मुस्लिम राजनीति के विकास के इतिहास को वीन भागों में वांटा जा सकता है। पहिले भाग का प्रारम्भ सर सैयद ब्रहमद की उस नीति से होता है, जो उन्होंने भारतीय मुसल्मानों को कांग्रेस से ऋलहदा रखने के सम्बन्ध में धारण की थी। सर् सैयद ऋहमद ऋपने इस प्रयत्न में बहुत सफल न हो सके। उनकी त्रावाज़ एक छोटे तवक्रे तक ही पहुंच सकी। उनके जीवन-काल में ही कुछ प्रगति-शील मुसल्मान नेतात्रों ने उनकी नीति से ऋपना विरोध प्रगट करना प्रारम्भ कर दिया था । उनकी मृत्यु के बाद प्रमुख भारतीय मुसल्मान-शिवली नोमानी, अल्लाफ़ हुसैन हाली, अबुलकलाम आज़ाद, मुहम्मद अली श्रौर डा॰ इक्कवाल-राष्ट्रीयता की स्रोर स्राकर्षित हुए । मुसल्मानों में राष्ट्रीयता की धारा हिन्दू-समाज के राष्ट्रीय त्रान्दोलन से स्ववंत्र थी। पहिले महायुद्ध, ग्रौर कुछ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, ने दोनों धारात्रों को एक दूसरे के बहुत नज़दीक ला दिया । १६२०-२१ में दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से देश में विद्रोह की एक ऐसी ऋांघो उठो कि उसने ऋंग्रेजी-शासन की जड़ों को ही हिला दिया। पर उस त्रान्दोलन के शिथिल हो जाने के वाद सांप्रदायिकता ने ज़ोर पकड़ा । इसी वीच सांप्रदायिक चुनावों के विषैले परिणाम भी सामने त्राने लगे। लाला लाजवतराय, मौलाना शौकत ऋली ऋौर कुछ दूसरे राष्ट्रीय नेता भी सांप्रदावि-कता के प्रभाव से ऋपने को बचा नहीं सके। पर इन दिनों भी कुछ प्रमुख मुसल्मान नेता—हकीम अजमलखां, मौलाना मुहम्मदग्रली, डा॰ श्रन्सारी, मौलाना त्राज़ाद त्रादि-राष्ट्रीयता में त्रापना विश्वास त्राजुएण बनाये रख सके। '३० श्रीर '३२ के सविनय-ग्रवज्ञा-ग्रान्दोलनों ने भी मुसल्मानों को राष्ट्रीय त्र्यान्दोलन की त्र्योर खींचा, प्रगतिशील प्रवृत्तियां एक वार फिर सशक़ वनने लगीं। १६३७ का चुनाव प्रतिक्रियात्मक प्रतृत्तियों पर प्रगतिशील विचार-धारा की विजय का स्पष्ट द्योतक था। पर १९३७ के बाद ही, सांप्रदायिकता ने एक बार फिर ज़ोर पकड़ा । श्रापसी मतभेद श्रीर वैमनस्य एक वार फिर प्रवल हो उठे । पाकिस्तान की त्रावाज़ देश के कोने-कोने से उठी। पर त्राज मुश्लिम राजनीति का यह वीसरा युग भी ढलाव पर है,पाकिस्तान की मांग भी ग्रव मिद्रम पड़ती जा रही है, राष्ट्रीयता का वेग ऋव फिर वाड पर है।

सरसैयद श्रहमदखां

त्राधुनिक भारतीय मुस्लिम समाज के विकास में तर तैयद ग्रहमद रां का स्थान यदि हम निर्धारित करना चाहें तो शायद यह कहना काफी होगा कि वह मुस्लिम समाज के राजा राममोहन राय हैं। सर सेयद दिल्लीके एक संभ्रान्त सेयद परिवार में उत्पन्न हुए थे, श्रोर श्रारम्भ से ही श्रभ्ययन श्रोर विद्वत्ता की श्रोर उनकी रुचि थी। विज्ञान, धर्म, इतिहास, वास्तुकला श्रादि पर प्रायः वह लिखते रहते थे, दिल्ली के ध्वंसावशेषों श्रोर मक्कवरों पर उनकी एक मर्मस्पर्शी रचना—'श्रसारे सनादियाल'—का फ्रेंच में भी श्रनुवाद हुश्रा था। १८५७ के 'ग़दर' के बाद उन्होंने इस्लाम श्रोर ईसाई-धर्म दोनों पर तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कुछ लिखा। ईसाई धर्म-प्रचारकों द्वारा इस्लाम-धर्म पर जो श्राक्रमण किया जा रहा था, सर सेयद उसका भी करारा जवाब देते रहे। राममोहन रायके समान शिद्धा-प्रचार, विशेष कर पश्चिमी कला श्रोर विज्ञान के प्रचार में, सर सेयद की विशेष हिच थी। १८७७ ई० में श्रालीगढ़ में उन्होंने मुसल्मानों के लिए एक कॉलेज की स्थापना की। मुसल्मानों के लिए एक शिद्धा-परिषद् का संगठन भी उन्हों के प्रयत्नों का परिणाम था। सर सेयद द्वारा स्थापित 'मोहम्मडन एंग्लो-श्रोरिएएटल कॉलेज' ही श्राज प्रख्यात श्रालीगढ़ विश्व-विद्यालय के रूप में, सर सेयद के शिद्धा-संम्वधी प्रयत्नों का श्रमर प्रतीक बनकर, हमारे सामने मौजूद है।

शिचा-प्रचार के इस कार्य के पीछे सर सैयद ग्रहमद का ध्येय विल्कुल स्पष्ट था। उनको विश्वास हो गया था कि ग्रंगे जों से स्थायी संवन्ध वनाये रखने में भारतीय मुसल्मानों का कल्याण है। '५७ के विद्रोह में उन्होंने सरकार का साथ दिया, ग्रौर इस कारण वह जनता में वहुत कुछ ग्राप्रय भी वन गए थे। १८५७ के बाद से ही वह इस प्रयत्न में लग गए कि एक ग्रोर तो ग्रंगे जों के मन से इस बात की निकाला जाय कि 'ग़दर' की घटनात्रों में मुसल्मानों का प्रमुख हाथ था, ग्रौर दूसरी ग्रोर मुसल्मान ग्रंगे जी शासन के फायदों को समम्तने लगें। इसी ध्येय को ग्रपने सामने रख कर सर सैयद ग्रहमद ने १८५७ में 'ग्रसवाये बग़ावते हिन्द' नाम की एक पुस्तक लिखी ग्रौर १८६०-६१ में 'हिन्दुस्तान के राजभक्त मुसल्मान' शिर्षक से धारावाही रूप से लिखते रहे।' १८६८-७० की इक्कलैंड-यात्रा ने तो उन्हें ग्रंगे ज़ी सम्यता का ग्रौर भी कहर समर्थक बना दिया।' उनके शिचा-प्रयत्नो के पीछे भी यही उद्देश्य काम कर रहा था। एम० ए० त्रो० कॉलेज के उद्घाटन के ग्रवसर पर, लॉर्ड लिटन के सामने, सर सैयद ने कहा कि उक्त कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य 'पूर्व की

१-सर सैयद ने लन्दन पहुंच कर श्रपने एक पत्र में लिखा, "शिचा-प्रचार श्रीर चरित्र की दृष्टि से श्रच्छे से श्रच्छे हिन्दुस्तानी श्रॅंग्रे जों की तुलना में ऐसे ही हैं जैसे गन्दा जानवर किसी योग्य श्रीर सुन्दर मनुष्य की तुलना में।" Graham: Life and work of Sir. Syed Ahmad Khan. शिक्ता को पश्चिम के साहित्य श्रीर विज्ञान से संश्ठिष्ट कर देना, भारतीय मुसल्मानों को श्रंग्रेजी-राज्य के योग्य प्रजाजन वनाना व उनमें एक ऐसी राजभिक्त की भावना को विकसित करना था जिसका जन्म विदेशी शासन की गुलामी को श्रांख मींच कर स्वीकार कर लेने में नहीं, परन्तु एक श्रच्छे शासन की खूबियों को समक्त लेने में होता है।"

इस वीच, हिन्दू समाज में धार्मिक-सुधार की प्रेरणा से नवयुग (Renascence) की जिस धारा ने जन्म लिया था वह, समाज-सुधार के रास्ते होती हुई, राजनैतिक समस्यात्रों से टकराने लगी थी। स्थान-स्थान पर राजनैतिक दलों का संगठन होने लगा था। पहिले उनका कर्म-चेत्र श्रपने-श्रपने प्रान्तों तक ही सोमित था। कलकत्ते का इरिडयन एसोसिएशन, मद्रास की महाजन सभा. पूना की सार्वजनिक सभा त्रादि संस्थाएं इसी कोटि की थीं। पढ़े-लिखे भार-तीयों की सिविल सर्विस में प्रविष्ट होने की श्राकांचा ने इन प्रान्तीय प्रवृत्तियों को त्र्राखिल भारतीय रूप दे दिया । १८७७-७८ में सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने समस्त भारत में जो यात्रा की थी, उसका मुख्य उद्देश्य सिविल सर्विस की परीक्तात्रों में भार-तीय विद्यार्थियों की ऋसुविधान्त्रों को दूर करने के सम्बन्ध में न्न्यान्दोलन करना था, पर उसका परिणाम यह निकला कि अवतक प्रान्तीय आधार पर जो राज-नैतिक कार्य किया जा रहा था उसे अखिल-भारतीय रूप मिल गया। राजनीति के त्राखिल-भारतीय रूप लेते ही एक त्राखिल-भारतीय राजनैतिक संस्था के निर्माण की दिशा में प्रयत्न होने लगा । इन प्रयत्नों के परिग्राम-स्वरूप १८८५ ई० में कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस वहुत शीघ ही पढे-लिखे हिन्दुस्तानियों की राज-नैतिक भावनात्रों को त्रभिव्यक्त करने वाली एकमात्र संस्था वन गई। सब प्रान्तों क्रीर सब संप्रदायों में राजनैतिक प्रवृत्ति रखने वाले सर्वश्रेष्ट व्यक्तियों को उसने श्रपनी श्रोर श्राकर्षित किया । यद्यपि उसके निर्माण में ह्यम श्रोर वेडरवर्न श्रादि क्रांत्रोज़ों का हाथ भी था, क्रीर ऋनुमान तो यह भी है कि उसकी स्थापना की प्रेरणा उस समय के वड़े लाट डफ़रिन से प्राप्त हुई थी, पर ब्रारम्भ से ही एक निर्भीक रवैया इंग्लियार करने के कारण कांग्रेस शीघ ही सरकार की कृपाद्यां से केवल हाथ ही न धो बैठी, उसकी त्रांखों में खटकने भी लगी। स्वयं लॉर्ट इफ़रिन ग्रपने शासन के ग्रन्तिम दिनों में उसके प्रति बहुत जुब्ध रहे ।

कांग्रेस के प्रति सर सैयद श्रहमद का क्या रवैया होगा, यह जानने के लिए लोगवाग उन दिनों उत्सुक रहा करते थे । भारतीय राष्ट्रीयता श्रीर भारतीय श्राकां-साश्रों से सर सैयद को पूरी सहानुभृति थी । १८६० ई० में ही उन्होंने भारतीयों के धारा-सभाश्रों में लिए जाने के संबंध में श्रापनी श्रावाज उटाई थी। १८६६ में ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन की स्थापना के समय उन्होंने भय की वृत्ति को छोड़ देने ग्रीर स्रष्टता ग्रीर ईमानदारी से ग्रापनी शिकायते सरकार के सामने रख देने की सलाह दो थी। सर सैयद स्वयं वहें निर्मीक ख्रीर वेधड़क व्यक्ति थे। लॉर्ड लिटन के पञ्जाव यूनिवर्सिटी विल का उन्होंने वड़ा ज़ोरदार विरोध किया था। त्रागरा-दर्वार से वह उठकर चले गए थे, क्योंकि वहां बैठने की व्यवस्था में हिन्दु-स्तानियों ग्रीर ग्रंगेज़ों के बीच भेद-भाव रखा गया था। १८७७ में सुरेन्द्र-नाथ बनर्जी ग्रापने सिविल सर्विस ग्रान्दोलन के सम्बन्ध में ग्रालीगढ में जिस सभा में बोले थे, सर सैयद ने ही उसका सभापतित्व किया था। १८८४ में, पज्जाव में एक सार्वजनिक भाषण देते हुए, उन्होंने सभी संप्रदायों के सामान्य-हितों पर ज़ोर दिया, ग्रौर सहयोग ग्रौर संगठन की भावना से कार्य करने की ग्रपील की। उन्होंने कहा, 'हम (हिन्दू ऋौर मुसल्मान) एक दिल ऋौर एक ऋात्मा हैं, श्रीर हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए । इस प्रकार हम एक-दूसरे की वहुत ऋधिक सहायता कर सकेंगे। यदि हम एक न हो सके तो दोनों का ही पतन ऋौर सर्वनाश निश्चित है।' सर सैयद प्रायः हिन्दू ऋौर मुसलमानों को 'एक खुवसूरत दुलहिन की दो त्रांखें कहा करते थे। वह न केवल साम्प्रदायिक भावना से ही मुक्त थे, प्रान्तीय विद्वेष भी उन्हें छू न गया था। वंगालियों को वह देश का गौरव मानते थे। वह कहा करते थे कि हमने स्वतंत्रता श्रौर राष्ट्रीयता की भावना वंगाल से ही प्राप्त की है।

सर सैयद के सम्बन्ध में इन तथ्यों को जान लेना यड़ा जरूरी है। सांप्रदायिक विद्वेष की भावना उनमें तिनक भी न थी। प्रांतीयता की संकुचितता से
वह सर्वथा मुक्त थे। राष्ट्रीयता की भावना से वह स्र्योत-प्रोत थे। निर्मीकता
उनके चरित्र का मुख्य श्रङ्क थी। चरित्र की ऊंचाई के साथ बुद्धि की प्रखरता
भी उनमें थी। यह कहना उनके व्यक्तित्व का श्रपमान करना है कि सांप्रदायिकता
की स्रोर उनके मुकाव का कारण उन पर वैक, माँरीसन श्रादि उन श्रंप्रेज़ों का
प्रभाव था, जिन्हें उन्होंने समय-समय पर श्रलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर
नियुक्त किया था। भारतीय साम्प्रदायिकता जैसे व्यापक श्रान्दोलन की उत्पत्ति
व्यक्तिगत कारणों में दूंढ़ना, इतिहास में विचारों का जो ववण्डर वड़े-से-वड़े
व्यक्तियों को श्रपने साथ उड़ा ले जाता है, उसका निरादर करना है। सच तो
यह है कि हम यदि भारतीय-साम्प्रदायिकता के मूल-कारणों को जान लेना चाहते
हैं तो हमें ऐतिहासिक घटनाश्रों की गहराई में कुछ श्रिषक प्रवेश करना होगा।
वे कारण क्या थे जिन्होंने सर सैयद श्रहमद जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति के सिर सांप्रदाविकता के नेतृत्व का सेहरा वांध दिया ? क्यों सर सैयद श्रहमद ने यह निश्चय

किया कि भारतीय राष्ट्रवाद की जिस प्रवल धारा ने कांग्रेस को जन्म दिया, वह भारतीय मुसलमानों को उससे ऋलहदा रहने की सलाह दें ?

साम्प्रदायिकता का सूत्रपात

इस बात को समभ्तने के लिए हमें एक श्रोर तो कांग्रेस के निर्माण की मनोवृत्ति को जान लेना होगा ऋौर दूसरी ऋोर उन प्रवृत्तियों से ऋवगत हो लेना होगा, जिन्होंने सर सैयद ब्रहमद के न्यितित्व को बनाया था। कांग्रेस के सामने शुरू से ही राष्ट्रीयता का वह विशद श्रीर प्रखर रूप नहीं था, जिससे हम ब्राज परिचित हैं। राष्ट्रीयता कई युगों को चीरती हुई ब्रपनी ब्राज की स्थिति तक पहुंच सकी है। कांग्रेस का प्रारम्भ भारतीय समाज के एक वर्ग-विशेष के संगठन से हुआ। वह वर्ग था पश्चिम की विचार-धाराख्रों के संपर्क में ग्राया हुआ हिन्दुस्तान का पढ़ा-लिखा समुदाय । पढ़े-लिखे लोगों में ही राजनैतिक विचारों ने जन्म लिया था । वे ही इस वात के लिए वेचैन थे कि उन्हें ऊंचे सरकारी श्रोहदे श्रीर शासन में श्रिधक-से-श्रिधक श्रिधकार मिल सकें। पढे-लिखों में संप्रदाय का भेद-भाव नहीं था, पर क्योंकि हिन्दू-समाज ने ही ग्रंगेज़ी शिक्ता से सवसे ऋषिक लाभ उठाया था, यह स्वाभाविक ही था कि कांग्रेस में ऋारम्भ से ही हिन्दुत्रों का वहुमत होता। यों तो, कांग्रेस के पहिले ऋधिवेशन में दो मुसल्मान शामिल थे, दूसरे में उनकी संख्या ३३ श्रीर तीसरे में १५६ तक पहुँची । पारसी, सिख, हिन्दुस्तानी ईसाई ऋौर यूरोपियन भी उसके साथ थे, पर प्रधानता हिन्दुऋौं की ही थी। जहां तक मुस्लिम-समाज का संबंध था, शिचा के चेत्र में वह बहुत श्रिधिक पिछड़ा हुस्रा था। सर सैयद के सामने सबसे बड़ा ध्येय यह था कि उसे शिचा को दृष्टि से हिन्दुत्रों का समकच बनादें। हिन्दुत्रों को ता अंची नौकारेयां स्त्रीर शासन में ऋधिकार मिलना स्त्रारम्भ हो गए थे, इसलिए वह 'स्त्रीर श्रिधिक' के लिए श्रान्दोलन करने का साहसपूर्ण क़दम उठा सकते थे। मुस्लिम-समाज ग्रमी उस स्थिति में नहीं था। वड़े धीरज ग्रीर वड़ी लगन से. वड़ी-वड़ी कठिनाइयों के मुक़ाविले में, सर सैयद ग्रहमद मुस्लिम-समाज के प्रति शासकों के श्रविश्वास को हटा पाये थे, श्रौर स्वय मुसल्मानों में सहयोग को श्रांत को जन्म दे सके थे। कांग्रेस की स्थापना ने सर सैयद श्रहमद को एक कांटन परि-स्थिति में ला खड़ा किया । यदि सर सैयद श्रहमद कांग्रेस का साथ देते वो यह सहज ही मुसल्मानों को शासकों के श्रविश्वास का पात्र बना लेते-श्रीर इस प्रकार अपने जीवन-व्यापी कार्य को अपने हाथों ही जुत्म कर देते । इसी कारण. कांग्रेस के आदशों से पूरी सहानुभूति रखते हुए भी सर सैयद ने मुसल्मानी की उससे श्रलहदा रहने की सलाहं दी ।

कांग्रेस के प्रति सर सैयद ग्रहमद ने जिस नीति को ग्रापनाया था, उसके पीछे राजनैतिक, ऋार्थिक ऋौर व्यक्तिगत कारण थे, सांप्रदायिकता की मलीनता नहीं थी । जैसा कि शिवली नोमानी ने लिखा, "प्रकृति ने उन्हें समस्त देश का नेता होने की पात्रता दी थी, परन्त परिरिथतियों श्रीर उनके वातावरण ने उन्हें मुसल्मानों को राष्ट्रीय ग्रांदोलन से ग्रलहदा रखने की नीति धारण करने पर मजबूर कर दिया ।" सर सैयद ग्रहमद का कांग्रेस के प्रति विरोध मुसल्मानों का राष्ट्रीय झांदोलन के प्रति विरोध नहीं था। वह तो मध्यम श्रेगी के एक पिछड़े हए वर्ग द्वारा, जो अनिश्चितता की गहरी खाई के किनारे खड़ा था, उस आगे वढ़ने वाले वर्ग का विरोध था, जो अब खतरनाक स्थिति में नहीं रह गया था, त्रीर जिसे यह विश्वास हो चला था कि ब्रांदोलन करने से ऊंची नौकरियां मिल सकेंगी। यह तो परिस्थितियों का परिणाम था कि ग्रागे वढे हुए दल में हिंदुग्रों की संख्या त्र्याधिक थी; ग्रीर जो दल पिछड़ गया था उसमें मुसलमान ज्यादा थे। सच तो यह है कि बजाय यह कहने के कि मध्यम वर्ग के मुसल्मान मध्यम वर्ग के हिंदुओं के मुकाविले में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए और राज-नैतिक दृष्टि से श्रंग्रेजी शासन के श्रिधिक सम्पर्क में थे, यह कहना श्रिधिक ठीक होगा कि देश का मध्यम वर्ग दो भागों में बंट गया था। एक अपनी शक्ति पहि-चानने श्रीर शासन में दोप निकालने लगा था श्रीर दूसरा श्रार्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ और अंग्रेंजी शासन का समर्थक था, और इन दोनों दलों में से पहिले में हिंदुओं की संख्या अधिक थी और दूसरे में मुसल्मानों की ।

सर सैयद का व्यक्तिगत साहस कितना ही वढ़ा-चढ़ा क्यों न रहा हो, उनकी राजनीति भीक्ता की राजनीति थी। १८८७ में, जब कांग्रेस मद्रास में एक मुस्लिम सभापित के नेतृत्व में ग्रपना ग्राधिवेशन कर रही थी, सर सैयद ग्रहमद ने "ग्रवध के तालुकदारों, सरकारी नौकरों, फौजी ग्रफसरों, वकीलों ग्रौर ग्रख़वार नवीसों" की सभा में भाषण करते हुए कहा कि मुसलमानों को कांग्रेस से ग्रलहदा रहना चाहिए "ताकि उनके प्रति राजद्रोह का संदेह न किया जा सके"। सर सैयद जानते थे कि वह समय की गति के विरुद्ध काम कर रहे हैं, पर वह उस ज़मीन पर से ग्रपनी जड़ें नहीं समेट सकते थे जिस पर उनके समस्त जीवन का विकास हुग्रा था। सर सैयद ने ग्रारम्भ से ही मुस्लिम-समाज की उन्नति को ग्ररने जीवन का ध्येय वनाया था। वह प्रधानतः समाज-सुधारक थे, न कि राष्ट्रीय कार्यकर्ता। उन्नीसवीं शताब्दी में समाज-सुधार की जितनी प्रवृत्तियों ने जन्म लिया उनका कार्यहोत्र हिंदू ग्रौर मुस्लिम समाजों की सीमाग्रों में १८८. Smith: Modern Islam in India.

त्रपने को वचा रखना किटन होगया, जो हिन्दू-समाज की त्रानेकानेक प्रवृत्तियों के समान इस्लाम में भी क्यापक होती जा रही थीं। जनता के मन की तो वही चीज़ थी, जनता ग्रपना ग्रात्मविश्वास खोना नहीं चाहती थी। इस सम्बन्ध में ग्रमीरम्रली की रचनाम्रों का वहा प्रभाव पड़ रहा था। उनकी 'स्पिरिट ग्रॉफ इस्लाम' नाम की प्रसिद्ध पुस्तक का पहिला संस्करण १८६१ ई० में निकला था। इस्लाम के प्राचीन गौरव का विशद चित्र भारतीय मुसल्मानों के सामने रख देने, ग्रौर इस्लाम में उनके ग्रात्मविश्वास को जागृत करने में ग्रमीरम्रली का बहुत वड़ा हाथ रहा है। उन्होंने पैगम्बर के व्यक्तित्व का कोमल पच्च सुन्दर से-सुन्दर रूप में ग्रपने पाठकों के सामने रखा। पैगम्बर व प्रारम्भिक खलीफ़ाम्रों के मस्तिष्क की प्रखरता, भावनाम्रों की उदारता ग्रौर ग्राचार की पवित्रता ग्रमीरम्रली के शब्द-चित्रों में जीवित हो उठी। इस्लाम में मुसल्मान जनता का ममत्व जागा। ग्रमीरम्रली ने जिस काम को, शुरू किया था, खुदाबख्श ग्रादि लेखकों ने उसे ग्रौर ग्रागे बढ़ाया।

सर सैयद ग्रहमद के निकट श्रनुयायियों पर भी हम इस नई विचार-धारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से पाते हैं। चिराग़ ऋली और मोहसिनुल्युल्क ने तो सर सैयद के नेतृत्व का ही ऋनुकरण किया। वे दोनों पश्चिमी विचारों ऋौर ऋंग्रेज़ी शासन के उतने ही कट्टर समर्थक थे जितने सर सैयद। पर श्रीर लोग जो उम्र में कम थे, तेज़ कदम रखने के लिए तैयार थि। इनमें ग्रल्ताफ हुसैन हाली, शिवली नोमानी, नज़ीर ग्रहमद ग्रादि के नाम मुख्य हैं। सर सैयद ने मसल्मानों को एक नयी राह पर चलने का आदेश दिया था, पर वह राह मुसल्मानों की ग्रापनी राह नहीं थी, पश्चिम की राह थी। ग्राल्वाफ़ हुसैन हाली ने सबसे पहिले मुसल्मानों के त्रारम-विश्वास की जागत किया। हाली भी सर सैयद के समान मुसल्मानों के वर्तमान जीवन से दुःखी थे, पर उनमें श्रौर सर सैयद में एक वड़ा श्रन्तर था। सर सैयद सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रेरणा पश्चिम से प्राप्त करना चाहते थे: हाली के सामने मुस्लिम संस्कृति का प्राचीन वैभव था। हाली ने मुसल्मानों की अपनी ज़वान में ही उन्हें नव-विर्माण का संदेश दिया। सर सैयद का उर्द् को विकसित करने का प्रयत्न बहुत दिनों न चल पाया था, पर इस वीच जकाउल्ला श्रीर नज़ीर श्रहमद जैसे लेखकों ने उद्दें को साज-संवार दिया था। इस मंजी हुई भाषा में हाली का धारा-प्रवाह अपने पूरे वेग से चला । हाली सर सैयद के रास्ते से हट कर ग्रापना ग्रालग रास्ता बना चुके थे । शिवली नोमानी ने इस नये रास्ते को ग्रीर भी प्रशस्त वनायां। शिवली नोमानी का दृष्टिकोग्। भी वही था जो हाली का था। सर सैयद इस्लाम को

पश्चिम की वैज्ञानिक दृष्टि से कसना श्रीर परखना चाहते थे। हाली श्रीर शिवल नोमानी ज्ञान, कला, संस्कृति सब कुछ इस्लाम की कसौटी पर कसते थे। शिवली एक वड़े साहित्यकार ऋौर राष्ट्र-निर्माता थे। उनका 'शैर-उल-ग्रजम' फ़ारसी कविता के गहरे ऋध्ययन का परिचायक है। 'सिरातुन्नवी' के नाम से उन्होंने पैग़म्बर की एक महान् जीवनी लिखी । शिवली ने इस्लाम के कई ऋन्य महान् व्यक्तियों के भी वड़े प्रभावशाली जीवन-चरित्र लिखे हैं। १६०८ में वह लखनऊ के 'नदवत-उल-उल्मां' के प्रिंसिपल नियुक्त होगए थे, पर वहां से जल्दी ही त्रजलहदा होगए, त्र्रौर त्राज़मगढ़ में उन्होंने एक लेखक संघ—'दार-उल-मुसन्निफ़ीन'—की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इस्लाम के त्रादशों का प्रचार करना था। आज भी यह संस्था, सुलेमान नदवी के नेतृत्व में, वड़ा अच्छा काम कर रही है। सर सैयद के समान शिवली भी ऋंग्रेंज़ी शासन में विश्वास रखते थे, पर ग्रन्तर यह था कि शिवली की इस्लाम-भिक्त उनकी राजभिक से कहीं वढ़ी हुई थी। १६०८ के बाद से उन्होंने ऋपनी इन दोनों प्रवृत्तियों में विरोध पाया, स्त्रीर तवसे वह, खुले-स्राम, स्रंग्रेज़ी शासन के विरोध में, स्त्रीर इस्लाम के पत्त में, त्रा खड़े हुए थे। ज़माना तेज़ी से करवटें ले रहा था। मुस्लिम समाज में भी त्रात्म-विश्वास त्रीर राजनैतिक जाग्रति की भावनाएं फैलती जा रही थीं।

इक्बाल

इन्हीं दिनों भारतीय इस्लाम में एक महान् व्यक्तित्व अपनी अट्ट प्रतिमा लेकर आया, जिसने अपने प्रभाव की अमिट छाप आने वाली पीढ़ियों पर लगादी। यह थे डॉ॰ इक्कवाल। डॉ॰ इक्कवाल का जन्म १८७३ ई॰ में, पञ्जाव में, हुआ। किव के नाते तो वह अपने कॉलेज-जीवन से ही प्रसिद्ध हो चले थे — यद्यपि उनकी पहिली प्रसिद्ध किवता 'कोहे हिमाला' अप्रैल १६०१ के 'मख़ज़न' में प्रकाशित हुई। एक नई फिलॉसफ़ी के संदेशवाहक के रूप में इक्कवाल हमारे सामने १६०८ के बाद ही आये। इस्लाम में अडिंग विश्वास उन्हें अपने लाहीर के शिक्तों और साथियों—टी॰ डब्ल्यू॰ आनील्ड, मोलाना मीरहसन आदि—से मिला था। १६०५ से १६०८ तक इक्कवाल इंग्लैंड व जर्मनी में रहे। यहां रह कर उनका यह विश्वास और भी मज़वूत बना। पश्चिमी सम्यता की सारहीनता और खोखलेपन का भी उन पर वड़ा गहरा असर पड़ा। उस सम्यता के पीछे शिक्त की व्यापकता से भी वह प्रभावित हुए विना न रह सके। इक्कवाल ने देखा कि यह शिक्त ध्वंसात्मक कार्यों में लगाई जा रही है। व्यिक्ति गत जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं है। सामृहिक जीवन संघर्षमय है। व्यिक्ति का व्यिक्त से, वर्ग का वर्ग से, अरीर राष्ट्र का राष्ट्र से संघर्ष चल रहा है।

उन्होंने यह भी देखा कि पूर्व में ग्रादर्शवादिता ग्रोर मिल-जुल कर काम करने की प्रवृत्ति है, पर पूर्व में शिक्त नहीं है। इक्तवाल ने ग्रापने सरल पर सशक व्यक्तित्व का समस्त वल ग्रापने देशवासियों में शिक्त का संचार करने में लगा दिया।

इक्रवाल का शिक्त का संदेश हमें स्वामी विवेकानन्द की याद दिलाता है। ग्रपने देशवासियों के लिए विवेकानन्द का सन्देश भी यही था। विवेकानन्द ने कहा था. ''सबसे पहिले बलवान बनो । सशक बनो । मेरे मन में तो दृष्ट व्यक्ति के लिए भी ब्रादर है, यदि उसमें पुरुषत्व ब्रीर शक्ति है, क्यों कि शक्ति उसे किसी भी दिन अपनी दुष्टता छोड़ने पर मजवूर कर सकती है, श्रीर उसे यह प्रेरणा दे सकती है कि स्वार्थ की दृष्टि से किये जाने वाले श्रपने सव कामों को छोड़ दे, श्रीर इस प्रकार उसे चिरन्तन सत्य से तदाकार कर सकती है।" इक्कवाल का यह भी कहना था कि ज़िन्दादिल व्रतपरस्त काफ़िर भी उस मुसल्मान से ग्राच्छा है जो हरम में सोया पड़ा रहता है। विवेकानन्द ने जैसे फांफ, करताल, मृदङ्ग ब्रादि के साथ भिक्त की सस्ती भावप्रवर्ण ब्राभि-व्यक्ति को बुरा बताया था वैसे ही इक्रवाल सूफ़ियों की इसी किस्म की बहुत सी बातों के खिलाफ़ थे। उनका मत था कि यह सब ग्रारव की पुरुपत्व-प्रधान सम्यता पर यूनान की स्त्रेण सम्यता के प्रभाव का परिणाम था। व्यक्तित्व की महानता में इक्तवाल का विश्वास था । अभ्तपूर्व प्रतिभा वाला एक महान् सशक्त, व्यक्तित्व—उनका त्र्यादर्श था । नीत्शे की Super-Man की कल्पना का उन पर स्पष्ट प्रभाव था। इक्कवाल की कवितात्रों में चाहे हम उनके किसी भी संग्रह को उठा लें - शिक्षशाली व्यक्तित्व के निर्माण पर ज़ोर दिया गया है। उनके इस सन्देश से भारतीय मुसल्मानों को निःसन्देह एक नया वल पात हुआ।

राष्ट्रीयता का विकास

इस वीच, मुसल्मानों में राष्ट्रीय भावना प्रवल होती जारही थी। इस राष्ट्री-यता का आधार भारतीय मुस्लिम-समाज की वैसी ही प्रतिगामी प्रवृत्तियां थीं, जिन्होंने हिन्दू-समाज में राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। इस्लाम की महानता में एक अमिट विश्वास को आधार वनाकर मुसल्मानों में राष्ट्रीयता की भावना फैली। अमीरअली आदि उसके प्रवर्त्तकों में हैं। शिवली नोमानी का उसके निर्माण में वड़ा गहरा हाथ था। १६१२ के बाद इस राष्ट्रीयता ने ज़ोर पकड़ा। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से उसे प्रोत्साहन मिला। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में, टकीं के सुल्तान अब्दुल हमीद के नेतृत्व में, इस्लाम के एक

विश्व-व्यापी संगठन का जो ग्रान्दोलन चला, उसका उद्देश्य राजनैतिक ग्रिधिक था, धार्मिक कम । उस समय तो भारतीय मुसल्मानों पर इस आ्रान्दोलन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, पर १९१२ के स्त्रास-पास जब टकों पर योरोपियन राष्ट्रों का त्राक्रमण होने लगा त्रौर मुसल्मानों का एक ऐसा देश, जिस पर वह नाज़ कर सकते थे, नष्ट होता दिखाई दिया, तो उनमें सहानुभूति की एक लहर दौड़ गई। इस नये राष्ट्रीय उत्साह ने उर्दू के उन दिनों के साहित्य में एक नया जीवन ला दिया । अक्रवर ने अपने तीखे ब्यंग, शिवली ने पैनी चुटिकयों व इक्कवाल ने फड़का देने वाली कवितात्रों से मुसल्मानों में त्रंग्रेज़ों की उपेचा, उनकी संस्कृति के प्रति अवज्ञा और राष्ट्रीयता की एक नई लहर पैदा कर दी। इन्हीं दिनों उच्चकोटि के कुछ पत्र भी सामने स्राये। स्रबुल कलाम स्राज़ाद का 'त्रवित्वाल' बड़ी ज़ोरदार शैली में सामाजिक श्रीर राजनैतिक दोनों चेत्रों में वड़े उम्र विचारों को व्यक्त किया करता था। ज़फ़रस्राली ख़ां के 'ज़मींदार' ने तो उत्तरी भारत के उद् जानने वालों में ऋख़वार पढ़ने का एक नया शौक़ ही पैदा कर दिया । मोहम्मदन्राली त्रापने त्रांग्रेज़ी के 'कॉमरेड' व उर्दू के 'हमदर्द' द्वारा इस नये इन्क्रिलाव में पूरा हाथ बंटा रहे थे। मोहम्मदन्न्रली कियात्मक राजनीति में भी प्रमुख भाग ले रहे थे—१६१२ में उन्होंने डॉ० स्त्रन-सारी के नेतृत्व में एक मिशन टर्की भेजा। महायुद्ध में जव श्रंग्रेज़ी सेनाएं दर्जी के खिलाफ़ लड़ रही थीं तब तो हिन्दुस्तान के मुसल्मानों में हुन्बुलवतनी का एक नया जोश मौजें लेने लगा । सरकार का दमन-चक्र उसे रोक तो सका, पर कुचलने में त्रासमर्थ रहा। त्राज़ाद, मोहम्मदत्राली त्रादि सव जेलों में थे, पर जन-साधारण में राष्ट्रीयता की भावना फैलती जारही थी। १६१६ में मुस्लिम-लीग श्रीर कांग्रेस ने एक समभौते पर दस्तख़त किये। १६१७ में श्रंपेज़ी सर-कार को हिन्दुस्तान में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की नीति घोषित करने पर मजबूर होना पड़ा । परन्तु श्रसन्तोष सुलगता रहा । युद्ध समाप्त हुन्ना तो काला क़ानून त्र्राया त्र्रौर उसके साथ गांधीजी के सत्याग्रह की धमकी, त्र्रौर **अ्रमृतसर का हत्याका**ग्ड! राजनैतिक **त्रान्दोलन की लपटें** त्र्याकाश को चूमने के लिए वढीं - ग्रीर हिन्दुस्तान के मुसल्मानों ने देश के लिए वड़ी-से-वड़ी विल देने की तैयारी कर ली।

१६२०--२१ में देशव्यापी एक बड़े राजनैतिक स्रान्दोलन का होना श्रान्-वार्य था—पर गांधीजी के नेतृत्व ने उसकी रूपरेखा को वदल दिया। विखरे हुए हत्याकाएडों के स्थान पर एक संगठित स्रहिंसात्मक स्रान्दोलन का विकास हुस्रा। मुस्लिम-समाज ने खुले दिल से गांधीजी के नेतृत्व को स्वीकार किया। देशभर में ख़िलाफ़त कमेटियां वन गईं च्रौर एक केन्द्रीय ख़िलाफ़त कमेटी के नेतृत्व में उन्होंने दर्की के प्रति श्रंग्रेज़ी सरकार की नीति का खुला विरोध श्रारम्भ कर दिया । १९१६ के ग्रन्त में गांधीजी के प्रयत्न से, जब ग्रालीवंधु जेल से छूटे तव इस ग्रान्दोलन को एक नया वल मिला । उलमात्रों का हार्दिक समर्थन उसे पहिले से ही पाप था-श्रंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ख़िलाफ़त के पच में जो ग्रान्दोलन किया जा रहा था उसे देश के कोने-कोने तक फैलाने में उनका वड़ा हाथ रहा है। १६२० में जब अबुल कलाम आज़ाद जेल से निकल कर ग्राये, तव ग्रान्दोलन का वेग ग्रीर भी प्रवल होगया। मई १६२० में ग्राखिल भारतीय ख़िलाफ़त कमेटी ने गांधीजी के 'ख्रदम-तत्र्यावन' (ब्रसहयोग) के कार्य-क्रम को ग्रपनाया—कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को कई महीने वाद स्वीकार किया। मुस्लिम-लीग के लिए भी पांछे रहना कठिन होगया । मौलाना शौकतन्त्रली की प्रेरणा से मुस्लिम-लीग ने भी असहयोग के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया-पर वास्तविक काम खिलाफ़त-कमेटी के नेतृत्व में ही हुन्ना । १६२०-२१ में भारतीय राष्ट्रीयता की स्वतन्त्र रूप से विकसित होने वाली दो विभिन्न धारायें— गङ्गा श्रीर यसुना के समान—एक दूसरे से जा मिलीं, श्रीर उनके इस सम्मिलन से राष्ट्रीय त्रान्दोलन को एक त्रमृतपूर्व वल प्राप्त हुत्रा । ऋंग्रेज़ी शासन की जड़ें हिल उठीं । यह सच है कि बहुत कम हिन्दू या मुसल्मान यह जानते थे कि वह किस लच्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष श्रीर विलदान कर रहे हैं; वह तो संघर्प में ही एक नये गौरव का अनुभव कर रहे थे। १६२०-२१ का वह स्वातंत्र्य-युद्ध हमारी राजनीति के इतिहास में सचसुच एक गौरवशाली स्मृति है!

साम्प्रदायिकता की प्रगति

त्रान्दोलन का धार्मिक पत्त विल्कुल स्पष्ट था। आजाद और मोहम्मदस्रली उसके दो प्रमुख नेता थे, दोनों के जीवन की प्रेरणा का मूल-स्रोत धर्म था। आजाद के लिए तो यह मुसल्मान का फर्ज़ था कि वह या तो अपने को खत्म करदे या अपनी आजादी कायम रख सके। मोहम्मदस्रली भी कम धार्मिक नथे। राष्ट्रीय-ख़िलाफ़त आन्दोलन के दिनों की दो प्रमुख घटनाओं—१६२० की हिजरत और १६२१ के मोवला-आंदोलन—से भी इस धार्मिक प्रशृत्ति का पता लगता है। १६२१ के अंत में आजाद और अलीवन्धु फिर गिरफ्तार कर लिए गए। फर्वरी १६२२ में, चौरीचौरा के हत्याकाएड के वाद, गांधी जी ने आन्दोलन स्थगित कर दिया। नवम्बर १६२२ में मुस्तफ़ा कमाल के उस समय के सुल्तान-ख़लीफ़ा को पदच्युत करके टक्षों के शासन की वागडोर अपने हाथ में लेते ही ख़िलाफ़त आंदोलन का सारा आधार ही ख़त्म होगया। आने वाले

वर्षों में निराशा श्रीर खीभ हमारी राजनीति का मुख्य विषय वन गई। सांप्र-दायिकता के आधार पर होने वाले कौंसिलों के नये चुनाव ने सांप्रदायिक विद्वेष को प्रोत्साहन दिया। ग़लतफ़हिमयों के इस वातावरण में दूसरों के दोष ढूँढ़ निकालना कठिन नहीं था। हिन्दुन्त्रों में यह भावना ज़ोर पकड़ने लगी कि ख़िलाफ़त का साथ देकर उन्होंने एक संकुचित धार्मिकता का समर्थन किया था। मुसल्मानों का ख्याल था कि हिन्दुत्रों के दब्बूपन की वजह से उन्हें सफलता नहीं मिल सकी । ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय-शक्ति का सांप्रदायिकता की धाराओं में वह निकलना स्वाभाविक ही था। स्रंग्रेज़ी सरकार से जब बस न चला तो हिन्दुत्रों ने मुसल्मानों के कान उमेठने की कोशिश की । त्रौर मुसल्मानों ने भी हिन्दुन्त्रों पर त्रपना गुस्सा निकालना चाहा । सांप्रदायिकता के इस प्रवल भन्भा वात में राष्ट्रीय नेतृत्व का एक वहुत वड़ा श्रंश डिग उठा। मौलाना मोहम्मद त्राली ने १६२३ में जेल से छूटने पर कहा कि त्राव वह एक छोटे कैदलाने से वड़े क़ैदलाने में त्रागये हैं। उसी वर्ष कोकोनाडा कांग्रेस के वह समापित वने। पर, उनकी राजनीति उतनी उम्र नहीं रह गई थी, श्रौर धीरे-धीरे वह कियात्मक राजनीति के चेत्र से हटते गए, यद्यपि वह ऋपने ऋन्तिम दिनों तक भी सांप्रदा-यिकता के कट्टर समर्थक नहीं बन सके थे। पर, मौलाना शौकतन्त्रली ने तो अपने को सांप्रदायिकता के हाथ वेच ही दिया। उधर स्वामी श्रद्धानन्द ने, जो दिल्ली में मशीनगनों के सामने छाती खोलकर खड़े होगए थे स्रौर जिन्हें मुस-ल्मानों ने जामामस्जिद में भाषण देने पर मजवूर किया था, हिन्दू सांप्रदायिकता का नेतृत्व ऋपने हाथों में लिया । ऋौर, लाजपतराय जैसे कहर ऋौर मंजे हुए देशसेवी भी सांप्रदायिकता की स्रोर भुक चले। इन घटनास्रों की प्रतिक्रिया . मस्लिम-जनता पर होना स्वाभाविक ही था। बड़े-बड़े लेखक भी इस प्रभाव से वच न सके। ऋमीरऋली ने श्रंगेज़ों की ऋालोचना करना वन्द करदी. श्रौर खुदावख्श खुले श्राम हिन्दुश्रों को गालियां देने लगे।

इक्तवाल के शिक्तशाली व्यक्तित्व की चर्चा अपर आ चुकी है। इक्तवाल कियात्मक राजनीति के च्लेत्र में कभी नहीं रहे, पर उनके प्रभावशाली साहित्य और सशक्त व्यक्तित्व का प्रभाव मुसल्मान राजनैतिक कार्यकर्ताओं के जीवन और आदशों पर बहुत गहरा पड़ रहा था। यह प्रभाव, यह कहने में हिचिकिचा हट नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रीयता के सर्वथा विरुद्ध था, और सामाजिक संगठन के मार्ग में भी रुकावट डालने वाला था। इक्तवाल अपने योरुप-प्रवास से लौटने के वाद से ही राष्ट्रीयता के कहर विरोधी होगए थे। उन्होंने योरुप में राष्ट्रीयता का नम-ताएडव देखा था और तभी से अन्तर्राष्ट्रीयता में वह

विश्वास करने लगे थे, यद्यपि उनकी अन्तर्राष्ट्रीयता की कल्पना एक अखिल-मुस्लिम-संगठन की सीमाओं से बंधी थी। जबिक कुछ मुसल्मानों ने अपनी राष्ट्रीयता की प्रेरणा धर्म से प्राप्त की, इक्तवाल का मत था कि राष्ट्रीयता धर्म की शत्रु है। उन्होंने कहा—

> इन ताज़ा खुदात्रों में वड़ा सबसे बतन है, जो पैरहन उसका है वह मज़हब का कफ़न है।

ग्रीर--चीनो ग्रास्य हमारा हिन्दोस्तां हमारा । मस्लिम हैं हम वतन है सारा जहां हमारा ॥

इस विचार-धारा से राष्ट्रीयता का ग्रहित ग्रीर साम्प्रदायिकता का समर्थन होना स्वाभाविक था। इक्तवाल की ग्रान्तर्राष्ट्रीयता भी कभी शद रूप न ले सकी । सन्त्र तो यह है कि इक्कवाल पर विचारों का अधिक प्रभाव पड़ता था, वस्त-रिथित का कम । इस्लाम के वह प्रशंसक थे-पर उसके ख्रीर मुस्लिम समाज के वर्त्तमान संगठन के ऋन्तर को वह न देख सके, एक विश्व-न्यापी संगठन में उनका विश्वास था—इस्लाम में भी उन्हें इस संगठन का रूप मिला। उन्होंने यह सोचने की चिन्ता नहीं की कि उनके सामने इस्लाम का जो रूप था, उसमें विश्व-व्यापी संगठन का ग्राधार वनने की पात्रता रह नहीं गई थी, न उन्होंने यही सोचा कि उनके सामने भी किसी ऐसे ही विश्व-व्यापी संगठन का एक कोई विशव प्रयोग किया जा रहा है। इक्कवाल प्रधानतः कवि थे। मावनायें उन्हें उड़ा ले जाती थीं । इस्लाम को उन्होंने ग्रादर्श माना इसलिए राजनैतिक चेत्र में उन्होंने राष्ट्रीय संस्थाओं के बदले मुस्लिम संस्थाओं का —कांग्रेस के बदले मुस्लिम लीग का —समर्थन किया । इक्तवाल ने भारतीय मुस्लिम समाज के सामने शिक्त का एक नया ग्रादर्श रखा, पर उसके प्रयोग की दिशा के सम्बन्ध में वह भीन रहे। इक्तवाल का शक्ति का सन्देश व्यक्ति के लिए था-उसका ग्रादर्श व्यक्तित्व को विकास की चरम सीमा तक ले जाना था, पर समाज-सेवा का कोई ग्रादर्श उन्होंने व्यक्ति के सामने नहीं रखा। विवे-कानन्द ग्रौर उनमें यही ग्रन्तर था--ग्रौर इसी कारण जहां हम एक ग्रोर हिन्द-समाज का नेतृत्व विवेकानन्द के वाद गांधी के हाथों में पाते हैं, जो जीवन में बड़ी से बड़ी शिक्त प्राप्त तो करना चाहता है पर उसे समाज की सेवा में लगा देता है, मुस्लिम-समाज में इक्तवाल के बाद जिस व्यक्ति का सबसे ग्राधिक प्रभाव रहा वह हैं मुहम्मदत्राली जिन्ना जो सारी शांकि त्रापने त्रापमें केन्द्रित कर रखना चाहते हैं।

राष्ट्रीयता का पुनरुत्थान

सांप्रदायिकता के इन ऋंधेरे दिनों में भी कुछ प्रमुख मुसल्मान नेता राष्ट्री-यता में अपना विश्वास अडिंग वनाये रह सके । इनमें मौलाना अबुल कलाम त्राज़ाद, डॉ॰ ग्रन्सारी, हकीम अजमल खां, चौधरी ख़लीकुज्ज़मा आदि के नाम मुख्य हैं। जमीयत-उल-उल्मा, जिसकी स्थापना १६१६ में मौलाना मोहम्मद-उल-हसन के नेतृत्व में हुई थी, श्रीर जिसने १६२१ में मुसल्मानों को त्रप्रसहयोग्न का मार्ग स्वीकार करने का प्रसिद्ध 'फ़तवा' दिया था, सुफती किफ़ा-यतुला के नेतृत्व में, त्रानवरत रूप से, राष्ट्रीयता का समर्थन करती रही। मुस्लिम लीग भी राष्ट्रीयता का समर्थन कर रही थी-यद्यपि इन दिनों उसकी शांक श्रिधिक नहीं थी। १६२७ में सायमन-कमीशन की नियुक्ति के बाद मुस्लिम-लीग में दो दल होगए। सरकार-परस्त दल ने फ़ीरोज़खां नून ऋौर डॉ॰ इक्क-वाल के नेतृत्व में ऋपना संगठन किया, पर एक बड़े दल ने मुहम्मदऋली जिन्ना के नेतृत्व में कमीशन के वहिष्कार का निश्चय किया । १६२८ में नेहरू रिपोर्ट के प्रकाशन से राष्ट्रीय विचार रखने वाले मुसल्मानों की स्थिति कुछ स्त्रीर कम-ज़ोर हो गई। प्रथम-श्रेंग्। के कुछ मुसल्मान नेतात्रों ने, जिनमें मौलाना मुहम्मद-त्राली मुख्य थे, उसका विरोध किया । मुसल्मानों के एक सर्वदल सम्मेलन ने, जिसमें लीग का वह दल भी शामिल हुन्ना था जिसके नेता मि॰ जिन्ना थे, नेहरू रिपोर्ट को ग्रस्वीकृत कर दिया-पर, इसका परिगाम भी यह हुन्ना कि कांग्रेस के समर्थक मुसल्मानों ने फौरन ही एक 'राष्ट्रीय मुस्लिम दलं की स्थापना कर ली। १६३० के सविनय ऋवज्ञा ऋान्दोलन में मुसल्मानों ने वड़ी संख्या में भाग लिया । १६३१ में लखनऊ में सर ऋली इमाम के नेतृत्व में देश भर के राष्ट्रीय मुसल्मानों की एक वहुत बड़ी कान्फ्रेंस हुई, जिसमें कई हज़ार व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके कुछ ही दिनों पहिले इलाहावाद में डॉ॰ इक्कवाल के सभापतित्व में मुस्लिम-लीग का वार्षिक उत्सव होकर चुका था, जिसमें ७५ से भी कम व्यक्ति शामिल थे।

१६२६-३० के विश्वव्यापी अर्थ-संकट के बाद से प्रायः प्रत्येक देश और वर्ग में दो परस्तर विरोधी विचार-धाराएं एक दूसरे से टकराने लगी थीं। एक और तो प्रगतिशील शिक्तयां थीं, जो समाज के वर्तमान ढांचे को तोड़ फेंकना, और एक नये समाज का निर्माण करना, चाहती थीं, और दूसरी और प्रतिक्रियात्मक शिक्तयां थीं, जो अपना सारा बल उसे न केवल सुर्राह्मत रखने, पर अधिक सशक्त बनाने में, लगाना चाहती थीं। हमारे देश में, और देश के मुस्लिम-समाज में भी, १६३० से १६३७ तक प्रगतिशील शिक्तयों का प्राधान्य रहा। इन वर्गों में

मुसल्मान एक बड़ी संख्या में कांग्रेस का साथ देते रहे। हुसैन ग्रहमद मदनी ग्रीर उवैदुला सिंघी जैसे प्रमुख उलमा वरावर कांग्रेस के साथ रहे । कांग्रेस के मुस्लिम नेतात्रों में मौलाना श्राज़ाद, हकीम श्राजमल खां, डॉ॰ किचलू, डॉ॰ श्रन्सारी श्रादि मुख्य थे। श्रपने धार्मिक चिन्तन, प्रगाढ़ विद्वत्ता, श्रीर प्रभाव-शाली वक्तृत्वशाक्त से मौलाना त्राज़ाद ने सदा ही समभ्तदार मुसल्मानी के एक बहुत बड़े तबके को कांग्रेस के साथ रखने में सहायता पहुंचाई है। कांग्रेस के साम्यवादी वर्ग में तो मुसल्मानों को एक वड़ी संख्या थी। यूसुफ़ मेहरत्र्यली का नाम इस सम्बन्ध में ख्रानायास ही याद ख्रांजाता है । मैकडोनल्ड के 'सांप्रदा-यिक निर्णय'के प्रांत कांग्रेस के ग्रानिश्चय के रवैये ने जहां एक ग्रोर कुछ हिंदुग्री को असंतुष्ट किया था, वहां उससे कुछ मुसल्मान भी नाराज़ हुए, श्रीर श्रन्सारी, ख़लीक़ुज़्ज़मां त्रादि ने कांग्रेस को छोड़ देने की धमकी भी दी। कांग्रेस में मुसल्मानों को तादाद ज़रूर कम होगई, पर ऋधिकतर मुसल्मान बहुत-सी ऐसी मुस्लिम संस्थात्रों में शामिल होगए, जिनके त्रादर्श कांग्रेस से मिलते-जुलते थे। इनमें पंजाब का ऋहरार 'दल प्रमुख था। इसकी स्थापना १६३० में हुई। '३० श्रीर '३२ के श्रान्दोलनों श्रीर क़ुर्वानियों में श्रहरार पार्टी ने कियात्मक भाग लिया । तब से वह देश की एक प्रमुख संस्था वन गई है । 'राजनैतिक श्रादशों में कांग्रेस से समानता रखते हुए भी सामाजिक विचारों में श्रहरार दल उससे त्रागे वढ़ा हुन्त्रा है। राजनीति में उसका दृष्टिकीण अन्तर्राष्ट्रीय है। १६३६ में जब वर्तमान महायुद्ध का प्रारम्भ हुन्ना, श्रहरारों ने सबसे पहिले साम्राज्यवादी युद्ध होने के नाते उसकी आलोचना की, श्रीर अपने इन विचारों के कारण ऋहरार दल के बहुत से सदस्य जेलों में गए। सीमाप्रांत में इसी प्रकार लान ग्रन्दुल ग़फ्फ़ारलां के नेतृत्व में खुदाई ख़िदमतगारों का संगठन हुन्ना। सदियों से जिन पठानों के हाथ ख़ून से रङ्गे रहे हैं उनके हृदयों में श्रहिंसा का सफल प्रवेश किस प्रकार हो सका, यह इस युग की एक ग्राश्चर्य-घटना है। १६३० के त्रान्दोलन में खुदाई ख़िदमतगारों ने ऋपने ऋहिंसात्मक ऋनुशासन का वड़ा ज्वलन्त परिचय दिया । तव से यह सारा ग्रान्दोलन कांग्रेस के 'संरक्तण में चलता रहा है, परन्तु पठानों तक ही सीमित है, ख्रीर सीधा कांग्रेस के ख्रान्तर्गत नहीं है। ख़ान ग्रब्दुल ग़फ्फ़ारखां के व्यक्तित्व द्वारा ही वह उससे सम्बद्ध है। मुसल्मानों के निम्न-वर्ग, विशेषकर जुलाहों, में भी राष्ट्रीय जीवन के चिह्न दिखाई देने लगे थे। इन लोगों ने 'त्राखिल भारतीय मोमिन कान्फ्रेंस' की स्थापना की। उनका दावा है कि यह संस्था देश के ४॥ करोड़ मुसल्मान कारीगरों का प्रति-ं बत्व करती है। इसके ब्रालावा मुसल्मानों में, शिया पोलिटिकल कान्प्रेंस

त्रादि त्रन्य राजनैतिक दल भी हैं जिनका भुकाव राष्ट्रीयता की त्रोर है। कुछ प्रांतीय प्रवृत्तियां भी समय-समय पर संगठित होती रही हैं। इनमें शेख़ मोहम्मद त्रब्दुल्ला द्वारा संगठित जम्मू त्रौर काश्मीर की मुस्लिम कान्फ्रेंस, वंगाल की कृषक-प्रजा पार्टी, व पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी प्रमुख हैं।

१६३७ को चुनाव प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों पर प्रगतिशील प्रवृत्तियों के प्राधान्य का स्पष्ट प्रतीक था। प्रोफ़्तेसर हुमायूं कबीर के शब्दों में, "हिंदुऋों में जगह-जगह कांग्रेस की जीत हुई, श्रीर पुराने विचारों के समर्थक बड़े-से-बड़े व्यक्ति उसके सामने टिक न सके । मुसल्मानों में भी प्रतिक्रियावादी तत्त्व पीछे भकेल दिये गए, यदापि वे नष्ट नहीं किये जा सके। बंगाल में लीग, जिसे पूंजी-वादी वर्ग का प्रतिनिधित्व प्राप्त था, प्रजा पार्टी के टिकट पर खड़े होने वाले फ़ज़-लुलहक्त के सामने टिक न सकी । पंजाब में कहर सांप्रदायिकता की समर्थक लीग सर सिकंदर के नेतृत्व में हिन्दू ऋौर मुसल्मान नरम राजनीतिशों का जो संग-टन किया गया था उससे दारी । युक्तप्रांत में लीग, कुछ प्रगतिशील तन्त्रों का प्रतिनिधित्व करने के कारण, नवाव छतारी श्रीर उनके प्रतिक्रियावादी समर्थकों पर विजय प्राप्त कर सकी । सीमाप्रांत में कांग्रेस ने लीग को उखाड़ फेंका, श्रौर सिंध में भी वह ऋधिक सफल न हो सकी।"" दूसरे शब्दों में, १६३७ में देश के सामने एक ऐसा अवसर था जब यदि हिंदू ख्रौर मुसल्मान प्रगतिशील शक्तियां मिल जातीं तो वहुत कुछ काम कर सकती थीं। पर १६३७ की इन राज-नैतिक घटनात्रों के पीछे इतिहास की जो प्रवल शिक्तयां काम कर रहीं थीं, उन्हें कौन रोक पाता ? कुछ लोगों का अनुमान है कि चुनाव के वाद ही यदि कांग्रेस सभी प्रांतों में मन्त्रिमएडल बनाने पर तैयार होजाती तो चुनाव से प्राप्त की गई इस शिक्त को संयोजित किया जा सकता था। वंगाल में फ़ज़लुलहक़ कांग्रेस के कियात्मक सहयोग के लिये वेचैन थे, पर जब कांग्रेस ने पद-ग्रहण न करने का निश्चय कर लिया, तो उन्हें मजबूर होकर लीगकी शरण लेनी पड़ी । सर सिकंदर को भी ऐसी ही परिस्थितियों में लीग का सहारा टटोलना पड़ा। लीग को उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में फ़ज़लुलहक़ ऋौर सर सिकंदर का वहुत नड़ा हाथ रहा है। उन प्रांतों में भी, जिनमें कां ग्रेस का नहुमत था, उसकी इस त्र्यनिश्चयात्मक नीति ने प्रतिकियावादी शक्तियों को वल दिया। मुस्लिम-लीग चुनाव के दिनों की करारी हार से ऋव उभरने लगी थी, ऋौर ऋपने संगठन में जुट गई थी। उसे स्राशा थी कि मंत्रिमण्डल वनाने में कांग्रेस उसका सहयोग चाहेगी, पर जब कांग्रेस ने उसकी अवज्ञा की, उसने अपनी सारी शक्ति १-प्रो॰ हुमायृं कवीर : Muslim Politics, 1906-42, ए॰ १४-१४।

मुसल्मानों को उसके ख़िलाफ़ संगठित करने में लगादी। अनुभव की कमी, श्रौर राष्ट्रीयता के शुद्ध-स्वरूप को न पहिचान पाने के कारण कांग्रेस मंत्रियों ने कुछ ग़लितयां भी कीं। मुस्लिम-लीग ने कांग्रेस को वदनाम करने, श्रौर मुसल्मानों को उसके ख़िलाफ़ भड़काने में इन ग़लितयों से पूरा लाम उठाया। इन्हीं दिनों, श्रांतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को लेकर, कांग्रेस श्रौर श्रांग्रेज़ी सरकार के वीच संघर्ष एक व्यापक रूप ले रहा था। कांग्रेस की शिक्त को कुचलने के लिए सरकार के लिए प्रतिक्रियावादी शिक्तयों का समर्थन प्राप्त करना श्रानवार्य होगया। लीग ने इस अवसर से लाम उठाकर श्रपनी स्थिति को मज़बूत बना लिया। इस प्रकार, भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के मार्ग में श्रंग्रेज़ी सरकार श्रौर मुस्लिम सांप्रदायिकता दोनों ने मिलकर एक दुर्में प्रपितिकयावादी मोर्चा स्थिपित कर लिया। श्रगले श्रध्याय में हम इस मोर्च की वारीकियों से श्रवगत होने का प्रयत्न करेंगे।

मुस्लिम लीग श्रीर पाकिस्तान की मांग

इक्बाल का स्वप्न

यह बात साधारण्तया मानी जाती है कि हिन्दुस्तान के बंटवारे का विचार सबसे पहिले डॉक्टर इक्तवाल ने मुस्लिम लीग के १६३० के इलाहाबाद-ऋधिवेशन के सामने रखा था। इस सम्बन्ध में कुछ बातें जान लेना ज़रूरी हैं। डॉक्टर इक्तवाल ने इस भाषण में कहा था कि ऐसा जान पड़ता है कि भारतीय मुसल्मानों का भाग्य उन्हें मुस्लिम उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के एक राजनैतिक संगठन की ऋोर ले जा रहा है। यह कल्पना ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के उनके ऋपने ऋध्ययन का परिणाम थी। इस कल्पना ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के उनके ऋपने ऋध्ययन का परिणाम थी। इस कल्पना के पीछे एक विश्व-व्यापी मुस्लिम-संघ का उनका स्वप्न तो पृष्ठ-भित्ति का काम कर ही रहा था, पर हिन्दुस्तान के राजनैतिक प्रश्नों पर दृष्टि रखते हुए भी इक्तवाल का यह विश्वास हो चला था कि प्रान्तों के पुनः संगठन से हमारी साम्प्रदायिक समस्या का हल प्राप्त हो सकेगा। सांप्रदायिक चुनाव के वह कट्टर विरोधी थे, ऋौर उनका विश्वास था कि यदि प्रांतों का फिर से संगठन किया जाय, ऋौर मुस्लिम-प्रांतों को पूर्ण स्वायत्त-शासन दे दिया जाय तो मुसल्मानों के लिए दूसरी क्रीमों से समभौता कर लेना ऋगसान हो जायगा। इस तरीक़ को साम्प्रदायिक चुनाव पर वह तरजीह देते थे।

इक्तवाल ने अपने भाषण में यह तो विल्कुल ही स्पष्ट कर दिया था कि यह विचार केवल उनकी अपनी 'व्यक्तिगत इच्छा' है 1 वह जानते थे कि जहां तक मुस्लिम-जनता का प्रश्न है, वह निस्संदेह संघ-शासन का समर्थन करेगी। 'व्यक्तिगत-इच्छा' की दृष्टि से भी इक्तवाल देश के वंटवारे का समर्थन नहीं कर रहे थे। वह तो केवल इस सिद्धान्त का विश्लेषण कर रहे थे कि हिन्दुस्तान को आवहवा, वर्ण, भाषा, धर्म और सामाजिक संगठन की विचित्रताओं को देखते हुए यह संभव हो सकता है कि उसके अन्तर्गत भाषा, वर्ण, इतिहास, धर्म और आर्थिक स्वायों की एकता के आधार पर कई ऐसे छोटे राज्यों की स्थापना की जा सके, जो एक वड़ी सीमा तक स्वाधीन हों। इसी सम्बन्ध में उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया था कि मुस्लिम उत्तर-पश्चिमी प्रान्त अखिल-भारतीय संघ-शासन के अन्तर्गत एक राजनैतिक इकाई का रूप ले सकेगा। हम इस वात को मुला नहीं सकते कि डॉक्टर इक्तवाल सारे देश के लिए एक संघ-शासन की स्थापना के पत्त में थे। पर, वह एक 'सच्चा संघ-शासन' चाहते थे, जिसमें वे सब अधिकार जो केन्द्रीय-शासन को सोंपे न गए हों, प्रांतीय सरकारों के हाथ में

रहें, श्रीर केन्द्रीय-शासन केवल उन्हीं श्रधिकारों का प्रयोग कर सके जो प्रान्तीय शासन द्वारा स्पष्टतः उसे दे दिये गए हों। श्रपने इन विचारों में इक्षवाल निस्संदेह अपने समय से बहुत श्रागे बढ़े हुए थे।

कैंत्रिज: पाकिस्तान की जन्मभूमि

यह एक दिलचस्य वात है कि पाकिस्तान का विचार सवसे पहिले कैंब्रिज-यूनीवर्सिटी के मुस्लिम विद्यार्थियों के एक छोटे से दल में उत्पन्न हुन्रा । जनवरी १६३३ में, जब पार्लमेण्ट की एक संयुक्त-कमैटी हिन्दुस्तान के भावी शासन-विधान के संबन्ध में खोजबीन कर रही थी, कैम्त्रिज के चार मुसल्मान विद्यार्थियों ने-जिनके नाम थे, मोहम्मद ग्रस्लम खां, रहमतत्राली, शेख मुहम्मई सादिक श्रीर इनायतुल्लाखां—'श्रव या कभी भी नहीं' के नाम से चार पृष्ठींका एक पैम्फ़-लेट छापा, जिसमें, पहिली बार, हिन्दुस्तान को दो हिस्सों में बांटने का विचार प्रगट किया गया था। दलील यह थी कि हिन्दुस्तान के मुसल्मान ग़ैर-मुसल्मानों से हर तरह से मुख्त लिक्ष हैं। उनका खाना-बीना, पहिनना-श्रीढना, रस्म-रिवाज, शादी के तरीक़े वग़ैरा सब अलहदा हैं, और इन कारणों से वह एक अलग राष्ट्र मान लिए जाने के हक़दार हैं। ऋलग राष्ट्र होने के नाते उनका यह ऋषि-कार होजाता है कि वह अपने एक अलग राज्यका संगठन करें। प्रकृति ने पञ्जाव, कारमीर, सिन्ध ऋौर सीमा-प्रदेश के प्रान्तों को इसके लिए निर्धारित किया है। इन प्रान्तों को मिलाकर यदि एक राज्य का निर्माण किया जाय तो उसकी भौगोलिक सीमा फ्रांस से दुगुनी श्रीर श्रावादी लगभग वरावर होगी। कैम्ब्रिज के इन विद्यार्थियों ने डॉक्टर इक्षवाल से ऋपना मत-भेद स्पष्ट शब्दों में प्रगट किया। उन्होंने कहा कि इक्रवाल की कलाना तो केवल यही थी कि इन प्रान्तों को मिला कर एक राज्य बना दिवा जाय, और वह अखिल-भारतीय संघ-शासन के अन्तर्गत हो । उसके विरुद्ध, यह लोग चाहते थे कि इन प्रान्तों को मिलाकर एक पूर्ण स्वतन्त्र राज्य की स्थापना को जाए, देश के अपन्य भागों से जिसका राजनैतिक सम्बन्ध केवल अन्तर्राष्ट्रीय इंग का हो । यदि देश में संब-शासन की स्थापना हुई तो उसमें हिन्दुन्त्रों की प्रधानता त्र्यनिवार्य है ज्रौर मुसल्मानों को ऐसे संघ में शामिल होना पड़ा तो उनकी हालत ग़ुलामों से भी वदतर होगी। यह विचार काफ़ी दिनों तक केवल कुछ ख़ब्तो-दिमाग़ों की उरज माने जाते रहे। गोलमेज-परिपद् में शामिल होने वाले प्रमुख मुसल्मान प्रतिनिधियों से जब उसके सम्बन्ध में पूछा गया तो एक ने तो बताया कि वह 'कुछ लड्कों की योजना है त्रौर दूसरे ने 'काल्पनिक ग्रौर श्रव्यावहारिक कह कर उसकी ग्रालोचना की। इस पैम्फलेट पर दस्तलत करने वाले चार व्यक्तियों में से एक, रहमतत्र्यली,

ने त्रापने इस प्रचार को पूरे ज़ोर के साथ जारी रखा। जुलाई १६३५ में उन्होंने एक नया पैम्फ़ तेट छापा, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी दलीलों को फिर से दोहराया, श्रौर इस बात पर श्राश्चर्य प्रगट किया कि जबिक बर्मा हिन्दुस्तान से त्र्यलहदा किया जा सका तो पाकिस्तान के एक स्वतन्त्र राज्य वनाये जाने में क्या कठिनाई हो सकती है। १६४०में करांची में 'पाकिस्तान नेशनल मूबमेएट' के तत्त्वा-वधान में की गई एक सभा में उन्होंने एक वयान दिया जो 'इस्लाम की मिल्लत च्यौर भारतीयता का खतरां के नाम से बाद में प्रकाशित किया गया । इस पैम्फ़लेट में उन्होंने वताया कि 'मिल्लत' के सामने जो सबसे वड़ा काम है, वह 'हिन्दुस्तान को तोड़ना त्रौर एशिया का पुनर्निर्माण करना है। उन्होंने भारतीयता की इस्लाम के लिए घातक वताया । ऋौर लिखा कि 'मिल्लत' के वचाव के लिए यह ज़रूरी है कि वह हिन्दुस्तान से अपने सम्बन्ध तोड़ दे। उनका विश्वास था कि हिन्दुस्तान न तो कभी मुसल्मानों की मातृभूमि था, न कभी होगा । इस वीच, रहमतत्राली के त्र्यान्दोलन की सीमाएं उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों से वहुत त्र्यागे वढ़ चुकी थीं। वह एक मुस्लिम राज्य की नहीं, कई मुस्लिम राज्योंकी कल्पना करने लगे थे। उत्तर पश्चिमी प्रान्तों को मिलाकर पाकिस्तान बनाने की जो योजना थी, उस पर तो रहमतस्त्रली पूरा ज़ोर दे ही रहे थे, परन्तु उन्होंने ऋच इस वात का प्रचार करना ऋारम्भ किया कि वंगाल और त्रासाम मिलकर 'वंगे-इस्लाम' का रूप ले लें, हैदरावाद की रियासत 'उसमानित्तान' के रूप में एक स्वतन्त्र राज्य वन न्त्रीर ये तीनों स्वतन्त्र मुहिलम राज्य ऋपना एक संघ कायम कर लें।

डाक्टर लतीफ की योजना

१६३८ई० में उस्मानिया यूनीवर्सिटी के एक भूतपूर्व ग्रध्यापक,डॉक्टर लतीफ, पाकिस्तान के विचार को सस्ती भावप्रवर्णता के च्रेत्र से निकाल कर विद्वत्तापूर्ण विचार-विनिमय के च्रेत्र में ले त्र्याये। १६३८ ई० में उन्होंने 'भारतवर्ष का सांस्कृतिक भावेष्य श्रीर 'भारतवर्ष के विभिन्न सांस्कृतिक प्रदेशों का एक संघ' नाम की दो विद्वतापूर्ण पुस्तिकाएं लिखों। १६३६ ई० में उन्होंने 'भारतवर्ष में मुस्लिम समस्या' नाम की एक पुत्तक में श्रपने इन विचारों को वहे विशद रूप

1-10 मार्च 1884 को जन्दन में एक भाषण में मुस्लिम लीन से श्रंपने 'पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट' का श्रंतर बताते हुए रहमतश्रली ने कहा, "मुस्लिम लीन दो पाकिस्तानी राज्य चाहती है, हम श्राठ चाहते हैं, लीन ३-३॥ करोंड मुसल्मानों को हिन्दुस्तान के श्रन्तर्गत छोड़ देने के लिए तैपार है। हन उनके छः श्रीर राज्य बना लेना चाहते हैं। लीन हिन्दुस्तान को हिन्दू श्रीर मुसल्मान दोनों की सामान्य मातृभूमि मानती है। हम इस विचार ने सहमत नहीं हैं।"

धिकार प्रांत में रखने में ही सर सिकंदर का विश्वास था।

सर सिकंदर ह्यात ख़ां की योजना वड़ी दोपपूर्ण थी। यह समभना कठिन है कि वह किस सिद्धांत के द्याधार पर देश को सात भागों में वांटना चाहते थे। उनकी योजना के पीछे न तो समस्या के सांस्कृतिक पत्त का कोई गहरा ग्रध्ययन था, न द्यार्थिक पत्त की जानकारी। दित्त्ग्ण भारत को वह दो भागों में वांटना चाहते थे। मद्रास-प्रांत, ट्रावन्कोर, मद्रास की देशी रियासतें ग्रौर कुर्ग को एक भाग में रखने का उनका प्रस्ताव था, श्रीर वम्बई प्रांत, हैदरावाद, पश्चिम की देशी रियासतें मिलकर एक दूसरे समूह का निर्माण करने वाली थीं। इस प्रकार वंदवारे में सांस्कृतिक समानता का तिनक भी ध्यान नहीं रखा गया है। एक श्रीर तो हम गुजराती श्रीर मलयालम भाषात्रों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को एक ही समृह में पाते हैं, श्रीर दूसरी श्रीर मराठी, तेलगू श्रीर कन्नड़ भाषा-भाषी विभिन्न समूहों में वांट दिये गए हैं। यह समम्भना भी वड़ा कठिन है कि मध्यप्रांत के देशी राज्यों का मध्यप्रांत से ऋलहदा किया जाना किस वड़े उद्देश्य की पुर्ति के लिए है। राजपुताना के देशी राज्यों को भी कई भागों में बांट देने का प्रस्ताव है। वीकानेर श्रीर जैसलमेर पंजाव वाले समृह में मिला दिये जायंगे। शेष रियासर्ते एक ऐसे श्रस्तव्यस्त समृह में शामिल होंगी जो करधनी के समान देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला होगा, जिसमें ग्वालियर, मध्य-भारत के देशी राज्य, विहार ग्रीर उड़ीसा के देशी राज्य, ग्रीर मध्यप्रांत ग्रीर विहार के सूवे होंगे । सर सिकंदर की योजना श्रास्पष्ट श्रीर कई दोपोंसे पूर्ण है, पर उसका महत्त्व इसमें है कि उसने पहिली वार हिंद्स्तान को कई भागों में बांट देने के विचार को क्रियात्मक राजनीति के चेत्र में ला खड़ा किया। सर सिकंदर की योजना किसी पंडित की अपने अध्ययन-कन्न में तैयार की गई सैद्धांतिक योजना नहीं थी, एक राजनीतिज्ञ का गम्भीरता से पेश किया गया प्रस्ताव था।

मुस्लिम-लीग का निर्णय

यह है पाकिस्तान के विचार के विकसित और पत्तवित होने का एक संज्ञिस हितहास। इस अवसर पर मुस्लिम-लीग ने अचानक इस ज्ञेत्र में प्रवेश किया, और वहें उत्साह के साथ इस विचार को अपना लिया। जब कि पाकिस्तान के सम्बन्ध में दुनियां भर की काल्पनिक योजनायें बनाई जारही थीं, मुस्लिम-लीग उनके सम्बन्ध में विल्कुल तटस्थ थी। १६२८ में, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए लीग ने अपने एक प्रस्ताव में घोषित किया कि "भारतीय परिस्थितियों में केयल एक ही दंग की शासन-व्यवस्था उपयुक्त हो सकती है, और वह है संध-शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतों में पूर्ण स्वायत्त-शासन हो, व उस

शासन को वे सब ऋधिकार प्राप्त हों जो उसने स्वष्टतः केन्द्रीय शासन को सींपः न दिये हों।" इक्कबाल की कल्पना का 'सच्चा संघ-शासन' भी यही था। जव १६३५ का एक्ट पास हुन्रा, जिसमें स्वायत्त-शासन के सिद्धांत के त्राधार पर प्रांतों का संगठन किये जाने व उनके एक केन्द्रीय-शासन से संबद्ध-संश्लिप्ट कर दिये जाने की योजना थी, तो लीग ने उसे, 'उसका जो भी उपयोग हो सके कर लेना चाहिए' की नीति को दृष्टि में रखते हुए, प्रयोग में लाना स्वीकार किया—यद्यपि उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि "उसमें बहुत सी ऐसी वातें भी हैं जो एतराज़ के क़ाविल हैं, स्रोर जो शासन स्रोर व्यवस्था के सारे चेत्र पर वास्तविक नियंत्रण श्रौर मंत्रियों श्रौर धारासभा द्वारा सच्चे उत्तरदायित्व के निर्वाह को असम्भव वना सकती हैं।" १६३६ में चुनाव के अवसर पर, मुस्लिम-लीग ने ऋपने उद्देश्यों के सम्बंध में जो घोषणा की थी, उससे भी उसकी नीति पर प्रकाश पड़ता है। लीग ने ऋपने उन प्रतिनिधियों के सामने, जो धारा-सभा में जाकर काम करने वालें थे, दो उद्देश्य रखे थे—एक तो यह कि मौजूरा प्रांतीय शासन ऋौर प्रस्तावित केन्द्रीय शासन दोनों को हटाकर उनके स्थान पर 'प्रजातंत्रात्मक स्वराज्य' की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जाय, स्रौर दूसरे, जहां तक वर्त्तमान धारा-सभात्रों का सम्बंध है, "राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न त्रेंत्रों में जनता के लाभ के लिए उनका ऋधिक से ऋधिक उपयोग किया जा सके।" इस प्रगतिशील घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि "जब तक सांप्रदायिक चुनाव हैं, मुस्लिंम-लीग को अपनी अलग स्थिति तो खना है ही, पर वह किसी भी ऐसे दल के साथ जिसके उद्देश्य और स्रादर्श लगभग वही हैं, जो लीग-पार्टी के, पूरे सहयोग की भावना में काम करेगी।" इस घोषणा-पत्र में हम कोई वाल ऐसी नहीं पाते जिसे सांप्रदायिक, प्रतिक्रियावादी ग्रथवा संकृचित कह सकें। प्रगतिशीलता उसमें कूट-कूट कर भरी है। वह हमें एक सोनहले भविष्य का विश्वास दिलाता है, जिसमें देश की समस्त प्रगतिशील शक्तियां मिल-जुल कर काम करेंगी। पं० नेहरू ने कांग्रेस की स्रोर से भी यही स्राश्वासन दिया-"कांग्रेस धारासभात्रों में एक निश्चित कार्यक्रम ग्रौर एक निश्चित नीति के साथ प्रवेश कर रही है। वह धारासभात्रों में, वहुमत में हो या त्राल्यमत में; **ऋपने इस कार्यक्रम ऋौर नीति को ऋागे वढ़ाने में दूसरे दलों** के साथ वड़ी खुशी के साथ सहयोग करेगी।"

पर, स्यांस्त के रङ्गीन वादलों की तरह, त्राशा त्रौर विश्वास की यह कल्पना त्र्राधिक दिनों नहीं टिक सकी । कांग्रेस के मंत्रिमरडल बना लेने के दाद ते ही सारा दृश्य यदल चला । मि॰ जिन्ना ने घोषणा की कि "कांग्रेसी शासन ने लोगों को काफ़ी सप्रमाण दिखाई दिया, तो इसमें भी क्या छाश्चर्य था ? कांग्रेसी मंत्रिमएडलों के इस्तीफ़ा देने के बाद मुस्लिम-लीग का महत्व अचानक, ग्रोर तेज़ी से, वढ़ त्वला था—यह ग्रंग्रेज़ी सरकार की नई नीति का परिणाम था। कांग्रेसी मंत्रिमएडलों के इस्तीफ़ा दे देने से पहिले तो ग्रंग्रेज़ी शासन को ग्राश्चर्य ग्रीर कुछ दुःख हुग्रा। कुछ दिनों तक उसे ग्राशा रही कि कांग्रेस ग्रपना रवैया वदल देगी। तब उन्होंने मुस्लिम-लीग ग्रीर दूसरी सांप्रदायिक संस्थाग्रों की ग्रोर सहयोग का हाथ बढ़ाया। सरकारी प्रचार की दिशा फ़ौरन बदल दी गई। कांग्रेस को बदनाम किया जाने लगा। यह कहा जाने लगा कि वह ग्रल्प-संख्यक जातियों के विकास के मार्ग में वाधक है—यहां हम यह न भूलें कि जब तक कांग्रेस ने पद न छोड़े थे कभी किसी गवर्नर ने उस पर सांप्र-दायिकता का दोप नहीं लगाया था ग्रीर कांग्रेस के इस्तीफ़ा दे देने के बाद भी कई गवर्नरों ने कांग्रेसी मंत्रिमएडलों के ग्रासांप्रदायिक होने का समर्थन किया था, परन्तु ग्रव क्योंकि ग्रंग्रेज़ी नीति में परिवर्तन हो जुका था, लीग ग्राचानक भारतीय मसल्मानों की एक मात्र प्रतिनिधि बन गई थी!

पाकिस्तान का मनोविज्ञान

मि॰ जिन्ना के सामने यह एक ग्रामृतपूर्व ग्रावसंर था, ग्रीर उन्होंने उससे पूरा लाभ उठाया। वह श्रंग्रेज़ी शासन के दृष्टिकीण से श्रपना महत्त्व समभ गए थे, और उसे ऋधिक से ऋधिक वढा लेने का कोई ऋवसर छोड़ना नहीं चाहते थे। लीग के लाहीर-श्रिधवेशन में उन्होंने कहा भी--- "श्राप लोग यह न भूलें कि युद्ध की घोषणा के अवसर तक वायसराय गांधी, श्रीर केवल गांधी, की वात ही करते थे।" अव मि० जिन्ना का मौक्ता आया था! उन्होंने अपने आपको अंग्रेज़ी नीति का साधन वन जाने दिया-क्योंकि इससे उनके श्रपने सांप्रदायिक स्वाथों की पुष्टि होती थी। उन्होंने ग्रव ग्रंग्रेज़ी शासन पर ज़ोर डाला कि वह स्वष्ट रूप से इस वात की घोषणा कर दे कि वह किसी ऐसे विधान को स्वीकृत नहीं करेगा जिसके लिए मुस्लिम भारत की स्वीकृति पहिले से प्राप्त न कर लो गई हो । श्रंभेजो सरकार ने उनकी यह बात फ़ौरन मान ली। १६४० की अगस्त-घोपणा में यह वात अस्पष्ट रूप से मान ली गई कि विधान में किसी भी प्रकार का स्थायी: अथवा अस्थायी परिवर्तन, विना मुस्लिम-लीग के समर्थन ऋौर स्वीकृति के नहीं किया जायंगा । ऋंग्रेजी सरकार के लिए तो यह एक ग्रच्छा ग्रवसर था। विदेशों में जनमत तेज़ी से भारतीय स्वाधीनता के पद्म में होता जा रहा था—उसे इस भुलावे में रखा जा सकता था कि ग्रंग्रेज यदि भारतवर्ष को स्वाधीनता नहीं दे रहे हैं तो

इसका कारण यही है कि भारतीय मुसल्मान एक-राय से उसका विरोध कर रहे हैं। भारत-मंत्री एमेरी यह कहते हुए थकते न थे कि अंग्रेज़ी सरकार भारतीयों को शासनाधिकार सौंप देने के लिए बेचैन है, पर सवाल यह है कि उसे सौंप किसके हाथों में। भारतीय राजनैतिक दलों में जहां एका हुआ, वह फ़ौरन भारतीयों के हाथ में शासन के सब अधिकार दे देंगे। जिन्ना साहिव के लिए मुस्लिम-लीग की ताक़त को बढ़ा लेने का यह बड़ा अच्छा मौक्रा था। अंग्रेज़ी सरकार और जिन्ना दोनों अपनी-अपनी स्थिति को मज़बूत बनाने की दृष्टि से एक मैत्री के स्त्र में बंध गए। यह सममौता कांग्रेस के ख़िलाफ़ था। उसके पीछे केवल कूटनीतिज्ञता थी, विश्वास अथवा सिद्धांतों की सामान्यता न थी। यह तो वैसा ही सममौता था जैसा कुछ महीनों पहिले नात्सी जर्मनी और सोवियट रूस में हुआ था। जर्मनी और रूस के सममौते के समान इस समभौते से भी अंग्रेज़ी सरकार और लीग दोनों की स्थित अधिक दृढ़ हो सकी।

भारतीय राजनीति की इस पृष्ठभूमि पर पाकिस्तान के प्रस्ताव को रख कर ही हम उसके वास्तविक महत्त्व को समभ सकते हैं। हमें यह वात भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का प्रस्ताव कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के पद-त्याग के चार महीने वाद-एक ऐसे समय जब श्रंग्रेज़ी सरकार को कांग्रेस के ख़िलाफ़ सभी राजनैतिक तत्त्वों को सशक्त बनाने की नीति स्वीकार करने पर विवश होना पड़ा था-हमारे सामने श्राया । यह कहना ठीक न होगा कि जिन्ना साहिव श्रंग्रेज़ी शासन के हाथ में कठपुतली का काम कर रहे थे—सच तो यह है कि वह श्रंग्रेज़ों की कमज़ोरी का पूरा लाभ उठाने में लगे हुए थे। वह जर्मनी के फ़यूरर से भी अधिक तेज़ी के साथ अपने हाथों में शक्ति संग्रहीत कर रहे थे। ग़ैर-कांग्रेसी सवों में उनकी धाक ऐसी थी जैसी किसी ज़माने में शायद मुग़ल-सम्राट की भी न रही हो । मंत्रिमण्डलों का निर्माण श्रीर पतन उनके इशारे पर निर्मर रहता था । पंजाय त्र्यौर वंगाल के सुरिलम-प्रांत भक्ति, बल्कि भय से, जिन्ना साहय की त्राज्ञात्रों का पालन कर रहे थे। वायसराय की रत्ता-समिति(Defence Council)से वह वहें से वहें मुसल्मान नेतात्रों को अलहदा रखने में सफल हुए-श्रीर जिन्होंने त्रासानी से उनका कहना नहीं माना उन्हें लीग से निकाल बाहर करने की उन्होंने धमकी दी। मध्य-कालीन युद्धों में जिस प्रकार सिपाहियों के जोश को ताजा रखने के लिए मारू वाजे वजते रहते थे, वैसे भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि पर मुस्लिम-लीग व उसके प्रमुख नेतान्त्रों द्वारा पाकिस्तान की मांग वरावर दोहराई जाती रही—श्रौर कांग्रेस के ख़िलाफ़ लड़ाई श्रपने पूरे ज़ोर में चलती रही। अप्रैल १६४१ में लीग ने मद्रास अधिवेशन में अपनी

इस मांग को फिर से दोहराया, श्रौर लाहौर-प्रस्ताव के चेंत्र की श्रौर भी विस्तीर्ण बना लिया।

मुस्लिम-लीग की शिक्त दिन व दिन वढती जा रही थी। दिसम्बर १६४१ में लीग की वर्किङ्ग-कमैटी ने अपने नागपुर-अधिवेशन में इस वात पर अपना 'गहरा ग्रसन्तोष ग्रोंर विरोध' प्रकट किया कि 'ग्रांग्रेज़ी ग्राखवारों ग्रीर राज-नीतिज्ञों में कांग्रेस की संतप्ट करने की नीति पर अधिकाधिक ज़ीर दिया जा रहा है,' ग्रीर घोषित किया कि ''यदि 🗕 ग्रगस्त १६४० की नीति ग्रीर गम्भीर घीपणा में ग्रयवा मसल्मानों के साथ किए गए वायदों में किसी प्रकार का ग्रांतर पड़ा तो हिन्दुस्तान के मुसलमान उसे ग्रापने प्रति एक वड़े विश्वास-घात के रूप में देखेंगे, ग्रथवा यदि नीति में कोई ऐसा परिवर्त्तन हुन्ना या कोई ऐसी नई घोपणा हुई जिससे पाकिस्तान की मांग पर बुरा श्रसर पड़ा श्रथवा जिसके परि-गाम-स्वरूप एक ऐसी केन्द्रीय-सरकार का संगठन हुन्ना जिसमें हिन्दुस्तान की एक इकाई माना गया और मुसल्मानों को अल्प-संख्या में डाल दिया गया, तो मुसल्मानों को इससे वड़ा च्लोभ पहुंचेगा ह्यौर वे ऋपनी समस्त शक्ति लगाकर इसका ऐसा ज़ोरदार विरोध करेंगे जिसका प्रभाव, इस नाज़क स्थिति में देश के युद्ध-प्रयत्तों पर, वहुत बुंरा पड़ना ऋवश्यम्भावी है.....।" कांग्रेस भी ऋपनी धम-कियों में कभी इतनी दूर तक न गई थी ! इसके वाद, अंग्रेज़ी सरकार की श्रोर से, किप्स प्रस्ताव के रूप में, जो नई वैधानिक योजना रखी गई उसमें देश को दो भागों में बांट देने की मुस्लिम-मांग का जितना अधिक समर्थन किया जा सकता था, मौजद था।

श्रगस्त १६४२ में, नेताश्रों की गिरफ्तारी के बाद, देश भर में विद्रोह श्रीर विद्योम की जो श्रांधी उठी, मि॰ जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम-लीग उस समय भी श्रपनी नीति को श्रांडग रख सकी—राष्ट्रीयता का यह श्रभृतपूर्व उत्कर्ष मुस्लिम-लीग का स्पर्श न कर सका। किसी भी परिस्थिति में, श्रीर किसी भी नैतिक कीमत पर, श्रपनी पार्टी को सशक्त बनाने (real-politik) की जिस पश्चिमी नीति को मि॰ जिन्ना ने श्रपनाया था, कान्ति के उन सुलगते हुए दिनों में भो वह उसे छोड़ने के लिए तैयार न हुए। जिन्ना साहिब ने घोषणा की कि "कांग्रेस का निश्चय"—उनका इशारा श्रगस्त प्रस्ताव की श्रोर था— "न केवल श्रंग्रेज़ी सल्तनत के खिलाफ बग़ावत की घोषणा है, यह एक ग्रह-युद्ध की खुली चुनौती भी है, श्रीर यह श्रान्दोलन चलाया ही इसलिए गया है कि श्रंग्रेज़ी सरकार को कांग्रेस की मांग स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया जाय, श्रीर हमारा विश्वास है कि कांग्रेस की मांग हमारी मांगों के प्रतिकृल

है।" उन्होंने भारतीय मुसल्मानों को ज्ञान्दोलन से अलहदा रहने की सलाह दी—यद्यपि उस ज्ञान्दोलन के पीछे भारत की संपूर्ण जनता के लिए शक्ति प्राप्त करने की ज्ञाकांन्ता थी, साम्प्रदायिकता का उसमें अंश भी नहीं था, ज्ञौर मुस्लिम-हितों का उससे कोई विरोध नहीं होता था। मैं यह जानता हूं कि उन संकामक घड़ियों में देश में अनेकानेक मुसल्मान ऐसे थे जो क्रान्ति की उन ख़तरनाक लहरों से खिलवाड़ करने के लिए वेचैन थे जो देश को ज्ञपने प्रवल ग्राधातों से हिला रही थीं। पर इसे मि० जिन्ना ग्रौर मुस्लिम-लीग का उन पर प्रभाव ही मानिए कि उनके ग्रादेश पर इनमें से अधिकांश ने अपने को उस समय की राजनैतिक घटनात्रों से अलहदा रखा। पर, यह शक्ति ग्रौर प्रभाव किन साधनों द्वारा, किन परिस्थियों में, मि० जिन्ना ग्रौर उनकी लीग ने प्रक्ष किया था, यह वहत कम लोग जानते थे।

त्र्यगस्त १६४२ के वाद तो यह दशा हुई कि एक त्र्योर तो .सरकार का दमन-चक अपने प्रे वेग से राष्ट्रीयता पर प्रहार कर रहा था और उसके आधातों से कांग्रेस की मशीनरी टूटती जा रही थी, ख्रीर दूसरी ख्रीर मुस्लिम-लीग अपनी शक्ति बढ़ाने के एकाकी-प्रयत्न में दत्तिन तथी। 'ग्रान्दोलन' के प्रारम्भ होने के एक हफ्ते वाद ही लीग की वर्किङ्ग-कमेटी ने ऋंग्रेज़ी-सरकार से मांग की कि वह मुसल्मानों को इस वात का ग्राश्वासन दे कि उन्हें ग्रात्म-निर्णय का पूरा त्राधिकार होगा, त्रीर यदि मुसल्मानी का वहुमत पाकिस्तान के पच में हुन्ना तो वह उसे मान लेगी। मुस्लिम-लीग ने यह प्रस्ताव भी रखा कि वह दूसरे ऐसे दलों के साथ जो सहयोग के लिए तैयार हों, एक ऐसी ग्रास्थायी सरकार वनाने के लिए भी तैयार है, जो देश की समस्त शक्तियों का उपयोग उसके बनाव, ग्रीर युद्ध के सफल संनालन, के लिए कर मके -पर शर्ज यह होगी कि मुसल्मानों की मांग पूरी कर दी जानी चाहिए। मुस्लिम-लीग की नीति में यह एक नया परिवर्त्तन था-श्रव वह कांग्रेस के राजनैतिक च्लेत्र से हट जाने से जो परिस्थिति पैदा होगई थी. उसका पूरा लाभ उठाना चाहती थी। भ्रव तक तो जिला साहिव की दलील यह थी कि जब तक पाकिस्तान की मांग स्वीकार न कर ली जाए, विधान में, स्थायी अथवा अस्थायी, किसी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं किया जाना चाहिए, पर, श्रव उन्होंने यह मांग पेश की कि सम-भौता हो या न हो, मुसल्मानों को शासन के अधिकारों से केवल इसलिए वंचित नहीं रखना चाहिए कि कांग्रेस जेल में है। मुस्लिम वहमत वाले प्रांती में तो मुस्लिम-लीग ने अपने मंत्रि-मण्डल वना ही लिए थे। निध में, खान वहादुर श्रात्तावख्श को विना किसी कारण के हटा दिया गया, श्रीर मुस्लिम-

लीग का मंत्रिमण्डल कायम कर दिया गया। वंगाल में फ़ज़ल्लहक से जनर्दस्ती त्याग-पत्र पर दस्तख़त कराए गए, श्रीर सर नज़ीमुद्दीन, जिन्ना श्रीर वंगाल गवर्नर के संयुक्त ग्राशीर्वादों के साथ, प्रधान-मंत्री की गदी पर बैठें। जिन्ना साहित ने पंजाब में भी यूनियनिस्ट-पार्टी के प्रभाव को कम करने, व सर सिकंदर ह्यातलां को लीग के ऋधिक कड़े अनुशासन में लाने, की चेष्टा की। सर सिकंदर मंजे हुए खिलाड़ी थे - परन्तु फिर भी पंजाब में मुस्लिम जनता पर श्रपने प्रभाव को मि॰ जिन्ना ने बहुत बढ़ा जिया। सर सिकंदर की श्रसामयिक मृत्यु,ग्रौर ख़िज़र हयात ख़ां विवाना के नेतृत्व में एक नए मंत्रिमण्डल के निर्माणे, से मि॰ जिन्ना को पंजाब में त्रापनी शक्ति बढ़ाने का फिर एक त्रावसर मिला। मि॰ जिन्ना इन दिनों शिक्त स्त्रीर प्रतिष्ठा के ऊंचे स्त्राकाश में थे, स्त्रीर उनकी शिक्त ज्यों-ज्यों बढ़ती जारही थी, मुस्लिम-लीग की जड़ें गहरी ग्रीर मज़बूत वनती जारहीं थीं-परन्तु, ग्रंग्रेज़ ग्राधिकारी इस स्थिति से ग्रव कुछ चिन्तित ही चले थे। एडगर स्नो ने ग्रापनी नई पुस्तक('Glory & Bondage', 1945) में लिखा है कि अप्रैल १६४३ में जब वह अपने ६ महीने के रूस के प्रवास से लौटे, 'मुस्लिम लीग के मुग़ल-सम्राट कायदे आज़म' अपनी शक्ति के शिग्वर पर थे। वायसराय के एक ब्राफ़सर ने उनसे कहा, "जिन्ना इस समय देश की सबसे ऋच्छी मख़मली घास पर वैठे हैं। सारा चोत्र उनके हाथ में है। गांधी को जिंदने ज़्यादा दिन जेल में ख्वा जायगा, जिन्ना की मौज है। लेकिन ऋव हम चिन्तित हो चले हैं। पाकिस्तान वर्फ़ की खुढ़कती हुई गेंद की तरह तेज़ी से बढता जारहा है। वह समय शायद दूर नहीं है, जब उसे रोकना ग्रसम्भव होजाय।''

इन परिस्थितियों में यह स्वामाविक ही था कि मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान के पीछे एक धार्मिक कट्टरता का वातावरण वन जाता । विभिन्न विचार-धाराख्रों के मानने वाले मुसल्मानों में से हर एक को उसमें ख्रपने ख्रादशों की पूर्ति होती दिखाई दी । मुस्लिम राजनीतिशों को उसमें राजनैतिक सौदों का एक वड़ा ख्रच्छा ख्राधार मिल गया था । धार्मिक वृत्ति वाले व्यक्तियों ने कल्पना की कि पाकिस्तान के रूप में पृथ्वी पर एक ऐसे स्वर्गीय राज्य की स्थापना होने जा रही है जहां इस्लाम-धर्म के उच्चतम ख्रादशें जीवन के दैनिक व्यवहार की चीज़ वन जायंगे । इन पंक्तियों के लेखक को उन दिनों ख्रहमदिया-ख्रादोलन के एक प्रमुख नेता से वात करने का ख्रवसर मिला, जो पाकिस्तान का समर्थन ख्रुद धार्मिक ख्राधार पर कर रहे थे । मुस्लिम साम्यवादियों को उसमें एक साम्यवादी राज्य की भलक दिखाई दी । युवकों को संघर्ष के लिए एक राजनैतिक नारा

मिल गया था। जनता की ब्रात्मा एक नए उत्साह से उद्देलित हो उठी—
उसने शिंक का एक नया विस्तार, ब्रौर भविष्य के सपनों का एक व्यापक
ब्राधार पा लिया था। ऐसे सनसनीख़ेज़ वातावरण में, जब विवेक सोयां हुब्रा
था ब्रौर भावुकता ब्रपने रङ्गीन पंखों को फैलाकर कल्पना के व्यापक ब्राकाश में
उड़ चली थी, पाकिस्तान के विचार ने मूर्च-रूप लिया। एक ब्रानवरत प्रचार
के द्वारा, जिसे एक विदेशी सरकार का समर्थन प्राप्त था, इस विचार ने विश्वास
का रूप लिया, विश्वास ने धर्म का जामा पिंहना, धर्म कट्टरता की शक्त में
परिवर्तित होगया। परिस्थितियों की कटोर वास्तविकता से भाग निकलने का
यह एक ब्राक्ष्यंक मार्ग था, परन्तु भावनात्रों के त्फ़ानी प्रवाह में उसके
समर्थक यह न जान सके कि इस मार्ग का ब्रान्त होता था विदेष, ब्रविवेक ब्रौर
ब्रात्महत्या की एक ब्रथेरी गुफ़ा में।

. પ્ર:

श्रंग्रेज़ी शासन श्रौर हमारी वैधानिक प्रगतिः

भारत और अंग्रेज

ं भारत में ऋंग्रेज़ी शासन की स्थापना के सम्बन्ध में कई भ्रांतिपूर्ण धारणायें फैली हुई हैं। इनमें से एक यह भी है कि यह एक ब्राकिसक ब्रीर दैवी घट-नां थी। श्रंग्रेज़ों के सामने इस देश में श्रपने साम्राज्य का निर्माण कर लैने का कोई लच्य नहीं था। यह सच है कि अंग्रेज केवल व्यापार के लिए ही ग्राए थे, पर जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की राजनैतिक रिथित से लाभ उठाया जा सकता है तो उन्होंने व्यापार को गौण श्रौर साम्राज्य-निर्माण को श्रपना प्रधान लच्य बनाया; श्रीर श्रपने इस लच्य की प्राप्ति में श्रच्छे-बुरे कैसे भी साधनों को उठा न रखा । सशक्त ऐतिहासिक प्रवृत्तियां उनके इस काम के पीछे थी, जिनमें इंगलैंड की श्रीद्योगिक क्रांति मुख्य थी। जन तक मुग़ल-साम्राज्य ग्रपनी शक्ति के शिखर पर रहा, श्रंग्रेज व्यापारियों को ऋपने वाणिज्य-व्यापार के चेत्र के बाहर दृष्टि डालने का साहस न पड़ा, पर उसके पतन के बाद हमारी राजनैतिक स्थिति में जो ग्रस्थायित्व ग्राया उसका उन्होंने पूरा लाभ उठाया। ऋपने योरोपियन प्रतिद्वंदियों, पुर्तगीज़, डच, ऋौर विशेपकर फ्रांसीसियों, से निवटने में ही उन्हें काफ़ी समय लग गया। इस वीच मराठे दिच्ण में निज़ाम व उत्तर में राजपूतों को पीछे, हटाकर उस समय के भारतीय राज्यों में सबसे प्रमुख स्थान ले चुके थे---ग्रीर एक ग्रीर सिखों व दूसरी ग्रीर श्रवध श्रीर वंगाल के नवावों पर श्राक्रमण कर रहे थे। इसी वीच जब मराठे उत्तरी भारत की राजनीति में श्रापने की खोए हुए थे, दूर-दिज्ञ्ण में हैदरश्रली ने एक शिक्तशाली राज्य की नींव डाली। १७६१ ई० से १७७२ ई० तक पेशवा माधवराव प्रथम के समय में सराठे पानीपत की हार से उभरने की चेष्टा में लगे रहे-श्रंग्रेज़ों ने इसका उपयोग बंगाल में अपनी शक्ति की स्था-पना में किया। मराठों त्रीर मैसूर के मतभेद का भी अंभे ज़ों ने पूरा लाभ उठाया-ग्रीर मराठों के साथ मिलकर मैसूर को समाप्त कर दिया। परन्तु, मैसूर के पतन के वाद मराठों ने देखा कि उन्होंने स्वयं ही अपने और अंग्रेज़ों के वीच की दीवार को दहा दिया है, श्रीर तव उन्हें एक लम्बे समय तक श्रंगेज़ों के साथ जीवन त्रौर मरण के संग्राम में जूफो रहना पड़ा । प्रथम-मराठा-

युद्धं (१७७६-८३ ई०) का अन्त स्पष्ट मराठा विजय में हुआ । कुछ अंग्रेज़ राजनीतिश तो यह भी सोचने लगे गे कि वे मराठों के साथ मिलकर हिंदुस्तान को दो दुकड़ों में वांट लें, पर तभी मराठा-साम्राज्य का पतन एक अभृतपूर्व तेज़ी से शुरू होगया, और १८१८ में उनकी शिंक का विल्कुल अन्त होगया। मराठा-साम्राज्य के पतन के वाद अंग्रेज़ी-साम्राज्य के विस्तार का मार्ग अधिक सुगम होगया।

हिंदुस्तान में ऋंग्रेज़ी सल्तनत के फैल जाने के बारे में एक दूसरी ग़लत धारणा यह है कि उसे हिंदुस्तानियों को स्रोर से किसी वड़े मुक्ताविले का सामना नहीं करना पड़ा । मैं यह मानता हूँ कि वह मुक्काविला संगठित नही था, उसके पीछे राष्ट्रीयता जैसी किसी प्रज्वलनशील विचार-धारा का वल भी नहीं था, पर हिंदुस्तानियों ने किसी भी जगह त्रासानी से घुटने देक दिए हों, यह वात नहीं थीं। भारतीयों की स्रोर से स्रंग्रेज साम्राज्य-वादियों को एक वड़े विरोध का सामना करना पड़ा इसका प्रमाग तो इसी तथ्य से मिल जाता है कि उन्हें ऋपने काम में - पलासी से सत्तावन के विद्रोह तक- एक शताब्दी से ऋधिक का समय लग गया । हर ऋदम पर उन्हें एक कड़े मुक्काविले का सामना करना पड़ा । वंगाल में ही उन्हें काफ़ी समय जग गया, मराठों के साथ संघर्ष त्राधी शताब्दी के लगभग चला, श्रीर श्रन्त में सिखों को श्रपने श्राधिपत्य में लेते-लेते उन्हें बीस वर्ष के क़रीब लग गए । देश भर में उनका साम्राज्य स्थापित होते ही त्र्यसंतोष की एक देश-न्यापी लहर सत्तावन के विद्रोह में रूप में उठी ! भारतीय विरोध को सफलता क्यों नही मिली, श्रीर कैसे मुद्दी भर श्रंगेज़ इतने वड़े देश पर ऋपना शासन स्थापित कर सके. ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर इतिहास के पृष्ठों में टटोलना होगा, इस स्थान पर उनका विश्लेपण श्रनुपयुक्त ही होगा।

त्रंग्रेज़ी-राज्य के भारत में स्थापित होने के सम्बन्ध में एक तीसरी यात जो वारवार दोहराई जाती है यह है कि अंग्रेज़ों के भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के पहिले हमारा अपना शासन-तंत्र, और हमारी अपनी राज्य-व्यवस्था, दिल्कुल टूट चुके थे, देश भर में अशान्ति और अराजकता फैले हुए थे, और इस अशान्ति और अराजकता से अंग्रेज़ों ने आकर हमें मुक्त किया, और वहीं उदारता से, हमारे लिए एक नये शासन-तंत्र की नींव डाली ! इस सम्बन्ध में हमें यह बात हर्गिज़ नहीं भूलना चाहिये कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के दाद देश में जो राजनैतिक टूट-फूट हुई थी उसके ध्वंसावशेषों पर एक नई राजनैतिक-व्यवस्था के निर्माण का कार्य भारतीय नेतृत्व में बहुत पहिले से प्रारम्भ हो चुका था ! अटारहवीं शताब्दी भारतीय इतिहास का वैसा अध्वारम्भ युग नहीं है, जिला

साधारणतः माना जाता है। वह सिराजुदौला, हैदरत्र्यली श्रीर टीपू, पेशवा माधवराव, महादर्जी सिन्धिया, नाना फड़नवीस, ग्राहिल्यावाई होल्कर ग्रीर कई त्र्यन्य प्रमुख सेनानायकों त्रीर राजनीतिज्ञों की शताब्दी है। इन भारतीय नेतात्र्यों ने, ग्रंगेजों से बहुत पहिले, भारतीय एकता की दिशा में निर्माण-कार्य श्रारम्भ कर दिया था। यह सच्च है कि इनके सामने कार्य की रूप-रेखा बहुत स्पष्ट न थीं, श्रीर इन लोगों के लच्य प्रायः एक-दूसरे से टकरा भी जाते थे। पर श्रंग्रेज़ी साम्राज्य की स्थापना के पहिले ही मराठे श्राखिल-भारतीयता की भावना को एक काफ़ी विकसित रूप दे चुके थे। उनके अंग्रेज़ों से उलके रहने के कारण हैदरग्रली को सशक्त होने का मौका मिल गया। यदि श्रंग्रेज वीच में न स्राजाते तो मुभे पूरा विश्वास है कि मराठे टीपू की शक्ति का स्नन्त कर देते श्रीर वे निःसन्देह देश के एकमात्र शासक होते । मराठा राज्य के पतन के वाद जिस ग्रंग्रेज़ी राज्य की स्थापना इस देश में हुई न तो उसके शासन-तंत्र में ही कछ नवीनता, थी ख्रौर न उसकी व्यवस्था पर पश्चिम की प्रगतिशील विचार धाराख्रों का कुछ प्रभाव था। वह तो तीसरे दर्ज के ख्रंग्रेज़ी शासकों के हाथ में एक निम्नकोटि की तानाशाही थी। कोई भी हिंदस्तानी शासन-व्यवस्था उससे कहीं ग्रधिक अगतिशील होती।

एक वात ग्रीर, ग्रीर तब हम ग्रापने वर्तमान बैधानिक विकास के सूत्रों की पकड़ सकेंगे। ग्राम तौर से यह भी माना जाता है कि जब ग्रंगेज़ों ने इस देश की राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू की वह सांस्कृतिक पतन के निम्नस्तर तक जा पहुँचा था। भारतीय संस्कृति ग्रापने जीवन की ग्रान्तिम सिसिकियां ले रही थी, या वह सप्राण ग्रीर सतेज थी, इसका ग्रान्दाज़ा तो इसीसे लगाया जा सकता है कि राजनैतिक चेत्र में पुनर्निर्माण के ग्रारम्भ होने के बहुत पहिले ही सांस्कृतिक चेत्र में एक नवजीवन की चेतना का संचार होने लगा था। वंगाल में ग्रंगेज़ी राज्य की स्थापना की ग्रागली पीढ़ी में ही वंगाली तरुणों के ग्रंगेज़ी भाषा ग्रीर साहित्य, कला ग्रीर विकान के संपर्क में ग्राने की उत्सुकता के प्रमाण मिलते हैं। भारतीय नवयुग (Renascence)का स्त्रपात उन्हीं दिनों हुग्रा। जब कई मिशनरियों व जन सेवा की भावना से प्रेरित ग्रान्य बोरो-पियन सज्जनों ने कलकत्ता नगर में कई स्थानों पर, ग्रीर श्रीरामपुर ग्रीर ग्रास

१—देखिए इंडियन-हिस्ट्री-कांग्रेस के १६३८ के इलाहाबाद-श्रिधवेशन में पढ़ा गया मेराप्रवन्ध : An Early Chapter in the History of Indian Renascence — Proceedings of the Indian History Congress, 1938.

पास के कई गांचों में ग्रंग्रेज़ी स्कूल ग्रौर छात्रावास खोले तो भारतीय विद्याधियों ने एक बहुत बड़ी संख्या में वहां ग्राना शुरू कर दिया। १८०१ में कलकत्ते में लॉर्ड वेलेज़ली ने कंपनी के नौकरों के लिए फ़ोर्ट-विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह कॉलेज शीघ ही पूर्व ग्रौर पश्चिम की विद्वत्ता ग्रौर संस्कृतियों के लिए एक संपर्क-स्थल वन गया, ग्रौर इसी सिम्मलन ग्रौर पार-स्परिक प्रभाव की नींव पर ग्राज की भारतीय सभ्यता का विशाल भवन गवड़ा है। १८१८ ई० में, जब ग्रंग्रेज़ भारत के सार्वभौम शासक वने भी नहीं थे, राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड ग्रम्हर्स्ट को ग्रपना वह ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि हिंदुस्तान में यदि शिक्ता का प्रसार करना हो तो वह पश्चिमी साहित्य ग्रौर विज्ञान की शिक्ता होनी चाहिए। सच तो यह है कि हमारे देश में प्राचीन की ग्रन्त्येष्टि के पहिले ही नवीन के निर्माण का शंखनाद उद्घोषित हो उठा था। कमी-कभी तो विनम्रता को ताक पर उठा कर रख देने ग्रौर चींख़ उठने को जी चाहता है—है संसार का कोई दूसरा राष्ट्र जिसने ग्रथः पतन के दलदल में धंसते हुए भी इतनी नड़ी जीवनी-शिक्त का परिचय दिया हो !

इस ब्राह्म-विश्वास की भावना के वल पर ही हमारी राष्ट्रीयता का विकास हुआ। पश्चिम के 'वैलैंज' का जवाव हमने सबसे पहिले धार्मिक चेत्र में दिया। राममोहनराय ने उपनिषदों, दयानन्द सरस्वती ने वेदां, श्रौर सर सैयद श्रहमद ऋौर ऋमीरऋली ऋादि ने इस्लाम की पाचीन महानता, को पुनर्जीवित करके हमारे मन में इस भावना को जन्म दिया कि हम धर्म के च्रेत्र में पिश्चम से किसी प्रकार, कंम नही हैं । भारतीय पुरातन्व में दिलच्छी रखने वाले शोपन-हॉवर, मोनियर विल्सन श्रादि कई योरोपियन लेखकों ने हमारे प्राचीन साहित्य की महानता में हमारे त्रात्म-विश्वास को जायत किया। सामाजिक चेत्र में भी हम परिवर्त्तन ऋौर सुधार के लिये वेचैन हो उठे, ऋौर धर्म ऋौर ममाज के मुधार के कई मिले-जुले त्र्यान्दोलन देश के कोने-कोने में उट खड़े हुए । राजनेतिक दृष्टि से ग़लाम होते हुए भी हम यह महसूस करने लगे कि हम एक ऐसी महान् सम्यता के उत्तराधिकारी हैं जिसके नीचे से नीचे स्तर तक पश्चिम ग्राज भी नहीं पहुंच सका है, ऋौर तब हमारे मन में इस भावना का विकास हुआ कि यदि हम गुलामी के इस तौक को फेंक दें तो एक वार फिर श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व हमारे हाथ में आ सकता है। इस भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति हमें स्वामी विवेकानन्द के व्यक्तिन्व में मिलती है। उन्होंने पश्चिम को लद्द्य करके वहा, "पार्थिव ज्ञेत्र में तुमने हम पर विजय प्राप्त की है: हम श्राध्यातिमक ज्ञेत्र में तुम

पर विजयी होंगे।" इस ब्रात्म-विश्वास, ब्रीर चुनौती के साथ, हमारे राष्ट्रीय-जागरण का प्रारम्भ होता है । इन्हीं दिनों इटली के राष्ट्र-निर्माता मैजिनी का एक ग्राध्यात्मिक राजनीति का संदेश भी हमारे हृदय के संवेदनशील तारों को भंकृत कर रहा था । भारतीय राष्ट्रीयता के पहिले युग में मैज़िनी का प्रभाव भी लगभग उतना ही पड़ा जितना वंकिमचन्द्र या गीता के नए अध्ययन का विवेकानंद के शक्ति के संदेश ने जिन प्रसुप्त भावनात्रों को जागृत किया था, ग्रीर जिन्हें मैजिनी ने देश-प्रेम का ज्वलन्त रूप दिया थां, वंकिमचन्द्र के 'ग्रानंदमट'ने उनके संगठित होने में मार्ग प्रदर्शन किया । भारतीय संस्कृति की महानता में इस ब्रात्म-विश्वास की जागृति के साथ ही साथ पश्चिम के प्रति एक महान् श्रवज्ञा का भाव भी हमारे मन में विकास पाने लगा । श्रमरीका से लौटने के वाद के विवेकानन्द के भाषणों में हम उसकी प्रतिध्वनि पाते हैं। १८८६ में श्रवीसीनिया द्वारा इटली पर विजय व १६०५ में रूस पर जापान की विजय ने इस भावना की पुष्ट किया । पहिले महायुद्ध के दिनों में, जब हिंदुस्तानियों ने पश्चिम के लोगों को साम्राज्य-लिप्सा ग्रीर तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए कटते-मरते देखा, यह भावना अपनी चरम-सीमा तक जा पहुँची। गांधी के व्यक्तित्व में, ग्राप्यात्मिक ग्रार राजनैतिक दोनों च्लेत्रों में, पश्चिम के प्रति विद्रोह की इस प्रवृत्ति को पूर्ण ग्राभिव्यक्ति मिली।

वैधानिक प्रयोगीं का आरम्भ.

भारतीय राष्ट्रीयता की इस बढ़ती हुई शिक्त की पृष्ठभूमि पर ही हम उन वैधानिक प्रयोगों को ठीक से समभ सकेंगे जिन्हें हमारे छंग्रेज शासकों ने प्रजानत्त्र की स्थापना के नाम पर समय-समय पर हमारे देश में कियातमक रूप दिया। भारतीय जनता में छात्म-विश्वास छौर नागरिक श्रिधकारों की चैतना के जागत होते ही शासकों के सामने एक समस्या खड़ी होगई। साम्राज्यवाद का विपैला पोधा तो छजान के छंधेरे में ही छज्छा फूलता-फलता है, पर, भाग्य की बात, हमारे देश में इस छजान को दूर करने में स्वयं साम्राज्यवादी शासकों का ही हाथ रहा है। यह तो स्पष्ट ही है कि छंग्रेज़ी सरकार ने शिक्ता का प्रसार इस उद्देश्य से किया था कि उसे क्लकों की एक ऐसी सेना मिल सके जिसके सहारे यह शासन चला सके। छंग्रेज़ी शिक्ता के हारा भारतीय विद्यार्थी स्वतन्त्रता, समता छौर भ्रातृमाव के पश्चिमी सिद्धांतों के संपर्क में छाए। जिन लोगों ने छंग्रेज़ी पढ़ ली थी वे सभी तो सरकारी नौकरियों में खप नहीं सकते थे;न जिस किरम की सरकारी नौकरियां उन दिनों मिल रही थीं उनसे उन सबकी छाकांना तृप्त हो सकती थी। इस प्रकार नवीन विचार-धाराग्रों, छाकांना छोगे छौर स्वरनों को

लिए पट्टे-लिखे व्यक्तियों का एक नया दल इस देश में खड़ा होगया, जिसकी अवशा नहीं की जा सकती थी। परन्तु, इसे उत्साहित भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसका अर्थ होता ऐसी आकांचाओं को जन्म देना, जिनकी पूर्ति के लिए सरकार तैयार न थी। कुछ थोड़े से अंग्रेज़ तो दूर भविष्य में, जबिक हिन्दुस्तानियों के हाथ में शासन के अधिकार देना ज़रूरी हो जायगा, विना किसी भय के देख सकते थे, परन्तु आधिकांश के मन में हिन्दुस्तानियों के प्रति विश्वास अथवा सौहाई का तिनक भी भाव नहीं था। उन्नीसवीं शताब्दी के बीच तक तो अंग्रेज़ों और हिन्दुस्तानियों का सामाजिक संपर्क प्रायः मिट चुका था।

परन्तु, १८५७ के विद्रोह के बाद, जो ऋधिकांश ऋंग्रेज़ों के लिए एक श्रप्रत्याशित घटना थी, यह ज़रूरी दिखाई देने लगा कि सरकार को जनमत के सम्पर्क में रहना चाहिए। '५७ की घटनात्रों ने यह स्पष्ट वता दिया था कि ऐसे सम्पर्क का न होना कितना ख़तरनाक हो सकता है। १८६१ का एक्ट, जिसके कारण पहली बार धारासभात्रों की स्थापना हुई, इस उद्देश्य से वनाया गया था कि सरकार को कुछ प्रमुख ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों का सहयोग मिल जाय-जिससे एक स्त्रोर से सरकार भारतीय जनमत से स्रपना सीधा संपर्क रख सके ख्रौर दूसरी ख्रोर हिन्दुस्तानियों की शासन में ख्रिधिकार पाने की बढ़ती हुई श्राकांचा को एक सीमा तक तृप्त किया जा सके। १८६१ के एक्ट का उद्देश्य इससे ग्राधिक नहीं था। उसे भारतीय प्रजातन्त्र की ग्रोर पहला क़दम कहना गुलत होगा । इस एक्ट के बनने के ३१ वर्ष बाद, कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड व हिन्दु-स्तान दोनों में सात साल तक किये गए श्रानवरत परिश्रम श्रीर प्रचार के बाद, एक दूसरा एक्ट बना जिसमें चुनाव के सिद्धान्त की ऋव्यक्त रूप से माना गया व धारासभात्रों की सदस्य-संख्या ग्रीर ग्राधिकारों को थोड़ा-सा वहा दिया गया, पर उस समय भी लॉर्ड डफ़रिन ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया था कि उक्त 'सुधारों' का मंशा हर्गिज़ यह नहीं था कि हिन्दुस्तान में ग्रंग्रेज़ी हंग की पार्लमेएट स्थापित कर दी जाय । इस घोषणा से शासन-विधान सम्बन्धी इन दोनों योजनात्रों के उद्देश्य का स्पष्ट पता चल जाता है ।

१६०५ के वायकॉट व स्वदेशी आन्दोलनों व सरकार द्वारा दमन-चक्र का आरम्भ होने के वाद से ही धीरे-धीरे देश भर में फैल जाने वाले कान्तिकारी आन्दोलनों के कारण भारत सरकार के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। इसका मुकाविला भी उन्होंने अपने उसी वैधानिक अस्य से किया। शासन में सुधारों की घोषणा हुई—नये प्रान्तों में धारासभाएं वनीं, पुगनों में उनके

सदस्यों की वृद्धि हुई, सभी जगह धारासभात्रों की त्राधिक त्राधिकार मिले । चुनाव के सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से मान लिया गया । प्रान्तीय व केन्द्रीय कार्य-कारिगी सभाग्रों में हिन्दुस्तानियों को नियक्त किया गया, पर, इस वार भी सरकार का स्पष्ट उद्देश्य यही था कि शासन में ऋधिकार का लालच देकर वह नम्र-दल के राजनीतिजों को अपने साथ ले ले. और तब इस नैतिक वल का उपयोग राष्ट्रीय ग्रान्दोलन की उग्र प्रवृत्तियों को कुचलने में करे। इस वार तो ग्रीर भी स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया कि हिन्दुस्तानी यह आशा न रखें कि अंग्रेज़ी सरकार उन्हें पालंमेएटी ढंग का शासन देना चाहती है: वह तो उसकी प्रकृति के श्रनुकुल वस्तु थी ही नहीं। श्रनुदार दल के वायसराय लॉर्ड मिन्टो ने तो यही कहा था कि इन (१६०६ के) सुधारों का उद्देश्य "भारतवर्ष में पश्चिमी ढंग के किसी प्रजातंत्रात्मक शासन की स्थापना नहीं है" परन्तु उदार-दल के भारत-मन्त्री मि॰ मॉर्ले ने एक क़दम श्रीर श्रागे वह कर कहा-"'यदि यह धारणा किसी भी श्रंश में ठीक निकली कि वर्तमान सुधार, व्यक्त श्रथवा श्रव्यक्त किसी भी रूप में पश्चिमी ढंग का शासन स्थापित करने में सहायक होंगे तो मैं उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना पसन्द न करूंगा।" ऐसी परिस्थिति में यदि १६०६ के 'स्थारों' की धारा-सभात्रों ने वाद-विवाद के त्रखाड़ों का रूप ले लिया तो इसमें ग्राश्चर्य क्यों हो ? इससे बड़े किसी उद्देश्य की उनसे ग्रापेक्षा हीं कब की गई थी ?

प्रजातंत्रं की जड़ों पर श्राघात

परन्तु, अग्रेज अधिकारियों ने प्रजातंत्र-शासन को हिन्दुस्तान के लिए अनुपयुक्त माना हो, केवल यही वात नहीं थी, उन्होंने जान-वृक्ष कर ऐसे साधनों
का प्रयोग किया जिनसे प्रजातंत्र-शासन हमारे देश में कभी पनप ही न सके ।
प्रजातंत्र की स्थापना और विकास के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता
होती है—एकता, मैत्री और सहानुभृति के वातावरण की । उसकी सफलता के
लिए यह ज़रूरी है कि देश में रहने वाले विभिन्न समुदाय एकता की भावना से
प्रेरित होते हों, और एक-दूसरे के साथ पूरी सहानुभृति और एक-दूसरे के हिएकोणों को समम्भने की पूरी ज्ञमता रखते हों—दूसरे शब्दों में, जाति और संप्रदाय
की सीमा को पार कर राष्ट्रीय भावना सब में समान रूप से क्यात हो । हमारे
देश में इस प्रकार की भावना जन्म ले चुकी थी, और विकास के पथ पर थी—
१६०५-६ की देश-स्थापी राजनैतिक जाग्रीत इसकी साज्ञी थी । इस प्रवृत्ति का
चरम लच्च भारतवर्ष में पूर्ण-प्रजातंत्र शासन की स्थापना ही था । परन्तु, अग्रेज़ी
सरकार ने अपनी नीति से राष्ट्रीयता के इस पनपते हुए पौधे को, प्रजातंत्र की

श्रोर बढ़ती हुई भारतीय जनमत की विचार-धारा को, बीच में ही काट डालना चाहा, श्रीर देश में ऐसा वातावरण बनाना चाहा जिसमें तानाशाही के श्रलावा किसी भी प्रकार की शासन-पद्धति का गुज़र नहीं हो सकता था।

त्रपने भारतीय शासन में त्र्यंग्रेज़ों ने बहुत पहले से भेद-भाव की नीति को बरतना शुरू कर दिया था। यों तो १८२१ में, 'एशियाटिक जर्नल' में हम एक लेखक को लिखते हुए पाते हैं, "भारतीयों में भेदभाव की सृष्टि हमारे शासन का मूल-मंत्र होना चाहिए।" इसी श्रंक में एक दूसरे सज्जन ने लिखा, ''हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि (भाग्यवश) इस देश में धर्म स्रौर जातियों की जो विभिन्नता है उसे स्थायित्व प्रदान करें, न कि यह कि उसके मिटाने की चेष्टा करें।" १८५८ में लॉर्ड एलिफेस्टन को हम इस नीति का सर-कारी रूप से समर्थन करते हुए पाते हैं। जहां तक हिंदुस्तान के दो वड़े समाजों का संबंध था उन्नीसवीं शताब्दी के प्रायः अन्त तक मुसल्मानों पर सरकार की कोपदृष्टि थी ख्रौर हिंदू उसके कृपापात्र थे, पर हिंदुद्यों में ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय-ख्रांदो-लन-ज़ोर पकड़ता गया, सरकार की नीति में परिवर्त्तन होता गया श्रीर श्रव उसने हिंदुऋों के विरुद्ध मुसल्मानों का समर्थन प्राप्त करना चाहा। १६०४ के वंग-भंग के पीछे हिंदुक्रों क्रौर मुसल्मानों में भेद डाल देने की नीति स्पष्ट थी। त्रपनी 'India in Transition' नाम की पुस्तक में सर हैनरी कॉटन ने स्पष्टतः लिखा है-- ''इस योजना का उद्देश्य एकता श्रीर संगठन की भावनाश्रों को कुचल डालना था--उसके पीछे शासन-सुविधा संबंधी कोई कारण नहीं था। लॉर्ड कर्ज़न की साष्ट नीति यह थी कि राष्ट्र-प्रेम की उभरती हुई प्रवृत्ति को कुचल दिया जाय ऋौर राष्ट्रीयता की वढ़ी हुई शक्ति को कमज़ोर वना दिया जाय।" कलकते के 'स्टेट्समैन' ने लिखा—''योजना के पीछे वास्तविक उद्देश्य यह था कि पूर्वी वंगाल के मुसल्मानों की ताक़त को बढ़ाया जाय, जिससे हिंदुस्रों की तेज़ी से बढ़ती हुई ताक़त को पूरे ज़ोर के साथ रोका जा सके।"

१६०६ के 'सुधारों' के पीछे भी संप्रदाय को संप्रदाय के प्रति खड़ा कर देने की यही भावना काम कर रही थी, श्रीर स्पष्टतः इसी उद्देश्य से इन सुधारों के साथ सांप्रदायिक चुनाव की योजना को कियात्मक रूप दिया गया। हिंद्य- हाईनेस श्रागाख़ां के नेतृत्व में जो डेपुटेशन लॉर्ड मिटो से शिमला में मिला था उसे मौ॰ मोहम्मदश्रली ने १६२२ में कांग्रेस के सभापित के पद से ''एक श्रादेश के श्रनुसार किया गया काम'' कहा था। भारत-सरकार के एक दड़े कर्मचारी ने लोर्ड मिटो हारा सांप्रदायिक चुनाव के सिद्धांत को मान लिए जने के बाद के एक पत्र में लिखा—''श्राज एक बहुत बड़ी बात हुई है। राजनैतिक

दूरदिशंता का एक ऐसा काम हुआ है जिसका प्रभाव हिंदुस्तान और उसके इतिहास पर एक लम्बे समय तक रहेगा। यह काम है ६ करोड़ २० लाख व्यक्तियों (मुसल्मानों) को राजद्रोह की सफ़ों में शामिल होने से रोक लेना।" यहां हम यह वात भी न भृत्तें कि सांप्रदायिक चुनाव के सिद्धांत का देश-न्यापी विरोध होने पर भी सरकार उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। ब्रिटिश इंग्डियन एसोसिएशन के मन्त्री ने लिखा—"हमारी कमेटी इस निश्चय का विरोध करती है। यदि एक धार्मिक वर्ग के साथ पत्तपात किया गया तो दूसरे सव धमों के मानने वाले ऋपने-ऋपने लिए विशेष प्रतिनिधित्व की मांग करेंगे।" इस ग्रालोचना में तिनक भी ग्रातिशयोक्ति न थी-कई धार्मिक संपदायों ने ऋपने लिए ऋलहदा चुनाव की मांग उपस्थित कर भी दी थी। मद्रास के लैंड होल्डर्स एसोसिएशन ने लिखा-"'इससे उन विपमतात्रीं के वढ जाने का भय है जो धार्मिक चेंत्र को छोड़कर हर जगह ख़त्म होती जा रही हैं, साथ ही यह जनता में एकता की उस भावना के उन्नति की एक ग्रावश्यक शर्त है, जो,विकास पाने में बाधक होगा।'' भारत-सरकार के १ ग्राक्त्वर १६०८ के पत्र से भी स्पष्ट है कि वह जानती थी कि हिंदुक्रों में साधारग्तः यह माना जाता था कि ''इन प्रस्तावों में एक धर्म को दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिशा" है। बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन की राय में, "सुधार के प्रस्तानों का मूल-सिद्धांत पढे-लिखे वर्ग के प्रभाव के विरुद्ध एक नई शक्ति को खड़ा कर देना था।" गुजरात सभा के विचार में इससे एक वर्ग के विरुद्ध दूसरे वर्ग के उठ खड़े होने, श्रीर भारतीय जनमत की शक्तियों के ग्रापस में ही लड़ कर विखर जाने श्रीर एक दूसरे को नष्ट कर देने का भय था।" परन्तु इस देशन्यापी विरोध के बावजूद भी भारत-सरकार ने सांप्रदायिक चुनाव के सिद्धांत को हमारे शासन-विधान का एक प्रमुख द्यांग बना ही दिया ।

सांप्रदायिक चुनाव के भयंकर परिणामां से भारतीय राजनीति का प्रत्येक विद्यार्थी परिचित है, परन्तु एक लम्बे ग्रस्ं तक वह राष्ट्रीयता के ग्रदभ्य प्रवाह को रोक नहीं सका। हिंदू ग्रौर मुसल्मानों में भेद डालने की सरकारी नीति की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू ग्रौर मुसल्मानों में राष्ट्रीयता के ग्राधार पर एकता स्थापित करने की दिशा में संगटित प्रयत्न ग्रारम्भ होगए। मालवीद जी के प्रयत्न से इलाहाबाद व ग्रन्य स्थानों में हिंदू-मुस्लिम एकता को मज़बूत बनाने की दिशा में कई एकता-सम्मेलन हुए। ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां भी भारतीय मुसल्मानों को ग्रंगे ज शासकों का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थीं। टकीं के प्रति इंग्लैंड की जो नीति थी वह भारतीय मुसल्मानों के ग्रसन्तोप व विज्ञोभ को

चढ़ा रही थी। १६१२ के बाद से मुसल्मानों में राष्ट्रीय चेतना का जो निर्वाध स्रोत प्रवाहित हुन्ना उसका ज़िक ऊपर न्नाचुका है। मुस्लिम-लीग जैसी प्रतिक्रियावादी संस्था भी इस प्रभाव से न्नपने को न्नाचहदा न रख सकी। १६१३ में उसने भारतवर्ष में स्व-शासन की स्थापना को न्नपना लच्य बनाया। राष्ट्रीय विचार वाले न्नासंख्य मध्यम-श्रेणी के मुसल्मान लीग में शामिल होगए। इन प्रगतिशील तत्तों के लीग में न्नाजाने से कांग्रेस व लीग के वीच का न्नप्तर बहुत कम हो गया। कई वधों तक प्रायः एक ही स्थान पर कांग्रेस व लीग के वार्षिक न्नाधिन निश्चन होते रहे। १६१६ में दोनों के वीच एक वैधानिक समभौता भी होगया, जिससे कांग्रेस ने मुसल्मानों के न्नालहदा चुनाव का विरोध न करने न्नीर ली ग ने 'होम-रूल' के न्नादोलन को न्नपना लेने का निश्चय कर लिया। ज़िलाफ़त के प्रश्न को लेकर मुसल्मानों में न्नांग्रेज़ी शासन के विरोध की भावना न्नीर भी तीखी होती जारही थी। सभी सांप्रदायिक शिक्तयां शासन के विरुद्ध एक निकट संगठन में वंधती जा रही थी।

💛 राष्ट्रीय त्र्यांदोलन का विस्तार एक दूसरी दिशा में भी हो रहा था। त्र्यवतक राष्ट्रीय ऋांदोलन मध्यम-वर्गके पढ़े-लिखे व्यक्तियों तक ही सीमित था; परन्त ग्रय उसमें नई ऋौद्योगिक श्रेणियां भी शामिल होती जा रहीं थीं। भारतीय उद्योग-धंधों के विकास के साथ यह रिथित ग्रानिवार्य थी। उन्नीसवीं शताब्दी के ग्रांत तक सरकार ने भारतीय उद्योग धन्धों को पनपने ही न दिया था, पर उसके वाद नये साम्राज्यों की स्यापना ऋौर ऋँगेज़ी साम्राज्य से उनकी प्रतिद्वंद्विता का लाभ उठाकर भारतीय उद्योग-धन्धे भी संगठित होने लगे थे। वस्वई में कपड़े व बंगाल में जूट की मिलें तेज़ी के साथ खड़ी होती जा रहीं थीं। इनके सहारे हमारे देश में भी पंजीवादी वर्ग का निर्माण हो रहा था। इस वर्ग की सहानुभृति राष्ट्रीय च्यान्दो-लन के साथ होना स्वाभाविक थी। एक ग्रोर जैसे मध्यम-श्रेगी के पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी डॉक्टरी, वकीली, पत्रकार कला ग्रादि चोत्रों से ग्रंग्रेज़ों की हटा कर इन धन्धों को खयं श्रपने हाथ में ले लेने के लिए उत्सुक थे, उसी प्रकार पंजी-पतियों के लिए भी यह खाभाविक था कि वह ग्रौद्योगिक च्रेत्र से ग्रंगेज़ीं का प्रभुत्व हटा कर खबं उनका स्थान ले लें। राष्ट्रीय ज्ञवन्तोप का प्रमुख ग्रस्त्र स्वदेशी का ग्रान्दोलन था। इस ग्रान्दोलन का प्रभाव भारतीय उचीन-धन्धी के विकास पर श्रन्छा पड़ रहा था । ऐसी दशा में हमारे नवे पूँजीपितवां द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थन होना खाभाविक ही था। इनके छलावा विद्यार्थी, ंच्यापारी, छोटे-मोटे दुकानदार, दफ्तरों के क्लर्क और निम्न मध्यम श्रेग्। के अन्य व्यक्ति भी राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में भाग लेने लगे थे। महायुद्ध ने दहें से लेका

छोटे तक सभी वर्गों को भारतीय शासन के ख़िलाफ़ संगठित कर दिया। युद्ध के परिणाम-स्वरूप भी पूंजीपतियों का धन व शिक्त दोनों बहुत बढ़ गए थे—इससे भी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का बल बढ़ा। हिंदू और मुसल्मान, पूंजीपित और अभिक, किसान और व्यापारी, सभी वर्गों में सरकार के प्रति असंतोप और संगठन की प्रवृत्ति, बढ़ते जा रहे थे। वातावरण में कम्पन और गित, और आने वाले विस्फोट की गंध थी।

परिस्थितियों की चुनौती दिन-व-दिन गम्भीर रूप लेती जा रही थी । उसे स्वीकार किये विना चारा नहीं था, श्रौर एक सीमा तक संतुष्ट करते हुए दूसरी स्रोर से राष्ट्रीयता पर एक स्रोर भी बड़ा प्रहार करना स्रव जरूरी हो गया था। १६१६ के 'सुधारों' की यही पृष्ठभूमि थी। कहा यह गया कि युद्ध में हिंदुस्तान ने साम्राज्य की जो ऋगुल्य सेवाएं की हैं—उसकी सुरत्ता में दस लाख से ग्रिधिक व्यक्ति ग्रीर लगभग ढाई ग्ररव रूपया भेंट चढा दिया है-उसके पुरस्कार में उसे ये. ऋधिकार दिये जा रहे थे। परन्तु वैधानिक परिवर्तन का मुख्य कारण तो देश की राजनैतिक परिस्थित ही हो सकती थी। २० श्रगस्त १६१७ को सम्राट की वह ऐतिहासिक घोषणा प्रकाशित की गई जिसमें कहा गया था कि "भारत में ऋंग्रेजी राज्य का ऋन्तिम लच्य शासन के प्रत्येक विभाग में ऋधिक-से-ऋधिक हिंदुस्तानियों को शामिल करना व हिंदुस्तान में स्व-शासन की ऐसी कमवद उन्नति, जिसके परिणाम-स्वरूप वह ग्रंथेज़ी साम्राज्य के ग्रन्त-र्गत रहते हुए पूर्ण उत्तरदायी शासन की ख्रोर ख्रयसर होसके, होगा।" भारत में स्रोगेज़ी राज्य के इतिहास में सचमुच यह एक नया दृष्टिकीए। था। स्राय तक सभी दलों के प्रमुख श्रं ग्रेज़ राजनीतिज्ञ इस वात से इन्कार करते रहे थे कि वे हिंदुस्तान में ज़िम्मेदार हुकूमत के बनने में सहायक होना चाहते हैं। प्रतिनिधि संस्थाएं बन गई थीं, श्रीर उनके सदस्यों की संख्या व श्रिधिकार भी धीरे-धीरे बढाये जा रहे थे, पर श्रव उत्तरदायी शासन को ही हिंदुस्तान में श्रंग्रेज़ी राज्य का सीधा लच्य मान लिया गया था। यह एक वड़ा ब्राकर्षक ब्रादर्श था, पर

3—1808 में भारतीय मिलें राष्ट्रीय आवश्यकता का केवल ६ फीसदी माल तैयार करती थीं, श्रीर ६४ फीसदी विदेशों से, विशेष कर, इंग्लेंड से आता था। १६२१ में ४२ फीसदी आवश्यकता देशी माल से प्री होने लगी थी, श्रीर श्रायात २६ फीसदी रह गया था। इसी प्रकार १६१३ में हिन्दुस्तान में केवल १३००० टन लोहा श्रीर फीलाद तैयार किया जाता था, पर १६१८-१६ में यह संख्या १२३,८६० टन एक जा पहुंची थी। युद्ध केवपों में ही (१६१४-१८ तक) सूती कपड़े पहले से दुगुने व जूट व ऊन के कपड़े तिगुने बनने लगे थे। जहां तक वस्तु स्थिति का प्रश्न था, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस ऋादर्श की प्राप्ति ''धीमी किंश्तों'' में होगी ऋौर ''हर क़दम का समय ऋौर माप'' ऋंग्रेज़ी शासन द्वारा निर्धारित किया जायगा।

उत्तरदायी शासन की पहली किश्त के रूप में हमें १६१६ का विधान मिला। प्रजातन्त्रीकरण के दिखावे के रूप में उसमें बहुत कुछ था। केन्द्रीय धारासभा के दोनों भागों में चुने हुए सदस्यों को बहुमत दे दिया गया धा-श्रीर उन्हें शासन की श्रालोचना करने व उस पर प्रभाव डालने के श्रिधक साधन दे दिये गए थे। प्रांतीय धारा-सभान्त्रों के सदस्यों की संख्या वहत श्रिधिक बढ़ा दी गई थी-श्रीर उनमें भी चुने हुए सदस्यों को बहुमत दे दिया गया था । प्रांतीय कार्यकारिणी में भी परिवर्तन किये गए-उसका एक भाग, जिसके अन्तर्गत कुछ गौगा-विभाग थे, चुने हुए मन्त्रियों को सौंपा गया। मत देने के श्रंधिकार का विस्तार बढ़ा दिया गया। परन्तु जहां एक श्रोर श्रंमेजी सरकार हिंदुस्तान में प्रजातंत्र के नाम पर नई शासन-योजनाएं बना रही थी, दूसरी स्रोर वह स्वयं स्रपने हाथों देश के राजनैतिक जीवन से प्रजातन्त्र की जड़ों को ही उखाड़ फेंकने में व्यस्तथी। मोंटफ़ोर्ड कमेटी ने एक राय से सांप्रदायिक चुनाव को बुरा वताया था, पर स्वयं उसने न केवल इस वात की सलाह दी कि मुसल्मानों के लिए उसका क़ायम रखना ज़रूरी है, पर सिखों के लिए भी उसी ढंग के चुनाव की सिफ़ारिश की। १६१६ के एक्ट में न केवल मुसल्मानों के लिए ही सांप्रदायिक चुनाव कायम रहा, सिखों को भी अलहदा चुनाव के अधि-कार दिये गए । मद्रास के श्रवाहाणों श्रीर मराठों श्रीर कुछ श्रन्य जातियों के श्रिधिकारों को भी माना गया, दलित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए कुछ विशेष सदस्यों को नामज़द किया गया, संगठित उद्योगों को प्रतिनिधित्व दिया गया, स्त्रौर भारतीय ईसाइयों, ऐंग्लो-इपिडयन स्त्रौर वोरोपियन जातियों को श्रलग चुनाव का श्रधिकार मिला। सांप्रदायिक चुनाव का सिद्धांत विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के लिए मान लिया गया । इस बीच मॉन्टेन्यू के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण नरम दल के नेता कांग्रेस से ग्रालग होगए थे-ग्रीर उन्होंने श्रपनी एक श्रलहदा संस्था, लिबरल फ़ैडरेशन, का निर्माण कर लिया था। ग्रन्य प्रतिकियावादी शिक्तियों को भी अपने साथ लेने के प्रयत्न में सरकार हती। हुई थी । वह देशी राजाओं के प्रति भी अपनी नीति बदल रही थी । उन्हें ग्रय साधारण सामन्त की स्थिति से उठाकर सार्वभौम सत्ताधीशों की धेरी में लाया जा रहा था । १६२१ में 'नरेन्द्र मण्डल' का संगठन हुन्ना ।

यह कहना सल्य नहीं है कि १६१६ की शासन-योजना को विकस्ति होने के

लिए उचित वातावरण नहीं मिला । उसका प्रारम्भ तो निस्संदेह एक श्रशुभ घड़ी में हुया था, जब काले कानून, जिलयानवाला वाग़ और गांधीजी के सत्याग्रह-ग्रान्दोलन पर देश की दृष्टि जमी थी। परन्तु, यह नहीं कहा जा सकता कि देश ने उसे विकास का पूरा मौका नहीं दिया। नरम, दल के नेता शुरू से ही उसका समर्थन कर रहे थे। सपू वायसराय की कार्यकारिगी के सदस्य वने । चिन्तामणि ने अक्तप्रान्त में शिद्धा-मन्त्री का पद ग्रहण किया । सरेन्द्रनाथ वंगाल में मन्त्री वने । कांग्रेस का उग्र दल भी, खराज्य पार्टी के रूप में,कैंसिलीं में प्रविष्ट हो गया । कांग्रेस के विद्वलामाई पटेल केन्द्रीय धारासमा के प्रथम चुने हुए ग्रध्यद्ध वने । परन्तु नये सुधारों का खोखलापन जल्दी ही लोगों पर प्रगट हो गया--- श्रोर नरम दल वाले भी श्रिधिक दिनों तक उसे श्रिपना सहयोग न दे सके। सप्र ऋौर चिन्तामणि दोनों की इस्तीफ़ा देने पर वाध्य होना पड़ा । लोगों ने देखा कि १९१९ के सुधारों का एकमात्र परिगाम यह निकला कि गयर्नर की शक्ति पहले के मुकाबिले में कई गुना अधिक वह गई। केन्द्रीय सरकार द्वारा जितने श्रिधिकार प्रान्तीय सरकार को सौंपे गये वे सब उत्तरदायी मन्त्रियों के स्थान पर गवर्नर के हाथ में ग्रा गए, ग्रीर उत्तरदायी मन्त्रियों का स्थान वही रह गया जो किसी विभागीय अध्यक्त का होता है--वे सर्वथा गवर्नर के अधीन थे श्रीर श्रपनी धारासभाश्रों के प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं रह गए थे। मद्रास के एक मन्त्री, सर के ० वीं ० रेड्डी द्वारा एक कमीशन के सामने दी गई गवाही १६१६ के शासन-विधान पर श्रच्छा प्रकाश डालती है । उन्होंने कहा:--''मैं राष्ट्रीय संपत्ति के विकास का मन्त्री हूं, पर जंगल मेरे ग्रान्तर्गत नहीं हैं। में श्रीचोगिक विभाग का मन्त्री हूं, पर कल-कारख़ानों से मेरा सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वह गवर्नर के स्वतन्त्र अधिकार में है, और कल-कारखानों के विना श्रीचोगिक विभाग की कल्पना करना कठिन है। मैं कृषि का मन्त्री हूं, पर , श्रावपाशी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं मैं श्रीद्योगिक, विभाग का मन्त्री हं , पर उसमें भी विजली के कारखाने से मेरा सम्बन्ध नहीं, वह तो सुरक्तित विभाग है। मज़द्र ग्रौर मशीनरी के विषय भी सुरक्षित हैं।"

१६३४ की शासन-योजना

हमारे वैधानिक इतिहास में द्यागला महत्वपूर्ण प्रयोग १६३५ की शासन-योजना है। उसके निर्माण में जितना समय क्रीर श्रम लगा, संसार के किसी भी देश की शासन योजना में उसका चौथाई भी शायद ही लगा हो। यरसों तक विचार-विनिमय, वाद-विवाद,कमेटी—कान्फ्रेंसें, गवाही क्रीर व्हाइट पेपर का कम रहा। सायमन-कमीशन की नियुक्ति हुई। उसने हिन्दुस्तान भर में दौरा किया। त्रपनी रिपोर्ट पेश की l वह उठाकर एक स्रोर रख दी गई l एक, दो, तीन गोलमेज़-परिषदें हुईं । संयुक्त पार्लमेंटरी कमेटी की अनेकों मीटिंग हुईं, पार्ल-मेएट में महीनों बहस की गई, तब जाकर १६३५ का विधान बना । ऐसी दशा में यदि हम उसमें राजनीतिज्ञता की पराकाष्ठा की त्राशा करें तो इसमें क्राश्चर्य नहीं होना चाहिए। पर, शेवलंकर ने उसे "साम्राज्यवादी कूटनीविज्ञवा की पराकाष्ठा" कहा है-''एक ऐसी व्यापक श्रीर प्रतिभाशाली योजना जिसका उद्देश्य स्वतन्त्र भारत की कल्पना को ही समाप्त कर देना श्रौर जहां तक वैधा-निक उपायों द्वारा हो सकता था, ऋंग्रेज़ी साम्राज्य को उन परिस्थितियों के वदल जाने पर भी जिनमें उसकी स्थापना हुई थी, क़ायम रखना था।" १६३५ का विधान देखने में वड़ा ऋाकर्षक है, उसके द्वारा प्रान्तीय शासन, न्याय श्रौर रत्ता के विभागों समेत, ऐसे मन्त्रियों के हाथों में सौंप दिया गया था जो संयुक्त रूप से धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी थे। ऋंग्रेज़ी शासन के इतिहास में यह पहला अवसर था जब प्रान्तीय शासन में भी कुछ वास्तविक अधिकार जनता के मनोनीत व्यक्तियों के हाथ में दिये गए हों ि भौगोलिक सीमात्रों व जन-संख्या की दृष्टि से हमारे प्रान्त रूस के ऋतिरिक्त योरुप के अन्य वड़े देशों से किसी प्रकार कम नहीं हैं। इतने वड़े प्रदेशों में प्रजातन्त्र शासन की स्थापना के महत्त्व को दृष्टि से ऋोभल नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार केन्द्रीय शासन में भी रत्ना ऋौर वैदेशिक विभाग को छोड़कर, शासन का प्रायः सारा शेप भाग एक उत्तरदायी मन्त्रिमएडल के हाथों में दिये जाने का प्रस्ताव था। मत देने का श्रिधिकार भी लगभग ४ करोड़ व्यक्तियों को. जिनकी संख्या १६१६ के विधान की तुलना में लगभग पांचगुनी थी, दे दिया गया था। परन्तु, एक च्रीर जहां शासन के एक बड़े स्रंश को उत्तरदायित्व-पूर्ण बनाने का स्रायोजन था, दूसरी न्त्रीर 'विशेष उत्तरदायित्वों' के नाम पर श्रंमेज़ी सरकार द्वारा नियुक्त गवर्नर-जनरल को इतने ऋषिकार दे दिये गए थे कि, सर वैरीडेल कीथ के शब्दों में. उससे उत्तरदायी शासन के ख़त्म हो जाने का ही डर था। इसी कारण वो सर सेम्यएल होर जैसा अनुदार राजनीतिज्ञ इंग्लैयड की साधारग्-सभा को यह ग्राश्वासन दिला सका कि १६३५ के विधान के ग्रन्तर्गत उग्न दल के व्यक्तियों के केन्द्रीय शासन पर श्रिधिकार पा जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

इंग्लैएड के अनुदार दल में भारत के प्रति सदा से जो अविश्वास रहा है, १६३५ के विधान में उसकी अधिक-से-अधिक अभिन्यिक हुई है। यों तो प्रत्येक वैधानिक परिवर्तन के अवसर पर उत्तरदायी शासन पर अधिक-से-अधिक प्रतिवंध लादने की चेष्टा की गई है, पर १६३५ के विधान में इन प्रतिवंधों का

हम एक ग्रम्वार-सा पाते हैं, न्यूयॉर्क के ग्राकाश चुम्वी प्रासादों के समान, एक के ऊपर एक । प्रांतीय शासन में भी गवर्नर के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति दे दी गई है-वह ग्रपने 'विशेष ग्राधिकारों' के नाम पर शासन में जब चाहे तब हस्तचीप तो कर ही सकता है, विना मन्त्रिमण्डल से पुंछे, क़लम की हल्की-सी गति से, वैधानिक शासन को विल्कुल समाप्त करके अपने हाथों में सारी शक्ति केन्द्रित कर लेने का तानाशाही ग्राधिकार भी उसे प्राप्त है। केन्द्रीय शासन तो प्रजातन्त्र का मखौल है। प्रमुख विभागों में उत्तरदायी शासन के लिए कोई स्थान नहीं है, परन्तु जिन थोड़े से विभागों में उसका प्रवेश है उनमें भी गवर्नर जनरल द्वारा 'विशेष उत्तरदायित्व' के नाम पर हस्तज्ञेव की पूरी सुविधा है। गवर्नर जनरल को यह भी ऋधिकार है कि वह देशी राजाओं और ऋल्पसंख्यक दलों के समुचित प्रतिनिधित्व के नाम पर मिन्त्रमण्डल की एकता को नष्ट कर सके । जिस धारासभा के प्रति यह मन्त्रिमएडल उत्तरदायी माना जाता था खयं उसकी रचना कुछ श्रनोखे सिद्धान्तों के श्राधार पर की गई है। उसके दोनों भागों में एक तिहाई से ऋधिक देशी राजाओं द्वारा नियुक्त सदस्य होंगे, कौंसिल श्रॉफ़ स्टेट के ब्रिटिश भारत से श्राने वाले सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा रखा गया है, यद्यपि उस चुनाव में भाग लेने का ऋधिकार वहत ऋधिक धनी व्यक्तियों को ही दिया गया है। नीचे के चैंवर में जो सदस्य ब्रिटिश भारत के होंगे उन्हें चुनने का श्रिधिकार साम्प्रदायिक चुनाव के श्राधार पर चुनी गई प्रान्तीय धारासभात्रों के सदस्यों को होगा। चुनाव के इस त्राभृतपूर्व तरीक्षे से चने जाने के बाद भी केन्द्रीय धारासभा को बहुत कम अधिकार दिये गए हैं। रत्ता, विदेशी नीति, राष्ट्रीय कर्जे का लेनदेन, सिक्के श्रीर विनिमय-दर, रेलवे-यह सब उसके ग्राधिकार के बाहर हैं। केन्द्रीय बजट की ८० फ़ीसदी से ग्राधिक रक्तम के सम्बन्ध में उसे मत देने का ऋधिकार नहीं है। क्वानून बनाने ऋथवा शासन पर नियंत्रण त्रादि चेत्रों में वह गवर्नर जनरल के ऋधिकारों से बंधी हुई है। जहां तक व्यापार श्रौर श्रर्थनीति का सम्बन्ध है, वर्षों के परिश्रम से ऐसे प्रतिवंध विधान में पिरो दिये गए हैं कि भारतीयों के लिए उनका स्पर्श करना भी ग्रसम्भव होगा। दूसरी ग्रोर, गवर्नर-जनरल के हाथ में सार्वभीम सत्ता दे दी गई है। उस पर जनता द्वारा चुनी गई धारासभाद्यों का कोई नियंत्रण नहीं है। वह न केवल धारासभात्रों के प्रत्येक निर्णय को ग्रास्वीकत ही कर सकता है, बल्कि स्वयं ग्रपने ग्राधिकार से ग्रस्थायी ग्रौर स्थायी दोनों प्रकार के कानून बना सकता है। मंत्रियों से अमहयोग की स्थिति में उसे सारे शासन-तंत्र की ख़त्म करने का पूरा ऋधिकार है। न तो गवर्नर जनरल श्रीर न प्रान्तीय गवर्नर ही

उस सलाह को मान लेने के लिए वाध्य हैं जो उन्हें जनता के प्रतिनिधि-मिन्त्रयों द्वारा दी जाय ।

वैधानिक प्रयोगों की विशेषताएं : एक विश्लेषण

हमारे देश में १८६१ के एक्ट से १६३५ के शासन-विधान, ऋौर १६४२ की किप्स योजना और १६४५ के वेवल प्रस्तावों तक, प्रत्येक वैधानिक परिवर्त्तन के पीछे कुछ प्रमुख भावनाएं काम करती रहीं हैं। प्रत्येक वैधानिक प्रस्ताव एक विशेष परिस्थिति का सामना करने की दृष्टि से उठाया गया । १८६१ में शासन के जन-मत के सम्पर्क में रखने की जुरूरत: १८६२ में कांग्रेस की दिन-व-दिन वढती हुई मांगों को कहीं-न-कहीं रोक देने की इच्छा: १६०६ में राष्ट्रीय त्रांदोलन में एक त्रोर तो सांप्रदायिक त्राधार पर भेद डाल देने त्रौर दूसरी त्रोर नरम स्रौर उप्र राजनीतिज्ञों को एक दूसरे से ऋलहदा कर देने की नीति: १६१६ में स्वराज्य की राष्ट्रीय मांग को कमज़ोर वना देने की इच्छा: श्रौर १६३५ में दिन-प्रति-दिन सशक्त बनते जाने वाले राष्ट्रीय त्र्यांदोलन का किसी रूप में मुक्काविला करना — इस प्रकार प्रत्येक वैधानिक परिवर्त्तन के पीछे देश की राज-नीति का एक विशेष युग रहा है। १९४२ ख्रौर '४५ के ग्रसफल प्रस्तावों के पीछे भी भारताय स्वाधीनता के पक्त में बढते हुए ग्रन्तर्राष्ट्रीय दवाव का प्रभाव स्रष्ट था । प्रत्येक 'सुधार' के पीछे घटनात्रों का एक लम्बा चक रहा है: परन्त राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई शिक्त सदा ही उसका प्रमुख कारण रही है, इसलिए प्रत्येक 'सुधार' में हम राष्ट्रीयता की इस शक्ति के साथ समभौते की भावना तो पाते ही हैं, पर साथ ही, एक हाथ से कुछ थोड़े से ऋधिकार देते हुए, दूसरे से साम्राज्य की जड़ों को मज़बूत बनाने की चेष्टा भी हम पाते हैं। सच तो यह है कि ये वैधानिक 'सुधार' उस संघर्ष के पथ पर मील के पत्थरों के समान हैं जो पिछुली स्त्राधी शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीयता ख्रोर स्त्रंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के वीच एक बढ़ते हुए वेग से चलता रहा है।

यद्यपि प्रत्येक वैधानिक प्रगति के साथ हमारे राजनैतिक अधिकारों का विस्तार हुआ है, पर वे अधिकार हमारों मांग और आशा की तुलना में सदा ही कम से कम रहे हैं। १८६२ की योजना कांग्रेस के सात वर्ष के अनवस्त आन्दोलन का फल थी—िकसी ने उसके सम्बंध में ठीक ही लिखा कि वह पहाड़ खोदकर चूहा निकालने जैसा प्रयत्न था। १६०६ के सुधारों से, स्वयं मीटकोई कमेटी के शब्दों में, भारतीय आकांचाओं की तृप्ति न तो हुई और न हो हो सकती थी। १६१६ का द्वैध-शासन सर्वथा असफल रहा। १६३५ के संब शासन की सराहना हिंदुस्तान में शायद ही कियो ने को हो। किया-दोजन, बांग्रेस, लीन,

महासभा, सिख कान्केंस, सभी ने अवजा के साथ ठुकरा दी। वेवल प्रस्तावों का आरम्भ एक नाटकीय परिस्थिति में हुआ और अंत ग्रीक-ट्रैजिडी के समान। क्यों ऐसा होता रहा है ? इसका तो केवल एक ही उत्तर हो सकता है, और वह यह कि इन योजनाओं के बनाने वालों की नीयत कभी साफ नहीं रही है। उत्तर से वे राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने की इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं, पर उनका केन्द्रीय विचार सदा ही अपने हाथों में सत्ता को रोके रहना रहा है। उन्होंने परछाई से लुभाना चाहा है, ठोस मौलिक वस्तु कभी नहीं दी है।

ग्रपनी इस नीति की उन्होंने तरह-तरह के वहानों से छिपाना चाहा है। १९१६ तक तो बहाना था कि पार्लमेंटरी ढंग का प्रतिनिधिक व उत्तरदायी शासन हिंदुस्तान के लिए उपयुक्त नहीं है। परन्तु, पिछले महायुद्ध के दिनों में प्रजावाद ग्रीर राष्ट्रीय ग्रात्म-निर्णय के सिद्धांतों ने जो ज़ीर पकड़ा उसके बहाव में यह वहाना टिक न सका, ग्रौर श्रंग्रेज़ों ने उत्तरदायी शासन को भारत में श्रपनी नीति का ग्रान्तिम लच्य घोपित किया, परन्तु साथ ही वे इस बात का भी लगातार ऐलान करते रहते हैं कि श्रशिचा,साम्प्रदायिक मतभेद, राजनैतिक श्रपरि-पक्रता, राष्ट्रीय मनोवृत्ति त्रादि-त्रादि ऐसे त्रानेक कारण हैं जो उत्तरदायी शासन के विकास में वाधक हैं। इसके ग्रालावा ग्रंथेंज़ों का यह दावा भी लगातार वढ़ता गया है कि हिंदुस्तान के ''सामाजिक व धार्मिक ग्राल्पसंख्यक वंगों की रचा" की जिम्मेदारी भी उन पर है। १९३७ के बाद से सांप्रदायिक मतभेदीं के वहुत ग्रधिक वढ़ जाने ग्रौर उन्हें क़ायम रख सकने के ग्रगम विश्वास के कारण, ग्रव तो ग्रंग्रेज सरकार ने इस ग्राकर्षक सिद्धांत की सृष्टि भी करली है कि भारत के वैधानिक भाग्य-निर्णय का ऋधिकार भारतीयों को ही होना चाहिए। श्रंग्रेज़ी सरकार तो किसी मी ऐसी वैधानिक योजना की मान लेगी जिसे हिंदुस्तान के सब बगों और जातियों और प्रमुख राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। इस सम्बंध में वह त्राश्वस्त है ही कि यह एक ऐसी शर्त है जिसकी पूरा न होने देना स्वयं उसके हाथ में है। किप्स श्रीर वेवल प्रस्तावों की ग्रसफलता से इस कथन का श्रीचित्य स्पष्ट होजाता है।

इन सव वैधानिक 'सुधारों' का परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में एक सम्प्रदाय के ख़िलाफ़ दूसरा सम्प्रदाय, एक जाति के ख़िलाफ़ दूसरी जाति और एक दल के विरुद्ध दूसरा दल,खड़ा होता गया और भारतीय समाज अनेकानेक दुकड़ों में वंटता गया। यह एक ऐसी प्रशृत्ति थी जो प्रजावाद के विल्कुल विरुद्ध जाती है। प्रजावाद का अर्थ जहां देश में एकता की स्थापना करना है, प्रजावाद के नाम पर हमारे शासकों द्वारा जो वैधानिक योजनाएं वनाई जा रही थीं, उनका स्पष्ट उद्देश्य प्रजावाद की जड़ों को ही उखाड़ फेंकना था । १६०६ श्रीर १६१६ के विधानों ने मुसल्मानों को हिंदुत्रों से, ऋौर नरम विचारों के राजनीतिशों को उग्र विचार वालों से, त्रालहदा करने की दिशा में वहुत सफलता प्राप्त की। १६२५ में वर्कनहैड ने लॉर्ड रीडिंग को स्वराज्य-पार्टी में फूट डलवाने के लिए प्रयत्न करने की सलाह दी, ऋौर १६२८ में इन्हीं सज्जन ने इन्हीं वायसराय को लिखा कि वह सायमन कमीशन के विरोध में जो शिक्तयां एकत्रित हो गई थीं, उनमें मतभेद डालने की चेष्टा करें। रोलमेज परिषदों का भी यही उद्देश्य था। "उसमें मुसल्मानों को हिंदुत्रों के ख़िलाफ़, सिखों को मुसल्मानों के ख़िलाफ़, किसानों को ज़मींदारों के ख़िलाफ़, ऋौर देशी नरेशोंको ऋपनी प्रजा के ख़िलाफ़ — उभाड़ा गया था।" भैक्डोनल्ड-निर्ण्य ने दलित जातियों को हिंदुत्रों के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश की। गांधी जी के उपवास ग्रीर पूना पैक्ट के वन जाने से इसमें तो उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली। परन्तु, त्रपनी एक-दूसरी चाल में वह सफल हो गए। वह मुस्लिम प्रांतों को हिंदू प्रांतों के ख़िलाफ़ खड़ा कर देने की योजना थी। पंजाव श्रौर वंगाल में मुसल्मानों को विशेष श्रिधिकार देकर उन्हें मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों में परिग्गत कर दिया गया। सीमाप्रांत में भी धारा-सभात्रों की स्थापना करके मुस्लिम प्रांतों में दो की वृद्धि की गई। श्चव मुस्लिम प्रांतों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया जा सकता था। उधर, १९३५ की योजना ने देशी नरेशों को राष्ट्रीयता के विरुद्ध संगठित कर ही दिया था। कौंसिल त्रॉफ स्टेट में २६० में से १०४ त्रौर फ़ैडरल एसेम्बली में ३७५ में से १२५ सदस्य नियुक्त करने का श्राधिकार देशी राजाओं को दे दिया गया था। इन सदस्यों का सरकारी ६शारे पर नाचना त्रीर प्रगति के रास्ते में एक बड़ी वाधा के रूप में खड़े होना एक निश्चिन्त वात थी।

यह है हमारी वैधानिक प्रगति का एक संद्धित ख़ाका, श्रीर उसकी विशेष-ताश्रों का एक सूक्त्म विश्लेषण । श्रंगेज़ लेखक प्रायः इस बात का दावा करते हैं कि हमारे देश की वैधानिक प्रगति श्रंगेज़ी साम्राज्य के श्रन्य श्रंगों, कैनेडा, दिख्या श्रफ्रीका, श्रास्ट्रेलिया श्रादि की तुलना में दुगुने वेग से हुई है। इस कथन में तान्विक दृष्टि से चाहे कितनी ही सचाई हो, इससे श्राधिक कटोर श्रीर ज्वलंत सत्य यह है कि प्रजातन्त्र की दिशा में हमें ले जाने का दावा करने वाले इन 'सुधारों' की श्राड़ में लगातार हमारे देश में एक ऐसा वातावरण १-के॰बी॰कृष्णाः The Problem of Minorities, १० सं० २०७०

२-शार्बसिंह कवीशरः Non-Violent Non-co-operation.

खड़ा कर देने की पृण्ति चेष्टा चलती रही है जिसमें प्रजातन्त्र का विकास सर्वथा असम्भव हो जाय। मत देने का अधिकार पढे-लिखे लोगों में से लगभग २५ फ़ीसदी को मिल गया है, त्रौर प्रान्तीय शासन में बहुत काफ़ी त्राधिकार मिल गए हैं। परन्तु प्रजातन्त्र की भावना को जो चीज़ें दृढ वनाती हैं उनकी श्रोर विल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। शिक्षा श्रीर समाज सुधार के चेत्र में विकास सर्वथा ग्रसंतोपजनक रहा है। हमारी सरकार ने शिचा में कभी दिलचर्स्य नहीं ली, ग्रौर समाज-सुधार उसके वाहर की वात रही है। पिछले १५० वर्ष के ऋंग्रेज़ी शासन में १० फ़ीसदी जनता भी शिक्तित नहीं वन पाई है। शिचा का कहीं अधिक प्रचार तो श्रंप्रेजी शासन की स्थापना के पहले था। यंग्रेज़ी शासन में शिचा का विकास जिस गति से हुया है उसे देखते हुए समस्त जनता के शिक्तित होने में कम से कम ६-७ सौ वर्ष लगेंगे। गति के इस धीमेपन से एक और भी ख़तरा है। राजनैतिक ग्राधिकारों के साथ ही साथ यदि शिचा का प्रचार नहीं होता रहा तो खार्थी नेताओं के लिए अशिक्ति जनता की भावनात्रों का उभाइना, और उसे स्वार्थ के लिए गुलत दिशा में प्रवृत्त कर देना वड़ा त्रासान हो जाता है। जैसा लेनर्ड ने लिखा है-"'जनता द्वांरा शासन" एक ऐसा ब्रादर्श है जो हमें इस सिद्धान्त के परे ले जाता है कि श्रल्पसंख्यक दलों की बात सुन ली जायगी श्रीर हर एक नागरिक की श्रपने विचारों को न्यक्त करने का ऋधिकार होगा। ऋधिकार, बिना उनका उपयोग करने की चमता के, ऋर्थहीन होते हैं।" यह चमता शिचा द्वारा ही त्राती है, परन्तु एक ऐसी शिक्ता के द्वारा जिसका जीवन से सीधा सम्बन्ध हो. श्रीर जो व्यक्ति में समाज-सेवा की ऐसी त्राकांचा सुलगा दे कि वह उसे चैन से बैठने न दे । जनतक समाज में विषमताएं हैं, ज्यित के लिए सामृहिक रूप से सोचना दुःसाध्य ही रहेगा। एक विदेशी सरकार कभी समाज-सुधार के काम को अपने हाथ में नहीं ले सकती । ऐसी दशा में यदि हमारी धारासभाएं, जो श्रंग्रेज़ी शासन के बोक से दवी हुई हैं, श्रभी तक समाज स्थार के चेत्र में कुछ नहीं कर सकी हैं तो इसमें ग्राश्चर्य ही क्या है ? सच तो यह है—ग्रीर यह एक कड़वा श्रीर तीखा सत्य है—िक हमारे देश की सरकार प्रगतिशील शिक्तेयों की तुलना में प्रतिक्रियावादी शिक्तयों के सहारे पर श्रिधिक निर्भर है। तभी तो वह कायम है।

हमारे देश में एक दल ऐसा है जो वस्तुस्थित के इस विश्लेपण का ग्राधार लेकर इस निष्कर्प पर पहुँचा है कि हमारे देश में प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए उचित वातावरण नहीं है। वह यह मानने के लिए तैयार है कि इसका उत्तर- दायित्व हमारी राष्ट्रीय मनोद्वत्ति नहीं, विदेशी सरकार के श्रनवरत प्रयत्नों श्रीर श्रपरिवर्तनशील नीति पर है, पर वह यह भी मानता है कि कारण चाहे कुछ भी क्यों न रहे हों, वस्तुरिथित त्र्याज ऐसी है कि हम प्रजातन्त्र शासन के योग्य त्राव रह नहीं गए हैं। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ—न मैं श्रपने देश में पूर्ण प्रजातन्त्र शासन की सफलता के सम्बन्ध में त्र्यविश्वासी हूँ । मैं यह जानता हूँ कि हमारे देश में एक त्रोर यह प्रयत्न चलता रहा है, त्रीर चलता जा रहा है, कि प्रजातन्त्र की सफलता के लिए जिस वातावरण की स्रावश्यकता होती है वह न वन सके, परन्तु, दूसरी ऋोर,पिछले डेंढ् सौ वर्षों में, धीमे,पर निश्चय के साथ, एक उत्फल्ल, सप्राण, प्रगतिशील नागरिक जीवन का विकास होरहा है, जो हमें पूर्ण प्रजातन्त्र के लिए तैयार कर रहा है । इन वर्षों में हमारे देश में अभृतपूर्व प्रतिभा वाले महान् व्यक्तियों के नेतृत्व में सशक्त धार्मिक ऋौर सामाजिक ऋौर राजनैतिक त्रांदोलन, ज्वार की फेनिल लहरों के समान, एक तूफ़ानी वेग से त्रागे वढते रहे हैं —जिन्होंने एक स्रोर हमारे व्यक्तिगत स्रोर सामाजिक जीनव में साहस, कष्ट सहन त्र्यौर शुद्धता के त्रामर स्रोतों को जन्म दिया है, त्रीर दूसरी त्रीर उन प्रति-कियावादी शक्तियों पर लगातार ऋाकमण किया है जिनका श्राधार लेकर श्रंगेज़ी साम्राज्य का ऊपर से भन्य दीखने वाला, पर भीतर से खोखला, भवन खड़ा है।

राष्ट्रीयता हमारे त्र्याज के समस्त व्यापक जीवन का मूल-मन्त्र है, वह देश के सर्वोगीण जीवन,धर्म श्रीर कला,साहित्य श्रीर संस्कृति, को श्रपने गृद जैसे सशक स्रोर व्यापक पंखों के नीचे लिये हैं। धार्मिक प्रेरणा में, इस राष्ट्रीय जीवन का मुल त्राधार है। सामाजिक सुधार की विभिन्न प्रवृत्तियां उसके स्तम्भ हैं। ऐसी नींव और ऐसे स्तम्भों का श्राधार लेकर ही तो हमारी राष्ट्रीयता एक श्रपरि-गृही, सत्य श्रीर श्रिहिंसात्मक राजनैतिक श्रांदोलन में फलीभृत हो सकी है। गांधी, जो भारतीय राष्ट्रीयता के सबसे बड़े प्रतीक हैं, राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, रानाडे श्रीर गोखले के व्यक्तित्वों का ही विकास हैं—जैसे एक ही श्रात्ना जन्म-जन्मांतरों में विकास पाती चली जा रही हो-शिधतन्त्रों की योनियों में होती हुई बुद्धत्व की पूर्णता तक । गांधी का हुदय समाज-सुधार की भावना से द्रविव है—हरिजनों की सेवा उन्हें प्रांतीय मन्त्रिमएडलों के निर्माण से ऋधिक प्रिय है। उनके व्यक्तिल की गहराई में हम श्रीर भी नीचे जायं तो उन्हें मृततः एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में पायंगे । गांधी, जिस राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं, यह प्राज हमारे जीवन के सभी श्रंगों में व्याप्त होगई है। कला श्रीर साहित में हम उसी का स्वंदन पाते हैं। वह खाज की भारतीय जनता को प्रेक्त करने याचे विचारों में सब से प्रमुख है। वह भारवर्ष के विभिन्न वर्गे और समझये मे

समन्वय की भावना उत्पन्न कर सका है। राष्ट्रीयता की इस प्रवल विचार-धारा का ही यह फल है कि अली-वंधु वर्षों तक महात्मा गांधी के साथ काम करते रहे, श्रीर आज भी सीमा-प्रांत के गांधी, मौलाना आज़ाद और दूसरे नेता देश के लिए वहें से वड़ा त्याग करने के लिए तत्पर हैं।

में यह जानता हूँ कि हमारा राष्ट्रीय त्रांदोलन निर्दोप नहीं है। मैं यह भी जानता हूँ कि वह सदा ही समाज-सुधार की प्रवृत्ति के साथ अपने की संबद्ध नहीं रख सका है। कई बार उसने ग्रापने की प्रतिक्रियावादी शक्तियों के हाथ का खिलौना वन जाने दिया है। प्रगतिशील शक्तियों को इससे हानि पहुँची है। मध्ययुग की प्रेरणात्रों से भी वह सर्वथा मुक्त नहीं है। सांप्रदायिक दृष्टि-कोण भी कभी-कभी उसकी दृष्टिको धुंधला बना देता है, पर इन सव किमयों के होते हुए भी हमारी राष्ट्रीयता त्र्याज के विश्व की एक स्वस्थ ऋौर सशक विचार-धारात्रों में से एक है। उसकी यह शिक्ष लगातार बढती जा. रही है। देश के सभी वर्गों, हिंदू ऋौर मुसल्मान, ग़रीव ऋौर ऋमीर, किसान श्रीर मज़दूर, श्रमजीवी श्रीर पूंजीपति, का सहयोग उसे प्राप्त है, श्रीर इस सहयोग की व्यापकता श्रीर गहराई, श्रीर उस सहयोग के पीछे त्याग का भाव ऋौर कप्ट-सहन की चमता,दिन-प्रति-दिन वहते जारहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय ऋांदोलन को मध्यकालीन प्रेरणात्र्यों त्र्यौर सामाजिक विषमतात्र्यों से मुक्त कर देने का त्रांतरिक प्रयत्न भी त्रपने पूरे वेग पर है—हमारी राष्ट्रीयता दमन की लपटों में पड़कर कुन्दन की तरह निखरती रही है। ऐसी दशा में मैं निश्चय के साथ यह कह सकता हूँ कि ग्रापनी सब किमयों के बावजूद भी, ग्रीर उनसे ग्रापना संघर्ष कायम रखते हुए त्र्याज भारतीय राष्ट्रीयता ने इतनी शक्ति त्र्यौर इतनी चमता स्रवश्य संग्रहीत करली है कि यदि देश के शासन का उत्तरदायित्व उसे सौंप दिया जाय तो वह पूर्ण प्रजातन्त्र के सिद्धांतों पर सफलता पूर्वक उसका संचालन कर सकेगी।

भारतीय राजनीति के प्रमुख तत्व

पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न राजनैतिक चेत्रों में यह विश्वास फैलता जा रहा था कि देश की राजनैतिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रजातंत्र शासन को ही हमारे राजनैतिक विकास का एकमात्र रास्ता मान लेना शायद टीक न हो। हमारे वैधानिक विकास की निरर्थकता श्रौर वैधानिक प्रगति के साथ-साथ श्रापसी मतभेदों के लगातार वढते जाने से इस धारणा को ऋधिक वल मिल गया है। बहुत कम न्यिक्त उन विरोधी शिक्तियों से, जो हमारे वैधानिक विकास के पीछे काम करती रही हैं, परिचित थे, ऋौर बहुत कम लोगों ने यह सोचा कि यदि हम किसी प्रकार के प्रजातन्त्र शासन की स्थापना ऋपने देश में नहीं करना चाहते. स्रीर यदि प्रजावाद हमारे लिए हितकर नहीं है, तो तानाशाही श्रथवा इसी प्रकार का ऋन्य कोई शासन-तन्त्र हमारी विभिन्त राजनैतिक समस्यार्थ्या को किस प्रकार एक सफल समाधान की दिशा में ले जा सकेगा । इसी वीच, वर्त्तमान महायुद के ब्रारम्भ होने के बाद से, ब्रौर विशेषकर जब से हमारी राष्ट्रीयता की वास्तविक शिक्त का कुछ ग्रन्शज़ा हमारे साम्राज्यवादी शासक लगा सके, इंग्लैंड में एक संगठित स्रान्दोलन ही इस 'सिद्धान्त' को लेकर उठ खड़ा हन्ना कि भारतवर्प में प्रजातन्त्र की स्थापना करना उसकी प्राचीन संस्कृति,वर्त्तमान राजनीति श्रीर समस्त राष्ट्रीय मनोवृत्ति के विरुद्ध जाना है। इस सम्बन्ध में 'भारतवर्ष श्रीर प्रजातन्त्र' के लेखकद्वय सर जॉर्ज शूरटर व गाई विंट, ग्रीर 'भारतवर्ष की वैधानिक समस्या पर रिपोर्ट' के लेखक प्रो॰ सर रेजीनल्ड कृपलैंड का नाम सहज ही स्मरण हो श्राता है।

इस विचार-धारा को कृटनीति का जामा पहिनाने में हमारे भृतपूर्व भारत-मन्त्री मि॰ एमेरी ने तो कमाल ही हासिल कर लिया था। उन्होंने किस प्रकार उसे भारतवर्ष के वैधानिक विकास के मार्ग में एक स्थायी चट्टान के रूप में ला खड़ा किया, इसका कुछ अनुमान उनके असंख्य भाषणों में से एक अवदरण ने किया जा सकेगा। १६ नवम्यर १६४६ को मैंचेस्टर में 'भारतीय वैधानिक समस्या' पर योलते हुए मि॰ एमेरी ने कहा—''एक बात जो हम—धीर पहिले के अधिकांश भारतीय नेता भूल जाते हैं, वह यह है कि हमारे दंग का शासन-विधान एक ऐसे संयुक्त-समन्वित समाज में ही सफल हो सकता है जहां राज- नैतिक दल निश्चित सार्वजनिक समस्याश्रों को लेकर अपने मतमेदों को व्यक्त करते हों, ख्रोर उन्हें केन्द्र मान कर देश का व्यापक जन-समाज अपनी धारणाश्रों को बनाता ख्रोर बदलता रहता हो, परन्तु जीवन के मूल-सिद्धांतों अथवा मूल-विश्वासों के संबंध में कोई स्थायी वैपम्य न हो। दुर्भाग्यवश, ऐसी परिस्थितियां भारतवर्ष में, कम से कम ग्राज के मारतवर्ष में, मौजूद नहीं हैं।" इन प्रमुख लेखकों ख्रोर कूटनीतिज्ञों के ख्रतिरिक्त कुछ अन्य लेखक व अनुदार पत्रों के सम्वाददाता भी इसी ख्राशय के विचारों का प्रचार करने में लगे हैं, और क्योंकि वही आकर्षक और वैज्ञानिक भाषा में ये विचार पाटक के सामने ख्राते हैं, इनंका प्रभाव और भी भयंकर रूप में उसके मन पर पड़ता है।

प्रजातन्त्र शासन भारतवर्षं के लिए उपयुक्त नहीं है, इस विचार के फैलने में कुछ हमारी त्र्यांतरिक परिस्थिति, त्र्यौर कुछ त्र्यन्तर्राष्ट्रीय घटना-चक्र, से सहायता मिली । पिछले कुछ वपों, ग्रीर विशेष कर १६३७ के वाद से, हमारी सांप्रदा-यिक समस्या ने एक गम्भीर रूप ले लिया है । कांग्रेस द्वारा पदग्रहण किए जाने के कुछ ही महीनों के बाद मि॰ जिन्ना ने, लीग के लखनऊ ग्रिधिवेशन में इस वात की घोषणा की कि मसल्मान कांग्रेस से न तो ईमानदारी की आशा कर सकते थे श्रौर न भलमनसाहत की। मुस्लिम-लीग की शक्ति, श्रौर विरोध, लगातार बढते जा रहे थे। कांग्रेस के शासन के पहिले ६ महीनों में लीग की १७० नई शाखाएं खुल चुकी थीं, जिनमें ६० संयुक्त प्रांत में व ४० पंजाव में थीं, श्रीर केवल संयुक्त-पांत में ही एक लाख से श्रिधिक सदस्य वन चुके थे। कांग्रेस के पदरयाग करने पर लीग ने देश भर में एक 'मुक्ति-दिवस' मनाने का श्रायोजन किया, श्रीर उसके कुछ हो महीने बाद उसने देश के बंटवारे की मांग सामने रखी। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के लिए जो हिंदू-मुस्लिम संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभृमि से परिचित न थे, यह धारणा वना लेना कि हमारे यहां प्रजातन्त्र के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है, सहज-स्वाभाविक था। उधर, ऋन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भी प्रजातन्त्र के प्राचीर ख्रीर दुर्ग एक-एक करके दह रहे थे। दो महायुद्धों के वीच प्रजातन्त्र के जिस विरोध ने जर्मनी में एक सशक कियात्मक रूप ले लिया था, सितम्बर १६३६ में उसका प्रताड़न-चक्र ग्रपने पूरे वेग में चल पड़ा था। पोलैएड, नॉर्वे, डेनमार्क, वेल्जियम, हॉलैएड, योरुप के छोटे-छोटे देश जिन्होंने प्रजातन्त्र की थाती को अपने प्राणों से सिमटा कर पीषित किया था, तानाशाही के थपेड़ों में चकनाच्र होते जारहे थे। फ्रांस का

१-एल॰ एस॰ एमेरी: India and Freedom, ए॰ ४०। २-प्रो॰ कृपलेंड: Indian Politics, 1936-42, ए॰ १८३। गौरवशाली साम्राज्य दो हफ्तों में धूल चाटने लगा था। इंग्लैएड पर विनाश के बादल मंडरा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में प्रजातन्त्र में लोगों का विश्वास यदि डिग उठा था तो उसमें ऋाश्चर्य ही क्या था? महायुद्ध की प्राथमिक घटनाऋों से प्रत्येक देश में प्रजातन्त्र की श्रेष्ठता में जनता का जो विश्वास दृढ़तर होता जा रहा था, उसमें एक गहरी ठेस लगी। भारतीय परिस्थितियों का प्रभाव जैसे विदेशी चिन्तन की एक धारा-विशेष पर पड़ा बैसे ही ऋन्तर्राष्ट्रीय घटनाऋों का प्रभाव भारतीय विचार-धाराऋों पर पड़ना भी ऋनिवार्य था।

हमारे राजनैतिक दल : कांग्रेस

सबसे प्रमुख दलील जो प्रायः इस धारणा का समर्थन करने के लिए दी जाती है कि प्रजातन्त्र भारतवर्ष के लिए अनुपयुक्त है, वह यह है कि हमारे राजनैतिक दल अपने संगठन व आदशों में पिर्चम के राजनैतिक दलों से विल्कुल भिन्न हैं। इस सम्बंध में सबसे बड़ी आलोचना जिस दल की की जाती है वह है हमारे देश की सबसे बड़ी राजनैतिक संस्था—कांग्रेस। कांग्रेस के सम्बंध में प्रायः यह कहा जाता है कि वह विभिन्न समूहों व समुदायों का संग्रह-मात्र है। उसके सामने कोई निश्चित आर्थिक अथवा राजनैतिक आदर्श नहीं हैं। 'भारतवर्ष और प्रजातंत्र' के लेखक-ह्य शूरूटर और विट के शब्दों में, उसमें ''करोड़पित और मज़दूर, ज़मींदार और किसान, संत और ठग, शिच्चक और अशिक्ति, गंवार और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विशारद, उदार विचारों वाले. कांतिकारी, समाजवादी, सन्यासी, कहर मुसल्मान और कड़िवादी हिंदू'' समी शामिल हैं, और ''अंग्रेज़ी शासन के प्रति घृणा ही इन सब परस्वर-विरोधी तत्त्वों को एक दूसरे के साथ संयोजित किए हुए है।"'

इन लेखकों के मतानुसार पार्लमेंटरी संस्थान्नों में कांग्रेस का विश्वास दिखावा-मात्र है । जब तक पार्लमेंटरी संस्थान्नों में उसका बहुमत सुरिहत है, तभी तक कांग्रेस उनका समर्थन करेगी । यदि परिस्थितियां बदल गई तो वह उन्हें दुकरा देगी । इसके समर्थन में कहा जाता है कि द्यपने द्यांतिरक मामलों में कांग्रेस एक छोटे समूह के संपूर्ण नियंत्रण में है, जो उस पर स्वेच्छाचारिता से शासन करता है । इस संबंध में १६३६ की श्री० सुभाप बोस के चुनाव की घटना ही बार-बार दोहराई जाती है । यह भी कांग्रेस की फ़ासिस्ट मनोहिन का ही परि-चायक माना जाता है कि उसने द्याने प्रांतीय शासन के दिनों में एक द्योर तो देशी राज्यों में राजनैतिक द्यसंतीप को उकताया, चौर दूसरी द्योर मुक्तिम जनता से सीधा संपर्क स्थापित करके मुख्लिम लोग को एक्स करना चाहा । यह

१—गुस्टर धौर विंट : India and Democracy, ३० ९६६

इमारी राजनैतिक समस्याएं

नैतिक दल निश्चित सार्वजनिक समस्याश्रों को लेकर श्रपने मतमेदों को व्यक्त करते हों, श्रौर उन्हें केन्द्र मान कर देश का व्यापक जन-समाज श्रपनी धारणाश्रों को बनाता श्रौर बदलता रहता हो, परन्तु जीवन के मूल-सिद्धांतों श्रथवा मूल-विश्वासों के संबंध में कोई स्थायी वैषम्य न हो । दुर्भाग्यवश, ऐसी परिस्थितियां भारतवर्ष में, कम से कम श्राज के मारतवर्ष में, मौजूद नहीं हैं।" इन प्रमुख लेखकों श्रौर कूटनीतिशों के श्रातिरिक्त कुछ श्रन्य लेखक व श्रनुदार पत्रों के सम्वाददाता भी इसी श्राशय के विचारों का प्रचार करने में लगे हैं, श्रौर क्योंकि बड़ी श्राकर्षक श्रौर वैश्वानिक भाषा में ये विचार पाटक के सामने श्राते हैं, इनंका प्रभाव श्रौर भी भयंकर रूप में उसके मन पर पड़ता है।

प्रजातन्त्र शासन भारतवर्ष के लिए उपयुक्त नहीं है, इस विचार के फैलने में कुछ हमारी त्रांतरिक परिस्थिति, त्रीर कुछ त्रान्तर्राष्ट्रीय घटना-चक्र, से सहायता मिली । पिछले कुछ वपीं, ग्रीर विशेष कर १६३७ के वाद से, हमारी सांप्रदा-यिक समस्या ने एक गम्भीर रूप ले लिया है । कांग्रेस द्वारा पदग्रहण किए जाने के कुछ ही महीनों के बाद मि॰ जिन्ना ने, लीग के लखनऊ ग्रिधिवेशन में इस वात की घोषणा की कि ससल्मान कांग्रेस से न तो ईमानदारी की आशा कर सकते थे श्रौर न भलमनसाहत की। मुस्लिम-लीग की शक्ति, श्रौर विरोध, लगातार बढते जा रहे थे। कांग्रेस के शासन के पहिले ६ महीनों में लीग की १७० नई शाखाएं खुल चुकी थीं, जिनमें ६० संयुक्त प्रांत में व ४० पंजाब में थीं, श्रीर केवल संयुक्त-पांत में ही एक लाख से श्रिधक सदस्य वन चुके थे। कांग्रेस के पदत्याग करने पर लीग ने देश भर में एक 'मुक्ति-दिवस' मनाने का श्रायोजन किया, श्रीर उसके कुछ हो महीने बाद उसने देश के बंटवारे की मांग सामने रखी। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के लिए जो हिंद-मुस्लिम संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभृमि से परिचित न थे, यह धारणा बना लेना कि हमारे यहां प्रजातन्त्र के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है, सहज-स्वाभाविक था। उधर, ग्रन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भी प्रजातन्त्र के प्राचीर ग्र्रीर दुर्ग एक-एक करके दह रहे थे। दो महायुद्धों के बीच प्रजातन्त्र के जिस विरोध ने जर्मनी में एक सशाक कियात्मक रूप ले लिया था, सितम्बर १६३६ में उसका प्रताड़न-चक ग्रापने पूरे वेग में चल पड़ा था। पोलैएड, नॉवें, डेनमार्क, वेल्जियम, हॉलैएड, योरुप के छोटे-छोटे देश जिन्होंने प्रजातन्त्र की थाती को अपने प्राणों से सिमटा कर पोपित किया था, तानाशाही के थपेड़ों में चकनाच्र होते जारहे थे। फ्रांस का

१-एत॰ एस॰ एमेरी: India and Freedom, ए॰ ४७। २-प्रो॰ कृपलैंड: Indian Politics, 1936-42, ए॰ १८३। गौरवशाली साम्राज्य दो हफ्तों में धूल चाटने लगा था। इंग्लैएड पर विनाश के वादल मंडरा रहे थे। ऐसी परिस्थित में प्रजातन्त्र में लोगों का विश्वास यदि डिग उटा था तो उसमें त्राश्चर्य ही क्या था ! महायुद्ध की प्राथमिक घटनात्रों से प्रत्येक देश में प्रजातन्त्र की श्रेण्टता में जनता का जो विश्वास दृढ़तर होता जा रहा था, उसमें एक गहरी ठेस लगी। भारतीय परिस्थितियों का प्रभाव जैसे विदेशी चिन्तन की एक धारा-विशेष पर पड़ा वैसे ही त्रान्वर्राष्ट्रीय घटनात्रों का प्रभाव भारतीय विचार-धारात्रों पर पड़ना भी त्रानिवार्य था।

हमारे राजनैतिक दल: कांग्रेस

सबसे प्रमुख दलील जो प्रायः इस धारणा का समर्थन करने के लिए दी जाती है कि प्रजातन्त्र भारतवर्ष के लिए अनुपयुक्त है, वह यह है कि हमारे राजनैतिक दल अपने संगठन व आदशों में पश्चिम के राजनैतिक दलों से विल्कुल भिन्न हैं। इस सम्बंध में सबसे बड़ी आलोचना जिस दल की की जाती है वह है हमारे देश की सबसे बड़ी राजनैतिक संस्था—कांग्रेस। कांग्रेस के सम्बंध में प्रायः यह कहा जाता है कि वह विभिन्न समूहों व समुदायों का संग्रह-मात्र है। उसके सामने कोई निश्चित आर्थिक अथवा राजनैतिक आदर्श नहीं हैं। 'भारतवर्ष और प्रजातंत्र' के लेखक-द्वय श्रस्टर और विट के शब्दों में, उसमें ''करोड़पित और मज़दूर, ज़मींदार और किसान, संत और ठग, शिच्चक और अशिचित, गंवार और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विशारद, उदार विचारों वाले, कांतिकारी, समाजवादी, सन्यासी, किटर मुसल्मान और रूढ़िवादी हिंदू'' समी शामिल हें, और ''अंग्रेज़ी शासन के प्रति घृणा ही इन सब परस्पर-विरोधी तन्त्रों को एक दूसरे के साथ संयोजित किए हुए है।"'

इन लेखकों के मतानुसार पार्लमेंटरी संस्थात्रों में कांग्रेस का विश्वास दिखावा-मात्र है। जब तक पार्लमेंटरी संस्थात्रों में उसका वहुमत सुरित्तत है, तभी तक कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। यदि परिस्थितियां वदल गई तो वह उन्हें उकरा देगी। इसके समर्थन में कहा जाता है कि अपने आंतरिक मामलों में कांग्रेस एक छोटे समूह के संपूर्ण नियंत्रण में है, जो उस पर स्वेच्छाचारिता से शासन करता है। इस संबंध में १६३६ की श्री० सुभाष बोस के चुनाव की घटना ही वार-वार दोहराई जाती है। यह भी कांग्रेस की फ़ासिस्ट मनोवृत्ति का ही परि-चायक माना जाता है कि उसने अपने प्रांतीय शासन के दिनों में एक ग्रोर तो देशी राज्यों में राजनैतिक असंतोष को उकसाया, और दूसरी ओर मुस्लिम जनता से सीधा संवर्ष स्थापित करके मुस्लिम-लीग को ख़त्म करना चाहा। यह

१—गुस्टर और विंट : India and Democracy, पृ० १६६

भी कहा जाता है कि पद-ग्रहण के दिनों में काग्रेस-मंत्रिमण्डल ग्रापने चेंत्र के डिक्टेंग्र के प्रति ग्राधिक उत्तरदायी थे, प्रांतीय धारासभा के प्रति कम। इन लोगों ने तो यह कहने में भी कसर नहीं रखी कि ग्रापने शासन-काल में कांग्रेस एक ऐसे पड्यन्त्र में लगी हुई थी जिसका उद्देश्य राज्य को पार्टी के ग्राधीन ले ग्राना था। ये सब दलील कुछ इस ढंग से पेश की जाती हैं कि वे इस परिणाम पर जैसे ग्रापने ग्राप ही पहुंच रही हों कि जब तक कांग्रेस है हिन्दु-स्तान में प्रजातन्त्र-शासन कभी सफल नहीं हो सकता।

कांत्रेस का विधान : एक दृष्टि में

सबसे पहिले कांग्रेस के विधान के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना ज़रूरी है। कांग्रेस के विधान का मूल-भृत सिद्धान्त 'प्रजातन्त्रारमक केन्द्रीकरण' (Democratic Centralisation) कहा जा सकता है। स्थानीय सदस्य ज़िला-कमैटी का चुनाव करते हैं; ज़िला-कमैटियां प्रान्तीय कांग्रेस-कमैटी के सदस्यों को चुनती हैं: प्रान्तीय कांग्रेस-कमैटियां ऋखिल-भारतीय कांग्रेस-कमैटी का निर्माण करती हैं। सभापति का चुनाव साधारण सदस्यों द्वारा होता है। प्रो॰ कृपलैएड ने कार्य-सिमिति की नियुक्ति के तरीक़े को कांग्रेस की ग्र-प्रजातन्त्रीय प्रवृत्ति का एक उदाहरण वताया है १६३६ तक कार्य-समिति अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमैटी द्वारा चुनी जाती थी। तत्र से उसे नियुक्त करने का भार सभापति पर है । इस परिवर्त्तन को हम किसी प्रकार भी ऋ-प्रजातन्त्रीय नहीं कह सकते । प्रायः सभी प्रजातनत्र-देशों में मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति का ऋधिकार प्रधान को ही रहता है। अमरीका में प्रेज़ीडेंट अपने सब मन्त्रियों को नियक्त करता है। इंग्लैंड में इस काम की ज़िम्मेदारी प्रधान-मन्त्री पर है। इस सम्बन्ध में हमारे यहां कुछ स्वस्थ परम्पराएं (Conventions) भी वन गई हैं । कार्य-समिति में देश के चुने हुए नेता रहते हैं, श्रीर साथ ही इस वात का ध्यान भी रखा जाता है कि सब प्रान्तों का समन्वित प्रतिनिधित्व हो सके ।

कांग्रेस और गांधीजी

. एक दूसरा श्राच्चेप कांग्रेस में गांधीजी की श्र-वैधानिक, श्रथवा विधान से ऊपर की, स्थिति के सम्बन्ध में किया जाता है। जैसा कि सब जानते हैं, गांधीजी कांग्रेस के चार-श्राना सदस्य भी नहीं हैं, कांग्रेस में वपों से उन्होंने कोई पद-ग्रहण नहीं किया, पर कांग्रेस शायद ही कभी उनके समर्थन के विना किसी महत्त्व-पूर्ण निर्णय पर पहुंची हो। क्या यह कांग्रेस की तानाशाही प्रवृत्ति का एक श्रव्छा उदाहरण नहीं है? यदि हम वस्तुस्थिति का विश्लेपण करें तो हम देख सकेंगे कि कांग्रेस पर गांधीजी का प्रभाव किसी ऐसे शक्तिशाली दल के द्वारा नहीं

है जिसकी सृष्टि ग्रौर जिसका सङ्गठन उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही भीतर कर जिया हो। कांग्रेस पर उनके शासन का गुख्य कारण है भारतीय जनता के हृदयों पर उनका शासन —ग्रौर यदि कांग्रेस उनकी सलाह को मान्यता देती है तो इसिलए कि वह उसमें जनता की ग्राकांचाग्रों की ग्राभव्यिक पाती है। गांधी ने कांग्रेस को ग्रारामतलय राजनीतिशों की सभा से एक लड़ाकू संस्था के रूप में परिणत किया। गांधी ने हमारी प्रसुप्त जनता में राष्ट्रीयता की चेतना का प्रसार किया। गांधी ने ही हमें एक नई ग्राशा ग्रौर एक नया दृष्टिकोण दिया। कांग्रेस यदि एक ऐसे व्यक्ति की सलाह के ग्रानुसार काम करती है तो इसमें ग्राश्चर्य नहीं होना चाहिये: वैसे तो ऐसे उदाहरण भी कम नहीं हैं जब कांग्रेस ने गांधी जी के ग्रादेश पर चलने में ग्राप्ने को ग्रासमर्थ पाया।

साथ ही हमें यह भी न भूलना चाहिए कि कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभाव दो प्रकार का है। साधारणतः तो वह कांग्रेस के कायों के संचालन से अपने को दूर ही रखते हैं। १६३४ में जब गांधी जी ने देखा कि उनका प्रभाव कांग्रेस में अन्य विचार-धाराओं के विकास में वाधक है उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। १६४४ में जेल से छूटने के बाद कांग्रेस के कार्य-संचालन में वह उस समय तक मार्ग-निर्देश करते रहे जब तक कि राष्ट्रपति व कार्यसमिति के सदस्य जेल में थे। उनके बाहर आते ही गांधी जी ने राजनैतिक कार्यों से तटस्थता धारण करली। शिमला-कांग्रेस में भी वह एक तटस्थ की हैसियत से ही मौजूद थे। पर, विशेष मौकों पर, जब किसी राजनैतिक आन्दोलन का संचालन करना होता हैं, गांधी जी कांग्रेस की संपूर्ण-सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। युद्ध में स्वभावतः ही प्रजातन्त्र का रूप बदल जाता है। सिपाहियों को तो सेनानायक के इशारे पर ही चलना पड़ता है। उसका शब्द ही उनके लिए कान्त्र है। इस कारण कांग्रेस यदि आंदोलनों का संचालन गांधी जी के एकाकी नेतृत्व में सौंपकर अपने को उनके आदेशों के आधीन बना लेती है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो प्रजातन्त्र की भावना के विरुद्ध जाती हो।

शिक का केन्द्रीकरण

कांग्रेस पर जो दो अन्य बड़े आचेप लगाए जाते हैं, वह हैं—शिक्त का केन्द्रीकरण और सर्वहर प्रवृत्ति (totalitarianism)। पिहले आचेप का मुख्य आधार कांग्रेस के 'हाई कमाण्ड' द्वारा शासन के सब अधिकारों का अपने हाथ में केन्द्रित रखना है। कांग्रेस के आलोचकों को इस बात का दुःख है कि एक ऐसे समय जब कि संघ-शासन का प्रयोग इस देश में किया जारहा था, और प्रांतों को पहिलो बार स्वायत्त-शासन प्राप्त हुआ था, कांग्रेस ने सब प्रांतों की शासन-सत्ता एक पार्लमेंटरी सव-कमेटी के हाथ में केन्द्रित करके उसके समुचित विकास में वाधा डाली । इस सम्बन्ध में हम यह न भूलें कि पार्लमेएटरी
सव-कमेटी की नियुक्ति कुछ ग्रसाधारण पिरिश्वितयों को ध्यान में रखते हुए की
गई थी । साधारणतः यह विश्वास किया जाता था—ग्रौर ग्रंग्रेज़ी शासन के
पिछले इतिहास को देखते हुए यह विश्वास न किया जाता तो ग्राश्चर्य होता-कि
१६३५ की योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना को भङ्ग करना ग्रौर
प्रांतीयता को प्रोत्साहन देना था । देश की ग्राज़ादी के लिए सतत, प्रयत्नशील
कांग्रेस जैसी संस्था के लिए इस प्रवृत्ति से संघर्ष करना ज़रूरी था । वह प्रांतीयता
के विषेले प्रभाव को ग्रवाधगित से कैसे वढ़ने दे सकती थी ? साथ ही यह भय भी
था कि प्रांतीय मंत्रि-मएडलों को मुक्त, निर्वन्ध, रखा गया तो वे कहीं पार्लमेएटरी
शासन की गुत्थियों में एक वड़े ग्रादर्श को ग्रपनी दृष्टि से ग्रोभल न कर वैठें।

यह कहा जा सकता है कि इस केन्द्रीकरण के मुख्य कारण चाहे कुछ मी क्यों न हों उसका प्रभाव यह पड़ा कि मन्त्रियों में धारा-सभाग्रों के प्रति उत्तर-दायित्व की भावना का, जो प्रजातन्त्र-शासन का मुख्य श्राधार है, समुचित विकास नहीं हो सका । मन्त्रिमएडल ग्रपने ग्रापको धारा-सभाग्रों व उनके चुनने वाले मत-दातात्रों के प्रति उतना उत्तरदायी नहीं मानते थे जितना कांग्रेस के 'हाई कमाएड' के प्रति । इससे प्रान्तीय शासन में एक परोक्त ख्रौर ख्र-वैधानिक सत्ता का प्राधान्य होगया । पर, इस सम्बन्ध में भी कांग्रेस के ऋालोचक यह भूल जाते हैं कि प्रांतीय व केन्द्रीय राजनीति पर इस प्रकार का 'राष्ट्रीय' नियन्त्रण प्रायः प्रत्येक देश में पाया जाता है । प्रांतीय चेत्रों में भी उम्मीदवार साधारणतः श्रिष्विल राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा ही खड़े किये जाते हैं, श्रीर जो लोग उनके पत्त में अपना मत देते हैं, वे प्रधानतः राजनैतिक दल को ही अपना मत देते हैं और केवल गौगा-रूप से चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति को । यह बात संसार के सभी प्रजातन्त्र-देशों में पाई जाती है। हमारे देश में तो इस प्रवृत्ति के विकास के लिए श्रीर भी गुंजाइश थी। यहां प्रांतों द्वारा शासन-श्रिधकार प्राप्त किये जाने से बहुत पहले ही त्र्राखिल-भारतीय राजनैतिक दल स्थापित होचुके थे। एक या दो शुद्ध मांतीय राजनैतिक दलों को छोड़कर हमारे सब राजनैतिक दलों का कार्यचेत्र देश -व्यापी है। कांग्रेस के सम्बन्ध में तो संसार के किसी भी राजनैतिक दल की तुलना में यह वात ग्रौर भी ग्राधिक सच है कि जनता ने किसी व्यक्ति को नहीं, पर कांग्रेस अौर उसके कार्यक्रम के लिए अपना मत दिया था। इस कारण कांग्रेस ही देश की समस्त प्रजा के प्रति ज़िम्मेदार थी। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल सीधे मतदातात्रों के प्रति ज़िम्मेदार नहीं थे।

सर्वहर प्रवृत्ति (Totalitarianism)

कांग्रेस पर सर्वहर (totalitarianism) होने का जो स्राचिप लगाया जाता है, वह सचमुच यड़ा मनोरज्ञक है। इस सम्बन्ध में जो सबसे वड़ा प्रमाण दिया जाता है वह है कांग्रेसी पांतों स्रोर ग़ैर-कांग्रेसी पांतों में मन्त्र-मण्डलों के निर्माण की नीति का स्रन्तर। कांग्रेस ने मिश्रित मन्त्रि-मण्डल बनाने से इन्कार कर दिया था, स्रोर क्योंकि कांग्रेस के बहुमत खो देने की सम्भावना नहीं थी, उसके मन्त्रिमन्डल स्थायी थे। दूसरी स्रोर, पंजाय को छोड़कर, सभी ग़ैर-कांग्रेसी प्रांतों में मिश्रित मन्त्रिमण्डल थे, स्रोर सत्ता का स्राधार रोज़-रोज़ बदलता रहता था। यह है कांग्रेस के सर्वहर होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण ! क्यू क्लैंग्ड की राय में ग़ैर-कांग्रेसी प्रांतों के शासन में (जहां मन्त्रिमण्डल प्रायः गर्वनर के हाथों में कठपुतली के समान नाचते थे) प्रजातन्त्र की भावना की स्राधिक रज्ञा हो सकी। इस विचार के पीछे यह शरारत मरा सुकाव भी है कि कांग्रेस ने स्रल्प-संख्यक दलों के प्रांत उपेत्ता की भावना रखी, जबिक दूसरे मन्त्रिमण्डलों ने स्रल्प-संख्यक दलों को स्रापने साथ लेकर उनके प्रति स्रपनी शुमेच्छा का प्रदर्शन किया।

कांग्रेस के सर्वहर होने के पत्त में श्रीर भी बहुत से प्रमाण दिये जाते हैं। मो० कृपलैंगड का कहना है कि सरकारी व म्युनिसिपल इमारतों पर राष्ट्रीय फंडे लगाने में भी कांग्रेस का उद्देश्य यही था कि वह दूसरी जातियों की भावना को ठेस पहुंचाये। इसी प्रकार, कहा जाता है, कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत के नाम पर एक ऐसे गीत को सरकारी प्रश्रय दिया जो संस्कृत शब्दों श्रीर हिन्दू धार्मिक भावनात्रों से भरा हुन्ना था । संस्कृतमयी हिन्दी का प्रचार भी कांग्रेस के सर्वहर होने का एक प्रमाण है। प्रो० कृपलेंग्ड का विश्वास है कि कांग्रेस ने विद्या-मन्दिर-योजना को अपना समर्थन देकर साम्प्रदायिकता की इस नीति को अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। सच तो यह है कि कांग्रेस के खिलाफ बुरे से बुरे इलज़ाम लगाने में प्रो॰ कृपलैएड तिनक भी नहीं किसके हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ग्राम-सुधार की योजना के पीछे भी कांग्रेस का उद्देश्य यही था कि वह गांवों में अपनी शिक्त की जड़ों को मज़वूती से जमा ले। कांग्रेस के प्रति प्रो॰ कूपलैएड का विद्वेष श्रौचित्य श्रौर मनुष्यता की सभी सीमाश्रों को पार कर जाता है जब वह त्रापने त्रांग्रेज़ पाठकों के सामने बड़े निश्चय के साथ यह वात रखते हैं कि कांग्रेस अपने शासन-काल में चुपचाप अपनी एक अलहदा फ़ौज खड़ी करने के काम में लगी हुई थी, श्रीर इसके साथ ही साथ श्रॉक्स-फ़ोर्ड के यह विद्वान प्रोफ़ेंसर अपने सहमें हुए पाठक-वर्ग के सामने जर्मनी अौर

इटली की उस भयंकर स्थिति का विषद चित्र भी खींच देते हैं, जो वहां पर इस प्रकार की ग्राथकचरी सेनाग्रों के संगटित किये जाने से उपस्थित हो गई थी।

इनमें से वहत से इलज़ाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा करना भी समय नए करना है। यहां कुछ थोड़ी-सी वातों को लिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि कांग्रेस विभिन्न जातियों की भावनात्रों को कुचलने के स्थान पर उन्हें ग्राधिक से ऋधिक सन्तुष्ट करने के प्रयत्न में लगी रही। कांग्रेस का भांडा कांग्रेस-द्वारा पद-ग्रहरा करने के वर्षों पहले से-यह कहना चाहिए कि राष्टीय ग्रान्दोलन के कियात्मकरूप लेने के समय से ही-मौज़द था। परन्त जब कांग्रेस ने देखा कि कुछ वगों की ग्रोर से उसका विशेष किया जा रहा है तो उसने ग्रन्य राजनैतिक दलों को भी कांग्रेस के भांडे के साथ अपना भांडा लगाने की इजाज़त दे दी, थ्रीर उन दिनों कभी-कभी तो एक ही इमारत पर एक साथ चार या पांच **फं**डे लहराते नज़र खाते थे। जर्मनी, इटली, या स्वयं इंग्लैएड या ख्रमरीका में भी, क्या ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है ? इसी प्रकार, जहां तक राष्ट्रीय-गीत का सम्बन्ध है, कांग्रेस को ब्रारम्भ में तो ध्यान भी नहीं था कि वन्देमातरम्' का विरोध होगा। वर्षों से वड़े से वड़े मुसल्मान नेता उसके प्रते ग्रापना ग्रादर व्यक्त करते रहे थे। परन्त जब कांग्रेस ने देखा कि उसका विरोध किया जा रहा है तो उसने पहले तो यह निश्चय किया कि उसके केवल पहले दो पद—जिनमें किसी प्रकार की साम्प्रदायिक भावना का स्वर्श भी नहीं था-गाये जायं ग्रौर वाद में उसे विलक्कल ही वन्द कर दिया । इसी प्रकार जहां तक कांग्रेस की भापा-सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है, यह तो भारतीय राजनीति से जो व्यक्ति थोड़ा भी परिचित है वह जानता है कि कांग्रेस ने कभी संस्कृत प्रधान भाषा के प्रचार का प्रयत्न नहीं किया । कांग्रेष का उद्देश्य हिन्दुस्तानी ग्रथवा एक ऐसी भाषा का प्रचार था जिसमें हिंदी श्रीर उर्द् के सरल श्रीर सर्वसाधारण में वोले जाने वाले शब्दों का प्रयोग होता हो। यहां हमें यह भी भूल नहीं जाना चाहिए कि कांग्रेस ने हिंदी या हिन्दुस्तानी के प्रचार की दिशा में ठोस काम केवल मद्रास में किया, जहां मुसल्मानों की संख्या बहुत कम है, ग्रौर वहां पर भी हिंदी के प्रचार का विरोध मुसल्मानों की ग्रोर से नहीं विलक ग्र-ब्राह्मणु जिस्टस पार्टी की त्रोर से हुत्रा, ग्रीर उस विरोध के कारण विशुद्ध राजनैतिक थे।

कांग्रेस के विरुद्ध प्रायः यह दोप लगाया जाता है कि उसने उन प्रांतों में, जिनमें उसका बहुमत था, ग्रापने मन्त्रिमण्डलों में कांग्रेस के ग्रातिरिक्त किसी ग्रान्य संस्था के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया। इस सम्बन्ध में हमें कुछ वातें ग्रापने ज्यान में रखनी हैं। पहली बात तो यह है कि उन सब देशों में, जहां प्रजातन्त्र-शासन है, श्रिधिकांश में वही राजनैतिक दल श्रपना मन्त्रिमण्डल वनाता है जिसका चुनाव में बहुमत रहा हो, श्रीर इस मन्त्रिमएडल में उसी दल के प्रमुख व्यक्ति रहते हैं। उदाहरण के लिए, इग्लैंड में यदि 'लेबर' पार्टी को वहमत प्राप्त हो, या ग्रमरीका में प्रेज़ीडेन्ट 'रिपब्लिकन' पार्टी में से चुना जाय, तो वे मन्त्रिमण्डल में केवल ग्रापने ही दल के व्यक्तियों को स्थान देंगे, 'कंजवेंटिव' या 'डेमाकोटक'या किसी अन्य दल के व्यक्तियों को निमन्त्रित नहीं करेंगे। जेनिंग्स ने ग्रपनी 'ग्रंगेज़ी शासन-विधान' नाम की पुस्तक में इस पद्धति का समर्थन करते हुए लिखा है कि "इससे एक स्थायी सरकार का निर्माण होता है। सरकार 'हाउस त्रॉफ़ कामन्स' के बहुमत के प्रति उत्तरदायी होती है, स्त्रीर उसका नेतृत्व भी करती है। सरकार ग्रपने प्रस्तावों के स्वीकृत किये जाने की ग्राशा रखती है। वह अपने दल के बहुमत पर उस समय तक निर्भर रह सकती है, जब तक कि वह उसके सिद्धांतों के विल्कुल ही ख़िलाफ़ कुछ न कर रही हो। (इसका परिगाम यह होता है कि) वह कम समय में ग्रीर विश्वास के साथ काम कर सकती है, क्योंकि वह जानती है कि उसे ऋावश्यक समर्थन प्राप्त है। ये बहुत बड़े लाभ हैं..... श्रल्य-संख्यक दलों की सरकार सदा कमज़ोर होती है, क्योंकि वह शासन कर ही नहीं सकती। मिश्रित सरकारें साधारणतः कमज़ोर होती हैं, क्योंकि उनमें ग्रापसी मतभेद बहुत श्रधिक रहता हैं।""

प्रजातन्त्र-देशों में मिश्रित मिन्त्रमण्डल किसी अभ्तप् व परिस्थित का मुकाविला करने के लिए ही बनाये जाते हैं, और उस विशेष परिस्थित का अन्त
होने के साथ ही वह समाप्त कर दिये जाते हैं— इंग्लैएड में महायुद्ध को सफलता
से चलाने की दृष्टि से एक सर्व दल सरकार का निर्माण हुआ था, पर जर्मनी के
हथियार डालते ही दुवारा चुनाय हुए और एक दल की सरकार बन गई।
१६३७ में हमारे देश के सामने कोई ऐसी असाधारण राजनैतिक परिस्थिति नहीं
थी, जिसके कारण मिश्रित-मिन्त्रमण्डलों का निर्माण आवश्यक माना जाता।
प्रत्युत, उस समय तो परिस्थितियों का तक्काज़ा यही था कि एक दल वाले सशक
मिन्त्रमण्डल बनाये जायं। कांग्रेस का ध्येय अंग्रेज़ गवर्नर और नौकरशाही
के अनिच्छुक हाथों से सत्ता छीनना था। ऐसी स्थिति में संयुक्त मोर्चे की ज़रूरत थी, और वह मिश्रित मिन्त्रमण्डलों द्वारा संगठित नहीं किया जा सकता था।
कांग्रेस द्वारा मिश्रित मिन्त्रमण्डल बनाने की नीति के विरोध का यही मुख्य
कारण था। कांग्रेस के मन में अल्प-संख्यक वर्गों के प्रति उपेन्ना का भाव
विनक भी नहीं था। कांग्रेस का तो सभी वर्गों की प्रतिनिधि-संस्था होने का सदा
१-जेनिंग्स: The British Constitution, १० ६३।

से दावा रहा है। कांग्रेस के शासन काल में प्रायः प्रत्येक प्रांत के मिन्त्रमण्डल में मुसल्मान लिये गए थे। उसकी पालंमेंटरी कमेटी के समापित व संयोजक मी॰ ग्राज़ाद थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने यदि ग्रापने. मिन्त्रमण्डल वनाने में ग्रान्य पालंमेण्टरी देशों की पद्धित को ग्रापनाया, ग्रीर ग्रान्य दलों के प्रतिनिधियों को ग्रापने मिन्त्रमण्डलों में शामिल नहीं किया, तो इसमें ग्राल्पसंख्यक वगों के प्रति उपेन्ता की मावना हुं द निकालना बहुत ही हल्के दंग का ग्रान्तेष हैं।

त्राज तो मैं चारों त्रोर वैधानिक पिडतों को यह कहते हुए सुनता हूं कि १६३७ में कांग्रेस ने मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधियों को मन्त्रिमएडलों में न लेकर एक वहत वड़ी ग़लती की । मैं जानता हूँ कि ज्ञाज परिस्थिति वदल गई है । त्राज मुस्लिम-लीग इतनी शिक्तशाली वन गई है, श्रीर मुस्लिम हितों का इतना श्रिधिक प्रतिनिधित्व उसमें श्रागया है, कि श्राज की परिस्थिति में कांग्रेस के लिए केन्द्रीय व प्रांतीय दोनों शासनों में मस्लिम-लीग के साथ किसी प्रकार का सम-भौता कर लेना वांछित हो सकता है, वशर्त कि मुस्लिम'लीग इस सहयोग के लिए तैयार हो। ११६३७ में तो हमारे देश के राजनैतिक जीवन में मुस्लिम-लीग की कोई स्थिति थी है। नहीं । मुस्लिम-लीग द्वारा खड़े किये गए उम्मीदवारों में से जो सफल हुए उनकी संख्या प्रांतीय धारा-सभात्रों के कुल सदस्यों की केवल ४॥ फ़ीसदी ग्रौर मुसल्मान सदस्यों की ११ फ़ीसदी थी। किसी भी प्रांत में मुरिलम-लीग के प्रतिनिधियों का काम-चलाऊ बहुमत भी नहीं था। यदि पंजाब ऋौर बंगाल में मुसल्मान मन्त्रिमण्डल बनाये जा सके तो इसका कारण यूनियनिस्ट ग्रीर कृषक-प्रजा-पार्टी का बहुमत था । सर सिकन्दर हयात खां ग्रीर फज़लुल-हक्त दोनों लीग के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, ग्रीर उनके विरोध में ही जीते । सिंध में मिश्रित-मण्डल वना । उत्तर-पश्चिमी-सीमा-प्रांत में, जहां की प्रायः सारी त्र्यावादी मुसल्मान है, शुद्ध कांग्रेसी मन्त्रिमएडल वना । १६३७ में कांग्रेस मिश्रित मन्त्रिमण्डल वनाने की रिथित में थी या उसे ऐसा करना चाहिए था, यह कहना उस समय की गुजनैतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में श्रपना श्रज्ञान प्रगट करना है।

देशी-राज्यों के प्रति कांग्रेस की नीति

कांग्रेस के विरुद्ध, उस समय की नीति के सम्बंध में ही जो उसने पद-प्रहण् के दिनों में वरती, दो ग्रीर वड़े इल्ज़ाम लगाये जाते हैं। उनमें से एक यह है कि कांग्रेस ने ग्रापने दल की शांकि वढ़ाने के उद्देश्य से देशी राज्यों की प्रजा को

1-मुस्लिम-लीग के शिमला-कान्फ्रेस के खैंये से यह स्पष्ट हो गया है कि वह कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का समकीता करने के लिए तैयार नहीं है। उकसाया । देशी राज्यों के प्रति कांग्रेस द्वारा वस्ती जाने वाली नीति को देखते हुए इस दोपारोपण में ऋतिशयोक्ति दिखाई देती है। कांग्रेस तो देशी राज्यों के त्र्यांतरिक प्रश्नों में हस्तत्त्रेप करने से सदा वचती रही है। १६३४ में जब कांग्रेस के एक पत्त ने देशी राज्यों की राजनीति में कांग्रेस द्वारा अधिक इस्तत्तेप करने का प्रश्न उठाया था तो उस समय के सभापति डा॰ राजेन्द्रप्रसाद ने इस्तीफ़े की धमकी दी थी। १६३७ तक कांग्रेस तटस्थता की ज्रापनी इसी नीति पर जमी रही। परन्तु ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्त-शासन की स्थापना का प्रभाव देशी राज्यों पर पड़ना स्वाभाविक था । देशी राज्य श्रीर ब्रिटिश भारत भौगोलिक, सांस्कृतिक ग्रौर ग्रार्थिक दृष्टियों से इतने संवद्ध हैं कि उन्हें एक-दूसरे के प्रभाव से मुक्त रखा ही नहीं जा सकता । ब्रिटिश-भारत में प्रजातन्त्र-शासन की स्थापना के साथ-साथ देशी राज्यों में भी राजनैतिक स्वत्त्वों की मांग का प्रभाव-शाली वन जाना ऋनिवार्य था। इसी कारण १६३७ के वाद से ही हम देशी राज्यों में एक नवीन चेतना के चिह्न पाते हैं। कुछ में तो राजनैतिक स्रिधिकारों के लिए छोटे-मोटे सत्याग्रह त्र्यांदोलन भी उठ खड़े हुए थे। कांग्रेस ने इन राजनैतिक त्र्यांदोलनों में कभी कोई सीधा भाग नहीं लिया। वास्तविक कार्य इन्हीं राज्यों के प्रजा-मण्डल ऋ।दि ऋपनी स्थानीय संस्थास्त्रों द्वारा हुस्रा ।

यदि ब्रिटिश भारत के राजनीतिज्ञों ने देशी राज्यों की समस्यात्रों में कभी हस्तचें किया भी तो उन्हीं देशी राज्योंके ऋधिकारियों के निमंत्रण पर । राजकोट का ही उदाहरण लें । राजकोट के मामले में गांधी जी, ऋथवा वल्लभ भाई पटेल, स्वयं नहीं पड़े, परन्तु राज्य के अधिकारियों, स्वयं राजकोट के दीवान द्वारा, वल्लभ भाई पटेल से यह प्रार्थना की गई थी कि वह उनके आंतरिक मामलों के सुलकाने में सहायता दें । इसी प्रकार लिम्बड़ी-राज्य में भी राज्य के ऋधि-कारियों ने श्री मुन्शी को निमन्त्रित किया था। दोनों स्थानों पर समभौता न हो सकने का कारण यह था कि भारत-सरकार का राजनैतिक-विभाग यह नहीं चाहता था कि व्रिटिश भारत के राजनीतिज्ञ देशी राज्यों के मामलों में दख़लू दें। लार्ड लिनलिथगो ने भी जब गांधीजी के उपवास के ऋवसर पर हस्तद्वीप किया तो अपने राजनैतिक विभाग की सलाह के ख़िलाफ़ । दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखना है वह यह है कि इन दिनों स्त्रयं भारत-सरकार भी इस चात के लिए उत्मुक थी कि किसी प्रकार देशी राज्य अपनी मध्य-कालीन वानाशाही से वाहर निकल सकें, त्रौर त्रपने यहां कुछ वैधानिक सुधारों का प्रारम्भ करें। जहां तक इस नीति का सम्बंध था, कांग्रेस व भारत सरकार दोनों का ध्येय एक ही था। कांग्रेस ने देशी नरेशों के सार्वभौम अधिकारों का अतिकमण करने की कभी चेष्टा नहीं की।

मुस्लिम-जीग परं प्रहार

दूसरा वड़ा गम्भीर इल्ज़ाम जो कांग्रेस के इन दिनों के रवैये के वारे में लगाया जाता है, वह यह है कि कांग्रेस मुस्लिम-जनसाधारण से सीधा संपर्क स्थापित करके मुस्लिम-लीग की जहां को ही उखाड़ फेंकना चाहती थी। यह सच है कि कांग्रेस ने पद-ग्रहण करने के वाद ही मुस्लिम-जन-संपर्क द्यांदोलन का त्यारम्भ कर दिया, परन्तु इसमें कांग्रेस कोई नई वात नहीं करने जा रही थी। कांग्रेस तो पिछले पचास वपों से संपूर्ण मारतीय जनता का सचा प्रतिनिधित्व पा लेने के प्रयत्न में लगी हुई थी ग्रीर मुस्लिम-जनता का ग्राधिक से-ग्राधिक सहयोग पा लेना उसी प्रयत्न का एक भाग था। हमें यह वात स्वष्ट रूप के समभ लेनी चाहिए कि कांग्रेस त्यान जीवन-काल के ग्रारम्भ से ही एक दोहरे कार्यक्रम में लगी हुई है। एक त्यार तो वह त्रंग्रेज़ी साम्राज्यवाद को ख़त्म कर देने के प्रयत्न में जी-जान से जुटी है, ग्रीर दूसरी न्योर वह राष्ट्रीय त्यांदोलन को ग्राधिक से ग्राधिक व्यापक वना देना चाहती है। ग्रांग्रेज़ी साम्राज्यवाद से प्रायः प्रत्येक वड़ी टक्कर के वाद उसने ग्रावरिक सङ्गटन को सशक्त वनाने का प्रयत्न किया है। मुस्लिम-जन-संपर्क त्रांदोलन के वास्तविक उद्देश्यों को जानने के लिए हमें कांग्रेस-कार्यक्रम के इस पन्त को भी ध्यान में रखना है।

लीग की शक्ति के तेज़ी से बढ़ने से कांग्रेस अपने मुस्लिम-जन-संपर्क ब्रांदोलन की सफलता के सम्बन्ध में तो निराश होगई, पर इसका यह ब्रर्थ नहीं है कि वह अपने कर्तव्य के सीधे मार्ग से हट गई। अक्टवर १६३७ में कांग्रेस की वर्किङ्क कमेटी ने श्रापने कलकत्ता-श्राधिवेशन में यह विल्कल स्पष्ट कर दिया था कि वह अल्पसंख्यक वर्गों के स्वर्त्वों की रज्ञा करना व उन्हें विकास के श्रधिक से श्रधिक श्रवसर, व सांस्कृतिक जीवन में श्रधिक से श्रधिक भाग ले सकने की सुविधार्ये, देना ऋपना प्रमुख कर्तव्य मानेगी । फ़र्वरी १६३८ में, हरिपरा में कांग्रेस ने ऋल्य-संख्यक स्वत्वों के सम्बंध में विकेड़-कमेटी के कलकत्ते के प्रस्ताव को स्वीकार किया, श्रीर साथ ही यह घोषणा भी की कि वह ग्रल्प-संख्यक जातियों के धार्मिक, भाषा-संबंधी, सांस्कृतिक श्रीर श्रन्य स्वन्वों की सरका को त्रपना प्रधान कर्त्तव्य ग्रौर प्रमुख नीति मानती है, ग्रौर किसी भी ऐसी भावी शासन-योजना में, जिसके निर्माण में उसका हाथ होगा, उनके विकास, और देश के राजनैतिक, त्रार्थिक त्रौर सांस्कृतिक जीवन में उनके पूर्ण सहयोग, के लिए श्रिधिक से श्रिधिक सुविधायें होंगी। कांग्रेस ने लीग के साथ समसौते की वात-चीत भी की । पं॰ जवाहरलाल नेहरू ने लीग के कायदे-ग्राज़म की कई पत्र लिखे। गांधी जी ने कई दिन तक घएटों उनसे वातचीत की। सुभापचन्द्र

नोस ने भी उन्हें ऋपनी श्रद्धांजिल चढ़ाई। परन्तु वातचीत इस कारण सफल न हो सकी कि लीग के नेता ने यह ऋाश्वासन चाहा कि कांग्रेस लीग को भारतीय मुसल्मानों की एकमात्र प्रतिनिधि-संस्था मानले। इन सव वातों से यह तो स्पष्ट होजाता है कि कांग्रेस लीग को ख़त्म कर देने के प्रयत्नों में लगी रहने के स्थान पर उससे समभौता करने की लगातार कोशिश करती रही—विल्क सांप्रदायिक मनोवृत्ति वाले हिंदुऋों का सहयोग उससे दिन-व-दिन इस कारण खिचता गया कि उनका विश्वास था कि वह लीग से समभौता करने की कोशिश में हिंदुऋों के स्वत्वों व ऋधिकारों की हत्या कर रही है। कांग्रेस निःसन्देह मुसल्मानों को एक वड़ी संख्या में राष्ट्रीय विचार-धारा में ले ऋाने के लिए व्यग्न थी, पर इसमें उसका उद्देश्य यही था कि वह जनता तक स्वतन्त्रता का सन्देश पहुँचा दे, ऋौर इस प्रयत्न के पीछे उसका यह विश्वास था कि वह हिंदू ऋौर मुसल्मान के भेद-भाव से ऊपर उठकर जनता के लिए ही सव कुछ कर रही है। कांग्रेस का दृष्टिकोण शुद्ध राजनैतिक था। सांप्रदायिकता उसमें लेश-मात्र भी नहीं थी।

कांग्रेस के उद्देश्य व आदर्श

सच तो यह है कि कांग्रेस के प्रति इस प्रकार के ग़लत प्रचार की थोड़ी सी भी सफलता का मुख्य कारण यह है कि जन-साधारण में कांग्रेस के उहें श्यों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है, श्रीर कांग्रेस के विरोधियों ने जान-बूभ कर उसके ब्रादशों को तोड़ा-मरोड़ा है। हम यह बात भूल नहीं सकते कि कांग्रेस देश में प्रजातन्त्रात्मक संस्थात्रों की स्थापना के बहुत पहले से मौजूद थी, श्रीर यदि उसने धारा-सभात्रों में एक राजनैतिक दल की हैसियत से प्रवेश करने का निश्चय किया तो केवल इसलिए कि वह अपने उस आदर्श की ओर एक कदम न्त्रीर वढा सके, जिसकी प्राप्ति के लिए उसकी स्थापना हुई थी। दूसरे शब्दों में. कांग्रेस पहले हिंदुस्तान की त्राज़ादी के लिए लड़ने वाली संस्था है, ब्रौर धारा-सभात्रों में एक राजनैतिक दल की हैसियत से किया हुन्ना उसका कार्य उसकी स्थिति का केवल एक गौगा पच है। इस कारण पश्चिम के राजनैतिक दलों से हम उसकी सर्वथा तुलना नहीं कर सकते । पश्चिम के राजनैतिक दल का उद्देश्य रहता है, बहुमत द्वारा राजतन्त्र को ऋपने ऋधिकार में लेना और ग्रपने सिद्धांतों व त्रादशों के त्रनुसार उसका सञ्चालन करना। कांग्रेस का देश के वर्तमान राज-तन्त्र की उपयुक्तता में तिनक भी विश्वास नहीं है। वह तो उसे उखाड़ फेंकना चाहती है - इस ऋर्थ में वह एक क्रांतिकारी संस्था है--न्त्रीर देश में प्रजातन्त्र-शासन की स्थापना करना चाहती है। कांग्रेस प्रजातन्त्र के अन्तर्गत सङ्गिटित किया गया एक दल नहीं है। वह तो प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए प्रतिज्ञावद्ध, किट्यद्ध और जीवनोत्सर्ग के लिए सतत् तत्पर, एक जीवित संस्था है। उसके अन्तर्गत कई राजनैतिक विचार-धारायें हैं, सोशिलस्ट-पार्टी है, फार्वर्ड ब्लाक है, कम्यूनिस्ट हैं, जो देश में प्रजातन्त्र की स्थापना हो जाने पर विभिन्न राजनैतिक दलों का रूप ले लेंगी। फिर भी राजनैतिक दल की हैसियत से कांग्रेस जब कभी धारा-सभाओं में काम करती है, वह प्रजातन्त्र-शासन के सिद्धांतों का सदा ही अन्तरशः पालन करती है। कांग्रेस के पद-प्रहण करने का अर्थ यह कभी नहीं होता कि वह सता को हड़पना या अल्य-संख्यक वर्गों को कुचलना चाहती है। वह यदि शिक्त प्राप्त करना चाहती है तो भारतीय जनता के लिए—और अल्यसंख्यक वर्गों के स्वत्वों की रन्ताके लिए वह उतनी ही प्रयत्नशील है जितनी बहुसंख्यक वर्गों के स्वत्वों की रन्ताके लिए वह उतनी ही प्रयत्नशील है जितनी बहुसंख्यक वर्गों के। देश से एक विदेशी शासन को हटाकर प्रजातन्त्र की स्थापना करना ही जिस संस्था का धर्म हो वह अपनी कार्य-प्रणाली में किसी अन्य मार्ग का अवलंबन कर ही कैसे सकती है ?

राजनैतिक दलः आन्तरिक प्रवृत्तियां

हमार देश में प्रजातन्त्र की स्थापना के मार्ग में जो सब से बड़ी बाधा मानी जाती है वह यह है कि हमारे राजनैतिक दलों के संगठन का आधार धर्म में है। कांग्रेस के सम्बन्ध में तो यह बात नहीं कही जा संकती । वह एक ग्रुद्ध राजनै-तिक संस्था है। परन्तु कांग्रेस के ग्रालावा जो ग्रान्य राजनै तेक दल हैं - जैसे लिवरल फ़ेंडरेशन, इंग्डियन वोल्शेविक पार्टी, ग्रादि--उनका जनता पर विल्कुल भी प्रभाव नहीं है। कांग्रेस के बाहर केवल एक राजनैतिक दल ऐसा है जिसका संगठन श्रोर प्रचार बड़ी तत्वरता के साथ किया जा रहा है। वह है कम्यूनिस्ट पार्टी । परन्तु, १६४२ के ब्रान्दोलन में कम्यूनिस्ट पार्टी का जो खैया रहा उस से वह बहुत बदनाम हो गई है, त्र्योर उसकी प्रतिष्ठा को बड़ी ठेस पहुंची है। व्यापकता, शिक्त व संगठन की दृष्टि से देखा जाय तो कांग्रेस के वाद जिस संस्था का नाम लिया जा सकता है, वह है मुश्लिम लीग । श्रीर उसके बाद यदि कोई राजनैतिक दल ऐसा है जिसका संगठन ग्रौर प्रचार देश-व्यापी है तो वह हिन्दू महासभा है । मुस्लिम-लीग ग्रौर हिन्दू-महासभा दोनों कट्टर साम्प्रदायिक संस्थाएं हैं, त्रोर दोनों का त्राधार धर्म में है। मुस्लिम लीग मुसल्मानों तक ही सीमित है, त्रौर हिन्दू-महासभा का प्रधान उद्देश्य हिन्दू-हितों त्रौर स्वाथों की रक्ता करना है।

यह सच है कि मुस्लिम-लीग का कार्य-चेत्र मुसल्मानों तक ही सीमित है

श्रौर हिन्दू-महासभा हमारी राजनैतिक समस्याश्रों को हिन्दू दृष्टिकोण से ही देखना श्रौर समभना चाहती है। परन्तु हमें यह बात भूल नहीं जाना चाहिए कि उनके संगठन का श्रीधार चाहे कुछ हो उनका कार्य शुद्ध राजनैतिक है, धार्मिक नहीं। मुन्तिलम-लीग श्रौर हिन्दू-महासभा दोनों का संगठन राजनैतिक उद्देश्यों को लेकर किया गया है, श्रौर समय-समय पर उन्होंने राजनैतिक श्रादशों पर ही ज़ोर दिया है।

मुस्लिम-लीग की स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों में जहां मुसल्मानों में राजभिक की भावना को विकसित करना व उनके ऋौर सरकार के वीच सद्भावना को स्थापित करना था, वहां भारतीय मुसल्मानों के राजनैतिक व अन्य अधिकारों की रचा करना व उनकी ग्रावश्यकतात्रों त्रीर त्राकांचात्रों को सरकार के सामने रखना भी था। मुस्लिम-लीग ने सदा ही मुसल्मानों के राजनैतिक अधिकारों पर ही विशेष ज़ोर दिया है। १९१३ में मुस्लिम-लीग के उद्देश्यों में भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन की स्थापना को शामिल किया गया। उसके बार कई वर्षों तक कांग्रेस स्त्रीर लीग के वार्षिक स्त्रधिवेशन एक ही स्थान पर होते रहे । १६२०-२१ के ऋसहयोग के ऋान्दोलन को लीग का समर्थन प्राप्त था। १६२७ में, मि॰ जिन्ना के नेतृत्व में, लीग का बहुमत साइमन कमीशन के वहिष्कार में राष्ट्रीय तत्त्वों के साथ था । १६३६ में चुरान के अवसर पर लीग ने जिस नीति की घोषणा की वह प्रगतिशीलता की द्योतक थी। स्रक्ट्वर १६३७ में मुस्लिम-लीग ने अपने को आज़ादी के पत्त में घोषित किया; संघ शासन की भर्त्सना की, श्रौर श्रार्थिक कार्य-क्रम की रूप-रेखा वनाई। १६४० के मुस्लिम लीग के पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव के पीछे भी राजनैतिक उद्देश्य ही प्रधान रहे हैं । इसी प्रकार हिन्दू-महासभा भी हिन्दुन्त्रों के राजनैतिक स्वन्वों की रक्ता के लिए सामने आई और ज्यों-ज्यों हिन्दुओं का यह भय बढ़ता गया कि कांग्रेस कहीं मुसल्मानों को सन्तुर करने के प्रयत्न में हिन्दू-हितों की वृंलि न दे डाले, उसका वल वढता गया है। पाकिस्तान की मांग के साथ ऋखएड-हिंदुस्तान का ऋान्दोलन भी ऋधिक प्रवल हो गया है।

हमारे इन साम्प्रदायिक दिखाई देने वाले दलों के पीछे राजनैतिक विचार-धाराख्रों का ख्रांतरिक संघर्ष भी वीव होता जा रहा है। सबसे पहले मुस्लिम-लीग को ही लें, जो हमारे देश की सबसे कहर साम्प्रदायिक संस्था मानी जाती है। १६३७ के बाद से, जब से मुस्लिम लीग की शक्ति का बढ़ना ख्रारम्म हुद्या, उसमें एक ख्रोर तो प्रतिक्रियावादी तत्त्वों का समावेश हुद्या, ख्रौर दूसरी छोर प्रगतिशीलता की धाराएं सशक्त हो चलीं। १६३६ के चुनाव के घोषणा-पत्र में प्रगतिशीलता की प्रधानता स्पष्ट है। १६३७ में मि॰ जिन्ना ने लख-नऊ में कहा-"श्राप लोगों का प्रधान कर्त्तव्य जनता के लाभ के लिए एक रचनात्मक और सुधारवादी कार्य कम की योजना करना है।" कांग्रेस के विरोध में लीग का प्रतिक्रियावादी पक्त सामने आयां, परन्त आंतरिक संघर्ष वरावर चल रहा था। मई १६३८ की कानपर की हड़ताल में इस संघर्ष की अच्छी अभि-व्यक्ति मिलती है। लीग के प्रतिकिया वादी पत्त ने पहले तो हड़ताल वन्द करने की चेष्टा की पर जब उसे सफलता नहीं मिली तो लीग का प्रगतिशील वर्ग सामने श्राया श्रीर उसने हड़त लयों का साथ दिया—उनकी सफलता पर वधाई दी श्रीर साथ ही एक वहें बहमत से यह प्रस्ताव भी पास किया कि लीग का कोई पदाधिकारी ज़मींदारों की किसी संस्था का सदस्य न बने । यों तो मई १६४३ में दिल्ली ग्राधिवेशन में ही लीग के सामने यह प्रस्ताव लाया गया था कि पाकिस्तान का शासन-विधान प्रजातन्त्र ग्रौर साम्यवाद के इस्लामी सिंद्धान्तों पर स्थापित होना चाहिए, परन्त दिसम्बर १६४३ के करांची ग्राधिवेशन में इस श्रान्दोलन ने एक स्पष्ट रूप ले लिया । जिन्ना साहव को लीग के जन-सम्पर्क के सम्बन्ध में त्र्यधिक ज़ीर देना पड़ा । सिन्ध प्रांतीय लीग के ऋध्यन्न जी०एम० सैयद ने कहा कि लीग को जनता के स्वार्थों को ध्यान में रखना चाहिए, श्रीर ऐसे प्रस्ताव पास किये गए जिनमें जनता की ऋार्थिक समस्याओं को सलकाने व लीग के मन्त्रिमएडलों द्वारा एक निश्चित सामाजिक, शैद्धिक ग्रौर ग्रार्थिक कार्य-कम को ग्रमल में लाने पर, ज़ोर दिया गया था।

प्रायः सभी प्रान्तों में राजनैतिक विचारधारात्रों को लेकर इस प्रकार का आन्तरिक संघर्ष जारी है। सिन्ध, आसाम और सीमाप्रान्त में तो वहां की अनुदार सरकारों को लीग की सभाशों पर भी प्रतिवन्ध लगाना पड़ा, पर जनता के आन्दोलन के सामने उन्हें भुक्तना पड़ा। पंजाब में लीग ने इस वात की मांग की कि या तो कांग्रेस के कैदियों को छोड़ दिया जाय या उन पर खुली अदालत में मुक्तदमा चलाया जाय। पंजाब में लीग का नेतृत्व मुमताज़ दौल-ताना और उनके प्रगतिशील साथियों के हाथ में आ गया है। संयुक्तप्रांत में लीग के नेता नवाब इस्माईल खाँ व चौधरी ख़लीकुष्जमा स्वयं प्रगतिशील हैं, पर रिज्ञवानुल्ला दल के नेतृत्व में और भी प्रगतिशील तन्त आगे आ रहे हैं। वंगाल में लीग के प्रगतिशील मन्त्री अब्दुल हाशिम ने लीग को एक कियाशील संस्था में परिणत कर दिया है। सिन्ध में एक प्रगतिशील नेता, जी० एम० सैयद, लीग के अध्यक्त हैं। वम्बई में डा० अब्दुल हमीद काज़ी के नेतृत्व में प्रगतिशील दल ने अपने को खूब संगठित कर लिया है। इन प्रगतिन

शील तन्तों को प्रधानता मिलने के साथ ही दूसरे राजनैतिक दलों से सहयोग की मांग भी वहती जा रही है। सितम्बर १६४४ के गांधी-जिन्ना वार्तालाप के पीछे इस मांग का वल था—यद्यिष कुछ ऐतिहासिक कारणों से यह वातचीत सफल न हो सकी। केन्द्रीय धारा सभा में कांग्रेस और लीग ने भूलाभाई देसाई और नवावज़ादा लियाक़त अली खाँ के नेतृत्व में एक संयुक्त मोर्चा बना लिया था। आसाम और पंजाव की धारा सभाओं में भी कांग्रेस और लीग ने मिल-जुल कर काम किया। लीग के नेता इस समय एक विषम परिस्थिति में हैं। उन्हें एक ओर तो लीग की प्रगतिशील विचार-धारा का समर्थन करना पड़ रहा है, परन्तु दूसरी ओर वह रूढ़िवादी तन्त्वों को छोड़ना भी नहीं चाहते, अन्यथा लीग में फूट पड़ जाने का भय है, परन्तु ज्यों-ज्यों यह संघर्ष बढ़ता जायगा उन्हें एक स्पष्ट निर्णय कर लेने पर विवश हो जाना पड़ेगा।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि, मुस्लिम-लीग, हिंदू महासभा श्रीर दूसरे सांप्रदायिक दलों के अन्तर्गत विभिन्न राजनैतिक विचार-धाराओं का विकास हो रहा है। हमारे राजनैतिक दलों की स्थापना का उद्देश्य प्रांतीय श्रथवा केन्द्रीय शासन में कुछ राजनैतिक सत्ता प्राप्त कर लेने तक ही सीमित नहीं रहा। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य स्वाधीनताके युद्ध को जारी रखना है। मुस्लिम-लीग की स्थापना इस उद्देश्य से हुई कि भारतीय प्रजातन्त्र में मुसल्मानों के ऋधिकार सुरक्तित रह सकें, ख्रौर वह ख्रयने इस काम में जुटी हुई है। हिंदू महासभा मुसल्मानों के त्र्यतिक्रमण् से हिंदू स्वार्थों की रचा करना चाहती है,क्योंकि उसे डर है कि राष्ट्रीय त्रांदोलन के साथ मुसल्मानों का यह अतिक्रमण वढता जाएगा। इन सव राजनैतिक दलों की रूप-रेखा में बड़ी तेज़ी के साथ परिवर्त्तन होता जा रहा है। विभाजन की सामाजिक ऋौर ऋार्थिक रेखाएँ ऋधिक स्वष्ट होती जा रही हैं। सच तो यह है कि हमारे इन राजनैतिक दलों में कोई दल ऐसा नहीं है जो शुद्ध सांप्रदायिक कहा जा सके। वास्तव में ये सव राजनैतिक दल ही हैं। स्त्रीर यदि देश में एक सचा प्रजातन्त्रीय शासन स्थापित किया जा सके तो मुक्ते पूरा विश्वास है कि ये राजनैतिक दल, नई परिस्थितियों को दृष्टिकोण में रखते हुए, ऋपने ऋापको परिवर्तित कर सकेंगे, ऋौर, पलक मारते, पश्चिम के राजनैतिक दलों का रूप ले लेंगे। कांग्रेस तो वार-त्रार इस वात की घोषणा करती रही है कि वह शक्ति ऋपने लिए नहीं परन्त भारतीय जनता के लिए प्राप्त करना चाहती है ! इस कारण यह सोचना कि देश में स्वराज्य की स्थापना हो जाने के वाद कांग्रेस तानाशाही के रूप में उस पर शासन करेगी, एक व्यर्थ की कल्पना को प्रश्रय देना है। इसी प्रकार एक स्थायी शासन विधान में एक उचित सम-

भौते के ग्राधार पर भारतीय मुसल्मानों को न्याय संगत ग्राधिकार ग्रीर संरच्या मिल जाने के बाद मुस्लिम-लीग भी ग्रापने वर्त्तमान रूप को कायम नहीं रख सकेगी संभव है उसकी विभिन्न विचार-धाराएं कांग्रेस के ग्रान्तर्गत जो विचार-धाराएं स्पष्ट होती जारही हैं उनसे एक रूप हो सकें। हिंदू महासभा की स्थिति तो ग्रीर भी नाजुक है—देश में एक स्वतन्त्र शासन की स्थापना हो जाने के बाद उसका कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इस प्रकार यह कहना कि हमारे राजनैतिक दल प्रजातन्त्र के विकास में वाधक हैं, वस्तुरिथित को एक ग़लत दृष्टिकीय से देखना है। सच तो यह है कि हमारे राजनैतिक दलों में जो किमयां हैं उसका मुख्य कारण देश में प्रजातन्त्र का ग्रामाव है। प्रजातंत्र की किरणों के फूट निकलते ही हमारे राजनैतिक दल ग्रापने उचित, वांछित ग्रीर ग्राभित्तत मार्ग पर चल पढ़ेंगे, ग्रीर उनके ग्राधार पर एक प्रवल प्रजातंत्र का सङ्गठन हो सकेगा।

वर्त्तमान स्थिति : राजनैतिक गत्यावरोध

भारतीय इतिहास में बहुत कम त्र्यवसर ऐसे त्र्याए हैं जब भारतवर्ष त्र्यौर श्रंग्रेज़ों के सम्बन्ध इतने श्रच्छे रहे हों जितने १९३४ से १९३६ तक । १९३४ तक दूसरा सविनय ग्रवज्ञा त्र्यांदोलन छिन्न-भिन्न होचुका था। १८ त्र्यस्टूबर १६३४ को कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा का परित्याग करके पार्लमेएटरी कार्यक्रम को ग्रपना लिया । उसके वाद से कांग्रेस के प्रमुख नेता, भूलाभाई देसाई, सदस्यों व सरकारी ऋफ़सरों के साथ दिखाई देने लगे। १६३७ में कांग्रेंस ने प्रांतीय चुनाव लड़ने का निश्चय किया, स्त्रीर चुनाव में स्त्रिष्कांश प्रांतों में उसे एक अभृतपूर्व बहुमत भी प्राप्त हुआ। कांग्रेस की इस विजय से इङ्गलैंग्ड का त्रनुदार दल चाहे विचुब्ध हुन्ना हो, पर जन-साधारण पर त्राच्छा त्रसर पड़ा l चुनाव जीतकर भी जब कांग्रेस ने पद-ग्रहण करने से इन्कार कर दिया, तब इक्कलैंग्ड में निराशा की एक लहर दौड़ गई। लेकिन प्रांतों में ऋस्थायी मन्त्रि-मण्डल बना देने के बाद भी सरकार कांत्रेस की मना लेने के प्रयत्न में ईमान्दारी से लगी हुई थी। कांग्रेस भी सहयोग के लिए उत्सुक थी। जब कांग्रेस ने . श्राश्वासन चाहा कि गवर्नर साधारर्शतः श्रपने विशेष श्रिधकारों का उपयोग नहीं करेंगे, यद्यपि उतने स्पष्ट शब्दों में वह आश्वासन नहीं दिया गया, पर वायसराय व भारत-मन्त्री दोनों ने कांग्रेस की शङ्कात्रों को दूर करने का भरसक प्रयुत्न किया । परिगाम यह हुन्ना कि न्त्रस्थायी मन्त्रिमण्डल तोड़ दिए गए, स्रौर कांग्रेस के 'ग़हार' नेतास्रों ने स्रिधकांश प्रांतों में शासन के सूत्र स्रपने हाथों में लिए ।

कांग्रेस श्रीर सरकार के बीज सहयोग की यह भावना उसके शासन-काल के र७ महीनों में दृढ़ से दृढ़तर होती चली। गवर्नरों ने श्रपने श्राश्वासन पर श्रमल किया। मिन्त्रमण्डलों के निर्माण में उन्होंने तिनक भी हस्तत्तेप नहीं किया। कांग्रेस ने उड़ीसा को छोड़ कर शेष सब प्रांतों में श्रपने मिन्त्रमण्डलों में मुसल्मान सदस्य भी शामिल किए थे। उड़ीसा में जब कई मुस्लिम संस्थाश्रों के प्रतिनिधियों ने गवर्नर से मेंट करके इस बात पर ज़ोर दिया कि मिन्त्रमण्डल में मुसल्मान सदस्य श्रवश्य होने चाहिए, गवर्नर ने स्वष्ट शब्दों में उनसे कह

दिया कि वह इसे त्रावश्यक नहीं मानते थे, ग्रौर साथ ही उन्होंने ग्रापना यह विश्वास भी प्रगट किया कि कांग्रेसी मन्त्रिमगडल द्वारा गुरिलम-हितों को तिनक भी हानि पहुँचने की संभावना नहीं थी। मंत्रिमण्डलों के निर्माण के बाद कांग्रेस को संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत के विकास का पूरा ग्रवसर मिला । गवर्नरों ग्रौर मन्त्रिमण्डलों के ग्रापसी सम्बन्ध बड़े ग्रच्छे रहे । दो बार-संयुक्त प्रांत व विहार में राजनैतिक क़ैदियों को छोड़ने, श्रीर उड़ीसा में चीफ़ सेकेटरी के गवर्नर नियक्त किये जाने के सम्बंध में-जब प्रांतीय-शासन पर सङ्कट के बादल मंडराते दिखाई दिये, कांग्रेस व सरकार दोनों ने ही समभौते की वृत्ति से काम लिया, ग्रीर वे दोनों सङ्कट टल गए । संयुक्त-प्रांत के गवर्नर ने ग्रपने प्रांतीय ंधारा-सभा के भाषण में कहा, ''जब हर चीज़ बदल गई है, गवर्नर की स्थिति भी वह नहीं रह गई है जो पिछले शासन-विधान में थी।" मद्रास के कांग्रेस मंत्री डॉ॰ राजन ने गवर्नर के रवैये के सम्बंध में कहा कि वह "दोस्त, सलाहकार श्रौर तत्त्ववेत्ता" का काम करते रहे । श्रंग्रेज गवर्नरों व सरकारी ग्राफ़सरों की कांग्रेस के प्रति जो भावना रही उसे देखते हुए यदि यह धारणा प्रवल होती गई कि हिंदुस्तान ग्रोर इङ्गलैएड के संबंधों में एक नवीन युग का सत्रंपात होरहा है तो इसमें आश्चर्य क्या था ?

महायुद्ध की प्रतिक्रिया

पास्परिक विश्वास और सहयोग की इस पृष्ठभूमि पर, सितम्बर १६३६ में ग्राचानक महायुद्ध के काले बादल घिर ग्राए। यह घटना बिल्कुल ही ग्राप्ता-शित तो नहीं थी, परन्तु जीवन ग्रीर मरण् की समस्या संसार के प्रत्येक देश के सामने यों ग्रा खड़ी होगी, इसकी स्वष्ट कल्पना किसी ने नहीं की थी। लड़ाई जब ग्राप्ते पूरे वेग में चल पड़ी, तब भी किसी को यह विश्वास नहीं था कि उसे लेकर, कांग्रेस ग्रीर सरकार के बीच जिस सहयोग की जड़ें गहरी होती जारहीं थीं, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ग्रा उपस्थित होगा। सच तो यह है कि ग्रान्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इझलैएड ग्रीर हिंदुस्तान के दृष्टिकोणों में किसी प्रकार का वैपम्य था ही नहीं। दोनों फासिज़्म के ख़िलाफ़ ग्रीर प्रजातन्त्र के समर्थक थे। हिंदुस्तान में तो फासिस्ट विरोधी मनोवृत्ति, विशेष कर जवाहरलाल जी के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण्, ग्रापने शिखर पर थी। हम लोग तो इझलैएड की विदेशी नीति के भी उस हद तक कड़े ग्रालोचक थे, जहां वह फ़ासिज़्म का समर्थन सा करती दिखाई देती थी, परन्तु इंग्लैएड के प्रति हम कभी ग्रासहिष्यु नहीं वने, क्योंकि हम जानते थे कि वह एक ग्रीर तो परिरिथतियों का, व दूसरी ग्रोर एक ग़लत नेतृत्व का, दास बना हुग्रा

था । मंचूरिया पर जापान का ब्राकमण, ब्रवीसीनिया में इटली के साम्राज्य-वाद का नग्न तांडव, स्पेन के गृह-युद्ध में फ़ासिस्ट देशों का खुला सहयोग, हिटलर द्वारा त्रास्ट्रिया व ज़ेंकोस्लोवांकिया का खात्मा, इन घटनात्र्यों ने हमें बहुत ग्रिधिक विचलित किया था, इसलिए मार्च १६३६ में जब इंग्लैएड ने हिटलर की बढ़ती हुई मांगों के सामने पोलैएड को यह श्राश्वासन दे दिया कि वह जर्मनी द्वारा त्राकमण किए जाने पर उसकी सहायता की त्राशा कर सकताहै, उसके प्रति हमारा श्रादर-भाव वह गया, श्रीर सितम्वर १६३६ में जर्मनी द्वारा पोलैएड पर त्राक्रमण किये जाते ही जब उसने जर्मनी के प्रति युद्ध की घोषणा की, तब तो हमारा वह त्रादर श्रद्धा में परिशत होगया । हमारे गएय-मान्य नेतात्रों ने खुले दिल से स्रोर विना किसी शर्त्त के फ़ासिस्ट-देशों के विरोध में इंग्लैएड न्त्रीर न्त्रन्य प्रजातंत्र-देशों के साथ न्त्रपनी सहानुभूति प्रगट की । गांधी जी ने वायसराय से मिलने के वाद ही ऋपने एक वक्तन्य में कहा, ''मैं इस समय हिंदुस्तान की त्राज़ादी की वात नहीं सोच रहा हूँ। वह तो त्र्रायेगी ही, पर यदि इंग्लैएड या फ्रांस का पतन होगया तो उसकी क्या क़ीमत रह जायगी ?" कांग्रेस की कार्य-समिति ने ऋपने एक प्रस्ताव में कहा, "कांग्रेस ने वार-बार फ़ासिस्टवाद व नात्सी-वाद की विचार-धारात्रों व कार्य-प्रणाली, उनके युद्ध व हिंसा के सिद्धांतों ऋौर उनके द्वारा किये जाने वाले मानवी ऋात्मा के कुचलने के प्रयत्नों के संबंध में ऋपनी गहरी ऋसहमित प्रकट की है। वह जर्मनी की नात्सी-सरकार द्वारा पोलैएड के ख़िलाफ़ जो वाज़ा त्राक्रमण किया गया है उसकी -ज़ोरदार शन्दों में भर्त्सना करती है, श्रीर उन देशों के साथ श्रपनी सहान-भृति प्रगट करती है जो इस त्राक्रमण का विरोध कर रहे हैं।" इंग्लैएड श्रीर भारतवर्ष के श्रापसी संबंधों के इतिहास में यह वह सोनहला श्रवसर था, जब सहानुभूति के एक हल्के से इशारे से इंग्लैएड हिंदुस्तान के सहयोग को सदा के ेलिए प्राप्त कर सकता था ।

गत्यावरोध का सूत्रपात

परन्तु, इंग्लैंगड की त्रोर से सहयोग की त्रिभिन्यिक्त की स्चना देने वाला कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके विपरीत, इंगलैंगड ने एक के बाद एक कई ऐसे काम किए जिनसे उसने हिंदुस्तान की सहानुभृति को विलक्कल ही खो दिया। उसके नेतात्रों व धारासभा से भी पूंछे विना हिंदुस्तान के लड़ाई में शामिल होने की घोषणा करदी गई, देश में त्राडिनेंस राज्य कायम होगया त्रीर शासन-विधान में भी कुछ युद्ध-कालीन परिवर्त्तन कर दिये गये। कांग्रेस ने सहानुभृति त्रीर सहयोग का जो हाथ वढ़ाया था, यह उसे बुरी तरह से भिटक

देना था। कांग्रेस भी १६३६ में ऐसी स्थित में नहीं रह गई थी कि सरकार द्वारा की गई अवजा को जुपचाप सह लेती। वह इंग्लैंग्ड व प्रजातन्त्र-देशों का समर्थन अवश्य करना चाहती थी, पर कुछ शत्तों पर। इस सम्बंध में कांग्रेस का प्रस्ताव विल्कुल स्पष्ट था। ''यदि इंग्लैंग्ड प्रजातन्त्र के बचाव व विस्तार के लिए लड़ रहा है, तो उसके लिये यह आवश्यक है कि वह अपने आधीन देशों में साम्राज्यवाद का अन्त करदे और भारतीय जनता को आत्म-निर्णय का अधिकार दे दे—स्वतन्त्र भारत अत्याचार के विरुद्ध, सामान्य-रचा की दृष्टि से, वड़ी प्रसन्तता से दूसरे स्वाधीन राष्ट्रों का साथ देगा।'' कांग्रेस की कार्य-समिति ने इंग्लैंग्ड की सरकार से इस बात की मांग की कि वह अपनी अद्ध-नीति को स्पष्ट शब्दों में घोषित करदे, और साथ ही यह भी स्पष्ट करे कि वह अपनी उस नीति का भारतवर्ष में किस प्रकार पालन करना चाहती है।

ं इंग्लैएड की सरकार इस प्रश्न को यों साफ़-साफ़ सुलक्का लेना नहीं चाहती थी। कुछ दिनों तक उसे यह ख्याल रहा कि कांग्रेस शायद अपनी स्थिति पर इतनी दृढ़ न रहे, श्रीर सरकार के साथ श्रसहयोग के गम्भीर क़दम को न उठाए । उधर, कांग्रेस लगातार इस त्राशा में रही कि युद्ध की विपम परि-श्यितियां सरकार को उसके साथ समभौता करने पर मजबूर कर दिंगी। कांग्रेस श्रपनी निम्न-मांग से हटने के लिए तैयार नहीं थी-यदि कांग्रेस ऐसा करती तो न केवल अपने स्वामिमान को ही खो बैठती, देश का भी बड़ा अहित करती। सितम्बर १६३६ में गांधीजी ने इस वातको स्पष्ट कर दिया था कि वह श्रंग्रेज़ी सरकार को उसके युद्ध प्रयत्नों में विना किसी शर्त्त के सहायता देने के लिए 'तैयार हैं, वह केन्द्रीय शासन में कांग्रे सं के लिए केवल इतना अधिकार चाहते थे कि जितने से प्रांतों का उत्तरदायी शासन श्रिपने उत्तरदायित को निभा सके। इस योड़े से ऋधिकार की प्राप्ति पर भी गांधी जी ने ज़ोर इसलिए दियां कि वह देख रहे थे कि युद्ध के नाम पर प्रांतीय मन्त्रिमएडलों को एक ग़ैरं-ज़िम्मेदार केन्द्रीय शासन के हाथ का खिलौना-मात्र वनने पर मजबूर होना पड़ रहा था। जहां तक कि कांग्रेसके अन्तिम लद्य का संबंध था, सितम्बर १६३६ में गांधीजी इस बात से संतुष्ट होने के लिए भी तैयार थे कि सरकार इस वात की घोषणा भर कर दें कि हिंदुस्तान लड़ाई के बाद एक स्वाधीन ग्रौर प्रजातन्त्रात्मक देश हो जायेगा । परन्तु, जब्र सरकार ने गांधीजी के इस विनम्र प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया तो यह स्वष्ट होगया कि वह हिंदुस्तान पर अपने साम्राज्यवाद के ,शिकंजे को ज़रा भी ढीला करने के लिए तैयार नहीं थी।

मनोवैज्ञानिक पक्ष

इस राजनैतिक गत्यावरोध के मनोवैज्ञानिक पत्त पर मी थोड़ा ग़ौर करलें। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के पद-त्याग से अंग्रेज़ों को पहले तो त्राश्चर्य हुन्ना त्रीर धीरे-धीरे वह श्राश्चर्य विक्रोभ में परिणत हो चला । श्रंग्रेज़ तो भला इस बात की कल्पना ही कैसे कर सकते थे कि जिन भारतीयों पर वह पिछले डेंढ-सौ वर्षों से उपकार पर उपकार लादते जा रहे थे वह उनके ऐसे सङ्घट के श्रवसर पर राजनैतिक सौदे की बात करेंगे ? उनके लिए तो यह विश्वास-धात से कम न था। दूसरी त्रोर कांग्रेस हर चीज़ को हिंदुस्तान की त्राज़ादी की कसौटी पर कस श्रीर परख रही थी। उसके लिए यह विश्वास करना कठिन हो रहा था कि विना हिंदुस्तान को आतम-निर्णय का अधिकार दिए इंग्लैएड और उसके साथी संसार में प्रजातन्त्र को स्थापना कर सकेंगे। कांग्रेस तो यह जानना चाहती थी कि क्या इंग्लैएड सचम्च फ़ासिज्म के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, श्रीर यदि ऐसा था तो वह स्वयं त्राने फ़ासिज्म को ख़त्म कर देने की दिशा में क्या क़दम उठाना चाहता था। कांग्रेस ने इस संबंध में जितना ऋधिक सोचा, उसका यह विश्वास दृढ होता गया कि भारतीय समस्या विश्व की समस्या की कुं जी है श्रीर संसार में प्रजातन्त्र की स्थापना, श्रथवा युद्ध का श्रंत, उस समय तक ग्रसम्भव है जब तक हिंदुस्तान ग्राज़ाद नहीं हो जाता। उसे हिंदुस्तान की श्राज़ादी केवल हिंदुस्तान की दृष्टि से ही नहीं, विश्व की दृष्टि से भी श्रावश्यक दिखाई दे रही थी।

ग़लतंफ़हमी को फैलाने में कुछ श्रीर वातों का हाथ भी रहा। कांग्रेस ने श्रंग्रेज़ी सरकार की ईमानदारी में वहुत दूर तक विश्वास रखा। पद-त्याग के वाद भी उसे श्राशा थी कि सरकार सममौते की दिशा में कोई न कोई प्रयत्न श्रवश्य करेगी, उसे इस वात का श्रंदाज़ा नहीं था कि श्रंग्रेज़ी सरकार का विज्ञोम कितना गहरा चला गया था। कांग्रेस ने ईमानदारी के साथ युद्ध - प्रयत्नों में वाधा न डालने की नीति वरती। श्रंग्रेज़ी सरकार ने उसे कांग्रेस की कमज़ोरी का द्योतक माना। कांग्रेस उन दिनों कठिन परिस्थिति में थी भी। उसके २७ महीनों के पद-ग्रहण ने उसके विरोधी-तत्वों को वड़ा सशक्त बना दिया था। देशी नरेश नाराज़ थे, क्योंकि उन्हें ख्याल था कि वह उनकी प्रजा को उनके ख़िलाफ़ मड़का रही है। मुसल्मानों का विरोध दिन प्रति-दिन तीन होता जा रहा था। हिंदू भी कांग्रेस का साथ छोड़ रहे थे, श्रीर मुस्लिम-लीग के सांप्रदायिक प्रचार की प्रतिक्रिया के रूप में हिन्दू सांप्रदायिक संस्थान्त्रों में शामिल हो रहे थे। कांग्रेस का वाम-पज्ञ, किसानों श्रीर मज़दूरों के हितों के

· ...

नाम पर, उसके दिल्ल्य-पत्त के प्रति विद्रोह की घोषणा कर चुका था। कांग्रेस में एक दल ऐसा भी था जो अंग्रेज़ी सरकार से सहयोग करने के लिए वेचैन था, श्रीर टूटी-फूटी सत्ता को भी अपने हाथ से खोना नहीं चाहता था। उधर, जनता कांग्रेस की अन्तर्राष्ट्रीय नीति को समभने में सर्वथा असमर्थ थी। वह तो अंग्रेज़ी नीति के कारण जितना अधिक विज्ञुच्घ होती जा रही थी, शत्रु राष्ट्रों के प्रति उसका ममत्व बढ़ता जा रहा था, अरेर अंग्रेज़ों की हार और अपमान से वह एक अस्वस्थ संतोष का अनुभव कर रही थी। ऐसी परिस्थितियों में यदि सरकार ने कांग्रेस के विरोध को अधिक महत्त्व नहीं दिया तो यह स्वाभाविक ही था।

देश में एक ऐसा दल प्रवल होता जा रहा था जो युद्ध की परिस्थितियों से लाभ उठा कर सरकार पर दवाव डालने के पत्त में था-कम्यूनिस्ट तो इस दल के अप्रगएय थे। जनता में ज्यों-ज्यों वेचैनी बढ़ती जा रही थी, यह दल अधिक मज़बूत बनता जा रहा था। पर कांग्रेस का नेतृत्व सरकार पर इस प्रकार का नाजायज दवाव नहीं डालना चाहता था। बहुत संभव है कि, युद्ध की लेकर, कांग्रेस में एक बार फिर ग्रान्तरिक विस्फोट होता, श्रीर उसके वाम श्रीर दिच्च पत्त एक दूसरे से ग्रालहदा हो जाते। परन्तु, गांधी जी ने देश को इस संकट से बचा लिया। वह फ़ौरन ही देश के समस्त तत्त्वों की, परस्पर-विरोधी तत्त्वों को भी, एक साथ ले आए। सुभाष वीस अवश्य भाग निकले और शत्रु-पन्न के रेडियो से गांधी जी के काम को ऋसफल बनाने का भरसक प्रयत्न करते रहे। मि ० जिन्ना ने भी अपनी नई शिक्तशाली स्थिति को छोड़ने से इन्कार कर दिया-श्रंग्रेज़ी सरकार की नीति के कारण उनका वल व शक्ति बहुत बढ़ गए थे। इन्हें छोड़ कर देश की अन्य सभी विचार-धाराओं ने गांधी जी का साथ दिया। गांधी जी एक च्रोर तो देश की बढ़ती हुई शक्ति की बिखरने देना नहीं चाहते थे, दूसरी श्रोर वह सरकार के युद्ध-प्रयत्नों में वाधा पहुँचाना भी नहीं चाहते थे।

श्रगस्त १६४० में सरकार ने देश के सामने जो प्रस्ताव रखे, यह हमारी राष्ट्रीयता के लिए एक खुली चुनौती के रूप में थे। वायसराय ने वड़ी उदारता-पूर्वक इस वात की घोषणा की कि वह श्रपनी कार्यकारिणी-सभा में कुछ श्रन्य सदस्यों को ले सकते हैं, व एक भारतीय रज्ञा-समिति की स्थापना भी कर सकते हैं। युद्ध के समाप्त होते ही भारतीयों को श्रपना शासन-विधान स्वयं बनाने का श्राधिकार दिए जाने का श्राश्वासन भी था। कांग्रेस ने इस चुनौती का जवाव 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' के श्रान्दोलन द्वारा दिया, परंन्तु गांधी जी श्रीर कांग्रेस

जितना अधिक संयम से काम लेते रहे, सरकार ने उनकी स्थिति को उतना ही ग़लत समका। कांग्रेस के संयम में उसे कमज़ोरी की भावना दिखाई दी, कांग्रेस के प्रांत उसका अवश्वास श्रीर भी प्रगाढ़ हो चला, श्रीर उसने एक श्रीर तो भारतीय मुसल्मानों को कांग्रेस के ख़िलाफ़ उभाड़ा, श्रीर दूसरी श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय जनमत को श्रपने पद्ध में करने का अथक प्रयत्न किया।

कांग्रेस की युद्ध-सम्बन्धी नीति को लेकर किस प्रकार श्रंग्रेज़ी सरकार श्रीर लीग में एक निकटतम संपर्क स्थापित हो चुका था, इसकी विस्तृत चर्चा एक पिछले श्रध्याय में त्रा चुकी है। हमारी सांप्रदायिक कठिनाइयों की लेकर संसार को यह नताने की कोशिश की गई कि हमारी राजनैतिक समस्याएं इतनी जिटल हैं कि युद्ध के वीच उन्हें छूना भी एक वारूद के ढेर में चिनगारी लगाने के समान है। भारत-मन्त्री मि॰ एमेरी ने १४ अगस्त १६४० को हाउस ऑफ़ - कॉमन्स में बोलते हुए कहा, ''ब्राल्प्स पर्वत की ऊंची चोटियों में छूरी की धार जैसे संकीर्ण वर्फ पर संभल कर चल लेना श्राधिक स्रासान है, वर्त्तमान भारतीय राजनीति के पेचीदा, श्रीर गढ़ों से भरे हुए, दलदल में से विना ठोकर खाए या किसी को नाराज़ किए, निकल जाने की तलना में।" "पदि कांग्रेस सचमुच भारतीय राजनीति के प्रमुख तत्त्वों का प्रतिनिधित्व कर पावी, जैसा कि वह दावा करती है, तव तो उसकी मांग चाहे कितनी वढी हुई क्यों न होती, हमारी समस्या विल्कुल भिन्न, श्रीर श्राज के मुक़ाविले में कहीं श्रिधिक सरल, होती। यह सत्य है कि वह संख्या की दृष्टि से ब्रिटिश-भारत में सबसे बड़ी राजनैतिक संस्था है, परन्त देश का प्रतिनिधित्व करने का उसका दावा भारतवर्ष के जटिल राष्ट्रीय जीवन के नड़े स्नावश्यक तत्त्वों द्वारा स्त्रस्वीकार किया जा रहा है।" इनमें पहला स्थान स्वभावतः "महान् मुस्लिम-समाज को, जिसकी संख्या ६ करोड़ है, श्रीर जो उत्तर-पश्चिमी व उत्तर-पूर्वी भारत में बहुमत, श्रीर देश-भर में श्रल्प-मत, के रूप में फैला हुआ है," दिया जा रहा था। "धार्मिक श्रीर सामाजिक दृष्टिकोण में, ऐतिहासिक स्मृतियों व संस्कृति में, उनमें श्रीर उनके हिंद देश-वासियों में अन्तर यदि अधिक नहीं तो कम से कम उतना गहरा तो है जितना यूरोप के दो राष्ट्रों में।" इसके वाद देशी नरेशों का स्थान श्राता था—''जिनका राज्य हिंदुस्तान के एक-तिहाई भाग में फैला हुन्ना है, न्त्रौर जिसके स्रंतर्गत देश की एक-चौथाई स्रावादी रहती है।" मि॰ एमेरी का मत था कि मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रे स की मांग एक व्यवहारिक मांग नहीं है।""

> १—India and Freedom, पृ॰ ६६। २—वही, पृ॰ ६८। ३—वही, पृ॰ ७१।

१६ नवंबर १६४१ को अपने एक दूसरे भाषण में मि॰ एमेरी ने कहा, "हम प्रजातन्त्र के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हिंदुस्तान में उसकी स्थापना क्यों न कर दी जाय, यह दलील देखने में तो तर्कपूर्ण और अकाट्य है, परन्तु कोई ऐसी राजनैतिक संस्था न तो मौजूद है, और न किसी ऐसी संस्था के निकट-भिष्य में बन जाने की आशा है, जो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्य कर सके या हिंदुस्तान के नाम पर कोई संयुक्त मांग पेश कर सके। प्रजातन्त्र का ऐसा कौनसा रूप है जिसके अन्तर्गत भारतवर्ण की जनताएं साथ-साथ रहने के लिए तैयार हो सकें १' इस प्रकार के बक्तन्यों से हमारे मन में विद्योभ का बढ़ना स्वाभाविक था। गांधी जी ने लिखा, "सङ्घट में प्रायः लोगों के दिल नरम पड़ जाते हैं, और उनमें वस्तु-स्थित को समभने की तत्परता आजाती है, परन्तु ब्रिटेन के सङ्घट का, जान पड़ता है, मि॰ एमेरी पर रन्ती भर प्रभाव भी नहीं पड़ा है।"

क्रिप्स प्रस्ताव

७ दिसंबर १६४२ को जब जापान ने ग्रचानक पर्ल बन्दरगाह पर हमला कर दिया, श्रीर हांग-कांग, सिंगापुर, फ़िलिपाइंस, मलाया, वरमा श्रादि श्रमरी-कन व अंग्रेज़ी साम्राज्य के गढ एक के वाद एक, और तेज़ी से, धराशायी होने ज्ञगे—श्रोर जापान की सेनाएं भारतवर्ष की श्ररान्तत उत्तर-पूर्वी सीमा तक श्रा पहुँचीं—तव फिर, श्रचानक, श्रंग्रेज़ी सरकार की श्रोर से सर स्टैफ़र्ड किप्स हिंदुस्तान स्राये, स्रीर देश के नेतास्रों से राजनैतिक गत्यावरोध को दूर करने की दिशा में वातचीत त्रारम्भ की । भारतीय हृदयों में एक वार फिर त्राशा की योति चमकी। हमने यह अनुभव करके संतोष की सांस ली कि, देर से सही, अभेज़ी सरकार जागी तो ! किप्स ने इस देश में अपने पहले भाषण में ही कश कि नई योजना में हिंदुस्तान को इतनी आज़ादी होगी कि वह यदि चाहेगा तो युद्ध के फ़ौरन बाद ही ऋपने की पूर्ण स्वाधीन घोषित कर सकेगा। परन्तु राष्ट्र की उत्सुक वागी ने पूंछा, "त्राज के लिए श्रापकी योजना क्या कहती है ! श्राज जो हमारे राजनैतिक निकास की गति बिल्कल रुद्ध होरही है, इससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी ?" किप्स के पास इसका जवाव नहीं था । किप्स ने राष्ट्र-पित मी॰ त्राज़ाद से त्रापनी पहली वातचीत में कहा था कि भारतवर्प में शीघ्र ही एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो सकेगी, और वायसराय की स्थिति वही रह जायगी जो इंग्लैएड के सम्राट की ग्रापने देश में है। परन्तु, बाद में जब मौलाना श्राज़ाद ने भविष्य के सभी प्रश्नों को एक श्रोर उठाकर रख देने की श्रपनी तत्परता वताई, श्रीर कहा कि "यदि सची राष्ट्रीय सरकार वनती है तो

१---बही, ए० ४१।

कांग्रेस अन भी उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार है", तो क्रिप्स अचानक सारी वातचीत के • असफल होजाने की घोषणा के साथ इंग्लैयड के लिए खाना हो गए!

इसके लिए देश सचमुच तैयार नहीं था। तो क्या क्रिप्स प्रस्ताव भी एक धोले की टट्टी था, दुनियां की ऋांखों में धूल भोंकने का एक प्रयत्न ? क्या चर्चिल ने सर स्टैफ़र्ड किप्स को हिंदुस्तान इसलिए भेजा था कि वह हमारे त्र्यापसी मत-भेदों का दिंदोरा संसार के सामने पीट सकें १ किप्स-मिशन की त्रसफलता के कारणों के विशेष विश्लेषण की यहां श्रावश्यकता नहीं है। २६ ऋक्ट्वर १६३६ को स्वयं क्रिप्स ने कहा था, ''वर्त्तमान गत्यावरोध ऋंग्रेज़ी सरकार के समभौता न करने के निश्चय के कारण है, कांग्रेस पर उसका उत्तर-दायित्व नहीं है। कांग्रेस भारतीय जनता के न्यायपूर्ण ऋधिकारों की मांग सामने ला रही है। वायसराय का यह प्रस्ताव कि खयं उनके द्वारा एक सलाहकार-समिति का निर्माण कर लिया जाय, भारतीय जनता को, जो श्रातम-निर्णय का ऋधिकार मांग रही है, ऋपमानित करना है। यह दलील कि सांप्र-दायिक कठिनाइयों के कारण, हिंदुस्तान में एक स्वतंत्र-शासन की स्थापना नहीं की जा सकती, निरर्थक है।" किप्स द्वारा निर्घारित सिद्धांतों पर ही यदि उनकी योजना को कसा जाय तो उसकी सारहीनता स्पष्ट प्रगट होजाती है। उसमें भारतीय जनता की उन 'न्यायपूर्ण मांगों' को, जिनका कांग्रेस प्रतिनिधित्व कर रही थी, पूरा करने का कोई प्रयत्न नहीं था। युद्ध के दिनों में एक सलाहकार-समिति के ऋतिरिक्त कुछ भी देने के लिए वह तैयार नहीं थे। भारतीय जनता के ब्रात्म-निर्णय के ब्रिधिकार को विना किसी शर्त ब्रीर वहाने के मानने का कोई संकेत किप्स-प्रस्तावों में नहीं था। सांप्रदायिक कठिनाइयों को वढा-चढा कर वताने श्रीर, मुस्लिम-हितों के नाम पर, देश की एकता श्रीर शक्ति को छिन्न-मिन्न कर देने का उसमें स्पष्ट ऋायोजन था। ऐसी दशा में यदि देश ने उन प्रस्तावों के संबंध में विशेष उत्साह प्रगट नहीं किया तो यह स्वाभाविक ही था। किप्स प्रस्तावों के सम्बंध में हमारे राजनैतिक दलों ने वाद में कुछ भी निर्णय बनाये हों, उनके सम्बंध में नेतात्रों से जो बातचीत चल रही थी उसे बीच में ही खयं किप्स ने खतम कर दिया था। प्रायः यह कहा जाता है कि हमें क्रिप्स प्रस्ताव स्वीकार कर लेने चाहिए थे, पर, सच ती यह है कि हमारे श्रस्त्रीकृत करने के पहले ही स्वयं क्रिप्स ने, उन्हें एक जलते हुए श्रङ्गारे के समान, दूर फेंक दिया था।

निराशा की मध्यरात्रि

किप्स प्रस्ताव के ग्रसफल हो जाने की प्रतिक्रिया वड़ी भीपण हुई, क्योंकि वह श्रंग्रेज़ी सरकार की श्रोर से सहयोग का श्रांतिम प्रस्ताव या जिसके संबंध में वड़ी ऊंची-ऊंची ग्राशाएं वांध ली गई थीं। उसकी ग्रसफलता पर देश में निराशा, ग्रसंतोप ग्रौर विद्धोभ की एक ग्रांधी-सी उठ खड़ी हुई। कुछ प्रखर-बुद्धि राजनीतिज्ञों ने उल्पमन से निकलने की वैधानिक चेष्टाएं कीं। श्री राज-गोपालाचार्य ने ग्रपनी पाकिस्तान संबंधी योजना के द्वारा कांग्रेस श्रौर मुस्लिम-लीग को निकट लाने का प्रयत्न किया । परन्तु, किप्स प्रस्तावों के खोखलेपन ने गांधीजी के धैर्य को डिगा दिया था, ग्रौर वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि स्रव सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं रह गया था कि संग्रेजों से साफ शब्दों में हिंदुस्तान छोड़ने के लिए कह दिया जाय। गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि इसमें न केवल हिंदुस्तान का ही फ़ायदा है, परन्तुं इंग्लैएड की रचा का भी इसके श्रातिरिक्त कोई उपाय नहीं है। गांधी जी देश के वर्त्तमान शासन पर त्र्यराजकता को तरजीह देते थे। श्रव वह हिंदू-मुस्लिम एकता की स्थापना के लिए भी रुकने के लिए तैयार नहीं थे-उनका यह विश्वास भी हढ होगया था कि जब तक ग्रंग्रेज़ हैं, हिंदू ग्रीर मुसल्मानों में एका होना ग्रसंभव है। गांधीजी की विचार-धारा को, जो देश के ग्रासंतोप का सचा प्रतिनिधित्व कर रही थी, कांग्रेस के ''ग्रगस्त-प्रस्ताव'' में ग्रामिन्यिक मिली।

यह सब जानते हैं कि अगस्त १६४२ में गांधीजी या कांग्रेस फ़ौरन ही कोई बड़ा आदोलन चलाना नहीं चाहते थे। समभौते और वातचीत की नीति को उन्होंने विल्कुल ही छोड़ नहीं दिया था। परन्तु, सरकार द्वारा "अगस्त-प्रस्ताव" का जो उत्तर दिया गया, वह भारतीय राष्ट्रीयता पर सब से बड़ा और सशक्त प्रहार था। गांधी जी व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सब सदस्य, व देश के सभी प्रमुख कांग्रेसी, एक साथ, विना किसी जांच-पड़ताल के, जेलों में डाल दिये गए। इसके परिखाम-स्वरूप जब देश भर में जनता ने अपना असंतोष प्रगट किया, तब मशीनगनों, लाठियों और घोड़ों की टापों के द्वारा उस असंतोष को कुचलने का प्रयत्न किया गया। कई स्थानों पर तो हवाई जहाज़ से वम भी गिराये गए। "अगस्त आदोलन" और उसमें वस्ती जानेवाली सरकारी नीति ने राजनैतिक गत्यावरोध को अपनी चरम सीमा तक पहुँचा दिया। उन दिनों अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा हो चली थी कि यह भारत और इंग्लैएड के आपसी संबंधों पर ऐसा आघात था, जिसकी च्वंत-पूर्ति भविष्य में हो पाना असंभव होगया था। उसके बाद घटनाएं भी कुछ ऐसा रूप लेती गई जिससे इस

धारणा को पृष्टि मिली । १५ श्रगस्त '४२ को जेल में महादेव देसाई की श्रचानक मृत्यु के संवाद से तो मानवता में हमारा विश्वास ही डिग उठा था। फ़र्वरी १६४३ में गांधी जी ने २१ दिन का उपवास किया। उसमें उनकी हालत ख़तरनाक हो जाने व संसार भर से उनके छोड़ दिये जाने के श्राग्रह के सामने भी सरकार ने श्रपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। कस्त्रजा गांधी का श्रस्वास्थ्य श्रीर देहावसान भी जिन परिस्थितियों में हुआ वे सरकार की हृदय-हीनता की द्योतक थीं। बाहर, हिंदू महासभा, नरम दल श्रादि सभी राजनैतिक संस्थाश्रों के श्रथक श्रीर श्रनवरत प्रयत्न भी गत्यावरोध में तिनक भी कम्पन उत्पन्न करने में श्रसमर्थ रहे।

सममौते की अनिवार्यता

फिर भी राजनीति की गहराई तक जाने वाले न्यिक्त के लिए यह परिशाम निकाल लेना ठीक नहीं होता कि भारत और इंग्लैएड में अब किसी प्रकार का समभौता होने की त्राशा रह ही नहीं गई थी, क्योंकि राजनीति तो समभौते का त्राधार लेकर ही त्रागे वढती है। राजनैतिक गत्यावरोध भारत स्त्रौर इंग्लैएड के ब्रापसी संबंधों के इतिहास में कोई नई चीज़ नहीं है। जब कभी भारतवर्ष की स्वाधीनता की मांग ने एक प्रवल रूप ले लिया तिभी राजनैतिक गत्यावरोध उठ खड़ा हुन्ना—न्त्रीर जब कभी इस मांग में कुछ शिथिलता न्नाई, न्नथवा दूसरी श्रोर से समभौते के लिए कोई क़दम बढ़ाया गया, तभी वह सुलभ गया। सच तो यह है कि भारतीय राजनीति के क्रियात्मक वर्षों के इतिहास को देखा जाय तो उसमें हमें एक वैज्ञानिक कम दिखाई दे सकता है । राष्ट्रीय भावनात्रों की प्राय: एक वाद-सी त्राजाती है, जिसकी त्रभिन्यिक हम संस्कृति त्रीर कला, साहित्य श्रथवा समाज-सुधार की नवीन प्रवृत्तियों में पाते हैं। इसके वाद सरकार की स्रोर से भारतीय राष्ट्रीयता के स्राधार-तत्त्वों में फूट डालने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ न्ई समस्याएं खड़ी कर दी जाती हैं। १६०६ में सांप्रदायिक चुनाव, १६३० में देशी नरेशों की सार्वभौमता का सिद्धान्त, १६४२ में मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांग का अप्रत्यन्त समर्थन-इसी प्रकार की समस्याएं थीं। भारतीय राष्ट्रीयता उसका उत्तर देश में एकता की स्थापना के लिए एक विशद प्रयत्न के रूप में देती है--श्रीर इस प्रयत्न का श्रांत प्रायः एक वड़े राजनैतिक त्र्यांदोलन में होता है। इस राजनैतिक त्र्यांदोलन में भारत त्र्योर इंग्लैएड के त्र्यापसी सम्बंधों को जो ठेस पहुँचती है उसे पूरा करने की दिशा में एक त्र्योर वो बड़े-बड़े विधान-शास्त्री लग जाते हैं—१६२४ में मोतीलाल नेहरू श्रोर चितरञ्जनदास, १६३४ में कांग्रेस का समग्र दिच्च ए-पच्च, १६४५ में राजाजी

श्रीर सपू-कमेटी—श्रीर दूसरी श्रीर गांधीजी श्रपने रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा न केवल उस चित की पूर्ति में ही कटियद्ध होजाते हैं, परन्तु राष्ट्रीय जीवन को श्रीर भी सशक्त बना लेते हैं, जिससे वह श्रगले संघर्षमें विजयी होने का प्रयत्न कर सके।

राजनीति में निराशा का कोई स्थायी स्थान नहीं है। यह मान लेना कि श्रांश्रेज़ सत्ता छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, एक श्रसंभव कल्पना को प्रश्रय देना है। श्रांश्रेज़ों के हाथ से सत्ता पहले भी हटी है, श्राज भी हट सकती है, भविष्य में हटेगी भी। सच तो यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों ने सत्ता को उनके हाथों में सौंपा, श्रीर उन्हीं परिस्थितियों का उल्टा चक उन्हें सत्ता को छोड़ देने पर वाध्य भी कर सकता है। भारत में श्रंश्रेज़ी-साम्राज्य को श्राचुएए। बनाये रखने का निश्चय उस समय संभव हो सका जब श्रंश्रेज़ी सरकार ने देखा कि कांग्रेस कमज़ोर है, श्रीर शिक्त के प्रदर्शन से, व चालाकी से उसे श्रिहंसा की पटरी से उतार देने से, वह कुचली जा सकती है। उसने यह भी देखा कि मुस्लिम-लीग श्रपने स्वार्थ के कारण, उसकी सहायता करने के लिए तैयार है। उसे यह भी श्राशा थी कि श्रपने श्रपरिमित प्रचार-साधनों द्वारा वह संसार को धोखे में रख सकेगी। वह यह भी जानती थी कि स्वयं उसके देश की जनता, श्रुद्ध के नाम पर, ख़ामोश रखी जा सकती थी।

राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति

अगस्त १६४२ श्रीर उसके बाद के महीनों में सरकार ने राष्ट्रीय-श्रादोलन को कुचलने के लिए जो भी किया जा सकता था किया। देश भर में दमन-चक श्रपने पूरे बेग से चला। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों पर। लाठियों की मार पड़ी, श्रीर कॉलेज के विद्यार्थियों पर मशीनगनें चलाई गई। ऐसे लोग भी, जिनका राजनीति से दूर का संबंध भी नहीं था, जेल में डाल दिये गए। राष्ट्र एक वार तो वौखला उठा। जनता श्रात्म-नियंत्रण खो वैठी, श्रीर कुछ स्थानों पर उसने हिंसा का मार्ग भी श्रपनाया। उससे सरकार को श्रांदोलन के दवाने में सहायता मिली, पर श्रपने समग्र बल के समूचे प्रयोग से भी सरकार देश की राष्ट्रीय-भावनाश्रों को कुचल नहीं सकी। यह सच है कि मुस्लिम-जनता श्रांदोलन से सहानुभृति रखते हुए भी, मि॰ जिन्ना व श्रल्लामा मशिकी के श्रादेश के सामने, उसमें पूरा भाग न ले सकी, परन्तु उसने, मि॰ जिन्ना की इस घोपणा के बावजूद भी कि श्रगस्त-अस्ताव सरकार के प्रति विद्रोह का ऐलान ही नहीं, ग्रह-युद्ध के लिए खुली चुनौती भी था, कहीं राष्ट्रीय श्रान्दोलन का खुला विरोध नहीं किया। सरकार द्वारा युद्ध के श्राधुनिक हथियारों के प्रयोग के सामने श्रांदोलन का रूप बदल जाना तो स्वाभाविक ही था। महीनों

तक, देश के कोने-कोने से गुप्त संवाद-पत्र प्रकाशित होते रहे, हज़ारों-लाखों व्यिक्तियों ने स्वाधीनता की वेदी को अपने त्याग और बिलदान से सुलगते रखा, और नई-नई घटनाएं घटती रहीं। यह सच है कि दिन व दिन निराशा भी बढ़ती जा रही थी। पर, मई १९४४ में गांधीजी के छूटने के एक महीने के भीतर देश ने अपने खोये आत्म-विश्वास को फिर से पा लिया। उसके बाद एक वर्ष बीता भी नहीं था कि पूर्ण-स्वतन्त्रता की मांग को एक बार फिर हम न सिर्फ मकान की चोटियों से दोहराने ही लगे थे, आसपास के बातावरण में उसकी पूर्णि का आभास भी पाने लगे थे।

श्राज यह बात स्पष्ट होगई है कि भारतीय राष्ट्रीय श्रांदोलन एक ऐसी शक्ति है, जिसे कुचला नहीं जा सकता। स्राज तो कट्टर स्रंग्रेज़ भी इस तथ्य को समभ गए हैं। प्रवल दमन के बाद वातावरण में कुछ सन्नाया-सा रहता है, परन्तु उसका चक्र थमता भी नहीं कि ऋसंतोष की चिनगारियां फिर फूट निक-लती हैं। पुराने देश-भक्त जेलों में टुंस दिये जाते हैं। नये देशभक्तों की एक श्रमवरत शृङ्खला उनका स्थान लेने के लिए सामने श्रा जाती है। विरोधी पत्त की स्रोर से प्रत्येक 'चैलेंज' के बाद राष्ट्रीय स्रांदोलन ऋधिक सशक्त हो उठता है। जब सरकार ने मध्यम श्रेगी के राजनैतिक स्नान्दोलन-कर्तास्रों के विरुद्ध कुषकों के हित के सम्बंध में ऋपनी चिंता प्रगट की, कांश्रेस ने फ़ौरन किसानों को ऋपने न्यापक ऋांदोलन में समेट लिया । जब ऋंग्रेज़ी सरकार ने मसल्मानों को राष्ट्रीय-स्रांदोलन के विरुद्ध खड़ा करना चाहा, कांग्रेस उनमें से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को ऋपने साथ ले सकी । यह कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही था कि कांग्रेस ऋगरत १६४२ की उत्क्रांति में मुसल्मानों का पूरा सहयोग प्राप्त नहीं कर सकी । सरकार द्वारा ब्रस्पृश्य जातियों को मिला लेने के लिए जितने भी प्रयत्न हुए हैं, वे सब राष्ट्रीयता की चट्टान पर चकनाचूर होते रहे हैं। कांग्रेस तो देशी नरेशों के परम्परागत प्रभुत्व को पार करके उनकी प्रजा की अविभाज्य भिक्त को भी प्राप्त कर सकी है। पिछले कुछ वधों में शायद ही कोई हिंदुस्तानी ऐसा रह गंया हो, चाहे वह ऊंची सरकारी नौकरी में हो चाहे फ़ौज में, जो हिंदुस्तान की पूर्ण त्राज़ादी में विश्वास न रखता हो।

साम्प्रदायिक समभौते की सम्भावनाएं

परन्तु, यह कहा जा सकता है कि जब तक हमारी सांप्रदायिक समस्या सुलभ्त नहीं जाती, जब तक हिंदू और मुसल्मान दोनों मिलकर आज़ादी के लिए प्रयत्न-शील नहीं होते, तब तक हमारा स्वतन्त्र होनो असम्भव है। क्या भारतीय राष्ट्रीयता अपने समस्त बल को लगा कर भी सांप्रदायिक समस्या को सुलभा सकेगी १ इस संबंध में भी मैं निराश नहीं हूँ, यद्यपि शिमला कान्केंस (जून-जुलाई, १६४५) में मुस्लिम-लीग का जो खैया रहा उससे यह स्वष्ट होगया है कि समस्या जितनी कठिन दिखाई देती थी, उससें कहीं ग्राधिक कठिन है। सरकार ने मुसल्मानों को राष्ट्रीय जीवन से ग्रालहदा करने के जितने भी प्रयत्न किये, कांग्रेस उन सबको काटती छाई है। १६४२ में जब सर स्टैफ़र्ड किप्स ने पाकिस्तान की ग्रस्पप्ट मांग को व्यवहारिक राजनीति के स्तर तक उटा दिया, तव फ़ौरन राजाजी ने ग्रपनी योजना के द्वारा कांग्रेस श्रीर लीग के वीच की खाई को पाटने की कोशिश की। कांग्रेस उन दिनों ग्रंग्रेज़ी-साम्राज्य से संघर्ष में लगी हुई थी, इस कारण इस योजना पर अधिक ध्यान न दे सकी, परन्तु १६४४ में जेल से खाते ही गांधी जी ने उसके खाधार पर लीग के नेता से वातचीत श्रारम्भ कर दी । सितम्बर १६४४ में तीन सप्ताह तक गांधी जी श्रीर मि॰जिन्ना साप्रदायिक प्रश्नों पर विचार-विनिमय करते रहे। इस विचार-विनिमय में गांधी जा, भारतीय हितों को दृष्टि से श्रोभल न करते हुए, मुसल्मानों को संतुष्ट करने की दिशा में जितना आगे जा सकते थे, गये। हिंदू और मुसल्मान दो श्रलग राष्ट्र हैं, इस सिद्धांत की मानने के लिए तो वह तैयार नहीं थे, पर इसके श्रविरिक्त वह मुसल्मानों को सब कुछ देने के लिए तैयार थे। लाहौर-प्रस्ताव के सम्बंध में उन्होंने कहा कि वह विल्कुल उचित है, "जहां मुसल्मानों का बहुमत है वहां उन्हें श्रपना एक स्वतन्त्र-राज्य क़ायम करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, श्रीर यह बात राजाजी की व मेरी दोनों योजनाश्रीं में मान ली गई है। यह ग्रधिकार मुसल्मानों को, विना किसी हिचकिचाहट के, दे दिया गया है। परन्तु जहां तक एक ऐसी पूर्ण स्वतन्त्र सार्वभीम सत्ता का प्रश्न है जिसके श्रनुसार दोनों देशों में कोई सामान्य तत्व रहे ही नहीं, उसे मैं श्रसम्भव मानता हूं।" पिछले दिनों राष्ट्रपति मी॰ ग्राज़ाद ने ग्रपने वक्तव्यों द्वारा ग्रीर कांग्रेस-कार्य-सिमिति ने ऋपने प्रस्तावीं द्वारा प्रांतीय आत्म-निर्णय के सम्बन्ध में श्रपनी स्थिति को विल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है- श्रीर मैं मानता हूं कि सितम्बर १६४४ में क़ायदे-ग्राज़म के साथ ग्रपनी वातचीत में गांधीजी ने जो दृष्टिकोग्। लिया था, उसमें ग्रीर कांग्रेस की वर्त्तमान स्थिति में कोई ग्रान्तर नहीं है ।

मुस्लिम-लीग के पिछले रवैये, थ्रौर मुस्लिम जनता में लीग की लोकप्रियता, को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मुसल्मानों के सामने थ्राज धर्मान्धता थ्रौर राष्ट्रीयता के वीच एक को चुन लेने का सवाल है। मुस्लिम-लीग थ्रापने उस उदेश्य पर ही, जिसकी पूर्ति के लिए उसकी स्थापना हुई थी, थ्राज हट़ नहीं है। उसके निर्माण का मुख्य उदेश्य तो यह था कि मुसल्मानों के हितों व स्वाथों की रत्ता की जाए, परन्तु त्राज वह एक ऐसे त्रादर्श को लेकर -चल रही है जो मुस्लिम हितों व स्वार्थों के विल्कुल ही विरुद्ध जाता है। श्राज़ वह शिक्त की राजनीति (power-politics) में विश्वास करने लगी है--श्रीर मुस्लिम-जनता में श्रपनी शांकि को वढ़ाने के श्रच्छे-बुरे किसी भी साधन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी कारण, पिछले कई वर्षों में कांग्रेस द्वारा किए गए समभौते के सभी प्रस्तावों को वह ठुकरा चुकी है। वह न तो पाकिस्तान की अपनी मांग से हटने के लिए तैयार है और न अपने इस दावे को छोड़ने के लिए ही उद्यत है कि वह मुसल्मानों की एक मात्र प्रतिनिधि-संस्था है। ऐसी दशा में, मुस्लिम-लीग का राष्ट्रीय संग्राम में कांग्रेस के कंधे से कंधा मिड़ा कर खड़ा होना एक ऋसंभव कल्पना है। यह संभव हो सकता है कि मुस्लिम-लीग का प्रगतिशील स्रंग उसे ऋपना वर्तमान प्रतिकियावादी दृष्टिकीण वदलने पर मजबूर कर दे-पर इसमें मेरा श्रिधिक विश्वास नहीं है। मैं समभता हूँ कि ज्यों-ज्यों मुस्लिम-लीग एक कहर सांप्रदायिक दृष्टिकी ए लेती जाएगी, राष्ट्रवादी मुसल्मान ऋपनी शक्ति ऋौर संगठन को बढ़ाते जाएंगे। धर्माधवा ऋौर राष्ट्री-यता के वीच किसी एक चीज़ को चुन लेने की मुसल्मानों की जो ज़िम्मेदारी है, उसकी, पूरी अनुभूति उन्हें करा देने का दायित्व राष्ट्रवादी मुजल्मानों को ही है--- स्त्रीर, जान पड़ता है, शिमला-कान्फ्रेंस के वाद से वे लोग ऋपनी इस ज़िम्मेदारी को वहत ब्रब्छी तरह से समफने लगे हैं। मेरा तो पूरा विश्वास है कि स्नाने वाले चुनावों का परिणाम चाहे कुछ भी हो-कांग्रेस द्वारा उठाई गई त्राज़ादी की पुकार का देश के ऋधिकांश मुसल्मानों द्वारा समर्थन किया जाना त्र्यनिवार्य है—ऐतिहासिक परिस्थितियों त्रौर जनमत की त्रपरिमित शिक्तयों के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। हिंदुस्तान को त्राज़ाद होना है; हमें त्रपने देश के लिए प्रजातंत्र-शासन का एक नया प्रयोग करना है, मुसल्मान त्रात्म-निर्णय का ऋधिकार लेकर रहेंगे। ये ऐतिहासिक सत्य हैं जिनकी ऋोर से हम श्राँख मूँद नहीं सकते।

अन्तर्राष्ट्रीय जनमत

हमारे देश में एक दल ऐसा रहा—जिसके प्रतिनिधि सुभाष वोस थे—जो ऋंग्रेज़ों के शत्रु-राष्ट्रों की सहायता से हिंन्दुस्तान को ऋाज़ाद कर लेना चाहता था। हममें से ऋधिकांश ने कभी इसमें विश्वास नहीं किया, परन्तु ऋाज तो इस ऋाशा का स्रोत ही नष्ट हो गया है। एक दूसरा वहुत वड़ा वर्ग ऐसा था जो इंग्लैंड पर मित्र-राष्ट्रों के दवाव की ऋाशा रखता था। मेरा तो कुछ ऐसा विश्वास है कि उस नैराश्य ऋौर खीभ से भरी घड़ी में, जब कांग्रेस ने ऋपना

त्रगस्त-प्रस्ताव पास किया था, तव भी उसके प्रमुख नेतात्रों के मन से यह स्राशा विल्कुल ही लुप्त नहीं हो गई थी कि स्नन्य मित्र-राष्ट्र इंग्लैपड को भार-तीय राष्ट्रीयता के विरुद्ध कोई बड़ा क़दम नहीं उठाने देंगे। गांधी जी के फ़र्वरी १६४३ के उपवास के दिनों में, व बाद में जब इयू पीयर्सन ने रूज़बेल्ट के नाम फ़िलिप्स का पत्र छापा, ग्रौर विजयलद्मी पण्डित की ग्रामरीका-यात्रा के त्र्यवसर पर भी, लोगों की यह धारणा वनी रही कि इंग्लैएड पर शायद दवाव पड़े 📍 यह श्चन्तर्रोष्टीय जनमत का कुछ है कि हम अब इस बात को समफने लगे हैं कि अपनी आज़ादी के लिए हम केवल ग्रान्तर्राष्ट्रीय घटना-चक्र पर ही निर्भर नहीं रह सकते। यदि हम आज़ादी चाहते हैं तो हमें एक ओर तो हिन्दू-मुस्लिम समस्या का हल हूं ह निकालना है, ग्रीर दूसरी ग्रीर भारतवर्ष ग्रीर इंग्लैंग्ड के ग्रापसी संबंधों को निश्चित करना है। हम यह भी जानते हैं कि ये दोनों समस्याएँ एक दूसरे के साथ गुँथी हुई है, परन्तु हम यदि इन्हें सुलमा लें ग्रीर श्रपना राष्ट्रीय वल वढ़ा लें तो इंग्लैयड की इच्छा-शक्ति हमें ग़ुलाम रखने के पद्म में चाहे कितनी ही सशक्त क्यों न हो, हम उसे मुका सकेंगे।

हमें अपनी आज़ादी की लड़ाई में विदेशों से चाहे किसी प्रकार की सीधी सहायता न मिली हो, पर उसे अन्य देशों के लोकमत का समर्थन प्राप्त है, यह भी कुछ कम बात नहीं है। संसार के लोकमत का प्रभाव इंग्लैएड की भारतीय नीति पर पड़ना ग्रानिवार्य है। इंग्लैएड संसार से ग्रालहदा नहीं है-ग्रान तो कोई भी देश अपने को दुनियां से अलहदा नहीं मान सकता। अमरीका या रूस या चीन हिंदुस्तान की ऋाज़ादी के लिए क्या सोचते हैं, उसके प्रभाव से वह ग्रपने को मुक्त नहीं रख सकता। इंग्लैएड जानता है कि पिछले पाँच वर्षों में संसार का लोकमत कितना श्रिधिक भारतीय स्वतंत्रता के पत्त में वन गया है। कुछ प्रमुख ग्रमरीकन राजनीतिज्ञों--विल्की, वैलेस ग्रीर सम्नर वेल्स--ने हिन्दु-स्तान की ग्राज़ादी का खुले शब्दों में समर्थन किया है। रूस ने स्पष्ट शब्दों में श्रिधिक नहीं कहा, परन्तु उसके विदेश-मंत्री मो० मोलोटोव ने सैनफ्रांसिस्को में हिन्दुस्तान के संबंध में रूस के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से ग्राभिन्यक कर दिया है। मार्शल त्र्यौर मैडम च्यांग-काई शेक ने तो सदा ही हिन्दुस्तान की त्राज़ादी का पच्च लिया है। मध्य-पूर्व के सभी देशों में हिन्दुस्तान को ग्राज़ाद देखने की उत्सुकता है। इंग्लैएड में भी जनमत तेज़ी से भारतीय स्वतन्त्रता का समर्थंक वनता जा रहा है। प्रतिदिन सशक वनने वाजे विश्व के इस संगठित लोकमत के सामने इंग्लैएड की सरकार को अकना ही पड़ेगा।

समाधान की दिशा

फिर भी वास्तविक संघर्ष भारतीय राष्ट्रीयता--- त्राज़ाद होने की लगन--श्रौर श्रंग्रेज़ी साम्राज्यवाद-भौतिक सुविधाश्रों के मोह-के बीच है। भार-तीय राष्ट्रीयता जितनी सशक्त बनेगी, हमारी आजादी की लगन जितनी तीब्र होगी, उतना ही हम श्रंग्रेज़ी सरकार को समसौता करने के लिए श्रिधिक विवश कर सकेंगे । हमारे सामने सबसे बड़ा कार्य उन शिक्तयों का सुजन करना है जो इंग्लैएड में समभौते की भावना जायत कर सकें। केवल ग्रपनी त्र्यान्तरिक-सांप्रदायिक-समस्या का समाधान हूं ह लेने से ही काम नहीं चलेगा--यद्यपि उससे काम के चल निकलने में सुभीता बहुत ऋधिक हो जाएगा । इसी प्रकार केवल अन्तर्राष्ट्रीय जनमत को अपने पत्त में कर लेना ही काफ़ी नहीं है-वह तो त्र्याज भी पर्यात मात्रा में हमारे पक्त में है ही । हमारी राजनैतिक समस्या सुल-भेगी हमारे श्रीर इंलैएड के बीच एक सीधे समभौते,या संघर्ष, के परिखाम खरूप। इंग्लैंड को वह समभौता करने के लिए जिन साधनों के द्वारा मजबूर किया जाए वे हिंसात्मक हों ऋथवा ऋहिंसात्मक, यह भी एक प्रश्न है। मैं मानता हूं कि केवल भारतीय परिस्थितियों में ही नहीं, संसार के किसी भी देश में आज संगठित सरकार का हिंसा-द्वारा विरोध संभव नहीं रह गया है। परन्तु, यदि हिंसा व्यवहार्य नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी आशा के दीपक को बुक्ता दें, स्त्रीर भाग्य के सामने घुटने टेक दें। सौभाग्य से, स्त्राज हमारे बीचे श्रमर श्राशा का ध्रुव-तारा, गांधी, मौजूद है। वह हमारा मार्ग-प्रदर्शक है। उसके वताए हुए अहिंसा के मार्ग पर चल कर ही आज हमारी राष्ट्रीयता ने इतनी शिक्त संगृहीत की है। सिवनय अवज्ञा का प्रयोग अपने सामृहिक रूप में विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है-स्त्राज वे परिस्थितियां देश में मौजूद नहीं हैं-परन्तु, गांधी जी का बताया हुन्रा रचनात्मक कार्यक्रम हमारे सामने है। राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने का इससे अञ्छा स्रोर प्रभावपूर्ण दूसरा मार्ग नहीं है। रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा यदि हम त्रपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाते चलें तो हमारे देश के प्रति ऋंग्रेज़ों की न्याय वृत्ति ऋपने ऋाप ही सजग ऋौर दीपित हो उठेगी । तब हमें श्राज़ादी माँगनी नहीं पड़ेगी, वह दौड़ कर हमारे पास ऋाएगी।

: **=** :

पाकिस्तान : व्यवहारिक कठिनाइ्यां

सीमात्रों का निर्धारण

पाकिस्तान-संबंधी त्यांदोलन किस प्रकार देश के मुस्लिम-समाज में व्यापक होता गया, किन परिस्थितियों में मुस्लिम-लीग ने उसे ऋपनाया, ऋौर किन कारणों से उसने ब्राज इतना वल संगृहीत कर लिया है, इसकी विस्तृत चर्चा पहले श्राचुकी है। इस श्रध्याय में हम यह दिखाने की चेष्टा करेंगे कि यदि यह मान भी लिया जाय कि पाकिस्तान की मांग सर्वथा न्याय-संगत है, स्रौर हमारी सांप्रदायिक समस्या के सुलभाने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग है ही नहीं, तो भी कहां तक उसकी पुत्तिं सम्भव ग्रोर व्यवंहार्य है । इस संबंध में सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि मुस्लिम-लीग की वास्तविक मांग है क्या? लाहीर प्रस्ताव के अनुसार, "भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरी के समीप-स्थित इकाइयों की ऐसी हदवन्दी होनी चाहिए कि, स्रावश्यक प्रादेशिक हेर-फेर के बाद, जहां मुसल्मान बहुसंख्या में हों, जैसा कि भारत के उत्तर-पश्चिमी ख्रीर पूर्वी भागों में है, वहां उन्हें मिलाकर स्वाधीन राज्यों की स्थापना की जा सके।" यह मांग निःसंदेह त्रस्पष्ट है, त्रौर मुस्लिम-लीग व उसके नेतात्रों से स्वभावतः ही यह स्राशा की जाती थी कि वे इसकी विशद व्याख्या देश के सामने रखेंगे, पर न्त्राज तक लाहौर प्रस्ताव के स्पष्टीकरण की दिशा में कोई क़दम नहीं उठाया गया। प्रत्युत, ऋषैल १६४३ में जब मि॰ जिन्ना से पूंछा गया कि पाकिस्तान की हदवन्दी के सम्बन्ध में उनकी क्या कल्पना है, तो उन्होंने उसका उत्तर यह दिया कि मुस्लिम-लीग ने पाकिस्तान का कोई नवशा तैयार नहीं कराया है।

इस सम्बन्ध में पिछुले वर्षों में जो वाद-विवाद, विचार-विनिमय, भाषण-संभाषण, ऋख़वारी वयान व चर्चा, होते रहे हैं उनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम वहु-संख्यक प्रांतों में—उत्तर-पश्चिम, में सीमाप्रांत, पञ्जाव व सिंध, ऋौर उत्तर-पूर्व में वंगाल व ऋासाम, को मिलाकर वनाया जाएगा। परन्तु, जान पड़ता है, मुस्लिम-लीग ने ऋारम्भ से ही इस वात को समभ लिया था कि यदि ये प्रान्त ऋपने वर्त्तमान रूप में ही पाकिस्तान में सम्मिलित कर लिए गए तो उससे पञ्जाव व बङ्गाल के उन भागों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ वड़ा ऋत्याय होगा, जिनमें ग़ैर-मुसल्मानों की संख्यां मुसल्मानों के मुक्ताविले में बहुत ज़्यादा है। सम्भवतः इसी कारण 'प्रादेशिक हेर-फेर' की बात कही गई है। प्रादेशिक हेर-फेर के सम्बंध में यह ऋनुमान किया जाता है कि पज्जाव से ऋंवाला-डिबीज़न व बङ्गाल से वर्दवान-डिबीज़न को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त मिल सकेगी। यदि ऐसा हुऋा तो पज्जाव व बङ्गाल में मुसल्मानों की स्थिति ऋधिक हट हो सकेगी—क्योंकि उनका बहुमत कमशः ५७.१ से ६२.७ प्रतिशत और ५४.७ से ६५ प्रतिशत बटु जायगा।

प्रस्ताव में कहीं यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि पाकिस्तान की सीमात्रों के निर्धारण का त्राधार क्या रहेगा, परन्तु साधारणतः माना यह जाता है कि त्रात्म-निर्णय के त्र्रिधकार की दृष्टि से प्रत्येक प्रान्त को एक इकाई माना जायगा त्रौर उसकी धारासभा को, प्रान्त के लिए, निर्ण्य करने का ऋधिकार होगा। परन्तु इसमें कठिनाई यह त्राती है कि इतना बड़ा त्रीर महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रान्तीय धारासभा के बहुमत के हाथ में छोड़ देना कहां तक न्याय सङ्गत होगा। इस कठिनाई से वचने के लिए सर स्टैफ़र्ड किप्स ने यह सुभाव उपस्थित किया था कि यदि ऋखिल-भारतीय संघ-शासन में शामिल होने के पत्त में प्रान्तीय धारा-समा के ६० प्रतिशत से कम सदस्यों का मत हो तो इस प्रश्न का निर्णय प्रांत के वयस्क पुरुषों के हाथ में छोड़ देना चाहिए, पर मुस्लिम-लीग ने इस सुकाव को अस्वीकृत कर दिया। लीग का कहना था कि जब कि पाकिस्तान का . स्राधार इस सिद्धान्त में है कि मुसल्मान एक स्रलहदा राष्ट्र हैं, स्वभावतः उसके निर्माण में केवल मुसल्मानों का मत ही लिया जाना चाहिए। मुस्लिम-लीग का यह आग्रह स्वष्टतः ही अनुचित है, क्योंकि यदि किसी प्रान्त के मसल्मानों को त्रात्म-निर्णय का त्रिधिकार दिया जाता है, तो कोई कारण नहीं है कि उस प्रान्त के हिन्दू क्यों उस श्रिधिकार से वंचित रखे जाएं। इस कठिनाई से वचने के लिए डा॰ श्रम्येडकर ने यह सुभाव पेश किया था कि मुसल्मानों व हिन्दुश्रों को त्रलहदा-त्रलहदा त्रपनी सम्मति व्यक्त करने का श्रिधिकार दिया जाए । यह प्रस्ताव भी व्यवहारिक दृष्टि से वड़ा दोप पूर्ण है।

सिखों की समस्या

परन्तु, पंजाव के इस प्रकार के विभाजन के संबंध में सबसे वड़ा प्रश्न जो हमारे सामने आता है वह सिखों का प्रश्न है। अम्वाला-प्रदेश को पंजाव से अलहदा कर दिए जाने का अर्थ होगा, सिखों की मातृ-भूमि को दो भागों में वांट देना। सिख कदापि इस बात के लिए तैयार न होंगे। सिखों की संख्या बहुत कम है—पंजाव में भी उनकी आवादी १५ फ़ीसदी से अधिक नहीं है—

परन्तु वह एक योद्धा क्रीम हैं, श्रीर उनकी इच्छा की श्रासानी से श्रवज्ञा नहीं की जा सकती। पंजाव की राजनीति में सदा ही सिखों का प्रमुख भाग रहा है। यों तो देश की रहा में सिखों ने अपनी संख्या के अनुपात से बहुत अधिक भाग लिया है, पर ग्राज का पंजाव, ग्रार्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक सभी दृष्टिकोणीं से. सिखों का वड़ा ऋणी है। पंजाव में सिखों के ७०० से ग्राधिक गुरुद्वारे हैं, जिनकी ग्रपनी वड़ी संपत्ति है, व जिनके साथ उनके गुरुग्रों, सन्तों व शहीदों की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। ४०० से ग्राधिक शिचा-संस्थाएं, जिनमें कॉलेज, स्कूल, कन्या-पाठशालाएं ग्रौर ग्रौद्योगिक-शिचा संबंधी संस्थाएं शामिल हैं, उनके तत्वावधान में चल रही हैं। प्रान्त की सब से उपजाऊ ज़मीन उनके पास है, ग्रीर प्रान्त की ग्राय का ४० प्रतिशत से ग्राधिक सिखों द्वारा दिया जाता है। १९१९ के सुधारों में, गवर्नर की कार्यकारिसी के ३ सदस्यों में से १ सिख होता था, ग्रीर १६२६ से १६३७ तक, जब कार्यकारिणी में एक मुसल्मान सदस्य की वृद्धि हो गई थी, तत्र भी सिखों का प्रतिनिधित्व २५ प्रतिशत रहा। युनियनिस्ट मंत्रि मंडल के वनने के वाद भी उसे उस समय तक स्थायित्व नहीं मिल सका था, जब तक कि उसने सिखों के एक दल-विशेष के साथ समभौता नहीं कर लिया, ऋौर ऋकाली-दल के नेता सरदार वल्देवसिंह को मंत्रिमंडल में नहीं ले लिया ।

यह सब जानते हैं कि सिख अपने समस्त बल से पाकिस्तान का विरोध करेंगे। सिख इस बात को मान लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि पंजाब मुसल्मानों का प्रान्त है। उनका कहना है कि जब पंजाब की शहरी सम्पत्ति का द० फ़ीसदी से ज्यादा हिस्सा ग़ैर-मुसल्मानों के पास है, जब प्रान्त के आय-कर व सम्पत्ति-कर आदि का द० फ़ीसदी से अधिक भाग ग़ैर-मुसल्मानों द्वारा दिया जाता है, जब प्रांत के उद्योग-धंधे, कल-कारखाने, इंश्योरेंस व फ़िल्म कम्पनियां, ज्यापार और वाण्ज्यि, प्रधानतः ग़ैर-मुसल्मानों के हाथ में हैं, और जब प्रान्त के सांस्कृतिक जीवन के निर्माण और निर्देशन के स्रोत भी ग़ैर-मुसल्मान ही हैं, तब पंजाब को मुस्लिम-प्रांत मान लेना वस्तु-स्थिति का उपहास करना है। सिखों ने आरम्भ से ही पाकिस्तान का विरोध किया। उनके किप्स-प्रस्तावों को उकरा देने का मुख्य आधार यही था कि उनसे प्रांतों के बहुमत को आखिल-भारतीय संघ से अपने प्रांत को खलहदा कर लेने की इजाज़त मिल जाती थी। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की, ''अखिल-भारतीय-संघ से पंजाब को अलहदा करने के प्रयत्न का मुकाविला हम प्रत्येक संभव-साधन के द्वारा करेंगे।''

सिखों द्वारा पाकिस्तान का जो विरोध किया जा रहा है, उसे हम उपेक्षा की

दृष्टि से नहीं देख सकते। यदि, सिखों के विरोध के बावजूद भी, पाकिस्तान स्नमल में स्नाता है तो यह निश्चित मानना चाहिए कि पंजाब के स्नन्तर्गत एक सिख-पाकिस्तान का निर्माण होकर रहेगा। राजनैतिक, स्नार्धिक व सांस्कृतिक चेत्रों में सिखों को जो स्नमुविधाएं रही हैं, उनके संबंध में मुसल्मानों से कम कड़-वाहट उनके मन में नहीं है। उनका कहना है कि यों तो १६३५ के शासनिधान में ही, उन्हें पंजाब की धारासभा में १७५ में से केवल ३३, सीमाप्रांत में ५० में से ३ व केन्द्रीय धारासभा में २५० में से ६ स्थान देकर उनके राजनैतिक जीवन पर एक मर्माधात किया गया है, परन्तु स्वयं उनके स्रपने प्रांत, पंजाब, में भी उनके साथ स्नन्याय हुस्ना है। युक्त-प्रान्त में मुसल्मानों की स्नावादी केवल १३ प्रतिशत है, पर उन्हें ३० प्रतिशत स्थान प्राप्त हैं, परन्तु सिखों को पंजाब में केवल १६ प्रतिशत स्थान दिए गए हैं। पंजाब के मुस्लिम-मंत्रिमंडल की नीति के संबंध में भी उनकी शिकायतें कांग्रेसी-प्रांतों में मुसल्मानों की शिकायतों की तुलना में कम गंभीर नहीं हैं। उनका कहना है कि—

१—प्रांतीय शासन के कार्य-कारी-मंडल में सिखों का श्रनुपात कम कर दिया गया, व शासन के उच्च पद ज्यों ज्यों ख़ाली होते रहे, मुसल्मानों को दिए जाते रहे, सिखों को उनमें कोई स्थान नहीं मिला।

२—सिखों की शिक्ता-संस्थात्रों को निरुत्साहित करने की दिशा में यूनि-यनिस्ट-मंत्रिमंडल ने भरसक प्रयत्न किया, उन्हें जो सरकारी सहायता मिलती थी उसमें कमी की गई, व कई संस्थात्रों को सहायता देने से इनकार कर दिया गया।

३—प्रांत के हिन्दू, मुसल्मान व सिख सभी की मातृ-भाषा पंजावी होते हुए भी सारा सरकारी काम-काज उदू -भाषा व फ़ारसी लिपि में किया जाता है श्रौर प्रारंभिक शिद्धा के लिए भी उद् को ही माध्यम माना गया है।

४—सिखों के धार्मिक जीवंन में भी हस्तच्चेप किया गया। सरकारी व ग्रार्ड-सरकारी संस्थात्रों में 'भटके' पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सिखों का तो यहां तक कहना है कि पञ्जाव का समस्त शासन-तन्त्र मुसल्मानों का पच्चात, व ग़ैर-मुसल्मानों के साथ श्रन्याय, करता रहा है। इस विश्वास के होते हुए यदि वे किसी भी मुस्लिम वहुमत वाले शासन में श्रपने को पूर्ण सुरिच्चत न माने तो हम इस सम्बन्ध में उनसे कोई शिकायत कैसे कर सकते हैं ?

इसके साथ ही सिखों का एक अलग राष्ट्र होने का दावां भी कम से कम मुसल्मानों के दावे से कम वल नहीं रखता। पञ्जाव उनकी अपनी मातृभूमि है। मास्टर तारासिंह के शब्दों में, "पजात्र मुस्लिम प्रांत नहीं है। मैं तो यह भी नहीं मानता कि पञ्जाव की त्र्यावादी में मुसल्मानों का वहुमत है ।...पञ्जाव का इतिहास सिखों का इतिहास है। पञ्जाव सिख धर्म व सिख गुरुश्रों का जन्म-स्थान है। पंजाब के ऋधिकांश शहीद सिख शहीद हैं। सिख ही ऐसे लोग हैं जो उसकी संस्कृति ग्रौर भाषा में गौरव का ग्रानुभव करते हैं....मुस्लिम-कवि मका श्रीर मदीना के स्वप्न देखता है, हिंदू-किव गंगा श्रीर वनारस के गीत गाता है, परन्तु सिख कवि रावी ऋौर चिनाव का प्रेम ऋपनी कविता में ऋभिव्यक्त करता है। सिख ही सच्चे पंजावी हैं।" श्राखिल-भारतीय सिख-विद्यार्थी-संघ ने श्रपनी भावनात्रों को त्रौर भी ज़ोरदार शब्दों में व्यक्त किया है। उनका कहना है कि ''हिंदुस्तान में यदि कोई जाति एक ग्रालहदा राष्ट्र होने का दावा कर सकती है तो वह सिख जाति ही है । सिखों की हर वात निराली है । दुनियां में केवल यही एक ऐसी जाति है जिसमें सब व्यक्तियों के नाम का स्रंतिम शब्द एक ही है—यह उनकी स्रांतरिक एकता स्रोर स्रन्य लोगों से विभिन्नता का स्रच्छा उदाहरण है।...उनकी लिपि भी अन्य लिपियों से विलकुल भिन्न है। कपड़े व शक्त स्रत में भी उनमें त्रापस में बहुत त्राधिक समानता है। त्रांतरिक दृष्टि से हम एक बहुत ही सुसङ्गठित जाति हैं। हमारे श्रपने रस्मो-रिवाज हैं।" विचार कभी-कभी त्र्यांधी के वेग से वढते हैं। यदि कुछ ग़ैर-जिम्मेदार विद्यार्थियों के दिमाग से पैदा होकर पाकिस्तान की कल्पना अपना वर्त्तमान व्यापक रूप ले सकी, तो कौन कह सकता है कि ख़ालिस्तान की कल्पना कुछ लोगों के दिमाग में घट कर ही दम तोड़ देगी ?

पंजाब का विभाजन : अन्य कठिनाइयां

सिखों के विरोध की बात यदि हम छोड़ भी दें तो भी पड़ाब के विभाजन में अन्य व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं। पड़ाब के विभाजन का विचार नया नहीं है। सर जॉर्ज कॉर्बेट ने गोलमेज़-परिषद के अवसर पर उसे उठाया था। अक्टूबर १६४२ में कुछ हिंदू व सिख नेताओं ने दिल्ली में उस पर विचार-विनिमय किया था। यह कहा जाता है कि यदि उत्तर से दिल्ला तक, लाहीर-डिबीज़न को बीच से चीरती हुई, रेखा खोंची जाए तो उसके पश्चिम में रावल-पिएडी और मुल्तान के मुस्लिम बहुमत वाले, व पूर्व में अम्बाला और जालंधर के ग़ैर-मुस्लिम बहुमत वाले, प्रदेश होंगे, और लाहीर का प्रदेश ऐसे दो हिस्सों में बंट जायगा जिनमें से एक में मुस्लिम-बहुमत वाले व दूसरे में ग़ैर-मुस्लिम बहुमत वाले जिले होंगे। परन्तु, नक्शे पर पेंसिल से रेखाएं खींच देना एक बात है, और राज्यों की भौगोलिक सीमाएं निर्धारित करना दूसरी। यदि विभाजन के

इसी सिद्धांत को मान लिया जाय तो यह सवाल उठेगा कि स्वयं लाहीर नगर को पजाब के किस भाग में रखा जाय ? यदि हमारी विभाजन-रेखा लाहीर से पूर्व की स्त्रोर है, तो इसका यह अर्थ होगा कि लाहीर और अमृतसर दो विभिन्न देशों में रखे जायंगे । इन दोनों स्थानों के स्त्रार्थिक स्त्रीर सांस्कृतिक सामान्यत्त्वों को भी यदि दृष्टि से स्त्रोफल कर दें तो भी प्रश्न यह उठता है कि देश के बचाव के दृष्टिकीण से क्या यह तिनक भी सम्भव है कि लाहीर स्त्रीर स्त्रमृतसर के बीच कहीं भी विभाजन की यह रेखा खींची जा सके ? यदि हम पजाब के भौगोलिक मान-चित्र को देखें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इस प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार की हदवन्दी की गई तो वह पजाब की नहरों के जाल को, व उस पर निर्भर स्त्रार्थिक जीवन की एकता को, नष्ट-स्रष्ट कर देगी । स्त्रीर इन सब बातों के साथ-साथ हम यह भी न भूलें कि हमें यह सीमा-निर्धारण एक देश के दो प्रांतों के बीच नहीं, परन्तु दो विभिन्न देशों के बीच करना है, जिनके एक-दूसरे से विल्कुल स्वतन्त्र बनाये जाने की कल्पना की जा रही है, स्त्रीर जो, यह भी सम्भव है, इस स्वतन्त्रता का स्त्राधार लेकर एक-दूसरे से युद्ध में प्रवृत्त हो सकते हैं।

उत्तर-पूर्व की समस्या

उत्तर-पूर्व के प्रांतों में भी विभाजन की यह समस्या कुछ कम गम्भीर नहीं है। मुस्लिम-लीग सम्भवतः यह कल्पना कर रही है कि उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान में, वर्दवान-डिवीज़न निकाल कर, बङ्गाल व सारा त्र्यासाम शामिल होंगे । परन्तु समस्त श्रासाम को पाकिस्तान में सम्मिलित करने का विचार क्यों किया जा रहा है ? ग्रासाम की श्रावादी ६६'१ ग़ैर-मुसल्मानों की है। केवल सिलहट के ज़िले में मुसल्मान ६१°१ हैं। परन्तु श्रासाम की पाकिस्तान में शामिल न करने का प्रस्ताव भी उतना ही भ्रव्यवहारिक है, जितना शामिल करने का। यदि श्रासाम को हिंदुस्तान में रखा जाय, तो उसकी स्थिति दूर-पार के एक ऋाश्रित देश जैसी होगी, क्योंकि उसके और हिंदुस्तान के वीच पाकिस्तान की ज़मीन होगी । यह देखते हुए किं ग्रासाम के द्वारा हिंदुस्तान पर त्र्यासानी से त्र्याकमण किया जा सकता है, यह स्थिति त्र्यौर भी गम्भीर हो जाती है। परन्तु, पश्चिमी वङ्गाल को शेप-वङ्गाल से ग्रालहदा करने का प्रश्न तो इससे भी श्रिधिक जिंटल है। उसे किस सिद्धान्त के श्राधार पर वंगाल से जुदा किया जा सकेगा ? क्या इस संवंध में उसके निवासियों की सम्मति ली जायगी, श्रौर यदि ऐसा किया गया तो, क्या उनके निर्णय को मान्यता मिलेगी ? क्या पश्चिमी वंगाल की जनता के मन में मुस्लिम-तंस्कृति श्रीर उसके श्राधार पर वनने वाले उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान के प्रति घृणा श्रीर श्राकोश के भाव इतने प्रवल हो उठेंगे कि वह उस वंगाल से, जिसकी अिक के श्रावेश में श्राज वह 'श्रामार जननी, श्रामार वंग भूमि' के गीत गा रहे हैं, सदा के लिए श्रपना संवंध-विच्छेद करने के लिए तैयार हो जायंगे ? क्या हम इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि जिन वंगालियों ने कर्ज़न द्वारा वंग-भंग किये जाने पर श्राकाश को श्रपनी लपटों से चूमने वाला एक इन्क्रिलावी श्रान्दोलन खड़ा कर दिया था, वे श्राज उसकी पुनरावृत्ति को च्रपनाप स्वीकार कर लेंगे ?

यदि यह मान लिया जाय कि पाकिस्तान के पद्म में जो तर्क है वह अपनी तेज किरणों से बंगाल-प्रेम की इस भावना को काटने में समर्थ हो सकेगा, तो भी कुछ व्यवहारिक किटनाइयां रह ही जाती हैं। एक वड़ी किटनाई कलकत्ते के सम्बन्ध में है। कलकत्ते को किस देश में शामिल किया जायगा? कलकत्ता वंगाल का व्यापार-केन्द्र तो है ही, उसकी संस्कृति का भी हृदय है। व्यापार और संस्कृति दोनों की दृष्टि से उस पर हिन्दुओं का प्रभुत्व है। उसके ग्रास-पास जो ज़िले हैं उनमें हिन्दुओं की ग्राबादी ही ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या इस बात की कल्पना भी की जा सकती है कि कलकत्ता पश्चिमी बंगाल से हृद्यया जाकर पाकिस्तान में शामिल किया जा सकेगा? परन्तु,यदि कलकत्ता पूर्वी-पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया—ग्रीर कोई कारण दिखाई नहीं देता कि वह क्यों शामिल किया जाय—तो पूर्वी पाकिस्तान का क्या महत्त्व रह जायगा? उसकी स्थिति निष्प्राण शरीर जैसी रह जायगी, ग्रीर उसे प्रेरणा ग्रीर नेतृत्व के लिए, एक चौथे दर्जे के राष्ट्र के समान, उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान पर सर्वथा निर्भर रहना पड़ेगा। क्या यह स्थिति वड़ी बांछनीय ग्रीर स्ट्रहणीय होगी?

श्रावादियों की श्रदल-वदल

पंजाव व वंगाल के विभाजन की इन किटनाइयों के सामने यही मार्ग रह जाता है कि पाकिस्तान के प्रांतों में जो हिन्दू ग्रावादी है, उसे हिन्दुस्तान, व हिंदु-स्तान में जो मुस्लिम-श्रावादी रह जाय उसे पाकिस्तान, भेज दिया जाय। ग्रावादियों की ग्रदल-वदल का यह विचार प्रथम-महायुद्ध के वाद यूरोप में बहुत लोक-प्रिय हो गया था, परन्तु यूनानी ग्रीर तुर्की ग्रावादी की ग्रादल-वदल में जो ग्रामानुपिक, लोमहर्पक, ग्रीर भयंकर दृश्य देखने में ग्राये, उन्होंने इस विचार की ग्राव्यवहारिकता को विल्कुल ही स्पष्ट कर दिया। भारतीय परिस्थितियों में तो ऐसा होना विल्कुल ही ग्रासम्भव है। क्या हम इस वात की कल्पना भी कर सकते हैं कि एक मुसलमान किसान जो सैकड़ों वर्षों से, हिन्दू किसानों के वीच रह कर,

उनसे भाईचारे श्रीर मुहब्बत का वर्ताव रखता हुआ, अपनी ज़मीन को जोतता रहा है, श्रीर धूप श्रीर वारिश से अपने भींपड़े की रच्चा करता रहा है, किसी दूर-देश में जा वसने के लिए केवल इसलिए तैयार हो जायगा कि कोई एक मुस्लिम नेता या कोई एक मुस्लिम-जमात श्राज चीख़-चीख़ कर इस वात को कह रही है कि उसका अपना एक अलग राष्ट्र है, और इसलिए उसका अपना एक श्रलग देश भी होना चाहिए ? क्या हम सोच भी सकते हैं कि सिर्फ़ इसी श्राधार पर लखनऊ, दिल्ली या हैदराबाद में रहने वाले मुसल्मान पेशावर, करांची या ढाका में जा वसने को तैयार हो जायंगे, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि उन्हें जलवायु, भाषा, संस्कृति सभी में एक बड़े अन्तर का सामना करना पड़ेगा ? मैंने इस सम्बन्ध में देश के विभिन्न-प्रांतों में फैले हुए सैकड़ों मुसल्मानों से बात की है, श्रीर मैंने देखा है कि अपना जन्म-स्थान छोड़ने के लिए वे तिनक भी तैयार नहीं हैं—पाकिस्तान का समस्त आकर्षण भी उन्हें ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर सकता।

पाकिस्तान का ऋार्थिक-पहलू

सीमा-निर्धारण की कठिनाई से भी बड़ी एक त्रीर कठिनाई है जो पाकिस्तान की कल्पना के कियात्मक रूप लेने में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित करेगी। वह इस समस्या का त्रार्थिक-पन्न है। त्राव तक इस सम्बन्ध में लोगों के विचार बहुत स्पष्ट नहीं थे—तरह-तरह की कल्पनात्रों से काम लिया जा रहा था—पर हाल में ही होमी-मोदी त्रीर सर जॉन मथाई ने इस प्रश्न का विस्तृत त्र्रध्ययन करके त्रापनी रिपोर्ट सपू-कमेटी के सामने रखी थी, उससे पाकिस्तान के त्रार्थिक-पन्न पर त्राच्छा प्रकाश पड़ता है। इन लोगों के त्र्रध्ययन ने इस सम्बन्ध में बहुत-सी ग़लतफ़हिमयों को दूर करने में भी सहायता पहुंचाई है। मोदी-मथाई विज्ञाप्त में इस प्रश्न को तीन दृष्टिकोणों से देखा गया है। पहिले तो उन्होंने यह देखने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की सरकार त्रापनी वार्षिक त्राय-व्यय का उचित प्रवन्ध कर सकने की स्थित में होगी भी या नहीं। दूसरे, उन्होंने यह जानना चाहा है कि पाकिस्तान के बन जाने से उसमें रहने वाले व्यक्तियों के रहन-सहन के स्टैएडर्ड पर कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। त्रीर तीसरे, उन्होंने इस वात का विशेष त्रध्ययन किया है कि देश की रन्ना के दृष्टिकोण से पाकिस्तान की त्रार्थिक स्थित कैसी होगी।

मोदी-मथाई विज्ञिष्त में इन प्रश्नों का श्रध्ययन पाकिस्तान-संबंधी दोनों योजनाश्रों—मुस्लिम लीग की मांग व राजाजी-योजना—को दृष्टि में रखते हुए किया गया है। इन विद्वान् लेखकों का कहना है कि दोनों में से कोई भी योजना श्रमल में लाई जाय, पहिली दो वातों के दृष्टिकी ए से, उसकी रिथित श्राज के मुक्ताविले में बुरी नहीं होगी। उन प्रांतों को, जो अपने खर्चे के एक वड़े अंश के लिए ग्राज केन्द्रीय-सरकार की सहायता पर निर्भर रहते हैं, यदि यह सहायता मिलनी वन्द भी हो गई, तो भी उनके ग्राय के स्रोत इतने वह जायंगे कि वे प्रांतीय-शासन का भार स्वयं ही वहन करने की स्थिति में ग्रा जायंगे। ग्रन्य प्रांत भी शासन का ग्रापना वर्तमान स्टैएडर्ड क्रायम रख सकेंगे। लोगों के रहन-सहन पर भी बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। किसी भी देश के निवा-सियों का रहन-सहन, उसकी अनाज की उपज, औद्योगिक विकास के साधनों, श्रीर व्यापार श्रादि पर निर्भर रहता है । इस दृष्टि से पाकिस्तान की स्थिति हिन्दुस्तान की तुलना में कुछ बुरी नहीं रहेगी। इन प्रांतों में काफ़ी ऐसी ज़मीन है, जो उपजाक बनायी जा सकती है, और जिस ज़मीन पर आज खेती हो रही है वह भी-क्म-से-कम पश्चिमी-पाकिस्तान में-हिन्दुस्तान की ज़मीन से श्रिधिक उपजाऊ है। उद्योग-धन्धों के विकास की दृष्टि से यद्यपि पाकिस्तान में कोयले, मंगानीज व अन्य खनिज-पदार्थों की कमी होगी, पर ये चीज़ें, श्रावश्यक-तानुसार, ग्रन्य देशों से मंगाई जा सकती हैं, इनकी कमी पाकिस्तान के श्रीचोगी-करण में वाधक नहीं हो सकेगी। एक बात जो हमें ध्यान में रखना है,वह यह है कि पानी के वहाव से विजली पैदा करने की जितनी सविधा पाकिस्तान में होगी उतनी हिन्दुस्तान में नहीं होगी-पंजाव ही इतनी ग्राधिक 'हाइड़ो-इलैक्ट्रिक' शक्ति तैयार कर सकता है, जिससे समस्त देश की ऋावश्यकतास्त्रों की पूर्ति हो सके।

रज्ञा-सम्बन्धी व्यय

पर, वास्तविक समस्या तो रत्ता—सम्बन्धी व्यय को जुटा पाने की है। स्राने वाले वधों में रत्ता-विभाग पर हमें वहुत अधिक ख़र्च करना पड़ेगा। हमें स्रपनी पैदल-फ़ौज को, श्राधुनिक पद्धति पर, पुनः संगठित तो करना ही है, पर जहां तक हमारी समुद्री व हवाई ताक़त का संबंध है, उनका तो हमें नये सिरे से ही निर्माण करना है। लड़ाई के पहिले हमारा रत्ता-संबंधी ख़र्च ५० करोड़ रुपए वार्षिक के लगभग था। जानकार लोगों का कहना है कि लड़ाई के वाद हमारा वार्षिक व्यय कम से-कम १०० करोड़ का होगा। इसके स्रलावा, यदि हिन्दु-स्तान को दो टुकड़ों में वांट दिया गया तो विदेशी स्राक्रमणों का डर स्राज के मुक्ताविले में बहुत स्रधिक बढ़ जायगा स्रोर यह भी स्रभी तो निश्चित नहीं है कि हिन्दुस्तान स्रोर पाकिस्तान के स्राप्त संवंध मैत्री के ही होंगे। यदि इन परि-रिथितियों को भी ध्यान में रखें तब तो पाकिस्तान स्रोर हिन्दुस्तान दोनों को स्रप्ता स्वा-व्यय कई गुना स्रधिक बढ़ाना पड़ेगा। पर यदि तर्क के लिए यह

मान भी लिया जाय कि हिन्दुस्तान का बंटवारा ऋापसी समभौते से होता है, श्रौर बाद में भी इन दोनों पड़ौसी ऋौर स्वतन्त्र देशों में मैत्री ऋौर भाई-चारे का वर्ताव रहता है, तो भी दोनों देशों को मिल कर रच्ना-विभाग के लिए कमसे-कम १०० करोड़ रुपए वार्षिक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मुस्लिम-लीग के लाहौर-प्रस्ताव के ऋनुसार पाकिस्तान का निर्माण यदि प्रांत के ऋाधार पर होता है तो उसे इस ख़र्चे में से २६ करोड़ का भार ऋपने ऊपर लेना होगा, ऋौर यदि वह, राजाजी-योजना के ऋनुसार, मुस्लिम बहुमत वाले ज़िलों के ऋाधार पर वना तो उसके हिस्से २३ करोड़ रुपए का ख़र्चा ऋायेगा। क्या पाकिस्तान की ऋार्थिक स्थित ऐसी होगी कि वह रच्ना पर इतना ऋधिक ख़र्च कर सकेगा?

इस संबंध में विल्कुल सही संख्यात्रों का ऋनुमान लगा लेना तो ऋसंभव ही है, पर मोदी मथाई विज्ञति में इस प्रश्न पर वड़ी उदारता से विचार किया गया है, स्त्रीर उसका निष्कर्ष यह है कि पाकिस्तान, प्रांत स्त्रथवा ज़िले पर वनाये जाने की स्थिति में, क्रमशः १४ ऋथवा ६ करोड़ रुपया इस काम के लिए वचा सकेगा, स्रोर यदि पाकिस्तान की सरकार ने इस दिशा में बहुत ही स्रिधिक प्रयत्न किया, श्रीर एक श्रीर शासन का खर्चा कम करके व सर्वसाधारण के लाभ की समस्त योजनात्रों को बन्द करके ऋौर दूसरी ऋोर संपत्ति ऋौर ज्यापार ऋादि पर टैक्स बढ़ाकर कुछ ऋौर रुपया निकालना चाहा तो वह एक तो जनता की तकलीफ़ों को वढ़ा देगा, श्रीर उनमें विच्छोभ व नाराज़गी की भावनाश्रों को जन्म देगा और दूसरे, इतना कम होगा कि उससे स्थिति के सुधरने की विशेष स्राशा नहीं होगी। यहां हम यह न भूलें कि मोदी-मथाई विज्ञति में इन संख्यास्रों पर ऋधिक-से-ऋधिक उदारता से विचार किया गया है। प्रो॰ कृपलैएड के श्रनुसार पाकिस्तान साधारगतः ३ करोड़ से श्रिधिक रुपया श्रपने रज्ञा-विभाग के लिए नहीं वचा सकेगा, श्रौर श्रन्य उपायों द्वारा भी वह ५ करोड़ से श्रिधिक रुपया इस काम के लिए नहीं जुटा पाएगा। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि पाकिस्तान करेगा क्या ? यदि वह अपने सैनिक इयय में कमी करता है तो वह खुले-स्राम विदेशी स्राक्रमण-कारियों को निमन्त्रण देता है। यदि इस सम्बन्ध में वह हिन्दुस्तान की सहायता पर निर्भर रहता है तो यह निश्चित है कि जिस सार्वभीम-सत्ता की कल्पना त्राज पाकिस्तान के समर्थकों के मन में है वह स्वप्न-मात्र रह जायगी; वैसी स्थिति में बहुत-सी दूसरी वातों के लिए भी पाकि-स्तान का हिन्दुस्तान पर निर्भर रहना त्र्यनिवार्य हो जाऐगा त्र्यौर याँद, पाकिस्तान इंग्लैएड ग्रथवा श्रन्य किसी वाहरी देश पर इसके लिए निर्भर रहा तो उसका भाग्य, ग्रथवा दुर्भाग्य, रह जायगा सदियों तक उस विदेशी राष्ट्र की ग़लामी का

तौक ग्रपने गले में डाल कर उसके इशारे पर नाचना। सच तो यह है कि ग्राज स्थिति यह है कि यदि त्राजादी की कल्पना की जा सकती है तो राष्ट्रीय एकता के त्राधार पर ही; इस एकता के छिन्न-भिन्न होने का श्रथ होगा आजादी के सपनों को धूल में विखेर देना।

श्रार्थिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से

यदि हम वस्तु-स्थिति की गहराई में प्रवेश करें तो यह स्पष्ट देख सर्केंगे कि त्राज तो राष्ट्रीय बचाव का ऋर्थ होगया है, देश का ऋौद्योगीकरण । वही देश ग्राज ग्रपने वचाव की ग्राशा कर सकता है जिसके पास ग्रार्थिक उन्नित के श्रपरिमित साधन हों, श्रीर जो उन साधनों का समुचित विकास करने की स्थिति में हो। इस दृष्टि से यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को देखें तो .इस युद्ध में मित्र-राष्ट्रों की विजय का श्रेय जिन दो वड़े राष्ट्रों को दिया जा सकता है, वे हैं ग्रमरीका ग्रीर रूस, ग्रीर दोनों ही ऊपर दी गई शर्त्त को पूरा करते हैं, दोनों के पास श्रापरिमित साधन हैं, श्रीर दोनों ने उनका श्राधिक से-ग्राधिक विकास किया है। जिन देशों की ग्रर्थनीति नितांत स्वावलंबिनी नहीं थी-जर्मनी, इटली, जापान ग्रादि—वे सब हारे। स्वयं इंग्लैएड की स्थिति भी डांवाडोल है। प्रो॰ लॉस्की ने ग्रभी उस दिन कहा था कि ग्रय वह स्वेडन के समान, एक द्वितीय श्रेगी की शिक्त रह गया है। यदि वह अमरीका या रूस दोनों में से किसी एक पर निर्मर-- ग्राश्रित नहीं रहना चाहता तो उसके लिए केवल यही एक मार्ग रह गया है कि वह पश्चिमी-यूरोप के देशों को राजनैतिक व स्त्रार्थिक दोनों दृष्टियों से संघ-वद बनाने का प्रयत्न करे । उन छोटे देशों के लिए तो त्र्याज की दुनियां में कोई स्थान रह ही नहीं गया है, जो ग्रपने सीमित साधनों से ग्रपना वचाव करना चाहते हैं। ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों का विश्वास है कि संसार में ग्रामरीका ग्रीर रूस को छोड़कर केवल दो ग्रान्य देश हैं जो विना किसी वाह्य-शिक्त पर निर्मर रहते हुए, ऋार्थिक दृष्टि से संपूर्ण-स्वावलंत्री हो सिकते हैं, ग्रौर जिनमें संसार की महान् शांकि वनने की चमता है—वे हैं चीन ग्रौर हिंदुस्तान ।

हिंदुस्तान दुनियां की आने वाली राजनीति में एक शानदार स्थान प्राप्त कर सकता है—वशर्त्त कि वह आज की अपनी भौगोलिक एकता को कायम रख सके। हिंदुस्तान यदि इस आदर्श को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी आर्थिक उन्नित के समस्त साधनों का विकास करे। परन्तु देश के दुकड़ों में वंट जाने के वाद यह आर्थिक विकास असंभव हो जायगा। आर्थिक विकास की दृष्टि से भी आज उन विस्तृत भू-खरड़ों का, जो

भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरे के समीप हों, मिल-जुल कर काम करना आवश्यक होगया है। किसो भी दृष्टि से हम इस प्रश्न का विचार करें, हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि, ग्रपनी भौगोलिक एकता को क़ायम रखते हुए, श्राज हिंदुस्तान के सामने विकास का एक अभूतपूर्व अवसर है। किसी भी उद्देश्य से सही, ऋंग्रेज़ी शासन ने पिछले डेढ़-सौ वर्षों में समस्त देश को एक शासन-सूत्र में पिरो दिया है । देश भर भें एक ही मुद्रा का प्रचार है; रिज़र्व-वैंक का स्त्राधार लेकर वैङ्कों को एक-दूसरे से गूंथ देने वाला एक जाल-सा फैला है; देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैली हुई हज़ारों मील लम्बी सड़कें हैं, ट्रेनों के आने-जाने की न्यवस्था है, श्रीर सभी महत्त्व के स्थानों पर हवाई जहाज़ों के श्रेड्डे हैं। इसके श्रविरिक्त, हमारे पास एक श्रोर कृषि के लिए काफ़ी ज़मीन है श्रीर दूसरी श्रोर सभी त्रावश्यक खानज पदार्थ पयास मात्रा में हैं। संसेप में, हमारे पास वे सभी साधन मौजूद हैं जो एक बड़े राष्ट्र के लिए ब्रावश्यक हैं। केवल एक चीज़ है, जो हमारे त्राज के विषएण जीवन श्रीर भविष्य की महानता के मार्ग में व्यवधान वनकर खड़ी है-वह है हमारी गुलामी। गुलामी की इन ज़ंज़ीरों के टूटते ही-ग्रौर स्रव इनके दिन इने-गिने ही रह गए हैं—हम स्रंतरीष्ट्रीय जगत में उचित स्थान पा सकेंगे।

पर यह तभी सम्भव है जब हिंदुस्तान की राजनैतिक एकता कायम रखी जा सके । हिंदुस्तान के दो कृत्रिम श्रीर श्रप्राकृतिक भागों में वंटते ही श्रार्थिक पुनर्निर्माण की समस्त योजनाएं, ऋौर राजनैतिक महानता के समस्त स्वप्न, ऋपने श्राप ही ख़त्म हो जायंगे। जलवायु, ज़मीन श्रीर खनिज पदाधों के चंटचारे की जो विभिन्नता एक ऐसे वड़े देश में, जहां ग्रायात-निर्यात की ्गति मुक्त ग्रौर निर्वाध है, शक्ति का त्राधार वन जाती है, वही छोटे-छोटे दुकड़ों के न्यार्थिक विकास में एक वड़ी वाधा वन कर ऋा खड़ी होगी। इस संबंध में हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि देश के इस बंटवारे में आर्थिक हिए से अधिक हानि पाकिस्तान के प्रांतों की होगी। उसके दोनों भागों-उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान व उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान-के वीच में ७०० मील लम्बी ज़मीन एक विदेशी सर-कार के ग्राधिपत्य में होगी—ऐसी स्थिति में उसके लिए ग्राधिक विकास की एक संयुक्त समन्वित योजना बना पाना भी संभव नहीं होगा । इसके ऋतिरिक्त कोयले, लोहे, मंगानीज़ व ग्रन्य खनिज पदायों की उसकी कमी ग्रौद्योगिक विकास में वाधक तो होगी ही - चाहे वह महंगे दामों पर इन चीज़ों को दूछरे देशों से खरीद कर श्रपने उद्योग-धन्धों के विकास का प्रयत्न करे। यदि पाकि-स्तान के पास श्राधिक साधन ऋधिक नहीं हैं, श्रीर जो हैं, उनका भी यह सम्-

चित विकास नहीं कर पाता, तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका भविष्य बहुत आशाप्रद नहीं होगा। संसार का कोई भी सशक्त राष्ट्र उसे अपने पैरों तले रोंद सकेगा, और उसकी दशा एक शतरंज के मोहरे जैसी होगी, जिसे कुशल खिलाड़ी, अपनी शिक्त बढ़ाने की दृष्टि से, जहाँ चाहे वहाँ रख देता है।

अन्य विरोधी तत्त्व : अंग्रेजी सरकार

इन भौगोलिक ग्रौर ग्रार्थिक किठनाइयों के साथ हम.उन शिक्तशाली राजनैतिक तन्तों को भी नहीं भूल सकते जिनका विरोध पाकिस्तान की समस्त कल्पना को कियात्मक रूप लेने से वैसे ही रोक सकता है—जैसे एक मज़बूत वाँध एक छोटी-सी नदी के प्रवाह को । इन राजनैतिक तन्त्रों में हम सबसे पिहले ग्रंग्रेज़ी सरकार को ही लें । यह सच है कि वर्तमान महायुद्ध के प्रारंभिक वर्षों में, जब मित्र-राष्ट्रों की परिस्थित डांबाडोल थी, भारत की ग्रंग्रेज़ी सरकार ने मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की माँग का ग्रप्रत्यक्त रूप से समर्थन किया, पर उसके लिए तो कुछ विशेष परिस्थितियां जिम्मेदार थीं । उन परिस्थितियों के बदलते ही ग्रंग्रेज़ी सरकार का दृष्टिकोण भी बदला—ग्रौर तब से प्रमुख ग्रंग्रेज़ ग्रिधिकारी देश की एकता की ग्रावश्यकता पर ज़ोर देने लगे हैं । सच तो यह है कि ग्रंग्रेज़ इस प्रश्न पर ग्रपने स्वाथों ग्रौर हितों की दृष्टि से ही ग्रपनी नीति निर्धारित करेंगे । वे न तो कांग्रेस के कहने भर से हिन्दुस्तान छोड़ कर चले जायंगे ग्रौर न मुस्लिम-लीग के इस सुकाब पर ही कि पहिले हिन्दुस्तान को दो हिस्सों में वाँट दें ग्रौर तब चले जायं, ग्रमल करेंगे । उनका वस चलेगा तो वे हिन्दुस्तान में ग्राथसी मतमेदों को क्रायम रखेंगे, ग्रौर यहाँ जमे रहेंगे।

ग्रंगे कों को यदि हिन्दुस्तान से जाना ही हुन्रा तो वे उसे दो ऐसे भागों में वाँट देने के वदले, जिनके सशक्त वन जाने की सम्भावना होगी, कई छोटे-छोटे भागों में वाँट देना श्रिषक श्रन्छा समभेंगे। इस संवंध में प्रो॰ कृपलैपड श्रादि कई श्रंगे कों को योजनाएं हमारे सामने हैं हीं, परन्तु, यदि यह मान लिया जाय कि श्रमी कुछ श्रसें तक, हिन्दुस्तान के श्राज़ाद हो जाने पर भी, इंग्लैएड एशिया में श्रपने श्राधिक स्वाथों को कायम रखने की चेष्टा करेगा, तो यह श्रिषक संमान्य दिखाई देता है कि वह हिन्दुस्तान की शासन-सम्बन्धी एकता के कायम रखने पर ज़ोर देगा। यहाँ हमें यह न भूज जाना चाहिए कि श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से श्राज राजनैतिक गुरुत्व-शक्ति का केन्द्र श्रटलंगिटक से हट कर प्रशान्त-महासागर में श्रा गया है। इस दृष्टि से समस्त एशिया की राजनीति श्रीर श्र्यंनीति के द्वेतों में श्रपने हितों की रज्ञा की दृष्टि से इंग्लैएड के लिए यह श्रिन्वार्य होगा कि वह एक संयुक्त-भारत के विकास में सहायक हो।

भारतीय राष्ट्रीयता की सहानुभूति प्राप्त करके ही वह एशिया में अपनी खिति कायम रख सकता है। फिर भी इंग्लैग्ड के लिए तो यही कहना ठीक है कि वह इस संबंध में अपना दृष्टिकाण, परिखितियों के अनुसार, अपने स्वाधों और हितों को प्रमुखता देते हुए ही बनायेगा। जहाँ तक आज की स्थिति है, यह निश्चय जान पड़ता है कि अंग्रेज़ी सरकार पाकिस्तान-संबंधी किसी ऐसी योजना का समर्थन नहीं करेगी जिसमें उसकी एक स्वतंत्र, सार्वभौम सत्ताका निर्माण होता हो। कट्टर हिन्दू दृष्टिकोण

'अखएड हिन्दुस्तान' के नारे के साथ कहर हिन्दुओं द्वारा पाकिस्तान का जो विरोध किया जाता है, उसका श्राधार तर्क से श्रिधिक भावना में है। तर्क की दृष्टि से यदि उसे तौला जाय तो वह पाकिस्तान के समर्थन में एक वड़ी दलील का रूप ले लेगा । उसका आधार इस भावना में है कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं का है, श्रीर मुसल्मान इस देश में एक विदेशी तत्त्व के रूप में हैं। वे यदि हिन्दुर्श्रों के संरक्तरण में, उनकी दया के पात्र वन कर, रहना चाहें तो रह सकते हैं, श्रन्यथा जहाँ जाना चाहें, जा सकते हैं। कभी-कभी तो उनकी तुलना यहदियों से की जाती है, ऋौर उनके लाभ के लिए, यहूदियों के प्रति नात्सी-सरकार का जो व्यवहार रहा, उसकी श्रोर उनका ध्यान श्राकर्षित किया जाता है। कांग्रेंस के भीतर भी एक दल ऐसा है जो एक संस्कृत-प्रधान भाषा को मुसल्मानों पर लादने के पत्त में है, ऋीर जो यह मानता है कि 'वन्देमातरम्' व राष्ट्रीय भंडे के प्रति स्रादर व्यक्त करने के लिए उन्हें वाध्य किया जाना चाहिए । पर, हिन्दू महासभा तो इस सम्बन्ध में नीति ख्रीर मर्यादा ख्रीर राज-नीति की सभी सीमात्रों को लांघ चुकी है। वीर सावरकर के 'वीरतापूर्ण' शब्दों में, ''जब हम बदला लेने की स्थिति में होंगे, श्रीर बदला लेंगे, तो एक दिन में मुसल्मानों के होशा ठिकाने त्र्या जायंगे—त्वत्र उन्हें पता लगेगा कि हिन्दुत्रों पर जुल्म करने की कोशिश का नवीजा क्या होता है श्रीर उससे मुसल्मानों को कितना वड़ा नुक्तसान पहुँचने की संभावना है - तव वे भले आदिमियों का-सा वर्ताव करना सीखेंगे।"

यह मनोवृत्ति है जिसने पाकिस्तान की कल्पना को जन्म दिया । यदि हिन्दुग्रों का विश्वास है कि मुसल्मान इस देश में एक विदेशी तन्त्र हैं, ग्रौर उन्हें उपेत्ता ग्रौर घृगा की दृष्टि से देखना चाहिए, तो मुसल्मानों के मन में यह भावना उठना स्वाभाविक है कि उन्हें ग्रपनी एक स्वतन्त्र शासन-सत्ता की स्थापना कर लेना चाहिए । वैसी शासन-सत्ता वे इस देश के वाहर कहाँ खड़ी १. दिसम्बर १६३= में सभापति के पद से दिये गए भाषण का एक ग्रंश। कर सकते हैं ? वे भी हिन्दुस्तान की मिट्टी से वने हैं, ग्रीर हिन्दुस्तान की ज़मीन के ज़रें-ज़रें पर उनका उतना ही हक है जितना हिन्दुग्रों का । यदि हिन्दू ग्रीर मुसलमान मिल-जुल कर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो हिन्दु-स्तान का दो हिस्सों में वंटवारा कर दिया जाना उतना ही स्वाभाविक ग्रीर न्याय-संगत है जितना उन दो भाइयों का ग्रपनी मौरूसी जायदाद को वाँट लेने के लिए ग्राग्रह-शील होना, जो प्रेम से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं । सच तो यह है कि हिन्दुग्रों का हिन्दुत्व के नाम पर देश के एकाधिपत्य का स्वप्न देखना ही दो राष्ट्रों की कल्पना को वल देता है, ग्रीर मुसलमानों के लिए एक स्वतन्त्र-देश के निर्माण की माँग को ग्राधिक तर्क-पूर्ण बना देता है । पर, तर्क से ही तो काम नहीं चलता । मैं यह जानता हूँ कि कटर हिन्दू इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, ग्रीर भारतीय राष्ट्र की एकता के सम्बन्ध में वे इतने संवेदन-शील ग्रीर भाव-प्रवण हैं कि ग्रपने समस्त बल को लगा कर भी वे पाकिस्तान का विरोध करेंगे । इस विरोध के पीछे, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, तर्क का बल चाहे ग्रधिक न हो, पर इतने बड़े समुदाय का भावना-वल इतना ग्रधिक होगा कि उसकी भी उपेन्ना नहीं की जा सकती।

गृह-युद्ध की सम्भावना ?

तव, होगा क्या ? यदि हिंदू ऋौर मुसल्मान दोनों ही ऋपने ऋाम्रहसे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्यों न एक गृह-युद्ध के द्वारा इस प्रश्न को सुलमा लिया जाय ? यह हो सकता है कि उसके वाद हम या तो स्विज़रलैएड श्रीर श्रमरीका के संयुक्त-राज्य के समान अपना एक संघ वना लें यां दिच्चा अमरीका के समान ऋपने को कई देशों में वांटने का निश्चय कर लें। परन्तु यह मानते हुए भी कि देश में हिंदुऋों की संख्या ऋधिक है, कीन कह सकता है कि इस यह-युद्ध का परिणाम क्या होगा ? बहुत संभव है कि यह परिणाम देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न रूप ले ले। यह भी संभव है कि जिन प्रांतों में ज्याज मुसल्मानों का बहुमत है, वहां वह ग्रापने बाहु-वल से ग्रापना स्वतन्त्र-राज्य क्वायम कर सर्वे-श्रीर तब उस संघर्ष के परिणाम-स्वरूप उन प्रदेशों की स्वतन्त्र-सार्वभौम सत्ता मानने के लिए हमें विवश होना पड़े जिन्हें ज़वरर्दस्ती भी ग्रापने साथ रखने के लिए हम त्राज इतने उतावले हैं! परन्तु, ग्रीर यह एक ग्रावश्यक ग्रीर महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, क्या जव कि श्रंग्रेज़ी सरकार मौजूद है, वह हमें ऐसे गह-युद्ध की सुविधा देने के लिए उद्यत हो जायगी ? यह हो सकता है कि, हमारी सांप्र-दायिक मनोवृत्ति के पोपण की दृष्टि से, वह देश में यहां-वहां छोटे-मोटे दुन्ने हो जाने दे, परन्तु वह हमारे लिए एक देश-व्यापी यह-युद्ध का आयोजन तो कदापि

नहीं करेगी । इस प्रकार के गह-युद्ध संगठित राजतन्त्रों की शिक्तित सेनाश्रों द्वारा लड़े जाते हैं—वैसा होना ब्रिटिश-राज्य के रहते श्रसम्भव है। सच तो यह है कि इस प्रकार की तैयारी की भनक भी यदि उसके कान में पड़ गई तो वह उसे,जनता की रक्ता के नाम पर, श्रपनी सैन्य-शिक्त श्रौर देश पर श्रपने शिकंजे को श्रौर श्रिक मज़बूत बना लेने के काम में उपयोग करेगी।

राष्ट्रवादी मुस्तिम-संस्थाओं का मत

इस सम्यंध में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सभी मुसल्मान पाकिस्तान की मांग का समर्थन नहीं कर रहे हैं—कुछ तो उसका तीव्र विरोध भी कर रहे हैं। यह कहना तो कठिन है कि देश की मुस्लिम आवादी का कितना भाग मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांगके पीछे हैं। मुस्लिम-लीग की सदस्यता की ठीक संख्याका अनुमान करना भी कठिन ही है। १६३६ में तो प्रांतीय धारा-सभाओं में लीग की ओर से कुल १०८ सदस्य चुनेगए थे, जबिक अन्य मुस्लिम-संस्थाओं की ओरसे ३६६ सदस्य थे। यह सच है कि पिछले द्वधों में मुस्लिम-लीगका वल बहुत बढ़ गया है, पर आज भी वह मुसल्मानों की अकेली प्रतिनिधि-संस्था तो कदापि नहीं है। अशित्ति और राजनैतिक चेतना-धारा से कोलों दूर जो करोड़ों मुसल्मान इस देश में हैं, उन्हें छोड़ भी दिया जाय, और केवल उन्हों मुसल्मानों को लिया जाय जो राजनैतिक हिष्ट से जागत और विचार-शील हैं तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि उन सभी ने मुस्लिम लीग को अपनी एकिन्छ राजमिक दे रखी है, अथवा वे पाकिस्तान को हमारी सांप्रदायिक और राजनैतिक समस्याओं का एक-मात्र राजमार्ग मानते हैं।

मुस्लिम-लीग के वाहर भी श्रानेकों मुस्लिम राजनैतिक संस्थाएं हैं। ख़ाकसार हैं, जमीयत-उल-उल्मा है, श्रहपर हैं, शिया राजनैतिक कांफ्रेंस हैं, मोमिन हैं, कांग्रेस-वादी मुसल्मान हैं श्रोर वे सहस्त-सहस्र मुसल्मान हैं, जो श्रपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। इनमें से कोई भी पाकिस्तान के पत्त में नहीं है—श्रोर श्रिथकांश तो उसे एक ग़ैर-इस्लामी नारा मानते हैं। १६४० में इस प्रकार की ६ मुस्लिम-संस्थाश्रों ने मिल कर एक श्रांखिल-भारतीय श्राज़ाद-मुस्लिम वोर्ड की स्थापना की। मार्च १६४२ में, इस वोर्ड ने श्रपनी एक वैठक में लीग के मारतीय मुसल्मानों के प्रतिनिधित्व के दावे को एक 'श्रांबिश्वस्तीय धोखां' दताया, श्रोर हिंदुस्तान की एकता में श्रपना विश्वास प्रगट किया। श्रांखिल भारतीय नोमिन-कांग्रेंस ने श्रपने एक प्रस्ताव के द्वारा घोपणा की कि ''वह हिंदुस्तान की श्रांबिभाव्यता, एकता व सङ्गठन को भारतीय जनता के सामान्य लाभ की हिंद से, श्रोर विशेष- कर भारतीय मुसल्मानों के हित की हिंद से, श्रांविवार्य समस्ती है।"

परन्तु, हम यह न भूलें कि लीग का लाख-विरोध करते हुए, व पाकिस्तान की कल्पना को निराधार और मुस्लिम हितों को घातक मानते हुए भी, वे मुस्लिम राजनैतिक दल भारतीय मुसल्मानों के सच्चे हितों की विल देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। मुस्लिम-लीग व इन संस्थाओं में केवल यही ग्रंतर है कि जब मुस्लिम-लीग का दृष्टिकोण पहले सांप्रदायिक है, ग्रीर शायद बहुत दूर जाकर भी ग्राधिक राष्ट्रीय नहीं रह गया है, राष्ट्रवादी-मुस्लिम-संस्थाएं राष्ट्रीय हितों को प्राधान्य देती हैं, पर मुस्लिम-हितों की रत्वा के सम्बन्ध में भी तत्वर हैं। खुदाई-ख़िदमतगारों ने भी, जैसा कि सीमाप्रांत की कांग्रेस के उस समय के समापति ने ग्रपने एक वक्तव्य में कहा था, राजाजी के मुसल्मानों को ग्राह्म-निर्ण्य का ग्राध्कार देने के प्रस्ताव का "संपूर्ण-समर्थन" किया था। जमीयत-उल-उल्मा ने, १९४२ की एक बैठक में, हिंदुस्तान के लिए ग्राज़ादी मांगते हुए भी ऐसे वैधानिक संरत्त्रणों की मांग पेश की जिनसे "मुसल्मानों के धार्मिक, राजनैतिक ग्रौर सिस्कृतिक ग्राह्मनिर्ण्य के ग्राधिकारों की रत्ना" हो सके। ग्राज़ाद मुस्लिम कान्केंस, भारतीय स्वाधीनता के ग्रान्तर्गत, ग्राल्य-संख्यक वर्गों के लिए ग्राह्म-निर्ण्य के सिद्धान्त को ग्रावर्यक मानती है।

समारोप

यह सच है कि पाकिस्तान की कल्पना को लेंकर मुसल्मानों में एक सस्ती भाव-प्रवण्ता ने एक वड़ा लोकमत अपने पद्म में संग्रहीत कर लिया है। मुसल्मान आज आसानी से यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि मुस्लिम-संस्कृति वास्तु-कला, चित्रकला, साहित्य और तत्वज्ञान, जीवन के सभी चेत्रों में, अपने विकास की चरम-सीमा पर हिन्दुस्तान में, हिन्दू-संस्कृति के निकट-संपर्क में रहकर ही पहुँची, न वे इसी बात पर विश्वास करेंगे कि पाकिस्तान के कियात्मक रूप लेते ही मुस्लिम-संस्कृति, अपने जीवन-स्रोतों से उन्मूलित होकर, अपने स्वामाविक विकास को खो बैठेगी, पर साथ ही हम यह न भूलें कि पाकिस्तान की कल्पना यदि दिन के सपने से अधिक स्थापित्व नहीं रखती तो दूसरी ओर हम अपने देश के लिए ऐसे शासन-विधान की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसमें अल्प-संख्यक जातियों, विशेषकर मुसल्मानों, के लिए, विशेष अधिकारों और संरक्त्यों की व्यवस्था न की गई हो। जहां तक राजनैतिक आत्म-निर्णय का सम्बन्ध है, मुसल्मानों के सभी वर्ग उसके लिए आग्रहशील हैं, और प्रगतिशील हिन्दू भी उसका समर्थन कर रहे हैं।

यह मांत्र संपूर्णतः न्यायसंगत है भी । जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता कि भारतीय मुसल्मानों का एक ऋलग सुसंगठित समाज नहीं है, जिसकी देश के अन्य समाजों से अपनी एक अलग स्थित है, तवतक उन्हें राजनैतिक रूप से भी अलग एक इकाई मान कर चलना ही पड़ेगा। ह करोड़ की आवादी वाले एक समाज से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सदा के लिए एक ऐसे वहुसंख्यक वर्ग के प्राधान्य को स्वीकार कर लेगा, जिसका धर्म व संस्कृति उसले अलहदा हो। मुसल्मानों को एक अलग राष्ट्र माना जाय या नहीं —पर, उनके इस आग्रह में कोई ऐसी वात नहीं है जिस पर इतनी कड़वाहट का फैलना ज़रूरी हो। इतिहास के लंबे युगों में राष्ट्रीयताओं की सीमाओं में सदा ही परिवर्तन होता रहा है। परन्तु, यदि मुसल्मानों को एक अलग राष्ट्र न भी माना जाय तो भी, एक अलग समाज होने के नाते, उनके आत्म-निर्णय के अधिकार को तो मानना होगा ही, और उसे देश के मावी शासन-विधान में कियातमक रूप देना होगा। मैं यह नहीं कहता कि वहुसंख्यक वर्ग सदा ही अलग-संख्यक वर्ग को कुचलने की चेष्टा करेगा, और न मैं यही मानता हूँ कि मुसल्मानों को आत्म-निर्णय का अधिकार देते ही सांप्रदायिक वैमनस्य का अन्त हो जायगा, पर यह अवस्य कहा जा सकता है कि ऐसा करने से समाधान का मार्ग अधिक प्रशस्त और सुगम वन सकेगा।

पाकिस्तान: सैद्धांतिक विश्लेपण

मस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांग का मुख्य ग्राधार यह विश्वास है कि मुसल्मान एक ग्रलहदा राष्ट्र हैं। इस विचार का यों तो एक लम्या इतिहास है, पर इसके सम्बंध में अधिक चर्चा लीग के लाहौर-प्रस्ताव के बाद ही सनाई देने लगी है। सच तो यह है कि लीग की पाकिस्तान की मांग पहले हमारे सामने त्राई, ग्रीर उसके समर्थन में, मुसल्मानों का एक ग्रलहदा राष्ट्र होने का दावा, उसके वाद से ही दोहराया जाने लगा है। वार-वार के दोहराए जाने से उसमें कुछ वल भी ह्या गया है। इस दावे को सबसे ऋधिक स्पष्ट शब्दों में, सितम्बर १९४४ की श्रपनी वातचीत में, मि॰ जिन्ना ने गांधी जी के सामने रखा। उन्होंने कहा, ''हमारा यह दढ विश्वास है कि राष्ट्रीयता का निर्धारण करने वाली किसी भी कसौटी पर जांच करने से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि मुसलमान ग्रीर हिंद दो भिन्न-राष्ट्र हैं । हमारा १० करोड़ की संख्या का एक ग्रलहदा राष्ट्र है, ग्रीर हमारी श्रपनी ग्रलग संस्कृति ग्रीर सम्यता, भाषा ग्रीर साहित्य, कला ख्रीर वास्त-कौशल, नाम ख्रीर उपनाम, जीवन के मुल्यों के संबंध में धारगाएं व विश्वास, क़ानृत श्रीर नैतिक वंधन, रिवाज श्रीर रहन-सहन, इतिहास ग्रौर परम्पराएं, दृष्टिकोगा श्रीर श्राकांचाएं, हैं।..संचेप में, जीवन का, ग्रीर जीवन के संबंध में, हमारा ऋपना एक दृष्टिकीण है। ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से भी हम एक ग्रलहदा राष्ट्र हैं।"

दो राष्ट्रों का सिद्धांत

मि॰ जिन्ना के मुसल्मानों के एक अलहदा राष्ट्र होने के दावे की, लीग के वाहर के, सभी मुस्लिम राजनैतिक दलों व नेताओं ने अमान्य ठहराया है। आज़ाद वोर्ड, अखिल भारतीय मोमिन कांफ्रेंस आदि ने उसके विरोध में प्रस्ताव पास किये हैं। मौलाना आज़ाद ने तो यह घोषणा की थी कि पाकिस्तान की कल्पना ही इस्लाम-धर्म के विरुद्ध जाती है। परन्तु, गांधी जी ने इस सिद्धांत की जैसी तीव आलोचना की है, वैसी शायद किसी ने भी नहीं की। उनका कहना है कि यदि हिंदुओं और मुसल्मानों में कोई अन्तर है तो वह उनके धार्मिक विश्वास का अन्तर है। उन्होंने जिन्ना साहित्र की दलीलों का उत्तर देते हुए लिखा, ''मैं तो इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखता जब कि किसी देश के

रहने वाले व्यक्तियों श्रोर उनकी सन्तान ने, केवल धर्म-परिवर्तन के श्राधार पर, श्रपने को श्रपने परम्परागत राष्ट्र से श्रलग एक राष्ट्र माना हो। श्राप यह नहीं कहते कि श्रापने हिंदुस्तान को जीता, इसलिए श्राप एक श्रलहदा राष्ट्र हैं। श्राप तो श्रपने को एक श्रलतदा राष्ट्र इसलिए मानते हैं कि श्रापने श्रपना धर्म बदल लिया है। क्या श्राज हिंदुस्तान एक राष्ट्र वन जायगा यदि हम सव लोग इस्लाम-धर्म को स्वीकार कर लें? क्या वंगाली, उड़िया, श्रांधवासी, तामिल, मराठे, राजराती श्रादि श्रपनी विशेषताश्रों को खो देंगे यदि वे मुसल्मान वन जायं?" गांधी जी के इस प्रश्न का श्राज भी उत्तर नहीं मिल सका है।

यदि धर्म की विभिन्नता के ऋाधार पर मुसल्मानों को एक ऋलग राष्ट्र मान लिया जाय, तो उसी त्राधार पर फिर सिखों को भी एक त्रालग राष्ट्र क्यों न माना जाय ? परन्तु, इसके लिए जिन्ना साहिव तैयार नहीं हैं - यद्यपि दिन्नण भारतीयों द्वारा द्रविक्तान के रूप में अपना एक अलग राज्य स्थापित कर लेने में उन्हें कोई स्रापत्ति नहीं है । १६४२ की स्रपनी पंजाव-यात्रा में उन्होंने सिखों के संबंध में स्रात्म-निर्णय के ऋधिकार के उठाए जाने का वड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुसल्मान तो यह ऋधिकार इसलिए चाहते हैं कि "वह एक निश्चित भू-भाग में, जो उनकी मातृभूमि है स्रीर जहां उनका बहुमत है, एक राष्ट्रीय समष्टि के रूप में रह रहे हैं.....परन्तु क्या कभी इतिहास में यह भी सुना गया है कि एक ऐसा ऋदं-राष्ट्रीय (sub-national) वर्ग, जो देश के भिन्त-भिन्त भागों में वंटा हुन्ना है, एक स्वतन्त्र-राज्य के निर्माण की मांग करे १...मुरिलम-समाज इस प्रकार का ऋदी-राष्ट्रीय वर्ग नहीं है। ऋात्म-निर्ण्य के त्रिधिकार का उसका दावा उसका जन्मतिद्ध त्रिधिकार है।" यह दलील समभ में नहीं त्राती। यदि मुसल्मान हिंदुत्रों से अपनी विभिन्नतात्रों के श्राधार पर एक श्रलहदा राष्ट्र होने का दावा करते हैं तो कोई कारण नहीं कि सिख, जो हिंदू श्रीर मुसल्मान दोनों से भिन्न हैं, श्रपने को एक श्रलहदा राष्ट्र न मानें।

राष्ट्रीयता के श्राधार-तत्त्व

परन्तु, यह राष्ट्रीयता है क्या वस्तु ? कव कोई जाति अपने को एक अलहदा राष्ट्र मानने का अधिकार प्राप्त कर लेती है ? राष्ट्रीयता के जो आधार-तन्त्व माने जाते हैं यदि हम उनकी कसौटी पर मुस्लिम-लीग के दावे को लें तो उसकी अयधार्थता वड़ी जल्दी स्पष्ट होने लगती है । जाति (race) की दृष्टि से देखा जाय तो हिन्दू और मुसल्मानों के वीच हम किसी प्रकार की दिमाजन-रेखा नहीं खींच सकते—इस सम्बन्ध में हम एक पंजावी हिन्दू और पंजावी मुसलमान में अधिक सादृश्य पाएंगे, एक पंजाबी हिन्दू श्रीर वंगाली मुसलमान में बिल्कुल भी नहीं । जाति की दृष्टि से, बंगाली ग्रौर ग्रासामी में शायद हम तिब्बती अथवा मंगोल-रक्त का समावेश पा सकें, और मद्रासी और मराठों में द्रविड़ रक्त का, पर किसी भी प्रदेश के हिन्दू और मुसल्मानों में इस दृष्टि से कोई भेद नहीं किया जा सकता। भाषा के दृष्टिकोण से भी यह स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान के मुसल्मानों की कोई ऋलहदा भाषा नहीं है-पंजाव में वे पंजावी वोलते हैं, सिंघ में सिंघी, पश्चिमी संयुक्त-प्रान्त में फ़ारसी के शब्दों से भरी हुई हिन्दुस्तानी, उसीके पूर्वी-प्रदेशों में उसी भाषा का संस्कृत-प्रधान रूप, वंगाल में ठेंठ संस्कृतमयी वंगला । उर्द उनकी ग्रापनी भाषा नहीं है—उसके निर्माण में हिन्दु श्रों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, श्रौर श्राज भी हिन्दु श्रों की एक वहुत बड़ी संख्या, विशेष कर पूर्वी पंजाव व पश्चिमी युक्त-प्रान्त में, उसे ऋपनी मातृभाषा मानती है । जहाँ तक सामान्य-हितों का प्रश्न है, एक मुश्लिम ज़र्मादार श्रोर मस्लिम-किसान में हितों श्रोर स्वाथों का वैषम्य एक मुसल्मान किसान और हिन्दू-किसान के मुक्काविले में कहीं अधिक है। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से हम यदि इस प्रश्न पर विचार करें, तो हम यह स्पष्ट देख सकेंगे कि हिन्दुस्तान में कहीं भी ऐसी निदयां या पर्वत-श्रेणियां नहीं है, जो हिन्द-इलाक़ों श्रीर मुसल्मान इलाकोंको एक दूसरेसे श्रालहदा करती हों । देशके हर कीनेमें हिंदू श्रीर मुसल्मान एक ही जुमीन पर,एक ही सूरजके नीचे, साथ-साथ रहते हैं। केवल -धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो हिन्दु श्रों श्रीर मुसल्मानों में सामान्य नहीं है।

में जानता हूँ कि जाति, भाषा, सामान्य-हित अथवा भौगोलिक स्थिति से ही राष्ट्रीयता का निर्धारण नहीं हो जाता। उसके मूल में इनसे भी गहरी भावनाएं हैं। जैसा कि रेनान ने लिखा है, "राष्ट्रीयता तो देश की आत्मा को कहते हैं। वह एक आध्यात्मिक सिद्धान्त है। दो वस्तुएं, जो गहराई में जाकर एक हो जाती हैं, इस आत्मा अथवा आध्यात्मिक सिद्धान्त का मृजन करती हैं। इनमें से एक का सम्यन्ध भूतकाल से है, दूसरी का वर्तमान से। एक का जन्म प्राचीन सामान्य-संस्कृति और स्मृतियों में सामान्य गौरव की अनुभृति से होता है, दूसरी का विकास होता है दैनिक जीवन के वास्तविक समसौते में, साथ रहने की इच्छा में, और मिल-जुल कर एक वैभवशाली भविष्य के निर्माण की सामान्य-आकांचाओं में।" इस दृष्टि से भी यदि हम हिन्दू और मुसल्मानों के आपसी सम्बन्धों को देखें तो हमें यह जात हो सकेगा कि इन दोनों जातियों ने मिलकर एक राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र, का निर्माण किया है। वे लगभग एक १. रेनान: What is a Nation?

हज़ार वर्ष तक मिल-जुल कर एक साथ रहे हैं, श्रौर, सामान्य कला श्रौर साहित्य, श्रौर सामान्य दर्शन-शास्त्र का निर्माण किया है। वे कंधे से कंधा भिड़ा कर युद्धों में सामान्य-शत्रुश्रों के साथ जूभे हैं, श्रौर रण-चेत्रों में उनका रक्त साथ-साथ वहा है। सच तो यह है कि श्राज का भारतीय-समाज, श्राज की भारतीय संस्कृति श्रौर सम्यता, श्राज के भारतीय भाषा श्रौर साहित्य, कला श्रौर वास्तु-कौशल, इतिहास श्रौर परम्पराणं, कान्त्न श्रौर नीति, सभी कुछ हिन्द श्रौर मुसलमानों की सामान्य-सृष्टि हैं।

मैं यह मानता हूँ कि इन दोनों जातियों की 'साथ रहने की स्पर्धा' स्त्राज उतनी तीन नहीं रह गई है। राजनैतिक मत-भेदों के साथ सांस्कृतिक विभिन्न ताएं भी ऋपने विषेले फनों को ऊपर उठा रही हैं। सर सैयद ऋहमद ने मुसल्मानों के लिए एक ऋलग पोशाक की कल्पना की । पिछली ऋर्ड-शताब्दी में ऋलीगढ़, लाहौर, हैदरावाद ऋादि नगरों में एक नई भाषा का विकास हो रहा है, जो फ़ारसी च्रौर च्रारवी शब्दों से भरी हुई है। वंगाल में भी मुसल्मान 'जल' के स्थान पर 'पानी' शब्द का प्रयोग ऋधिक पसंद करने लगे हैं (यद्यपि वे भूल जाते हैं कि पानी का सम्यन्ध भी संस्कृत के 'पाणीय' शब्द से है)। पाकिस्तान की मांग ज़ोरों पर है। मुसल्मान प्रारम्भिक ख़लीफ़ात्रों के जीवन में ऋधिक दिलचस्पी लेते हैं, ऋादिलशाह या ऋकवर के जीवन में कम। परन्तु, यह प्रवृत्ति, जैसा कि पहिले देखा जा चुका है, एक विशेष विचार-धारा का, जो प्राचीन के पुनरुत्थान के साथ सम्बद्ध थी, परिगाम थी, श्रीर कुछ बाह्य-परि-स्थितियों, त्रौर एक विदेशी शासन की मौजूदगी, ने उन्हें प्रोत्साहन दिया। परन्तु, प्रतिक्रियावादी तत्वों की सख्त, मैली मिट्टी को फोड़ कर, सशक प्रगति-शील तत्त्व ग्रापने स्वस्थ त्र्यंकुरों को लेकर वाहर निकल ग्राये हैं, ग्रीर इनका विकास ऋनिवार्य दिखाई दे रहा है। भविष्य इन शिक्तियों के हाथ में है। एक नये भारतीय राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। परन्तु, इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं भविष्य के इन सोनहले स्वप्नों में मुसल्मानों की ज्ञाज की मांग को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं तो रेनान के इस कथन में विश्वास करता हूँ कि "राष्ट्र की स्थिति तो उसकी दैनिक स्वीकृति का प्रश्न है, उसी प्रकार जैसे न्यांक ग्राविस्त रूप से प्रतिक्रा श्रपने जीवित रहने का प्रमाण देता रहता है।" यदि मुसल्मान त्र्याज की विशेष परिस्थितियों में त्रपने को एक ऋलहदा राष्ट्र मानने पर कटिवड हैं, तो मैं इस सम्वन्ध में किसी प्रकार का दुराग्रह रखने के पद्म में नहीं हूँ । मैं मानवा हूँ कि उनके इस ग्राग्रह को हमें मान्यता देनी चाहिए।

'राष्ट्रीय आत्मनिर्णय' का सिद्धांत

परन्तु, यहां एक ग्रीर, इससे भी कठिन, प्रश्न हमारे सामने ग्राकर उपस्थित होता है। यदि हम मान भी लें कि मुसल्मान एक ग्रालहदा राष्ट्र हैं, तो क्या इसका अर्थ यह होजाता है कि उन्हें एक अलहदा राज्य कायम करने का अधि-कार भी मिल जाना चाहिए ! प्रत्येक राष्ट्र को ग्रापने लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का ग्राधिकार है, इस सिद्धांत का जन्म फ्रांस की राज्य-क्रांति के दिनों में हुआ। ग्रंग्रेज़ी के प्रसिद्ध विचारक जे० एस० मिल ने ज़ोरदार शब्दों में उसका समर्थन किया। उनका विश्वास था कि ''यदि किसी समाज में राष्ट्रीयता की भावना प्रवल है तो उस समाज का यह ऋधिकार भी हो जाता है कि वह ग्रपने सब सदस्यों को एक सामान्य-शासन के ग्रान्तर्गत संगठित कर सके, श्रीर वह शासन खतंत्र श्रीर सार्वभीम हो ।" ° १६१६ की संधि-चर्चा के दिनों में यह सिद्धांत ग्रापनी लोकप्रियता के उच्चतम शिखर तक जा पहुंचा। प्रेज़ीडैंट विल्सन ने उसका विशेष रूप से समर्थन किया । उन्होंने लिखा, "ग्रात्म-निर्णय केवल एक ग्राकर्षक महाविरा नहीं है। वह तो कियात्मक राजनीति का एक श्रानिवार्य सिद्धांत है, जिसकी राजनीतिज्ञ उपेचा नहीं कर सकते । यदि वे ऐसा करना चाहेंगे तो उन्हें वड़े ख़तरे का सामना करना पड़ेगा।" १९१६ के राजनीतिशों ने उसकी उपेचा नहीं की । परन्त उन्हें उससे भी वड़े खतरे का सामना करना पड़ा, जिसका प्रेज़ीडैंट विल्सन को भयंथा। इस सिद्धांत की ग्रमली रूप देने का ग्रर्थ यह हुग्रा कि यूरोप को कई छोटे-छोटे देशों में बांट दिया गया । जहां कोई भी ऐसा ग्रल्पसंख्यक वर्ग था, जो राष्ट्रत्व का दावा कर रहा था, वहीं उसके लिए एक स्वतंत्र-राज्य की स्थापना करनी पड़ी--ग्रौर इस प्रकार लिथुत्र्यानिया, लाटविया, एस्टोनिया, ज़ैकोस्लाविया, पौलैएड, त्र्यास्ट्रिया, हंगरी, युगोस्लाविया, रूमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस ग्रादि-ग्रादि ग्रनिगनत स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई। परन्तु, इससे न तो श्राल्पसंख्यक वर्गों के स्वच्यों की समस्या सुलभ्त सकी, और न कोई अन्य समस्या ही। दो महायुद्धों के बीच का यूरोप का इतिहास उस सिद्धांत के, धीमे पर निश्चित रूप से, नप्ट-भ्रष्ट होते रहने का इतिहास है जिसका अथक और अनवरत प्रचार अमरीका के प्रेज़ीडेंट ने किया था।

त्राज यह वात स्पष्ट होगई है कि १६१६ की संधि की ग्रसफलता का मुख्य कारण यही था कि उसके नियन्तात्रों ने 'राष्ट्र' ग्रीर 'राज्य' के ग्रन्तर को ठीक से नहीं समभा था । उनका समस्त चिन्तन उन्नीसवीं शताब्दी की सामाजिक १—ते॰ एस॰ मिल—Representative Government. स्थिति की पृष्ठभूमि पर था--जन राष्ट्रीयता त्र्यौर प्रजातन्त्र एक मैत्री-सूत्र में वंधे हुए थे। उस समय तक कोई यह नहीं कह जानता था कि इन दोनों सिद्धांतों का त्र्यांतरिक वैषम्य किसी दिन इतना बढ़ जायगा कि एक त्र्योर तो राष्ट्रीयता प्रजातन्त्र की जड़ों को ही उखाड़ फेंकने में तत्पर हो जायगी—जैसा मध्य-यूरोप के देशों, जर्मनी इटली ऋादि, में हुऋा--ग्रौर दूसरी ऋोर प्रजातन्त्र की भावना राष्ट्रीयता के खोल को फाड़ कर फेंक देगी-जैसा रूस में हुन्ना। त्र्राज हम इस बात को स्पष्ट रूप से समभ गए हैं कि राष्ट्रीयता त्र्यौर सच्चा प्रजातन्त्र परस्पर-विरोधी वस्तएं हैं। यदि हम राष्ट्रीयता को प्राधान्य देते हैं तो उसमें भय है कि देश का पूंजीवादी वर्ग उस भावना का उपयोग श्रमिक वर्ग को चुसने में करेगा-श्रीर उसके परिणाम-स्वरूप या तो फ़ासिज्मकी स्थापना होगी या इंग्लैएड श्रीर श्रमरीका के ढंग के ऋर्ड-फ़ासिज्म, पूंजीवादी-प्रजातन्त्र, की । दूसरी श्रोर, यदि हम इस बात का प्रयत्न करें कि प्रत्येक व्यक्ति को न सिर्फ़ बोट देने के सम्बन्ध में वरावरी का ऋधिकार प्राप्त हो, परन्तु भोजन ऋौर वस्त्र की सुविधा भी सव लोगों को वरावर मिल सके, तो हमें उसके लिए ब्राज की राजनैतिक सीमा-रेखाएं वदलना पड़ेंगी, ऋौर राष्ट्रीयता के प्रश्न को एक गौण रूप देना होगा। हमें राष्ट्रीयता श्रीर प्रजातन्त्र इन दो में से एक को चुन लेना है, श्रीर यदि हमने यह चुनाव नहीं कर लिया तो वह खुले-हाथों विपत्ति को निमंत्रण देना होगा । पश्चिम के देशों ने इस चुनाव में देर की, इसी कारण उन्हें वर्त्तमान महायुद्ध का सामना करना पड़ा ।

इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। 'राष्ट्रीय' श्रीर 'श्रात्मनिर्ण्य' इन दो शब्दों में ही क्या विरोधाभास नहीं है श्रियदि किसी समाज को
केवल इस श्राधार, पर कि वह एक 'राष्ट्र' है श्रपने लिए एक स्वतन्त्र राज्य के
निर्माण का श्रिधकार मिल जाता है, तो इसमें 'श्रात्म-निर्ण्य' के लिए स्थान
कहां रहा श्रियदि उन सत्र लोगों का जो पोलिश-भाषा वोलते हैं, पोलैएड का
नागरिक वन जाना श्रानिवार्य है, या वे सत्र लोग जो लिथुत्र्यानिया-भाषा का
प्रयोग करते हैं, लिथुत्र्यानिया-राज्य के शहरी ही वन सकते हैं, श्रथवा वे सत्र
व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहते हैं श्रीर इस्लाम में विश्वास रखते हैं, श्रपने लिए
एक स्वतन्त्र राज्य का निर्माण करने के श्रिधकारी हो जाते हैं,
तो इसमें 'श्रात्म-निर्ण्य' का प्रश्न तो कहीं रहा ही नहीं। राष्ट्रीयता का निर्धारण
करने के लिए धर्म तो एक बहुत ही मध्य-कालीन श्राधार है परन्तु यदि हम
भाषा को भी ले लें, जो कि १६१६ के निर्ण्यों का श्राधार थी, तो भी यह नहीं
कहा जा सकता कि वे सत्र व्यक्ति जो एक भाषा त्रोलते हैं, सदैव एक राज्य में

रहना ही पसन्द करेंगे। पहले महायुद्ध के बाद यूरोप में कई स्थानों पर जनता की राय ली गई थी। उनमें से, एलेंस्टाइन में, जहां ४६ प्रतिशत व्यक्ति पोलिश-भाषा का प्रयोग करते हैं, केवल दो प्रतिशत व्यक्तियों ने पोलैएड राज्य के ख्रांतर्गत रहना स्वीकार किया। मेरींवर्डर, उत्तरी साहलेशिया ख्रीर क्लोगनफ़ुर्त में भी भाषा-सामान्य ख्रीर राजनैतिक ख्राकांचाख्रों के वीच एक वड़ा ख्रंतर दिखाई दिया।

'त्र्यात्म-निर्ण्य' का अर्थ यह नहीं है कि पूर्व-निर्धारित राष्ट्रों की अपने राजनैतिक भविष्य के निर्ण्य का ग्राधिकार दे दिया जाय, परन्तु वह ग्राधिकार तो देश ग्रथवा समाज के व्यक्तियों, वयस्क पुरुपों व स्त्रियों, को दिया जाना चाहिये। उदाहरण के लिए, भारतीय मुसल्मानों के स्वत्वों ख्रीर ख्रिधकारों के संबंध में यदि हमें किसी निर्णय पर पहुँचना है, तो कोई कारण दिखाई नहीं देता कि हम एक राष्ट्र के रूप में, समष्टि की दृष्टि से, तो उन पर चर्चा कर लें, पर व्यक्तिगत रूप से भारतीय मुसल्मानों को इसमें क्या हानि-लाभ है उसके संबंध में विल्कुल भी न सोचें। यह तो कोई दूरदर्शिता की वात नहीं होगी कि हम भारतीय मुसल्मानों को, केवल धार्मिक ग्रौर सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण, उनके उस सैनिक ग्रौर ग्राथिक परस्परावलंबन की व्यापक ग्राधार-भूमि से, जो देश की भौगोलिक एकता पर स्थापित है, उखाड़ कर उन्हें एक स्वतन्त्र राज्य के सुपुर्द कर दें। हमारे सामने प्रश्न यही नहीं है कि हम कुछ स्वयं निर्णीत नेतात्रों की वार-वार दोहराई जाने वाली मांग पर ही ध्यान दें, हमें यह यह भी तो देखना है कि मुस्लिम-जनता क्या चाहती है, ऋौर उसका हित किसंमें है। लीग के सैंकड़ों प्रस्तावों से इस वात का निर्णय नहीं होगा। उसके लिए वो मुस्लिम जन-मत की ग्रावश्यकता है।

परन्तु, यदि श्राधुनिक प्रचार-साधनों के एक व्यापक संगठन के द्वारा भावनाश्चों की एक श्रांधी का सजन किया जा सका, जिसके प्रभाव में भारतीय मुसल्मानों ने देश के बँठवारे के पद्म में श्रपना मत दे दिया, तो क्या पाकिस्तान की स्थापना करना उचित होगा, यह जानते हुए भी कि उनकी मांग खयं उनके लिए श्राहितकर श्रीर श्रात्म-धातक है। प्रोफ़ेसर कार के शब्दों में, ''किसी भी राजनैतिक इकाई के श्राकार-विस्तार व शासन तन्त्र के निर्धारण में श्रात्म-निर्णय के सिद्धान्त का बड़ा महत्त्व है, परन्तु उसे ऐसा एकाकी अथवा सर्वोपिर सिद्धांत मान लेना कि उसके सामने श्रन्य सभी वैचारिक श्रीर श्राव-स्यक प्रश्नों को, श्रानवार्य श्रीर महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को भी, गौण मान लिया जाय, उचित नहीं होगा । श्रात्म-निर्णय का श्राधकार भी उसी प्रकार

से एक सार्वभीम श्रिषकार नहीं माना जा सकता जैसे प्रजातन्त्र में यह नहीं माना जा सकता कि हर एक व्यक्ति को वह जैसा करना चाहे वैसा करने की इजाज़त मिल सकेगी। श्रात्म-निर्णय के सिद्धान्त के श्राधार पर इंग्लैएड या जर्मनी के बीच में रहने वाला व्यक्तियों का कोई दल यह नहीं कह सकता कि उसे एक स्वतन्त्र, सार्वभीम राज्य की स्थापना का श्रिषकार मिल जाना चाहिए। इसी प्रकार, वेल्स, कैटेलोनिया श्रथवा उज़विकस्तान के लोगों के लिए, केवल इस श्राधार पर कि इन प्रदेशों की जनता का बहुमत यह चाहता है, एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना का दांवा माना नहीं जा सकता: श्रात्म-निर्ण्य के श्रिषकार को क्रियात्मक रूप देने के उनके इस दावे पर इंग्लैएड, स्पेन श्रीर सोवियट रूस के हितों को दृष्टि में रखते हुए ही विचार किया जा सकता है।" भारतीय परिस्थितियों में यदि हम इस प्रश्न पर विचार करें तो हमें पहिले तो यह देखना होगा कि मुस्लिम-बहुमत वाले प्रान्तों का एक स्वतन्त्र-राज्य बना देना उन प्रांतों की मुस्लिम श्रीर ग़ैर-मुस्लिम जनता के लिए कहाँ तक हितकर होगा, श्रीर तव यह देखना होगा कि वह समस्त देश के हितों की दृष्टि से कहाँ तक श्रावश्यक है।

'श्रात्म-निर्णय'ः रक्षा-संत्रंधी समस्याएं

त्र्यातम-निर्ण्य के सिद्धान्त पर पहिला त्राधात प्रथम महा-युद्ध के दिनों में हुआ, दो युद्धों के बीच के वर्षों में उस पर एक बड़ी चोट लगी, स्रौर वर्त्तमान महायुद्ध में तो वह चकनाचूर हो चुका है। ६सका प्रमुख कारण यह था कि इन वर्षों में युद्ध की पद्धति में श्रामूल-परिवर्त्तन होते रहे हैं। १६१४ के पहिले एक छोटे राष्ट्र के लिए एक वड़े युद्ध में भी ऋपनी तटस्थता की रत्ता करना कठिन नहीं था । परन्तु, जब बेल्जियम श्रीर यूनान, श्रपनी इच्छा के विरुद्ध भी, प्रथम-महायुद्ध की लपटों में घसीट लिये गए, और अन्य कई राष्ट्रों को भी न्नपनी तटस्थंता की सीमा-रेखात्रों को लांघने पर विवश हो जाना पड़ा, तो यह सिद्धान्त सचमुच एक भयावह स्थिति में पड़ गया। १६१६ की सन्धि का परिणांम यह हुन्ना-क्योंकि उसका त्राधार उन्नीसवीं शताब्दी की चिन्तन-धारा में था-कि यूरोप में कई छोटे-मोटे राज्यों की स्थापना हो गई। इसने समस्या को कुछ अधिक जटिल बना दिया। परन्तु, तब भी आशा यह थी कि संयुक्त-रचा (Collective Security) के उपायों द्वारा, जिन्हें राष्ट्र-संघ (League of Nations) में कियात्मक रूप देने का प्रस्ताव था, यह समस्या सुलभाई ज़ां सकेगी। परन्तु, कुछ ब्रान्तरिक वैपम्यों के कारण राष्ट्र-१—ई.एच. कार—Conditions of Peace, १०, ४७-४=।

संघ इस दिशा में कुछ भी कर सकने में ग्रसमर्थ रहा । इसी वीच कुछ वहें देश ग्रपने विस्तृत साधनों का उपयोग ग्रपने सैनिक वल को बढ़ाने में कर रहे थे । छोटी शिक्तयां ग्रोर भी छोटी श्रीर ग्रशक्त वनती जा रही थां । इसका परिणाम यह हुग्रा कि १६४० में जब जर्मनी की संगठित सेनाग्रों ने ग्रस्त्र संभाल लिये तो किसी भी छोटे देश के लिए ग्रपनी तटस्थता की रज्ञा करना ग्रसम्भव हो गया । नॉर्च, हॉलैण्ड, बेल्जियम, एक के बाद एक, धराशायी होने लगे । राष्ट्रीय ग्रात्म निर्णय के सिद्धान्त का खोखलापन कभी इतना स्पष्ट नहीं हुग्रा था जितना १६४० के ग्रीष्म में । ग्राज तो किसी भी छोटे राज्य के लिए किसी बड़े राज्य का मुक्ताविला करना ग्रसम्भव हो गया है, जब तक वह ग्रपनी सैनिक स्वतन्त्रता किसी ग्रन्य वहें राज्य के सुपूर्व न कर दे । ग्राज परस्परा-वलम्बन के द्वारा ही कोई देश ग्रपने वचाव की ग्राशा कर सकता है ।

'वस्तु-स्थिति की हम उपेचा नहीं कर सकते । हिन्दुस्तान को यदि दो भागों में वाँट दिया जाय तो वह रूस, चीन, जापान या किसी भी ग्रन्य प्रथम-श्रेगी के देश के र्योकमण का मुकाविला कदापि नहीं कर सकेगा। रज्जा-व्यय की दृष्टि से वँटवारे के ग्रार्थिक पत्त पर हम विचार कर चुके हैं। ग्रपनी रत्ता के लिए पाकिस्तान को हिन्दुस्तान, या ग्रान्य किसी देश, पर निर्भर रहना पड़ेगा, ग्रीर इस दशा में उसे ग्रापनी सार्वभीमता के साथ समभौता करना पहेगा। वहत संभव है कि किसी बाहरी ब्राकमण की पहिली ब्राफ्तवाह के साथ ही पाकिस्तान की सरकार हिन्दुस्तान का ग्राश्रय टटोले। यह भी सम्भव है कि, ग्रापनी स्वतन्त्रता के संबंध में बहुत ऋधिक भावुक ऋौर संवेदन-शील होने के कारण वह ऐसा न भी करे-वैसी दशा में उसे उसी स्थिति का सामना करना पहेगा जो जुन १६४० में फ्रांस ने इंग्लैएड के साथ मिल जाने के प्रस्ताव की ग्रस्वीकार करके अपने लिए उत्पन्न कर ली थी। वर्तमान महायुद्ध की समाप्ति के साथ सभी युद्धों की समाप्ति नहीं हो गई है। सच तो यह है कि दूसरा महायुद्ध नियटा भी नहीं था, तभी से तीसरे महायुद्ध की चर्चा सुनाई दे रही है। ग्रन्वर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन ग्रौर समन्वय की ग्रावस्था ग्रामी दूर है। यह प्रयोग करने का समय नहीं है। राजनैतिक गुरुत्व का केन्द्र अटलांटिक से प्रशांत में चले ग्राने से ग्रन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में हमारे देश की स्थिति ग्राधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है। ग्राने वाले महायुद्धों में हमें ग्राधिक कियात्मक भाग लेना होगा । यदि हम ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ग्रापना स्थान बनाना चाहते हैं तो हमें ग्रपने देश को ग्रविभाज्य, ग्रीर ग्रपने सैन्य-यल को संगठित, रखने की त्र्यावश्यकता है ।

'श्रात्म-निर्णय' : श्रार्थिक पक्ष 🚶

रत्ता-संबंधी समस्यात्रों पर विचार करना यदि त्रावश्यक है, तो त्रार्थिक प्रश्नों का विश्लेषण त्रानिवार्य ही माना जाना चाहिए । त्राज की त्रान्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के इतना जटिल होने का मुख्य कारण यह है कि "एक श्रोर तो जन-साधारण छोटी-छोटी सांस्कृतिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए व्यय हैं, **ऋौर दूसरी ऋोर ऋार्थिक दृष्टि से बड़े-बड़े** भूखंडों का समन्वित किया जाना श्रनिवार्य होता जा रहा है।" राजनैतिक श्र-क़ेन्द्रीकरण के साथ-साथ श्रार्थिक केन्द्रीकरण की भावना बढ़ती जा रही है। १९१६ की संघि ने यूरोप के छोटे-छोटे राष्ट्रों को राजनैतिक स्रात्म-निर्णय का ऋधिकार तो दे दिया था, परन्तु काम करने ऋथवा भूखों न मरने का ऋधिकार नहीं दिया—जब कि १६१६ के यूरोपियन राजनीतिज्ञों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न राजनैतिक अथवा सीमा निर्धा-रण संबंधी नहीं था, परन्तु स्त्रार्थिक था। जैसा कि प्रसिद्ध स्त्रर्थशास्त्र-वेत्ता जे॰ एम॰ कीन्स ने लिखा, "संधि के समय भोजन, कोयले और यातायात के साधनों के स्त्रावश्यक प्रश्नों को ऋधिक महत्त्व नहीं दिया गया, स्त्रीर इसका परिगाम यह हुन्ना कि जिन छोटे-छोटे राष्ट्रों को न्नपने स्वतन्त्र राज्य क्वायम कर लेने की सुविधा मिल गई थी उनकी ऋार्थिक समस्याएं बहुत ऋधिक भीषण हो गई ।"

इस संबंध में हम प्रो॰ कार की चेतावनी की उपेत्ता नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा है—''जैसे बोट देने का अधिकार कोई अर्थ नहीं रखता यदि उसके साथ-साथ काम करने और पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार न हो, इसी प्रकार राष्ट्रीय आत्म-निर्णय का अधिकार भी बहुत बड़े अंशों में अपना आकर्षण खो देता है, यदि वह आर्थिक त्तेत्र में कड़े प्रतिवन्धों की सृष्टि करने का कारण हो। 'राष्ट्रीय अधिकार व्यक्ति के अधिकारों के समान खोखले और अर्थ हीन माने जायंगे, यदि वह आर्थिक विकास, या कम से कम आर्थिक निर्वाह, के लिए मार्ग तैयार नहीं करते, और सड़क पर काम करने वाले मज़दूर और खेत में काम करने वाले किसान की समस्या को हल नहीं करते।" न तो तर्क से और न कल्पना की वड़ी-से-चड़ी उड़ान से यह विश्वास किया जा सकता है कि पाकिस्तान के बन जाने से देश के, अथवा उसके किसी भाग-विशेष के, आर्थिक विकास में कोई सहायता मिलेगी। इस संबंध में यदि थोड़ा

१—जे. एम. कीन्स—The Economic Consequences of the Peace, पृ. १३४।

र—ई. एच. कार—Conditions of Peace, पृ. ६०।

भी विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि त्यार्थिक दृष्टि से पाकिस्तान एक ग्रात्म-घातक प्रयोग होगा कि हमारे देश की भौगोलिक एकता एक ऐसा वड़ा तथ्य है, जिसकी उपेता, सैनिक ग्रीर ग्रार्थिक दोनों में से किसी भी दृष्टि से, नहीं की जा सकती। भृगोल ने हमारे देश की संसार के दूसरे देशों से, ऊंची पर्वत श्रेरिएयां श्रीर गहरे समुद्रां द्वारा, श्रलहदा करके, श्रीर उसके भ्रान्तरिक प्रदेशों में किसी भी प्रकार का वड़ा व्यवधान उपस्थित न करके, सैनिक ग्रौर ग्रार्थिक दोनों दृष्टियों से उसे एक सम्पूर्ण ग्रौर स्वावम्बी इकाई का रूप दे दिया है। इस भौगोलिक एकता को ग्राधार बना कर, विशेष कर शासन की सुविधा की दृष्टि से, हमारे शासकों ने एक ग्राधिक व्यापक एकता का विकास कर लिया है। सड़क और रेल, तार और डाक ग्रादि से सारा देश एक स्त्र. में पिरो दिया गया है। इस प्रकार त्र्यार्थिक पुनर्निर्माण की वड़ी-से-वड़ी योजना के लिए भी एक व्यापक ग्राधार की सृष्टि कर ली गई है। वड़ी-वड़ी योजनाएं, वम्बई-योजना ग्रौर गांधीवादी योजनाएं, हमारे सामने ग्रा भी रहीं हैं। परन्तु, त्यार्थिक पुनर्निर्माण की किसी भी योजना की सफलता के लिए यह त्र्यावश्यक है कि देश की राजनैतिक एकता को , कायम रखा जा सके। उसके विना किसी भी योजना का स्थायित वालू पर खड़े किये गए प्रासाद से श्रिधिक न होगा।

भारतवर्ष की भौगोलिक एकता

भौगोलिक दृष्टि से हिन्दुस्तान की तुलना प्रायः यूरोप से की जाती है। विस्तार में हमारा देश उतना वड़ा है जितना रूस को निकाल कर समस्त यूरोप। यह कहा जाता है कि यदि यूरोप कई विभिन्न राज्यों में वाँटा जा सकता है तो हिन्दुस्तान को दो भागों में वाँटने के संबंध में हमें चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु, हमारे देश की यूरोप से तुलना करना एक मिध्यावाद को जन्म देना है। प्रकृति ने यूरोप को कई भिन्न-भिन्न प्रदेशों में वांटा है: उसके लम्बे समुद्र-तट में सशक्त लहरें मीलों तक व्रुसती चली गई हैं, एक देश श्रीर दूसरे देश के बीच में हुमें य पर्वत श्रीग्यां हैं, निदयों के प्रवाह ने भी यूरोप के इस मौगोलिक विभाजन में सहायता पहुँचाई है। यूरोप में जो आन्तिक प्रादेशिक सीमा-रेखाएं हैं वे प्रायः जाति, भाषा और सांस्कृतिक परम्पराओं की विभिन्नता को और मी स्पष्ट बना देती हैं। मारतवर्ष मौगोलिक दृष्टि से अविभाजन-रेखा है, और सांस्कृतिक दृष्टि से हिन्दू और मुसल्मानों के वीच यदि कोई विभाजन-रेखा है, तो वह धर्म है, और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि भौगो- लिक प्रतिवन्धों ने विभिन्न धर्मावलिक्यों को विभिन्न प्रदेशों में वाँट दिया हो।

यदि पाकिस्तान बन भी गया तो लगभग ढाई करोड़ मुसल्मान उसकी सीमाश्रों के बाहर रह जायंगे, श्रीर उससे भी बड़ी संख्या में हिन्दू, सिख श्रीर श्रन्य धर्मावलम्बी पाकिस्तान में शामिल कर लिये जायंगे।

भारतवर्ष श्रीर यूरोप के बीच इस भौगोलिक श्रन्तर का प्रभाव उनके समस्त इतिहास पर पड़ा है। भारतवर्ष में सदा ही केन्द्रीकरण की भावना प्रवल रही है, जब कि यूरोप की प्रमुख प्रवृत्ति अकेन्द्रीकरण की स्रोर है। हमारे देश में, हल्के से प्रयत्न से, बड़े-बड़े साम्राज्यों की नींव पड़ सकी है-मौर्य, गुप्त, पठान, मुग़ल, मराठा, श्रंग्रेज़, एक के बाद एक साम्राज्य की स्थापना होती रही है। यूरोप में, मध्य-कालीन पवित्र रोमन साम्राज्य के वाद से-जिसके सम्बन्ध में वोल्टेन्नर ने लिखा था कि वह न पवित्र था, न रोमन, स्रौर न साम्राज्य ही कहलाया जा सकता था-दो या तीन बड़े राष्ट्रों में मैत्री के संबंध क़ायम रखना भी कठिन हो गया है। यूरोप में तब से संघर्ष-तत्पर ऋनेकों पाकिस्तानों का ही प्राधान्य है, सच तो यह है कि यूरोप का अनुकरण करने के बदले हम उससे नसीहत ऋौर चेतावनी ले सकते हैं। पिछले सौ वर्षों से तो यूरोप शान्ति नाम की वस्तु से सर्वथा अपरिचित रहा है। युद्धों के वीच का श्रवकाश-काल सदा ही श्राने वाले युद्धों के शाप से प्रसित श्रीर श्राकान्त रहा है। इससे उसकी सामाजिक श्रीर सांस्कृतिक उन्नित को भी बड़ी ठेंस पहुँची है, क्योंकि जिस शिक्त का उपयोग इन चेंत्रों में किया जाना चाहिए था उसका ऋपव्यय सामरिक वैयारियों में हुआ है । यूरोप में युद्ध का दानव जिस प्रकार त्रपना नग्न-ताराडव करता रहा है, स्त्रीर उसकी प्रेत-छाया में बुभुक्ता स्त्रीर महामारी करोड़ों व्यक्तियों को ऋपना ग्रास बनाते रहे हैं, उसकी पुनरावृत्ति यदि हम अपने देश में भी करना चाहंते हैं तो हमें अवश्य पाकिस्तान की स्थापना कर लेना चाहिए।

विभाजन का मनोविज्ञान

यहाँ हम यह भी न भूलें कि यदि हमने अपने देश को दो भागों में बाँट दिया तो हम घटनाओं के एक ऐसे चक्र को गति प्रदान कर देंगे जो न जाने कब तक अवाध-कम से चलता रहेगा। डॉ॰ वेनीप्रसाद के शब्दों में, "प्रत्येक राजनैतिक प्रवृत्ति की अपनी एक गति होती है, जिसे एक वार कियात्मक रूप दे देने के बाद रोकना दुःसाध्य हो जाता है। विग्रह और विभाजन के सिद्धान्त को यदि एक वार गति मिली तो वह ग्रीक-ट्रैजिडी के समान एक हृदयहीन वेग से अधिक से-अधिक सशाक बनता जायगा, और लीग और कांग्रेस का कोई भी समभौता उसकी इस गति को रोकने में सर्वधा असमर्थ

4.5

रहेगा ।" १६४० में, ग्रापने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पास करनेके बाद १६४१ में, मद्रास ऋधिवेशन में, लीग के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह दित्त्। भारतीयों की द्रविङ्खान की माँग का भी समर्थन करे। सिखीं की खालिस्तान की मांग का विरोध तो उसे, ग्रात्म-रचा की दृष्टि से, करना था ही, इसलिए उसने सिखों को एक ग्राई-राष्ट्रीय समृह वताया । परन्तु, यदि मुसल्मान ग्रापने को एक अलहदा राष्ट्र मानते हैं, तो उनका सिखों के इसी प्रकार के विश्वास का विरोध वड़ा निर्वल रह जाता है। पाकिस्तान के कियात्मक रूप लेते ही ख़ालिस्तान का ग्रान्दोलन प्रवल हो जायगा, ग्रीर यदि ख़ालिस्तान वन जाता है, तो ग्रकालिस्तान क्यों न वने--ग्रौर कीन कह सकता है कि ग्रकेन्द्रीकरण की प्रदृत्ति कहाँ जाकर रुकेगी ? इसकी प्रतिक्रिया एक ग्रोर तो समाज के विभिन्न वर्गों पर, श्रौर दूसरी श्रोर हमारे देशी राज्यों पर होना भी स्वाभाविक है। जैसा प्रो॰ कूपलैएड ने लिखा था, "एक वार राष्ट्रीय ग्रथवा ग्रर्ड-राष्ट्रीय त्र्यात्म-निर्ण्य के सिद्धान्त के कियात्मक रूप ले लेने पर, क्या मराठे श्रीर राजपूत एक ऋखंड-हिन्दुस्तान में शामिल होने के लिए ऋपनी स्त्रीकृति दे देंगे, श्रीर क्या देशी नरेश, हैदराबाद के निज़ाम के नेतृत्व में, स्वतन्त्रता के बँटवारे में श्रपने श्रधिकार को खो देने के लिए उद्यत हो जायंगे ?"

मुस्लिम चिन्तन-धारा की प्रवृत्ति

भारतीय मुसल्मानों द्वारा पाकिस्तान की जो माँग उठाई जा रही है, वह अन्य मुस्लिम-देशों की चिन्तन-धारा के विल्कुल ही विरुद्ध जाती है। आज समस्त मुस्लिम देश अपने इस विश्वास को कि धर्म को राजनैतिक संगठन का आधार माना जाय, छोड़ रहे हैं। समस्त मुस्लिम देशों को एक-सूत्र में संगठित कर लेने का 'पैन-इस्लामिड्म' का आन्दोलन आज भारतीय मुस्लिम-समाज के अलावा अन्य सभी मुसल्मानों द्वारा दफ्तना दिया गया है। आज तो सभी मुस्लिम-देशों में, अल्जीरिया और मोरकों से अफ़्तानिस्तान और इराक्त तक, राष्ट्रीयता को आराधना की जा रही है। आज धर्मान्धता के लिए किसी भी मुस्लिम देशों में कोई स्थान नहीं रह गया है। पहिले महायुद्ध के बाद, ख़िलाफ़त के अंत और कमाल पाशा द्वारा ठकीं के शुद्ध राजनैतिक आधार पर पुनर्निर्माण से इस प्रक्रिया का आरम्भ हुआ, और आज मिश्र, ईरान, इराक, सीरिया आदि सभी मुस्लिम देशों में राजनीति को धर्म से अलहदा कर लेने

१—वेनीप्रसाद: Communal Settlement, ४. ४०।

२—क्पर्लेंड : Constitutional Problem of India, तृतीय भाग, १. १०४।

की यह प्रशृत्ति अपनी चरमसीमा तक पहुँच गई है। यह सचमुच आश्चय की बात है कि हिन्दुस्तान के मुसल्मान एक ऐसे समय में भी, जब दुनियाँ के सभी मुसल्मान राष्ट्रीयता और पश्चिमीकरण की ओर अपसर हो रहे हैं, एक मध्यकालीन विश्वास से अपना संबंध बनाये रखने के लिए इतने आग्रह-शील हों।

इस प्रश्न पर यदि थोड़ा ऋौर भी विचार करें तो हम यह स्पष्ट देख सकेंगे कि यद्यपि पाकिस्तान की धारणा के पीछे धर्म को राजनीति का ग्राधार मान लेने का आग्रह है, परन्तु मुस्लिम-लीग का प्रमुख लच्य धर्म नहीं है, राजनीति है। ऋपनी कल्पना को हम कितना ही गतिशील वनाना चाहें, हम इस विश्वास तक कभी पहुँच ही नहीं सकेंगे कि मि॰ जिन्ना के सभापितता में मुस्लिम-लीग का संगठन ऋौर विकास एक धार्मिक संस्था के रूप में हुऋा है। पाकिस्तान की मांग का प्रमुख लच्य भी न तो इस्लाम-धर्म के महत्त्व को बढ़ाना है, त्रौर न भारतीय मुसल्मानों के धार्मिक हितों का संरच्चरा है, परन्तु भारतीय मसल्मानों की स्थिति को, शुद्ध राजनैतिक दृष्टिकीण से, सवल वनाना है। क्तायदे-स्राज्ञम जिन्ना के हाथों हज़रत स्राह्मामा इक्तवाल की कल्पना में एक श्रामूल-परिवर्त्तन हुन्ना है। इक्कवाल का प्रधान लच्च इस्लाम-धर्म के विकास पर था: जिन्ना भारतीय राजनीति में मुसल्मानों के विशेष अधिकारों पर ज़ोर दे रहे हैं । पाकिस्तान की मांग हिंगेज़ इसलिए नहीं उठाई जा रही है कि उसके समर्थक इस्लाम के उच्च-सिद्धान्तों को कियात्मक रूप देना चाहते हैं—यदि वह ऐसा करना चाहते तो कम-से-कम मैं उनके इस कार्य का ज़ोरों से समर्थन करता-परन्तु उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि थोड़े से मुसल्मानों को आर्थिक शोषण स्रीर स्रविभाज्य राजनैतिक सत्ता के उपयोग के स्रभृतपूर्व स्रवसर प्राप्त हो सकें।

ऋन्तर्राष्ट्रीय विचार-धारा का भुकाव

श्रन्त में, हम श्रन्तर्राष्ट्रीय विचार-धारा की वर्त्तमान प्रश्चित पर भी हिष्णात कर लें। प्रो० कार के शब्दों में, "सभी लोग श्रव इस वात को दिन-प्रति-दिन श्रिधक मानते जा रहे हैं कि श्रात्म-निर्ण्य का सिद्धान्त ऐसा सीधा-सादा सिद्धान्त नहीं है—जैसा १६१६ में माना जाता था—कि जनमत के श्राधार पर उसका निर्ण्य किया जा सके।" हर जगह—हम श्रमरीकन महाद्वीप लें, या दिल्ल्य-पूर्वी यूरोप, या मध्य-पूर्व—राजनैतिक चिन्तन की प्रश्चित वहें संघ-वद संगठनों की श्रोर है। वाल्कान-राज्यों में भी इस प्रकार का एक संघ बना लेने की दिशा में प्रयत्न चल रहे हैं। सच तो यह है कि श्राज दुनियां के हर एक

देश में प्रजातंत्र के सामने सवाल यह है कि वह वचाव के सशक्त साधनों के साथ ग्रापना सांमजस्य किस प्रकार स्थापित कर सकता है। राष्ट्रीयता की भावना वड़ी ग्राकर्षक है, परन्तु केवल राष्ट्र-प्रेम ग्राथवा प्रजावाद में ग्रास्था से ही कोई देश ग्रापना वचाव नहीं कर सकता। ग्राज तो ग्रुद्ध के साधन इतने वैज्ञानिक हो गए हैं, ग्रीर वहें राज्यों की शक्ति इतनी दुर्धप हो गई है कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विना बचाव की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राज्य की सार्वभौम सत्ता की जो परम्परागत कल्पना है, वह ग्राज ग्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ग्रीर संगठन में एक वड़ी वाधा प्रमाखित हो रही है। हमारे सामने इस विश्वास को कि प्रत्येक राष्ट्र ग्रापना एक स्वतंत्र राज्य वना ले, ग्रीर प्रत्येक राज्य सार्वभौम सत्ता का उपयोग करे, सर्वथा छोड़ देने के ग्रातिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह गया है। राष्ट्रों के लिए ग्राज तो सांस्कृतिक स्वत्वों ग्रीर सामाजिक संस्थाओं के संरक्तण के नैतिक ग्रीर वैधानिक ग्राश्वासनों से संतुष्ट होना ग्रानिवार्य हो गया है; इससे ग्राधिक की मांग स्वयं उनके लिए ग्राहतकर हो सकती है।

श्रव 'सांस्कृतिक इकाइयों' श्रीर 'राजनैतिक इकाइयों, के वीच का श्रन्तर स्पष्ट रूप से माना जाने लगा है। एक समाज केवल जाति, श्रथवा भाषा, ग्रथवा धर्म की दृष्टि से एक होते हुए भी ग्रपने लिए एक स्वतन्त्र-राज्य की मांग नहीं उटा सकता। प्रजातन्त्र त्र्याज संकामक-स्थिति में है। उसे एक नया राज्य-तंत्र, एक नया संगठन, एक नई समाज-व्यवस्था का निर्माण करना है। उसे एक ग्रोर तो, राष्ट्रों ग्राथवा राज्यों की सार्वभीम-सत्ता की कल्पना का परित्याग करना है, ऋौर एक ऐसे संघ-शासन की छोर बढ़ना है जिसमें कई प्रजातन्त्र-देशः एक दूसरे से मिल-जुल कर ग्रपनी विदेशी ग्रौर ग्रान्तरिक समस्यात्रों को सुलभा सकें, ग्रीर दूसरी ग्रीर ग्रकेन्द्रीकरण की दिशा में एक कान्तिकारी कदम उठाना है। हमारी राजनैतिक समस्यास्रों का समाधान स्राज इस दिशा में नहीं रह गया है कि हम अपने देश को, विभिन्न राष्ट्रीयताओं के श्राधार पर, कई भागों में बाँट दें। हमें अपने राष्ट्रीय प्रश्नों पर अन्तर्रा-ष्ट्रीय दृष्टिकोरा से विचार करना है, विश्व की ग्रावश्यकतात्रों ग्रौर प्रवृत्तिथों की त्र्योर सजग रहते हुए । हमें एक त्र्योर तो र्ससार के कुछ प्रमुख देशों से एक निकटतर संपर्क स्थापित करना है, ग्रौर दूसरी ग्रोर श्रपनी केन्द्रीय-सरकार के पास कम-से-कम शक्ति रखना है- -- यह श्रवश्य है कि इस सीमित चेंत्र में वह शिक्त संपूर्ण और अविभाज्य हो। अन्तरींष्ट्रीय विचार धारा का समस्त भुकाव त्राज इसी दिशा में है।

मो कार का विश्वास है कि "केन्द्रीकरण और अ-केन्द्रीकरण के इस

सामंजस्य में ही, इस धारणा में कि शासन-संवंधी कुछ कार्यों के लिए त्राज से कहीं बड़े, श्रीर कुछ श्रन्य कार्यों के लिए श्राज से बहुत छोटे, समूहों की त्रावश्यकता है, हम त्रात्म-निर्ण्य की कठिन समस्या का समाधान पा सकेंगे ।"° मैकार्टने ने लिखा, ''हमारी त्राज की कठिनाइयों का मुख्य कारण है राष्ट्रीयताके त्राधार पर स्थापित राज्य की हमारी वर्त्तमान कल्पना, त्रीर यह विश्वास कि किसी राज्य के समस्त निवासियों की राजनैतिक श्राकांचात्रों श्रीर उनके वहु-संख्यक वर्ग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदशों में तादातम्य है। यदि एक वार मौलिक विभिन्नता रखने वाली इन दो वस्तुत्रों के त्रांतरिक विरोध को समभ लिया जाय तो कोई कारण नहीं कि विभिन्न राष्ट्रीयतात्रों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति एक ही राज्य में पूर्ण सहयोग के साथ क्यों न रह सकें।" श्राज तो विश्व की प्रगति विभिन्न राष्ट्रीयतात्र्यों वाले एक राज्य की ऋोर हो रही है। लॉर्ड एक्टन ने १८६२ में जो लिखा था, उसे ऋाज ऋधिक से ऋधिक समर्थन मिल रहा है, "एक राज्य में कई राष्ट्रों का रहना सभ्य जीवन की उतनी ही आवश्यक 'शर्त है जितना समाज में विभिन्न व्यक्तियों का रहना । जो पिछड़ी हुई जातियां हैं वे मानसिक दृष्टि से अपने से आगे वही हुई जातियों के राजनैतिक संसर्ग से त्र्यागे वढ़ने का त्र्यवसर पाती हैं I जो राष्ट्र थके हुए त्र्यौर पतनोन्मुख हैं, वे नवीन स्रीर सराक्त राष्ट्रों के सहयोग से एक नव-जीवन की प्राप्ति कर लेते हैं।...राज्य के श्रंतर्गत ही वह समन्वय संभव है जो मानव जाति के एक भाग की शक्ति, ज्ञान ं स्रोर चमता दूसरे भाग तक पहुँचाता है।" हिंदुस्तान का तो सारा इतिहास ही श्रीर विशेष कर पिछले १५० वर्षों का इतिहास, लॉर्ड एक्टन के इस कथन की सचाई का साची है। स्राज का वर्त्तमान भारतीय-मुस्लिम-समाज, हिंदू-समाज में बढ़ने वाली नवचेतना का त्राधार पाकर, उससे प्रेरणा लेकर, कभी-कभी उसकी प्रतिक्रिया के रूप में भी, श्रपने समस्त जीवन के नव-निमांग में व्यस्त है । सैयद श्रहमद को हम राम मोहन राय के चरण-चिह्नों पर चलते पाते हैं, जिन्ना मुस्लिम राष्ट्रीयता के निर्माण में गांघीजी का स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, श्रौर इसी प्रकार हिंदू-समाज पर भी उसके इस नव-जीवन की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। पाकिस्तान पारस्परिक प्रेरणा के इन मूल-स्रोतों को ही सदा के लिए सुखा डालेगा ।

१—ई॰ एच॰ कार: Conditions of Peace पु॰ ६३।

२—मैकार्टने: Nation-States and National minorities,

्विभाजन की कुछ अन्य योजनाएं

पाकिस्तान की ग्रव्यावहारिकता ग्रौर सैद्धांतिक ग्रनुपयुक्तता को ग्रव ग्रंग्रेज़ राजनीतिज्ञ भी मानने लगे हैं, श्रीर इस कारण, उनकी श्रीर से, कुछ पर्याय-योजनाएं हमारे सामने ग्रा रहीं हैं । इन्हीं में ग्रॉक्सफ़ोर्ड-यूनीवर्सिटी के विद्वान् प्रोफ़ोसर कृपलैएड की प्रसिद्ध योजना भी है.। प्रो॰ कृपलैएड ने श्रपनी योजना के लिए एक वड़ा ग्राकर्पक नाम रखा है—Regionalism । उनकी योजना का मुख्य त्राधार है देश को सांप्रदायिक दृष्टिकीण से दो भागों में न बांटते हुए त्रार्थिक दृष्टिकोण से चार भागों में बांट दिये जाने का प्रस्ताव । मुस्लिम-लीग की प्रमुख मांग तो यह है कि देश की दो हिस्सों में बांटा जाये; प्रो॰ कृपलैएड उससे एक क़दम आगे जाने के लिए तैयार हैं, और वह चाहते हैं कि ' उसे चार 'च्रेत्रों' (regions) में वांट दिया जाय, ग्रौर ये चारों च्रेत्र एक निःशक्त केन्द्रीय शासन द्वारा एक दूसरे से संबद्ध रखे जायेँ। प्रो० कृपलैएड का यह विचार नया नहीं है। वह स्वयं तो, विभाजन की ग्रन्य सभी योजनाग्रों के समान, उसका प्रारम्भ डॉ॰ इक्तवाल के ऐतिहासिक इलाहावाद-भाषण से करते हैं, पर यद्यपि उनकी यह धारणा निराधार श्रौर भ्रान्तिम्लक है, परन्त यह निश्चय कहा जा सकता है कि यीट्स-योजना व सिकन्दरहयातलाँ योजना से प्रो॰ कपलैएड की योजना का एक निकट, कौटुम्बिक, संबंध अवश्य है।

विभाजन की इन योजनात्रों के कमबद्ध श्रध्ययन श्रीर श्रालोचनात्मक श्रम्वेपण से कुछ मनोरज्ञक वातों पर प्रकाश पड़ता है। पहिली वात तो यह है कि इन सभी योजनात्रों की सृष्टि या तो श्रमुदार दल के श्रंग्रेज़ों के मिस्तिष्क से हुई, या ऐसे हिन्दुस्तानियों के दिमाग़ से, जिनका जीवन नौकरशाही के संरक्षण में बीता है। वूसरी वात यह है कि यद्यपि इन सब योजनात्रों का संबंध मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांग के साथ बताया जाता है, पर यदि उन पर गहराई से विचार किया जाय तो हम यह स्पष्ट देख सकेंगे कि इन योजनात्रों श्रीर पाकिस्तान की कल्पना में कहीं कोई समानता है ही नहीं, श्रीर इसी संबंध में यदि हम कुछ संदेहपूर्ण श्रीर श्रालोचनात्मक दृष्टि से देखें तो हम यह भी समभ सकेंगे कि इन योजनात्रों का मुस्लिम-हितों के संरक्षण का दावा कूंटा श्रीर शरारत-पूर्ण है, श्रीर वे वास्तव में बनाई ही इसलिए गई है कि एक श्रीर तो

विभाजन की कुछ अन्य योजनाएं

मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांग की ख़त्म कर दिया जाय, श्रौर दूसरी श्रोर श्राज़ादी की राष्ट्रीय मांग निर्वल बनाई जा सके।

इन निष्कषों के समर्थन में पाठक का ध्यान उस राजनैतिक वातावरण की स्रोर स्राकर्षित किया जा सकता है जो इन योजनात्रों के लिए पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। इन सव योजनात्रों का विकास १६३६ त्र्रीर १६४४ के वीच में हुन्ना। हमारी राजनैतिक चेतना की उत्क्रान्ति की दृष्टि से यह सभय वड़ा महत्त्वपूर्ण था। महायुद्ध ने, ऋौर उसके प्रारम्भिक वर्षों की राजनैतिक परिस्थिति ने, एक स्रोर तो हमारी स्राज़ादी की मांग को प्रवल बना दिया था, श्रीर दूसरी श्रीर सरकारी नीति, व व्यक्तिगत नेतृत्व श्रीर समूहगत शोषण की भूख, पाकिस्तान की कल्पना को एक प्रखर रूप देने में सकल हो सर्की थी। कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' का नारा बुलन्द कर रखा था। कायदे-स्राजम कहते थे, 'पाकिस्तान दो, और भारत छोड़ों।' स्रंग्रेज़ी सरकार की स्पष्ट नीति यह थी कि वह न तो पाकिस्तान देना चाहती थी, श्रीर न हिन्दुस्तान छोड़ना। केन्द्रीय-शासन में वह तनिक भी ऋधिकार देने के लिए उद्यत न थी--- ऋौर यही सरकार ऋौर कांग्रेस के बीच गत्यावरोध का प्रमुख कारण था। १६३६ में स्थिति यही थी कि कांग्रेस चाहती थी कि केन्द्रीय-शासन पर उसका कम-से-कम इतना ऋधिकार हो जाय कि जिससे प्रान्तीय शासन को एक ग़ैर-ज़िम्मेदार केन्द्र के अवांछित दवाव से बचाया जा सके, परन्तु श्रंग्रेज़ी सरकार इस दिशा में एक इंच भी आगे वढना नहीं चाहती थी। पर, साथ ही वह यह भी जानती थी कि भारतीय राष्ट्रीयता का वल इतना ऋधिक वढ गया था, श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय जनमत का दवाव इतना ऋधिक वढता जा रहा था, कि वह ऋपनी इस स्थिति पर बहुत दिनों तक मज़बूत नहीं रह सकती थी। वह जानती थी कि एक दिन श्रायगा, श्रीर उसे डर था कि वह दिन शायद जल्दी श्राजाव, जब उसे केन्द्रीय शासन में भी भारतीय राष्ट्रीयता को श्रिधिकार देने पर विवश होना पड़ेगा। इसी कारण, ऋंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के कुटबुद्धि समर्थकों ने यह प्रयत्न किया कि इस केन्द्रीय-शासन को ही इतना कमज़ोर, त्रौर निकम्मा, वना दिया जाय कि उसके लिए श्रंग्रेज़ी सरकार की सहायता पर निर्भर रहना श्रानिवार्य हो जाय। उन्होंने ऋपनी इस बौद्धिक उपज के लिए एक वात्विक पृष्ठभूमि तैयार करना भ्रारम्भ की। एक निर्वल केन्द्रीय शासन की खापना के लिए ही इन लोगों ने, देश के विभाजन की एक के वाद एक योजना उपस्थित करना प्रारम्भ की, श्रीर उन सबका उद्देश्य मुसल्मानों की मांग को सन्तुष्ट करने की त्रावश्यकता वताया गया।

इन योजनाओं का ऐतिहासिक विकास

देश को कई 'चेत्रों' में वांट देने के विचार के सूत्रपात का श्रेय भी, पाकिस्तान की योजना के समान, डॉ॰ इक़वाल को ही दिया जाता है। इस्लाम के इस महान् कवि श्रीर विचारक ने 'भाषा, जाति, इतिहास, श्रीर धर्म की एकता व त्रार्थिक स्वार्थों की सामान्यता के ब्राधार पर स्वतन्त्र राज्यों के निर्माण, की चर्चा ग्रवश्य की थी, ग्रौर, उदाहरण के रूप में, उत्तर-पश्चिम में एक भारतीय मुस्लिम राज्य की स्थापना का विचार उपस्थित किया था, परन्तु देश को कई भागों में बांट देने से ग्राधिक दिलचस्पी उन्हें 'पैन-इस्लामिज्म' ग्रीर 'मुस्लिम संगठन' में थी। भारतीय एकता को छिन्न-भिन्न करने अथवा केन्द्रीय शासन को निर्वल वनाने का विचार उनके मन में कभी आया ही नहीं। सच तो यह है, इस विपय में डॉ॰ इक़वाल ने कभी गम्भीरता से सोचा ही नहीं था। प्रो॰ कूपलैएड की योजना का मुख्य त्राधार सर सिकन्दर-हयातख़ाँ की देश को सात भागों में बांट देने की कल्पना थी। इसी प्रकार की कुछ ग्रन्य योजनाएं भी समय-समय पर सामने त्राती रही हैं। ये सव सिकन्दर-योजना से इस संबंध में तो सहमत हैं कि मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेशों को दों 'त्तेत्रों' में वांटा जाय, पर हिन्दू 'त्तेत्रों' की संख्या व उनके विभाजन के सिद्धान्त के संबंध में उनमें मतभेद है। वर्त्तमान प्रांतों को मिटा देने की कल्पना किसी योजना में नहीं है-वे तो शासन की प्रमुख इकाइयों (units) के रूप में मौजूद रहेंगे ही-परन्तु वे 'चोत्रों' से संघवद कर दिये जायंगे, ख्रीर इसी प्रकार सव होंगों को एक अखिल-भारतीय-संघ-शासन में आवद कर दिया जायगा । सर सिकन्दर संभवतः पहिले व्यक्ति थे, जिन्होंने त्तेत्रीय-शासन के इस माध्यमिक स्तर की कल्पना को जन्म दिया था। उनका सुभाव था कि शासन के ऐसे बहुत से सूत्र जिनका संचालन ग्राज केन्द्रीय सत्ता के द्वारा होता है, चेत्रीय-सत्ता के हाथों सींप दिये जाने चाहिएं। इन चेत्रों की अपनी कार्य-कारिगी और ग्रपनी धारासभा होनी चाहिए। सर सिकन्दर यह भी चाहते थे कि प्रांतीय शासन ग्रौर देशी राज्यों को 'त्त्रेत्र' के अन्तर्गत एक दूसरे से संबद्ध कर देना चाहिए।

प्रो० क्पलैएड ने सिकन्दरहयातलाँ के प्रस्तावों की ग्रपनी योजना का मुख्य ग्राधार बनाया है, परन्तु उसका विकास भारतीय सिविल सर्विस के एक सदस्य, मि० यीट्स, की योजना के पद-चिह्नों पर किया है। मि० यीट्स ने, जो १६४१ में हिन्दुस्तान के सेंसर-कामश्रनर थे, यह सुमाव पेश किया था कि, ग्राधिक विभिन्नताग्रीं की दृष्टि से, हिन्दुस्तान को चार हिस्सों में वाट देना

चाहिए। इस विभाजन का स्त्राधार उन्होंने बड़ी-बड़ी नदियों द्वारा सींची जाने वाली ज़मीन को माना है। मि॰ यीट्स का विचार था कि, इस सिद्धान्त के श्राधार पर, उत्तरी हिन्दुस्तान को तीन भागों में वाँटा जा सकेगा—(१) सिंधु-नदी का प्रदेश, काश्मीर से करांची तक (पाकिस्तान की भूमि), (२) गंगा-यमना का प्रदेश, पंजाव श्रीर वंगाल के बीच में (हिन्दुस्तान का इलाक़ा), न्त्रीर (३) गंगा-ब्रह्मपुत्र का प्रदेश, विहार न्त्रीर पूर्वी सीमा के वीच में (उत्तर-पूर्वी हिन्दुस्तान का पर्याय)--श्रौर दिक्त्गा-भारत का समस्त प्रदेश एक इकाई माना जायगा । इस योजना के प्रस्तावक मि॰ यीटस ने अपनी योजना के सम-र्थन में, श्रावपाशी के महत्त्व श्रीर 'हाइड्रो-इलेक्ट्रिक' शक्ति की श्रपरिमित संभावनात्रों पर विशेष-रूप से ज़ोर दिया है। कूपलैयड ने भी त्रामरीका के 'टेनेसी वैली ऋाँथोरिटी' का उदाहरण दिया है, ऋौर इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि हिन्दुस्तान में भी उसका अनुकरण किया जाय। सर सिकन्दर-ह्यातलाँ के समान मि॰ यीटस भी मानते थे कि देशी राज्यों को इन चेत्रों में त्रवश्य सम्मिलित करना चाहिए, परन्तु इस विषय का निर्णय वह उन्हीं के हाथों में छोड़ देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि देशी राज्यों के सम्मि-लित न होने की दशा में भी उनकी योजना को कियात्मक रूप मिलना चाहिए। वैसी दशा में, देशी राज्यों को निकाल कर, शेष प्रदेशों को, उसी सिद्धांत के ब्राधार पर, चार भागों में वांट दिया जाय, ब्रीर इनमें से प्रत्येक भाग स्वतन्त्र श्रीर स्वावलंबी हो ।

क्रिप्स-योजना

किप्स-योजना की देश को कई खएडों में वांट देने वाली इन योजनाश्रों में सिम्मिलित कर लेना कुछ लोगों को शायद श्राश्चर्य-जनक लगे, परन्त तथ्य यह है कि किप्स-योजना में भी, मुस्लिम मांगों को पूरा करने के नाम पर, देश को श्रानेकानेक खएडों में बांट देने का श्रायोजन ही है। किप्स-प्रस्ताव में प्रत्येक प्रांत को यह स्वाधीनता दी गई है कि वह स्वयं इस बात का निर्णय करे कि वह श्राखिल भारतीय संघ शासन में शामिल होगा या नहीं। इस प्रकार देश मर में नये शासन-विधान की स्थापना प्रांतों की श्रपनी इच्छा-श्रानिच्छा पर निर्मर रहेगी। यदि कोई प्रांत श्राखिल-भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहेगा तो उसे यह स्वाधीनता होगी कि वह श्रपना मौजूदा शासन-विधान कायम रख सके। उसे यह सुविधा भी होगी कि वह भविध्य में जब चाहेगा, श्राखिल भारतीय संघ-शासन में शामिल हो सकेगा। एक श्रीर वात जो हमें इस सम्बंध में ध्यान में रखना है, यह है कि उन सब प्रांतों को, जो श्राखिल-

भारतीय संघ-शासन में शामिल नहीं होंगे, यह अधिकार भी दे दिया गया है कि वे यदि चाहें तो अपना एक अलहदा संघ कायम कर सकते हैं, और उसके लिए जैसा चाहें वैसा शासन-विधान बना सकतें हैं। पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लेने का यह एक अनोखा ढङ्ग था। यदि वे सब प्रांत या देशी राज्य, जो ऋखिल-भारतीय संघ-शासन में शामिल होने के लिए तैयार न हों, श्रपना एक श्रलहदा संघ कायम करना भी न चाहें, तव १ वैसी स्थिति में क्या देश भर में छोटे-छोटे खएड-शासनों की स्थापना नहीं होजायगी ? यह भी संभव है कि इनमें से कुछ पांत ग्रीर कुछ देशी राज्य तो ग्रापना एक संघ बना लें, श्रीर कुछ श्रपनी स्वतन्त्र स्थिति कायम रखना चाहें। उसका श्रर्थ होगा, प्रांतीय श्रात्म-निर्णंय के श्राधार पर, देश की श्रनेकानेक भागों में विभाजित कर देना । व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से यदि इस समस्या पर सोचें तो हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि देशी राज्यों की निकाल कर, कांग्रेसी प्रांत भारतीय-संघ में सम्मिलित होंगे व शेष अपना एक अलहदा संघ बना लेंगे। ''परन्तु,'' इस समस्या का विश्लेषण करते हुए श्री॰ मन्शी ने लिखा है, ''यदि उदाहरण के लिए, हम यह मान लें कि पंजाब, वड़ौदा और हैदरावाद के देशी राज्य श्रपना एक श्रालहदा संघ वनाना चाहते हैं तो उस संघ के विभिन्न भागों में भौगोलिक ग्रथवा सांस्कृतिक ग्रथवा किसी भी प्रकार की एकता की कल्पना कर पाना असम्भव है ।.....यदि वम्बई प्रांत तो भारतीय-संघ में शामिल हो जाय, श्रीर वड़ौदा का राज्य श्रलहदा जाना चाहे, तो दोनों में से किसी भी संघ के लिए यह सम्भव नहीं रह जायगा कि वह बिना किसी दूसरे के मामलों में हरतचेप किये अपना काम चला सके।" इस प्रकार के अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं।

कूपलैएड-योजना

इन सब योजनात्रों को एक सूत्र में बांधने छोर वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय प्रो॰ कूपलैएड को है। उन्होंने एक सम्पूर्ण, व्यवस्थित छोर वैज्ञानिक दिखाई देने वाली योजना हमारे सामने रखी। प्रो॰ कूपलैएड ने यह प्रस्ताव किया कि नदियों द्वारा सिंचाई किये जाने वाले प्रदेशों को एक दूसरे से छालहदा संगठित किये जाने की मि॰ थीट्स की जो योजना थी उसे फ़ौरन छमली रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने विभिन्न मू-खएडों के लिए शासन विधान की एक वाह्य रेखा हमारे सामने रखी, छौर साथ ही केन्द्रस्थ-शासन के लिए भी, जिसे उन्होंने एक 'दुर्वल, माध्यमिक केन्द्र' (weak agency centre) का नाम दिया, शासन की योजना का प्रस्ताव किया। उनका सुकाव था कि हमें छपनी राष्ट्र- निष्ठों को संकुंचित श्रौर प्रांत-भाक्ति की श्रधिक व्यापक बनाना चाहिए--जिससे केन्द्र श्रौर प्रांत के वीच शासन-दृष्टि से जिस नये भू-भाग श्रथवा 'च्रेंत्र' की सृष्टि का उनका प्रस्ताव है उसके प्रति ऋपनी भाति को विकसित कर सकें। उनका विश्वास है कि हमारी सांप्रदायिक समस्या को सुलभाने का यही एकमात्र उपाय है। ग्रपनी इस योजना के समर्थन में वह सबसे बड़ी दलील यह देते हैंकि इसके द्वारा देशकी एकता की रत्ता की जा सकेगी। देशकी एकताकी रत्ताके सम्बंध में प्रो॰ कूपलैएड ने अपने आपको बहुत ही उत्सुक वताया है। मि॰ यीट्स के समान, प्रो॰ कूपलैएड भी यह चाहते हैं कि देशी राज्य भी विभिन्न 'चेत्रों' में सम्मिलित हों, परन्तु, उनके विपरीत निर्णय की रिथित में, उनके विना भी त्र्यपनी योजना को कार्यान्वित देखना चाहते हैं। प्रो० कूपलैएड ने केन्द्रीय, न्तेत्रीय व प्रांतीय कार्यकारिखी-समितियों व धारा-सभात्रों के शासन-विधान की एक संपूर्ण वाहा रेखा हमारे सामने रखी है, श्रीर उनके श्रापसी सम्बन्धों का निर्धारण किन सिद्धांतों के स्त्राधार पर हो, इस विषय पर भी प्रकाश डाला है। शासन के विभिन्न स्तरों के वीच सत्ता के बंटवारे के सम्बन्ध में भी उनकी योजना वड़ी स्पष्ट ऋौर विशाद है। एक ऋच्छा विधान-शास्त्री ऋपनी योजना को जितना स्पष्ट रूप दे सकता है, कूपलैएड-योजना में हम उसे पाते हैं।

एक और बात जो हमें इस संबंध में अपने ध्यान में रखना है वह यह है कि चर्चिल-एमेरी दल पर प्रो॰ कूपलैएड का बहुत श्रिधिक प्रभाव था, श्रीर इस कारण उनकी योजना के पीछे सरकारी समर्थन की कल्पना की जा सकती है, श्रीर इंग्लैयड में हाल के वड़े राजनैतिक परिवर्त्तनों के वाद भी, प्रो॰ कूपलैएड स्रोर उनके मित्रों का प्रभाव कम नहीं हुन्ना है। सर स्टैफ़र्ड किप्स जव स्रपनी योजना लेकर हिंदुस्तान में त्राये तन प्रो॰ कृपलैएड, सेकेटरी की हैसियत से, उनके साथ थे। त्राज भी स्टैफ़र्ड किप्स पर उनका प्रभाव है—त्रीर त्र्रेगेज़ी सरकार की स्रोर से प्रस्तावित की जाने वाली किसी भी योजना में सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स का प्रमुख हाथ रहेगा, यह एक निर्विवाद तथ्य है। त्र्राज भी, वीच-वीच में, ऋंग्रेज़ी समाचार पत्रों में, किप्स-प्रस्तावों ऋौर कृपलैएड-योजना की चर्चा प्रायः त्राती रहती है । भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न पर लेवर पार्टी का दृष्टिकील बहुत श्राशापद नहीं है। यह निश्चित है कि वह एक श्रोर वो हमारी स्वाधीनवा की मांग को यल देना चाहती है, श्रौर दूसरी श्रोर मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के पत्त में भी नहीं है। इस दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए कूपलैयड-योजना से ऋच्छी कोई योजना हमारे सामने नहीं है। ऐसी स्थिति ' में हमें स्राश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यदि किसी दिन स्रेंग्रेज़ी सरकार हमारे लिए एक

ऐसे शासन-विधान की तजवीज़ कर दे जिसका ग्राधार कूपलैएड-योजना में हो। विधान-निर्मात्री-सभा की चर्चा तो की जा रही है, परन्तु ग्रभी यह कहां निश्चित है कि उसका निर्माण किन सिद्धांतों पर, व किन तत्त्वों से, होगा, व उसमें मौलिक मतभेद होने की स्थितिमें कौन हमारे भावी शासन-विधान की सृष्टि करेगा ? इसी कारण कूपलैएड-योजना पर वड़ी गम्भीरता से विचार करने की ग्रावश्यकता है। क्षेत्रीय विभाजन के श्राधार-भूत सिद्धांत

त्तेत्रीय विभाजन के सिद्धांत के प्रतिपादकों ने उसके पत्त में यड़ी-वड़ी वातें कही हैं। उनका कहना है कि इसके द्वारा हमारे देश की दो वहुत वड़ी समस्याएं सुलभ सकेंगी-एक ग्रोर तो हम ग्रपनी राजनैतिक एकता को क़ायम रख सकेंगे, ख्रौर दूसरी ख्रोर मुसल्मानों की ख्राशंकाख्रों को दूर कर सकेंगे। इस श्राधार पर उन्होंने हिंदू श्रीर मुसल्मान दोनों से श्रपने श्राग्रह को थोड़ा शिथिल बनाने की ऋषील की है। मुसल्मानों से उनकी दरख्यास्त है कि वह देश को दो हिस्सों में बांट देने की श्रपनी मांग पर इतना ज़ोर न दें, श्रीर हिंदुश्रों से उनका कहना है कि वे प्रजातन्त्र के सिद्धांत के नाम पर वहु-संख्यक वर्ग के प्राधान्य की ग्रपनी धारणा में थोड़ा परिवर्त्तन करें। चेत्रीय-विभाजन का सिद्धांत त्रपने पत्त में जो सबसे बड़ी दलील उपस्थित करता है, वह यह है कि उसके द्वारा देश की एकता को क़ायम रखा जा सकेगा । यह कहा जाता है कि वह राष्ट्रीयता श्रीर श्रात्म-निर्ण्य के सिद्धांत के वीच एक सममौता है-कृपलैएड किसी भी समाज के राष्ट्रीयता के दावे को तो फ़ौरन ही मान लेने के लिए तैयार हैं, परन्तु त्र्यात्म-निर्णंय के ऋधिकार को इतना ऋासानी से मानने के लिए तैयार नहीं। चेत्रीय-विभाजन के सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि मुस्लिम-लीग की दो प्रमुख मांगें हैं--(१) वे अपने लिए एक अलग प्रदेश ऐसा चाहते हैं जहां कि उनके राष्ट्र के व्यक्तियों की प्रधानता हो ऋौंर (२) वे चाहते हैं कि उनके राष्ट्रीय प्रदेशों में एक स्वतन्त्र स्त्रीर सार्वभीम शासन की स्थापना हो । कृपलैएड स्त्रीर उनके साथी इन दोनों मांगों के सम्बन्ध में दो भिन्न मत रखते हैं । वे मुस्लिम-लीग की इस मांग को पूरा करने के लिए तैयार हैं कि मुसल्मानों के लिए एक त्रालग प्रदेश निर्धारित कर दिया जाय—उन्हें इस वात में भी त्रापत्ति नहीं होगी यदि इस प्रकार के कई प्रदेश हों--परन्तु जहां तक एक सम्पूर्ण सार्वभौम राज्य की स्थापना का प्रश्न है, वे उसे एक दिक्कयान्सी विचार मानते हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार की कल्पना यूरोप में १६-वीं शताब्दी में तो सम्भव थी, परन्तु १८६२ में जबसे लार्ड एक्टन ने कई राष्ट्रों के मिले-जुले राज्य की कल्पना को जन्म दिया तव से उस पर से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। उनका • यह भी कहना है कि क्योंकि मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांग का आरम्भ अभी कुछ दिन पहिले ही हुआ है इसलिए उसे विशेष महत्त्व देनेकी आवश्यकता नहीं है।

इन त्राधारभूत सिद्धांतों में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे गहरे मतभेद की गंजाइश हो, परन्तु उन पर जिस योजना का निर्माण किया गया है वह पाकिस्तान से भी ऋधिक ख़तरनाक है। कूपलैग्ड ऋौर उनके साथियों का कहना है कि देश के विभिन्न शासन-तंत्रों को एक सूत्र में पिरो देने के लिए एक केन्द्रीय शासन का होना त्र्यावश्यक है। उनका यह कहना है कि इस केन्द्रीय-शासन का संगठन हम उन सिद्धांतों के त्राधार पर नहीं कर सकते जो श्रव तक हमारे सामने रहे हैं, श्रीर न १६३५ के एक्ट के केन्द्रीय शासन से ही उसकी समानता होगी। १६३५ से पहले की केन्द्रीय शासन की हमारी कल्पना का त्राधार केन्द्रीकरण का सिद्धांत था; १६३५ के एक्ट में उसका संगठन संघ शासन के सिद्धांतों के त्राधार पर हुत्रा। चेंत्रीय योजना में केन्द्रीय शासन का रूप इन दोनों से भिन्न होगा । उसकी रिथित एक बीच की रिथित होगी। संघ-शासन में केन्द्र को जो ऋधिकार मिले होते हैं, इस योजना में वे विल्कल भिन्न होंगे। सच तो यह है कि संघ-शासन का इस योजना से एक मौलिक श्चन्तर होगा । इसमें न केवल शासन की इकाई का रूप ही भिन्न होगा परन्त उसके केन्द्रीय-शासनं की स्थापना के ब्राधार-भूत सिद्धांत भी उससे विल्कुल भिन्न होंगे। इसी कारण से च्लेत्रीय-विभाजन की योजना के समर्थक हमसे श्रपेका करते हैं कि हम संघ-शासन के संगठन के परम्परागत विचारों को श्रपने मन से निकाल दें ऋौर विल्कुल नये ढंग से सोचने के लिए तैयार रहें।

योजना का राजनैतिक महत्व

इस योजना की ऋार्थिक दृष्टिकोण से तो वड़ी सराहना की गई है, परन्तु उसका राजनैतिक महत्त्व भी बहुत ऋषिक बताया जाता है। पहली बात तो उसके पत्त में यह कही जाती है कि उसके द्वारा मुसल्मानों के लिए एक ऋलग प्रदेश की मुस्लिम-लीग की मांग को पूरा किया जा सकेगा—सिंधु ऋौर गंगा-ब्रह्मपुत्र द्वारा सिंचाई किये जाने वाले प्रदेश, पाकिस्तान ऋौर उत्तर-पूर्वी हिंदुस्तान का रूप ले लेंगे, और दूसरी वात यह है कि यदि इस योजना को ऋमल में लाया गया तो हिंदू बहु-संख्यक ऋौर मुस्लिम बहु-संख्यक प्रदेशों में समानता की स्थापना की जा सकेगी। यह तो स्पष्ट ही है कि इस योजना में मुस्लिम-लीग की दो प्रमुख मांगों में से एक मांग ही पूरी की जा सकेगी। मुसल्मानों के लिए स्वतन्त्र प्रदेशों की स्थापना हो सकेगी, परन्तु हिंदुस्तान से

संबंध-विच्छेद करने का उन्हें श्रिधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस योजना के समर्थक देश की एकता को बनाये रखने के लिये अपने को बहुत उत्सुक बताते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह योजनां कई प्रकार की विभिन्न मांगों को एक साथ ही सन्तुष्ट करने का दावा करती है। एक श्रोर तो वह श्रंप्रेज़ों के हाथों से हिन्दुस्तानियों के हाथों में राज्य की सत्ता को साप जाने की राष्ट्रीय मांग का समर्थन करती है—यह श्रलग बात है कि वह सत्ता कितनी खोंखली श्रोर सारहीन होगी—दूसरे, वह देश की एकता को बनाये रखने की हिन्दू मांग को पूरा करने का दावा करती है, श्रोर, तीसरे, मुसलमानोंके लिए श्रलहदा प्रदेश बना देने का श्रायोजन भी उसमें है। ये सब बहुत बड़े दावे हैं, श्रोर उनका एक सूक्त विश्लेपण करके हमें यह देखना है कि उसके पीछे सचाई का श्रंश कितना है।

क्षेत्रीय शासन-विधान

इसके लिए हमें उस प्रसावित शासन विधान पर दृष्टि डालना है जो चेत्रीय विभाजन के ग्राधार पर वनाया गया है I सबसे पहले हम केन्द्रीय शासन को ही लें । चेत्रीय योजना में केन्द्रीय शासन एक बहुत ही निर्वल श्रीर नि:शक्त शासन होगा-इस प्रकार के केन्द्रीय शासन के समर्थन में यह कहा जाता है कि भारतीय परिस्थितियों में इसके ग्रातिरिक्त ग्रीर किसी प्रकार के केन्द्रीय शासन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। प्रो० कृपलैएड ने केन्द्र के ऋधिकारों के संबंध में जो लिखा है उससे हमें मतभेद नहीं है। जिस सिद्धान्त पर उन्होंने इन ग्राधिकारों का निर्धारण किया है, वह भी विलकुल ठीक ही हैं । उनका कहना है कि भारतीय केन्द्रीय शासन के पास जो कम-से-कम अधिकार हों वे ऐसे हीं जिनसे वाहर से देखने से हिन्दुस्तान की एकता किसी प्रकार से भंग होती हुई दिखाई नहीं देती हो। दूसरे शब्दों में, यह अधिकार ऐसे हों जिनसे बाहर की दुनियां से हिन्दुस्तान का संबंध स्पष्ट होता हो। जैसे-(१) विदेशी नीति श्रीर रत्ना, (२) बाहर के देशों से व्यापार श्रीर श्रायात-निर्यात के संबंध की नीति, ग्रीर (३) मुद्रा (currency) यह विलक्कल ही उचित प्रतीत होता है। कृपलैएड ने देश के भीतर के छाने जाने के मागा श्रोर साधनों, मोटरों, रेलों श्रीर हवाई जहाज़ों, श्रादि के परन पर भी इस दृष्टि से विवार किया है कि उनका नियन्त्रण केन्द्रीय शासन के द्वारा हो ^{है} ग्रंथवा किसी ग्रान्तर्चेत्रीय सत्ता के द्वारा, ग्रीर इस संबंध में उनका मत यह है कि यह नियन्त्रण त्रान्तर्चेत्रीय सत्ता के द्वारा ही किया जाना चाहिए। यह विचार भी संघ शासन के उस सिद्धान्त की दृष्टि से ठीक ही है। जिसके अनुसार अधिक से-

श्रिधिक श्रकेन्द्रीकरण श्रीर कम-से-कम केन्द्रीकरण' पर ज़ोर दिया जाता है ।

कूपलैएड ने यह विलकुल स्पष्ट कर दिया है कि यह ज्ञान्तर्केंत्रीय संघ संघ-शासन से विलकुल भिन्न होगा ऋौर साथ ही विभिन्न स्वतन्त्र राज्यों के, विशोध परिस्थितियों के कारण, एक ढीले-ढाले संगठन (confederacy) से भी भिन होगा । उसकी स्थिति बीच की होगी । संघ शासन से उसमें यह अन्तर होगा कि जब कि संघ शासन (१) साधारणतः तुलनात्मक दृष्टि से ऋपने से कम शिक्तशाली राजनैतिक इकाइयों से संबंध रखता है, (२) स्त्रीर उसका निर्माण राष्ट्रीय एकता त्रीर स्थानीय स्वतन्त्रता के त्राधार पर होता है, चेत्रीय विभा-जन का सिद्धांत हिन्दुस्तान को कुछ ऐसे वड़े-बड़े राज्यों में वांट देना चाहता है, जो यदि चाहें तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, श्रीर एक ऐसे केन्द्रीय शासन की स्थापना करना चाहता है जो शुद्ध रूप से स्नान्वर्जेत्रीय संस्था होगी, स्नीर जो अपने अधिकारों के लिए चेत्रीय शासन की दया पर निर्भर रहेगी। ये चेत्रीय शासन यदि चाहें तो शासन के ऋधिकारों का स्वतंत्र ऋौर सार्वभौम रूप से उपयोग भी कर सकेंगे, परन्तु वे देश की एकता के नाम पर ऋपनी ऋपा-दृष्टि पर सम्पूर्ण रूप से स्थिर रहने वाले एक केन्द्रीय शासन की स्थापना कर लेंगे। प्रो॰ कृपलैएड के शब्दों में ''श्रान्तर्ज्ञेत्रीय केन्द्र केवल उन्हीं न्यूनतम श्रिधकारों का उपयोग करेगा जिनका उपयोग देश की एकता को बनाये रखने की दृष्टि से विल्कुल ही स्रावश्यक होगा स्रौर उन स्रिधकारोंका प्रयोगभी वह किसी स्रिखिल भारतीय जन-मत के द्वारा दी गई सत्ता के आधार पर नहीं परन्तु चेत्रीय शासन के एक ग्राज्ञा-पालक की हैिसयत से ही करेगा।" इस ग्रन्तिम वाक्यं में ही . इस योजना ्का सारा ज़हर छलक उठता है। कूपलैएड का केन्द्रीय शासन चेत्रीय शासनों का त्राज्ञा-पालक भर होगा, उसकी त्रपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होगी स्त्रीर उसकी कार्यकारिशी-सिमिति स्त्रीर धारा-सभास्रों के सदस्यों का एक-मात्र कर्त्तव्य चेत्रीय शासन के त्रादेशों की पूर्ति करना होगा ।

प्रो॰ क्पलैएड ने हमें यह कह कर आश्वत्व करना चाहा है कि सर सिकन्दर-हयात ख़ां की योजना का केन्द्र तो इससे भी अधिक निर्वल था! इस कथन में सचाई अवश्य है। सिकन्दरहयातख़ां की केन्द्रीय शासन की कल्पना की जड़ में तो प्रतिक्रिया की भावना काम कर रही थी, एक ऐसे सार्वभीम सत्ता वाले केन्द्र के विरोध में, जो प्रांतीय शासन के कार्य में हस्तत्त्रेप करने की प्रतीन्ता में ही रहता हो। केन्द्रीय शासन के सम्बन्ध में उनकी धारणा थी कि वह "एक सहानुभूतिपूर्ण शासन-वन्त्र होगा" एक ऐसी संस्था जिसका निर्माण 'इकाइयों' द्वारा, केन्द्रीय शासन-व्यवस्था के नियंत्रण और निरीन्त्रण के लिए, किया जायगा श्रीर जिसका काम केवल यह होगा कि जो भार उसे प्रान्तोंके द्वारा सीपा जाय, वह उसे कुशलता, सदाशयता ग्रौर न्याय की भावना के साथ पूरा कर दे।" सर सिकन्दर तो उसे एक ''संयोजक-समिति" (Co-ordination Committee) के नाम से पुकारने को भी तैयार थे। कृपलैएड ने सर सिकन्दर के केन्द्र के संवंध में जो ग्रालोचना की है उससे यह ग्रनमान हो सकता है कि स्वयं उनके द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय शासन संभवतः कुछ ऋधिक सवल होगा । ऋपनी चेत्रीय योजना को उन्होंने विभिन्न राज्यों के एक संगठन (Confederay) से ऋषिक सुगठित माना है। उनका कहना है कि इस प्रकार के राज्य-संघ की अपनी कोई सत्ता नहीं होती, न कोई अधिकार ही होता है, और उसके जो निर्णय होते हैं वे ऐसे होते हैं जिनके संबंध में विभिन्न राज्यों की सहमित होती है। स्त्रीर जिन्हें कियात्मक रूप उन राज्यां द्वारा उनके ग्रापने खर्चे पर दिया जाता है। कृपलैएड का कहना है कि उनका प्रस्तावित ज्ञान्तर्ज्ञेत्रीय केन्द्र इसके विल्कुल विपरीत एक स्वतन्त्र शासन-तन्त्र होगा, जो स्वयं ऋपने सिपाहियों को स्वयं ऋपने ऋादेश दे सकेगा, ग्रौर ग्रपना खर्चा भी स्वयं ही करेगा । परन्तु इस शाब्दिक ग्राडम्बर के पीछे यदि हम वस्तुरिथित को समफाने का प्रयत्न करें तो हम स्पष्ट देख सकेंगे कि इन दोनों में विशेष अन्तर नहीं है।

इन योजनात्र्यों के बनाने वालों की मनोवृत्ति उस समय विल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है जब हम त्रान्तर्चेत्रीय केन्द्र की धारा-सभान्नों त्रीर कार्यकारिसी के प्रस्तावित विधानों पर दृष्टि डालते हैं। सरसिकन्दरह्यात खां ने तो १६३५ के एक्ट में प्रस्तावित धारा-सभा के वरावर वड़ी धारा-सभा की ही कल्पना की थी, वे केवल यह ग्रन्तर चाहते थे कि उसमें दो के स्थान पर एक चैम्बर हो, ३३ प्रतिशत स्थान देशी नरेशों के प्रतिनिधियों के लिए सुरित्तत हों, श्रीर २५० स्थानों में से ३३ प्रतिशत मुसल्मानों के लिए । कृपलैएड व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या बहुत कम कर देना चाहते हैं, श्रीर चाहते हैं हिंदू बहु-संख्यक न्त्रीर मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में एक 'संतुलन' की स्थापना करना । उनकी योजना के अनुसार मुसल्मान, जिनकी ज्ञावादी देश में २४ प्रतिशत है, यदि चाहें तो केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में ५० प्रतिशत स्थान प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार से वह कार्यकारिगी सभा के सदस्यों की संख्या व उसके महत्त्व की कम कर देना चाहते हैं। कार्यकारिगी का महत्त्व तो उस समय अपने आप ही कम हो जायगा, जब उसका बहुत कम विभागों पर श्रिधकार होगा । कूपलैएड एक राजनैतिक दल के हाथों में सता सींपे जाने के भी विरोधी हैं, श्रीर इसलिए वह यह भी चाहते हैं कि कार्यकारिणी का निर्माण मिश्रित रूप से हो, श्रर्थात् उसमें कई राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो । इस आधार पर जो कार्य-कारिणी सिमिति, या मंत्रिमण्डल, बनेगा उसकी स्थिति वड़ी नाजुक होगी । इसका अन्दाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि क्ष्पलैण्ड ने यह सुमाव पेश किया है कि मंत्रिमण्डल का संगठन स्विज़रलैण्ड के विधान के आधार पर हो, अर्थात् धारा-सभा के द्वारा उसका जुनाव तो हो जाय, परन्तु अपने दिन-प्रतिदिन के शासन में वह उसके प्रति उत्तरदायी न हो, उसके अन्तर्गत जो थोड़े से विभाग हों वे हिन्दू और मुसल्मान चेंत्रों में बरावर बांट दिये जायं, और उसका अध्यत्त वारी-वारी से एक हिंदू और एक मुसल्मान हों । ऐसा जान पड़ता है कि अपने इस केन्द्र के स्थायित्व में स्वयं क्ष्पलैण्ड को संदेह था, और इसी कारण अपने इन प्रस्तावों के अन्त में उन्होंने अपनी यह राय भी जाहिर कर दी है कि एक अलग धारा-सभा और एक अलग कार्य-कारिणी वनाने के बदले यदि एक उस प्रकार की मिली-जुली कोंसिल की स्थापना कर दी जाय जैसी कि अपने राज्य के प्रारम्भिक वधों में थी तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

क्या यह एक वड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि यह योजना जो हिंदुस्तान को ईस्ट इिएडया कम्पनी की अराजकतापूर्ण व्यवस्था की स्रोर लौटा ले जाने का प्रस्ताव करती है, हमारी त्राज की सांप्रदायिक समस्या का एक त्राच्छा समाधान होने का दावा भी करती है ? यह कहा जाता है कि विभिन्न चेत्रों में 'संतुलन' की स्थापना करने से यह समस्या मुलभ जायगी--इस योजना के समर्थकों को इस 'संतुलन' में ही सब समस्यात्रों का निदान दिखाई दे रहा है। सिकन्दर-ह्यातलां के प्रस्तावों को उन्होंने इस कारण ग्रस्वीकृत कर दिया कि वह दो मुसल्मान ग्रौर पांच हिंदू च्रेत्रों की कल्पना कर रहे थे। जान पड़ता है कि मुस्लिम हितों के संरक्त्ए के संबंध में प्रो॰ कृपलैएड सर सिकन्दरहयातखां से भी श्रिधिक सतर्क हैं! तभी तो वह हिंदू चेत्रों की संख्या पांच से घटा कर दो रखना चाहते हैं। प्रो॰ कृपलैएड का विश्वास है कि ऐसा करते ही हमारी सांप्रदायिक समस्या का हल निकल आयगा--नयोंकि अब देश के विभिन्न भागों की जनता सांप्रदायिक भावना के स्थान पर उन 'महान् देशों' के प्रति भिक्त की भावना को विकसित कर लेगी जिनका निर्माण चेत्रीय विभाजन की योजना के आधार पर होगा । केन्द्रीय संयुक्त-सिमिति में जो हिंदू ऋौर मुसल्मान सदस्य होंगे वे ऋपने-सम्प्रदायों द्वारा नहीं परन्तु 'च्लेत्रों' द्वारा चुने जायंगे। कृपलैयड ने हिंदू श्रीर मुसल्मान दोनों से यह ऋपील की है कि वह उनकी इस योजना को स्वीकार कर लें। हिंदु ग्रों से उन्होंने जो ग्रापील की है उसका ग्राधार यह है कि जिस सप्तक केन्द्रीय कार्यकारिगी-समिति श्रीर महान् राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा की वे कलाना

कर रहे हैं-- ग्रौर जिसकी ग्रोर १८६१ से १९४४ तक हिंदुस्तान ग्राग्रसर होता जारहा था-वह ग्राज की परिस्थितियों में ग्रसम्भव होगये हैं। ग्रपने उस स्वन को कार्यान्वित करने के लिए तो हिंदुस्तान को एक राष्ट्र के रूप में पुनर्जन्म लेने की त्रावश्यकता होगी। कपलैएड हिंदुस्तान को एक राष्ट्र में देखने की हिंदुक्रों की महत्वाकांचा को विल्कुल ही कुचल नहीं देना चाहते। पर उसके लिए वह उन्हें सब्र करने की सलाह देते हैं। "धीरज" प्रो॰ कृपलैएड एक स्थान पर लिखते हैं, ''राजनैतिक गुणों में सबसे श्रेष्ठ है। ग्रीर ग्रव तो यह स्पष्ट है कि यदि हिंदुस्तान की जनतायें कभी एक राष्ट्र वनना चाहें तो उसमें समय लगेगा।" इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रो० कृपलैएड ने इतनी दया अप्रवश्य की है कि हमारे हृदय से इस आशा और इस स्वप्न को कि हमारा देश किसी दर, धूमिल, भविष्य में शायद कभी एक राष्ट्र वन सके, विल्कुल मिटा नहीं दिया है। प्रो॰ कुपलैएड ने वैसी ही ज़ोरदार ग्रापील मुसल्मानों से देश को दो भागों में बांट देने की ऋपनी मांग को वापिस ले लेने, ऋौर उनकी चेत्रीय योजना को स्वीकार कर लेने, के लिए की है, क्योंकि उनका कहना है कि उक्त योजना के अनुसार उन्हें हिन्दुओं के वरावर अधिकार मिल जायंगे। जिस योजना के सम्बन्ध में इतने बड़े-बड़े दावे किये जा रहे हैं उसका ग्रार्थिक, सांस्कृतिक, साम्प्रदायिक श्रोर राजनैतिक, सभी दृष्टिकोगों से श्रध्ययन कर लेने का दायित्व हमारे ऊपर छा जाता है।

योजना का ऋार्थिक-क्षप

सबसे पहिले योजना के ग्रार्थिक पत्त को लें। त्रेत्रीय योजना का तो मुख्य ग्राधार ही यह है कि वह राजनीति को साम्प्रदायिक धरातल से उठा कर ग्राधिक धरातल पर प्रस्थापित कर देना चाहती है। ऊपर से देखने से तो यह वात वड़ी ग्राक्पक, ग्रोर प्रगतिशील, दिखाई देती है, परन्तु वस्त्रस्थित क्या है ? त्रेत्रीय विभाजन की योजना क्या ग्रुद्ध ग्राधिक दृष्टिकोण से हमारी भारतीय परिस्थितियों को सुधारने का सर्वश्रेष्ट उपाय है ? इस योजना में दो वातों पर विशेष जोर दिया गया है। एक तो नहरों से सिचाई; दूसरे पानी से विजली तैयार करना। यह मानते हुए भी कि हिन्दुस्तान के ग्रार्थिक विकास के लिए ये दोनों वातें ज़रूरी हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि वे ग्राज देश के सामने सबसे ग्राधिक महत्वपूर्ण काम है, ग्रीर इसके ग्रातिरिक्त, उनका विकास तो किसी भी प्रकार की सरकार के द्वारा, चाहे वह पाकिस्तान की सरकार हो या ग्राखण्ड हिन्दुस्तान की, किया जा सकता है। इसके लिए केवल ग्रान्तर्गान्तीय सहयोग की ग्रावश्यकता है, त्रेत्रीय योजना ज़ैसी ग्रीपिध का

प्रयोग, जो सम्भवतः बीमारी से भी ग्राधिक ख़तरनाक सावित हो, ग्रावश्यक प्रतीत नहीं होता। इसके ग्रावा चेत्रीय योजनात्रों में से ग्राधिकांश में ग्राधिक पच्च पर ग्राधिक ध्यान नहीं दिया गया है। सिकन्दर हयात ख़ां योजना में तो जान पड़ता है इस पर विल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। यदि उनकी योजना ग्रामल में लाई जाय तो मैसूर राज्य को उसके प्राकृतिक ग्राधिक सम्पकों से उन्मूलित कर दिया जायगा, क्योंकि उनका प्रस्ताव उसे मद्रास या मद्रास की रियासतों या कुर्ग में शामिल करने का नहीं परन्तु वम्त्रई, पश्चिमी भारत की रियासतों ग्रीर मध्य प्रान्त की रियासतों के साथ रखने का है। इसी प्रकार मध्य प्रान्त की रियासतों भी ग्रापने प्राकृतिक सम्पकों से ग्रालहदा करके वम्त्रई की रियासतों ग्रीर हैदरावाद में मिला दी जायंगी। यह समभना कठिन है कि देश के विभिन्न प्रदेशों को इस प्रकार, विना किसी वैज्ञानिक ग्राधार ग्राधा सिद्धान्त के, किसी भी शासन के सिपुर्द कर देने से कैसे उनकी ग्राधिक उन्नित हो सकेगी।

यह वात नहीं है कि इस प्रकार के दोष केवल सिकन्दरहयातलाँ योजना में ही हों, यीटस-योजना व कुपलैएड-योजना भी जो वैज्ञानिक होने का दावा रखती है, इन दोषों से मुक्त नहीं हैं, यद्यपि उनमें ये दोष इतने वड़े परिमाण में नहीं हैं। यीटस-योजना ने निदयों श्रीर उनके द्वारा सींचे जाने वाले मैदानों को विभाजन का ऋाधार माना है, परन्तु यह समभाना कठिन है कि किस सिद्धान्त के ऋनु-सार उन्होंने नदी के 'डेलटा' को उसके 'वेसिन' से अलहदा करने का प्रस्ताव रखा है-क्योंकि उनकी योजना में वंगाल को गंगा-यमुना के प्रदेश से ऋलग रखा गया है। स्रार्थिक विकास की किसी भी सुगठित .योजना के सम्यक् विकास के लिए यह त्र्यावश्यक है कि एक प्रमुख नदी द्वारा सींचा जाने वाला समस्त प्रदेश एक ही शासन के अन्तर्गत रखा जाय । इसके अतिरिक्त, यह भी कम ऋाश्चर्य की बात नहीं है कि सारा दिन्तिणी पठार एक ही चेत्र मान लिया गया है। इस संबंध में श्री॰ मुन्शी ने लिखा है, "पाकृतिक भूगोल की दृष्टि से भी प्रो० कृपलैएड की चेत्रीय योजना ऋर्यहीन है। निदयों के ऋाधार पर विभाजन की चर्चा में वह नदी द्वारा सींचे जाने वाले प्रदेश की प्रायः विलक्कल भूल गये हैं। राजपूताना सिंधु नदी से सम्बद्ध नहीं है। वंगाल, जिसे उन्होंने गंगा के मैदान से अलहदा कर दिया है, गंगा और उसकी सहायक-नदियों पर ही निर्भर है। उड़ीसा को उन्होंने गंगा के डेलटा के साथ जोड़ा है, पर उसकी ग्रपनी नदियां विल्कुल भिन्न हैं, गंगा के मैदान से ग्रथवा राजपूताने के देशी राज्यों से अनका कोई संबंध नहीं है। दिक्तिए का तो अपना कोई

श्रलहदा निदयों का समृह है ही नहीं।""

यीट्स ग्रीर कृपलैएड दोनों ने ग्रपनी च्लेत्रीय योजनात्रों की तुलना ग्रमरीका की 'टेनेसी-वैली-ग्रॉथोरिटी' से की है, परन्तु यह तुलना ग़लत ग्रीर भ्रमोत्पादक है। पहिली बात तो यह है कि टी० वी० ए० के प्रयोगों की सफलता के संबंध में सभी लोग एकमत नहीं हैं। कुछ तो उसके संबंध में बहुत सन्देह-शील भी हैं। इसमें तो संदेह नहीं कि इस प्रयोग में ग्रारम्भ में तो ग्रासफलता ही मिली थी। एक समय ग्रा गया था जब टेनेसी-नदी का बहुत बड़ा हिस्सा धूल से भर गया था, एक सशक्त केन्द्रीय सरकार के हस्तचेंप से ही टी० वी० ए॰ को इस भयावह स्थिति से मुक्ति मिल सकी। टी॰ वी॰ ए॰ के संबंध में वहत से राजनैतिक विचारकों का तो यह मत है कि यह संघ-शासन द्वारा एक ऐसे चेत्र में त्रानधिकार हस्तच्चेप है, जो वस्तुतः स्थानीय शासन के ब्रान्तर्गत होना चाहिए। दूसरे, जो लोग टी० वी० ए० का उदाहरण हमारे सामने रखते हैं वे प्रायः यह भूल जाते हैं कि यह प्रयोग केन्द्रीकरण की दिशा में है, न कि श्रकेन्द्रीकरण की, जब कि हमारी च्रेत्रीय योजनात्रों के विधाता केन्द्र की शक्ति को ही चकनाचर करके चेत्रों में वांट देना चाहते हैं। ग्रामरीका में टी॰ वी॰ ए॰ की स्थापना का परिगाम यह हुन्ना है कि विभिन्न राज्यों ने, जिनकी सीमान्त्रों के अन्तर्गत टेनेसी नदी का प्रवाह है, अपनी सार्वभौम सत्ता का एक अंश एक ऐसी केन्द्रीय सरकार के हाथों सौंप दिया है, जो बहुत से मामलों में अमरीका की केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत है। इस प्रयोग से अमरीका में केन्द्रीय सरकार की शक्ति तिनक भी कम नहीं हुई है, बिल्क, यह कहना चाहिए, कुछ बढ़ ही गई है। तीसरी वात जो इस संबंध में हम ध्यान में रखें वह यह है कि टी० वी० ए० का ऋधिकार-चेत्र बहुत ही सीमित है। उसका काम केवल यही है कि वह बाढ की रोक-थाम करे, नदी में यातायात के साधनों की उन्नति करे, न्त्रीर विद्युत्-शिक्त का विकास ग्रीर प्रसार करे। इसके विपरीत चेन्नीय योजना के समर्थक यह चाहते हैं कि चेत्रीय इकाइयां ही सार्वभौम-सत्ता की वास्तविक केन्द्र यने ।

एक वहुत बड़ा प्रश्न जो इस संबंध में उठता है, वह यह है कि क्या केवल आर्थिक चेत्रवाद (economic regionalism) को ही राज-नैतिक इकाइयों के निर्माण का एकमात्र आधार माना जा सकता है ? और यदि ऐसा किया भी गया तो क्या यह भारतीय परिस्थितियों में व्यावहारिक होगा ? हिन्दुस्तान को यदि हम आर्थिक चेत्रवाद के सिद्धान्त के आधार पर १—के॰ एम॰ मुन्शी: The Indian Deadlock, पु॰ १०३–४।

कई भागों में वांटना चाहें, तो हम देखेंगे कि हमारी सीमा-रेखाएं भाषा, इति-हास, संस्कृति त्र्यादि की सीमा-रेखात्रों को स्थान-स्थान पर काट देंगी, त्र्रीर समाज-शास्त्र का कोई भी विद्यार्थी यह जानता है कि किसी भी देश के सीमा-निर्माण में इन तत्त्वों का भी कितना ऋधिक महत्त्व है। ऐसी स्थिति में हमें यह पूछने का ऋधिकार है कि हिन्दुस्तान के ऋार्थिक विकास की दृष्टि से क्या चेत्रवाद ही एकमात्र, अथवा सर्वश्रेष्ठ, मार्ग है ? जैसा कि खयं प्रो॰ कूपलैएड ने माना है, चेत्रों द्वारा जो काम किया जा सकता है वह विभिन्न प्रांतों के सलाह-मश्चिरे श्रीर सहयोग से भी हो सकता है। इन परिस्थितियों में, भारतीय शासन-तंत्र में, जो ऋव भी कुछ, कम जटिल नहीं है, चेत्रों की वृद्धि विशेष वांछनीय नहीं मानी जा सकती। इसके ऋतिरिक्त, यदि प्रांतीय • 'इकाइयाँ' स्रपना वर्त्तमान स्वरूप स्रोर सत्ता कायम रखेंगे—स्रोर यीट्स स्रोर कृपलैएड दोनों यही चाहते हैं - तब तो चेत्रों की ग्रावश्यकता ग्रीर भी कम हो जाती है। इसके ऋतिरिक्त भी, एक ऋौर प्रश्न जो पूंछा जा सकता है वह यह है कि ऋार्थिक क्तेत्रवाद का सिद्धांत समस्त देश पर लाद देने की क्या त्र्यावश्यकता है, जब कि उसकी उपादेयता स्पष्ट ही कुछ भागों तक ही सीमित है ? उसकी स्रावश्यकता काश्मीर के थोड़े से भाग, समस्त पंजाव, सीमा-प्रांत के पूर्वी भाग, राजपूताना के उत्तर-पश्चिमी भाग ऋौर सिंध के लिए तो मानी जा सकती है, पर उसके त्राधार पर सारे देश की सीमाएं वदल डालना, श्रीर हिन्दू बहु-संख्यक चोत्रों का निर्माण कर लेना - जहां कि उसकी विल्कुल श्रावश्यकता नहीं है---वहुत न्यायसंगत नहीं जान पड़ता ।

सच तो यह है कि चेत्रवाद के आधार पर देश को कई भागों में बांट देना एक विल्कुल ही अ-वैज्ञानिक कार्य होगा । वैसे देखा जाय तो आर्थिक चेत्रवाद के सिद्धान्त को या तो प्रो० कृपलैएड ने ठीक से समका नहीं है, या जान-बूक्त कर उसके ध्रर्थ को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश की है! आर्थिक चेत्रवाद के सिद्धान्त को यदि हम उसके सही रूप में लें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि इस दृष्टि से समग्र, अविभाज्य, हिन्दुस्तान एक आर्थिक चेत्रव (region) है, उसका कोई एक भाग विशेष नहीं—उसके प्रत्येक भाग को अपने आर्थिक विकास के लिए अन्य भागों पर निर्भर रहना पड़ता है, परन्तु यदि हम समस्त देश को लें तो वह आर्थिक प्रनिर्माण की दृष्टि से एक स्वयं-संपूर्ण और स्वावलम्बी इकाई माना जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी विश्व की प्रवृत्ति ध्रव एक वड़ी आर्थिक इकाई की कल्पना की छोर अग्रसर हो रही है—अपरीका के महाद्वीपों, मध्य-पूर्व के देशों, यहां तक कि सतत-

युद्धोन्मुख यूरोप में भी, यह प्रवृत्ति हम स्पष्ट देख सकते हैं। हिन्दुस्तान तो संसार के उन थोड़े से देशों में से हैं — इस संबंध में कंवल दो ग्रन्य देशों, ग्रमरीका के संयुक्त-राज्य ग्रीर सोवियट रूस, का नाम लिया जा सकता है— जो भोगोलिक ग्रीर ग्रार्थिक दृष्टि से सम्पूर्ण इकाई माने जा सकें। हिन्दुस्तान में एकता की यह भावना काफ़ी विकास भी पा चुकी है— देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ने वाली सड़कें ग्रीर रेलें, तार ग्रीर डाक के साधन, सामान्य मुद्रा ग्रीर वैंक, सामान्य नियम ग्रीर ग्रनुशासन, ग्रीर एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक फेलता रहने वाला चिर-यात्रा-शील मानवं—समुदाय, कलकत्ते के सिख टैक्सी-ड्राइवर ग्रीर विहारी रिक्शावाले, देहली की सेकेटेरिएट के सहस्व- सहस्व मद्रासी क्लर्क, वम्बई के 'मय्ये'—ये सब प्रतित्तृत्व एकता की उन कड़ियों को मज़बूत बनाते रहते हैं। यदि हमने त्रेत्रीय विभाजन के सिद्धांत के ग्राधार पर देश को विभिन्न भागों में बांट दिशा तो वे समस्त ग्राधार तत्त्व जिन पर एक देश-व्यापी ग्रार्थिक योजना की स्थापना की जा सकती है, व्यरी तरह से चूर-चूर हो जायंगे।

योजना का सांस्कृतिक पक्ष

चेत्रीय योजना में सांस्कृतिक प्रश्नों को तो विल्कुल ही उपेचा की दृष्टि से देखा गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यदि इस योजना के श्रानुसार देश को कई भागों में बांट दिया गया तो उसमें भाषा, इतिहास, संस्कृति, परम्पराएं ग्रादि, जिनकी किसी भी राजनैतिक पुनर्निर्माण में उपेचा नहीं की जा सकती, विल्कुल ही उपेक्तित रह जायंगे । इस संबंध में सिकन्दर योजना तो वहत ही दोपपूर्ण है। उसमें, चेत्र नं० ५ में, गुजराती श्रौर मलयालम भापा-भाषियों को एक साथ रख दिया गया है, पर मराठी, तेलगू श्रीर कन्नड़ भाषा-भाषी विभिन्न चेत्रों में बांट दिए गए हैं। बीट्स व कूपलैएड की योजनाश्चों में भी हम सांस्कृतिक प्रश्नों की अवहेलना के कई उदाहरण पाते हैं। राजप्ताना, इतिहास, परम्परात्रों ग्रीर संस्कृति की दृष्टि से, एक सांस्कृतिक इकाई वन गया है, पर प्रो॰ कुपलैएड उसे तीन भागों में बांट देना चाहते हैं। उसकी दिचाणी रियासतें, वांसवाड़ा, दांता, इंगरपुर श्रीर पालनपुर वे दिल्ला में मिला देना चाहते हैं, पूर्वी रियासतें, भरतपुर, बूंदी, धीलपुर, करौली ख्रीर कोटा, गंगा-यमुना के प्रदेश के साथ संबद्ध होंगे, श्रोर शेप रियासतें सिंधु नदी के मैदान से जोड़ दी जायंगी । परन्तु, केवल राजपूताना ही एक ऐसी सांस्कृतिक इकाई नहीं है जिसका इस प्रकार से विभाजन किया गया हो । यदि प्रमुख नदियों के द्वारा सींची जाने वाली भूमि को ही विभाजन का ग्राधार वनाया गया, तो सिखों को

भी दो विभिन्न च्रेत्रों में बांटना होगा—क्योंकि अम्वाला डिवीज़न, अलवर और जिंद की रियासतों के सहित गंगा-यमुना के द्वारा सींचा जाता है, न कि सिंधु के । यदि उसे सिंधु नदी के प्रदेश में रखा गया तो आर्थिक च्रेत्रवाद के सिद्धांत की उपेचा होगी । उड़ीसा की समस्या भी काफ़ी जिंटल है । वह वैसे तो एक छोटा-सा प्रांत है, परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से उसकी अपनी एक स्वतन्त्र सत्ता है, उसके किसी भी प्रकार के निकट, जातिगत अथवा सांस्कृतिक, संबंध न तो वंगाल से हैं, और न मद्रास से । ऐसी स्थिति में यह निरुचय करना किटन होगा कि उसे किस च्रेत्र में रखा जाय । जहां तक उसकी नदियों का संबंध है, महानदी उसका संबंध मध्य-प्रांत से जोड़ती है परन्तु ब्राह्मणी का प्रवाह छोटा नागपुर की ओर है। कूपलैएड ने उड़ीसा को गंगा नदी के प्रदेश से संबद्ध किया है, 'पर किस आधार पर उन्होंने ऐसा किया है, यह नहीं लिखा ।

योजना का सांप्रदायिक पक्ष

प्रन्त, जेत्रीय योजना यदि हमारी सांप्रदायिक समस्या को सुलक्षा पाती है, तव तो हम उसकी दूसरी कमियों को वदीश्त कर लेने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। इस दृष्टि से, वह मुसल्मानों की उनके लिए ऋलहदा प्रदेशों की मांग की, सिंधु और डेलटा प्रदेशों के निर्माण के द्वारा, जो पाकिस्तान और उत्तर-पूर्वी हिंदुस्तान का पर्याय होंगे, पूरा तो करती है, बल्कि उनकी मांग से कुछ ऋषिक ही उन्हें दे देती है, परन्तु मुस्लिम संस्कृति के संरच्या की दृष्टि से इन प्रदेशों की स्थिति को कमज़ोर बना देती है। ज्ञेत्रीय योजना इन प्रदेशों की हिंदू स्त्राबादी की संख्या को बहुत बढ़ा देती है । इस संबंध में संख्यात्रों पर एक तुलनात्मक दृष्टिपात कर लें। जब कि राजाजी की योजना के पाकिस्तान में हिंदू श्रीर मुसल्मानों की संख्या का श्रनुपात पाकिस्तान में १७:८३ श्रीर उत्तर-पूर्वी हिंदुस्तान में २६:७१ होगा, श्रीर मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की कल्पना के अनुसार वह क्रमशः ३०:७० और ४५:५५ होना. कृपलैएट-योजना उसे वडा कर ४०:६० और ४५:५५ कर देनी। यह समसना कटिन है कि मुस्लिम प्रदेशों में हिंदुश्रों की संख्या वटा देने से सांप्रदायिक समस्या के सुलभने में सहायता कैसे मिलेगी। इससे हिंदू स्तेतों में सुसल्मानों की संस्या श्रवश्य कम हो जायगी जिसका परिणाम यह होगा कि वे लोग, दिना गुमल्मानी द्वारा किसी रोक-टोक के, अपनी संस्कृति का विकास कर सकेंगे. परन्तु सुस्तिस-चेत्रों में हिंदुओं की संख्या बढ़ा देने से तो उनकी समस्या आध्य जटेल ही हो जायगी, क्योंकि इतनी वड़ी संख्या वाला वर्ग द्यवस्य इन चेत्रों के शासन द्यीर धारा-सभात्रों में एक प्रभावपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहेगा ।

मुस्लिम-संस्कृति के विकास के प्रश्न को भी यदि हम एक ब्रोर रख दें, तो भी क्या इस योजना से देश का सांप्रदायिक वातावरण कुछ ग्राधिक शुद्ध वन सकेगा ? जब कि चेत्रोंके निर्माण का ग्राधार ही सांप्रदायिक है-सारा ग्रायोजन ही दो हिंद्'चेत्रों के 'संतुलन' में दो मुसल्मान चेत्रों को खड़ा करने का है—तो यह निर्विचाद है कि ये दोनों समूह, शान्ति से रहने के वदले, त्यापस में लड़ते-भगड़ते रहेंगे। इसका परिगाम देश के वातावरण पर बुरा ही पड़ेगा। इसके श्रितिरिक्त, प्रत्येक चेत्र की श्रपनी श्रान्तिरिक सांप्रदायिक समस्या तो वनी ही रहेगी । हिन्दू चोत्रों की शासन-व्यवस्था दिन-प्रति-दिन हिन्दू-संस्कृति के प्रमाय में त्राती जायगी, इससे वहां की मुसल्मान जनता का त्राधिकाधिक जुन्ध होना स्वांभाविक होगा, ग्रौर उनकी इन भावनाग्रों की प्रतिक्रिया मुसल्मान-त्रेत्रों द्वारा हिन्द-चेत्रों के प्रति चरती जाने वाली नीति पर भी ऋवश्य पड़ेगी। यदि मुस्लिम-चेत्रों में रहने वाले हिन्दू श्रीर मुसल्मानों के श्रापसी संबंध विगड़ते रहे, तो यह संभव है कि उनका यह संघर्ष एक बड़े ग्रह-युद्ध का रूप ले ले । इन चेत्रों में हिन्दुत्रों त्रौर मुसल्मानों की संख्या में विशेष त्र्यन्तर भी नहीं होगा-एक में उनका ग्रानुवात ४०: ६० व दूसरे में ४५: ५५ होगा । ऐसी स्थिति में इस प्रकार के गृह-युद्ध की संभावना श्रीर भी वढ़ जाती है। श्रीर क्योंकि इन चोत्रों की अपनी सार्वभौम-सत्ता होगी, एक निर्वल केन्द्रीय सरकार के लिए उन पर किसी प्रकार का दवाव डालना भी ऋसंभव ही होगा। सच तो यह है कि ऐसे निर्वल केन्द्रीय शासन के द्वारा इस प्रकार के इस्तच्चेंप की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन परिस्थितियों में हम तो केवल यही सोच सकते हैं कि इंग्लैएड का साम्राज्यवादी पंजा इस केन्द्रीय शासन का मुख्य त्राधार होगा, त्रौर देश में किसी भी प्रकार की ग्रशांति ग्रथवा ग्रराजकता की स्थिति में वह सार्वभौमता के उस निर्वल खोल को वड़ी स्थासानी से फाड़ कर फेंक देगा. जिसमें इस योजना के समर्थक चेत्रीय शासन को मह देना चाहते हैं।

योजना का राजनैतिक पक्ष

चेत्रीय योजना की समस्त प्रवृत्ति यह दिखाई देती है कि राष्ट्रीयता की भावना के टुकड़े-टुकड़ें करके उसे छोटी-छोटी भौगोलिक सीमाग्रों में वांट दिया जाय। इस पर भी चेत्रीय योजना भारतवर्ष की एकता को क्रायम रखने का दावा करती है! सच तो यह है कि इससे बड़ें मिथ्या दावे की कल्पना शायद ही की जा सके। चेत्रवाद हिन्दुस्तान को चार राज्यों, प्रो० क्ष्पलैएड के शब्दों में 'चार महान् देशों' में वांट देना चाहता है, ग्रोर उनसे ग्रयेचा करता है

कि प्रत्येक ऋपनी विभिन्न राष्ट्रीयता का विकास करे। परन्तु, राष्ट्रीयता की भावना क्या इस प्रकार, कृत्रिम साधनों द्वारा, विकास पा सकेगी ? समस्त चेत्रीय विभाजन अवैज्ञानिकता और स्वेच्छारिता पर निर्भर है। वह सांस्कृतिक समन्वय श्रीर श्रार्थिक सामान्य-हितों के सर्वथा विरुद्ध जाता है। ऐसी स्थिति में जनता से यह त्राशा करना कि वह डेल्टा-प्रदेश त्र्रथवा ब्लॉक नं० ४ के प्रति रातों-रात एक राष्ट्रीयता की भावना को परिवर्धित कर लेगी, एक दुराशा-मात्र है। ज्ञेत्रीय विभाजन का स्पष्ट परिगाम तो यही निकलेगा कि जिस राष्ट्रीय भावना का विकास हम पिछली त्राधी शताब्दी में, त्याग त्रीर साधना, विलदान श्रीर कष्ट सहन के रास्ते कर पाये हैं उसे एक गहरी ठेस पहुँचेगी, श्रीर हममें प्रांतीयता की भावना का विकास होगा। प्रांतीयता की भावना हममें काफ़ी गहरी है भी। त्र्याज तो वह राष्ट्रीयता के वेग में छिपी हुई है, पर देश की सजीव एकता की भावना जब हमारे सामने नहीं होगी, तब इन कृत्रिम चैत्रों के लिए उसे निर्वल बना पाना सर्वथा ऋसंभव होगा । तव तो प्रांतीयता ही हमारी न्त्राज की राष्ट्रीयता का स्थान ले लेगी, ऋौर, एक वार जब प्रांतीयता की भावना हद होने लगेगी, तव चेत्रीय विभाजन की जड़ें ऋपने ऋाप उखड़ती चली जायंगी । वंगाली ऋौर स्त्रासामी कव तक यह वर्दाश्त करेंगे कि वह एक निर्जीव डेल्य-प्रदेश से संबद्ध रहें। वह स्वभावतः ही श्राज़ाद होना चाहेंगे। इसी प्रकार, पंजाव ऋौर सिंध ऋौर सीमा-प्रांत भी सिंधु-चेत्र से स्वतन्त्र होने का प्रयत्न करेंगे, श्रीर युक्तप्रांत, व विहार व उड़ीसा श्रपने श्रलग स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लेंगे । देश को चार भागों में वांटते ही वंटवारे की यह प्रवृत्ति इतना उप रूप ले लेगी कि बहुत थोड़े अससे में ही हिन्दुस्तान कई छोटे-ह्योटे राज्यों में बँट जायगा-कहीं तो एक झांध-राज्य की सृष्टि होगी, कहीं उत्कल का निर्माण होगा, कहीं विदर्भ श्रीर महाकोशल श्रपनी समस्त ऐतिहा-सिक परम्परात्रों को लेकर पुनर्जन्म ग्रहण करते दिखाई देंगे, श्रीर ये सब स्वतंत्र कहलाने वाले 'राज्य' दूरस्थ ब्रिटेन के इशारे पर नाचेंगे ।

च्तेत्रीय विभाजन की समस्त योजनाश्रों को सभी दृष्टिकोणों से देखने के वादं मेरा वो यह निश्चित मत है कि, उनकी तुलना में, पाकिस्तान कहीं श्रिधिक श्रच्छा है। पाकिस्तान में कम-से-कम एक हिन्दू श्रीर एक मुसल्मान दो स्ववंत्र राज्यों की कल्पना वो की गई है, जो श्रपनी-श्रपनी संस्कृति के संरक्षण श्रीर विकास में दत्तचित्त हो सकेंगे। पाकिस्तान के बन जाने पर भी हम यह श्राशा वो कर ही सकते हैं कि किसी दिन ये दोनों स्वतन्त्र राज्य श्रपने सांप्रदायिक वैमनस्य से अपर उठ कर, जर्मनी श्रीर श्रास्ट्रिया के समान, एक राजनैतिक

एकता में त्रावद हो सकेंगे। यह बहुत संभव है कि देश की भौगोलिक एकता, त्रार्थिक हितों की समानता और रचा की त्रावश्यकताएं उन्हें एकता की ग्रोर बढने पर मजबूर कर दें । मेरे ग्रास्ट्यिन मित्रों का कहना है कि यद्यींप ग्रास्ट्या सांस्कृतिक दृष्टि से एक विल्कुल स्वतन्त्र ग्रीर संपूर्ण इकाई है, परन्तु ग्रार्थिक त्र्यावश्यकताएं उसे सदा ही जर्मनी के साथ एक निकटतम राजनैतिक संबंध बनाये रहने पर विवश करेंगी, उसके लिए उसे सांस्कृतिक दृष्टि से चाहे कितना ही त्याग क्यों न करना पड़ें। मैं समभता हूँ कि पाकिस्तान की स्थिति भी विल्कुल वैसी ही होगी। शायद हम पाकिस्तान को जर्मनी द्वाग ग्रास्टिया को दिये जाने वाले आश्वासनों से कहीं अधिक सवल और प्रामागिक आश्वासन दे सकेंगे। इसके ग्रातिरिक्त, पाकिस्तान की मुश्लिम-मांग के पीछे कम-से-कम एक गहरा विश्वास तो है-चाहे उसकी गहराई कितनी ही गुलत क्यों न हो श्रीर चाहे उस विश्वास से हम कितने ही जुब्ध क्यों न हों— कि मुसल्मान एक त्रालहदा राष्ट्र हैं। ऐसी दशा में यदि पाकिस्तान की स्थापना की गई, तो वह कम-से-कम एक 'राष्ट्रीय' मांग की पूर्ति के रूप में तो होगा, ग्रौर 'राष्ट्रीयता' की यह भावना, स्त्रीर सब विरोधी परिस्थितियों के होते हुए भी, पाकिस्तान के स्यायित्व का एक सवल ऋाधार वन सकेगी, परन्त, चौत्रीय विभाजन की योजना के पीछे न तो भविष्य के लिए कोई श्राशा होगी श्रीर न निकट-वर्तमान में किसी प्रकार की न्याय की भावना । जिस प्रकार के राज्य की कल्पना प्रो॰ कृपलैएड ने की है-जिसमें एक तोत्र के विरुद्ध दूसरा चीत्र, एक संप्रदाय के विरुद्ध दूसरा संप्रदाय, एक प्रांत के विरुद्ध दूसरा प्रांत होगा-वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में त्रपना कोई स्थान वना सकेगा, यह एक संदेहास्पद प्रश्न है। उसका तो ऋपना ऋान्तरिक वैषम्य—च्तेत्रीय, सांप्रदायिक, जातिगत—इतना ऋधिक होगा कि वह ऋन्य देशों, संभवतः ब्रिटेन, के हाथों में एक खिलौना-मात्र वना रहेगा। कौन कह सकता है कि यह स्थिति हमारे देश के लिए वांछनीय अथवा स्पृहणीय होगी ?

: ??:

(अ) भारतवर्ष और संघ-शासन

सांस्कृतिक आधार-भूमि

भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता इतिहास का एक निर्विवाद तथ्य है। इस एकता की नींव उस दिन पड़ी जिस दिन त्रायों ने ऋपनी ऋध्यातम-प्रधान संस्कृति की व्यापक परिधि में इस देश के ऋादिम-निवासियों को समाविष्ट करने का निश्चय किया । प्रागीतेहासिक-काल की भारतीय संस्कृति ग्रार्य ग्रीर द्राविड़ संस्कृतियों का समन्वय थी । ऋायों ने न केवल द्राविड़ जाति के देवता श्रों श्रोर उनकी उपासना की पद्धांत को त्रापनाया, पर उनकी भाषा त्रीर संस्कृति का भी बहुत श्रधिक प्रभाव उनकी श्रपनी विचार-धारा पर पड़ा । चितिमोहन सेन जैसे विद्वानों का मत तो यह है कि प्राचीन भारत में यद्यपि त्रायों ने राजनैतिक प्रमुखता प्राप्त कर ली थी, पर जिस वस्तु को ज्ञाज हम प्राचीन भारतीय संस्कृति के नाम से जानते हैं, उसमें द्राविड़ संस्कृति का प्राधान्य था। शिव च्रीर दुर्गा त्र्यादि की पूजा का त्रारम्भ इस सांस्कृतिक समन्वय के वाद ही हुन्ना । विदेशों से जो तत्त्व, शक ग्रौर हूण, कुशान ग्रौर सीथियन ग्रादि, भारतवर्प में ग्राते गये वे सब इस त्यार्य-द्राविड़ संस्कृति के त्राविभाज्य त्राङ्ग वनते चले गये । उन्होंने एक-दो पीढियों के बाद ही भारतीय देवतात्रों की श्राराधना श्रारम्भ कर दी, श्रीर श्रपने विदेशी नामां को छोड़कर भारतीय नामां को श्रङ्गीकार किया। त्रार्य-द्राविड़ त्रौर विदेशियों की इस ग्रनवरत-शृङ्खला द्वारा लाई जाने वाली मिश्री-यूनानी-श्रासीरियन-वैवीलोनियन संस्कृतियों के समन्वय से वह संस्कृति दनी जिसे ग्राज हम हिंदू-संस्कृति के नाम से जानते हैं।

मुस्लिम-न्नाहमण के पहिले इस हिंदू-संस्कृति का रूप स्वष्ट हो चला था, न्नीर उसकी वाह्य-रंखान्नों में कुछ कठोरता न्नाने लगी थी। फिर भी समन्वय की शिक्ति मिटी नहीं थी। दिक्षण भारत में जहां इस्लाम ने शान्तिपूर्ण उगरों से प्रवेश किया, हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय, प्रधानवः धार्मिक चेत्र में, बहुत जल्दी द्यारम्भ होगया था, परन्तु उत्तर भारत में इस्लाम का मंदा लेकर जो लोग न्नाये उनके न्नाई-सम्य, और कभी-कभी तो बहुशियाना, वरीकों का असर हिंदुओं पर अच्छा नहीं पड़ा, और कुछ दिनों तक उन्होंने आत्म-रज्ञा की दृष्टि से यही उचित समभा कि वे अपने समाज के चारों ओर कट्टरता की एक फ़िलेबन्दी कर लें, परन्तु आकमण की आंधी के थम जाने पर मुस्लिम-संस्कृति की लहरें इस चहारदीवारी की नींवों को चारों तरफ से खोखला बनाने लगीं, और धीरे-धीरे न केवल हमारी राजनीति ही मुसल्मानों के प्रभाव में आगई पर हमारे धार्मिक विचार और आचार, रहन-सहन और रीति-रिवाज, भाषा और साहित्य, मूर्तिकला और चित्रकला, सभी पर उनकी संस्कृति का गहरा प्रतिविंय पड़ा, और साथ ही जो मुसल्मान वाहर से आये थे, और आते गए, वे भी इस देश की संस्कृति के प्रभाव से अपने कोमुक्त नहीं रख सके। आज जिस चीज़ को हम भारतीय-संस्कृति, अथवा हिंदुस्तानी तहज़ीव, के नाम से पुकारते हैं, उसमें हिंदू और मुस्लिम प्रभाव ताने-वाने के समान एक-दूसरे में गुंथ-मिल गए हैं, और बगैर भारतीय-संस्कृति के तार-तार किये हुए, उन्हें एक दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता।

हमारे देश में जातियों त्र्यौर भाषात्र्यों की विभिन्नता के होते हुए भी सांस्कृतिक एकता का विकास हो सका है; विभिन्न प्रादेशिक संस्कृतियां अपने व्यक्तित्व को क्रायम रखते हुए भी, संगीत के स्वरों के समान, एक-रूप हो सकी हैं। जैसा कि एक ग्रंग्रेज़ लेखक ने लिखा है, "भारतवर्ष एक संस्कृति का नाम है, न कि एक जाति का," श्रीर प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेता सर हर्वर्ट रिज़ले के शब्दों में, ''शारीरिक और सामाजिक, भाषा, रीति-रिवाज और धर्म संबंधी, अनेकों विभिन्नतात्रों के होते हुए भी हिमालय से कन्याकुमारी तक देश का समस्त जीवन एक सूत्र में ही विरोया गया है। "अ० मुन्सी के शब्दों में, "भारत का साहित्य एक है, क्योंकि उसके संस्कार कुछ, ग्रालग-ग्रालग नहीं हैं। जिस तरह श्राकाश के श्रनिगनत तारे गिनने की उतावली में श्रज्ञानी लोग उनकी ताल पर सधी हुई चाल की परीचा नहीं कर सकते, उसी तरह विशाल अन्तर, विभिन्न लिपियों श्रीर भाषात्रों के भेद, की वजह से भारतीय साहित्य की श्रमली एकता को भी नहीं देख सकते।" एक ग्रन्य स्थान पर श्री० मुन्शी लिखते हैं, --''सारे देश के साहित्य का एक ही संस्कार में से जन्म हुआ है। उसमें एक ही किस्म के बीज बोये गए हैं, एक ही तरह का खाद डाला गया है। इस प्रकार एक ही क़िस्म के श्रंकुर, चेत्र की विशेषता की मात्रा से थोड़ा-बहुत श्रलगाव दिखलाते हुए भी विचित्र रंगों वाले एक ही प्रकार के रस-समृद्ध परिपाक से

१—श्रो'मैली—Modern India and the West.

र—रिज्बे—The People of India.

लहलहा रहे हैं। भारत का साहित्य एक था, एक है ऋौर एक रहेगा।""

इस ऐतिहासिक श्रौर सांस्कृतिक एकता को क्रायम रखना श्राज की राजनैतिक पोरिरिथति में त्रौर भी त्रावश्यक होगया है। हमारा देश त्राज एक शक्तिशाली साम्राज्य के साथ संघर्ष कर रहा है; एकता के त्राधार पर ही इस संघर्ष को सफल बनाया जा सकता है ! जिन लोगों का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का ज्ञान गहरा है उनका अनुमान है कि परिस्थितियां अव ऐसी आगई हैं कि हिंदुस्तान की आ्राज़ादी को बहुत दिनों तक रोका नहीं जा सकता। यह मान लेने पर कि हिंदस्तान की त्राजादी इतना निकट त्रागई है भारतीय एकता को बनाये रखने का हमारा दायित्व श्रीर भी बढ जाता है। त्राज़ाद हिंदुस्तान का विश्व की राजनीति में एक बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग होगा, इसमें तो संदेह है ही नहीं। श्र-तर्राष्ट्रीय राजनीति का गुरुत्व-केन्द्र श्रटलांटिक से प्रशांत-महासागर में श्राजाने से हिंदुस्तान का दायित्व ग्रौर भी त्र्राधिक वढ जाता है। भविष्य का महायुद्ध प्रशांत महासागर में होगा स्त्रीर उसमें हिंदुस्तान को एक महत्त्वपूर्ण भाग लेने पर विवश होना पड़ेगा। पूर्वी द्वीप-समूह में जिस विद्रोह की लपटें आज अपने पूरे वेग पर हैं, भारतीय राजनीति का 'एशिया छोड़ो' का ताज़ा नारा श्रपने श्चन्तराल में उसी के विस्फोट को लिये है। श्राज हिंदुस्तान विवश हो, श्राज त्रंग्रेजी त्रीर डच साम्राज्यवाद एशियायी त्राजादी की इस जंग को कुचल सकें,पर त्राज़ाद होजाने पर हिंदुस्तान इन सब प्रश्नों की यों ही नहीं छोड़ देगा । हिंदुस्तान की त्राज़ादी एशिया की त्राज़ादी में निहित होगी। गुलाम एशिया श्रीर श्राज़ाद हिंदुस्तान की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की एशिया की ऋाजादी के लिए भी लड़ना होगा। परिस्थितियों का सारा संकेत इसी दिशा में है कि श्रंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिदुस्तान ग्रपने लिए एक शिक्तशाली स्थान बना ले।

पिछले दो महायुद्धों, श्रीर उनके बीच के श्रशांविपूर्ण वर्षों में यह विल्कुल ही स्पष्ट होगया है कि किसी निःशक राष्ट्र के लिए श्रपनी तटस्थता के निश्चय में श्राश्वस्त रहना शेख़िचली के स्वप्न जैसा है। छोटे राष्ट्रों का श्रय कोई भविष्य नहीं रह गया है। भविष्य या तो श्रमरीका श्रीर रूस जैसे बढ़े राष्ट्रों के हाथ में है, जिन्हें प्रकृति ने ही स्वयं-संपूर्ण बना दिया है, या भौगोलिक दृष्टि से समीपित्र श्रीर श्रार्थिक दृष्टि से परस्तरावलंबी उन छोटे-छोटे राष्ट्रों के हाथ में, जो श्रपनी राष्ट्रीय सार्वभौमता को भुलाकर एक राजनैतिक श्रीर श्रार्थिक सृत में श्रावद हो सकते हैं। दिक्षण श्रमरीका की लैटिन रियासतें, पश्चिमी पृरोप के

१ - के॰ एम॰ मुन्शी : भारतीय साहित्य श्रीर भाषा ।

प्रजातंत्र देश, मध्य-पूर्व के द्यारव-राज्य द्यादि इस प्रकार के संघों का विकास कर सकते हैं। हिंदुस्तान द्यानी संभावनाद्यों की दृष्टि से, द्यानीका द्यार रूस का समकत्त्र है। वह यदि स्वतंत्र हों, द्योर द्यपने द्यार्थिक साधनों का समुचित विकास कर सके, तो उसकी गिनती संसार के महान् राष्ट्रों (Great Powers) में हो सकेगी। द्यपने द्यार्थिक साधनों को विकास की चरम-सीमा तक पहुंचा देना इस महानता की द्यावश्यक रार्च होगी। प्रत्येक देश की राजनीति द्याज उसकी द्यर्थनीति के साथ संबद्ध है। देश भर में फैले हुए इन राशि-राशि द्यार्थिक साधनों के समुचित विकास के लिए एक सराक्त केन्द्रीय सरकार की द्यावश्यकता होगी। द्यार्थिक पुनर्निर्माण की योजनाद्यों को कार्योन्वित करने के लिए प्रत्येक देश में इस प्रकार की सशक्त केन्द्रीय सरकार की द्यावश्यकता होती है, द्यार जिन देशों में वैसी सरकार नहीं है, वहां उसकी स्थापना करना पड़ती है। द्यांग्रेज़ी शासन से हमें जो एक द्यात्यच्च लाभ हुत्या है, वह यह है कि उसने देश में राजर्नातक व द्यार्थिक एकता की भावना को विकसित किया है। द्याज जब देश का भविष्य उसकी इस एकता पर निर्मर है, तव द्यांग्रेज़ी शासन के साथ उसे भी उत्वाङ फेंकना द्यारम-हत्या के समान होगा।

इसके साथ ही एक दूसरी बात भी हमें दृष्टि से खोमाल नहीं कर देना है। केन्द्रीकरण के तत्त्वों के साथ-साथ हमारे देश में अकेन्द्रीकरण की प्रश्चित भी श्रपने प्रवल रूप में हैं। उसकी जड़ें इतिहास की गहराई में हैं, यदापि पिछले पचाम वर्षों में उसका बहुत अधिक विकास हुआ है। ईसा से सात शताब्दी पहिले, जात भारतीय इतिहास के प्राराभिक काल में, हमें सोलह महाजन पदीं, ग्रथवा स्वतः व गज्यां का वर्णन मिलता है, ग्रीर उनकी जी सीमाएं थीं एक हद तक उनकी ही पुनरावृत्ति हम मुराल ब्रीर ब्रांग्रेज़ी साम्राज्यों के प्रान्तों में भी पाते हैं। जब कभी एक महान् साम्राज्य का विकास होता है- स्रौर हमारे देश के लम्बे इतिहास में ऐसे युग बहुत अधिक नहीं हैं — जनपदों की ये सीमा-रेखाएं भुँ धर्ली पड़ती जाती हैं, श्रीर मिट भी जाती हैं, पर साम्राज्यों के दहते ही वे फिर एक स्पष्ट रूप ले लेती हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से इस प्रश्न की देखें तो हमें पता लगेगा कि भारतीय संस्कृति की व्यापक परिधि के अन्तर्गत अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व लिए एक दर्जन से ग्राधिक संस्कृतियां हैं। वंगाल ग्रीर महा-राष्ट्र, पंजाव श्रीर गुजरात, सिंध श्रीर मलयालम, उड़ीसा श्रीर तामिलनाड में संस्कृति का मीलिक भेद नहीं है, यह कहना वस्तुत्थिति की अवहेलना करना है। हमारे देश की प्रान्तीय संस्कृतियों की विभिन्नता एक टोस ऐतिहासिक तथ्य है। सच दो यह है कि हमारे देश में संस्कृति की विभिन्नताओं का मुख्य ग्राधार

धार्मिक उतना नहीं है जितना भौगोलिक । वंगाली हिन्दू ग्रोर वंगाली मुसल्मान में भेद करना कठिन है,पर वंगाल के हिन्दू ग्रीर पंजाव के हिन्दू में वड़ी ग्रासानी से भेद किया जा सकता है । महाराष्ट्र का एक मुसल्मान उसी प्रदेश के हिन्दू के साथ ग्राधिक घरेलूपन महस्स करता है, युक्तप्रांत ग्रथवा सीमाप्रांत के मुसल्मान के साथ कम । हमारी राष्ट्रीयता की भावना के साथ-साथ वंगालियों का वंग-भृमि से प्रेम, मराठों का महाराष्ट्र की परम्यग्रों ग्रोर संस्कृति में गौरव की ग्रानुभृति, गुजरातियों की गुजरात की जय-कामना, यहां तक कि उत्कल ग्रीर विदर्भ, ग्रांध ग्रीर बुन्देलखरड, राजस्थान ग्रीर मालव की ग्रपनी स्थानीय-राष्ट्रीयता के भाव भी बढ़ते जा रहे हैं।

हिन्दू श्रौर मुसल्मानों में संस्कृति का भेद उतना गहग नहीं है, पर इन दोनों समाजों का ऋन्तर भी दिन-प्रति-दिन बढता ही जा रहा है, इसमें सदेह नहीं। यह ग्रान्तर राजनैतिक स्तेत्र तक ही सीभित नहीं है; बल्कि यह कहना चाहिए कि राजनैतिक चेत्र में वह उतना गहरा नहीं है, जितना सांरकृतिक चेत्र से । राज नैतिक च्रेत्र में तो एकता के प्रयत्न लगातार जार्ग हैं, पर हिन्दुय्रों र्य्यार मुसल्मानों की सांस्कृतिक विभिन्नताएं वहती जा रही हैं। भाषा के चेत्र में हिन्दुस्तानी, ग्रथवा हिन्दी-हिन्दुस्तानी, का माध्यम लेकर समन्वय के जितने प्रयत्न हुए, वे सभी श्रसफल रहे हैं। हिन्दी श्रार उर्दू का भेद बहुना आ रहा है -हिन्दु ख्रों का भुकाव प्रायः संस्कृतमयी हिन्दी की छोर है, मुसल्मान ऐसी उर्दू को जो फ़ारसी छोर छरवी के शब्दों से लदी हुई है. छपनाने जा रहे हैं। वंगाल, गुजरात और सुद्र दिच्या के मुसल्मान भी श्रव श्रामी प्रांतीय भाषाश्री की एक ग्रालग शैली का निर्माण करने में जुटे हैं। यहन-सहन, स्वान-पान ग्रीर श्राचार-विचार का श्रन्तर भी बढता जा रहा है। पोशाक श्रीर तहजीब, श्चदव श्चौर इख़लाक़ की श्रसमानताएं तो कुछ पहिले से थी हीं, राय वे श्चौर भी स्पष्ट होती जा रही हैं। एक दूसरे के उत्सव होंगर त्योहारों के प्रति उदासीनता का भाव बढता जा रहा है, पर साथ ही ग्राप्त त्योहार और उलावा को ग्राप्ते प्राचीन रूप में मनाने का आग्रह भी अब पहिले से अधिक प्रवल है। यह बढती हुई सांस्कृतिक विभिन्नता ही मुस्लिम-लीग के दो-राष्ट्री के सिद्धान्त की जड में है।

इस प्रकार, हमें एक छोर तो भारतवर्ष की राजनीतिक एकता की छानि-वार्यता को मानना पड़ता है, छौर दूसरी छोर सांप्रदायिक छीर प्रांतीय भेदों के छाधार पर-प्रस्थापित उसकी सांस्कृतिक विभिन्नता से भी एकार गर्ग विया जा सकता। छाज की सबसे बड़ी छान्यस्यकता इन दोनों के बीच एक समन्त्य

स्यापित करने की है। इम ग्राज करते यह हैं कि ग्रापनी राजनैतिक ग्राकांचार्ग्रों के ग्रावेश में सांस्कृतिक विभिन्नतात्रों की ग्रवहेलना करते हैं—दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों के विरोध श्रौर श्रखण्ड हिन्दुस्तान के नारे के पीछे राष्ट्रीयता का यह श्रनसमभ जोश ही है । श्रपनी इन सांस्कृतिक विभिन्नताश्रों का हमें खुले दिल से स्वागत करना चाहिए : वह हमारे गौरव की वस्तु है। यह विभिन्नता हमारी भारतीय संस्कृति को ऋधिक समृद्धिशाली ही बनाएगी। उसके लिए शर्त्त यही है कि हम ग्रपने सांस्कृतिक प्रश्नों को राजनैतिक प्रश्नों से संबद्ध करने की ग़लती से वर्चे । दूसरे शब्दों में, हम राजनैतिक इकाई ग्रीर सांस्कृतिक इकाई में भेद करना सीखें। राजनै तिक ग्रीर ग्रार्थिक दृष्टि से समस्त भारतवर्ष का एक सशक्त केन्द्रीय-शासन के श्रान्तर्गत रहना श्रात्यन्त श्रावश्यक है, पर सांस्कृतिक दृष्टि से उसे ग्रानेकों इकाइयों में बांटा जा सकता है, बांटा जाना चाहिए। उनमें से कुछ प्रदेशों में मुस्लिम-संस्कृति का प्राधान्य होगा, श्रधिकांश में हिन्द्-संस्कृति का, पर वे सब ऋपनी प्रांतीय संस्कृति का व्यक्तित्व लिए होंगे, श्रीर प्रत्येक में श्रपनी संस्कृति के चरम विकास के लिए पूरी सुविधाएं होंगी। जिस दिन हम सांस्कृतिक विविधता के साथ राजनैतिक एकता के सामंजस्य की स्थापना कर लेंगे, हमारी बहुत सी समस्याएं श्रपने श्राप सुलभ जाएंगी ।

संघ-शासन के श्राधार-तत्त्व

यह सामझस्य संघ-शासन के अन्तर्गत ही संभव है। संघ-शासन राजनीति के इतिहास में एक नया प्रयोग है, पर वह अपने छोटे से इतिहास में कई वड़ी-वड़ी समरयाओं को सुलमाने में सफल हुआ है। सच तो यह है कि संघ-शासन का विकास ही उन परिस्थितियों में हुआ है, जो आज हमारे देश में मोजूद हैं। एक और तो कई राजनैतिक इकाइयां रक्ता-सम्बंधी, राजनैतिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण मिल-जुल कर रहना चाहती हैं, और दूसरी और वह अपनी स्वतन्त्र सांस्कृतिक सत्ता को खोने के लिए भी उद्यत नहीं होती। संघ-शासन के निर्माण में जो प्रवृत्तियां काम करती हैं, उनका उल्लेख इस प्रकार किया जाता है—(१) राष्ट्रीय एकता का एक आध्यात्मिक आदर्श, (२) सामान्य आर्थिक स्वत्वों के विकास व सामान्य समस्याओं को मिल-जुल कर सुलमा लेने की तत्परता और (३) रक्ता और अन्तर्राष्ट्रीय साख की चिन्ता। प्रसिद्ध विधानशास्त्री डाइसी ने संघ-शासन की सफलता के लिए दो शर्तों को आवश्यक माना है—एक तो यह कि वे सब राज्य जो संघ-वद्ध होना चाहते हों भौगोलिक,।ऐति-हासिक, जातिगत आदि दृष्टियों से एक दूसरे के इतना निकट हों कि उनकी जनता के लिए एक सामान्य राष्ट्रीयता की अनुभृति सम्भव हो सके, और दूसरे,

इन राज्यों के निवासियों में अपनी स्वतन्त्र सत्ता के सम्बन्ध में भी प्रा वोध हो। संघ-शासन, इस प्रकार, दो परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों के समन्वय की दिशा में एक प्रयत्न है—उसमें केन्द्रीकरण की आवश्यकता और अकेन्द्रीकरण की अनिवार्यता दोनों एक-सी प्रवल होनी चाहिएं। संघ-शासन में एक ओर तो वे सब आवश्यकताएं प्री हो जाती हैं जिनकी किसी भी जन-समूह को एक रखने के लिए आवश्यकता होती है, और दूसरी ओर संघ में शामिल होने वाली इकाइयों को आंतरिक शासन में सम्पूर्ण स्वतंत्रता और अपनी संस्कृति के विकास के लिए सम्पूर्ण सुविधाएं प्राप्त रहती हैं। एक ऐसे देश में जहां अकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियां प्रवल हों, संघ-शासन ही एक सशक्त केन्द्र की स्थापना करने में सफल होता है।

संघ-शासन के विरुद्ध वहुत-सी वातें कही जाती हैं। विधान-वेत्तात्रों का कहना है कि ऋधिक-से-ऋधिक ऋनुकृत वातावरण में भी संघ-शासन जटिल-वास्रों स्रीर पेचीदागयों, कानृती भगड़ों स्रीर स्रराजकता से मुक्त नहीं रखा जा सकता । क़ानृन को ग्रमल में लाने के संबंध में तो वह शासन-तन्त्रों में सबसे निःशक्त माना जाता है। प्रसिद्ध क़ानून-वेत्ता जे० सी० मॉर्गन के शब्दों में "यदि हम एक इसी वात को ले लें कि संघ-शासन में 'त्रान्तरिक' सार्वभौमता, क्तानन श्रीर शासन दोनों चेत्रों में, केन्द्रीय शासन श्रीर उससे संबद्ध 'राज्यों' श्रथवा प्रान्तों में वंट जाती है, हम श्रासानी से समफ सकेंगे कि उसमें प्रत्येक नागरिक को ऋपनी 'निष्ठा' दो शासन-तन्त्रों को देना होती है ऋौर धर्म-पुस्तकों में दिए गए इस सिद्धान्त की सचाई कि कोई मतुष्य दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता सब संघबद समाजों के राजनैतिक इतिहास में मोटे श्रचरों में लिखी हुई है।" एक श्रास्ट्रेलियन लेखक, कैनेवे, का कहना है— "संघ-शासन की सबसे बड़ी ख़राबी यह है कि उसमें राष्ट्रीय सरकार के प्रति राजभिक्त की भावना बहुत निर्वल पढ़ जाती है।" उनका मत है कि छास्ट्रेलिया में संघ-शासन की स्थापना का परिखाम अच्छा नहीं हुन्त्रा, स्त्रौर स्त्रमरीका के संयुक्त-राज्य में भी क़ानृत के प्रति अवशा की भावना, जो पिछ्ले दपों में यहत बढ़ती जा रही है, इस दैध राजनिष्टा के परिणाम स्वरूप ही इतनी प्रवल हो सकी है।

भारतवर्ष में संघ-शासन की स्थापना के विरुद्ध तो ह्यौर भी बहुत-सी वार्ते कही जाती हैं। यह कहा जाता है कि पिछने वार्गे में हिंदुस्तान में जो भी प्रगति हुई है वह इस कारण कि हमारे यहां एक सशक्त वेन्द्रीमृत शासन विद्यमान था। उसके ध्रभाव में राष्ट्रीयता की भावना का दिवास पाना नासंभव

ही होता। एक सशक्त केन्द्रीभूत-शासन की स्थापना का ही यह परिणाम हुआ कि देश में एकता की भावना फैली, ग्रीर एक ग्राखिल-ग्राखण्ड-ग्राविभाज्य भारतवर्ष की कल्पना ने जन्म लिया । यह भी कहा जाता है कि अकेन्द्रीकरण की भावना भारतीय इतिहास की मुख्य प्रचृत्ति श्रौर प्रधान शाप रहे हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में पिछले १५० वर्षों में इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखा जा सका है, ग्रौर एक विरोधी कम की स्थापना की जा सकी है। हमें उस कम को श्रपनी चरम सीमा तक ले जाना है। श्रगले शासन-विधान के पीछे केन्द्रीकरण की भावना प्रमुख होनी चाहिये। अपने इतिहास के इस नाजुक अवसर पर यदि हमने इस प्रवृत्ति को रोका, श्रीर श्रकेन्द्रीकरणकी भावनाश्रों को:प्रोत्साहन दिया, तो हमारे देश में फिर वही अराजकता फैल जाएगी, जो अंग्रेज़ी शासन की स्थापना के पहिले थी। देश का विस्तार, संस्कृतियों की विविधता, त्रार्थिक त्रावश्यकताएं, प्रांतीयता के भाव के प्रवल होजाने का ख़तरा, सांप्रदायिक वैमनस्य के बहुने का हर, ये सब बातें ऐसी हैं जो एक सशक्त केन्द्रीय शासन की ग्रानिवार्यता की ग्रोर संकेत करती हैं। श्रांतिम, श्रीर सबसे बड़ा तर्क जो हमारे देश में संघ-शासन की स्थापना के विरुद्ध दिया जाता है, वह यह है कि संघ-शासन की कल्पना हमारे इतिहास स्त्रीर परम्परास्त्रों के विरुद्ध जाती है। जैसा कि लॉर्ड फ़िलीमोर ने, १६ जून, १६३५ के हाउस ऋॉफ़ लॉर्डस के ऋपने आष्या में कहा, ''क्या वे लोग (जो संघ-शासन का समर्थन कर रहे हैं) भारतवर्ष के लंबे इतिहास में कहीं भी संघवद होने की प्रवृत्ति पाते हैं ? क्या वे सोच सकते हैं कि जटिल प्रद्धतियों द्वारा चुनी गई धारा-सभात्रों त्रौर गवर्नर जनरल-के विशेषाधिकारों की यह भूल-भुलैयां भारतीय परिस्थितियों में पांच वर्ष भी टिक सकेंगी !" संघ-शासन निःसन्देह एक जटिल शासन-तंत्र है, ग्रौर उसकी यह जटिलता ग्रौर मेचीदगी, वैधानिक नियंत्रगों श्रीर संतुलन का प्राधान्य, तत्ता के बंटवारे की कठिनाइयां, ये सब तथ्य उसके विरुद्ध बार-बार दोहराए जाते हैं। यह कहा जाता है कि यदि और कोई कारण उसकी सफलता के मार्ग में वाधक नहीं हुआ तो उसकी यह पेचीदगी ही उसे खत्म कर देगी।

हमारे देश में संघ-शासन की स्थापना के विरुद्ध प्रधानतः ये तीन बातें कही जाती हैं---

- (१) संघ-शासन भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में बाधा उपस्थित करेगा।
- (२) वह ब्रिटिश भारत व देशी राज्य दोनों को एक साथ समन्वित करने के अपने प्रयत्न में दोनों के वैधानिक विकास में स्कावट पैदा कर देगा।

:(३) उससे स्वतंत्रता श्रीर प्रजातंत्र के समुचित विकास में भी बाधा पड़ेगी:।

१६३५ के संघ-शासन का त्रायोजन तो मानो इन तीन वादों को कियात्मक रूप देने के लिए ही किया गया था। उससे राष्ट्रीयता की भावना के ऋवरुद्ध होने ऋौर प्रांतीयता की भावना के विकसित होने की पूरी संभावना थी। उसमें देशी राज्यों का उपयोग ब्रिटिश भारत के वैधानिक विकास के मार्ग में रुकावट डालने के लिए किया गया था। यह भी निश्चित है कि यदि उसे स्रमल में लाया गया होता तो उससे भारतीय स्वतन्त्रता श्रौर प्रजातन्त्र दोनों को वड़ी चित पहुंचती। इसी वात को लच्य में रखते हुए लॉर्ड फ़िलीमोर ने हाउस त्रॉफ़ लॉर्डस के त्रपने उपर्युक्त भाषण में पूछा था, "क्या संघ शासन के विना स्राप श्राज़ादी की कल्पना कर ही नहीं सकते ? भारतवर्षके समस्त वैधानिक विकास को संकुचित-सीमाबद्ध दिशा में मोड़ देने के लिए क्यों सरकार इतनी व्यप्र है ? क्या उसका कारण यह नहीं है कि वह डरती है कि भारतीय राजनैतिक विकास को यदि प्राकृतिक रूप से बढ़ने दिया गया तो वह उसके वेगका सामना नहीं कर सकेगी?" परन्त. इस प्रकार की स्त्रालोचनास्रों का लच्य प्रधानतः १६३५का शासन-विधान था। १६३५ की शासन-योजना को ही संघ-शासन की सीमा नहीं माना जा सकता । उसे तो संघ-शासन का नाम देना भी एक महत्त्वपूर्ण वैधानिक प्रयोग का श्रपमान करना है। जे॰सी॰ मॉर्गन ने १६३५के शासन-विधानके संबंध में लिखा था-''द्सरे सभी संघ-शासनों में क़ानून वनाने वाली शक्ति ऋधिक-से-ऋधिक दो भागों में बंटी रहती है-एक स्त्रोर तो केन्द्रीय धारासभाएं इस काम को करती हैं, ऋौर दूसरी ऋोर राज्यों ऋथवा प्रांतों की धारासभान्नों पर उसका उत्तरदायिल रहता है, सत्ता का बंटवारा शासन को निर्वल तो बनाता ही है, पर उसे जितने क्रिधिक भागों में बांटा जाए, शासन की निर्वलता उतनी ही मात्रा में बढ जाती है । ह्वाइट पेपर द्वारा प्रस्तावित बंटवारा तहस-नहस की सीमा का स्पर्श करता है । , उसमें सत्ता दो भागों में नहीं, कम-से-कम ६ भागों में, बांटी गई है। उन प्रस्तावों के श्रवसार, प्रत्येक भारतीय को ६, वल्कि ७, विभिन्न, श्रीर प्रायः संघर्ष-शील, क्वानून बनाने वाली शक्तियों के श्रन्तर्गत रहना होगा, जिनमें से तीन तो गवर्नर-जनरल के बहुमुखी व्यक्तित्त्व में ही केन्द्रित होंगी, जिसका परिस्माम यह होगा कि गवर्नर-जनरल को अपने मंत्रियों से सहमत होने में तो कटिनाई पट्टेंगी ही, स्वयं श्रपने से भी सहमत हो पाना उनके लिए सदा संभव नहीं हो सदेगा।" यहां हमें यह बात स्वष्ट समभ लेनी चाहिए कि अपने देश के संघ-शासन की योजना हमें १६३५ के एक्ट के अनुसार नहीं बनाना है। उससे दिल्कुल स्वतन्त्र, श्रीर वहुत श्रंशों में विपरीत, सिद्धांतों पर ही हम एक सराल भारतीय संघ-शासन का निर्माण कर सकते हैं।

संघ-शासन की स्थापना के पत्त में ये तीन वातें उपस्थित की जा सकती हैं— (१) हिंदुस्तान की विभिन्न समस्याय्यों का एक मात्र निदान हम संघ-शासन में ही पा सकते हैं।

- (२) वैधानिक स्थिति कुछ भी हो, देशी राज्यों की राजनीति पर ब्रिटिश भारत की राजनैतिक विचार-धाराख्रों का प्रभाव पड़ना ख्रवश्यंभावी है।
- (३) संघ-शासन की हमारी प्रारम्भिक योजना यदि दोपपूर्ण भी हुई तो वैधानिक श्रदालतों द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्णयों से उसके सुधरते जाने की श्राशा है।

भारतीय परिस्थितियां में संघ-शासन ही एकमात्र रास्ता है, यह वात तो हमारे इतिहास की समस्त सांस्कृतिक ग्राधार-भृमि-केन्द्रीकरण ग्रौर ग्रकेन्द्रीकरण के एक अनोखे संतुलन—से ही स्पष्ट होजाती है। सर मॉरिस ग्वायर के शब्दों में, संघ-शासन ''एक ऐसा आयोजन है जो एक वहें पैराए पर संसार के दूसरे भागों में एकता व विविधता के बीच सामंजस्य स्थापित करने, ग्रीर स्थानीय निष्ठा के दावे को एक ऐसे प्रजातन्त्रात्मक केन्द्रीय शासन की आवश्यकता से, जिसमें विभाजन श्रीर श्रकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों को रोक रखने की शक्ति हो, संवद करने में सबसे श्राधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ है।" जो प्रयोग 'एक वड़े पैराए पर, संसार के दूसरे भागों में सफल हुआ है, वह हमारी वैसी ही परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकेगा, यह मानने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। देशी राज्यों का संघ-शासन में ले ब्राना भी, एक लंबे ब्रासें में उपयोगी ही सिद्ध होगा। व्रिटिश-भारत ग्रौर देशी राज्यों के वीच ग्राज जो राजनैतिक दीवारें े हैं वे कृतिम हैं। उनकी समकत्त वैचारिक ग्रौर सांस्कृतिक दीवारें कहीं हैं ही नहीं। , संघ-शासन में देशी राज्यों का शामिल होना ग्रारंभ में कुछ कठिनाइयां तो उपस्थित करेगा ही, पर उससे देशी राज्योंकी राजनैतिक जागृति ऋषिक गतिशील वनेगी, श्रीर हमारे सामृहिक राजनैतिक विकास में एक वोभ्ना वनने के स्थान पर देशी राज्य उसमें सहायक वन सकेंगे। सर तेज वहादुर समू के शन्दों में, "संघ-शासन की केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में एक सामान्य कार्य-चेत्र में ब्रिटिश-भारत ग्रौर देशी राज्यों के मिल-जुल कर काम करने का एक स्पष्ट परिणाम तो यह होगा कि देशी राज्यों के आज के स्वेच्छाचारी शासन से एक ऐसे वैधानिक शासन में, जिसमें जनता के ऋधिकारों की परिभाषा व गराना की गई हो, और उन्हें पूरा संरक्तरण मिला हो, परिवर्तित होने का मार्ग सरल हो जायगा।" शासन के पत्त में यह भी एक प्रवल दलील है। त्रांत में, यह भी एक निविवाद वथ्य तो है ही कि संघ-शासन एक जीवित शासन-तंत्र है। हम संयुक्त-राज्य

श्रमरीका का श्रादर्श लें, श्रथवा कनाडा श्रीर श्रास्ट्रेलिया के संघ-शासनों का उदाहरण, यह स्वष्ट है कि प्रत्येक देश में संघ-शासन की श्रमनी एक प्रवृत्ति होती है, उसके विकास का एक निश्चित मार्ग श्रपने-श्राप वन जाता है, श्रीर समय श्रीर परिस्थितियों की श्रावश्यकता के श्रनुसार उसकी सत्ता के विभाजन की ऊपर से दीखने वाली कठोर वाह्य-रेखाश्रों में धीरे-धीरे परिवर्त्तन होता रहता है।

इस संबंध में दो ऋौर बातें स्पष्ट कर देना ऋावश्यक हैं। एक वो यह कि अन्य शासन-तन्त्रों की तुलना में संघ-शासन के कुछ कम शिक्तशाली होने की धारणा वर्त्तमान महायुद्ध में निर्मुल सिद्ध हो चुकी है। यह कल्यना कि सार्व-भौम सत्ता के दो भागों में बंट जाने से शासन में किसी प्रकार की निर्वलता त्रा जाएगी एक भ्रामक कल्यना है। इस युद्ध में जिन दो राष्ट्रों को सबसे अधिक सफलता मिली, वे हैं अमरीका और रूस, और इन दोनों के शासन-सूत्रों का संगठन संघ-शासन के सिद्धान्त के अनुसार हुआ है। इसका कारण यह है कि संघ-शासन की कार्य-पद्धति साधारण रूप से एक प्रकार की होती है, परन्तु युद्ध के दिनों में उसका रूप विल्कुल बदल जाता है । साधारणुवः केन्द्रीय शासन का कार्य-चोत्र बहुत सीमित रहता है, पर विशोष परिस्थितियों में, बड़े स्रार्थिक संकट स्रथवा युद्ध के स्रवसर पर, वह राष्ट्रीय जीवन के सभी स्रावश्यक श्रंगों को श्रयनी परिधि में ले श्राता है। संघ-शासन की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि वह अनेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों और राष्ट्रीय सुरत्ता के प्रश्न के बीच एक सामंजस्य की स्थापना करता है। उसे राष्ट्रीय शक्ति को चीए। बनाने का कारण मानना ऐतिहासिक सत्य के विरुद्ध जाना है। इसी प्रकार की एक दूसरी भ्रामक कल्पना, जो साधारणतः प्रचलित है, यह है कि संघ-शासन हमारी ऐतिहासिक परम्पराश्रों के विरुद्ध जाता है। सच तो यह है कि हमारा विगत इतिहास श्रीर वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियां दोनों ही संघ-शासन की श्राद-श्यकता को पुष्ट करते हैं।

हिन्दुस्तान में संध-शासन की सभी श्रावश्यक शर्ते मौजूद हैं। उसके सभी प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से संबद्ध हैं। उन सवकी सामान्य ऐतिहा- सिक परम्पराएं हैं, श्रौर सांस्कृतिक कृतियों की एक लम्बा सामान्य इतिहास है। उनकी श्राधिक श्रावश्यकताएं सामान्य हैं। श्राभ्यात्मिक श्रौर राष्ट्रीय एकता की सामान्य श्राकांक्ता है। इसके साथ ही श्रपना व्यक्तित्व श्रौर श्रपनी स्ववन्त्रता को बनाए रखने की वेचैनी भी है। मुस्लिम-बहुसंस्वक प्रांतों में इस देचैनी ने वड़ा उम रूप से लिया है, पर श्रन्य प्रांतों में भी वह मौजूद है ही। श्राज वी

संघ-शासन की स्थापना के पत्त में ये तीन वार्ते उपस्थित की जा सकती हैं— (१) हिंदुस्तान की विभिन्न समस्याओं का एक मात्र निदान हम संघ-शासन में

ही पा सकते हैं।

(२) वैधानिक स्थिति कुछ भी हो, देशी राज्यों की राजनीति पर विटिश भारत की राजनैतिक विचार-धाराख्यों का प्रभाव पढ़ना ख्रवश्यंभावी है।

(३) संघ-शासन की हमारी प्रारम्भिक योजना यदि दोपपूर्ण भी हुई तो वैधानिक श्रदालतों द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्णयों से उसके सुधरते जाने की श्राशा है।

भारतीय परिस्थितियां में संघ-शासन ही एकमात्र रास्ता है, यह बात तो हमारे इतिहास की समस्त सांस्कृतिक ग्राधार-भूमि-केन्द्रीकरण ग्रौर ग्रकेन्द्रीकरण के एक ग्रनोखे संतुलन—से ही स्पष्ट होजाती है। सर मॉरिस ग्वायर के शब्दों में, संघ-शासन "एक ऐसा ऋायोजन है जो एक वहें पैराए पर संसार के दूसरे भागों में एकता व विविधता के बीच सामंजस्य स्यापित करने, ग्रीर स्थानीय निष्ठा के दावे को एक ऐसे प्रजातन्त्रात्मक केन्द्रीय शासन की आवश्यकता से, जिसमें विभाजन श्रीर श्रकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों को रोक रखने की शक्ति हो, संत्रद करने में सबसे अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ है।" जो प्रयोग 'एक वड़े पैराए पर, संसार के दूसरे भागों में सफल हुआ है, वह हमारी वैसी ही परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकेगा, यह मानने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। देशी राज्यों का संघ-शासन में ले ब्राना भी, एक लंबे ब्रासें में उपयोगी ही सिद्ध होगा । ब्रिटिश-भारत ग्रौर देशी राज्यों के वीच ग्राज जो राजनैतिक दीवारें े हैं वे कृत्रिम हैं। उनकी समकत्त वैचारिक और सांस्कृतिक दीवारें कहीं हैं ही नहीं। , संघ-शासन में देशी राज्यों का शामिल होना आरंभ में कुछ कठिनाइयां तो उपस्थित करेगा ही, पर उससे देशी राज्योंकी राजनैतिक जागृति ऋधिक गतिशील वनेगी, श्रीर हमारे सामृहिक राजनैतिक विकास में एक वोभ्ता वनने के स्थान पर देशी राज्य उसमें सहायक वन सकेंगे। सर तेज वहादुर समु के शब्दों में, "संघ-शासन की केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में एक सामान्य कार्य-केंत्र में ब्रिटिश-भारत ग्रीर देशी राज्यों के मिल-जुल कर काम करने का एक स्पष्ट परिणाम तो यह होगा कि देशी राज्यों के ब्राज के खेच्छाचारी शासन से एक ऐसे वैधानिक शासन में, जिसमें जनता के अधिकारों की परिभाषा व गणना की गई हो, और उन्हें पूरा संरक्षण मिला हो, परिवर्त्तित होने का मार्ग सरल हो जायगा ।" संघ-शासन के पत्त में यह भी एक प्रवल दलील है। श्रंत में, यह भी एक निर्विवाद वय्य तो है ही कि संघ-शासन एक जीवित शासन-तंत्र है। हम संयुक्त-राज्य

श्रमरीका का श्रादर्श लें, श्रथवा कनाडा श्रीर श्रास्ट्रेलिया के संघ-शासनों का उदाहरण, यह स्वष्ट है कि प्रत्येक देश में संघ-शासन की श्रपनी एक प्रवृत्ति होती है, उसके विकास का एक निश्चित मार्ग श्रपने-श्राप वन जाता है, श्रीर समय श्रीर परिस्थितियों की श्रावश्यकता के श्रनुसार उसकी सत्ता के विभाजन की ऊपर से दीखने वाली कठोर वाह्य-रेखाश्रों में धीरे-धीरे परिवर्त्तन होता रहता है।

इस संबंध में दो ऋौर वार्ते स्पष्ट कर देना ऋावश्यक हैं। एक तो यह कि श्रन्य शासन-तन्त्रों की तुलना में संघ-शासन के कुछ कम शिक्तशाली होने की धारणा वर्त्तमान महायुद्ध में निर्मुल सिद्ध हो चुकी है। यह कल्पना कि सार्व-भीम सत्ता के दो भागों में बंट जाने से शासन में किसी प्रकार की निर्वलता त्रा जाएगी एक भ्रामक कल्पना है। इस युद्ध में जिन दो राष्ट्रों को सबसे अधिक सफलता मिली, वे हैं अमरीका और रूस, और इन दोनों के शासन-सूत्रों का संगठन संघ-शासन के सिद्धान्त के अनुसार हुआ है। इसका कारण यह है कि संघ-शासन की कार्य-पद्धति साधारण रूप से एक प्रकार की होती है, परन्तु युद्ध के दिनों में उसका रूप विल्कुल बदल जाता है। साधारणतः केन्द्रीय शासन का कार्य-च्लेत्र बहुत सीमित रहता है, पर विशेष परिस्थितियों में, बड़े श्रार्थिक संकट श्रथवा युद्ध के श्रवसर पर, वह राष्ट्रीय जीवन के सभी श्रावश्यक अंगों को अपनी परिधि में ले आता है। संघ-शासन की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि वह अनेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों और राष्ट्रीय सुरत्ता के प्रश्न के बीच एक सामंजस्य की स्थापना करता है। उसे राष्ट्रीय शक्ति को चीण बनाने का कारण मानना ऐतिहासिक सत्य के विरुद्ध जाना है। इसी प्रकार की एक दूसरी भ्रामक कल्पना, जो साधारणतः प्रचलित है, यह है कि संघ-शासन हमारी ऐतिहासिक परम्पराश्चों के विरुद्ध जाता है। सच तो यह है कि हमारा विगत इतिहास श्रीर वर्त्तमान राजनैतिक परिस्थितियां दोनों ही संघ-शासन की आव-श्यकता को पृष्ट करते हैं।

हिन्दुस्तान में संघ-शासन की सभी त्रावश्यक शर्तें मौजूद हैं। उसके सभी प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से संबद्ध हैं। उन सबकी सामान्य ऐतिहा- सिक परम्पराएं हैं, त्रौर सांस्कृतिक कृतियों का एक लम्बा सामान्य इतिहास है। उनकी त्रार्थिक त्रावश्यकताएं सामान्य हैं। त्राष्यात्मिक त्रौर राष्ट्रीय एकता की सामान्य त्राकांचा है। इसके साथ ही त्रप्रना व्यक्तित्व त्रौर त्रप्रनी स्वतन्त्रता को बनाए रखने की वेचैनी भी है। मुस्लिम-बहुसंख्यक प्रांतों में इस वेचैनी ने वड़ा उम्र रूप ले लिया है, पर त्रान्य प्रांतों में भी वह मौजूद है ही। त्राज की

इन परिस्थितियों में संघ-शासन हमारे लिए अनिवार्य वन गया है। पर उसमें कोई ऐसी वात नहीं है जो हमारी ऐतिहासिक परम्पराओं के विरुद्ध जाती हो। संघ-शासन की वर्तमान कल्पना तो संसार की राजनीति में ही। एक नवीन प्रयोग है, पर कुछ शिथिल प्रकार के संघ समय-समय पर हमारे देश में वनते रहे हैं, विलक यह कहना भी अत्युक्ति न होगा कि हमारे वहुत से साम्राज्यों में भी वहुत अंशों तक साम्राज्यत्व कम और राज्य-संघ की भावना अधिक थी। प्रत्येक साम्राज्य के अन्तर्गत प्रायः वहुत से स्वतन्त्र राज्य रहते थे, और अनित्रिक शासन में इन राज्यों को प्रायः संपूर्ण स्वतन्त्रता मिली होती थी। यह कथन मौर्य अथवा गुप्त साम्राज्यों के लिए भी उतना ही सच है जितना मुग़ल-साम्राज्य के लिए। मुग़ल-साम्राज्य के बाद मराठा-शक्ति का संगठन जिन सिद्धान्तों पर हुआ उनमें और संघ-शासन के आधार-भूत सिद्धान्तों में बहुत ही अधिक साहश्य है। पूना की केन्द्रीय सरकार और होल्कर, सिंधिया, भोंसले और गायकवाङ की प्रान्तीय सरकारों के आपसी सम्बन्ध बहुत कुछ इसी आधार पर वने थे: उन्हें संघवद्ध रखने के पीछे मराठा-पद-पादशाही की भावना वैसी ही प्रवल थी, जैसी आज के संघ-शासन में राष्ट्रीयता की भावना होगी।

श्रन्य संघ-शासन : स्विज्रलैएड श्रीर रूस

संघ-शासन के ब्राधार पर प्रस्थापित भारतीय प्रजातन्त्र का मान-चित्र खींचने के पहिले हम यह देखने का प्रयत्न करें कि संसार के अन्य देशों ने इस समस्या को कैसे सुलभाया है। इस अध्ययन में मैं संसार के केवल दो देशों का उदाहरण पाठक के सामनें रखना चाहँगा, जिनमें भारतीय परिस्थितियों से बहुत ऋधिक समानता है। वे हैं—स्विज्ञरलैएड श्लीर सोवियट रूस । स्विज्रलैएड में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो जातिगत स्त्रीर सांस्कृतिक एकता के राष्ट्रीय सिद्धान्तों के विल्कुल विरुद्ध जाती हैं। देश की थोड़ी-सी स्नाबादी तीन विभिन्न भाषा-भाषियों में बंटी है; इसके अतिरिक्त, कई प्रदेशों में स्थानीय बोलियों का व्यवहार भी प्रचलित है। इन विभिन्न भाषा-भाषियों की संस्कृतियाँ भी एक दूसरी से जुदा हैं, ग्रौर इससे भी ग्राधिक महत्त्वपूर्ण ग्रौर गम्भीर बात यह है कि भौगोलिक स्थिति भी भाषा और संस्कृति की इस विभिन्नता को पुष्ट करती है। स्विजरलैएड के विभिन्न कैन्टन स्पष्टतः विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में बंटे हुए हैं : टिसिनो विल्कुल ही इटालियन-भाषा-भाषी प्रदेश है; जिनीवा, वॉड, न्यूरीटल, वैले, शुद्ध फांसीसी हैं; अन्य कई प्रदेश संपूर्णतः जर्मन हैं। इन प्रदेशों के निवासियों के लगभग उतने ही निकट सांस्कृतिक सम्पर्क इटली, फ्रांस श्रीर जर्मनी की जनता से हैं, जितने श्राप्त में । इनमें तीव धार्मिक मतभेद भी

हैं ही । कुछ प्रदेश प्रधानतः प्रोटेस्टैएट हैं, अन्य प्रधानतः रोमन कैथोलिक । स्विज्ञरलैएड के इतिहास में धार्मिक संघ्यों की भी कमी नहीं रही, और धार्मिक भेद भाव की अतिकिया आज भी वहां के राजनैतिक दलों के संगठन पर विल्कुल ही स्पष्ट है । पर, इन विविधताओं और मतभेदों के बावजूद भी, स्विज्ञरलैएड की जनता राष्ट्रीय एकता और देश भिक्त की ऐसी ज्वलंत भावना का विकास कर सकी है जिसकी समानता संसार के अन्य किसी देश में नहीं है ।

लार्ड ब्राइस के कथनानुसार, "'त्राधनिक प्रजातन्त्रों में जो थोड़े से सच्चे प्रजातन्त्र हैं, उनमें स्विज़रलैएड का स्थान सर्व प्रथम है। उसमें किसी भी ऋन्य देश की तुलना में प्रजातन्त्रात्मक सिद्धांतों पर स्थापित संस्थात्रों की विविधता कहीं ऋधिक है। ' ' सबसे बड़ा सबक्त जो स्विज़रलैएड हमें सिखाता है, वह यह है कि किस प्रकार ऐतिहासिक परम्पराएं भ्रौर राजनैतिक संस्थाएं मिल कर साधारण न्यक्ति में, एक भ्रम्तपूर्व रूप से, उन सव गुर्णों की सृष्टि कर देती हैं जो उसे एक ग्रन्छा नागरिक बना देने के लिए ग्रावश्यक हैं—कुशाग्र बुद्धि, संयम, समभदारी श्रीर समाज के प्रति कर्त्तव्य की भावना । स्विज़रलैपड की इसमें सफलता मिली है, इसी कारण वहां प्रजातन्त्र संसार के अन्य किसी भी देश की तुलना में कहीं ऋधिक प्रजातन्त्रात्मक है।" आनील्ड जुर्कर ने इसी सम्बन्ध में लिखा है-''धार्मिक त्रौर भाषा-सम्बन्धी विभिन्नतात्रीं, त्रौर -स्रान्तरिक मतभेदों के वावजृद भी, प्रत्येक युग में स्विज़रलैएड की क़ानूनी स्रोर नैतिक एकता ऋधिक सशक्त वनी है। ऋाज यूरोप में कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है, जिसमें राष्ट्रीय एकता श्रीर देशभक्ति की भावना उतनी गहरी हो जितनी स्विज़र-लैएड में । एक ऐसी दुनियां में, जो जाति श्रीर भाषा के श्राधार पर राजनैतिक ''त्रात्मनिर्ण्य' के त्राधिकार को वार-वार दोहराए जाने से थक गई हो, स्विजरलैएड इस बात का एक शानदार उदाहरण हमारे सामने रखता है कि इस सिद्धान्त के खुले विरोध में किस प्रकार राज्य की भावना श्रीर राष्ट्रीय देशभक्ति एक साथ प्रश्रय पा सकते हैं।"

यह सब कैसे संभव हुन्ना ? इसका एक ही उत्तर हो सकता है, श्रीर वह है संघ-शासन ! स्विज्ञरलैण्ड में सार्वभौम सत्ता के वंटवारे पर एक सरसरी सी हिए डाल लें । शासन की मूलभृत सत्ता केन्द्रीय सरकार के हाथों में है । उसके नियंत्रण में जो प्रमुख विभाग हैं, वे हैं विदेशी नीति श्रीर शान्ति श्रीर युद्ध के प्रश्नों संबंधी, इसके श्रितिरिक्त, जो ऐसे श्रार्थिक श्रीर व्यापार संबंधी प्रश्न हैं ।

१—ब्राह्स : Modern Democracies, भाग १, पृ० ३१७। रे—Governments of Continental Europe, पृ० ६८३।

जिनका संबंध सारे देश से है, जैसे मुद्रा, ग्राने-जाने के साधन, व्यापार, वर्जन श्रीर तौल, प्राकृतिक साधनों का संरच्चण श्रादि, वे भी केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में ही हैं। यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार का अधिकार-चेत्र धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। उसने टेलीफ़ोन ग्रीर वायरलैस के साधनों, ग्रीर रेल के शासन, को ग्रपने ग्रन्तर्गत ले लिया है। उसने ग्रपनी ग्राय की यहाने के उद्देश्य से कई नए टैक्सों की स्थापना कर ली है। पर इसके साथ ही विभिन्न प्रदेश (Cantons) ग्रपनी सार्वभौमता भी संपूर्ण रूप सें सुरिच्चित रख सके हैं। शासन के कुछ त्र्यावश्यक तत्त्व, जैसे शांति ग्रीर सुन्यवस्था की रचा, सार्वजिनक इमारतों श्रीर सङ्कों श्रादि का निर्माण-कार्य, चुनाव श्रीर स्थानीय शासन का प्रवंध त्रादि, त्राज भी संपूर्णतः प्रादेशिक सरकारों के त्राधीन ही हैं। केन्द्रीय सरकार के कार्य-चेत्र में भी विभिन्न प्रदेशों का प्रमुख हाथ रहता है। उदाहरण के लिए, क़ानूनों का निर्माण यद्यपि केन्द्रीय शासन के द्वारा होता है, पर उन्हें कार्य-रूप में परिगत करने का दायित्व प्रदेशों को है। इसी प्रकार केन्द्रीय शासन के सेना-संबंधी नियम-अनुशासन आदि का पालन भी प्रादेशिक शासन द्वारा ही किया जाता है, श्रीर वही केन्द्रीय सेना के लिए रंगरूट भरती करने श्रीर उन्हें सैन्य-शिद्धा देने का प्रबंध करते हैं। विधान के संशोधन में भी प्रदेशों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। केन्द्रीय शासन की शक्ति स्रीर संबद्ध इकाइयों की स्वर्तन्त्रता के बीच इस संपूर्ण सामंजस्य के कारण ही स्विज़रलैएड को त्राज संसार के देशों में इतना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है।

यहां यह कहा जा सकता है कि स्विजरलैएड तो एक छोटा-सा देश है, श्रीर उसका उदाहरण हिंदुस्तान जैसे महाद्वीप के सामने रखना ठीक नहीं है। इसलिए हम सोवियट रूस का उदाहरण ले सकते हैं। श्राल्पसंख्यक वर्गों की समस्या श्रीर विभिन्न प्रदेशों द्वारा स्वतंत्रता की इच्छा हिंदुस्तान की श्रपेत्ता रूस में संभवतः कहीं श्रिषक जटिल श्रीर तीन है। रूस में लगभग १८५ विभिन्न राष्ट्रीयताएं हैं, जो १४७ विभिन्न भाषाश्रों श्रीर बोलियों का प्रयोग करती हैं, परन्तु वहां भी ये सब राष्ट्र श्रीर राष्ट्रीयताएं, जाति श्रीर धर्म, समाज श्रीर संप्रदाय संघ शासन द्वारा एक सूत्र में बांध दिए गये हैं। वर्तमान महायुद्ध में रूस का जो शानदार भाग रहा है, उससे यह धारणा तो सदा के लिए खत्म हो जानी चाहिए कि संघ-शासन किसी प्रकार की राष्ट्रीय शक्त के मार्ग में वाधक सिद्ध होता है। रूस में प्रत्येक इकाई का श्रपना एक शासन-विधान है, श्रपनी धारा-समाएं श्रीर श्रपनी कार्यकारिणी-समितियां हैं, श्रपनी श्रदालतें श्रीर श्रपना कोष है। उनकी सीमाएं विना उनकी स्वीकृति के नहीं बदली जा सकतीं। संघ-

प्रवल है, कि उन्हें प्रत्येक संबं-शासन में शामिल होने वाली इकाइयों के नैसर्गिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता ।

इस संबंध में संघ-शासन की मूल प्रवृत्ति को एक बार फिर स्पष्ट कर देना त्रावश्यक है। वात साफ़ त्रौर सीधी होनी चाहिए। दुनियां के सभी देशों में संघ-शासन की प्रवृत्ति केन्द्रीय शासन के ऋधिकारों को बढ़ाने की ऋोर है। यदि हिंदुस्तान में संघ-शासन की स्थापना हुई तो यहां भी इस प्रवृत्ति को अनिवार्यतः प्रोत्साहन मिलेगा । इससे हमें भिभकना नहीं चाहिए। संघ-शासन (Federal) श्रौर केन्द्रीभृत (Unitary) सरकार में श्रांतर यह है कि संघ-शासन श्रकेन्द्री-करण की स्वस्थ प्रवृत्तियों को निरुत्साहित न करते हुए, उन्हें त्र्यावश्यकतानुसार वढावा देकर भी, उन सब तत्त्वों का संरत्त्रण कर लेता है जो एक सशक्त केन्द्रीय-सरकार को बनाये रखने के लिए ब्रावश्यक हैं। केन्द्रीभूत सरकार ब्राकेन्द्रीकरण की, खरुप ग्रथवा ग्रस्वस्थ, सभी प्रवृत्तियों को कुचलती हुई ग्रागे बढती रहना चाहती है, चाहे उसमें यह खतरा ही क्यों न हो कि किसी दिन अनेन्द्रीकरण के ये कुचले जाने वाले तत्त्व उसके विरुद्ध बगावत कर दें श्रीर उसकी स्थिति को ही जड़-मूल से समाप्त कर दें। संघ-शासन एक व्यवहार-कुशल शासन-तंत्र है, वह विश्व खलशील तत्त्वों को जान-बुक्त कर अपना शत्रु बनाने में विश्वास नहीं रखता, पर उसमें केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति के संरच्या पर भी पूरा ज़ोर रहता है। संघ-शासन की इस मूल-प्रवृत्ति से उसके विरोधी भली-भांति परिचित हैं, श्रीर इसी कारण एक श्रीर तो पाकिस्तान के समर्थक उसकी भर्त्सना करते हैं, श्रीर दुसरी श्रोर देश की खएड-खएड कर देने की श्रगिएत योजनाश्रों के कहरपंथी श्रंग्रेज़ें विधायकें उससे बंचे निकलना चाहतें हैं। इन दोनों दलों का मुख्य त्राक्रमण हमारे देश में एक सशक्त केन्द्र की स्थापना पर है। पर, प्रतिक्रियावादी शक्तियों के लिए जो हेय त्रीर त्रवांछित है, वही तो त्रांज हमारा प्रिय त्रीर श्रमीप्सित है। हमें केवल शब्दों की मरीचिका में भटकना तो है नहीं, हमें तो त्रपने देशें के लिए एकं महान् भेविष्य का निर्माण करना है। उसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अग्रगएय और अर्थनीति में स्वयमावलम्बी और एक महान देश का रूपं देनां है, उसके लिए शांब्दिक स्रांडम्बर से ऊपर उठना होगा। राष्ट्रीय स्रथवा सांस्कृतिक आत्म-निर्णय अथवा सार्वभौमता के आकर्षक और आमक सिद्धांतों को चुपचाप मान नहीं लेना होगा, उनका बौद्धिक विश्लेषण करना होगा, ऋौर उन्हें एक ग्रोर तो समस्त देश की ग्रावश्यकतात्रों ग्रीर दूसरी ग्रोर उसकी त्राधीरमूत इकाइयों के हिताहित से संश्लिष्ठ करना होगा। इस कारण मुक्ते यह कहने में संकोच नहीं है कि भारतीय संघ-शासन आज की भारतीय राजनीति के

प्रतिक्रियाचादी पत्त की भाव-प्रवण उद्घोषणा थ्रां को सन्तुष्ट नहीं कर सकेगा। जहां तक संघ-शासन(Federation) ख्रीर एच्य-संघ (Confederation) में चुनाव का प्रश्न है, हमारा निश्चित मत संघ-शासन को ही मिलना चाहिए। राज्य-संघ, जहां प्रत्येक सदस्य समिष्ट से ऋधिक ऋपनी सार्वभौमता के लिए चिन्तित रहता है, त्राज के युग ग्रीर उसकी जटिल ग्रावश्यकतात्रीं में एक ग्रसंबद-सी कल्पना है। कूपलैएड त्रादि भी ग्रवनी योजनात्रों को उससे कुछ ऊंचे स्तर पर ही रखते हैं, यद्यपि उनके वास्तविक रूप को समभ लेने पर उनका खोखलापन स्वष्ट होजाता है। पाकिम्तान एक देश में, जिसे भीगोलिक स्थिति, न्त्रार्थिक साधनों, रज्ञा संबंधी त्र्यावश्यकतात्रों ग्रौर सांस्कृतिक परम्परात्रों ने एक राजनैतिक इकाई बनाया है, दो संघों की स्थापना कर देना चाहुता है। ये दोनों ही मार्ग देश के वल को कम करने की दिशा में जाते हैं। संव-शासन ही एक ऐसा प्रयोग है, जो देश की शक्ति को कम नहीं करता। कई देशों के इतिहास से हमें पता लगता है कि केवल वही राज्य-संघ ग्रापने को क्वायम रख सके हैं, जिनका विकास, वाहरी दवाव ग्रथवा ग्रान्तरिक ग्रावश्यकतात्रों के कारण, संघ-शासन की दिशा में हो सका है। अन्य सभी राज्य-संघ बहुत शीघ ट्टक़र ग्रलग-म्रलग इकाइयों में वंट गए हैं। म्रमरीका का संयुक्त राज्य, कनाडा, ग्रास्ट्रेलिया, स्विज़रलैएड, सोवियट रूस, सभी का विकास इसी पद्धति से हुन्ना है, श्रीर इन सब में केन्द्रोय-शासन की शांक लगातार बढ़ती गई है।

सत्ता का वंटवारा : रक्षा और विदेशी नीति

सत्ता के बंटबारे के संबंध में, मैं समस्तता हूँ, इस सिद्धान्त पर चलना ठीक होगा कि उन अधिकारों को छोड़कर जिन्हें केन्द्रीय सरकार के हाथ में रखना अत्यन्त आवश्यक होगा, शेप सब अधिकार प्रांतीय सरकारों के हाथ में रहेंगे। इस संबंध में समू कमैटी के इस सुमाव को मान लेना चाहिए कि केन्द्रीय अधिकारों की संख्या कम-से-कम हो, और ये अधिकार मुख्यतः ऐसे हों जो विदेशों से हमारा संबंध स्थापित करते हों। मैं तो समम्तता हूँ कि समू-कमैटी ने केन्द्रीय सरकार के जो आधिकार प्रस्तावित किये हैं, उनमें भी कमी की जा सकती है। परन्तु, वे 'कम-से-कम' अधिकार क्या हों, और किस आधार पर उनका चुनाव किया जाय? इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की मूल एकता के संस्तृण की भावना में हमें वह आधार मिल सकता है। कुछ भी हो पर देश की यह मौलिक एकता विश्व खल न होने पाने, यह संघर शासन का ध्येय होना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से हिंदुस्तान के लिए इस एकता की कायम रखना ज़रूरी है ही। इस दृष्टिकीण से यह आवश्यक

शासन से अपना संबंध-विच्छेद कर लेने का भी उन्हें अधिकार है। इन राज-नैतिक इकाइयों का संगठन विभिन्न स्तरों पर किया गया है, कुछ बड़े-बड़े प्रजातन्त्र (Constituent Republics) हैं, कुछ उनसे छोटे (Autonomous Republics), कुछ, ह्मारे प्रांतों के समकत्त् (Autonomous Provinces) स्रोर कुछ राष्ट्रीय ज़िले (National Districts) भी हैं, जो अपने आंतरिक शासन में विल्कुल स्वतन्त्र हैं। परंतु इसके साथ ही केन्द्रीय-शासन को वे सब ऋधिकार प्राप्त हैं जो देश की शक्ति को वडाने के लिए आवश्यक हैं। विदेशी नीति, युद्ध और संधि, फ़ौज और जहाज़ी वेड़ा, विदेशी व्यापार, त्र्यावागमन के साधन, डाक स्रीर तार, मुद्रा, बैंक, न्याय, नागरिकता त्रादि विभाग केन्द्रीय शासन के नियंत्रण में हैं, श्रीर उसे यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह ब्रावश्यकता पड़ने पर ऐसे कानून बना सके जिनके द्वारा ज़मीन का उपयोग, प्राकृतिक साधनों का विकास, मज़द्रों की समस्या, शिद्या, सार्वजःनिक स्वास्थ्य त्र्यादि पर भी उसका मौलिक त्र्याधिकार स्थापित किया जा सके। ऋार्थिक पुनर्निर्माण की राष्ट्रीय योजनात्रों को प्रस्तावित ऋौर कार्यान्वित करने का समस्त दायिन्व उस पर है ही। स्थानीय स्वतन्त्रता के साथ एक सशक्ष केन्द्रीय सरकार के समन्वय के द्वारा ही, जो संघ-शासन का मूल-मंत्र है, सोवियट रूस आाज के विश्व में अपनी वर्त्तमान स्थिति को प्राप्त कर सका है।

(आ) प्रस्तावित संघ-शासन : अधारभूत सिद्धान्त

केवल यह निश्चय कर लेना ही कि वर्त मान भारतीय परिस्थितियों में संघ-शासन ही सबसे उपयुक्त सिद्ध हो सकता है काफ़ी नहीं है; हमें उसके आधार-भूत सिद्धान्तों का भी निर्णय करना होगा, और उसकी रूप-रेखा के संबंध में भी कुछ निश्चित विचार बनाने होंगे, संघ-शासन की एक विशेषता यह है कि उसमें केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के बीच सत्ता का बड़ा स्पष्ट बंटवारा रहता है। परन्तु, इस बंटवारे की स्पष्टता के बावजूद भी बहुत से ऐसे अधिकार होते हैं जिनके प्रयोग के सम्बन्ध में मतभेद की गुं जाइश रह जाती है। इन अव्यक्त, बंचे-खुचे अधिकारों (residuary power) का प्रयोग कहीं तो केन्द्रीय सरकार को सौंप दिया जाता है, और कहीं प्रांतीय सरकार को। संघ-शासन की प्रमुख प्रवृत्ति का मुकाब दूसरी ओर है। प्रायः प्रत्येक अच्छे संघ-शासन में इस प्रकार के अधिकार प्रांतीय सरकार के हाथ में ही रहते हैं। संयुक्त-राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया, स्विज्ररलैएड आदि सभी देशों के शासन-विधान उपर्युक्त कथन की पुष्टि करते हैं। हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था के विरुद्ध प्रायः यह बात कही जाती है कि उन देशों और हममें एक बड़ा अन्तर यह है कि जन कि उनमें से श्रधिकांश में कई छोटे-छोटे राज्यों ने श्रपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व को खोकर संघ-शासन का निर्माण किया, हमारे यहां इन इकाइयों के स्वतन्त्र व्यक्तित्व वनने के बहुत पहिले श्रिखिल देश का एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व मौजूद था। ऐसी परिस्थितियों में यह सिफ़ारिश की जाती है कि हमारे देश के प्रस्तावित शासन-विधान में विभाजन के बाद वच रहने वाली यह श्रव्यक्त सत्ता (residuary power) केन्द्रीय सरकार के हाथ में ही सोंपी जानी चाहिए।

कनाडा में ऐसा है भी, पर, जहां तक कनाड़ा का प्रश्न है, हमें दो बातों पर ध्यान रखेना है। एक तो यह कि इस सम्बन्ध में कनाडा अपवाद है, वह संघ-शासन के सामान्य अनुशासन में नहीं आता। दूसरे, कनाडा की स्थिति अपर से देखने में अन्य देशों से भिन्न होते हुए भी मूल-रूप में उनसे भिन्न नहीं है। जब कि ग्रमरीका के संयुक्त राज्य व ग्रन्य देशों में यह ग्रवाशिष्ट सत्ता प्रांतों को दी गई है, पर अदालतों ने अपने वैधानिक निर्णयों से केन्द्रीय सरकार को श्रिधिक-से-श्रिधिक सशक्त बना दिया है, कनाडा में इस सत्ता के केन्द्र के पास रहते हुए भी खदालती निर्णयों की प्रवृत्ति प्रांतों को सशक्त बनाने की है। इस प्रकार कनाडा ऋौर ग्रान्य देशों की वस्तु-स्थिति में विशेष ग्रान्तर नहीं है। इस सम्बन्ध में हम १८०० से १८३५ ई० तक ग्रमरीका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जिस्टिस मार्श ल के "निहित शक्तियों के सिद्धान्त" (the doctrine of implied powers) को ध्यान में रखते हुए यह निर्ण्य कर सकते हैं कि यह श्रवशिष्ट सत्ता उन ऋधिकारों के संबंध में, जो केन्द्रीय शासन के श्रन्तर्गत श्राते हों, केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहे, व इसी प्रकार उन अधिकारों के सम्बन्ध में, जो प्रांतीय शासन में निहित हों, उसका प्रयोग प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाय। इस सिद्धान्त को मान लेने पर श्रवशिष्ट सत्ता का चीत्र कुछ संकुचित तो श्रवश्य हो जायगा, पर फिर भी बहुत से ऐसे श्रव्यक्त श्रिधिकार रह जायगे, जिनके संबंध में यह निश्चय करना ज़रूरी होगा कि उनका प्रयोग किसे सौंपा जाय। मैं समभता हूँ कि उन्हें, विना किसी हिचकिचाहर के, प्रांतीय सरकारों के हाथ में सींप देना चाहिए। जबिक विदेशी नीति श्रीर राष्ट्रीय सुरद्धा संबंधी समी श्रिधिकार केन्द्रीय सरकार के पास होंगे, और 'निहित शिक्तयों के सिद्धांत' को कियात्मक रूप देने का दायित्व भी केन्द्रीय वैधानिक अदालत को ही होगा, तव इसके संबंध में हमें विशोप चितातुर होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के पांत स्त्रयं ही इतनी वड़ी राजनैतिक इकाइयां हैं, श्रीर उनमें से श्राधिकांश का ग्रपना सांस्कृतिक व्यक्तित्व श्रपने पीछे इतनी वड़ी ऐतिहा कि परम्पराग्रों को लिये हुए है, और उनमें से कुछ की 'आत्मनिर्णय' की मांग आज भी इतनी

प्रजातन्त्रात्मक प्रदेशों के सीमा-निर्धारण ऋथवा उनके ऋन्तर्गत नये स्वशासित प्रदेशों की सृष्टि भी केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर ही निर्भर है; इसके ऋतिरिक्त राष्ट्रीय रचा और ऋान्तरिक शान्ति का संरच्चण भी उसी के सिपुर्द है।

परन्त यदि हम इस प्रश्न की गहराई में जायं तो हम यह स्पष्ट देख सकेंगे कि रत्ना और विदेशी नीति के विभागों में केन्द्रीकरण के होते हुए भी, प्रान्तीय सरकार के हस्तच्चेंप की काफ़ी गुज़ाइश रह जाती है। इस सम्यन्ध में वैधानिक धारात्रों को उद्धत करना तो सम्भव नहीं होगा, क्योंकि संघ-शासन में प्रायः प्रान्तीय सरकार के ऋधिकारों की व्याख्या नहीं की जाती; उसमें तो यह मान लिया जाता है कि जो ऋधिकार स्पष्टतः केन्द्रीय सरकार को नहीं सौंप दिये गए हैं, उनके उपयोग का समस्त ऋधिकार प्रांतीय सरकार को ही रहेगा । ऋमरीका के संयक्त-राज्य में विभिन्न 'राज्यों' को किसी अन्य देश से सन्धि अथवा सम-भौता करने का ऋधिकार नहीं है, ऋौर न शांति के अवसर पर फ़ौजी या जहाज़ी वेड़ा रखने की इजाज़त ही है, परन्तु, रचा-विभाग के लिए उन्हें रुपया देना होता है, स्रौर इसलिए उसके शासन में हस्तचेंप करने का स्रधिकार उन्हें मिल जाता है, फिर भी, अमरीका में केन्द्रीकरण की मात्रा अन्य संघों की वुलना में ऋधिक है। स्विज़रलैएड में सेना-विभाग का शासन व उसके लिए क़ानून वनाने का ऋधिकार केन्द्रीय शासन को है, पर उन ऋधिकारों का उपयोग प्रधानतः प्रादेशिक सरकारों के द्वारा ही किया जाता है। विदेशी नीति का नियन्त्रण संघ की सरकार के हाथ में है, परन्तु प्रदेशों को एक सीमा तक, केन्द्रीय सरकार की अनुमित से, विदेशों से समभौते करने का अधिकार है। ग्रमरीका श्रीर खिज़रलैएड के विधानों में एक बड़ा श्रन्तर यह है कि जब कि स्रमरीका में देश की स्रान्तिरक शान्ति स्रौर सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व भी केन्द्रोय सरकार को है, श्रीर राज्यों में श्रशान्ति श्रीर श्रराजकता के फैलने पर उनकी प्रार्थना पर, ऋौर कमी-कनी 'ऋपनी इच्छा से भी, इस्तचेंप करने का उसे पूरा ऋधिकार है, स्विज़रलैएड में ऋान्तरिक शान्ति का दायित्व सम्पूर्णतः पादेशिक सरकारों पर ही है। फ़ौजी नियमों का पालन भी उनके द्वारा ही होता है, स्रोर वही केन्द्रीय सरकार की सेना की भूत्तीं स्रोर शिद्धा की व्यवस्था करती हैं।

सोवियट रूस में फ़र्वरी १६४४ के बाद से प्रान्तीय सरकारों को सेना व विदेशी नीति के सम्बन्ध में बहुत ऋधिक ऋधिकार दे दिये गए हैं। विधान में प्रस्तावित संशोधनों को पेश करते हुए मोलोटॉफ़ ने कहा था, "प्रस्तावित सुधार का महत्त्व विल्कुल स्पष्ट है। इसका ऋर्थ है कि 'यूनियन' के प्रजातन्त्रों का

कार्य-चेत्रं बहुत ग्रधिक विस्तृत हो जायगा, ग्रोर उनके राजनैतिक, ग्रार्थिक ग्रीर सांस्कृतिक, दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय, विकास की देखते हुए यह ब्रावश्यक भी ही गया है। यह हमारे छनेकों राष्ट्रों वाले सोवियट राज्य की राष्ट्रीय समस्या के व्यावहारिक ममाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, परन्तु, यह सुधार केवल हमारे प्रजातन्त्रों में संगठन की भावना के परिणांम-खरूप ही संभव नहीं हो सका, वह इसलिए भी संभव हो संका कि हमने ग्राखिल-यूनियन राज्य के चेत्र में भी एक अभतपूर्व संगठन की भावना को विकसित कर लिया है।"" इन सुधारों के साथ सोवियट राज्य ने निःसन्देह ग्रापने विकास के एक नये युग में प्रवेश कर लिया है। हमारे देश में भी, राष्ट्रीय शिक के विकास के साथ-साथ, रचा और विदेशी नीति के चैत्रों में श्रकेन्द्रीकरण के प्रयोग किये जा सकेंगे। विदेशी नीति के चेत्र में तो ब्रारम्भ से ही प्रांतां के दृष्टिकी एं का प्रभाव संघ-शासन के विदेशी सम्बन्धों पर पड़ना ऋतिवार्य होगां। रत्ता के चीत्र में वाद में जाकर वैसा ब्राकेन्द्रीकरण सम्भव हो सकेगा, जैसा ब्राज रूस में हुआ है। परन्तु, यहां हम यह न भूलें कि रूस में भी यह अन्नेन्द्रीकरण कागज़ पर श्रेषिक है, व्यवहार में कम । हिन्दुस्तान में भी यह सम्भव है, कुछ समय तक इन चौत्रों में केन्द्रीय सरकार का ही एकाधिपत्य रहेगा, पर, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ग्रीर त्रावश्यकतात्रों के ग्रानसार इस नीति में परिवर्त्तन तो होगा ही।

अधिक पुनर्निर्माण का प्रश्न

रचा श्रीर विदेशी नीति के साथ श्रार्थिक पुनर्तिर्माण के प्रश्न का भी वड़ा निकट का सम्बन्ध है। जैसा कि पिछले श्रध्यायों में वताया जा चुका है, श्रिप्र-रिमित श्रार्थिक साधनों श्रीर उनके समुचित विकास के लिए श्रार्थिक पुनर्निर्माण की एक विशद योजना के विना कोई भी देश श्राज की श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में श्रपने लिए स्थान बना लेने की कल्पना नहीं कर सकता। श्राज तो हम श्रार्थिक पुनर्निर्माण की योजनाश्रों (economic planning) के युग में जी रहे हैं। इस कल्पना का प्रारम्भ इस की प्रथम पंच-वर्षीय योजना (१६२८-३२) से हुश्रा; इस योजना का ही यह परिणाम था कि इस विश्व की राजनीति में श्रपने लिए एक श्रग्रगएय स्थान बना सका, श्रीर १६२६-३१ के संसार-व्यापी श्रार्थिक संकट से श्रपने की सर्वथा मुक्त रख सका। उसके बाद से तो इस प्रकार की कई श्रार्थिक योजनाएं हमारे सामने श्राती रही हैं। श्रमरीका ने श्रपनी 'नई व्यवस्था' (New Deal) प्रचलित की, कासिस्ट देशों ने श्रपने तरीके के १--New Powers of Soviet Republics, प्र०२।

दिखाई देता है कि हिंदुस्तानको एक रत्तानीति और एक ही फीज होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, रत्ता और विदेशी संबंधों में अंतिम अधिकार केन्द्रीय शासन को ही दिये जाने चाहिए। रत्ता के अन्तर्गत फोज, जहाज़ी वेड़ा और हवाई जहाज़ तोनों आ जाते हैं। इन सब पर संपूर्ण नियंत्रण केन्द्रीय सरकार का ही रहना चाहिए।

रत्ता ऋौर विदेशो नीति के संबंध में समभौते की गुंजाइश नहीं है। ऋाज की ऋव्यवस्थित और श्रास्थिर श्रःतर्राष्ट्रीय राजनीति में रत्ता का प्रश्न सबसे श्राधिक महत्त्वपूर्ण है । प्रशांत महासागर में शिक्त की राजनीति के खुले संघर्ष से हिंदुस्तान का दायिन्व और भी बढ़ गया है। अनुमान तो यह किया जाता है कि भविष्य के महायुद्ध का मुख्य केन्द्र प्रशान्तमहासागर में होगा: उसमें हिंदुस्तानका महत्त्वपूर्ण भाग लेना त्रानिवार्य होगा, ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान को अपनी सैन्य-शिक्त को अधिक-से-अधिक और सुसङ्गिठित रखने की आवश्यकता है। उसे प्रांतीय शासन के हाथों सौंप देना राष्ट्रीय त्रात्मघात के समान होगा। प्रांतों को त्रपनी फ़ौजें रखने का श्रिधिकार भी हो तो भी केन्द्र का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उन्हें किसी प्रकार के आपसी संघर्ष में न पड़ने दे, और उसे अपने इस उत्तरदायित्व को निवाहने के लिए स्वयं उन सब से ऋधिक सशक्त होना पड़ेगा ! प्रांतों के ऋापसी वैमनस्य को प्रोत्साहित न करने और केन्द्र ऋौर प्रांतों के बीच भी त्रावश्यक गु लवफ़हिमयों को खड़ा न होने देने को दृष्टि से भी यहीं उचित जान पड़ता है कि इस संबंध में अखिल, और अविभाज्य, अधिकार केन्द्रीय शासन को ही हों, वैसे, हमारें भावी विधान का आधार-भूत सिद्धांत भी यही होना चाहिए कि केन्द्र को कम-से-कम अधिकार प्राप्त हों, पर जो थोड़े से अधिकार उसे प्राप्त हों उनमें संपूर्ण सता उसके हाथों में रहे, देश की रक्ता की भावना व विश्व की भावी राजनीति में एक अप्रगएय स्थान पाने की आक्रांका, दोनों ही त्राज इतनी प्रवल हैं कि उनकी कीमत पर इन विभागों की सत्ता का विभाजन कल्पना के परे की वस्तु हो जाता है।

यदि हम संसार के दूसरे संघ-शासनों पर दृष्टि डालों तो हम देखेंगे कि रज्ञां श्रीर विदेशी नीति के विभागों पर प्रत्येक देश में केन्द्रीय शासन का ही सम्पूर्ण नियन्त्रण है—क्योंकि यदि इन चेत्रों पर भी केन्द्रीय सरकार का एकाधिपत्य न हुन्ना तो उसकी स्थिति का उपयोग ही क्या हुन्ना श्रीर क्यों संघ-शासन जैसे एक जिटल शासन-तन्त्र को खड़ा करने की त्रावश्यकता ही पड़ी १ जैसा कि त्रमरिका के संघ-शासन के नियन्ता जेम्स मैडीसन ने कहा है, "विदेशी त्राक्रमण के विरुद्ध बचाव सम्य समाज के मूल उद्देश्यों में से एक है। यह त्रमरीका के

संघ का एक उद्घोपित श्रीर श्रावश्यक लंदय है। उसे प्राप्त करने के लिए जितनी शिक्त की श्रावश्यकता हो, वह सब केन्द्रीय सरकार को सम्पूर्ण रूप से सौंप दी जानी चाहिए।" श्रमरीका की केन्द्रीय सरकार को यह शिक्त प्राप्त है। मनरों के शब्दों में, ''विधान के निर्माताश्रों ने यह निश्चय कर लिया था कि, चाहे जो भी हो, नई राष्ट्रीय सरकार के पास वे सब शिक्तयां यथेए मात्रा में होनी चाहिएं जिनकी सहायता से यह बाहरी शत्रुश्रों श्रीर भीतर की श्रराजकता से देश की रत्ता कर सके।''' इसी कारण उन्होंने केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा को इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी-बड़ी शिक्तयां दे डालीं। युद्ध की घोषणा करने, फ्रौजों की भन्तीं व फ्रीजियों को कील-कांट से लैस करने, जहाज़ी वेड़ के संगठन श्रीर संरक्षण, जमीन श्रीर समुद्र की फ्रौजों के लिए नियम श्रीर श्रनुशासन की रचना, श्रद्ध-संगठित फ्रौज (militia) का निर्माण, क्रिलों श्रीर लड़ाई का सामान बनाने वाले स्थानों का नियन्त्रण, ये सब श्रिधकार श्रमरीका के संयुक्त-राज्य में केवल केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा को ही प्राप्त हैं।

कनाडा और आरटेलिया का संगठन अमरीका की पद्धति पर ही है। दूसरे, ग्रमी यह निश्चित नहीं है कि युद्ध श्रौर सन्धि की वास्तविक श्रौर श्रंतिम शांक इन देशों को प्राप्त है भी या नहीं, परन्तु, यदि हम दूसरे ढंग के संघ-शासनों को भी देखें तो हमें इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन श्रीर समर्थन मिलेगा । स्विजरलैएड में रत्ता श्रीर विदेशी नीति के विभाग केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं। प्रत्येक पुरुष-नागरिक को अपने उन्नीसर्वे वर्ष में वीन महीने के लिए अनि-वार्य सैन्य-शिक्ता लेना पड़ती है: उसके बाद ग्रागले बारह वर्ष तक प्रति वर्ष १३ दिन के लिए ऋपनी इस शिद्धा की पुनराकृत्ति के लिए उपस्थित होना पड़ता है। शिक्षा देने व निरीक्ष स्त्रादि का कार्य प्रादेशिक सरकारों के द्वारा किया जाता है, परन्तुं संघ के सैन्यं-विभाग के नियंत्रण में, श्रीर उसके खर्चे का एक भाग भी उन्हें संघ-शासन द्वारा दिया जाता है। सोवियट रूस में भी, इस वात के बावजूद कि फ़र्वरी १६४४ के विधान के अनुसार संघ के सदस्य प्रजातन्त्रों को ग्रापनी सेना व विदेशी सम्बन्धों के विभाग स्वतन्त्र रखने का श्रिधिकार दे दिया गया है, जहां तक राष्ट्रीय विदेशी नीति का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार पर ही उसका दायित्व है, युद्ध और सन्धि के प्रश्नों पर केवल वही निर्ण्य दे सकती है, नये प्रजातन्त्र यदि संघ में शामिल होना चाहें तो उन्हें समाविष्ट करने या न करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को ही है: आंतरिक

१—डब्ल्यू॰ बी॰ मनरो : The Government of the United States, प॰ ४४१ ।

द्याधिक पुनिर्नाण (planning) को ग्रपनाया, जापान ने दिन्तण-पूर्वी एशिया में सह-समृद्धि (Co-prosperity) के सिद्धान्तको जन्म दिया; डेन्मार्क ग्रीर स्वेडन जैसे छोटे-छोटे देशों ने इस मार्ग पर चल कर ग्रपनी ग्रार्थिक स्थिति को वहुत समुन्नत बना लिया। युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में जर्मनी का 'न्यू ब्रॉडर' (New Order) पराजित ग्रीर साथी देशों पर हावी रहा। हमारे देश में भी वम्बई योजना ग्रीर गांधीवादी योजनाएं हमारे सामने क्राईं। स्वाधीन हो जाने के बाद यह ग्रानिवार्य दिखाई दे रहा है कि हमें किसी विस्तृत ग्रार्थिक योजना को ग्रपनाना पड़ेगा।

त्रार्थिक पुनर्निर्माग का समस्त प्रश्न प्रायः सभी देशों में केन्द्रीय सरकार के हाथ में छोड़ दिया जाता है। यह सच है कि प्रांतीय सरकारें एक सीमा तक चाहे अपने आर्थिक साधनों का स्वयं भी विकास कर सकें, उद्योग-धन्धों और व्यापार की वृद्धि, कृषि की उन्नति स्रोर स्रावागमन के साधनों के विकास की दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि वे अपने पड़ौसी प्रांतों, और कभी-कभी दूर के प्रांतों पर भी, निर्भर रहें । वहत सी वातों के लिए उन्हें ऐसे ऋपरिमित साधनों की त्रावश्यकता भी होगी जो उनकी सीमित शक्ति के दायरे से बाहर होंगे। श्रन्य देशों का उदाहरण भी केन्द्रीकरण के पच्च में ही जाता है। रूस में प्रारम्भ से ही योजना-निर्माण का समस्त कार्य एक 'स्टेट प्लैनिंग कमीशन' के सिपुर्द किया गया था। इसके सदस्यों की नियुक्ति रूस की केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा (Council of People's Commissars) द्वारा होती है, स्रौर उन्हें कम्यूनिस्ट पार्टी के निकट-नियन्त्रण में अपना काम करना होता है। इस संस्था (Gosplan) का यह काम है कि वह देश भर से मिलने वाली सूचनात्रों का श्रध्ययन करके एक केन्द्रीभृत योजना का निर्माण करे । इस योजना को कार्या-न्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को यह श्रिधकार है कि वह संघ-शासन के सदस्य-प्रजातन्त्रों की त्र्यान्तरिक व्यवस्था में उतना हस्तत्त्रोप कर सके जितना उसे श्रपने कार्य की सफलता के लिए श्रावश्यक हो। रूस की तीनों पंच वर्षीय योजनास्त्रों का विकास इसी पद्धित से हुस्रा है। इन योजनास्त्रों के परिणाम-स्वरूप ही हम देखते हैं कि ऋाज रूस में उत्पादन के साधनों का व्यक्तिगत स्वामित्व विल्कुल मिट गया है, ग्रौर खेती-वाड़ी का काम, विना व्यक्तिगत लाभालाभ के विचार के, मिल-जुल कर किया जा रहा है । देश में उद्योगीकरण श्रभूतपूर्व तेज़ी से बढ़ा है, श्रीर श्रीद्योगिक उत्पादन पहिले के मुक़ाविले में कई गुना ऋधिक बढ़ गया है। मोलोटॉंं के कथनानुसार, रूस के १६३७ के श्रौद्योगिक उत्पादन का ८० प्रातेशत पहिली दो पंच-वर्षीय योजनात्र्यों का परि-

गाम था। इसी वर्ष रूस में जितने ट्रैक्टर काम में लाए जा रहे थे उनमें से ह० प्रतिशत उसके ग्रापने वनाए हुए थे। कहा जाता है कि १६२६ ग्रीर १६३७ के बीच रूस का ग्रीबोगिक उतादन ३०० से ४०० फ़ीसदी तक बढ़ गया था। यह सच है कि ग्राव भी ग्रीबोगिक उतादन में संसार के कुछ पूंजीवादी देश रूस से ग्रागे बढ़े हुए हैं, परन्तु, उनके ग्रीबोगीकरण के पीछे शताब्दियों का इतिहास है जब कि रूस ने बहुत थोड़े वपों में यह सब कर लिया है। रूस का यह कार्य कभी सफल नहीं हो पाता यदि उसका नियन्त्रण एक केन्द्रीभृत सत्ता के हाथ में न होता।

त्र्यार्थिक विकास की दृष्टि से हमारे देश में विकास के त्रप्रारिमित साधन मौजूद हैं । मुक्त-न्यापार (Free Trade) के लिए हमारे पास किसी भी देश की तुलना में कहीं ग्राधिक विस्तृत चेत्र है, जिसमें ग़रीवी श्रीर वेवसी चाहे कितनी रही हो, पर एक लंबे ऋषें से शान्ति और व्यवस्था भी मौजूद रही है। श्राचागमन के साधन श्रीर रेल श्रीर डाक श्रादि के विभाग भी पूर्ण विकसित हैं। प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है-लोहा ग्रौर कोयला प्रायः साथ-साथ पाए जाते हैं । ऐसी स्थिति में हमारे लिए ग्रौद्योगीकरण का मार्ग सुलभ ग्रौर प्रशस्त है। इस चेत्र में पिछले पचास वयों में जो प्रवृत्ति बढती गई है, पहिले महायुद में जिसे काफ़ी मोत्साहन मिला ग्रीर इस महायुद्ध में जो ग्रानिवार्यता की स्थिति तक जा पहुंची है, उसे भी रोका नहीं जा सकेगा । ग्राज हमारे लिए यह सोचने का अवसर नहीं रह गया है कि अौद्योगीकरण हमारे लिए हितकर है अथवा श्रहितकर, श्रथवा किस सीमा तक वह हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है; श्राज तो हमारे सामने मुख्य प्रश्न यही है कि किस प्रकार हम उसकी गति पर नियंत्रण पा सकें, ग्रीर उसे एक ग्रोर तो ग्रन्तर्राष्ट्रीय ग्रर्थनीति से, ग्रीर दूसरी ग्रीर ग्रपने ग्रामोद्योगों से, संबद्ध कर सकें । यह कार्य सरल नहीं होगा । यों तो ब्रार्थिक श्रौद्योगीकरण के लिए भी सदा राजनैतिक केन्द्रीकरण की श्रावश्यकता होती है, पर इमारे देश में त्र्यार्थिक पुनर्निमीण का प्रश्न केवल त्र्योद्योगीकरण का नहीं है। हमें अपने श्रीद्योगिक उत्पादन को वढाना तो है ही, हमारी ग़रीवी को दूर करने की दिशा में वह एक अनिवार्य कदम है, पर इसके साथ ही यदि हम अपनी कृपि-संबंधी स्थिति में भी सुधार न कर सके तो वह एकांगी कार्य होगा । पिछले दो महायुद्धों के वीच के अशांतिपूर्ण वपों में यह तो स्पष्ट होगया है कि हमें उत्पादन (Production) के साथ-साथ वितर्ण (Distribution) के प्रश्न को भी लेना है ! हिंदुस्तान की ६० फ़ीसदी ग्रावादी गांव में रहती है ग्रीर प्रत्यक् ग्रथवा ग्रप्रत्यक् रूप से कृषि पर निर्भर है; यदि उसकी ग्रार्थिक ग्रवस्था

को समुक्तत न किया गया, तो वह इस स्थिति में कभी नहीं होगी कि देश के बढ़ें हुए ख्रोद्योगिक उत्पादन की खरत (Consumption) में सहायता पहुंचा सके, ख्रोर यह तो निश्चित है कि ख्राज जब प्रत्येक देश ख्रार्थिक स्वावलम्बन (economic self-sufficiency) पर ज़ोर दे रहा है, तो हमें भी ख्रपनी ख्रौद्योगिक उत्पत्ति के एक बड़ें ख्रंश के लिए यहां वाजार तैयार करना पड़ेंगा। गरीबी का प्रश्न बहुत कुछ कृषि के चेंत्र में व्यक्तिगत उत्पादन-शिक्त की हीनता के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि कॉलिन क्लार्क ने ख्रपनी एक पुस्तक में वताया है, न्यूज़ोलैएड में श्रमिकों का (६.४) प्रतिशत ख्रपनी महनत के द्वारा कुल ख्राबादी के लिए ख्रब जुटा सकता है, जब कि ज़ार-कालीन रूस में उस काम के लिए २००फ़ोसरी व्यक्तियों की ख्रावश्यकता थी। हिंदुस्तान में इस व्यक्तिगत उत्पादन-शिक्त को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तभी ख्रौद्योगीकरण का प्रयत्न सफल हो सकेगा। ख्रौद्योगीकरण के कृषि-सुधारों के साथ संबद्ध करने का यह काम केवल एक सशक्त केन्द्रोय सरकार द्वारा ही संवन्न किया जा सकता है।

त्रार्थिक समस्यात्रों के साथ सामाजिक समस्याएं भी गुंथी-मिली रहती हैं। वेकार पड़ी हुई ज़मीन को जोतने की व्यवस्था, जिस ज़मीन में खेती हो रही है उसकी उत्ति वढाने के उपाय, कृषि में श्राधनिक वैज्ञानिक उपायों श्रीर उपादानों का प्रयोग, ये सब समस्याएं तो हैं ही, पर किसान की केवल आमदनी वढा देने से तो काम नहीं चलेगा । त्राज भी त्रपना पेट काट कर वह जो थोड़ा-वहत बचा सकता है, वह श्रंध-विश्वास श्रीर सामाजिक क्ररीतियों पर खर्च करता है। क़र्ज़ में वह बाल-बाल विधा रहता है। यदि उसकी स्नामदनी वढ गई तो यह मान लेने के लिए हमारे पास क्या कारण है कि उसका उपयोग वह **अपने खाने-पीने** श्रीर रहन-रहन के स्टैएडर्ड की वढ़ाने में करेगा ? सच तो यह है कि उसकी श्रार्थिक उन्नति के साथ उसके वौद्धिक विकास की व्यवस्था भी त्र्यावश्यक है। वास्तविक प्रश्न शिक्ता के प्रसार श्रीर समाज-सुधार की प्रवृत्ति की प्रोत्साहित करने का है। शिक्ता श्रीर समाज-सुधार के लिए राष्ट्रीय सरकार तो वांछनीय है ही, एक राष्ट्रीय ऋांदोलन की भी श्रावश्यकता होगी, श्रोर उसकी चिनगारियों को देश के कोने-कोने तक फैलाने के लिए स्रात्मोत्सर्ग के लिए सतत तत्रर राष्ट्र सेवकों की एक संगठित सेना खड़ी करना पड़ेगी। इन सब कामों के लिए एक केन्द्रीभृत संगठन की ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ त्रीर त्रानुसंधान का काम भी चलता रहना चाहिए। इस संबंध में कछ प्रयोग हमने अपने देश में किए हैं, और वहुत कुछ ज्ञान हम अन्य देशों से प्राप्त कर १-कॉलिन झाई: The Conditions of Economic Progress.

सकते हैं, पर विना एक वड़ी केन्द्रीय प्रयोगशाला के, जहां देश के ग्राग्रगएय वैज्ञानिक दिन-रात ग्राध्ययन ग्रोर ग्रानुसंधान में लगे हों, ग्रीर जिसके पास ग्रापरिमित साधन हों, यह काम नहीं किया जा सकता। प्रांतीय सरकारें इस चेंत्र में एक सीमा तक ही जा सकती हैं।

उपर्युक्त विचार-धारा का स्पष्ट भुकाव केन्द्रीकरण की दिशा में है। पर, मैं योजना-निर्माण त्र्यौर उसे कार्यान्वित करने की किया में भेद करना चाहुँगा। पुनर्निर्माण के संबंध में अनुसन्धान और योजना-निर्माण का काम तो केन्द्र के द्वारा ु करना ही ठीक होगा। श्रौद्योगीकरण के चेत्र में भी, प्राकृतिक साधनोंके देश भरमें विखरे होने व अन्य कारणों से नेतृत्व केन्द्रीय सरकारके हाथमें ही रहेगा । जहां तक हमारी राष्ट्रीय ऋर्थनीति को ऋन्तर्राष्ट्रीय ऋर्थ-नीति से संबद्ध करने का प्रश्न है, श्रांतिम सत्ता केन्द्र के हाथों में ही रहेगी, पर हमारी श्रार्थनीति का श्राधार यदि श्रीद्योगीकरण को कृषि श्रीर श्रामोद्योगों के साथ संबद्ध करने, श्रीर उसे सामाजिक शादीकरण की भूमि पर स्थापित करने का है, तव तो प्रांतीय सरकारों के लिए भी काफ़ी विस्तृत कार्य-चेत्र प्राप्त हो सकेगा । केन्द्रीय सरकार के द्वारा पुनर्निर्माण की संपूर्ण व्यवस्था (State Planning) के दोषोंसे भी हम अनिभन्न नहीं हैं। रूस श्रीर जर्मनी के उदाहरण हमारे सामने हैं। इन दोनों देशों में श्रार्थिक पुनर्निर्माण की वड़ी-वड़ी योजनात्रों को कार्यान्वित करने के लिए एक बहुत बड़ी नौकरशाही की त्र्यावश्यकता हुई: इस नौकरशाही ने, केंवल त्र्यपने कार्य की सफलता को दृष्टि में रखते हुए, नागरिक स्वाधीनता को बुरी तरह से अपने पैरों तले रौंदा है: उनमें से कुछ ने इस सत्ता का उपयोग श्रपने व्यक्तिगत स्वाथों की पृत्तिं के लिए भी किया; श्रीर इन सबका परिणाम यह हुन्ना है कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर श्राघात पहुंचा है । हमारे देश की परिस्थितियों में, जबिक श्रौद्योगी-करण के साथ-साथ ग्रामोद्योगों और कृषिक उन्नति को भी लेना है, संभवतः उतने केन्द्रीकरण की त्र्यावश्यकता न हो । काफ़ी दूर तक त्र्यार्थिक पुनर्निर्माण के प्रांतों के ब्राांतरिक विकास से संबंध रखने वाले प्रश्नों को प्रांतीय सरकार के हाथ में छोड़ा जा सकता है; उसका केन्द्रीय सरकार की अर्थ-नीति से संवद्ध भर रहना श्रावश्यक माना जाना चाहिए । इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के लिए श्रपनी अर्थनीति को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थनीति से संबद्ध रखने का प्रयत्न करते रहना आव-श्यक होगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनका निवटारा न तो प्रांत की अपनी सीमा में संभव होगा,ग्रौर न समस्त देशसे ही उनका सीधा संबंध होगा। इस संबंध में एक ही नदी द्वारा सींचे जाने वाले प्रदेशों की कृषिक उन्नति, ग्रथवा 'हाइड्रो-इलेक्ट्रिक' शक्ति के उत्पादन, का नाम लियां जा सकता है। पर, उनके लिए

किसी चेत्रीय शासन की विलक्षण सृष्टि से अधिक अच्छा मार्ग में यह समभता हूं कि उन्हें, केन्द्रीय सरकार के निर्देश में, आंतर्प्रान्तीय व्यवस्था के ज़िम्मे छोड़ दिया जाय। वास्तविक प्रश्न केन्द्र और प्रांतों में सहयोग की भावना के मौजूद होने का है। वैसी भावना की उपस्थित संघ-शासन में ही सम्भव हो सकती है। केन्द्रीय सरकार के अन्य अधिकार

श्रार्थिक पुनर्निर्माण के प्रश्न के साथ ही मुद्रा श्रीर विनिभय के प्रश्न गुंधे हुए हैं। मुद्रा च्रौर विनिमय के सम्बन्ध में देश भर में एक ही नीति का होना त्रावश्यक है। इस सम्बन्ध में विभिन्नता होने का भयावह परिशाम हम त्र्याज के यूरोप में स्पष्ट देख रहे हैं। सभी प्रान्तों श्रौर समस्त देश के श्रार्थिक जीवन के सभी श्रंगों के लिए देश में एक सामान्य मुद्रा का होना लाभपद होगा। इसी प्रकार भारतीय श्रीर विदेशी सिकों के बीच एक ही विनिमय-दर का होना भी ज़रूरी है। यदि प्रांत-प्रांत में विभिन्न सिके हुए, ऋथवा कुछ प्रांतों में विदेशी सिक्कों से विनिमय का दर एक हुन्ना न्नौर कुछ में दूसरा, तो न्नान्तरिक श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय दोनों च्रेत्रों में व्यापार का समुचित विकास नहीं हो सकेगा । सम्भव है, कुछ प्रदेशों में विदेशी माल ऋधिक संख्या में आकर पड़ा रहे, स्रौर एक प्रांत श्रीर दूसरे प्रांत के बीच व्यापार-कर (tariff) की दीवारें ऊंची उंठती चली जाएं। व्यापार का गला घोंटने, श्रीर हमारी राष्ट्रीय समृद्धि को ग्रसम्भव वना देने, का इससे श्रच्छा उपाय कोई नहीं हो सकता । यदि हम इस श्रराजकता को निमंत्रण देना नहीं चाहते तो हमें श्रपने मुद्रा श्रीर विनिमय के प्रश्नों को केन्द्रीय सरकार के हाथ में छोड़ना ही पड़ेगा। इस सम्बन्ध में एक यह वात भी अञ्छी है कि इन प्रश्नों के साथ सांप्रदायिकता का कोई सम्बन्ध नहीं है, स्त्रौर इस कारण उन्हें केन्द्रीय सरकार को सौंप देने में किसी को श्रापत्ति न होगी।

मुद्रा श्रौर विनिमय यदि श्रार्थिक पुनर्निर्माण का वाह्य-पत्त है, तो श्रावा-गमन व देश को एक कोनेसे दूसरे कोने तक संबद्ध करने के साधन (Transport and Communications) व उद्योग श्रौर वाणिज्य (Industry and Commerce) उसके श्रांतरिक पत्त । इन दोनों चेत्रों में भी विद्वानों की सम्मित उन्हें केन्द्रीय सरकार के हाथ में छोड़ देने के पत्त में ही है । इस सम्बन्ध में कुछ वर्क पूर्ण युक्तियां भी दी जा सकती हैं । हिन्दुस्तान ने श्रपने लम्बे इतिहास की कई शताब्दियां सड़कों, रेलों, तार श्रौर डाक की एक संगठित व्यवस्था, के विकास में लगा दी हैं । उस एकता को श्राज विकीर्ण कर देना शायद बुद्धिमानी का काम न हो । डॉ॰ वेनी प्रसाद के शब्दों में, ''सड़क, रेल, डाक, तार ग्रोर टेलीफ़ोन ग्रादि की जो न्यवस्था सेनिक ग्रावश्य-कता, सामान ग्रोर यात्रियों के ग्राने जाने की सुविधा, ग्रोर संदेशों के भेजे ग्रोर प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में की गई है, वह समस्त देश में फैली हुई है। सिन्धयों, ग्राहदनामों ग्रोर सार्वभोमता के द्वारा देशी रियासतों को भी ब्रिटिश भारत से संबद्ध कर दिया गया है। यदि इस ग्राधार को नष्ट कर दिया जाता है, तो रच्चा-सम्बन्धी योजनाग्रों ग्रोर ग्रार्थ नीति की सारी व्यवस्था को एक वड़ा धक्का लगेगा, विशेष कर उत्तर-भारत में, ग्रोर यात्रा ग्रोर सन्देश वाहन में बहुत बड़ी ग्रासुविधा खड़ी हो जाएगी। यदि उसे सुरच्चित रखना है तो उसके संचालन ग्रीर निरीच्चण के लिए एक सामान्य-सत्ता का होना ग्रावश्यक है।'' यह विल्कुल स्पष्ट है कि ग्राने जाने ग्रीर सन्देश भेजने ग्रीर प्राप्त करने के साधनों का ग्रायोजन, समग्र-रूप से, एक ग्राखिल-भारतीय सत्ता के द्वारा किया जाना चाहिए, ग्रीर उनके प्रमुख उपादानों, रेलवे लाइनों ग्रीर सड़कों, पर उसका सीधा ग्राधिकार होना चाहिए।'''

इस प्रश्न के ग्रान्तर्राष्ट्रीय पच को भी हम दृष्टि से ग्रीभल नहीं कर सकते, श्रीर यह पत्त श्राने वाले वर्षों में वड़ा महत्त्व ले लेगा, इसमें भी सन्देह नहीं है । यह त्रिल्कुल सम्भव है कि हिन्दुस्तान कुछ वर्षों में ही सड़क, या रेल से भी, वर्मा, चीन, ग्रफ़ग़ानिस्तान, ईरान ग्रादि देशों से संबद्ध कर दिया जाए। दुनियां भर में फैले हुए हवाई मागों की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी तो वह ब्राज भी है ही। उसकी जहाज़ी श्रीर समुद्री ताकृत भी भविष्य में तेज़ी के साथ बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में सड़कों, रेलों, समुद्री व हवाई जहाज़ों के रास्तों ख्रादि के सम्बन्ध में विदेशों से समभौते करना भी आवश्यक होगा, और हिंदुस्तान के लिए समय समय पर ऋन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंसों में हिस्सा लेना व इन प्रश्नों के सम्बन्ध में म्रन्तर्राष्ट्रीय नियम-म्रनुशासन म्रादि के निर्माण में सहयोग देना भी स्नावश्यक होगा। ऐसी परिस्थिति में उनकी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहना ही वांछनीय माना जाता है। इसी प्रकार, व्यापार और वाशिज्य के चेत्र में भी म्राखिल-देशीय व्यवस्था की ही ग्रावश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसके विना व्यापारिक इक्तरारनामों पर ग्रमल कराना ग्रीर धोखेवाज़ी को रोकना सम्भव सकेगा, ग्रौर यह देखते हुए कि ग्राने वाले वर्षों में हिन्दुस्तान का वाणिज्य न्त्रीर व्यापार बहुत तेज़ी के साथ बहुंगा, इस प्रकार के केन्द्रीभृत नियन्त्रण की त्र्यावश्यकता पर ग्रौर भी ग्रधिक ज़ोर दिया जाता है। इसके ग्रातिरिक्त हमें विदेशी-व्यापार को भी त्रापनी दृष्टि में रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि

३—वेनोप्रसाद: Communal Settlement, पृ॰ ११।

श्रार्थिक दृष्टि से हिन्दुस्तान एक समिष्ट है, श्रीर उसका विभाजन देश के लिए हानिकर ही सिद्ध होगा।

ंये सव वड़े प्रवल तर्क हैं, ऋौर सैद्धान्तिक दृष्टि से उनमें किसी प्रकार की कमी बताना सम्भव नहीं है, परन्तु, हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी तो इस प्रश्न पर विचार करना है। देश में संघ-शासन की स्थापना के प्रस्ताव का अर्थ ही यह है कि श्रव हम मानने लगे हैं कि हमारे प्रांतों में एक श्रोर तो श्रात्म-निर्णय की भावना प्रवल हो गई है, ऋौर दूसरी स्रोर उनमें राजनैतिक परिपकता भी त्राव इतनी मात्रा में त्रा गई है कि हम शासन-व्यवस्था में त्राकेन्द्रीकरण की दिशा में कुछ साहस-पूर्ण क़दम उठा सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रांतीय प्रेरणा श्रीर नियन्त्रण को हम अवज्ञा की दृष्टि से नहीं देख सकते: प्रत्युत उसे तो हमें प्रस्थापित स्रौर पोत्साहित करना है, स्रौर सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम प्रांतों श्रीर केन्द्र में किसी मौलिक-मतभेद के स्त्राधार पर नहीं चल रहे हैं। उनमें यदि पारस्परिक विश्वास है, तो हमें ऋकेन्द्रीकरण से भयभीत होने की ऋावश्यकता नहीं, बल्कि उसका स्वागत ही करना चाहिए। इन क्रेत्रों में प्रांतों को एक वहत वड़ी सीमा तक श्राधिकार दिए जा सकते हैं। पुनर्निर्माण की व्यापक योजनाएं, मुद्रा ऋौर विनिमय की नीति, ऋौर स्रावागमन स्त्रीर सन्देश वाहन के साधनों, व वाशिष्य श्रीर व्यापार का वाहा-पक्ष, जिनका सम्बन्ध दिदेशों से है, निःसन्देह केन्द्रीय सरकार के ऋधिकार में रहेंगे, पर ऋन्तिम विभागों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उनके आन्तरिक पक्ष को प्रान्तीय सरकारों के हाथों में सौंप देना ही वांछनीय होगा । सड़कों ऋौर रेलों के विभाग का ही उदाहरण लें। इनमें से ऋधिकांश का विस्तार प्रायः २ या ३ तीन प्रांतों तक है । उनका नियन्त्रण स्रान्तर्पान्तीय स्राधार पर किया जा सकता है। उनमें भी कुछ सहायक सङ्कें ऋौर रेलें ऐसी होंगी जिनका विस्तार एक प्रांत से ऋधिक नहीं है: उनमें तो केन्द्रीय सरकार का इस्तचेंप न केवल ऋवांछनीय विलक श्रहितकर भी सिद्ध होगा। यूरोप की श्रधिकांश रेलें वैयक्तिक सम्पत्ति हैं, श्रौर उनका विस्तार प्रायः २ या ३ देशों तक है, पर उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में कभी अयोग्यता की वात नहीं सुनी गई; तब कोई कारण नहीं कि हमारी प्रांतीय सरकारें इस काम को सफलता के साथ क्यों न कर सकें । इसी प्रकार, व्यापार के सम्बन्ध में भी यह अखिल-देशीय क़ानृत वन जाना तो आवश्यक है ही कि एक प्रांत श्रीर दूसरे प्रांत के बीच किसी प्रकार का श्रायात-निर्यात-कर न लगाया जाए, परन्तु व्यापार के त्र्यान्तरिक पत्त का नियन्त्रग् प्रांतीय सरकार के हाथों में छोड़ना ही ठीक होगा । इस ऋकेन्द्रीकरण के वावजूद भी इस आवश्यक

सिद्धान्त की उपेचा तो की ही नहीं जा सकेगी कि देश-न्यापी आपित के अवसर पर केन्द्रीय सरकार की यह अधिकार प्राप्त होगा कि इन प्रश्नों की वह सर्वथा अपने नियन्त्रण में ले ले।

केन्द्र और प्रांत के संयुक्त अधिकार

शासन के ऐसे बहुत से विभाग हैं जिनमें केन्द्र और प्रांत दोनों मिल-जुल कर काम कर सकते हैं, ऋार्थिक पुनर्निर्माण की योजना में भी, जिसे कार्यान्त्रित करने का एकमात्र उत्तरदाथित्व प्रायः केन्द्रीय सरकार की सें। जाता है. किस प्रकार प्रांतों को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर दिया जा सकता ्है, इसकी कुछ चर्चा ऊपर ग्रा चुकी है। मुद्रा ग्रीर विनिमय के प्रश्नों की छोड़ कर जिनमें केन्द्रीभृत नियंत्रण की वड़ी ग्रावश्यकता है, ग्रन्य संबंध में भी केन्द्रीय ग्रीर प्रांतीय सरकारें मिलजुल कर व्यवस्था कर सकती हैं, स्रावागमन के साधनों, व्यापार स्रादि के चौत्रों में व्यवस्था का स्राधिकांश भाग प्रांतों को सौपा जा सकता है। यहुत से श्रन्य मामलों में जहां तक क़ानून बनाने का संबंध है यह काम केन्द्रीय सरकार पर छोड़ा जा सकता है, पर जहां उस कान्त को श्रमली रूप देने का सवाल श्राए, वहां उसकी ज़िम्मेदारी प्रांतीय सरकार को दी जा सकती है। विवाह, तलाक ग्रादि की समस्याएं इस प्रकार की हैं। कॉपीराइट, मर्दु मशुमारी, पैमाइश, कस्टम-टैक्स, सामाजिक इंश्योरेंस, फ़ैनटरी-फ़ानून, ग्रार्थिक योजना-निर्माण ग्रादि ऐसे वहत से प्रश्न हैं, जिनकी व्यवस्था केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारें मिलज़ल कर कर सकती हैं। भागे हुए श्रपराधियों का पता लगाने व व्यापक पड्यन्त्रों का भंडाफोड़ करने के लिए भी इस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पहेंगी। ये सब प्रश्न ऐसे हैं, जो न तो केवल केन्द्रीय सरकार के हाथ में ही छोड़े जा सकते हैं, ग्रौर न प्रांतीय सरकारें ही सफलवापर्वक उन्हें सलभा लेने की स्थित में होंगी।

खायत्त-शासन भोगी प्रांती के अधिकार

कपर जिन विभागों का जिक आचुका है, उन्हें छोड़कर शासन के अन्य सभी चुनों पर स्वायत्त-शासन-भोगी प्रांतीय सरकारों की सार्वभौम सत्ता होगी। अविशिष्ट सत्ता (residuary power) विना किसी िक्सक अथवा हिचिकिचाहट के प्रांतीय शासन के हाथमें दे दी जायगी, यह सुभाव ऊपर आचुका है, प्रांतीय सरकार के अधिकारों की विस्तृत व्याख्या इसलिए आवश्यक नहीं है कि वे सब अधिकार जो स्पष्टतः केन्द्रीय सरकार के हाथ में सौंप नहीं दिए गए हैं, प्रांतीय सरकारों के पास रहेंगे। संघ-शासन का प्रमुख कार्य केन्द्रीय-शासन की सीमाओं का निर्धारण कर लेना है। ऊगर की विवेचना पर हम यदि एक बार फिर दृष्टि डालें तो यह देख सकेंगे कि ऐसे विभाग जो केन्द्रीय शासन के सर्वाधिकार में हैं, या जिन पर केन्द्रीय सरकार का दख़ल है, केवल पांच हैं। वे हैं—(१) विदेशी नीति, (२) रत्ता, (३) यातायात श्रादि के प्रमुख साधन, (४) व्यापार पर निर्यात-कर श्रादि की व्यवस्था, श्रीर (५) मुद्रा श्रीर विनिमय। इनके श्रातिरिक्त कुछ थोड़े से ऐसे विभाग हैं जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार को क़ान्न बनाने श्रथवा निरीत्त्रण श्रादि का कुछ श्रधिकार होगा। पर, इस सीमित त्रेंत्र को, जिसकी विधान द्वारा विस्तृत व्याख्या कर दी जायगी, छोड़कर शासन के सम्पूर्ण श्रधिकार प्रांतों को प्राप्त होंगे।

धार्मिक, सांस्कृतिक स्त्रीर सामाजिक स्त्रधिकारों के सम्बन्ध में प्रांतीय सरकारों को सम्पूर्ण सत्ता प्राप्त होगी-यद्यपि अल्प-संख्यक वर्गों के संरत्त्रण का प्रबंध विधान के द्वारा ही होगा। शिक्षा पर, प्रारंभ से लेकर यूनीवर्सिटी की श्रन्तिम कत्ता तक, उनका सम्पूर्ण श्रधिकार होगा-श्रौर शित्ता-सम्बन्धी श्रन्य विषयों, जैसे पुस्तकालय, संप्रहालय, भाषा ऋौर साहित्य, नाट्यशाला, सिनेमा, सङ्गीतालय त्रादि, सब पर उन्हीं का सर्वाधिकार होगा । इन सब विषयोंके संबंध में क़ानून बनाने व शासन-व्यवस्था की स्थापना का दायिन्व प्रांतों पर ही होगा। इसके ऋतिरिक्त कृषि ऋौर उससे सम्बद्ध बहुत से प्रश्न भी प्रांतीय ऋधिकारों के सीधे दायरे में ब्राते हैं। कृषि के साथ भूमिकर, जंगल, खनिज पदार्थों का नियंत्रण, सहयोग-समितियां, विभिन्न प्रकार के स्थानीय टैक्स स्रादि पर भी प्रांतों का त्र्याधिपत्य होगा। इसी प्रकार, स्थानीय स्वशासन, जनता के स्वारुथ-सम्बन्धी सभी संस्थाएं, श्रस्पताल, उपचार-गृह श्रादि, सार्वजनिक इमारतें, स्थानीय सड़कें ऋौर रेलें, गैस, पानी ऋौर विजली के कारलाने त्र्यादि भी प्रांतीय शासन के अन्तर्गत ही होंगे। प्रांतीय शासन की सार्वभौमता का सबसे बड़ा प्रवीक वो उसका शांति श्रीर व्यवस्था का उत्तरदायित्व होगा। यह विभाग संपूर्णतः प्रांतीय शासन के ऋधीन होगा । ऋावपाशी ऋौर निदयों श्रादि पर भी उनका ही नियंत्रण होगा । इन बातों, श्रौर इसी प्रकार की कुछ श्रन्य वातों, में श्रान्तर्प्रान्तीय सहयोग की श्रावश्यकता भी पड़ेगी, पर उससे प्रांवीय सार्वभौमता पर कोई असर नहीं होगा । यूरोप में प्रायः एक ही नदी चार पांच देशों में होती हुई जाती है। उसकी व्यवस्था का दायित्व उन सभी देशों पर होता है, स्रौर वे मिलजुल कर इस दायित्व को पूरा करते हैं, पर इसका स्रर्थ यह नहीं है कि इस प्रकार के संयुक्त ऋधिकार से उनकी राष्ट्रीय सार्वभौमता में किसी प्रकार की कमी त्राती हो। यदि हम कैवल इन्हीं विभागों पर दृष्टि डालें जिन पर एकमात्र प्रांतीय सरकार का ही सर्वाधिकार होगा, तो हम देख सकेंगे



(अ) वैधानिक विकास की दिशा

वैधानिक विकास की श्राधार-भूमि

भारतीय परिस्थितियों में संघ-शासन की उपयुक्तता मान लेने, व उसके श्राधार-भृत सिद्धान्तों की न्याख्या कर लेने, के वाद भी यह प्रश्न रह जाता है कि हमारे वैधानिक विकास का आरम्भ किस विन्दु से हो, उसकी आधार भूमि क्या हो, स्रोर उसके ऋन्तिम लच्च की स्रोर वढने के लिए किन मागों का हम श्रवलम्बन करें। इस सम्बन्ध में, यह कहा जा सकता है कि हमारे सामने चार निश्चित योजनाएं, अथवा मत, हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि हमारे वैधानिक विकास के प्रारम्भिक इतिहास में चाहे कितनी बड़ी ग़लितयां क्यों न रही हों, १६३५ का शासन-विधान हमें ऋपने वैधानिक भविष्य के लिए एक वड़े सुनिश्चित पथ की त्रोर संकेत करता है, त्रीर हमें, वीच के इन कई वर्षों के गत्यावरोध को चीरते हुए, उसी मार्ग पर एक वार फिर से चल पड़ना चाहिए । इस सम्बन्ध में हम यह न भूलें कि यद्यपि १६३५ की शासन-योजना के बनाने का समस्त श्रेय, श्रथवा दायित्व, श्रंग्रेज़ी सरकार का था, वह स्वयं उस मार्ग को कभी का छोड़ चुकी है। उसने इन पिछले वर्षों में जो दूसरा मार्ग हमारे सामने रखा है, उसका स्त्रपात अगस्त १६४० की घोषणा में, उसकी एक विस्तृत वाह्य-रेखा मार्च १६४२ के किप्स-प्रस्तावों में ऋौर उसकी कुछ कमियों की पूर्त्ति जून १६४५ के वेवल-प्रस्तावों में हम पाते हैं। वीसरा रास्ता वह है जिसकी मांग कांग्रेस पिछले कई वर्षों से कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हमारे भावी शासन-विधान का निर्माण एक विधान-निर्मातृ सभा के द्वारा होना चाहिए, श्रीर इस सभा में देश के सभी वयस्क व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना श्रावश्यक है। एक चौथा मार्ग भी है, जिसकी श्रोर मुस्लिम लीग ने मार्च १९४० में इशारा किया था, श्रीर जिसके संबंध में, कुछ उड़ती-सी व्याख्या, पहिली वार, नवम्बर १६४५ में, जिन्ना साहिव ने श्रमरीकन-प्रेस को एक इंटरव्यू देते हुए की थी। वह देश को दो हिस्सों में बांट देने, व प्रत्येक भाग को ग्रपना विधान ग्रपने ग्राप बना लेने का ग्रधिकार देने की योजना है। सर्व-साधारण में वह पाकिस्तान-योजना के नाम से प्रसिद्ध है। पिछले कई ऋष्यायों

कि उनमें जीवन के कुछ सर्वोपयोगी विभाग शामिल हैं, ग्रोर शासन की ऐसी श्रनेकों शाखाएं हैं, जो प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन का स्पर्श करती हैं, ग्रोर वे सब ग्राधिकार हैं जिनके सम्बन्ध में धार्मिक ग्रीर सांस्कृतिक दल संवेदनशील रहा करते हैं।

यदि इस प्रकार की योजना ग्रमल में लाई जा सकी, तो मुक्ते पूरा विश्वास है कि मुसल्मानों का वहसंख्यक वर्ग द्वारा शासित होने का भय वहुत कुछ निर्मुल किया जा सकेगा, ग्रौर उसके साथ ही न केवल मुस्लिम वह-संख्यकं प्रांतों, विलक प्रायः सभी प्रांतों, की स्नात्म-निर्णय की स्नाकां को भी सन्तुष्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही, त्रावश्यकता पड़ने पर, महत्त्वपूर्ण ऋखिल-भारतीय प्रश्नों के केन्द्रीय शासन द्वारा नियंत्रित किये जाने का आयोजन भी इसमें है ही। यहां हमें यह तो ध्यान में रखना ही है कि सत्ता का कैसा भी विभाजन, श्रौर प्रांतों को किसी भी सीमा तक दिया गया खायत्त-शासन, उस समय तक सन्तोषप्रद नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके पीछे समभौते की भावना में कार्य करने की तैयारी नहीं होती । दूसरी वात जो सारी योजना में निहित है. पर जिसे यहां स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है, यह है कि प्रस्तावित योजना में न तो एक निर्वल केन्द्रीय शासन की कल्पना की गई है, स्रौर न केन्द्र के इशारे पर नाचने वाले कठपतली प्रांतों की । प्रायः यह कहा जाता है कि हमें इन दोनों में से ही एक को चुन लेना है । संघ-शासन की सुन्दरता इसी में है कि वह न तो केन्द्र को निःशक्त बनाता है, स्त्रौर न सदस्य-राज्यों स्त्रथवा प्रांतों को कमज़ोर । वह सत्ता का एक कठोर विभाजन कर देता है, स्त्रीर केन्द्र स्त्रीर प्रांत दोनों को ऋपने-ऋपने त्रेत्र में उसके सम्पूर्ण, ऋविमाज्य, उपभोग का संपूर्ण अवसर देता है। उन विभागों में जो केन्द्रीय सरकार की सींप दिये गए हीं, उसे वड़े-से-वड़ा साहसपूर्ण कदम उठाने का ऋधिकार है, स्रीर इसी प्रकार प्रांतीय सरकार ऋपने ऋधीनस्थ विभागों पर ऋपनी सार्वभौमता का सम्पूर्ण उपयोग कर सकती है। हम शासन के इन दोनों स्तरों को अपने-अपने नियत चेत्रों में पूर्ण-रूप से सशक वनाये रह सकते हैं। फिर भी यदि यह आशंका रह जाय कि संघ-शासन राष्ट्रीय शिक्त का ही हास करता है, तो इसका तो इससे श्रच्छा उत्तर श्रीर क्या हो सकता है कि वर्तमान महायुद्ध में वे दो देश जो श्रपेना प्रमुख संसार के ऋधिकांश पर स्थापित करने में समर्थ हुए हैं, संघ-शासन के दो विभिन्न प्रयोगों के नियन्ता हैं १

(अ) वैधानिक विकास की दिशा

वैधानिक विकास की श्राधार-भूमि

भारतीय परिस्थितियों में संघ-शासन की उपयुक्तता मान लेने, व उसके त्राधार-भूत सिद्धान्तों की न्याख्या कर लेने, के वाद भी यह प्रश्न रह जाता है कि हमारे वैधानिक विकास का आरम्भ किस विन्दु से हो, उसकी आधार भूमि क्या हो, श्रीर उसके श्रन्तिम लच्च की श्रीर बढने के लिए किन मागों का हम श्रवलम्बन करें । इस सम्बन्ध में, यह कहा जा सकता है कि हमारे सामने चार निश्चित योजनाएं, त्रथमा मत, हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि हमारे वैधानिक विकास के प्रारम्भिक इतिहास में चाहे कितनी वड़ी गलतियां क्यों न रही हों, १६३५ का शासन-विधान हमें ऋपने वैधानिक भविष्य के लिए एक वड़े सनिश्चित पथ की श्रोर संकेत करता है, श्रीर हमें, बीच के इन कई वर्षों के गत्यावरोध को चीरते हुए, उसी मार्ग पर एक बार फिर से चल पड़ना चाहिए । इस सम्बन्ध में हम यह न भूलें कि यद्यपि १६३५ की शासन-योजना के बनाने का समस्त श्रेय, श्रथवा दायित्व, श्रंग्रेज़ी सरकार का था, वह स्वयं उस मार्ग को कभी का छोड़ चुकी है। उसने इन पिछले वर्षों में जो दूसरा मार्ग हमारे सामने रखा है, उसका सूत्रपात ऋगस्त १६४० की घोषणा में, उसकी एक विस्तृत वाह्य-रेखा मार्च १६४२ के किप्स-प्रस्तावों में ऋौर उसकी कुछ किमयों की पूर्ति जून १६४५ के वेवल-प्रस्तावों में हम पाते हैं। वीसरा रास्ता वह है जिसकी मांग कांग्रेस पिछले कई वर्षों से कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हमारे भावी शासन-विधान का निर्माण एक विधान-निर्मात सभा के द्वारा होना चाहिए, श्रीर इस सभा में देश के सभी वयस्क व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना श्रावश्यक है। एक चौथा मार्ग भी है, जिसकी त्रोर मुस्लिम लीग ने मार्च १९४० में इशारा किया था, श्रीर जिसके संबंध में, कुछ उड़ती-सी व्याख्या, पहिली वार, नवम्बर १६४५ में, जिन्ना साहिव ने श्रमरीकन-प्रेस को एक इंटरव्यू देते हए की थी। वह देश को दो हिस्सों में वांट देने, व प्रत्येक भाग को श्रपना विधान श्रपने श्राप बना लेने का श्रिधिकार देने की योजना है। सर्व-साधारण में वह पाकिस्तान-योजना के नाम से प्रसिद्ध है। पिछले कई श्रध्यायों

में उसकी विस्तृत विवेचना ग्रा चुकी है, ग्रौर वर्तमान भारतीय ग्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में उसकी ग्रनुपयुक्तता, ग्रसंगतता ग्रौर ग्रवैज्ञानिकता के संबंध में बहुत कुछ लिखा जा चुका है।

१६३५ के एक्ट के सम्बन्ध में बहुत-सी वातें कही जाती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके निर्माण में कई वर्षों का ग्रध्यवसाय, ग्रध्ययन ग्रौर विचार-विनिमय है, स्त्रीर उसका निर्माण संघ-शासन के स्त्राधार पर है। उसके केन्द्रीय पद्म के संबंध में कुछ भी कहा जाय, यह सच है कि प्रांतीय देत में उसके द्वारा एक सीमा तक जन-सत्ता की स्थापना हो सकी थी, श्रौर यदि विधान का संधीय भाग अमल में लाया जा सका होता, तो केन्द्र में भी प्रजासत्तात्मक प्रवृत्तियों का प्राधान्य होना सम्भव था । प्रांतीय चेत्रों में, गवर्नरीं के द्वारा, संरक्तरा ख्रीर विशेष अधिकारों के नाम पर इस्तक्तेय का न होना भी एक स्वस्थ संकेत था। यह त्राशा की जा सकती थी कि केन्द्रीय शासन में भी इस प्रकार के हस्तत्त्रें को टाला जा सकता था। लड़ाई के शुरू होने तक सारा काम अञ्छे ढङ्ग से चल रहा था । प्रांतीय शासन पर जब कभी वैधानिक संकट ग्राये, सरकार ग्रीर कांग्रेस दोनों की श्रीर से सदिच्छा का प्रदर्शन होने से वे संकट टल गए, श्रौर सरकार व कांग्रेस का श्रापसी सम्बन्ध कुछ मज़बूत ही वना । यदि महायुद्ध वीच में न त्राता, त्रीर कांग्रेस प्रांतीय शासन को दुकरा देने की गुलती न करती, तो भारतीयों ग्रीर श्रंग्रेजों का यह स्नेह-सम्बन्ध श्रीर भी परिपक हो जाता, श्रीर विना किसी कलुप श्रीर संघर्ष के, हिन्दुस्तान श्रंग्रेज़ी कॉमनवैल्थ में एक शानदार स्थान पा लेता। एक श्रंग्रेज़ लेखक के शब्दों में, ''जिन्होंने भारतीय परिरिथति व एक्ट की धाराख्रों का ख्रच्छा अध्ययन किया था, उनका विचार था कि मुकम्मिल श्राजादी पर संरत्त्रण श्रीर नियन्त्रणं काग़ज पर चाहे कितने ही बड़े क्यों न दीखें, भारतीय मन्त्रिगण, यदि उन्होंने उन विस्तृत श्रधिकारों का उपयोग किया जो उन्हें दिये गए थे, श्रपने श्रापको एक ऐसी सशक्त स्थिति में रख सकेंगे जिसमें किसी भी ऐसे काम के सम्बन्ध में जो हिन्दुस्तान के हित में हुन्रा, न्त्रीर जिसके पीछे भारतीय जनमत का समर्थन हुन्त्रा, नियन्त्रण लगाना कभी सम्भव नहीं हो सकेगा। इन लोगों को प्रांतीय शासन के प्रारम्भिक काल में आशा के लिए वहें चिह्न मिले, और उन्हें वे खतरे के उन संकेतों के मुक़ाविले में वड़ा समऋते थे, जो इस बीच उनके सामने ग्राये। परन्तु, ऋव वे निरुत्साहित हो गए हैं, ऋौर कांग्रेस नेता क्रों के वर्त्तमान रवैये से सचमुच चुब्ध हैं, और उन्हें शक होने लगा है कि ये लोग हिन्दुस्तान में प्रजा-तन्त्रात्मक ग्राधार पर सचा स्वराज्य जल्दी-से-जल्दी स्थापित कर लेने के लिए

क्या सचमुच उत्सुक हैं, या उनका उद्देश्य केवल कांग्रेस को हिन्दुस्तान का सबसे सशक्त राजनैतिक दल, श्रीर कांग्रेस के नेताश्रों के हाथ में शक्ति के सारे सूत्र केन्द्रित कर देने भर का है।""

भारतीय राष्ट्रीयता ने त्रारम्भ से ही १६३५ की शासन-योजना का विरोध किया. श्रीर श्रव तो वह उसे विल्कुल ठुकरा चुकी है : दन वर्ष पहले जो चीज़ श्रमान्य थी, श्राज की परिवर्धित श्रीर विकसित जन-जागृति के सामने वह त्याज्य श्रीर हेय हो चुकी है : जीवित रहने के लिए हमें भविष्य के सिंहद्वार में प्रवेश करना है, भतकाल की मुद्री गिलयों में लौटने की स्त्रावश्यकता नहीं। १६३५ के शासन-विधान की सबसे बड़ी ख़राबी यह थी कि उसमें सत्ता के आधार परिवर्त्तन से ऋधिक ज़ोर उसके नियन्त्रण पर था। शासन के हर चीत्र में नियन्त्रण, श्रौर नियन्त्रण पर नियन्त्रण, लगे हुए थे । ऐसी परिस्थिति में सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि श्रंग्रेज़ी सरकार उसे कार्यान्वित करने में उदारता से काम ले - श्रीर इंग्लैएड में श्रनुदार दल के प्रभुत्व के बढ़ने के साथ-साथ यह उदारता खत्म होती जा रही थी। यदि हम १६३५ की योजना के निर्माण की वैचारिक पृष्ठ-भूमि को देखें तो हमें पता लगेगा कि १६३० में उसका ब्रारम्भ एक ब्राच्छे वातावरण में हुआ था, पर १६३५ तक, जब उसने क़ानून की शक्क ली, सारा वातावरण बदल गया था, श्रीर १६३६ तक, जब उसे उठा कर एक स्रोर रख दिया गया, हिन्दुस्तान के प्रति स्रंग्रेज़ी सरकार का रुख़ बहुत ही संदेह-शील श्रीर प्रतिक्रियावादी बन गया था। १६३४ के शासन-विधान की वड़ी कमी यही थी कि उसे अच्छा या बुरा क्रप देना भारतीय राष्ट्रीयता के हाथ में नहीं, श्रंत्रे जी सरकार के हाथ में था। इसी का परिणाम यह हुआ कि १६३७ में जब अंग्रेज़ी सरकार ने प्रांतीय सरकारें कायम करना चाहा. वे वन गई । दो वर्षों तक उसने जनसत्तात्मक प्रवृत्तियों के साथ श्रपना सहयोग रखा, पर १६३६ के अन्त में जब उन्होंने उन प्रवृत्तियों को सशक्त बनते देखा; उनसे त्रपना सहयोग खींच लिया, त्रौर, ताश के महल के समान प्रांतीय सरकाहें ज़मीन पर त्रा गिरीं ! १६३५ के विधान में कुछ अधिकार चाहे भारतीयों को दे दिये गए हों, पर सार्वभौम-सत्ता का ऋगु-मात्र भी ऋंग्रेज़ी सरकार के द्वारा छोड़ा नहीं गया था—ग्रन्यथा जनता की त्रावाज़ को यों रोंदा नहीं जा सकता था । प्रजातन्त्र की भावना का ऋगर ज़रा भी ख्याल रखा गया होता, तो १६३६ में यदि अंग्रेज़ी-सरकार को इस वात का विश्वास हो गया था कि कांग्रेसी मंत्रि-

१—सर जॉर्ज श्रस्टर : India and Democracy, १६४१ ए० ३३६-४०। भएडलों के पीछे भारतीय जनमत नहीं है, तो उसे उनके स्थान पर ग्राधिक प्रति-निधि मिन्त्रयों को नियुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए था, न कि गर्वनर के हाथों में सारे ग्राधिकार सौंप देने का डिक्टेटरशाही काम करना था। इस संबंध में यह स्पष्ट हो जाना ग्रावश्यक है कि शासन-विधान की रूप-रेखा चाहे कुछ भी हो, हमारे देश में पालंमेएटरी ढङ्ग का शासन हो ग्रायवा प्रेज़ीडेंटी ढङ्ग का, उसे हम डोमिनियन-स्टेटस का नाम दे लें या मुकम्मिल ग्राज़ादी के नाम से पुकारें, हम सार्वभीम सत्ता का पूर्ण रूप से ग्रंग्रेज़ी सरकार के हाथों से हटाया जाना व भारतीय जनता के हाथों में सौंपा जाना चाहते हैं। इसके सम्बन्ध में समम्भीते की वातचीत करने का समय ग्राव नहीं रहा। इस दृष्टि से १६३५ के शासन-विधान की हम भर्स्यना ही कर सकते हैं। उसमें सत्ता के परिवर्त्तन का कोई ग्रायोजन नहीं था, न कोई इरादा ही था—चिक्त उसे मज़बूती से पकड़े रहने का दुराग्रह था।

हमारे त्र्यान्तरिक प्रश्नों को भी १६३५ का शासन विधान ठीक से सल्का नहीं पाया था । सांप्रदायिक समस्या का उसमें निदान नहीं था । वल्कि यह कहना चाहिए कि सांप्रदायिक कड़वाहट के सारे कारगों को बदस्तूर क़ायम रखते हुए उसमें, प्रांतीयता को प्रोत्साहन देकर, भारतीय राष्ट्रीयता को एक दूसरी श्रोर से चीरने का प्रयत्न किया गया था। सांप्रदायिक चुनाव का सिद्धान्त वैसा ही श्रक्तएण रखा गया था । मैक्डॉनल्ड-निर्णय के श्रनुसार पंजाव श्रीर वंगाल को मुस्लिम-बहुसंख्यक प्रांत वना कर और सिन्ध और सीमा-प्रांत में मुस्लिम-सरकारों की स्थापना संभव करके हिंदू-प्रांतों के विरुद्ध मुस्लिम-प्रांतों की संख्या बढाने का प्रयत्न भी किया गया था : सांप्रदायिकता से पांतीयता के गठबंधन का यह एक ग्रानीखा प्रयोग था। संघ-शासन के वास्तविक सिद्धान्तों पर उसका संगठन न होने के कारण प्रान्तीय इकाइयों को वे अधिकार नहीं मिले थे, जी सांप्रदायिक समसौते की दिशा में उपयोगी होते। प्रांतों की स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानी गई थी । प्रांतीय त्र्यात्मनिर्णय के लिए उसमें गुझाइश नहीं थी। इसलिए केन्द्र के प्राधान्य का डर था-उधर, केन्द्र निर्वल था, श्रीर श्रंग्रेज़ी सरकार पर ही सर्वथा त्र्याश्रित था। सच तो यह है कि १६३५ के विधान में संच शासन के निर्माण का प्रयत्न नहीं था, विलक एक केन्द्रीभृत शासन को ही, उसके दांत ग्रीर पंजे छिपाने के लिए, संघ-शासन का न्याकर्पक खोल पहिना दिया गया था। प्रजा-सत्ता की भावना दवोच दी गई थी, श्रीर उस डरी-सहमी, दवी-छिपी, प्रजा सत्ता पर, पीछे के दर्वाज़े से, देशी राज्यों के आक्रमण का पूरा त्र्यायोजन था । देशी राज्यों को ब्रिटिश भारत के साथ कुछ इस रूप से

संबद्ध किया गया था कि एक श्रोर तो राजाश्रों की स्वेच्छाचारिता के लिए पूरी सुविधा थी, श्रोर दूसरी श्रोर श्रंग्रेज़ी सरकार को श्रपनी डिक्टेटरिशप कायम रखने के लिए खुला मैदान मिल गया था : संघीय शासन पर देशी राज्यों के प्रतिकियात्मक प्रभाव के लिए पूरी से श्रिषक व्यवस्था थी—पर संघ के प्रगितिशील विचारों का उन पर प्रभाव नहीं पड़ सकता था । ऐसी स्थिति में, जब कि १६३५ की योजना न तो हिंदुस्तान श्रोर इंगलैंग्ड के श्रापसी संबंधों का प्रश्न एक संतोषप्रद तरीके से सुलभा न पाई थी, श्रोर न हिंदुस्तान के श्रांतरिक प्रश्नों का ही कोई हल निकाल सकी थी, भारतीय राष्ट्रीयता ने यदि उसे दुकरा दिया, तो इसमें श्राक्ष्यं की बात क्या थी !

एक ऋस्थायी शासन-योजना का प्रश्न

१६३७ ऋौर १६३६ के बीच में राजनैतिक घटनात्रों का कम कुछ विचित्र-सा रहा । १६३७ में कांग्रेस ने प्रांतीय शासन को क्रियान्वित करना तो स्वीकार कर लिया था, पर केन्द्रीय शासन-संबंधी योजना से वह बहुत ज्यादा असंतुष्ट -थी, ऋौर श्रीमती नायडू के शब्दों में, चिमटे से भी उसका स्पर्श करने के लिए वैयार न थी। उधर, सरकार उसे श्रमली रूप देने के लिए उद्यव दिखाई दे रही थी। पर, त्राने वाले दो वधों में तस्वीर की शक्क ही बहुत ज्यादा बदल गई। प्रांतीय शासन को चलाने के अपने अनुभव से कांग्रेस ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि उसे वैसी ही सदिच्छा का वातावरण मिला तो वह केन्द्रीय शासन को भी चला सकती है। श्रंग्रेज़ी सरकार की नेकनीयती में कांग्रेस का विश्वास कुछ जमता-सा जा रहा था । ऋव वह ऋाशा कर रही थी कि गवर्नर-जनरल द्वारा भी संरक्षण ऋौर नियंत्रण के विशेष ऋधिकार वैसी ही कंजूसी से प्रयोग में लाये जायंगे जिसका प्रदर्शन प्रांतीय गवर्नरों ने किया था। उधर ब्रिटिश भारत में राजनैविक जारावि के बढ़ने के साथ देशी राज्यों की प्रजा भी ऋपने नागरिक श्रीर राजनैतिक श्रधिकारों के सम्बन्ध में श्रधिक जागरूक होती जा रही थी, श्रीर उसकी उत्तरदायी शासन की मांग बढवी जा रही थी। स्थान-स्थान पर सत्याग्रह स्रादि भी हो रहे थे। देशी राज्यों की जनता के द्वारा प्रजासत्तात्मक संस्थान्त्रों के निर्माण की मांग का ऋप्रत्यच्च समर्थन वायसराय ऋौर भारतीय सरकार के कुछ उच त्राधिकारियों द्वारा मिल रहा था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का यह डर भी कुछ कम होता जा रहा था कि संघीय शासन में देशी राज्यों का प्रभाव सर्वथा प्रतिक्रियावादी होगा । उसे यह त्राशा हो चली थी कि केर्न्द्राय धारा-सभात्रों में देशी राज्यों की त्रोर से जो प्रतिनिधि होंगे उनके चुनाव में वहां की प्रजा का भी कुछ हाथ होगा । इन परिस्थितियों में १६३४ की शासन-योजना

के प्रति कांग्रेस के विरोध की तीवता कुछ कम होती जारही थी, परन्तु दूसरी श्रोर, देशी नरेशों श्रौर श्रंगेज़ी सरकार की श्रोर से उसके समर्थन का उत्साह भी शिथिल पड़ता जारहा था। देशी नरेशों ने संघ-शासन को प्रारम्भ में तो इस श्राशा से स्वीकार कर लिया था कि वह उन्हें, अपनी स्वेच्छाचारिता का परित्याग किये विना, ऋखिल भारतीय राजनीति पर प्रभाव डालने का एक श्रभ्वपूर्व श्रवसर देगा, पर ज्यों ज्यों संघ-शासन की मूल-प्रवृत्ति से वे परिचित होते गए, और उन्हें इस वात का ग्रहसास होता गया कि उनकी ग्रापनी सार्व-भौमता पर भी केन्द्रीय शासन श्रौर, उसका माध्यम लेकर, प्रजासत्तात्मक शक्तियों का आक्रमण निश्चित है, वे सशंकित और संघ-शासन के प्रति उदासीन होते गए। अंग्रेज़ी सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति का मुख्य ग्राधार देशी नरेशों की स्वीकृति में था। संघ-शासन उस समय तक ग्रमल में लाया ही नहीं जा सकता था जब तक देशी नरेशों का बहुमत उसमें शामिल होने के लिए तैयार - न होजाय । वैसा न होने में सत्ता के प्रगतिशील हाथों में चले जाने का डर था। १६३६ के आरम्भ तक देशी नरेशों कुन्हिं हिकोगी विल्कुल स्पष्ट होगया था। महायुद्ध के छिड़ जाने पर अंग्रेज़ी सरकार को, उसकी आड़ में, संघ-शासन की योजना को विलकुल ही परित्याग कर देने का वड़ा अच्छा अवसर मिल गया।

प्रांतीय शासन के कांग्रेस द्वारा परित्यक्त किये जाने, श्रीर १६३५ की योजना के केन्द्रीय पद्म की अन्त्येष्ट स्वयं अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा हो चुकने, पर हमारी वैधानिक समस्या ने एक दोहरा रूप ले लिया। एक ओर तो वर्तमान गत्यावरोध को मिटाने के लिए किसी तात्कालिक विधान की आवश्यकता थी, श्रीर दूसरी ओर एक ऐसा स्थायी शासन-विधान बनाना था जो इस देश की मूल-भूत समस्याओं का समाधान कर सके। लड़ाई के दिनों में अधिक आवश्यकता एक तात्कालिक विधान की थी,पर कुछ तो देश की बढ़ती हुई राजनीतिक मांग को सन्तुष्ट करने की दृष्टि से, और कुछ तात्कालिक योजनाओं के खोखलेपन को छिपाने के विचार से, मविष्य के सम्बन्ध में भी कुछ आशाएं दिलाई गई। लड़ाई के आरम्भ होते ही वायसराय ने देश के प्रमुख नेताओं से बावचीत की, और अक्टूबर १६३६ में देश के सामने प्रस्ताव रखा कि वह एक रिसी सलाहकार-समिति का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, जिसमें सभी प्रमुख राजनैतिक दलों और देशी-नरेशों के प्रतिनिधि शामिल हों, जो अपनी बैठकें

१—संव-शासन के प्रति देशी नरेशों के दृष्टिकीय में जो परिवर्त्तन हुआ उसके ऐतिहासिक विकास के सम्पूर्ण विवेचन के लिए देखिये—डा॰, रघुवीरसिंह; Indian States and the New Regime, स्वयं उनके संरक्तण में, ऋौर उनके निमंत्रण पर, करे श्लौर युद्ध के संचालन में भारतीय जनमत को सरकार के साथ रखे। जब वर्त्तमान के इस छिछले प्रलोभन का भारतीय राष्ट्रीयता पर कुछ प्रभाव न पड़ा तब, जनवरी १६४० में, बंबई स्रोरिएएट-क्लव के स्रपने भाषण में, वायसराय ने भविष्य के सम्बन्ध में एक सोनहला चित्र सामने रखा । वायसराय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान में श्रंभेज़ी नीति का लच्य युद्ध के समाप्त होने के बाद, कम-से-कम समय में, त्र्यौपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है। इस भाषण में पहिली वार यह कहा गया था कि स्त्रोपनिवेशिक स्वराज्य हिंदुस्तान का खद्य है--१६३५ के शासन-विधान में से इस घोषणा को वड़ी चालाकी के साथ निकाल दिया गया था—स्त्रीर यह स्त्रीपनिवेशिक स्वराज्य वेस्टिमस्टर विधान के ढंग का होगा । १६३५ की योजना को ऋभी बिल्कुल खत्म नहीं कर दिया गया था — यह कहा गया कि भारतीय जनमत यदि ऋनुकुल रहा तो युद्ध के समाप्त होने पर उस पर फिर से विचार किया जायगा। तात्कालिक समाधान की दिशा में सलाहकार-समिति की स्थापना के स्थान पर वायसराय ने यह स्वीकृत कर लिया कि वह श्रपनी कार्यकारियी-सभा में कुछ राजनैतिक नेताश्रों को लेने के लिए तैयार हैं--बशर्तें कि 'महान् जातियों' के नेता उन्हें श्राश्वासन दे सकें कि वे, श्रापसी मतभेदों को भुलाकर, उनके नेतृत्व में, युद्ध-प्रयत्नों में श्रपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान को ऋपने भाग्य-निर्णय का ऋधिकार देने का प्रश्न श्रभी भी नहीं उठा था। श्रगस्त १६४० में, इस एकता की श्रनुपस्थित में ही वायसराय ने श्रपनी कार्यकारिगी-समिति में कुछ हिंदुस्तानियों को ले लेने की घोषणा की । भविष्य के संबंध में दो महत्वपूर्ण सूचनाएं वायसराय की इस घोषणा में थीं । पहिली तो ऋल्पसंख्यक वर्गों के लिए थी । उन्हें ऋाश्वासन दिया गया था कि कोई भी वैधानिक योजना उनकी सहमति के विना कार्यान्वित नहीं की जायगी, श्रीर दूसरे यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हिंदुस्तान के भावी विधान के निर्माण का उत्तरदायित्व प्रधानवः हिंदुस्तानियों पर ही रहेगा, ऋौर उसका ऋाधार भारतीय जीवन को श्रिभिन्यक करने वाली सामाजिक, श्रार्थिक श्रीर राजनैतिक संस्थात्रों की भारतीय कल्पनात्रों पर होगा-पर साथ ही श्रंग्रेज़ी सरकार श्रवने उन कर्त्तव्यों श्रीर श्रिधिकारों को भी भुला नहीं सकेगी जो उसने हिंदुस्तान के साथ के ऋपने दीर्घकालीन सम्पर्क से प्राप्त किये हैं।

वर्त्तमान के संबंध में यह योजना ग्रापमान-जनक ग्रौर भविष्य के संबंध में ग्रास्पष्ट ग्रौर ख़तरनाक थी। क्रिष्स ने भावी-विधान के सम्बन्ध में कुछ ग्राधिक स्पष्ट सुभाव सामने रखे—

्र. उन्होंने एक भारतीय .संघः (: Indian Union) की .कल्पना की, : जिसका दर्जा आन्तरिक ज्यवस्था च विदेशी संबंधों के स्रोत्र में ब्रिटिश कॉमनवेल्य के अन्य उपनिवेशों की बराबरी का होगा।

्रः, इसः भारतीय संघःकेःविधानःकाः निर्माणः, त्र्यंग्रेजीः पार्लमेटः केःद्वाराः नहीं, ः जनताः द्वाराः चुनीः हुई सभाःके द्वारा होगा ।

्रश्च. इस विधान-निर्मातः सभा में देशी राज्यों का साग लेना ज्ञ्यनिवार्यकोगाः।

४. इस भारतीय संघ में शामिल होने या न होने का ग्राधिकार प्रांतों को होगा न हो यदि चाहेंगे तो ज्यपनी वर्तमान वैधानिक स्थिति को कायम रख सकेंगे, श्रीर बाद में भी भारतीय संघ में शामिल होने की उन्हें स्वाधीनता होगी। यदि विचाहेंगे तो अपने लिए एक अञ्चलहदा विधान वना लेने का अधिकार भी उन्हें होगा।

्रमः इस विधान-निर्मातृ सभा त्य्रौरः श्रंभेजी सरकार के बीच एक संधि पर इस्ताच्यक्तिये जायंगे, जिसमें उन सक आवश्यक आतों का विस्तृत लेखा होगा जी श्रंभेज़ों के हाथ से हिंदुस्तानियों के हाथ में सज्जाके संपूर्ण रूप से दिए जाने हों ।

्हाराः संधिः में, त्रांभेजी स्सरकार द्वारा दिये गए त्राश्वासनों के त्राधारः पर, ज़ातीय श्रीरःधार्मिक श्रल्पसंख्यक वर्गों के त्रंरच्या का पूरा निर्वाह ेहोगा।

्धः - युद्ध के समाप्तः होः जाने परः प्रांतीय-चुनावः होंगे, श्रौर उसके फीरन वाद ही प्रांतीय धारा-सभाश्रों के नीचे के चेम्बरों के समस्तः सदस्यः मिल कर, श्रानु-प्रांतिकः प्रतिनिधित्वः (: Proportional; Representation:) के सिद्धांत के श्राधार पर एक विधान-निर्मातः सभा का खुनाव करेंगे, जिसके सदस्यों की संख्या चुनाव करेंगे, जिसके सदस्यों की संख्या चुनाव करेंगे,

्राप्तः यदि अमुख सम्प्रदायों के नेता-विधान-तिमीतृ सभा के च्छुनाव के लिए किसी त्यानय सिद्धांत-पर सहसत् हो सके तो उसे स्वीकृत-किया जा : सकेगा—वैसा भाहोने पर उसका जुनाव उपर्युक्त पद्धति से ही होगा।

्धः इसिविधानः तिर्मातृः समाः में भारतीय राज्यों को अपनी आवादी के उसी अनुपात में प्रतिनिधि नियुक्तः करने का अधिकार होगा जिसमें विदिश भारतः के सदस्य चुने आए होंगे, और उन्हें अधिकार भी वैसे ही होंगे, जैसे विदिश भारतः के प्रतिनिधियों को ।

भविष्य के संबंध में यह योजना, कुछ शाब्दिक श्रौर कुछ मूलभूत व्परि.

वर्तनों के साथ, भारतीय राष्ट्रीयता को स्वीकार्य हो भी जाती, पर वर्तमान के संबंध में सर स्टैफ़र्ड किप्स उन पिछले प्रस्तावों से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, जो वायसराय और भारत-मंत्री अगस्त १६४० से अब तक इतने वार दोहराते रहे थे कि अब उनसे घृणा हो चली थी, और जिनके लिए प्रारम्भ में स्वयं किप्स ने बड़े जोरदार शब्दों में बुरा-भला कहा था, और भारतीय राष्ट्री- यता भविष्य के मुलावे में वर्तमान को भूलने के लिए तैयार नहीं थी।

भविष्य की इस योजना को ज्यों-का-त्यों रखते हुए, वर्तमान के सम्बन्धः में पहिला ऋदम जून १६४५ के बेवल प्रस्तावों में उठाया गया। वेवल-प्रस्तावों में एक बार फिर इस बात को दोहराया गया कि अंग्रेजी सरकार की मंशा हिंदुस्तान को पूर्ण-स्वराज्य की ओर लें जाने की हैं। और वह किसी प्रकार का वैधानिक समभौता उस पर लादना नहीं चाहती । वायसराय ने एक नई कार्य-कारिगी सभा के निर्माण की घोषणा की, जिसमें संगठित राजनैतिक जनमत का श्राधिक प्रतिनिधित्व होने की व्यवस्था थी । इस सभा में प्रतिनिधित्व का श्राधार राजनैतिक नहीं, सांप्रदायिक रखा गया। उस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का आधार यह था कि कार्यकारिणी सभा में ऊंची जाति के हिंदुस्रों स्रौर मुसल्मानोंकी संख्या" वरावर रखी गई थी। यदि विभिन्न सांप्रदायिक दलों के राजनैतिक नेता इन प्रस्तावों को मान लेते तो मौजूदा विधान के ख्रान्तर्गत वे कार्यकारियी-सभा बना सकते थे । वैसी स्थिति में वायसराय श्रीर कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर कार्य-कारिग्री के सारे सदस्य भारतीय होते । युद्ध-मन्त्रित्व का भार तो सेनाध्यक्त-के हाथ में छोड़ना ज़रूरी था ही, पर वायसराय विदेशी नीति के विभाग को भार-तीय मंत्री को सौंप देने के लिए प्रस्तुत थे। इन प्रस्तावों के श्रनुसार, श्रन्य उपनिवेशों के समान, हिंदुस्तान में भी एक श्रंग्रेज हाई क्रीमश्नर की नियुक्ति की जाने का प्रस्ताव था, श्रौर हिंदुस्तान में श्रंप्रेजों के व्यापारिक स्वार्थों के संरक्तरा का दायित्व उत्तेःसौंपा जाने का विचार था । इन प्रस्तावी में दो बड़ी खरावियां थीं । एक तो ऊंची जाति के हिंदुग्रों को, जिनकी संख्या ६६ प्रतिशत से त्राधिक है, मुसल्मानों के, जो भारतीय त्रावादी के २४ प्रतिशत से श्रिधिक नहीं हैं। वरावर ले स्त्राया गया था । दूसरे, वायसराय ने भूलाभाई-लियाक्तवस्रली वावचीत के-त्राधार पर कांग्रेस त्रीर लीग को वरावर स्थान मिलने का जो राजनैतिक प्रसाव था, उसे सांप्रदायिक रूप दे दिया था-श्रीर यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि कांग्रेस केवल हिंदुओं का ही प्रतिनिधित करती है। वायसराय ने जब श्रप्रत्यक्त रूप से, कांग्रेस के राष्ट्रीय संखा होने के दावे को मान लिया, तय कांग्रेस-ने भी सवर्ण हिंदुओं और मुसल्मानों के समान प्रतिनिधित के सिद्धांत का श्रपना

विरोध वापिस ले लिया । परन्तु, मुस्लिम-लीग द्वारा पेश किये गए इस दावे पर कि भारतीय मुसल्मानों की एकमात्र प्रतिनिधिक संस्था केवल वही है, श्रोर मिलक ख़िज़रहयातख़ां श्रोर श्रन्य मुसल्मान नेताश्रों द्वारा ही उस दावे के विरोध के परिणाम-स्वरूप, शिमला-कांन्फ्रेंस श्रसफल घोपित कर दी गई। इस वीच, महायुद्ध भी समाप्त होचुका था, श्रोर चारों श्रोर से यही राय व्यक्त की जाने लगी थी कि श्रव तात्कालिक समाधान का समय निकल गया है, श्रोर यह श्रावश्यक होगया है कि हिंदुस्तान के लिए एक स्थायी शासन-विधान वनाया जाय। ऐसी स्थित में केन्द्रीय श्रोर प्रांतीय धारा-सभाश्रों के चुनाव की घोपणा की गई, श्रीर श्रव कहा यह जा रहा है कि इन चुनावों का परिणाम घोषित हो जाने के बाद स्थायी शासन-योजना का निर्माण-कार्य हाथ में लिया जायगा।

विधान-निर्मातृ सभा की मांग

पिछले ५-६ वपों में अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा तात्कालिक समाधान और स्थायी शासन के सम्बन्ध में जो योजनाएं प्रस्तुत की जाती रही हैं—उनकी चरम-सीमा एक ग्रोर वेवल-प्रस्तावों ग्रौर दूसरी न्रोर किप्स-योजना में है - कांग्रेस के त्र्यादशों से वे बहुत नीचे रह जाती हैं। तात्कालिक समाधान की दिशा में कांग्रेस ग्रपने सिद्धांतों से बहुत दूर तक समभौता कर लेने के लिए तैयार थी. पर वह यह ज़रूर चाहती थी कि केन्द्रीय-शासन के ख्रान्तरिक व्यवस्था संबंधी भाग का एक वड़ा श्रंश भारतीय जनमत के प्रभाव में हो, श्रौर साथ ही श्रंग्रेज़ी सरकार यह घोषणा भी कर दे कि वह लड़ाई ख़त्म होने के फौरन बाद ही हिंदुस्तान की आज़ादी को मान लेगी। तात्कालिक समाधान में वह इस निश्चय का एक स्पष्ट, ऋौर कियात्मक, ऋाभास चाहती थी। सलाहकार-समिति ऋौर छाया मन्त्रिमण्डलं (shadow cabinets) उसे लुभा नहीं सकते थे। युद्ध की भीषणता ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, कांग्रेस ने ऋधिक-से-ऋधिक समभौते की भावना का प्रदर्शन किया । कांग्रेस का पूना-प्रस्ताव, जिसमें उसने ऋहिंसा के सिद्धांत को भी एक ख्रोर रख कर युद्ध के प्रयत्नों में सहायता देने का अपना विचार प्रगट किया था, इस दिशा में सबसे बड़ा कदम था। मुकम्मिल त्राज़ादी की अपनी मांग को दोहराते हुए श्रौर उसको फ़ौरन घोषित किये जाने की मांग को क्रायम रखते हुए, कांग्रेस ने, वात्कालिक समाधान की दिशा में, ऋपना यह प्रस्ताव रखा कि केन्द्र में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी जाय, जिसमें केन्द्रीय धारासभा में चुने गए सभी राजनैतिक तत्वों का प्रतिनिधित्व हो, श्रीर जो प्रांतों के उत्तरदायी शासन के पूरे सहयोग में काम कर सके। वारदोली-प्रस्तावों के द्वारा कांग्रेस ने एक वार फिर समभौते का दर्वाजा खोलने की

कोशिश की । पर श्रंग्रेज़ी सरकार के श्रविश्वास श्रीर संपूर्ण सत्ता को श्रपने हाथों में रखने के हह निश्चय के सामने ये सब प्रयत्न श्रसफल रहे । यह निश्चित है कि युद्ध के दिनों में कांग्रेस श्रपने सिद्धांतों के साथ काफ़ी दूर तक सममौता करने के लिए तैयार हो जाती, पर जहां तक भविष्य का सम्बन्ध है, मुकम्मिल श्राज़ादी के प्रश्न पर वह किसी तरह का समभौता नहीं करेगी । जैसा कि १६४० के रामगढ़-श्रिधवेशन में उसने घोषित किया, ''हिंदुस्तान की जनता संपूर्ण श्राज़ादी से कम कोई भी चीज़ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है । साम्राज्यवाद के ढांचे में हिंदुस्तान की श्राज़ादी की कल्पना नहीं की जा सकती । श्रीपनिवेशिक स्वराज्य, श्रथवा साम्राज्यवादी ढांचे के श्रन्तर्गत किसी श्रन्य प्रकार का विधान, हिंदुस्तान के लिए सर्वथा श्रमुपयुक्त होगा, वह एक महान् राष्ट्र के गौरव के श्रमुक्ल नहीं होगा, श्रीर श्रनेकों प्रकार से हिंदुस्तान को श्रंग्रेज़ी राजनीति श्रीर श्राथिक ढांचे के शिकंजे में जकड़ देगा।'' १६४२ का श्रगस्त-प्रस्ताव, इसी भावना की एक ज़ोरदार उद्घोषणा, था!

कांग्रेस ने त्रारम्भ से ही इस बात से इन्कार किया है कि हमारे देश के शासन-विधान के निर्माण का काम अंग्रेज़ी सरकार पर छोड़ा जा सकता है: . १९३५ के विधान के उसके विरोध का मूल कारण यही था। उसका विश्वास है कि यह काम एक ऐसी भारतीय विधान-निर्मातृ-सभा के द्वारा किया जाना चाहिए, जिसका चुनाव देश के सभी वयस्क व्यक्तियों द्वारा हो । १६३६ के चुनाव-म्रान्दोलन में जवाहरलाल नेहरू ने इस विचार को तेज़ी के साथ देश के कोने-कोने में फैला दिया था : कांग्रेस की चुनाव-घोपणा का भी वह एक महत्त्वपूर्ण त्रंग था। चुनाव जीत लेने के बाद, मार्च १६३७ में, कांग्रेस-कमेटी ने १६३५ के विधान की भत्तीना करते हुए कहा, "जनता ने इस वात की घोपणा भी कर दी है कि वह ऋपना विधान ऋपने-ऋाप बना लेना चाहती है, उस विधान का त्राधार होगा राष्ट्रीय स्वाधीनता, श्रीर उसके बनाने का दायित्व होगा एक विधान-निर्मातृ सभा पर, जिसके निर्माण में देश के सभी वयस्क न्यक्तियों का हाथ होगा।" सच तो यह है कि कांग्रेस ने पद-ग्रहण ही इसलिए किया था कि ''वह मौजूदा विधान को तोड़ दे, श्रीर एक विधान-निर्मात सभा के निर्माण, श्रीर स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए, ज़मीन तैयार करे।" १६३६ के त्रान्त में कांग्रेस की वर्किङ्ग-कमेटी ने इस विचार की कुछ श्रीर विस्तृत व्याख्या की। ऋत्य-संख्यक वर्गों के संबंध में यह तय किया गया कि उसका आधार देश की श्रावादी में इन वर्गों की संख्या के श्रनुपात में होगा, श्रीर यदि ज़ोर दिया गया तो उनके चुनाव में सांप्रदायिक श्राधार भी रखा जा सकेगा । यह सभा

एक ऐसा विधान वना सकेगी जिसमें अल्प-संख्यक वर्गों के अधिकार ऐसे होंगे जो उन्हें तृप कर सकेंगे और इन अधिकारों के संबंध में यदि कोई वात ऐसी हुई जिसपर एक-मत नहीं हुन्ना जा सका तो उसका निर्णय किसी बाहरी शक्ति परः जिसमें दोनों पत्तों का विश्वास हो, छोड़ा जा सकेगा। ।" कांग्रेस-वर्किङ-कमेटी की राय-में ''किसी ग्राजाद देश का विधान बनाने के लिए यही एकमात्र प्रजासत्तात्मकः मार्ग है, श्रीर कोई भी व्यक्ति जो प्रजातन्त्र श्रीर श्राजादी में विश्वास खताः है, इसके विरुद्ध नहीं∖जा सकता ।" कांग्रेस की राय में यह सभा ही ''सांप्रदा∹ यिक ग्रौर दूसरी कठिनाइयों को दूर करने का एक-मात्र साधन" हो सकती है। इसके कुछ ही दिन बाद गांधीजी ने भी विधान-निर्मातृ सभा की इस मांगः को ग्रापना लिया । मार्च १६४० में कांग्रेस ने ग्रापने खुले ग्राधिवेशन में इसका समर्थन किया । श्रगस्त १६४२ के 'खुले विद्रोह' में भी कांग्रेस की दृष्टि विधान-निर्मात सभा पर ही गड़ी थी। जवाहरलाल जी ने वर्किङ्ग-कमेटी के वर्धा-प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए कहा, "हिन्दुस्तान से श्रंग्रेज़ी राज्य के क्रम हो। जाने पर देश के जिम्मेदार व्यक्ति मिल कर एक अस्थायी सरकार का निर्माण कर लेंगे, जिसमें भारतीय जनता के सभी प्रमुख तन्त्रों का प्रतिनिधित्व होगा : श्रीर जो बाद में एक ऐसी योजना बना लेगी जिसके द्वारा विधान-निर्मात सभा का निर्माण किया जायगा, ग्रीर यह सभा भारतीय शासन के लिए एक ऐसा विधान तैयार करेगी, जो देश के सभी वर्गों को मान्य होगा। "

मुस्लिम-लीग द्वारा इस मांग का श्रारम्भ से ही विरोध किया जा रहा था। मि० जिन्ना की राय में यह विधान-निर्मातु-समिति ''कांग्रेस के श्रादमियों से भरी हुई श्रीर एक छोटे से दल के इशारे पर काम करने वाली' होगी। ग्रंग्रेज़ी सरकार ने श्रपनी श्रगस्त १६४० की घोषणा में मान लिया था कि 'नये विधान के बनाने के लिए युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिक भारतीय संस्था का निर्माण श्रावश्यक होगा, श्रीर इस बीच श्रंग्रेज़ी सरकार उन प्रयत्ने का स्वागत, श्रीर उनसे पूरा सहयोग करेगी, जो विधान बनाने वाली इस संस्था की रूपरेखा श्रीर कार्य-पद्धति के संबंध में देश में एक-मत बनाने की दिशा में किये जायंगे।'' परन्तु इस संस्था (constitution-making body) में श्रीर कांग्रेस द्वारा जिस विधान-निर्मातृ सभा (Constituent Assembly) की मांग की जा रही थी उसमें जमीन श्रास्मान का श्रन्तर है । एक प्रतिनिधि भारतीय समाद्वारा, जिसके चुनाव श्रीर श्रिषकार के प्रश्न श्रमी श्रानिश्चित थे, शासन-योजना का निर्माण एक बात है, श्रीर भारतीय जनता द्वारा चुनी गई विधान निर्मातृ सभा द्वारा, जिसके पास श्रन्तम सावे भी सत्ता हो, इस योजना का निर्मारिक सभा द्वारा, जिसके पास श्रान्तम सावे भी सत्ता हो, इस योजना का निर्मारिक

ंकिया ःजाना "विल्कुल व्हूसरी वात है। किप्स-प्रस्तावों में श्यंग्रेज़ी-सरकार एक क्तदमः आगे बढ़ी है। क्रिप्स ने अपनी योजना में एक विधान वनाने वाली स्सभा को िज़क किया है, पर वह काँग्रेस की कल्पना के अनुसार देश के सभी वयस्क व्यक्तियों द्वारा सीधे चुनाव द्वारा बनाई जाने वाली सभा नहीं है, उसका िनर्माण प्रांतीयः धारा-सभाश्रों द्वारा श्रप्रत्यक्त चुनाव के द्वारा होगा। श्रप्रत्यक्त रूप से ही सही, पर जनता द्वारा चुनी गई विधान-निर्मातृ सभा के सिद्धान्त की ्मानःकरः श्रंगेज़ीः सरकार ने प्रगट-रूप से जो एक श्रागे की तरफ क़दम उठाया ्या, वह उसः सभा में देशीः राज्यों के ऐसे प्रतिनिधियों की स्थान देकर, जिनके ्चुनाव में :जनता ःकी इच्छा-ग्रानिच्छा पर ेबिल्कुल ज़ोर नहीं दिया गया था, म्ब्रप्रत्यच्-रूप से उसे पीछे खींच लेने के समान था । किप्स-प्रस्तावीं की ब्रस्वी-्कृत करते 'हुए कांग्रेस की वर्किङ्ग-कमेटी ने कहा, ''विधान-निर्मातृ समा का िनर्माण भी अकु ऐसे दक्क से प्रस्तावित किया गया है, जिसमें जनता के आत्म-। निर्णय के अधिकार के अप्र-प्रतिनिधि तन्वों के द्वारा अतिक्रमण् किये जाने का ्डर है। '' अंग्रेज़ी सरकार ने व्यह तो मान लिया है कि हिन्दुस्तान का भावी ्शासर्न-विधान हिन्दुस्तानियों के द्वारा ही वनाया जायगा, पर ग्रमी भी । विधान-निर्मातृ : सभा के सम्बन्ध में कांग्रेस की मांग की, वैसे-का-वैसा ही, श्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

जनता द्वारा सीधे खुनी गई इस प्रकार की विधान निर्मातृ समा के विरोध में बहुत-सी बाँते कही जाती हैं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस द्वारा प्रस्ता वितः यह योजना अल्प-संख्यक वर्गों को मान्य नहीं है । मुस्लिम लीग तो प्रारम्भ से उसका विरोध कर ही रही है, परन्तु अल्प अल्प-संख्यक वर्ग भी उसके सम्बन्ध में उत्साही नहीं हैं। यह सच है कि कांग्रेस ने गीण प्रश्नों के संबंध में सममीते के मार्ग पर ज़ोर दिया है, पर इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि बड़े वहें प्रश्नों के संबंध में बहुमत का निर्णय ही मान्य रहेगा। मुस्लिम-लीग इस सम्बन्ध में सहमत होने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि केवल इस विधान-निर्मातृ समा के निर्माण का आधार देश के सभी वयस्क व्यक्तियों तक फैला देने से यह समस्या सुलभ जायगी: बहुत सम्भव है कि इस प्रकार के विस्तार से वह और उलभ जाय। मताधिकार की परिधि जितनी व्यापक बनाई जायगी, वे पढ़े-लिखे किसान और मज़दूर उसके अन्तर्गत आते जायंगे, और इसका नतीजा यही हो सकता है कि वे अपने को कुछ प्रभावशाली राजनैतिक नेताओं और दलों के हाथ में कठपुतली वना लेंगे। हिन्दू जनता सम्भवतः कांग्रेस की और सुकेगी, और मुसल्मान लीग की ओर।

ऐसी स्थित में इन दोनों दलों की शक्ति के अनुपात में विशेष अन्तर नहीं श्राएगा, श्रीर चुनाव के चोत्र को इतना विस्तीर्ण करने पर खर्च किया गया रुपया ग्रौर शक्ति न्यर्थ जायगी। सांप्रदायिक समस्या उससे तनिक भी न सुलभेगी । कांग्रेस मुसल्मान सदस्यों के चुनाव में सांप्रदायिक ग्राधार की मान लेने के लिए भी तैयार है, ऐसी स्थित में तो यही होगा कि जनाव में १० या १५ करोड़ व्यक्ति हिस्सा लें सकेंगे—पर समभौता करने में हम उतने ही ऋसमर्थ होंगे जितने ग्राज हैं। संघर्ष में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए ग्रपने ग्रन्यायियों की संख्या वढा लेना समभौते की दिशा में कभी सहायक नहीं होता है। यह भी कहा जाता है कि विधान-निर्मात-सभा की यह कल्पना उस समय चाहे व्यवहार-संगत रही हो, जब सांप्रदायिक वैपम्य इतना तीव नहीं था, पर ज्याज की रिथित में तो वह विलक्षल ही ऋन्यवहार्य है। इस संबंध में एक ऋौर वात यह कही जाती है कि विधान के निर्माण का काम श्रनुभवी जानकारों का है, जनता का नहीं, ग्रौर इन व्यक्तियों की संख्या जितनी कम हो, उतना ग्रन्छा है। सर मॉरिस ग्वायर ने बनारस विश्व-विद्यालय के दीक्वांत भाषण में कहा था-''(एक ऐसी छोटी सभा में) सदस्य एक दूसरे को श्रच्छी तरह से जान जाते हैं, दूसरों के अञ्छे गुणों को पहिचानने लगते हैं, श्रीर अपनी किमयों से भी अनिभन्न नहीं रहते । मस्तिष्कों के संघर्षण की प्रतिकिया होती ही है, श्रौर कुछ समय के बाद...। एक समिष्ट की भावना जन्म लेती है, ऋौर उसमें से यदि एक सामान्य इच्छा-शिक्त उत्पन्न न भी हो तो रचनात्मक निर्णयों के लिए एक सामान्य-इच्छा तो जागत हो ही जाती है।" श्रपने इस दीचान्त भाषण में विद्वान न्यायाधीश ने यह भी वताया कि जहां कहीं व्यापक मताधिकार के ख़ाधार पर विधान-निर्मातृ सभा का चुनाव हुत्रा है, उसे अपने कार्य में असफलता मिली है। १७६५ के कान्तिकारी फांस में ६०० सदस्यों की राष्ट्रीय सभा (NationalConvention)द्वारा वनाये हुए विधान ने नैपोलियन स्त्रौर वीस वर्षों के युद्धों का स्वागत किया; १८४८ के प्रजातन्त्रात्मक फ्रांस में ६०० सदस्यों की विधान-निर्मातृ सभा ने 'दूसरे साम्राज्य' ग्रौर फ्रांस के पतन की. सृष्टि की।

1—रायटर के राजनैतिक संवाददाता को १६ नवम्बर १६४४ को दिये गए एक इयटरव्यू में श्रो० लास्की ने कहा कि यह विधान-निर्मात सभा (१) छोटी हो, और (२) श्रमरीका का विधान बनाने वाली क्रिलाडे हिक्कया की सभा के समान श्रपनी बैठकें गुष्त रखे, क्योंकि यदि उसकी सारी कार्यवाही खुले श्रधि-वेशन में हुई, श्रीर उसमें श्रावेशपूर्ण वाद-विवाद रहे तो उसे श्रपने कार्य में सफलता श्रष्त करने की उम्मीद कम ही रखना चाहिए। १८४८ की जर्मन राष्ट्रीय सभा, जिसमें ५०० सदस्य शामिल थे, ब्रापने काम में ब्रासफल रही। १६१६ की वाइमार की सभा भी, जिसमें ४२० सदस्य उपस्थित थे, किसी स्थायी विधान की नींव नहीं डाल सकी। रूस की विधान- निर्मातृ सभा, जिसका चुनाव ४॥ करोड़ व्यक्तियों के द्वारा हुक्रा था, केवल एक बार मिल सकी। इसके विपरीत, जितने स्थायी शासन ब्राय तक बने हैं, वे सब थोड़े लोगों के द्वारा बनाये गए थे, जिनका चुनाव व्यापक जनता के द्वारा नहीं, ब्रापनी धारासभाद्रों ब्राथवा सरकारों के द्वारा हुक्रा था। फिलाडेल्फिया की जिस सभा ने ब्रामरीका का शासन-विधान बनाया उसमें ३० सदस्यों से ब्राधक ने भाग नहीं लिया। कनाडा का विधान जिन दो सभाक्रों में बना उसमें कमशः २२ ब्रीर ३३ सदस्य शामिल थे। ब्रास्ट्रेलिया ब्रीर दिच्छा ब्राफ्नीका का विधान कमशः ५० ब्रीर ३० व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया। सोवियट रूस का वर्तमान विधान केवल ३१ व्यक्तियों ने बनाया। इन सब सभान्त्रों में सारी कार्यवाही गुप्त रखी गई थी।

ये सब तर्क, ऊपर से देखने से, काफ़ी प्रभावशाली दिखाई देते हैं। पर, उनका आधार सच को छिपा लेने और फूठ पर ज़ोर देने में है। अंग्रेज़ी सर-कार द्वारा मानी गई विधान-निर्मातृ सभा ऋौर कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित विधान-निर्मातृ सभा में मुख्य अन्तर यह नहीं है कि एक में सदस्यों की संख्या कम और उसकी कार्यवाही गुप्त रखने पर ज़ोर दिया गया है, श्रौर कांग्रेस का विश्वास एक बहुत बड़ी ऋबाध, ऋनियंत्रित सभा में है जो [हर दलील पर लड़ने श्रौर भगड़ने के लिए तत्पर हो : कांग्रेस ने न तो वहीं उस सभा की बड़ी संख्या का ज़िक किया है, श्रौर न उसकी कार्यवाही के गुप्त रखने से श्रपना विरोध प्रगट किया है। इन दोनों प्रस्तानों में मुख्य ऋन्तर यह है कि सरकार उसके चुनान का त्राधार बहुत संकृचित रखना चाहती है, श्रीर कांग्रेस चाहती है कि उसके पीछे हर वयस्क हिंदुस्तानी का नैतिक वल हो । मौलिक श्रन्तर प्रजातन्त्र के सिद्धांतां में श्रविश्वास श्रौर उनके प्रतिपादन का है। सरकार मताधिकार के दायरे को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो उसमें जनता की त्रपार शिक्त के उभड़ त्राने का डर है, कांग्रेस उस शिक्त को उभाइना, न्त्रीर उसके व्यापक न्त्राधार पर देश के मावी शासन-विधान की प्रस्थापित करना, चाहती है। प्रजातन्त्र में इसके त्रालावा दूसरा मार्ग नहीं है। यदि हमें एक प्रजातन्त्र-शासन की नींव डालना है, तो उसके निर्माण की मशीनरी भी प्रजातन्त्रात्मक ही होनी चाहिए । जिन स्थायी शासनों की गराना सर मॉरिस ग्वायर ने श्रपने उपर्युक्त भाषण में की है, उन सबका निर्माण प्रजातन्त्र की

शांक्तियों के द्वारा हुआ। विधान-निर्मातृ सभा को चुनने के साधारगतः दो मार्ग हैं—एक सीधे चुनाव का, जिसका अवलंबन आस्ट्रेलिया, जर्मनी, आस्ट्रिया, श्रायलैंएड श्रीर मध्य श्रीर पूर्वी यूरोप के कई श्रन्य राज्यों में किया गया, श्रीर दुसरा,राजनैतिक इकाइयों की धारा-सभाग्रों के द्वारा, जैसा कि ग्रमरीका, दक्तिण ग्रफ्रीका ग्रादि में हुग्रा। दोनों का ग्राधार प्रजातन्त्र के सिद्धांतों में है। जिन देशों में प्रांतीय धारा-समात्रों द्वारा विधान-निर्मात सभा का चुनाव हुन्ना है, उन सबमें ये धारा-सभाएं जनता को मिले हुए व्यापक मताधिकार पर ही क्षायम थीं, हमारे देश के समान यह मताधिकार सीमित ग्रीर संकुचित नहीं था। यदि श्राज भी हमारी प्रांतीय धारा-समाश्रों के चुनाव में भाग लेने का श्राधकार प्रांत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मिल जाय तो मुक्ते पूरा विश्वास है कि कांग्रेस विधान निर्मातृ सभा के ग्राप्रत्यन्त चुनाव के सिद्धांत को भी मान लेगी। साथ ही, यह भी श्रावश्यक होगा कि देशी राज्यों से श्राने वाले सदस्य, उसी व्यापक श्राधार पर, उन राज्यों की जनता द्वारा चुने जायं। यह मान लेना कि विधान बनाने का काम केवल बहुत बड़े विद्वानों, ग्रथवा योग्य राजनैतिक नेतात्रों का है, चाहे उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त न हो, एक मिथ्यात्व को प्रश्रय देना है। जय तक वे जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति न हों, उनके द्वारा बनाये गए विधान का मूल्य, चाहे वह विधान कितना ही वैज्ञानिक ख्रौर विद्वत्तापूर्ण तरीके से क्यों न वनाया गया हो, कौड़ी वरावर भी नहीं है। उसकी मेहनत वैसे ही वेकार जायगी जैसी १६३५ के विधान बनाने वाली गोलमेज परिप्रदों, संयुक्त पार्लमेयटरी कमेटी स्त्रादि की। सप्र-कमेटी में विद्वानों की कमी नहीं थी, पर उनके जनता द्वारा चुने गए न होने के कारण उसके सुमान बहुत-कुछ वे-मानी से हैं। जहां तक इस विधान-निर्मातृ सभा के सदस्यों की संख्या का सवाल है, यदि वह संख्या बहुत बड़ी भी हुईं, तो हमें यह बात ध्यान में रखना है कि वह श्रपना काम खुले श्रिधिवेशनों में कम ही करेगी, कमेटियों के द्वारा श्रिधिक। कभी-कभी तो प्रमुख व्यक्तियों को भी यह काम सींप दिया जाता है। विभिन्न राजनैतिक दल तो अपनी-अपनी योजनाएं इस सभाके सामने पेश करते ही हैं। कमेटियों का काम इन विभिन्न योजनात्रों का ग्रध्ययन करना होगा, ग्रौर इन सव कमेटियों के काम को समन्वित करने का दायित्व भी एक कमेटी पर ही रखा जा

१-जैसे जर्मनी में इ्यूगो प्रियूस को, व जेकोस्लोवाकिया में प्रो० जीरी होयकोज को यह काम सींपा गया था।

२-फ़िलाडेरिफ़या समा के सामने रैंडोर्ल्फ-योजना श्रीर पैटर्सन योजना श्रादि रखी गईं, श्रीर कनेक्टीकट समकौते के रूप में उन्हें समन्वित किया गया। सकता है। विधान-निर्मातृ सभा के खुले ऋधिवेशन में तो प्रायः यही होता है कि उसकी किसी एक बैठक में विधान-निर्माण के ऋधिर-भूत सिद्धांतों को मान लिया जाता है, ऋौर वाद की बैठकों में केवल कमेटियों की सिफ़ारिशों पर चर्ची भर होती है। इन कामों में सभा के सदस्यों की संख्या ऋधिक होने से कोई वाधा उपस्थित नहीं हो सकती। सच तो यह है कि विधान की स्वीकृति का ऋाधार जितना न्यापक होगा, उसे उतना ही ऋधिक स्थायित्व मिल सकेगा।

विधान-निर्मातृ सभा के वन जाने पर अपनी कार्य-पद्धित के सम्बन्ध में निर्ण्य करने का अधिकार उसी को होगा। वह स्वयं अपना सभापित चुनेगी, विधान के आधार-भूत सिद्धांतों का निश्चय करेगी, और वैधानिक प्रश्नों के अध्ययन के लिए विभिन्न समितियों की स्थापना करेगी। हमारे भावी विधान की रूपरेखा संघ-शासन के सिद्धांत पर वनेगी अथवा केन्द्रीभूत-शासन के, इसका निर्ण्य विधान-निर्मातृ सभा ही करेगी। केन्द्र और प्रांतों के वीच सत्ता का वंटवारा किस प्रकार होगा, शासन के विभिन्न भागों के आपसी संबंध क्या होंगे, मताधिधिकार किन लोगों को दिया जायगा, चुनाव की पद्धित क्या होगी, अर्थनीति पर किन नियंत्रणों की सृष्टि करना आवश्यक होगा, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिनका निर्ण्य विधान-निर्मातृ सभा ही करेगी। वह विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए कमेटियां नियुक्त करेगी, संभव है उनकी रिपोटों में सामंजस्य लाने के लिए भी एक कमेटी नियुक्त कर दे, और उनकी रिपोटों पर विचार करेगी, और इस अध्ययन और अनुशीलन, विचार-विनिमय और वाद-विवाद के वाद विधान को

१—में समकता हूँ कि विधान-निर्मातृ-सभा के निर्माण का श्राधार भारतीय एकता पर ही होना चाहिए। सारा देश मिल कर उसे चुने। उसमें प्रतिनिधित्व भारतीय जनता का हो, न कि विभिन्न प्रांतों का। प्रांतीय श्राध्म-निर्याय के श्राधार पर एक संघ-शासन के निर्माण का पूरा श्राधकार तो उसे होगा ही, भारतीय एकता से चलकर प्रांतीय-स्वराज्य की श्रोर श्रप्रसर होना ही हमारी परि-स्थितियों के श्रनुकृत है भी। यदि श्रारम्भ में ही प्रांतों को स्वतन्त्र राजनैतिक हकाई मान लिया गया, श्रीर इस श्राधार पर विधान-निर्मातृ सभा का चुनाव हुआ, तो उसके कार्य में श्रकेन्द्रीकरण श्रीर विश्वंत्रलता के तत्वों के चहुत प्रयल बाधा बन जाने का भय है। प्रांतीय श्राध्म-निर्णय श्रीर, एक काफ़ी दूर तक श्रकेन्द्रीकरण, की श्रावश्यकता को मानते हुए भी हमें भारतीय एकता पर उसे तरजीह नहीं देना है। श्रीर जबिक प्रांतीय सीमाझों का प्रनिर्माण विधान-निर्मातृ सभा का एक मुख्य कार्य होगा, तब तो वर्त्तमान प्रांतों के श्राधार पर उसका चुनाव करना घोड़ के श्रागे गाड़ी को जोड़ने के समान होगा।

श्रन्तिम स्वीकृति देना भी उसी के श्रिधिकार में होगा । श्रिपने इस कार्य में वह श्रन्य देशों की विधान-निर्मातृ सभाश्रों के श्रानुभवों से भी पूरा लाभ उठायगी। इस सभा के द्वारा बनाया श्रीर स्वीकृत किया गया विधान ही समस्त भारतीय जनता के लिए मान्य होगा।

विधान-निर्मातृ सभा के सम्बन्ध में दो श्रन्य शंकाश्रों का स्वधीकरण भी श्रावश्यक है। एक तो यह माना जाता है कि जब तक देश भर में मूल-भूत सिद्धांतों के संबंध में समभौता न हो जाय, तब तक विधान-निर्मातृ सभा को अपने कार्य में सफलता मिलना असंभव ही होगा । प्रो॰ कृपलैएड के शब्दों में, ''मतदातात्रों की एक बहुत बड़ी संख्या राजनैतिक दलों श्रीर सादे नारों की दया पर निर्भर रहेगी । करोड़ों मत 'गांधी श्रौर पीली पेटी' या 'इस्लाम खतरे में' के नाम पर पड़ेंगे ।...सच तो यह है कि जब कि मतदातास्त्रों के नाम दर्ज करने श्रीर उनके मत देने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करने का काम समाप्त हो जायगा तव पता यही लगेगा कि यह काम तो, विना श्रिधिक महनत या खर्च के, मौजूदा व्यवस्था के द्वारा भी किया जा सकता था। ठोस अन्तर केंवल यही होगा कि मतदातात्रों की संख्या बहुत बढ़ जायगी ।....क्या इससे वैधानिक समाधान की प्राप्ति हो सकेगी ? उसे प्राप्त करने का तो एकमात्र रास्ता समभौते का है, श्रीर लड़ने वाले नेताश्रों के जनता को श्रपने पीछे ले श्राने से उसमें सहायता पहुंचना संभव नहीं है।" इं डॉ॰ बेनीप्रसाद ने लिखा— "जहां तक मुख्य राजनैतिक प्रश्नों के निर्ण्य का सवाल है, विधान-निर्मातृ सभा की स्थापना के पत्त में दलीलें तो वहुत प्रवल हैं, परन्तु जव तक संयुक्त निर्वाचन के ब्राधार पर पहिले से कोई समभौता नहीं हो जाता, तबतक इस पद्धति को अपनाना बहुत ही ऋधिक ख़तरनाक सिद्ध होगा।"" दूसरी बात इस संबंध में यह कही जाती है कि हमारी सांप्रदायिक समस्या को सुलभाने में भी विधान-निर्मातृ सभा के सफल होने की ख्राशा कम ही है, ख्रीर यदि सांप्रदायिक चुनाव की इजाज़त दे दी गई, जिसके लिए कांग्रेस तैयार जान पड़ती है, तब तो उससे हिंदू-मुस्लिम बैमनस्य के ख्रीर भी ज़्यादा बढ़ जाने का डर है। डॉ० वेनीप्रसाद के शन्दों में, ''विधान-

१-विस्तृत अध्ययन के लिए देखिये-

एन॰ गांगुली : Constituent Assembly for India. राममनोहर लोहिया : Constituent Assembly.

२–प्रो॰कृपलैंस: The Constitutional Problem of India, भाग ३, पृ॰ ३४-३४ ।

३-डा॰वेनीप्रसाद : Hindu Muslim Questions, पृ० १६७।

निर्मातृ सभा का काम विधान का निर्माण करना है, न कि सांप्रदायिक विषम-तास्रों का इलाज करना ।"

इन ज्यालोचनात्र्यों के पीछे एक ज्योर तो प्रजातन्त्र की शिक्तयों से भय की वृत्ति है, श्रौर दुसरी श्रोर यह गुलत मान्यता है कि हमारे श्राज के राजनैतिक दल देश की जनता का सचा प्रतिनिधित्व करते हैं त्र्रथवा, गहराई में जाकर, त्रपने भविष्य के संबंध में हम एकमत नहीं हैं। प्रजातन्त्र की शिक्तयों को उभाइना सोते हुए सांप को जगाने के समान ख़तरनाक तो है, पर जिस राज-नैतिक विधान की बुनियाद प्रजातन्त्र-रूपी शेषनाग के सहस्र-सहस्र फनों पर प्रस्थापित नहीं होती, विदेशी तलवार, या मशीनगन, या परमाग्रा वम पर रखी जाती है, वह आंधी में तिनके के समान उड़ जाया करता है। हमें तो जनता की इन शिक्तयों को जागृत करना है, श्रीर राजसत्ता के धारा-प्रवाह को उस जागृति के सशक्त स्रोत से संबद्ध करना है। ऐसी स्थिति में उस शक्ति से डर कर काम कैसे चलेगा ? विधान-निर्मातृ सभा के लिए जवाहरलालजी ने एक बार कहा था, "इसका ऋर्य जनता के एक समूह से नहीं है, न क़ाविल क़ानूनदानों की एक जंमात से, जो विधान को बनाने के निश्चय से इकडा हुए हों। इसका ऋर्थ तो एक राष्ट्र से है, जो अपने लद्य तक पहुँचने के लिए चल पड़ा हो, श्रीर जो श्रपने पुराने राजनैतिक, श्रीर संभवतः सामाजिक, ढांचे के ख़ोल को फाड़ फेंकना चाहता हो । इसका अर्थ है देश की जनता का, अपने चुने हुए प्रांत-निधियों के द्वारा, एक बड़े काम में जूभ पड़ना।" दूसरी ग़लत धारणा जो इस प्रयोग के स्त्रालोचकों के मन में है, वह यह है कि कांग्रेस स्त्रीर मुस्लिम-लीग, त्र्यथवा भारतीय राष्ट्रीयता श्रौर मुस्लिम-सांप्रदायिकता, का वर्त्तमान श्रन्तर बहुत गहरा है, ऋथवा देश की मुसल्मान जनता भी सांप्रदायिकता में उतनी ही रंगी हुई है जितनी मुस्लिम-लीग श्रौर उसके प्रमुख नेता । यह मानना वस्तु-स्थिति की गहराई में जाने से इन्कार करना है। सांप्रदायिक संघर्ष देश के एक वहत छोटे तबक़े तक, शहरों की मध्य-श्रेगी के एक वहें श्रंश तक, ही सीमित है। देश की जनता के सामने मुख्य प्रश्न सरकारी नौकरियां प्राप्त करने, श्रथवा ह्योटे-मोटे त्रार्थिक संघर्ष में पड़ने त्रथवा धारा-सभात्रों में घुसने का नहीं है, राज-नैविक आज़ादी हासिल करने, और अपनी ग़रीवी, अधनंगापन और मुखमरापन, दूर करने का है। यह भावना, जंगल में फैल जाने वाली त्याग की लपटों के समान, स्राज देश के कोने-कोने में फैली हुई है। उसे बुकाया नहीं जा सकता, द्याया नहीं जा सकता, कुचला नहीं जा सकता। वर्त्तमान को भरमतात करने. स्वाधीनता त्रीर त्रात्म-गौरव के त्राधार पर एक सोनहले भविष्य को निर्माण

करने के उसके निश्चय को रोका नहीं जा सकता । हमारी विधान-निर्मातृ सभा इस निश्चय का प्रतीक होगी । सांप्रदायिक संघर्ष के परे उसका स्थान है । सांप्र-दायिक कलह की भावना जो ब्राज एक धूमकेतु के समान हमारे समस्त राज-नेतिक जीवन पर ब्राकान्त है, देश की व्यापक जनता के संपर्क में ब्राकर पानी के बुदबुद के समान मिट जायगी । मेरा तो निश्चित विश्वास है कि हमारी सांप्र-दायिक समस्या का एकमात्र हल विधान-निर्मातृ सभा ही है ।

संघि और स्थायी विधान

ऊपर इस बात की चर्चा त्राचुकी है कि हिन्दुस्तान का भावी शासन-विधान वनाने के जो दो तरीक़े हो सकते हैं-एक अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा उस विधान का निर्माण श्रीर स्वीकृति, श्रीर दूसरा हिन्दुस्तान की जनता द्वारा चुनी गई विधान-पंचायत के द्वारा उसका निर्माण — उनमें से दूसरा तरीका ही श्रव संभव रह गया है। परन्त, विधान-पंचायत के द्वारा इस प्रकार का विधान यन जाने के बाद भी श्रंग्रेज़ी सरकार के साथ एक संधि की गुंजाइश तो रह ही जाती है। त्रायलैंड का उदाहरण हमारे सामने है। श्रंग्रेज़ी सरकार ने १६१४ में, लॉयड जॉर्ज की प्रेरणा से, आयर्लैंग्ड के लिए एक विधान बनाया था, जिसके अनुसार उसे दो भागों में बांट देने का आयोजन था, इन दोनों भागों को समन्वित करने के लिए एक संघीय समिति बनाने का प्रस्ताव था, श्रीर रचा श्रीर विदेशी नीति स्नादि महत्त्वपूर्ण विभाग स्रंग्रेज़ी सरकार के नियंत्रण में ही रखने का विचार था । श्रायलैंड की जनता ने इस विधान का वहिष्कार कियां, श्रीर चुनाव में भाग लेने व श्रंग्रेज़ी श्रधिकारियों की श्राज्ञा मानने से कर्तई इन्कार कर दिया। अप्रेज़ी सरकार ने कौमी आज़ादी के इस आन्दोलन को पहिले तो क्रचलने की चेष्टा की, पर, जब वे उस चेष्टा में सफल न हो सके तो, १६२१ में, संधि-चर्चा आरम्भ की। अंग्रेज़ी मंत्रिमएंडल के कुछ व्यक्तियों और आयर्लैंड की प्रजातन्त्र-पार्लमेएट (Dail Eireann) के उतने ही सदस्यों में बातचीत हुई , श्रीर उसके परिगाम-खरूप एक संधि-पत्र पर हस्ताचर किये गए, श्रीर बाद में इंग्लैंड श्रीर श्रायलैंड दोनों देशों की पार्लमेएटों ने उसे स्वीकार कर लिया। संभवतः यही उदाहरण अंग्रेज़ी-मंत्रिमंडल के सामने था, जब उसने किप्स-प्रस्तावों के द्वारा, हिन्दुस्तान के साथ भी इसी प्रकार की एक संधि का प्रश्न उठाया था। श्रुं प्रेज़ी सरकार श्रौर विधान-समिति (Constitutionmaking body) के बीच एक संधि पर इस्ताच्चर किये जाना किप्स-योजना को ग्रमल में लाने के लिए एक ग्रावश्यक शर्त मानी गई थी। इस संधि में उन सब त्रावश्यक बातों के शामिल किये जाने पर जोर दिया गया था, जिनका

संबंध हिन्दुस्तानियों के हाथों में राजसत्ता के सौंपे जाने, श्रौर विशेषकर जातीय श्रौर धार्मिक श्रत्पसंख्यक वर्गों के संरक्त्या, से हो।

ं किप्स द्वारा प्रस्तावित संधि एक बहुत ही ऋसंतोषजनक सुभाव है : वह हिन्दुस्तान की त्राज़ादी पर एक प्रतिवन्ध के रूप में पेश किया गया था। उसका त्राधार इस विश्वास में है कि हिन्दुस्तान त्रीर इंग्लैंड सदा ही एक निकट-संबंध में बंधे रहेंगे। ऋल्पसंख्यक वर्गों को भी जिन संरक्ष्णों के दिये जाने का प्रस्ताव है, उनका स्त्राधार ऋंग्रेज़ी सरकार द्वारा समय-समय पर किए गये वायदों में है। त्रायलैंड के साथ की जाने वाली १६२१ की संधि का त्राधार भी परावलंबन की इस भावना में था, श्रीर इसी कारण वह सफल नहीं हो सकी। श्रगले दस वर्षों में उसमें लगातार परिवर्त्तन होते रहे, श्रीर १६३२ में जब डी वैलेरा के हाथ में सत्ता ख्राई, उन्होंने इस संधि को उठा कर एक ख्रोर रख दिया, श्रीर, व्यावहारिक दृष्टि से, श्रायलैंड को पूर्ण स्वतन्त्र वना लेने का निश्चय कर लिया । १६३७ के नये शासन-विधान के ऋनुसार तो ऋायलैंड ने इंग्लैंड से संबंध-विच्छेद ही कर लिया है। ' यही बात हिन्दुस्तान के साथ की जाने वाली संधि के संबंध में कही जा सकती है। कोई भी ऐसी संधि जो हिन्दुस्तान की सार्वभौमता पर किसी प्रकार का नियन्त्रण लगाती हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती। जहां तक ऋल्पसंख्यक वर्गों के संरत्त्वण का प्रश्न है, उसका एकमात्र रास्ता इन संरक्षणों की हमारे भावी शासन-विधान में संश्लिष्ठ कर देने, पिरी देने, का है, किसी विदेशी शासन की कृपा और नीति पर वे नहीं छोड़े जा सकते। हमारे और इंग्लैंड के बीच की जाने वाली संधि में देश के आन्तरिक प्रश्नों के संबंध में कोई बात नहीं होगी । उसमें हिन्दुस्तान ग्रीर इंग्लैंड के ग्रापसी संबंधों, श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत में इन संबंधों की स्थिति, का स्पष्टीकरण होगा। श्रान्तरिक प्रश्नों को नित्रदाने का सर्वाधिकार स्वयं हमें होगा—सांप्रदायिक ग्रीर श्रिंगल-संख्यक वर्गों से संबंध रखने वाले सभी प्रश्न इसी कीटि में त्राते हैं। इसके श्रलावा, हिन्दुस्तान श्रीर इंग्लैंड के कुछ श्रापसी न्यापारिक संबंध हो सकते हैं, जिनकी व्याख्या इस संधि में की जा सकेगी—हिन्दुस्तान ग्रांग्रेज़ी माल की खपत के लिए कुछ सुविधाएं दे सकता है वशर्ते कि उसे इंग्लैंड से अपने श्रीचोगीकरण . १-विधान वेचाओं में इस सम्बन्ध में मतभेद था कि युद्ध के धवसर पर श्रायलैं यह इंग्लैंड से श्रलहदा श्रपनी कोई नीति वना पाएगा श्रथवा नहीं, पर दसरे महायुद्ध में, बड़ी कठिन परिस्थितियों के बीच. अपनी तटस्थता की रहा करके उसने इस महत्वपूर्ण चेत्र में भी श्रपनी पूर्ण स्वतन्त्रता का परिचय

दिया है।

में कुछ विशेष सहायता मिल सके। इसी प्रकार दृष्टिकोण अथवा स्वार्थों की सामान्यता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हिन्दुस्तान और इंग्लैंड के बीच एक समभौते की कल्पना तो की ही जा सकती है। ये सब प्रश्न उस संधि में स्पष्ट किये जा सकेंगे।

हिन्दुस्तान श्रीर इंग्लैएड के बीच की इस संधि के संबंध में दो वार्ते हमें ग्रपने ध्यान में रखनी हैं। एक तो यह कि वह संघि देश की सार्वभौमता पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो । ग्रान्तरिक व्यवस्था संबंधी प्रश्नों, ग्रथवा विदेशी श्राक्रमणों से देश की रत्ता के प्रश्न, में यदि हमने किसी भी श्रंश में इंग्लैएड पर निर्भर होना स्वीकार कर लिया तो हमारी ऋाजादी एक वे-मानी सी चीज़ हो जायगी। उस संधि की पहिली शर्त्त यही होगी कि वह हिन्दुस्तान के स्वार्थों को पहिला स्थान देगी, श्रीर उसका श्राधार हिन्दुस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता में होगा । संघ-शासन के विभिन्न सदस्यों ग्राथवा देश के विभिन्न धर्मावलंतियों के ग्रापसी संबंध निश्चित करने ग्रथवा उनके मतमेदों को सलमाने का प्रयत्न विधान के द्वारा किया जायगा । वह एक विदेशी सरकार के साथ सन्धि का विपय नहीं है । दूसरी वात यह है कि उस संधि में संशोधन-परिवर्त्तन ग्रादि के लिए पर्यात सुविधा होनी चाहिए। समय ऋौर परिस्थितियों के साथ इस प्रकार के परिवर्त्तन त्रावश्यक होंगे । संभव है कि त्राज हम प्रजातन्त्र त्रीर फ़ासिज्म के किसी संघर्ष में इंग्लैएड का साथ देना मंज़्र करलें, पर कल यदि साम्राज्यवादी इंग्लैएड, अन्य साम्राज्यवादी देशों के साथ के हमारे पड़ोसी राष्ट्रों को, जिनके स्वार्थ हमारे ऋपने स्वार्थ हों, कुचलने के लिए तैयार हो जाय, तो हम उसके प्रति श्रपनी नीति में परिवर्त्तन करना चाहें। संधि की शत्तों के संबंध में यदि दोनों देशों में मतभेद हो तो उसका निर्णय करने, श्रीर उस निर्णय पर दोनों देशों को ग्रमल करने के लिए बाध्य करने, का श्रिधिकार किसे हो, यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए । यह ऋधिकार उस समय की किसी सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को ही दिया जा सकता है।

मैं समभता हूँ कि सिन्ध ग्रीर विधान-निर्माण के प्रश्नों की ग्रलग-ग्रलग रखना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। संधि का संबंध हमारे ग्रीर इंग्लैएड के बीच का होगा। विधान हमारे ग्रान्तरिक प्रश्नों को सुलभाने की दिशा में एक वड़ा प्रयत्न होगा। यह भी हो सकता है कि विधान-निर्मातृ समा पहिले विधान बना ले, ग्रीर इंग्लैएड के साथ सिन्ध के प्रश्न को उस विधान द्वारा बनने वाली सरकार पर छोड़ दे, पर यह कुछ ग्रन्यावहारिक-सा दिखाई देता है, क्योंकि जब तक सार्वभीम-सत्ता ग्रंग्रेज़ों के हाथों से निकल कर विधान-निर्मातृ

सभा के हाथ में नहीं त्रा जाती है, तब तक उसके द्वारा किसी स्थायी सरकार के बनाये जाने का प्रश्न कुछ स्रवास्तविक-सा लगता है, स्रीर यह सत्ता का स्राधार-परिवर्त्तन सन्धि के द्वारा ही संभव है। संधि के बाद ही विधान निर्मातृ सभा को यह त्र्राधिकार प्राप्त हो जायगा कि वह देश के लिए एक शासन-विधान वना ले । विधान-निर्मातृ-सभा का वास्तविक कार्य तभी ख्रारंभ होगा, ख्रौर वह एक महान् दुस्तर कार्य होगा, इसमें तो संदेह है ही नहीं। विधान-निर्मातृ-सभा को ही यह तय करना होगा कि हमारा विवान संघ-शासन के स्त्राधार पर वने स्रथवा केन्द्रीभृत शासन उसका लच्य हो, उसका संगठन पार्लमेएटरी पद्धति पर हो ऋथवा प्रेज़ीडेंटी ढङ्ग से, उसमें सभी प्रान्तों को वरावर ऋधिकार हों ऋथवा हिन्दू-प्रांतों त्रौर मुस्लिम-प्रांतों के वीच सन्तुलन त्रौर समानता की भावना हो, शासन का ऋाधार व्यक्ति हो ऋथवा संप्रदाय, व्यक्ति के ऋधिकारों का समावेश विधान के ऋन्तर्गत हो ऋथवा उन्हें राज्यों की सदिच्छा पर छोड़ दिया जाय। इस प्रकार के सैकड़ों महत्त्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिन पर विधान-निर्मातृ-सभा को विचार करना होगा, श्रीर स्पष्ट निर्णय बनाने पड़ेंगे। उसे श्रपने इस कार्य में उस समय तक हर्गिज़ सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि उसे देश की समग्र-जनता का समर्थन प्राप्त न हो, दूसरे शब्दों में, जब तक वह स्वयं उनके द्वारा चुनी न गई हो।

(त्रा) समभौते की दिशा में वैधानिक प्रयंतन

मूलभूत ऋधिकारों का प्रश्न

विधान-निर्मातृ सभा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न सांप्रदायिक समभौते की दिशा में प्रयत्न करने का होगा। इसी दृष्टि से हमें मूलभूत ग्राधिकारों के प्रश्न पर चर्चा करना है। प्रत्येक देश में न्यक्ति के कुछ मृल-भूत ग्राधिकार होते हैं, जिनके सम्बन्ध में साधारणतः यह त्र्यावश्यक माना जाता है कि शासन के द्वारा उनकी स्वीकृति की घोषणा कर दी जाय, त्र्योर उन्हें केन्द्रीय व प्रांतीय दोनों विधानों में शामिल कर लिया जाय, जहां तक इन मूलभूत ग्राधिकारों के विधान में शामिल किये जाने का प्रश्न है, विधान-शास्त्री इस सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं। त्रांत्रेज़ लेखक प्रायः उसमें त्रापना त्राविश्वास ही प्रगट करते हैं। उनका विचार है कि ये श्राधिकार प्रायः ऐसे होते हैं कि कान्नी त्रादालतों द्वारा उनके सम्बन्ध में निर्ण्य किया जाना वड़ा कठिन होता है, त्रीर यदि वे किसी निर्ण्य पर पहुँच भी सकीं तो उसके श्रमल में त्राने में काफ़ी दिक्कृत पेश श्राती है। परन्त श्रन्य देशों के विधान-शास्त्री श्रंग्रेज़ लेखकों के इस तर्क से प्रायः सहमत

धर्म का पालन व प्रचार करने का हक-इस शर्त के साथ कि उससे सार्वजनिक व्यवस्था श्रीर नैतिकता का श्रातिकमण न होता हो ।

- (३) ग्रलपसंख्यक वर्गों ग्रौर विभिन्न भाषा-भाषी प्रदेशों की संस्कृति, भाषा ग्रौर लिपि का संरत्नुग् ।
- (४) क्रान्त की दृष्टि में संव नागरिकों की समानता, चाहे वे स्त्री हों या पुरुप, ग्रौर चाहे वे किसी धर्म, जाति ग्रौर सम्प्रदाय के सदस्य हों।
- (५) सरकारी नौकरी पाने, शक्ति अथवा प्रतिष्ठा के किसी स्थान पर नियुक्त किये जाने, और किसी भी न्यापार अथवा उद्योग को स्वीकार करने के अधिकारों के सम्बन्ध में किसी नागरिक पर उसके धर्म, जाति, सम्प्रदाय अथवा स्त्री या प्रक्र होने के आधार पर सभी प्रकार के प्रतिवन्धों का अभाव।
- (६) कुएँ, तालाव, सङ्कों, शिक्तालयों श्रीर सार्वजनिक स्थानों के सम्बन्ध में, जिनकी व्यवस्था राज्य के श्रथवा स्थानीय कोष से की जाती हो, श्रथवा जो व्यक्तियों द्वारा जनता के साधारण व्यवहार के लिए निर्माण किये गए हों, सब नागरिकों के श्रधिकारों व कर्त्तव्यों की समानता।
 - (७) राज्य की स्रोर से सब धमों के सम्बन्ध में तटखता की नीति का पालन । राजनैतिक संरक्षणों की समस्या

परन्तु, त्र्याज की भारतीय परिस्थिति में, केवल मूलभूत त्र्यधिकारों का विधान में सम्मिलित किया जाना काफ़ी नहीं होगा । कम-से-कम संकमण काल में, जिसकी श्रवधि दस या पन्द्रह वर्ष की हो सकती है—यह व्यवस्था कितने वर्षों तक चले, इसका स्पष्टीकरण पहिले से हो जाना आवश्यक है-यह अनि-वार्य होगा कि ऋल्प-संख्यक वर्गों को पूर्ण, रूप से ऋाश्वस्त करने के लिए कुछ विशेष संरक्ष्णों की त्रावश्यकता हो । इन संरक्ष्णों में सबसे महत्त्वपूर्ण होगा-धारासभा में स्थानों का बंटवारा । त्राज मुसल्मान हमारी त्राजादी की जंग के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण यह वताया जाता है कि उन्हें यह डर है कि प्रजातन्त्रीय संगठन के अन्तर्गत हिंदुओं के लिए धारासभा में अधिकांश स्थानों को पा लेना, श्रीर उन पर जमे रहना, श्रासान होगा । दूसरे शब्दों में, उन्हें यह डर है कि प्रजातन्त्र के नाम पर हिंदू-राज की स्थापना की जा सकेगी । मुस्लिम लीग प्रजातन्त्र के ख़िलाफ़ नहीं है, ग्रौर न ' पार्लमेएटरी संस्थाग्रों से ही उसे चिढ है। वह जिस चीज़ का विरोध करती है वह प्रजातन्त्र शासन का वह रूप है जिसने हिंदु बहुसंख्यक कांग्रेस की अधिकांश प्रान्तों में शासन के सूत्र श्रपने हाथों में ले लेने की सुविधा दी । मि॰ जिन्ना श्रीर मुस्लिम-लीग ने वार-वार जिस वात पर ज़ोर दिया है, वह यह है कि भविष्य में इस प्रकार के शासनों

के निर्माण का वे यथाशक्ति विरोध करेंगे।

इसके विरुद्ध जो दलील दी जाती है, मैं उससे पूर्णतया परिचित हूँ। कहा जाता है कि जब कि देश में हिंदुओं का बहुमत है, उन्हें इस वात का पूरा त्र्याधिकार है कि वे त्र्यपनी सरकार बना सकें, परन्तु, यह वात प्रजातन्त्र की मेरी कल्पना के विरुद्ध जाती है। मैं समभता हूँ कि प्रजातन्त्र का अर्थ केवल यही नहीं है कि उसमें बहुसंख्यक वर्ग-का शासन हो । मैं तो समभता हूँ कि प्रजातन्त्र जनता की ऐसी सरकार का नाम है जो समय जनता के हित को हिष्ट में रखते हुए काम करती हो । ऐसी स्थिति में, यदि मुसल्मानों को सचमुच यह डर है कि राज्य-शासन में हिंदु: क्रों की प्रधानता होजाने से उनकी संस्कृति को ख़तरा है, तो इस डर को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, श्रीर उस प्रयत्न की दिशा में धारा-सभा में मुसल्मानों को अपनी संख्या के अनुपात से कुछ अधिक स्थान देना भी त्रावश्यक हो तो वैसा करना चाहिए । हमारे वैधानिक इतिहास में यह कोई नई वात नहीं है। ऋव भी वर्ग विशेषों के लिए धारासभा में कुछ स्थान सुरक्ति रखने और उन्हें संख्या के अनुपात से कुछ अधिक स्थान देने की पद्धति हमारे विधान का एक महत्वपूर्ण ऋंग है ही। इस स्थिति के सम्बन्ध में हम त्रपना खेद प्रगट कर सकते हैं, पर उससे जल्दी छुटकारा पाने की हमें त्राशा नहीं है । १६३२ के सांप्रदायिक निर्णय के श्रमुसार मुसल्मानों को ब्रिटिश भारत में ३३.३ प्रतिशत स्थान दिये गए हैं, स्रोर पंजाव स्रोर वंगाल की धारासभास्रों में, जहां उनकी संख्या वैसे ही ऋधिक है, वहुमत बना लेने की सुविधा दी गई है। जहां तक केन्द्रीय धारासमा का संबंध है, मुसल्मान स्थानों के वर्तमान ग्रान-पात को त्रौर भी बढ़ाया जा सकता है। कुछ दिनों पहिले भारत-सरकार के भूतपूर्व सूचना-मन्त्री सर सुल्तानश्रहमद ने यह सुभाव सामने रखा था कि सवर्ण हिंदुत्रों श्रीर मुसल्मानों की संख्या वरावर कर दी जाय, श्रीर उनमें से प्रत्येक को ४० प्रतिशत स्थान दिये जायं, श्रीर २० प्रतिशत स्थानों को एक श्रीर दांलत जातियां त्र्योर दूसरी त्र्योर ईसाई, सिख, पारसी, एंग्लो-इपिडयन त्र्यादि में बरावर-वरावर बांट दिया जाय । इस प्रत्ताव को श्रमल में लाने का श्रमं होगा कि सवर्ण हिंदुस्त्रों की संख्या देश की स्रायादी का ६०.३७ प्रविशत होते हुए भी धारा-सभा में उन्हें केवल ४० प्रतिशत स्थान प्राप्त होंगे, श्रीर मुसल्मानों की संख्या लगभग २४ प्रविशव होते हुए भी उन्हें ४० प्रविशव स्थान मिल सकेंगे। इसमें हिंदुओं से त्याग की श्रपेका वो की ही गई है, पर मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इससे हिंदुस्त्रों के हितों स्त्रीर स्वार्थों पर धका लगेगा । हिंदुस्त्रों की संख्या मुसल्मानों से किसी प्रकार कम तो होगी नहीं। यदि अपने स्वायों की

रत्ता में वे किटबिंद रहें — ग्रीर जहां तक बड़े हिंदू स्वार्थों का सम्बन्ध होगा, कोई कारण दिखाई नहीं देता कि वे इस प्रकार से किटबिंद क्यों नहीं होंगे, ग्रपनी मांग के न्यायपूर्ण होने की ग्रवस्था में ग्रन्य ग्रल्पसंख्यक वर्गों के सहयोग की भी। वे ग्रपेता कर ही सकते हैं — तो वे ग्रपना बहुमत बना सकेंगे, यह सच है कि वह बहुमत वैसा सथाक नहीं होगा जैसा साधारण स्थिति में होगा। इसी प्रकार सुसल्मान भी किसी भी न्यायपूर्ण मांग के लिए यदि हिंदुग्रों के समर्थन की ग्रपेता न भी रखें तो ग्राल्प-संख्यक वर्गों का समर्थन तो प्राप्त कर ही सकेंगे। डॉ० वेनीप्रसाद ने सप्रू कमेटी को पेश की गई ग्रपनी विज्ञित में दिलत वर्ग को छोड़कर ग्रन्य ग्रल्पसंख्यकों की संख्या में कुछ कमी करके सवर्ण हिंदुग्रों की संख्या को कुछ बढ़ानेका सुकाव सामने रखा था। उनके मतानुसार सवर्ण हिंदुग्रों को ४३, मुसल्मानों को ४०, दिलत जातियों को १० ग्रीर दूसरे ग्राल्पसंख्यक वर्गों को ७ प्रतिशत स्थान दिये जाने चाहिएं। सप्रू कमेटी ने (दिलत जातियों को छोड़ कर) हिंदुग्रों ग्रीर मुसल्मानों को — 'उनकी ग्रावादी के ग्रनुपात में बहुत बड़े ग्रन्सर के होते हुए भी'— वरावर स्थान देने का ग्रसाव किया है।

सांप्रदायिकः चुनावः काः प्रश्न

परन्तु, सप्भानेटी ने हिंदू श्रीर मुसल्मान सदस्यों की संख्या में वरावरी के इस सिद्धांत को विना शर्त के नहीं मान लिया है। उसने अपने इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए यह शर्च ग्रावश्यक मानी है कि मुसल्मान सांप्रदायिक चुनाव के सिद्धांत को छोड़ने के लिए तैयार हो जायं। "कमेटी अपने इस मत पर जोर देना चाहती है," प्रस्तावों-में कहा गया है । 'कि यदि उसकी यह सिफारिश ज्यों की त्यों न मानी गई तो हिंदू-समाज को मी यह अधिकार होगा कि वह न सिर्फ प्रतिनिधित्व के संबंध में समानता के इसन प्रस्ताव को अस्वीकार ही कर दे, वल्कि सांप्रदायिक समभौते(Communal Award)के दोहराए जाने पर भी ज़ोर दे !" जहां तक सांप्रदायिक चुनाव का प्रश्न है; उसके अशुभ परिणामों के सम्बंध में अतमेद की विल्कुल गुंजाइश नहीं है। भारतीय राजनैतिक जीवन को उसने ज़हर से सीचा है । हमारे सांप्रदायिक वैमनस्य की पहिली जिम्मेदारी उस पर है। यदि अंग्रेज़ी राज्य की समाप्ति पर भी किसी अस्यायी श्रथवा स्थायी विधान में उन्हें रखा गया तो वह श्रंप्रेज़ी राज्य की सबसे बुरी विरासतः होगी। परन्तु जहां तक स्त्राज की मुस्लिम विचार-धारा काः सम्बन्ध है। वहः सांप्रदायिक चुनाव के उस्त से जकड़ी हुई है। किप्स-प्रस्तावों को श्रस्तीकार करते समय भी मुरिलम-लीग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह सांप्रदायिक ज्वनाव को मुसल्मानों के सच्चे प्रतिनिधियों के।चुने जाने का एक मात्र सही रास्ता? मानती है। जब तक

श्रल्य-संख्यक वर्गों की सहमति हमें प्राप्त न हो सके, तब तक सांप्रदायिक चुनाव के सिसान्त को जर से उखाए फेंकना शायद संभव न हो। इसके श्रलावा, समान-प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में यदि कोई श्रच्छाई है तो किसी श्रव्यावहारिक शर्त के विना ही उसे घ्रमल में क्यों नहीं लाया जाय । परन्तु सांप्रदायिक चुनाव के सिद्धांत में कुछ संशोधन करना तो त्रावश्यक होगा ही। यदि मुसल्मानों के दृष्टिकोण से यह 'त्रावश्यक सममा जाता है कि धारासभात्रों के मुसल्मान प्रतिनिधि ऐसे हों जो मुस्लिम-समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकें, तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह देखना भी आवश्यक है कि वे देश के व्यापक हितों के शत्रु न हों । सच तो यह है कि हमें इन दोनों दृष्टिकोणों के वीच एक समन्वय की स्थापना करना है। इलाहाबाद के एकवा-सम्मेलन में मौ॰ मुहम्मदश्रली द्वारा रखे गए प्रस्तावों के दंग पर किसी समभौते पर पहुंचा जा सकता है। उनका प्रस्ताव था कि "धारासभा में मुसल्मान उम्मीदवारों में से जिन्हें श्रंपने समाज के कम-से-कम ३० प्रतिशत मत प्राप्त हों, केवल वही उम्मीदवार चुना जाय तो संयुक्त-निर्वाचन में सबसे श्राधिक मत प्राप्त कर सके। यदि कोई भी उम्मीदवार ऐसा न हो जिसने श्रपने समाज द्वारा दिये गए मतों का ३० प्रतिशत प्राप्त किया हो तो उन दो सदस्यों में से जिन्हें श्रपने समाज में संबसे श्रिधिक मत मिले ही वह सदस्य चुना हुआ घोषित किया जाये जिसे संयुक्त निर्वाचन द्वारा दिये गए मतों का अधिकांश प्राप्त हो।" किसी भी दशा में, सांप्रदायिक चुनाव के आधार पर चुने गए किसी भी मस-ल्मान श्रथवा श्रन्य सदस्य के लिए धारासभा में स्थान पाने के लिए यह श्राव-श्यक माना जाना चाहिए कि वह दूसरे सम्प्रदायों द्वारा व्यक्त किये गए मतों का एक निश्चित प्रतिशत-२० या २५-भी प्राप्त कर सके ।

'वाह्य' श्रौर 'व्यक्तिगत' तत्त्वीं का निराकरण

श्रव तक श्रल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण का मुख्य श्राधार गवर्नर श्रथवा गवर्नर जनरल माना जाता था। १६३५ के विधान ने इस सम्बन्ध में इन लोगों के हाथों में बहुत बड़ी शिक्तयां दे डाली थीं। सच तो यह है कि श्रव तक तो ये लोग ही सांप्रदायिक संरक्षणों की समस्त योजना की धुरी के रूप में रहे हैं। उनका ही यह काम रहा है कि वे यह देखें कि केन्द्रीय व प्रांतीय शासन में श्रल्प-संख्यक वर्गों को उचित स्थान मिल रहे हैं श्रथवा नहीं। श्रल्पसंख्यक वर्गों के शीद्मिक श्रीर सांस्कृतिक श्रिधकारों की रक्षा का दायित्व भी उन्हीं पर रहा है। कित्स-प्रस्तांवों तक में श्रल्पसंख्यक वर्गों का पन्न लेकर शासन में इसत्त्वेप करने के श्रीष्ठार के श्रीधकार को श्रन्तुग्रण रखा गया है। इन प्रस्तावों में

हिंदुस्तान ग्रीर इंग्लैयड के बीच जिस सिन्ध की कल्पना की गई है, उसमें जहां उन सब ग्रावश्यक विपयों की चर्चा है "जो ग्रंगेज़ों के हाथ से भारतीयों के हाथ में पूर्ण सत्ता के सीप जाने से सम्बन्ध रखते हों," यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि "उसमें जातीय ग्रीर धार्मिक ग्रल्पसंख्यकों की रच्चा के लिए व्यवस्था" होगी। परन्तु, जहां तक किसी ऐसे विधान का सम्बन्ध है, जिसका ग्राधार हिंदुस्तान की ग्राज़ादी पर रखा गया हो, उसमें इस प्रकारके 'व्यक्तिगत' ग्रीर 'वाहरी' तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। गवर्नर ग्रीर गवर्नर-जनरल के विशेष ग्राधिकारों को खत्म कर देना होगा। यदि संक्रमण-काल में इन ग्राफ़सरों को रखना ज़रूरी भी समक्ता गया तो उनका स्थान शासन के वैधानिक ग्राध्यक्त से ग्राधिक दायित्वपूर्ण नहीं होगा।

संरक्षणों के इन 'वाह्य' ग्रीर 'व्यक्तिगत' तत्वों के निराकरण का ग्रर्थ होगा उनके स्थान में कुछ वैधानिक तजवीज़ों की सृष्टि करना । इनमें से एक तजवीज़ यह हो सकती है कि सांप्रदायिक प्रश्नों सम्बन्धी निर्ण्य धारासभा के बहुमत पर न छोड़े जायं, किंतु उनके लिए एक निश्चित श्रनुपात में उस सम्प्रदाय के सदस्यों का, जिससे वह सम्बन्ध रखते हों, समर्थन त्रावश्यक माना जाना चाहिए। कांग्रेस के विधान में एक ऐसी धारा थी, जो १६२१ के संशोधन में निकाल दी गई, जिसके अनुसार उसके अधिवेशन में किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती थी और न प्रस्ताव लिए जा सकते थे जिस पर मुसल्मान अथवा हिन्दू सदस्यों का ७५ प्रतिशत एतराज़ कर रहा हो---एतराज़ करने वाले सदस्यों की संख्या का कुल सभा का कम-से-कम चतुर्थीश होना भी त्र्यावश्यक था। मुस्लिम-लीग ने भी त्रपनी १६२६ की मांगों में इस वात पर ज़ोर दिया था कि, ''केन्द्रीय ग्रयंथा प्रांतीय किसी भी धारा-सभा में साम्प्रदायिक विषयों से सम्बन्ध रखने वाला कोई क़ानून, प्रस्ताव, सुकाव श्रथवा संशोधन उस समय तक पेश न किया जा सके, न उस पर वादविवाद हो, श्रीर न वह स्वीकार किया जाय, जब तक उसे हिन्दू श्रथवा मुसल्मान जिस समाज से उसका सम्बन्ध हो उसके तीन-चौथाई सदस्यों का समर्थन पात न हो जाय।" यदि यह सुम्नाव मान्य न समम्ना जाय तो 'स्कॉच-चोट' के ढङ्ग पर हम ऋपने यहां कोई नियम वना सकते हैं। इस ऋपने देश में भी इस प्रकार

१—'स्कॉच वोट' का अर्थ है कि जब कभी हाउस ऑफ कामन्स के सामने कोई ऐसा प्रश्न होता है जिसका सम्बन्ध केवल स्कॉटलेंड से हो, तब उस पर केवल उसी प्रदेश के निवासी-सदस्यों को अपनी सम्मति न्यक्र करने व मत देने का अधिकार होता है। की एक परम्परा स्थापित कर सकते हैं जिसके अनुसार यह आवश्यक माना जाय कि किसी भी सम्प्रदाय के व्यक्तिगत क़ान्न ग्रथवा संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों के निर्णय का अधिकार उसी सम्प्रदाय के सदस्यों को होगा। इस काम के लिए उन्हें एक 'स्टेंडिंग-कमेटी' के रूप में मान लिया जाय। फिर भी यह निर्णय करने की किटनाई तो रहेगी ही कि जिस क़ान्न ग्रथवा प्रस्ताव पर बहस की जा रही है वह क्या वास्तव में एक सम्प्रदाय-विशेष से सम्बन्ध रखता है। इस सम्बन्ध में डॉ॰ वेनीप्रसाद के इस सुम्नाव पर अमल किया जा सकता है कि यह निर्णय नीचे के चेम्बर के अध्यद्य पर छोड़ दिया जाय, और वह अपने इस निर्णय तक पहुँचने के लिए धारासमा की उस सिमित की सलाह ले ले जो सांप्रदायिक सद्भावना की स्थापना के उद्देश्य से ही बनाई गई हो।

सांप्रदायिक-सद्भावना समिति

यहीं पर सांप्रदायिक-सद्भावना-समिति (Board of Conciliation) ऋथवा इसी प्रकार की किसी ऋन्य संस्था के संगठन के प्रश्न को भी ले लें। यह समिति एक सलाहकारी समिति (advisory body) होगी, श्रौर उसका काम धारा-सभा ऋथवा सरकार के द्वारा उठाये गए प्रश्नों पर सलाह देने का होगा। परन्तु, इसके ऋलावा ऋौर भी कई वड़े कामों को वह ऋपने हाथ में ले . सकती है । वह समाज-शास्त्र के विस्तृत श्रध्ययन का एक वहुत वड़ा केन्द्र वन सकती है, स्रोर, देश की सांप्रदायिक मनोवृत्ति के विकास स्रोर गतिविधि पर श्रपनी दृष्टि रखते हुए, स्वयं भी धारासभा श्रीर सरकार के सामने श्रपने सुकाव रख सकती है। वैधानिक दृष्टि से इस सम्बन्ध में हमें यह निश्चय करना होगा कि इस समिति का संगठन किस प्रकार किया जाय। इस संगठन की कई शक्लें हो सकती हैं। एक तरीक़ा यह हो सकता है कि धारा-सभा के विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों को उसमें ले लिया जाय—इस संबंध में भी दो मार्ग हमारे सामने होंगे, एक वो यह कि इन सदस्यों को विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधित्व के ऋनु-पात में लिया जाय, श्रीर दूसरा यह कि प्रत्येक सम्प्रदाय में से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या वरावर हो । सांप्रदायिक-सद्भावना समिति में कुछ ऐसे सदस्यों को लेना भी त्रावश्यक होगा जो धारासभात्रों त्रथवा स्वयं समिति के द्वारा धारासभा के वाहर से लिये जा सकें। सप्रू-कमेटी ने इस सम्बन्ध में यह प्रस्ताव उपस्थित किया है कि प्रत्येक धारासभा में इस प्रकार की एक श्रल्पसंख्यक समिति (Minorities Commission) नियुक्त की जाय, जिसमें प्रत्येक ऐसे सम्प्रदाय का, जिसे धारासभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, एक प्रविनिधि हो (यह त्रावश्यक न माना जाय कि वह उस सम्प्रदाय का सदस्य

भी हो) श्रोर जिसका चुनाय धारासभा के सदस्यों द्वारा तो हो पर यह स्वयं धारासभा का सदस्य न हो । मैं सप्नू-कमेटी के इस सुभाव से सहमत नहीं हूँ कि इस श्रालप-संख्यक समिति में एक भी सदस्य ऐसा न हो जो धारासभा का सदस्य भी हो : यह प्रतिबंध कुछ श्रानावश्यक-सा प्रतीत होता है । यह संभव है कि यदि इस शत्तं को कड़ा बना दिया गया तो उक्त समिति की निष्पत्तता श्रोर श्रा-राजनैतिकता में लोगों का विश्वास वढ़ जाय । शेष वातों में सप्नू-कमेटी के प्रतावों को ज्यों-का-त्यों मान लेना वांछनीय जान पड़ता है । केन्द्रीय श्रोर प्रांतीय धारासमात्रों में सांप्रदायिक-सद्भावना समिति श्राथवा श्रालपसंख्यक समिति श्रादि की स्थापना के श्रालावा यह भी श्रावश्यक दिखाई देता है कि शहरों, श्रोर गांवों में भी, कुछ सद्भावना-समितियों (Goodwill Committees) की स्थापना की जाय । मैं समभता हूँ कि इन समितियों में जहां कुछ सदस्य सरकार द्वारा चुने गए हों, कुछ ऐसे भी होने चाहिएं जो जनता के सीधे प्रतिनिध माने जा सकें—इन सभाशों के श्रध्यक्त की निश्रुिक, कम-से-कम प्रारम्भिक काल में, सरकार द्वारा किया जाना ही वांछनीय जान पड़ता है।

सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व

सरकारी नौकरियों में ग्राल्पसंख्यक वर्गों के लिए कुछ स्थान निश्चित करने की जो परम्परा वन गई है, उसे छोड़ने का, संभव है, ग्राभी समय नहीं ग्राया है, यह परम्परा चाहे कितनी ही गुलत क्यों न हो । इस सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जा सकती है-साथ ही यह भी निश्चित हो जाना चाहिए कि कितने वर्षों तक, १० या १५ वर्ष से ऋधिक उसे क़ायम रखना ऋवांछनीय होगा-परन्तु, एंग्लो-इंडियनों को ग्राज जो भारी प्रतिनिधित्व मिला हुन्ना है उसमें कमी करना तो त्र्यावश्यक होगा ही। वर्त्तमान व्यवस्था, ग्रथवा उसके स्त्राधार-भूत सिद्धांत, को कुछ दिनों तक जारी रखने का ग्रर्थ यह हर्गिज़ नहीं होना चाहिए कि शासन में किसी प्रकार की अयोग्यता को प्रोत्साहन दिया जाय। यों तो सैद्धांतिक दृष्टि से इस प्रकार की किसी व्यवस्था को मानना ही एक वड़ी ग़ल्ती है, शासन की योग्यता पर उसका बुरा प्रमाव पड़ना एक ऋौर भी भयानक वात होगी । परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से, यह त्रावश्यक हो सकता है कि, सांप्रदायिक चुनाव के समान, सांप्रदायिक ऋाधार पर नौकरियों के बंटवारे को भी, एक निश्चित काल के लिए जारी रखा जाय। शासन के चेत्र में, जहां तक हो सके, हमें उसे राजनीति के प्रभाव से मुक्त करने (de-politicization) का प्रयत करना है। संयुक्त राज्य में मुक्तकिरण की यह प्रवृत्ति ग्रपने पूरे ज़ोर पर है, ग्रीर पिछले वर्षों में इंग्लैएड में भी वैसा करने का प्रयत किया गया

है। 'डॉ॰ वेनीप्रसाद का मत है कि ''दिन प्रतिदिन की शासन-व्यवस्था, जहांतक संभव हो उस सीमा तक, राजनैतिक दलों के हाथ से निकालकर विशेषज्ञों की स्वतंत्र ग्राथवा ग्राद्ध -स्वतन्त्र समितियोंके हाथों में सौंप दी जाय, जैसे पिल्लक सर्विस कमीशन, रेलवे ग्राथोरिटी, नेशनल इन्वेस्टमेंट वोर्ड, ब्रॉडकास्टिंग कार्पे-रेशन, इलेक्ट्रिसिटी वोर्ड ग्रादि-ग्रादि, तो उससे पार्लमेंटरी ढंगका शासन न केवल सरल होजाता है, उसमें शुद्धता ग्रीर कुशलता भी ग्राजाती है।"

कार्यकारिणी का निर्माण

इसके वाद, कार्यकारिणी के निर्माण का महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उप-स्थित होता है । इस सम्बन्ध में पार्लमेएटरी ग्रौर ग्रन्य पद्धतियों में से चुन लेने का सवाल भी पैदा होता है। हमारे देश में पार्लमेएटरी ढंग के शासन की अनु-पयुक्तता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। हमारे सामने यह दलील रखी जाती है कि पार्लमेएटरी पद्धति के सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि सत्ता एक ही राजनैतिक दल के हाथ में न रहे, परन्तु विरोधी दल भी इतने प्रवल हों कि, स्रावश्यकता पड़ने पर, वे शासन के सूत्र स्रपने हाथ में ले सकें। ऐसे देश में जहां राजनैतिक दलों का संगठन ही सांप्रदायिकता के आधार पर हो, श्रीर जहां एक धर्म के मानने वालों की संख्या देश की श्रावादी का दो-तिहाई हो, एक ही राजनैतिक दल ऋौर एक ही धर्म के मानने वालों का प्रभुत्व होने की संभावना है, श्रौर उसमें यह डर है कि श्रल्पसंख्यकों को राजनैतिक श्रौर सांस्क-तिक ग्राभिन्यिक्ति के लिए त्र्यवसर नहीं मिलेगा। जहां वहुसंख्यक वर्ग को यह भय रहता है कि यदि उसके कार्य लोकमत के विरुद्ध हुए तो दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग के सशक वन जाने की संभावना है, श्रीर वैसी स्थिति में सत्ता उसके हाथ से निकल कर दूसरे दल के हाथ में जा सकती है, वहां उसके कार्य में ज़िम्मेदारी की भावना वह जाती है, परन्तु यदि उसे यह विश्वास रहा कि बहुमत सदैव उसके साथ ही रहेगा, तो यह खाभाविक है कि उसके कार्यों में यह भावना बहुत प्रमुख न रहेगी। इसके ऋतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि पार्लमेएटरी ढंग की शासन-पद्धित तो इंग्लैएडकी अपनी उपज है, उसे हिन्दुस्तानके लिए ज्यों-का-त्यों श्रपना लेना भी शायद ठीक नहीं होगा । लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, ''श्रंग्रेज़ी विधान, जिसकी हम एक सूचम श्रीर जॉटल शासन-तंत्र के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के

3-श्रमेरिका में इस प्रवृत्ति के विकास के विश्व श्रध्ययन के लिए देखिए . विलोवी द्वारा लिखित Principles of Public Administration । इंग्लैंड में सेंट्रल इलेन्ट्रिसटी वोर्ड श्रीर श्रसिस्टेंस-बोर्ड इस प्रवृत्ति के श्रन्छे उदाहरण हैं। २-Communal Settlement, ए० ३६।

रूप में प्रशंसा करते हैं, यदि किसी दूसरे देश में प्रयोग में लाया गया तो कठि-नाइयों ग्रीर ख़तरों से भरा हुन्ना प्रमाणित होगा ।.....उसकी सफलता का मख्य कारण समभौते की वह भावना है जिसकी कोई लेखक व्याख्या नहीं कर सकता और वह मनोवृत्ति है जिसके वनने में सदियां लगी हैं।" हिंदुस्तान में सम-भौते की वैसी भावना ग्रौर वैसी मनोवृत्ति का सचमुच ही विकास नहीं हो सका है, पर, संयुक्त-निर्वाचित समिति (Joint Select Committee) ने त्रपनी रिपोर्ट में जो चित्र खींचा है, वह भी वड़ा त्रातिशयोक्तिपूर्ण है। उसका विश्वास था कि "हिंदुस्तानमें कोई भी राजनैतिक दल ऐसा नहीं है जिसे सच्चे श्रथों में यह नाम दिया जा सके, न किसी प्रकार का विकास-शील राजनैतिक लोकमत ही है। उनके स्थान पर हमारे सामने त्राता है हिंदू न्त्रीर मुस-ल्मान का ग्रापसी विरोध, ग्रौर ये दो धर्मों का ही नहीं दो सम्प्रदायों का प्रति-निधित्व करते हैं: इनके त्रालावा भी त्रानेकों स्वतन्त्र ग्रौर स्वयं संपूर्ण त्राल्यसंख्यक-वर्ग हैं, जो सब अपने भविष्य के संबंध में चिन्तायस्त हैं, और बहुसंख्यक वर्ग के, श्रीर त्रापस में एक दूसरे के, प्रति वेहद श्रविश्वास-शील हैं; श्रीर इसके श्रलावा जातियों का कठोर श्रीर श्रमिट विभाजन है, जो खयं प्रजातन्त्र के सभी उसूलों के खिलाफ़ जाता है।"

यह विश्लेषण वस्तुस्थिति को अपने सही रूप में पाठक के सामने रहीं रखता। हमारे देश में राजनैतिक दलों का आधार एक सीमा तक अवश्य सांप्रदायिक है, पर सबसे बड़े, सशक्त और व्यापक राजनैतिक दल, कांग्रेस, का सङ्गठन जिस आधार पर किया गया है, वह शुद्ध राजनैतिक आधार है। अन्य राजनैतिक दलों में केवल मुस्लिम-लीग की अपनी हस्ती है, पर उसका आधार भी सांप्रदायिक तो परिस्थितियों के कारण ही है, मुख्यतः प्रतिकियावादी है। प्रगति की दिशा में मुस्लिम-समाज के पिछुड़े हुए होनेके कारण प्रतिकियावादी तक्वों ने सांप्रदायिकता का जामा पहिन लिया है, पर, इस ख़ोल को चीरकर मुस्लिम-समाज के प्रगति-शील तक्व भी अब बाहर आरहे हैं, और पिछुले कुछ महीनों में तो उनका संग-ठन भी हद होता गया है। कांग्रेस के भीतर विभिन्न राजनैतिक विचार-धाराओं के दिन-प्रति-दिन अधिक स्पष्ट होते जाने हो भी इस विचार को पृष्टि मिलती है कि कांग्रेस द्वारा उसके मुख्य उद्देश्य, भारतीय स्वाधीनता, की प्राप्ति के बाद उसकी सत्ता ही समाप्त होजाय, और उसके भस्मावशेषों में से अनेकों फिनिक्स, राजनैतिक दल, जन्म ग्रहण कर लें। मेरा विश्वास है कि हमारे देश में तेज़ी के साथ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण और विकास होरहा है, जिनमें पार्लमेएटरी ढंग का शासन सफलता के साथ प्रयोग में लाया जा सकेगा। मैं यह जानता हूं

कि किसी भी सुसंगठित श्रल्पसंख्यक वर्ग का विरोध ऐसे शासन के लिए ख़तर-नाक सिद्ध हो सकता है, ऋौर मुस्लिम-समाज की स्थिति तो ऋल्पसंख्यक वर्ग से कहीं ऋधिक महत्त्व की है, पर साथ ही मेरा यह विश्वास भी है कि भारतीय राष्ट्री-यता के प्रति मुस्लिम-लीग का वर्तमान दृष्टिकी ए मुस्लिम लोकमत को ऋभिन्यिकि नहीं करता, श्रोर, देर से या जल्दी, वहुत सम्भव है कि जल्दी ही, मुस्लिम-लीग को या तो इस लोकमत के सामने भुकना पड़ेगा या उसे ऋपनी स्थिति को ही खत्म करने के लिए तैयार रहना चाहिए । पाकिस्तान के जिन रङ्गीन वादलों पर वह त्राज सवार है, सचाई की किरणों के कुछ तेज़ होते ही उनका घुल जाना श्रनिवार्य है। इसके श्रातिरिक्त, हम न तो यह भूल सकते हैं कि हमारी राजनैतिक विचार-धारात्रों का विकास बहुत कुछ स्राप्रेज़ी राजनैतिक विचारों, सिद्धांतों स्रौर कल्पनाञ्चों के सम्पर्क में हुन्नाहै, न्रीर न यह कि पिछले 尘 वर्षोंमें हमारा समस्त राजनैतिक शिक्तण भी अंग्रेज़ी शासन-संस्थाओं में ही हुआ है। इस लंबे संपर्क का हमारे विचारों पर जो प्रभाव पड़ा है, उसे विल्कुल मिटाया नहीं जा सकता । भविष्य के निर्माण के प्रयतों में हम भूतकाल से त्रिल्कुल सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकते, पर साथ ही इसका ऋर्य यह भी नहीं है कि यदि हम शासन के मूलभूत सिद्धांतों में इंग्लैएड का ऋनुकरण करना निश्चित करें तो उसके सङ्गठन में, परिस्थितिथों की विभिन्नता के त्रानुसार, काफ़ी वड़े परिवर्त्तन करने के लिए भी तैयार न रहें।

कुछ लोगों का मत है कि प्रजावन्त्र शासन के सिद्धांत को मानते हुए भी हम स्रपनी कार्यकारिणी का सङ्गठन संयुक्त राज्य स्रमरीका के द्राधार पर कर सकते हैं, यानी उसके स्रध्यक्त का चुनाव सीधे जनता के द्वारा कर लिया जाय, उसकी कार्य-स्रविध निश्चित कर दी जाय, उसे धारासभा से विल्कुल स्वतन्त्र बना दिया जाय, स्रोर उसे यह स्रधिकार दे दिया जाय कि वह स्रपने साथियों की नियुक्ति स्वयं ही कर ले श्रोर वे उत्तरदायी भी केवल उसी के प्रति हों।परन्तु ये लोग भूल जाते हैं कि इस पद्धित पर चलने का परिणाम यह हुन्ना है कि स्त्रमरीका में कार्यकारिणी स्रोर धारासभा के वीच एक निरन्तर सङ्घर्ष चलता रहा है, स्रोर इसी कारण संसार के किसी स्त्रन्य देश ने इस पद्धित को नहीं स्रपनाया है। स्त्रन्य विधान-शास्त्रियों का मत है कि स्विजरलैएड की पद्धित हमारे लिए स्त्रधिक उपयुक्त होगी। स्विजरलैएड में मन्त्रमण्डल के सदस्यों का चुनाव इस दृष्टि से किया जाता है कि उसमें सभी राजनैतिक दलों स्त्रौर देश के विभिन्न प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो, श्रोर यह चुनाव धारासभा के दोनों विभागों के सभी सदस्यों की एक मिली-जुली सभा के द्वारा किया जाता है। इस संवंध में भी कुछ स्त्रावश्यक वातें ऐसी

हैं जिन्हें हम ग्रपनी दृष्टि से ग्रोमल नहीं कर सकते। पहिली वात तो यह है कि यह नहीं कहा जा सकता कि एक शासन-पद्धित जो एक छोटे तटस्य देश में सफल हो सकी, ग्रोर जो उस देश की विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज है, हिंदुस्तान जैसे वहें देश में भी सफल हो जायगी। दूसरी वात यह है कि स्विज्ञरलैएड के ढंग की कार्यकारिणी का निर्माण जिस देश में भी हुग्रा—प्रशा, वैवेरिया, सैक्सनी, ग्रोर ग्रायर्लिएड के प्रयोग इसके उदाहरण हैं—वहीं उसे ग्रस-फलता मिली। तीसरी वात यह है कि इस पद्धित को ग्रपना लेने का ग्रर्थ यह होगा कि हमारे देश में वैधानिक विरोध नाम की चीज़ विल्कुल ख़त्म हो जायगी, ग्रीर उसका परिणाम यह होगा कि राजनैतिक दलों के नेताग्रों के हाथों में वहुत ग्राधिक शिक्त केन्द्रित हो जायगी। इन परिस्थितियों में, स्विज्ञरलैएड का उदाहरण भी, सम्भव है, हमारे देश के लिए उपयुक्त सिद्ध न हो।

कार्यकारिणी-सभा के निर्माण के सम्बन्ध में एक ग्रन्य सुफाव यह भी है कि उसका सम्बन्ध जनता द्वारा सीधे चुनी हुई किसी धारासभा से न होंकर ३० या ४० व्यक्तियों की एक ऐसी सभा से हो जिसका चुनाव प्रांतीय धारासभाग्रों द्वारा इस आधार पर किया गया हो कि उसमें देश के प्रत्येक स्वार्थ का प्रतिनिधित्व हो पर किसी एक स्वार्थ को बहुमत प्राप्त न हो। कार्यकारिगी-सभा इस वड़ी सभा से गवर्नर-जनरल या प्रधान-मन्त्री द्वारा एक निश्चित ग्रवधि के लिए चन ली जाय । उसके चुनाव में इस वात का भी पूरा ख्याल रखा जाय कि उसमें सभी प्रमुख दलों और देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हों, ख्रीर साथ ही देश के प्रत्येक भाग का भी उसमें प्रतिनिधित्व हो सके। कार्यकारिग्री के सदस्य एक निश्चित ग्रविध के लिए चुने जांय, ग्रीर जहां तक उनके उत्तरदायित का मश्न है वे बड़ी सभा,फ्रेंडरल कैंसिल,के प्रति नहीं बल्कि गवर्नर-जनरल के प्रति उत्तरदायी रहें । उनके लिए नीति-संबंधी सभी त्रावश्यक प्रश्नों पर फ़ेंबरल कोंसिल से सलाह-मश्चिरा करते रहना तो त्र्यावश्यक होगा ही। इस योजना के समर्थकों का विश्वास है कि इसके द्वारा (१) प्रत्येक राजनैतिक दल को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा पर साथ ही किसी एक राजनैतिक दल की इतना प्रभुत्व भी नहीं मिलेगा कि ग्रल-संख्यक वर्गों ग्रीर देशी राज्यों को उससे डर हो, (२) फ़ेंडरल केंछिल के सदस्यों की संख्या सीमित होने के कारण उसमें उत्तरदायित्व की भावना का पूरा विकास हो सकेगा, ऋौर इससे कार्यकारिणी ऋौर धारा-सभा के ऋापसी संबंधों के दृढ़ होने में महायवा मिलेगी, श्रीर (३) इस प्रकार की कार्यकारिसी में जनमत का कम-से-कम उतना प्रतिनिधित्व तो होगा ही जिससे धारासभा को संतुष्ट रखा जा सके।

इस योजना के पत्त में यह बात तो श्रवश्य कही जा सकती है कि उसमें प्रतिनिधित्व का ग्राधार सांप्रदायिक नहीं. भौगोलिक रखा गया है, पर कुछ ऐसी वातें भी हैं जिनके कारण उसे मान लेना कठिन हो जाता है। पहिली बात वो यह है कि उसमें एक ऐसी कार्यकारिगी की कल्पना की गई है, जो ऋडिग श्रीर श्रविचल है: इस प्रकार की सभा से उत्तरदायित की बहुत श्रिधक श्राशा नहीं रखी जा सकती। दूसरी बात यह है कि वह राजनैतिक दलों पर इतना ऋधिक निर्मर रहेगी कि यह सम्भव है कि वास्तविक सत्ता जनता के हाथ से निकल कर राजनैतिक दलोंके कुछ वड़े नेतास्रों के हाथों में केन्द्रित हो जाय: इसके साथ ही यह प्रश्न भी विचारणीय है ही कि विभिन्न, श्रौर परस्पर-विरोधी, राजनैतिक दलों का एक साथ प्रतिनिधित्व करते हुए यह सभा कब तक ऋपना स्थायित्व बनाये रह सकेगी । इस प्रकार की कार्यकारिग्री को सफलता प्राप्त करने के लिए ऋाज से एक विल्कुल विभिन्न वातावरण की ऋषेद्या होगी, जबकि हमारे राजनैतिक दल ग्रपनी शक्ति वढाने की गुरज़ से नहीं पर देश की समृद्धि श्रौर उन्नित को ही दृष्टि में रख कर काम करने की च्रमता पैदा कर लेंगे। इसके स्रालावा, इस प्रकार की कार्यकारिए। केन्द्र में यदि सफल भी हो सकी, तो यह सम्भव है कि वहत से प्रांतों में उपयुक्त सिद्ध न हो सके। किसी भी स्थिति में, यह तो सम्भव है ही कि केन्द्र व प्रांतों की कार्यकारिगी समितियां अपने निर्माण की पद्धति में एक-दूसरे से भिन्न हों, ऋथवा एक प्रांत की कार्यकारिगी-सभा का रूप दूसरे प्रांत की कार्यकारिग्री से ज़दा हो । जिन प्रांतों में ऋल्प-संख्यक वर्गों की संख्या कम है वहां पार्कमेएटरी ढङ्ग का शासन सफल हो सकता है, परन्तु जहां साम्प्रदायिक विषमताएँ बहुत गहरी हैं, वहां ऋत्य पद्धतियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं।

में समभता हूं कि यदि इस योजना पर अमल किया गया तो देश की एकता की दृष्टि से यह प्रयोग महंगा सिद्ध होगा, श्रीर साथ में कई श्रन्य जिटलताएं पैदा हो जायंगी। यदि हमें देश में एक सच्चे संघ-शासन की स्थापना करना है, तो प्रांतीय शासन की रूप-रेखा में भी समानता की रज्ञा करनी होगी। पिरिस्थितियों में छोटे-बंडे श्रन्तर के वावजूद भी, मेरा विश्वास है, यदि कोई शासन-पद्धित सभी प्रांतों में श्रपनाई जा सकती है तो वह पार्लमेएटरी पद्धित है। उसकी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारे राजनैतिक दलों के निर्माण का सांप्रदायिक श्राधार है, पर जैसा कि पिहले वतलाया जा चुका है, वह श्राधार तेज़ी से बदल रहा है। विचार-धाराश्रों की विभाजन-रेखाएं श्रव सांप्रदायिक कम श्रीर श्राधिक तथा राजनैतिक श्रिधक होती जारही हैं। इसके साथ ही, यदि धारा-सभाश्रों में मुसल्मानों का प्रतिनिधित्व श्रीर श्रिधक

बढ़ा दिया गया , सांप्रदायिक चुनाव की पद्धति में कुछ, संशोधन-परिवर्त्तन हुए, श्रीर सांप्रदायिक-सद्भावना समिति श्रथवा श्रल्पसंख्यक-समिति जैसी संस्थाएं वन गई तो यह कार्य ग्रौर भी ग्राधिक वेग से चल सकेगा। परन्तु जब तक वातावरण वैसा शुद्ध नहीं वन जाता, पर केवल उसी समय तक, मिश्रित मन्त्रि-मण्डल बनाने का प्रयोग भी किया जा सकता है। पार्लमेंटरी पद्धति में, विशेष ग्रवसरों पर, इस प्रकार के मिश्रित मन्त्रिमण्डल वनाने की व्यवस्था तो है ही। परन्तु मिश्रित मन्त्रिमएडल को ही एक आदर्श मान लेना एक ग़लत बात होगी। यदि मिश्रित-मन्त्रिमण्डल वनाना त्र्यावश्यक हुत्र्या तो मैं यह पसन्द करूंगा कि उसमें विभिन्न राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो, विभिन्न धर्मी ग्रथवा जातियों का नहीं। इस संबंध में सप्रू-कमेटी के सुक्तावों से मैं सहमत नहीं हूं। यदि विभिन्न सांप्रदायिक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया तो उससे सांप्रदायिक वैम-नस्य के बहुत ग्राधिक बढ जाने का डर है, पर यदि विभिन्न राजनैतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिला तो उनका सांप्रदायिक त्राधार धीरे-धीरे नष्ट होता जायगा, श्रीर वे देश के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मिलजुल कर विचार श्रीर निर्णय कर सर्केंगे। इस प्रकार देश में एक खस्य वातावरण का निर्माण होगा। ज्यों ही राजनैतिक दलों के रूप में परिवर्त्तन होगा, श्रीर उनका सङ्गठन श्रार्थिक श्रीर राजनैतिक विचार-धारात्रों के त्राधार पर होने लगेगा, हमारी कार्यकारिगी, त्राप ही त्राप, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करने के स्थान पर देश के ऋार्थिक ऋौर राजनैतिक विचार-धाराख्रों की ग्राभिव्यक्ति का साधन वन जायगी। तभी वह सच्चे श्रथोंमें— जिन ग्रथों में इस शब्द का प्रयोग ग्रन्य देशों, इंग्लैएड, फ्रांस, बेल्जियम, यूनान स्रादि में होता है—एक मिश्रित मन्त्रिमएडल कहला सकेगी। इस मिश्रित मन्त्रि-मण्डल का प्रचार-मन्त्री किसी ऐसे व्यक्ति को ही वनाया जाना चाहिए जो उन राजनैतिक दलों में, जो धारासभा के चुनाव में भाग ले रहे हों, सबसे बड़े दल का नेता हो, स्त्रीर वह, स्त्रपने समस्त मन्त्रिमण्डल के साथ, धारासभा के प्रति उत्तर-दायी हो । यह सुमाव कि प्रधान मन्त्री और उप-प्रधान मन्त्री विभिन्न जातियों के हों, ऋथवा वारी-बारी से हिंदू ऋौर मुसल्मान हों, विशेष महत्वं नहीं रखता। कार्यकारिग्री का धारा-सभात्रों के दोनों भागों के एक मिले-जुले ऋधिवेशन के द्वारा चुने जाने का जो तरीका स्विज्ञरलैएड में प्रचलित है, वह भी भारतीय परि-स्थितियों में ऋव्यावहारिक ही प्रतीत होता है।

सांस्कृतिक अधिकार

परन्तु कोई भी भारतीय शासन-विधान उस समय तक संपूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक उसमें देश के प्रमुख ऋल्प-संख्यक वर्गों के सांस्कृतिक ऋधि- कारों के संरत्तण की पूरी व्यवस्था न हो । हमारे देश की परिस्थितियों में तो इन सांस्कृतिक श्रिथिकारों के संरत्तण पर श्रिथिक-से-श्रिथिक ज़ीर देना श्रावश्यक होगा। मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि धर्म, संस्कृति श्रीर भाषा, सार्वजिनिक सभा करने, सिमिति-संगठन श्रादि वनाने, श्रपने विचारों को, सार्वजिनिक व्यवस्था श्रीर नैतिकता की सीमा में, व्यक्त करने, कानून श्रीर राजनैतिक श्रिथिकारों की हिंछ में समानता, श्रादि के संबंध में श्रह्मसंख्यक वर्गों को पूरे श्रिथिकार होने चाहिएं। परन्तु, देश के सांप्रदायिक वैमनस्य को देखते हुए इन श्रिथिकारों की श्रीर भी विस्तृत व्याख्या कर देना श्रावश्यक होगा। इस सम्बन्ध में पिछुले महायुद्ध के बाद मध्य-यूरोप के देशों में बनने वाले विधानों से हमें मार्ग-प्रदर्शन मिल सकता है। श्रह्मसंख्यक वर्गों के श्रिथिकारों की दृष्टि से पोलैयड श्रीर ज़ेको-स्लोविकिया के शासन-विधानों से हम विशेष सहायता की श्रपेत्ता कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में पोलैयड के विधान की ११०-११६ धारायें श्रीर ज़ेकोस्लोविकिया के विधान की १२६-१ श्रीर १३०-१३२ धारायें विशेष उपयोगी सिद्ध होंगी। इन धाराश्रों का सम्बन्ध निम्न चार वातों से है—

- (१) शिक्ता-सम्बन्धी सुविधायें देना, व ग्राल्यसंख्यक वर्गों की भाषात्रों की शिक्ता के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाना;
- (२) सार्वजिनक धन का शिक्षा श्रीर दान श्रादि में उचित वितरण, श्रीर श्रल्पसंख्यक वर्गों को दान सम्बन्धी शैक्षिक, सामाजिक श्रीर धार्मिक संस्थाश्रों की स्थापना, व्यवस्था श्रीर नियंत्रण का श्रीधकार देना।
- (३) कौटुंविक क़ान्न श्रौर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा श्रादि के सम्बन्ध में उच-जातियों की परम्पराश्रों की रक्ता का श्राश्वासन । श्रौर—
- (४) जिन सड़कों, रास्तों, जलाशयों श्रादि की खापना व न्यवस्था सार्व-जिनक न्यवहार के लिए की गई हो, उन्हें काम में लाने की सुविधा प्रत्येक नाग-रिक को, चाहे वह किसी धर्म,जाित श्रथवा संप्रदाय का हो,पहुंचाने की न्यवस्था।

हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए,मैं समभाता हूं,दो बातों पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए—(१) अल्यसंस्थिक वर्गों को इस वात का पूरा आश्वा-सन दे दिया जाय कि उनके लिए इस प्रकार की शिक्षा के संबंध में पूरो सुविधा दी जायगी जिससे उनके सांस्कृतिक व्यक्तित्व की रज्ञा हो सके, और (२) उनकी भाषा और साहित्य के संरज्ञ्य की दिशा में भी राज्य के द्वारा पूरा प्रयत्न किया जायगा। जैकोस्लोबाकिया के विधान की धारा १३१ में यह कहा गया है कि देश के जिस प्रदेश में भी नागरिकों का एक अश जैकोस्लोबाक-भाषा के अलावा किसी अल्य भाषा का प्रयोग करता हो, वहां उन नागरिकों के वच्चों को राज्य

के द्वारा उनकी ग्रपनी भाषा में ही शिचा की व्यवस्था की जायगी । हमारे देश में भी इस प्रकार के संरक्तण की वड़ी ब्रावश्यकता है, विशेषकर ब्राज जब हम यह देख रहे हैं कि एक श्रोर तो मुसल्मानों को यह डर है कि देश में उनकी भाषा (उर्दू) को जद-मूल से ही उखाद फेंकने का प्रयत चल रहा है, ग्रौर दूसरी श्रोर हिन्दू इस वात से चिन्तित हैं कि राष्ट्रीयता की वेगवती धारा में उनकी ग्रिपनी सदियों से इकहा की गई निधि (हिन्दी) वही जारही है। इस समस्या का निवटारा इसी प्रकार के उपाय द्वारा हो सकेगा। मुसल्मान ग्रीर दूसरे लोग जिनकी मातृभाषा उर्दू है श्रपनी भाषा श्रौर साहित्य के विकास की पूरी सुविधा पा सकेंगे । ग्रीर सरकारी ग्राधिकारियों ग्राथवा ग्राफसरों द्वारा कोई प्रयत इस प्रकार का नहीं किया जायगा जिससे यह कहा जा सके कि उर्दू भाषा को निकत्साहित किया जारहा है, ग्रथवा फ़ारसी ग्रीर ग्ररवी के उन शन्दोंके स्थान पर जो उसके ग्रङ्ग होगए हैं, संस्कृत के शब्दों को भर कर उसकी जड़ खोदने का ही प्रयत किया जा रहा है। इसी प्रकार, दूसरे प्रांतों में जहां जनसाधारण की मातृभाषा हिन्दी है, उन्हें ग्रपनी भाषा ग्रीर संस्कृति के विकासकी पूरी सुविधा होगी। सभी स्कूलों में दोनों भाषात्रों की शिक्ता का प्रवन्ध होगा । जहां मुसल्मानों की संख्या बहुत कम है, वहां भी यदि वे चाहें तो उद्किशी शिक्षा का प्रबंध करना श्रावश्यक होगा ।

इस सम्बन्ध में एक ग्रौर प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है, वह यह है कि हम इन मूलभूत ग्राधिकारों के संरक्षण का दायित्व देश की सबसे वड़ी वैधानिक ग्रादलत पर छोड़ें, ग्राथवा लीग ग्राफ नेशन्स या वर्ल्ड सिक्यूरिटी कांफेंस जैसी किसी ग्रान्तरींष्ट्रीय संस्था पर । जैसा कि सभी जानते हैं, पहिले महायुद्ध के बाद यूरोपीय देशों की ग्राल्पसंख्यक-संधियों का संरक्षण राष्ट्र-सङ्घ(League of Nations)को सौंपा गया था। यह कहना कठिन है कि इस प्रकार के प्रस्ताव के प्रति मुसलमानों की क्या भावना होगी, परन्तु मेरा ग्रानुमान है कि इस काम के लिए यदि किसी ग्रान्तर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया, ग्राथवा किसी वर्तमान ग्रान्तर्राष्ट्रीय संस्था पर इसका दायित्व सौंपा गया तो इससे स्थिति के बहुत ग्राधिक विषम ग्रौर जटिल होजाने का डर है। मुफ्ते इस प्रकार के ग्रान्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण, निरीक्षण ग्राथवा निर्णय में तिनक भी विश्वास नहीं है। संसार के सभी देश ग्राज शक्ति की राजनीति (Power politics) के इतने ग्राधिक दवाब में हैं कि किसी से भी निःस्वार्थता, निष्पत्त्वा ग्राथवा ईमानदारी की ग्राशा करना कठिन है। ग्राज की परिस्थित में इस प्रकार के ग्रान्तर्राष्ट्रीय संगठन के लिए गुंजाइश नहीं रह गई है। इसका ग्रार्थ यह नहीं है कि हिन्दुस्तान ग्रन्य

देशों से निकटसम संपर्क स्थापित नहीं करेगा। परन्तु इसके लिए यह त्रावश्यक नहीं है कि वह त्रपनी त्रान्तिरिक समस्यात्रों के निकटारे के लिए भी त्रान्य देशों का मुंह ताकता रहे। चाहे यह काम कठिन हो या त्रासान, उसे निकटाना तो स्वयं हमें ही है। इसी कारण, मेरा विश्वास है कि इन सांस्कृतिक स्वत्वों के संरत्त्रण का दायित्व जिस वैधानिक संस्था को हो, वह शुद्ध भारतीय हो। मैं समक्भता हूं कि हमारे देश की सबसे बड़ी वैधानिक त्रादालत इस काम को त्राच्छी तरह कर सकेगी।

म्रलासंख्यक सन्धियों का प्रयोग यूरोपमें ऋसफल हुन्ना है, यह भी हम भूल नहीं सकते । मूलभूत ऋधिकारोंकी एक सूची बना लेने और उसे विधानमें शामिल कर लेनेसे ही काम नहीं चल जायगा । उससे ऋधिक ऋावश्यक तो यह होगा कि एक सद्भावनापूर्ण ढंगसे उन्हें कियात्मक रूप दिया जाय। दो ऐसी स्रावश्यक बातें हैं, इन मूलभूत ऋधिकारों की सूची बनाने ऋौर कियात्मक रूप देने में जिनकी हम उपेक्वा नहीं कर सकते । इन वातों की ऋोर लॉसेन-क्रांफ्रेंस में इस्मत पाशा ने ज़ोरदार शब्दों में, हमारा ध्यान ऋाकर्षित किया था। इस्मतपाशा के शब्दों में, इन दो वातों में से एक तो बाहरी राजनैतिक तत्त्व है, जिसंकी अभिन्यिक अल्प-संख्यक वर्गों की रत्ता के वहाने से विदेशी राज्यों के द्वारा देश के आ्रान्तरिक प्रबंध में हस्तत्त्रेप करने की भावना में होती है, ऋौर दूसरा भीतरी राजनैतिक तत्त्व है, जिसकी अभिन्यिक अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा ही अपने स्वतन्त्र राज्य बना लेने की इच्छा में होती है। ये दोनों तत्त्व एक-दूसरे में गुंथे-मिले हैं। देश के आ्रान्तरिक प्रवंध में हस्त द्वीप करने के लिए उत्सुक विदेशी शक्तियां ऋल्पसंख्यक वर्गों को राज्य के विरुद्ध उकसाती रहती हैं, ऋौर जब उनका ऋसन्तोष किसी ऋांदोलन के रूप में प्रकट होता है, तब उनके बचाव के बहाने से वह बीच में कूद पड़ती हैं, पर उनका वास्तविक उद्देश्य सदा ही राज्य की शक्ति को कम करना होता है। जेकोस्लोवाकिया में १६३८ स्त्रीर १६३६ में जो कुछ हुस्रा, उससे इस्मत पाशा द्वारा १५ वर्ष पहिले कहे गये शब्दों का पूरा समर्थन मिलता है। सूडेटान-जर्मनों को जेकोस्लोवाक-सरकार के विरुद्ध भड़काने का काम नाजियों द्वारा ही किया गया था । जर्मनी की नात्सी सरकार द्वारा दी गई प्रेरेगा का ही यह परिगाम था कि उन्होंने सरकार के विरुद्ध बंगावत की, परन्तु इस बंगावत से जर्मनी की नात्सी सरकार को जेकोस्लोवाकिया की ब्रान्तरिक व्यवस्था में हस्तत्त्वेप का, बाद में उसे हड़प जाने का, मौक़ा मिल गया । हमारी श्रल्पसंख्यक समस्या का संर-च्नग किसी विदेशी शिक्त के हाथों में दे देने का भी यही परिगाम हो सकता है। किसी भी देश से हम पूर्ण निष्पत्नता की ऋपेता नहीं कर सकते । यह निश्चित है

कि हमें इंगलैएड को भी श्राल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के नाम पर श्रापने श्रान्तिक प्रश्नों में किसी प्रकार का इस्तक्षेप करने के श्रिधिकार से वंचित करना है। किस्स-प्रस्ताव की हमारी श्रस्वीकृति का एक सबसे वड़ा कारण यही था कि उसमें हमारे जातीय श्रोर सांप्रदायिक श्राल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के नाम पर ब्रिटेन की हिंदु-स्तान के भावी शासन-विधान में दखल देने का श्रिधिकार दिया गया था।

सप्र-कमेटी भी मूलमृत ऋधिकारों के शासन-विधान में सम्मिलित किये जाने के पत्त में है। उसका मत है कि हमारे भावी-विधान में व्यक्ति के राजनैतिक श्रौर नागरिक दोनों प्रकार के अधिकारों का पूरा संरत्त्या होना चाहिए, धार्मिक सहि-ध्युता का पूर्ण त्राश्वासन होना चाहिए, जिसमें धार्मिक विश्वासों; परम्परात्रों श्रीर संस्थाओं में हस्तचेंप न करने का श्राश्वासन शामिल होगा, श्रीर सव जातियों की भाषा ग्रोर संस्कृति के बचाव का त्राश्वासन भी होना चाहिए । सप्-कमेटी यदि उन ग्राधिकारों की विस्तृत न्याख्या कर देती, जो ग्राल्पसंख्यक वर्गों श्रीर विशेष कर भारतीय मुसल्मानीं, को दिये जाने चाहिएं तो श्रधिक श्रच्छा होता, परन्तु जान पड़ता है, उसने इस प्रश्न पर मानवी दृष्टिकोगा से ऋषिक विचार किया है, सांप्रदायिक दृष्टिको ए से कम । अन्त में, एक यह प्रश्न रह जाता है कि इन संरक्ष्मों को कियात्मक रूप कैसे दिया जाय। सप्र-कमेटी ने ग्राल्पसंख्यक समितियों (Minorities Commissions) के बनाये जाने का विचार उपस्थित कियां है, परन्तु इस प्रकार की ग्रल्पसंख्यक समितियों का काम केंवल सलाह देना हो सकता है। जहां तक ग्राल्पसंख्यक वर्गों के मूलभूत सांस्कृतिक संरत्ताणों को कियात्मक-रूप देने का प्रश्न है, यह काम सङ्घ-शासन के न्याय-विभाग के सिपुर्द ही सोंपा जाना चाहिए। सङ्घीय न्यायालय (Federal Judiciary) ही मूलभूत श्राधिकारों की रत्ता श्रीर सांप्रदायिक समभौते की स्थापना का दायित्व ग्रापने ऊपर ले सकता है, ग्रीर वही उन सब भागड़ों को निवटा सकता है जो मूलभृत श्रिधकारों को कार्यान्वित करने के संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय-शासन व विभिन्न इकाइयों के बीच पैदा हों।

: १३:

सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के पथ पर

शिक्षा श्रौर समाज-सुधार

वैधानिक योजनाएं श्रीर राजनैतिक सममौते हिन्दुस्तान में रहनेवाली विभिन्न जातियों के श्रापसी संबंधों को श्रञ्छा बनाने की दिशा में एक बड़ी सहायता पहुंचा सकते हैं। वे प्रजातन्त्र के प्रयोग की सफलता के लिए एक श्रच्छे वाता-वरण का निर्माण भी कर सकते हैं, पर वे काफ़ी नहीं हैं। संभव है कि वे वर्तमान की समस्याश्रों को सुलभा सकें, पर भविष्य के निर्माण में वे बहुत दूर तक नहीं जा सकते। उसके लिए देश में सद्भावना, शान्ति श्रीर सममौते का एक स्थायी वातावरण बनाना पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि हम केवल 'जनता का राज्य' ही कायम नहीं कर रहे हैं, परन्तु एक ऐसा राज्य स्थापित कर रहे हैं जो सचमुच जनता के लिए है। हमें यह देखना होगा कि देश का बहुमत सत्ता के मद में यह नहीं जाता, श्रीर श्रल्पसंख्यक वर्ग श्रपनी हीनता का ऐसा विकृत विश्वास श्रपने में विकसित नहीं कर लेते, जो उन्हें न्शंस बना दे।

देश में इसी प्रकार के वातावरण की स्थापना के लिए हमें शिद्धा के प्रश्न को ऋपने हाथ में लेना होगा । सच तो यह है कि प्रजातन्त्र का समस्त भविष्य शिक्ता पर ही निर्भर रहता है: शिक्ता की ऋाधार-भित्ति के विना प्रजातन्त्र का प्रासाद च्रुग में दह जायगा । देश में आज शिद्धा की दशा क्या है ! समस्त जनता का १० प्रतिशत भी पढ़ा लिखा नहीं है। यह १५० वर्षों के स्रंत्रे ज़ी शासन का वरदान (या ऋभिशाप) है ! जिस शासन के अन्तर्गत यह संभव हो उसे श्रिधिक दिनों तक क़ायम रखने का श्रिधिकार नहीं है। उसके स्थान पर किसी ऐसे शासन की स्थापना श्रावश्यक है, जो श्राधुनिक विचार-धारास्रों श्रीर परि-स्थितियों से ऋधिक निकट संपर्क में हो । शिच्वा-प्रसार के विना मताधिकार को वढा देना, जैसा हमारे देश में होता रहा है, वेमानी-सा, बल्कि ख़तरनाक, है। उससे तो यही होगा, जैसा हमारे देश में त्राज हो भी रहा है, कि शक्ति ऐसे नेतात्रों के हाथ में चली जायगी जो, ऋपनी संकीर्ण राजनैतिक दलों के लाभ को इप्टि में रखते हुए, जनता की भावनात्रों को ग़लत दिशा में उभाड़ने की चेष्टा करेंगे। प्रजातन्त्र में प्रत्येक वयस्क पुरुष या स्त्री को मत देने का न्त्रिधिकार तो दिया ही जाना चाहिए, परन्तु शिच्चा का प्रसार उससे भी ऋधिक तेज़ी के साथ होना चाहिए।

प्रजातन्त्र का वास्तविक ग्राधार शिचा ही है । जनता में जनतक शिचाका प्रचार न होगा, उसमें यह क़ावलियत नहीं ह्या सकती कि वह देश में वड़े-वड़े राजनैतिक प्रश्नों को सुलमा सके, जिनके सुलमाने का दायित्व एक प्रजातन्त्र-राज्य में उस पर है। परन्तु, शिचा का ग्रर्थ केवल पढना-लिखना ग्रा जाना या गणित का थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना नहीं है। शिक्ता का स्त्रर्थ कहीं स्त्रधिक व्यापक है। केवल यह नियम बना देना कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्वा प्राप्त करना ग्रानिवार्य होगा, काफ़ी नहीं है। यह देखना भी ज़रूरी होगा कि शिक्षा किस ढंग की हो । शिद्धा यदि न्यक्ति में सिंहप्पुता श्रौर समवेदना की भावना का विकास नहीं कर पाती, श्रौर उसमें दूसरे न्यिक के दृष्टिकोण को समभने की चमता पैदा नहीं करती तो उसे न्यर्थ ही मानना चाहिए । प्रजातन्त्र में शिचा का श्रर्थ होता है कि एक ऐसी समभदारी की भावना का विकास जो हमें सहानुभृति के साथ यह जान लेने की चमता दे कि दूसरे व्यक्ति यदि ग़लत राय भी रखते हैं,तो उनके इस प्रकारकी ग़लत राय बना लेनेके क्या कारख हैं,ऋौर, साथ ही हममें यह प्रवृत्ति भी उत्पन्न कर दे कि उस ग़लत राय में सचाई का जो थोड़ा-बहुत श्रंश भी हो उसे हम सही रूप में समभ सकें। इस प्रकार की समभ्रदारी उसी समय पैदा की जा सकती है जब कि जनता में सही ढंग की शिक्ता के प्रचार की व्यवस्था हो ।

प्रजातन्त्र में किस प्रकार की शिद्धा त्रावश्यक है, इस सम्बन्ध में भी कुछ विचार कर लें। पहिला त्रान्तर जो हमें प्रजातन्त्र-देशों व तानाशाही देशों की शिद्धा में मिलता है वह यह है कि प्रजातन्त्र देशों में विवेक बुद्धि के विकास पर ज़ोर दिया जाता है, जिसके परिणाम-स्वरूप मतों की विभिन्नता सामने त्राती है, त्रीर दूसरे के दृष्टिकोण को सहानुभृति के साथ समभने की च्रमता भी पैदा होती है, जिससे सहिष्णुता की भावना का विकास होता है, विभिन्नतात्रों के बीच समानता के सूत्र को खोज निकालने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तानाशाही देशों में, इसके विल्कुल विपरीत, शिद्धा का ज़ोर कहरता के विकास, सामृहिक भावनात्रों की ग्रामिव्यक्ति त्रीर ग्रसहिष्णुता के ग्राधार पर प्रस्थापित समानता की भावना की ग्रामिवृद्धि पर रहता है। एक दूसरी विशेषता जो हमें तानाशाही देशों की शिच्धा में मिलती है, यह है कि उसमें शिच्धा के शारीरिक पच पर श्रिषक ज़ोर दिया जाता है, ग्रीर उसके मनोवैज्ञानिक, भावना-शील ग्रीर सांस्कृतिक पच की उपेच्धा की जाती है। हिटलर ने जो ग्रादर्श त्रपने देश के युवकों के सामने रखा था वह यह था कि उन्हें शिकारी कुत्ते की तरह तेज, चमड़े की तरह सख्त, ग्रीर फ़ीलाद की तरह मज़बूत होना चाहिए। शारीरिक शिच्धा को उपेच्धा की टिष्ट से

नहीं देखना चाहिए, पर उसे ही शिक्ता का श्रान्तिम लक्ष्य मान लेना स्पष्टतः ग़लत होगा । प्रजातन्त्र में शिक्ता का मुख्य लक्ष्य विवेक रहता है, क्योंकि उसका विकास शरीर के विकास की श्रपेक्ता कहीं श्रिधिक श्रावश्यक है। शिक्ता में किन्हीं निश्चित श्रादशों पर भी ज़ोर नहीं दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों से यह श्रपेक्ता नहीं की जानी चाहिए कि वे श्रच्छे नाज़ी, या श्रच्छे कम्यूनिस्ट, या श्रच्छे प्रजातन्त्र-वादी भी, वनें। शिक्ता का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि उनमें मानवी गुणों का विकास हो सके। वह व्यक्ति को एक श्रच्छा मनुष्य बना दे, एक ऐसा मनुष्य जिसके श्रपने विचार हों, श्रोर जो उन विचारों को निर्मयता के साथ श्रभिव्यक्त कर सके, पर साथ ही जिसमें दूसरे मनुष्य के दृष्टिकोण को समभने की प्रवृत्ति श्रीर च्यमता भी हो।

त्र्याजकल प्रायः प्रत्येक देश में समाज-विज्ञान (Sociology) के त्रभ्ययन पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। शिक्ता के दृष्टिकोण में श्राज सर्वत्र एक स्नामूल-परिवर्त्तन होरहा है। सभी जगह शिद्धा को मनुष्य के सामाजिक जीवन से संबद्ध करने के प्रयत किये जा रहे हैं। हमारे देश में भी भूगोल, ऋर्थ-शास्त्र, इतिहास, राजनीति स्नादि विषयों को मानव के दृष्टिकोगा से स्रध्ययन करने की त्रावश्यकता है । समाज विज्ञान के समुचित त्राध्ययन से ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किये गये प्रचार या सामृहिक भावुकता के स्त्राक्रमणों से बुद्धि स्त्रौर इच्छा को वचाया जा सकता है, समाज-विज्ञान ही व्यक्ति को समाज की परिधि में ऋपना उचित स्थान पा लेने में सहायक हो सकता है, समाज-विज्ञान की शिच्छा को व्यापक बनाने के साथ ही एक दूसरा आवश्यक काम यह होगा कि हमारे शिचा-लयों में अधिक-से-अधिक विद्यार्थियों और वयस्कों की विभिन्न धर्मों, साहित्यों, कलाश्रों श्रौर संस्कृति के श्रन्य विभागों के तुलनात्मक श्रध्ययन की सुविधा दी जाय । डॉ॰ वेनीप्रसाद के शब्दों में, ''एक समुदाय के सदस्यों द्वारा इसरे समु-दायों के सिद्धांतीं श्रीर श्रादशों की जानकारी से एक-दूसरे को समभने में वड़ी सहायता मिलेगी, श्रीर श्राधुनिक सामाजिक शास्त्रों के श्रध्ययन से भारतीय विद्यालय न केवल उदार शिक्षा के केन्द्र वन जायंगे, पर वे विचार-क्षेत्र में भी शिक्तशाली त्र्यांदोलनों को जन्म देंगे। इसका प्रभाव धर्म, राजनीति त्र्यौर जीवन के प्रत्येक विभाग को उदार-चेता वनाने की दिशा में पड़ेगा । इससे नागरिक की भावना के दृढ़ बनने में भी सहायता मिलेगी।" सामाजिक शास्त्रों के ह्यलावा. उतना ही ज़ोर कल्पना-प्रसूत साहित्य श्रीर ललित कलाश्रों के श्राध्ययन पर भी दिया जाना चाहिए । कथा-साहित्य के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उससे

१-बेनीशसाद: Hindu-Muslim Questions ए० १०४:

हमें अपने साथियों को सहानुभृति के साथ समभने में सहायता मिलती है, परन्तु एकता की जिस भावना का जन्म वाद्य अथवा मौखिक सङ्गीत की सह-साधना में होता है वह किसी अन्य साधन के द्वारा सम्भव नहीं है। प्रसिद्ध लेखक लेनार्ड के शब्दों में, ''सङ्गीत-प्रेम राजनैतिक मतभेद और सामयिक श्रेगीभेद को चीरता हुआ व्यक्ति को उनसे ऊपर उठा ले जाता है। यदि वे लोग जो राजनीति में एक-दूसरे के विरोधी हैं, एक ही सङ्गीत-मंडली में, एक साथ वैख़ और हैरडेल के गीतों को दोहराएं तो उनमें सिहप्युता और पारस्परिक सहानुभृति की वह भावना जो शासन की प्रजातन्त्रात्मक पद्धित को सुरक्तित रखने के लिए निर्तात आवश्यक है, अधिक गहरी होगी, और सुदृद्ध वनेगी।"

प्रजातन्त्र की एक दूसरी वड़ी ब्रावश्यकता समाज-सुधार की भावना का विकसित होना है। शिचा ग्रौर समाज-सुधार का ग्रान्दोलन, दोनों साथ-साथ, बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यदि शिचा के साथ-साथ सबके सामने वरावर श्रवसर, श्रौर प्रत्येक व्यक्ति के सामने श्राधिक-से-श्राधिक श्रवसर, उपस्थित नहीं होजाते तो इसका परिगाम सम्भवतः सामाजिक श्रराजकता हो। शिक्ता में एक श्रामृल परिवर्त्तन के साथ-साथ हमारी सामाजिक संस्थात्रों के पुनर्निर्माण की त्रावश्यकता भी है। हम श्रवने को एक विचित्र परिस्थित में डाल लेंगे, यदि हम एक स्रोर तो नये ढंग की शिक्ता के विकास में जुट पहें, स्रोर दूसरी स्रोर ग्रपने पुराने रीति-रिवाजों ग्रौर समाज के मध्यकालीन ढांचे को भी ज्यों-का-त्यों रखने की चेष्टा करें। भारतीय नारी की वर्तमान स्थिति में एक वड़े सुधार की त्रावश्यकता है। त्रास्पृश्यता का कलंक हमारे देश से मिट ही जाना चाहिए। मज़दूरों के लिए ग्रन्छे मकान, वही हुई तनख्वाहों ग्रीर काम करने की परिस्थि-तियों में त्रामूल-मुधार की ज़रूरत भी है ही। जात-पांत की व्यवस्था को या तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, या नष्ट होना पड़ेगा। जब तक कि स्राज से कहीं ग्राधिक ग्रच्छे ढंग की शिचा के सार्वजनिक ग्रौर व्यापक प्रचार के साथ-साथ समाज सुधार का एक इन्किलाबी आन्दोलन खड़ा नहीं होजाता, हमारे देश में प्रजातन्त्र की जड़ें सदा खोखली ही रहेंगी ।

शिक्षा और ऋर्थिक पुनर्निर्माण

परन्तु हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शाप तो गरीबी है। एक काफ़ी लंबे अर्से तक हमारी शिद्धा और समाज-सुधार की समस्त प्रवृत्तियों का लद्द्य इस गरीबी को दूर करना होगा। शिद्धा और समाज-सुधार की प्रवृत्ति के अभाव का मुख्य कारण गरीबी है, और जब तक इन प्रवृत्तियों का समुचित विकास नहीं होजाता,

१—लेनार्ड : Democracy, प्र॰ ५३ :

गरीवी का दूर होना असंभव है। एक भयानक चक्र बन गया है, जिसके तोड़ने की ज़रूरत है, श्रीर वह तोड़ा उसी समय जा सकेगा, जब चारों श्रीर से उस पर एक साथ त्राकमण हो । हमारा देश कृषि-प्रधान माना जाता है, पर हमारे देश के ८० प्रतिशत व्यक्ति गांवों में रहते हैं, श्रौर उनमें से ६० प्रतिशत का जीवन-निर्वाह कृषि के द्वारा होता है। पर कृषि के हमारे साधन पुराने श्रीर दिक्तयानूसी हैं। ज़मीन का एक वड़ा हिस्सा बेकार पड़ा हुआ है, जो थोड़ी-सी मेहनत से उपजाऊ बनाया जा सकता है, श्रीर जो हिस्सा श्राज जोता जा रहा है, वह भी, यदि कृषि के वैज्ञानिक साधन काम में लाये जायं तो आज से कई गुना अधिक फ़सल पैदा कर सकता है। इन साधनों के अपनाये जाने पर आज क्यों ज़ीर नहीं दिया जारहा है, ऋंग्रेज़ी शासन के पहिले हिन्दुस्तानी केवल खेती पर ही नहीं रहते थे, उद्योग-धंघों में भी त्रागे बढ़े हुए थे। हिंदुस्तान के केवल जुलाहे ही एशिया, ऋफीका ऋौर यूरोप, तीन महाद्वीपों की कपड़े की ऋधिकांश ज़रूरत को पूरा करते थे। श्रंग्रेज़ी शासन में हमारे उद्योग-धंधों का श्रंत होगया, पर स्राज जब स्रंगेज़ी शासन का स्रन्त समीप है, तब इन उद्योग-धंधों को पुन-जींवित करना होगा, ज्यों-का-त्यों नहीं पर विज्ञान के नये श्राविष्कारों को ध्यान में रखते हुए । श्रोद्योगीकरण के भी कई स्तर होंगे, कुछ बड़े पैमाने पर, कुछ साधा-रण श्रीर कुछ गांवों के भोंपड़ों में बिखरा हुआ। यह सब करने के लिए नये ज्ञान ऋौर विज्ञान से परिचित होने की आवश्यकता होगी। विदेशों में अपने चुने हुए विद्यार्थियों को भेजना होगा। श्रीद्योगीकरण के इस पुनर्निर्माण को श्रपनी ग्राम-सधार की देश-व्यापी योजनात्रों से भी संबद्ध करना होगा। देश के उद्योग-धंधों की कमी के कारण ज़मीन पर जो बहुत श्रिधिक वोभा होगया है उसे कम करना होगा । जनता के एक बहुत बड़े श्रंश को खेती से हटाकर श्रौद्यो-गीकरण में लेना होगा। देश की समृद्धि श्रीर जनता के सुख को एक सूत्र में पिरो देना होगा । हमें ऋपना उद्देश्य यह रखना होगा कि देश का कोई वयस्क ्रश्रीर खस्य मनुष्य वेरोजगार न रहे ।

शिचा श्रीर समाज-सुधार की प्रवृत्तियों के द्वारा देश के धन श्रीर समृद्धि को तो बढ़ाया जा सकता है, पर जब तक सही शिचा श्रीर वास्तिवक समाज-सुधार न हो, तब तक देश में श्रार्थिक समानता की स्थापना नहीं की जा सकती, श्रीर विना इस श्रार्थिक समानता के देश के धन श्रीर समृद्धि का बढ़ाया जाना केवल व्यर्थ ही नहीं श्राहितकर भी सिद्ध होगा। हमारे मुख्य उद्देश्य यह नहीं हैं कि हमारे यहां के श्रमीर श्रिधक श्रमीर वन जायं, श्रीर गरीव श्रपनी गरीवी में ही सब करना सीखें। प्रंजीवाद को जितना वल मिलेगा, प्रजातन्त्र उतना ही

ख़तरे में पड़ेगा। जनता को केवल ऋपने राजनैतिक खात्वों के लिए ही नहीं, श्रपनी श्रार्थिक समानवा की रचा के लिए सतव जागरूक रहना पहेगा । श्राजादी चाहे वह राजनैतिक हो या श्रार्थिक, सतत, प्रतिच्ला, प्रतिपल जायत रहने में ही क़ायम रखी जा सकती है। इस कारण हमारी शिक्ता ग्रीर समाज में समानता की स्थापना करने के सभी प्रयत्नों ख्रीर ख्रांदोलनों के लिए ख्रार्थिक प्रश्नों से ख्रपना सीधा सम्बन्ध बनाये रखना आवश्यक होगा। शिक्ता की कल्पना यदि हम दो विभिन्न—साधारण श्रीर विशेष-चेत्रों में करें, तो यह कहा जा छकता है कि इमारी साधारण शिक्ता का ज़ोर समाज-सुधार की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने पर होगा, हमारे विशेष शिक्ता पाये हुए विद्यार्थी ग्रपना समस्त ज्ञान श्रार्थिक पुन-र्निर्माण की दिशा में लगा देंगे । विज्ञान ने हमारे जीवन के मूल्यों में श्रामूल-परिवर्तन कर दिया है। हमारी श्रौद्योगिक, कृषि-सम्वन्धी श्रौर सांस्कृतिक प्रगति, श्रीर हमारे देश का बचाव तक, श्राज विज्ञान पर ही निर्मर है। ऐसी दशा में, वैज्ञानिक ग्रनुसन्धान के लिए राज्य की ग्रोर से ग्राच्छे-से-ग्राच्छा प्रवन्ध होना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसन्धान के द्वारा ही इस देश के राशि-राशि प्राकृतिक साधनों से पूरा लाभ उठा सकेंगे, श्रीर पानी के बहाव में बंधी हुई श्रपार विद्युत-शिक्त को भी मुक्त करके उससे अपने सुख और-समृद्धि को बढाने का काम ले सकेंगे।

सामाजिक समानता की सृष्टि

शिक्षा के व्यापक प्रचार, समाज-सुधार की प्रवृत्ति के विकास ग्रौर श्रार्थिक समानता की स्थापना, के परिणाम-स्वरूप ही हम देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकरों, जिसमें सामाजिक समानता की भावना वह ग्रौर फैल सके। जब देश में काम बहुंगा, तब समाज के विभिन्न ग्रंगों के लिए एक दूसरे से मिलजुल कर काम करने के मौके भी वहेंगे, ग्रौर मिलने-जुलने से ही एक-दूसरे को समभा, ग्रौर एक-दूसरे के प्रति स्तेह ग्रौर ग्रादर की भावना को बहाया जा सकता है। मिल-जुल कर काम करने के मौके जितने श्रीधक मिलते हैं, मेल-जोल उतना ही ग्राधक बहुता है। एक कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति ग्रापने को धर्म ग्रथवा जाति के ग्राधार पर विभिन्न वर्गों में नहीं बांटते, ग्रार्थिक स्वार्थ ही उनकी दलवन्दी की मुख्य प्रेरणा का काम देते हैं। हिन्दू पूंजीपित जो मज़दूर की गाड़ी कमाई पर मौज उड़ाता है, हिन्दू-मज़दूर की दृष्टि में उतना ही हेय ग्रौर पितत है, जितना मुसलमान मज़दूर की। देश के ग्रार्थिक विकास के साथ सहकारी समितियों ग्रादि की भी ग्राधिक संख्या में स्थापना होगी। जैसे-जैसे उनकी संख्या बहेगी, ग्रौर एक बड़ी मात्रा में देश के विभिन्न वर्गों के सदस्य

उसमें भाग लेंगे, उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास पाना भी सहज स्वाभाविक होगा।

सच तो यह है कि ग़रीवी श्रीर ग़रीवी की यन्त्रखाएं ज्यों-ज्यों कम होती जायंगी, सामाजिक सहयोग की भावना बहेगी: भूखा त्रादमी तो रोटी के एक कौर के लिए भी प्रारा लेने या देने के लिए तैयार होजाता है, पर जिसके पास पेट भर रखने के लिए हो वह छोटी बातों पर भंगड़ा नहीं किया करता। श्राज के हमारे सांप्रदायिक वैमनस्य की जड़ में यह त्र्यार्थिक बेबसी है। किसान, छोटे दुकानदार, सरकारी नौकर, सभी के लिए ब्राज का मुख्य प्रश्न रोटी का संघर्ष है स्रोर स्राज हमारे स्नाय इतने दुर्बल होगए हैं, स्रोर हमारी विवेक बुद्धि इतनी कुंठित, कि जहां हमें रोटी के छिन जाने का भूंठ-मूंठ का भय भी होजाता है, हम वौखला से जाते हैं श्रीर वांछित-श्रवांछित सभी प्रकार के वर्गों के करने के लिए उद्यत होजाते हैं। यदि हमारे देश में रोज़गार का चेत्र इतना संक्रुचित न होता, श्रीर हमारे मध्यम वर्ग को, जिसके हाथ में प्रायः देशों का नेतृत्व रहा करता है, सरकारी नौकरी पर इतना निर्भर नहीं रहना पड़ता, तो मुक्ते पूरा विश्वास है कि, हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों का इतिहास त्राज से विल्कुल दूसरा होता । त्राज हम देश-व्यापी अथवा स्थानीय किसी भी प्रकार की राजनीति को लें, हम-अासानी से यह देख सकेंगे कि हमारे अधिकांश राजनैतिक सङ्घर्षों का मूल-कारण आर्थिक ही है। यदि मुसल्मान किसानों को हिंदू ज़र्मीदार के स्त्राश्रित न रहना पड़े, या हिंदू साहूकार से कर्ज़ न लेना पड़े, इसी प्रकार यदि हिंदुओं के साधारण आर्थिक स्वत्व किसी मुसल्मान के ऋार्थिक स्वत्वों की बिल पर ही निर्भर न हों, तो यह निश्चित है कि देश में एक विभिन्न वातावरण की सृष्टि हो सकेगी। यह एक नि:संदिग्ध तथ्य है कि जब देश में नये श्रीद्योगिक श्रीर व्यवसायिक धंधे निकल न्त्रायंगे, न्त्रौर वैज्ञानिक साधनों के न्त्रालंबन से पुराने धंधे भी एक नया जन्म ले लेंगे, हमारे समाज का वर्तमान रूप विल्कुल ही वदल जायगा। इन श्रार्थिक प्रवृत्तियों का एक सीधा प्रभाव तो यह होगा कि देश का वह मध्य-कालीन सामन्तशाही वर्ग, जुर्मीदार श्रादि जो ग्रामीण जीवन में हिन्दू श्रीर मुसल्मानों को एक साथ रखने की समता खो चुके हैं, अपना महत्व खो देंगे और एक ओर वो मध्यमवर्ग की शक्ति स्त्रीर संख्या दोनों का विस्तार होगा, स्त्रीर दूसरी स्त्रोर निम्न-श्रेगी की स्थिति स्राज से कहीं ऋषिक ऋच्छी होगी । मध्यमवर्ग वेरोज़गारी के उस आतङ्क से सर्वथा मुक्त होगा, जो आज के सांप्रदायिक मतभेदों की जड़ में है, न्त्रीर निम्न-वर्ग या तो राज्य की सुन्यवस्था के परिणाम-स्वरूप या एक वड़ी कांति के द्वारा, श्रपनी स्थिति ऐसी बना लेगा कि उसे भी श्रपनी दैनिक

श्रावश्यकताश्रों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना होगा । वैसी दशा में सांप्रदायिक गलतफहमियां श्रापने श्राप मिट जायंगी, क्योंकि हम में से हर एक की दृष्टि भूत-काल के भग्नावशेषों पर नहीं भविष्य के सुनहले स्वप्नों पर होगी ।

राष्ट्रभापा की समस्या

किसी भी देश के राष्ट्रीय जीवन में भाषा का स्थान वहें महत्व का है। भाषाहमारे विचारों का साधन है, उसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक न केवल ग्रपनी दैनिक ग्रीर साधारण ग्रावश्यकतात्रों को ही प्रदिशत कर सकता है परन्तु उनकी ग्रम्भृति की गहराई, कल्पना की उद्धान ग्रीर भावों की उदारता उसी में मूर्च-रूप धारण कर लेती है। भाषा, इस प्रकार, राष्ट्र-जीवन के साथ गुंथी हुई है। वह उस जीवन का प्रतीक भी है, भाषा के उत्थान-पतन में हम राष्ट्रीय-जीवन के उत्थान-पतन की कहानियां पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय-जीवन जब कभी ऊंची उद्धान लेता है भाषा ग्रपने ग्राप शुद्ध, प्रखर ग्रर्थवाहिनी वन जाती है, राष्ट्रों के पतन के साथ भाषा का तेज नए होता जाता है। ऐसी तेजहीन भाषा का सहारा लेकर साहित्य पनप नहीं पाता, ग्रीर राष्ट्रीय-जीवन दिन प्रतिदिन शुष्क होता चला जाता है।

हम यदि किसी देश की सची स्थिति जानना चाहें तो उसकी मापा को बारीकी से देखें। महाकिव मिल्टन के शब्दों में, "किसी देश के शब्द यदि कुरूप श्रीर वेढंगे हैं, श्रीर उनका उचारण श्रशुद्ध है, तो वे इस वात का प्रत्यच्च प्रमाण हैं कि उस देश के रहने वाले मुस्त, काहिल श्रीर निकम्मे हैं, जिनके दिमाग़ किसी भी प्रकार की गुलामी के लिए तैयार हैं।" इसी प्रकार यदि हम किसी देश को श्रपनी भाषा के प्रति सतर्क, श्रीर उससे उन्नतिशील ननाने में तत्वर पाते हैं तो, यह निश्चित है कि उसकी सम्यता कम-से-कम पतन की श्रीर मुकी नहीं है, श्रीर उसका भविष्य किसी प्रकार से चिन्तनीय नहीं है। जवाहरलालजी के शब्दों में, "जीवित भाषा नवचेतना से श्रनुप्राणित, सशक्त, परिवर्तनशील श्रीर सतत प्रगतिशील होती है, श्रीर उन लोगों के जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, जो उसे बोलते श्रीर लिखते हैं।"

किसी वढ़ते हुए देश के लिए तो भाषा का प्रश्न एक वहुत ही आवश्यक प्रश्न है। भाषा की एकता राष्ट्रीयता को सुदृढ़ बनाने बाले ज़रूरी तत्वों में से एक है। विना एक राष्ट्रभाषा के, जिसमें समस्त देश के सामान्य जीवन की ग्रामिन्यिक हो और जिसे देश का एक ग्राधिकांश भाग समक्त सके, किसी राष्ट्र का ग्रामे बढ़ना कठिन वात है। राष्ट्र में भाषाओं का जितना बाहुल्य होगा, एक दूसरे में जितना अन्तर होगा, राष्ट्रीयता की भावना के सवल बनाने में उतनी ही कठिनाई होगी। यह भी एक कारण है कि हमारी राष्ट्रीयता की समस्या इतनी

जटिल वन गई है। हमारा देश एक महाद्वीप के समान है, जिसमें दर्जनों भाषाएं वोली जाती हैं, श्रोर उनके सैकड़ों रूपान्तर हैं। उत्तर भारत में ही हिंदी श्रोर उद्दे के श्रालावा बंगला, मराठी श्रोर गुजराती हैं। दिल्लाण में तामिल, तेलगू, मलयालम श्रादि हैं। इनके श्रालावा उड़िया, श्रासामी, पंजाबी श्रोर पश्तो हैं। भाषाश्रों की इस विविधता के कारण एक ही संदेश एक साथ देश के कोने-कोने तक पहुंचाया जाना एक श्रसंभव काम है। दिल्लाण भारत की भाषाश्रों को उत्तर भारत की किसी साधारण सभा में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, श्रोर हिंदी वालों के लिए गुजराती, मराठी श्रथवा बंगला समक्तना बहुत श्रासान काम नहीं है। बंगाली गुजरात के किसी प्रदेश में श्रपनी भाषा से काम नहीं चला सकता। श्रोर केवल मराठी जानने वाले के लिए किसी भी मराठी-इतर प्रदेश में समक्ता जाना श्रसंभव है।

भाषात्रों की इस विविधता त्रौर दूरी के कारण ही त्रंग्रेज़ी ने हमारे राष्ट्रीय-जीवन में इतना प्रमुख स्थान ले लिया है। एक काफ़ी लंबे समय तक हमारे शिक्ति-वर्ग ने उससे राष्ट्र-भाषा का ही काम लिया है। पंजाबी इसके द्वारा एक शिचित मनुष्य पर, चाहे वह बंगाली हो ऋथवा मद्रासी, ऋपनी भावनाएं प्रगट कर सकता है। हमारी राष्ट्रीय चेतना का भी वह एक त्रावश्यक माध्यम रही है। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की थर्रा देने वाली वक्तताएं, महामना गोखले के ऋध्ययनपूर्ण भाषरा, गांधीजी की प्रमुख विचार धाराएँ श्रीर जवाहरलाल के अन्तर्राष्ट्रीय परि स्थिति के विश्लेषण हमें ऋंग्रेज़ी में प्राप्त रहे हैं। ऋाज भी राष्ट्रीय महासभा तक की कार्यवाही प्रधानतः ऋंग्रेज़ी में होती है। पर, यह शुभ लक्त्ए नहीं है। ऋंग्रेज़ों के सांस्कृतिक गुलाम वने रह कर राजनैतिक मुक्ति की कल्पना करना एक हास्या-स्पद बात है, क्योंकि वैसी दशा में हमारी शासन-व्यवस्था चाहे कितनी ही सुगठित श्रीर स्वतन्त्र क्यों न हो, हम बच्चे के समान श्रंग्रेज़ी-संस्कृति के श्रंचल में लिपटे रहेंगे | हमारी दशा उस क़ैदी के समान होगी, जिसके पैरों की वेड़ियां खोल दी जाती हैं, पर जो निष्कियता की एक लम्बी श्रादत सें श्रपने चलने की शक्ति को खो बैठा हो। एक राष्ट्र-भाषा को हम पालें, ऋौर ऋपने उल्लास, ऋाकां जा ऋौं त्र्यौर स्वप्नों से उसमें प्राण-प्रतिष्ठा कर सकें, तो स्वतन्त्रता हमारे दरवाजे पर श्रायगी श्रौर कहेगी, "मुक्ते स्वीकार करो"।

देश में भाषात्रों की इतनी विविधता होते हुए भी राष्ट्रभाषा का सवाल ऊपर से त्रासान दिखाई देता है, इस संबंध में ऋव विशोष मतभेद नहीं रह गया है कि हमारी राष्ट्र-भाषा वही हो सकती है जो उत्तर-भारत के ऋधिकांश भागों में वोली जाती है, ऋौर जो संस्कृत ऋौर फ़ारसी-ऋरवी के शब्दों के ऋनुपात से हिंदी

त्रथवा उर्दू के नाम से प्रख्यात है, श्रीर इसी श्रनुपात के श्राधार पर देवनागरी श्रथवा श्ररवी लिपि में लिखी जाती है। वंगला वालों की श्रीर से उत्तर-भारत की भापा का राष्ट्र-भापा के पद के इस दावे का विरोध भी हुत्रा, जो कुछ श्रंशों में श्रव भी मौजूद है, पर उसका श्राधार मजवृत नहीं था। वंगला वालों का कहना था कि क्योंकि उनका साहित्य श्रेष्ठ है, श्रीर हिन्दी ने वंकिम, रवीन्द्र-नाथ, शरत् चटजीं जैसे साहित्यकार पैदा नहीं किये, इसलिए वंगला को राष्ट्र-भापा का पद मिलना चाहिए। पर, राष्ट्र भापा के निर्णय के लिए साहित्य की ऊंचाई का मापदएड उपयुक्त नहीं है। यों तो मराठी श्रीर गुजराती वाले भी हिन्दी-साहित्य से श्रागे बढ़े होने का दावा, कुछ दिनों पहिले तक तो, कर ही सकते थे। श्रीर, यदि साहित्य की ऊंचाई से राष्ट्र-भाषा का निश्चय होता हो तो हम वंगला को क्यों लें, फैंच को क्यों न लें ? राष्ट्र-भाषा तो वही भाषा हो सकती है जिसे देश के श्रधिकांश लोग श्रासानी से समम सकें, सीख सकें श्रीर सिखा सकें।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि हम भारतीय भाषाओं में से किसे राष्ट्रभाषा के लिए चुनें। वह तो हिंदी अयवा हिंदु-स्तानी (उसे उर्दू भी कह सकते हैं) है ही। प्रश्न यह है कि उसका कीन-सा रूप राष्ट्रभाषा के लिए उपयुक्त है। पंजाब से लेकर विहार तक और काश्मीर से मध्य-प्रांत के सुदूर कोने तक इसी भाषा के कई रूप (shades) बोलचाल की भाषा के प्रयोग में आते हैं। लाहीर के सर्वसाधारण की भाषा में कारसी और अरवी के शब्द अधिक संख्या में पाये जाते हैं, दिल्ली की भाषा में कारसी और अरवी का रंग है तो, पर बहुत गहरा नहीं। कानपुर की भाषा में संस्कृत के शब्द मिल गये हैं, और इलाहाबाद और बनारस आदि में तो भाषा बहुत अधिक संस्कृतमयी होजाती है।

में बोलचाल की भाषा की बात कर रहा हूं; साहित्य को भाषा की नहीं ! यह हमारे देश का दुर्भाग्य हे—श्रीर भाषा की समस्या के साथ हमें उसे भी सुलमा लेना है—कि हमारे यहां जनसाधारण की मापा श्रीर साहित्य की भाषा के बीच एक बड़ी गहरी खाई पैदा होगई है, लो दिन-पर-दिन श्रिषक चौड़ी होती जारही है। साहित्य के लिए उत्तर-मारत में दो श्रालग-श्रालग भाषाएं बन गई हैं। वे हैं उर्दू श्रीर हिन्दी ! उनके श्रालग-श्रालग श्रीर एक दूसरे को कहीं स्पर्श न करने वाले (Exclusive) दायरे बन गए हैं। इन दायरों में ही उनका विकास भी तेज़ी के साथ होरहा है, एक के साहित्यकार श्रापनी प्रेरणा श्रारव श्रीर ईरान के साहित्य श्रीर जीवन से प्राप्त करते हैं, श्रीर दूसरी के, श्रापनी

भाषा को फ़ारसी और अरबी के प्रभाव से सर्वथा मुक्त बनाने, और उसे संस्कृत-मयी बनाने पर तुले हुए हैं। यह बात मैं उर्दू और हिन्दी दोनों साहित्यों की मुख्य धाराओं के लिए कह रहा हूं। दोनों भाषाओं के लेखकों में एक दल ऐसा भी है जिसने इस (Puritanical) और (Seporist) आन्दोलन के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ ऊंची की है।

हिंदी बनाम उद्

हिंदी श्रीर उर्दू मूलतः एक ही भाषा हैं, यह एक ऐसा तथ्य है जिसकी सचाई से इनकार नहीं किया जा सकता। भाषात्रों का सम्बन्ध जानने के लिए हमें तीन वातों पर नज़र रखना चाहिए—(१) शब्दों के उचारण की पद्धति, (२) वाक्य-रचना, श्रौर (३) शब्द-कोष। इन तीनों में से पहिली दो वार्ते मुख्य हैं। इनमें भी वाक्य रचना भाषा का मुख्य त्राधार होता है, जो प्रायः त्रपरि-वर्त्तनीय रहता है, शब्दों के उचारण की पद्धति में, एक लम्बे काल में थोड़ा-बहुत श्रन्तर श्रा जाता है, परन्तु शब्दकोष तो प्रायः सांस्कृतिक परिवर्त्तन के प्रत्येक भोंके के साथ बदलता रहता है.। काव्य-रचना की पद्धति अपने-स्राप से गठी हुई रहने के कारण अपरिवर्त्तनीय है, पर शब्द न तो इस प्रकार के किसी नियम का ही पालन करते हैं, न वे दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहते हैं। उनमें से हर एक की ऋपनी ऋलग स्थिति है। उनके वदलते रहने से भाषा नहीं बदला करती । राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के साथ-साथ भी कभी शब्दों में वड़ा परिवर्त्तन होजाता है। पहिले महायुद्ध में इस प्रकार शब्दों का बहुत श्रिधिक प्रत्यावर्त्तन हुआ है। अंग्रेज़ी शब्दों का विहष्कार हुआ: फ्रांस की रूढ़ि-पसन्द भाषा ने श्रपनी दोनों बाहें फैला कर श्रंग्रेज़ी शब्दों का स्वागत किया। रूसी लोगों ने अपने शहरों के नाम तक से जर्मनी का 'वर्ग' हटा कर अपने देश का 'ग्राड' रखा—इसी प्रकार सेंट पीटर्स वर्ग पैटरोग्राड वना, श्रीर पीटर-वंश के पतन पर लेनिनग्राड ।

इन नियमों के आधार पर यांद हम हिंदी और उद्दे की जांच करें तो हम देखेंगे कि दोनों भाषाओं का उचारण प्रायः एकता है, और न्याकरण भी मृलतः एक ही है। इस दृष्टि से उद्दे और हिंदी एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, और संस्कृति, वृजभाषा, अवधी, फ़ारसी और अरबी से काफ़ी दूर। अब रही शब्दों के चुनाव की बात। भाषा में कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो जन-साधारण में प्रचित्त हों, कुछ बाहर से उधार लिए जाते हैं, और कुछ दूसरे शब्दों को मिला- जुलाकर अपने बना लिए जाते हैं। उद् अपीर हिंदी दोनों में जन-साधारण में प्रचित्त जो शब्द पाए जाते हैं, वे एक ही हैं; बाहर से लिए जाने वाले शब्दों

में ज़रूर काफ़ी श्रंवर है, श्रीर बढ़ता जा रहा है। उर्दू फ़ारसी श्रीर श्ररवी से श्रपने शब्द चुनती है, हिंदी संस्कृत से श्रीर कभी-कभी संस्कृत से निकली हुई श्रन्य प्रांतीय भाषाश्रों से भी। इसलिए उनके रूप में इतना श्रिधक श्रन्तर होगया है।

इस अन्तर को स्पष्ट रूप से समक्त लेना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। उर्दू और हिन्दी मूलतः एक भापा होते हुए भी, और उनमें आज देश की किसी भी दूसरी भापा के मुकाबिले में आपस में बहुत अधिक साम्य होते हुए भी, अलहदा-अलहदा भापाएं बन गई हैं। हिंदी जानने वालों के लिए उर्दू का समक्तना मुश्किल काम है। लिपि की भिन्नता के कारण पढ़ना तो दूर की बात है, पर मुनकर भी उसके समक्तने में आप कल्पना से ही काम ले सकते हैं, और उस कल्पना को अधिक सतर्क बनाकर तो आप गुजराती, मराठी और बंगला समक्तने का प्रयास भी कर ही सकते हैं। इसी प्रकार उर्दू के समर्थक मित्र, जिनमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, हमारी आज की हिंदी समक्तने में अपने को विल्कुल असमर्थ पाते हैं। बोलचाल की भापां समक्तना उतना कठिन नहीं, पर साहित्य की भापा एक-दूसरे से विभिन्न हैं; किया, कियापद, सर्वनाम आदि को छोड़ दीजिये तो उनमें कहीं साम्य नहीं मिलेगा। नीचे के उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होगी—

" इसमें कोई कलाम नहीं कि इक्तवाल बहुत बलन्द पाया शायर अज़ीमुल मर्जवात मुफ़ाक्किर थे । बाज़ हज़रात को शायद इस बात के तस्लीम करने में पशोपेश हो कि वह उल्मे-रूहानी के मुग्रल्लम और असरारे बातिनी के हकीक भी थे। और उन्हें रूहानियत की गहराइयां मालूम और रमूज़े-मरस्क्री से बख़्वी आगाही थी।"

इसके मुक़ाविले में त्राज की हिन्दी का एक उदाहरण देखिए:-

"हिन्दी-कविवा की नीहारिका, सम्प्रिव, अपने प्रेमियों के वक्ण-उत्साह के वीव-वाप से प्रगित या साहित्याकाश में अत्यन्त वेग से घूम रही है। समय-समय पर जो छोटे-मोटे तारक-पिएड उससे टूट पड़ते हैं, वे अभी ऐसी शक्ति वथा प्रकाश संप्रहीत नहीं कर पाये हैं कि अपनी ही ज्योति में अपने लिए नियमित पंथ खोज सकें, जिससे हमारे ज्योतिपी उनकी गतिविधि पर निश्चित-सिद्धांत निर्धारित कर लें। ऐसी दशा में कहा नहीं जा सकता कि यह अस्तव्यस्त केन्द्र-परिधि- हीनद्रवित-वाप्प-पिएड निकट भविष्य में किस स्वस्थ स्वरूप में फलीभृत होगा, कैसा आकार-प्रकार प्रहर्ण करेगा।"

प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपित ग्रमरनाथ भा के शब्दों में × × उर्दू का

सारा वातावरण ऋौर प्रतिभा विदेशी हैं, भारतीय नहीं । इसका प्रमाग यह है कि एक हिन्दू भी, जो हिन्दू दन्तकथात्रों त्रौर पुराणों पर, हिन्दू-धर्म के वातावरण में पला होता है, उद् लिखते समय नौशेरवां, हातिम, शीरीं, लैला, मजनूं , यूसुफ़ की चर्चा करेगा और कभी भूलकर भी युधिष्ठिर, भीम, सावित्री, दमयन्ती, कृष्णा श्रीर दूसरे चरित्रों की, जिससे वह बचपन से परिचित रहा है, चर्चा नहीं करेगा । × × फरहंगे आसिफ़या में, जो हैदराबाद में तैयार किया गया उर्दू का एक नया शब्दकोष है, ७००० ऋरबी के शब्द हैं, ६५०० फारसी कें; श्रौर सिर्फ ५०० संस्कृत के । उद् किवता के लिए जिन छुन्दों का प्रयोग होता है, वे हिंदु-स्तानी नहीं, ईरानी हैं। उद्भें के बहुवचन भी भारतीय पद्धति के ऋनुसार नहीं हैं, फ़ारसी के नियमों का पालन करते हैं । × × पिछले कुछ वर्षों में हिन्दी लेखकों की प्रवृत्ति अपनी भाषा को कृत्रिम, संकुचित और त्राडम्बरमयी बनाने की श्रोर रहा है। वे संस्कृत के अपिरिचित, कठिन और क्लिप्ट शब्दों को प्रयोग में ला रहे हैं । वे प्राचीन हिन्दी काव्यों श्रोर गायकों की सादा शैली का त्याग करते जा रहे हैं। वे भाषा को जनता से, जिसके बीच वह पैदा हुई है, दूर लेते जा रहे हैं। सीधे-सादे प्रामीण जो सूरदास, कवीर ऋौर तुलसीदास को समभते हैं, निराला सुमित्रानन्दन पन्त, त्रौर जयशंकर 'प्रसाद' की भाषा को नहीं समभते।"

यही हमारी आज की भाषा की समस्या है। साहित्य की भाषा जनता की भाषा से दूर जा पड़ी है। मुसल्मानों ने हिन्दुओं से अलहदा अपनी एक भाषा बना ली है, और हिन्दू मुसल्मानों से हट कर अपनी अलग भाषा के विकास-परिवर्द्धन में व्यस्त हैं। इन अशुभ दायरों को तोड़ना है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि साहित्य की भाषा और जनता की भाषा में कुछ अन्तर ज़रूर होगा। श्री के० एम० मुंशी लिखते हैं: ''प्रत्येक भाषा के दो रूप होते हैं: एक से हमारी दैनिक आवश्यकताओं की अभिव्यिक होती है, और दूसरा हमारी कल्पना की उड़ान और विचारों की अभिव्यिक के लिए है। पहिला रूप ऐसा होना चाहिए जिसे सब लोग आसानी से समक्त सकें, और दूसरा रूप भी ऐसा होना चाहिए कि, उसमें कल्पना की उड़ान अपने को अभिव्यक्त और घोषित कर सके। × अने दे दर्जे का साहित्य और उसकी भाषा जनसाधारण की संपत्ति नहीं हो सकती, वह उनके वाहर की चीज़ है। हरएक कारीगर ताजमहल नहीं बना सके, न ताजमहल हरएक आमीण के लिए, रहने का उचित स्थान ही है।"

यह प्रवृत्ति साहित्य के लिए चाहे शुभ हो, पर राष्ट्रीय जीवन का उससे कल्याण नहीं हो सकता—वह साहित्यकार को राष्ट्रीय जीवन से अलहदा काट लेने का प्रोत्साहन देती है। एक गुलाम राष्ट्र के लिए वह लाभदायक नहीं है। उसके

लिए तो साहित्य में कान्ति का संदेश हो ग्रौर वह संदेश गांवों के कोने-कोने तक पहुंच सके । आज हमें साहित्य में कालिदास की ज़रूरत नहीं है, जो एक रोमांस के वातावरण में शकुन्तला जैसे पात्रों की सृष्टि करे, हमें तो गोर्की चाहिए जो मां जैसी चीज़ हमें दे सके। हमारे वीच कालिदास श्रीर भवभूति श्राज हां भी वो उनकी कल्पना की उड़ान की प्रशंसा कराने का समय ग्राज हमारे पास नहीं है, ग्राज़ादी की ग्रपनी इस लड़ाई के बाद शायद हमें उसके लिए फ़रसत हो, ग्राज के विश्व-संघर्ष में शायद वह भी संभव न हो सके । हमें त्राज साहित्यकार की जनता के संपर्क में ले ग्राना है। जवाहरलालजी लिखते हैं-- "ग्राज संस्कृति का श्राधार श्रधिक व्यापक होना चाहिए, श्रीर वही भाषा का जो संस्कृति की श्रभि-व्यक्ति का साधन है, आधार होगा।" आज के युग के सबसे वड़े कलाकार रोमां रोलां ने एक वार लिखा था, "जीवन-कला वही है जो मानवता के निकट संपर्क में हो।" रोमां रोलां लिखते हैं, "यह एक श्रन्छी प्रसिद्ध है, जो श्रपने को जीवन से काट कर, ग्रीर ग्रन्य मनुष्यों से मित्र वन कर, प्राप्त की जाती है ! इस प्रकार के सब कलाकारों का नाश हो । इस तो जीवन के साथ रहेंगे, पृथ्वी के स्तनों से दुरध-पान करेंगे, श्रौर जनसाधारण में जो गहराई श्रौर पवित्रता है उसे स्वीकार करेंगे।" कल्पना की उड़ान त्राकाश की ऊंचाई का स्पर्श करे, पर उसका ग्राधार पृथ्वी पर हो । कलाकार की कल्पना इन्द्र-धनुष के रंगों के समान ज़मीन की छुती हुई त्र्याकाश की त्र्योर उठे।

यह है समस्या का एक अंग। दूसरा अंग कृत्रिमता की उन दीवारों को, जो उर्दू और हिन्दी के बीच चिन दी गई हैं, तोड़ फेंकना है। एक ही प्रदेश के हिन्दू और मुसल्मान अलग-अलग भाषाओं में सोचें, अलग-अलग संस्कृतियों से अपनी प्रेरणा प्राप्त करें, उनके विचार जुदा-जुदा हों, उनकी अभिव्यक्ति का ढंग भिन्न हो, यह असहा है, और यदि इसे जारी रखा गया तो हमारे देश का भविष्य नितांत अंधकारमय है। मैं मानता हूं—और ऊपर की विवेचना में इसकी बहुत खप्ट स्वीकृति है—कि आज उर्दू और हिन्दी दो अलग-अलग भाषाएं वन गई हैं, और उनके साहित्य, और उन साहित्यों की मूल-प्रेरणा एक-दूसरे से भिन्न है, पर यदि हमारी राष्ट्रीयता को जीना है, और विकास पाना है तो शीघ ही मौजूदा उर्दू और हिन्दी के साहित्य इतिहास के संग्रहालयों में पहुंचा देनी चाहिए, और जन-साधारण में से एक सामान्य भाषा को चुन कर, उसमें नई कल्पना की उड़ान और नये भावों के प्रवेश से, एक नये साहित्य का निर्माण करना पढ़ेगा, जो शुद्ध हिंदू अथवा मुस्लिम-संस्कृति का एकान्त प्रतिनिधि न होकर उत्तर-भारत के हिन्दू और मुसल्मान दोनों के अन्यान्य उल्लास-आकांचा और स्वप्तों को हिन्दू और मुसल्मान दोनों के अन्यान्य उल्लास-आकांचा और स्वप्तों को

प्रतीक वन सके, जिसमें हमारे भूत-काल की सिद्धियों का संदेश, श्रीर भविष्य के धादशों की भलक हो ।

समाधान की दिशा

ंइन दोनों भाषात्रों के समन्वय से यदि एक राष्ट्रभाषा की सृष्टि की जाय तो उससे उर्दू वालों को यह डर है कि उर्दू भाषा के विकास को चिति पहुंचेगी। यह डर बिल्कुल काल्पनिक है। इसके पीछे ग़लतफ़हमी के ऋलावा कुछ नहीं है। यह सच है कि उद् हिंदी के समान ही, राष्ट्र-भाषा के लिए एक पोषक-धारां (Feeder) का काम करेगी । पर इससे उसका विकास रुकेगा नहीं । उर्दू के बिना जैसे राष्ट्र-भाषा की कल्पना करना कठिन है, वैसे ही बिना श्रपने को राष्ट्र-भाषा के संपर्क में रखे उर्दू ऋपना विकास भी नहीं कर सकती। वह केवल फ़ारसी श्रीर ऋरबी पर श्रवलंबित रह कर पनप नहीं सकती । इस ज़मीन में उसकी पैदाइश हुई है, इसीसे उसे ऋपनी जड़ों की सींचना होगा। विना इस जीवन-शिक्त को ग्रहरण किये वह सूख ऋौर मुरभा जायगी। स्राज उर्दू का साहित्य उस वेग से स्रागे नहीं वढ रहा है जैसे वंगला, मराठी, गुजराती स्रौर हिन्दी ऋागे वह रहे हैं, इसका कारण यही है कि उसने ऋपने को देश के जीवन से अलहदा कर लिया है। हम लोग जो उर्दू को एक Prodigal Son की तरह, राष्ट्र-भाषा के विस्तृत कुटुम्ब में लौटा ले स्त्राना चाहते हैं, उर्दू के लाभ के लिए भी उतने ही चितित हैं, जितने राष्ट्र के; क्योंकि हम जानते हैं कि उद् को नुकसान पहुंचा कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता ।

उदू एक श्रलग भाषा बन गई है श्रीर एक काफी लंवे श्रसें तक श्रलग भाषा के रूप में उसका विकास होगा। उसे मिटाने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह हमारे लिए मुस्लिम देशों से संपर्क का एक वड़ा श्रच्छा माध्यम वन सकेगी। इस्लाम की संस्कृति में जो सर्वश्रेष्ठ है, उदू के द्वारा हम उसे वड़ी श्रासानी से पा सकेंगे। इस रूप की श्रीर तत्वों के विना—में न तो राष्ट्र-भापा के विकास की ही कोई कल्पना कर सकता हूं, न राष्ट्र के उत्थान की—उदू ही हमें श्ररव-ईरान श्रीर तुर्कों की संस्कृति श्रीर भाषा के संपर्क में रख सकेगी।

सच पूछा जाय तो हिन्दी और उद्दं का आपस में कोई भगड़ा नहीं है— वह तो कुछ ग़लतफ़हमियों के कारण कुछ थोड़े से अर्से के लिए पैदा हो गया है, जिसका मिट जाना ज़रूरी ही नहीं स्वाभाविक भी होगा । गांधीजी ने इस संबंध में लिखा था, "असली प्रतिस्पर्धा तो हिन्दी और उद्दं में नहीं, विल्क हिन्दुस्तानी और अंग्रेज़ी में है। वही करारा मुक़ावला है। मैं तो उसके लिए निश्चय ही वड़ा ही चिन्तित हूं। हिंदी-उद्दं विवाद का कोई आधार नहीं है।

× × हिन्दुस्तानी को मूर्त-रूप देने के लिए हिन्दी ग्रीर उर्दू को उसकी पोषक भाषाएं समभना चाहिए। × × हिन्दी ज्यादातर हिन्दुःश्रों में श्रीर उर्द मुसल्मानों में महदूद रहेगी । × × कोई वजह नहीं कि इन दो वहनों में प्रतिस्पर्धा हो । हां, प्रेम-भरी प्रतिस्पर्धा तो हमेशा ही होनी चाहिए । X X मौलवी साहव ब्राब्दुल हक्क के योग्यतापूर्ण नेतृत्व में उस्मानियां यूनिवर्सिटी उर्दू की वड़ी सेवा कर रही है। यूनिवर्सिटी में उर्दू का एक वहुत वड़ा कीप है। इसकी भी कितावें उर्दू में तैयार की गई हैं, श्रीर तैयार की जा रही हैं। श्रीर चूं कि उस यूनिवर्सिटी में ईमानदारी के साथ उद् में शिक्ता दी जा रही है, इसलिए उसकी तरक्की होनी ही चाहिए । ग्रकारण तास्यव की वजह से ग्रगर स्राज हिंदी-भाषी हिन्दू वहां के बढ़ते हुए साहित्य से लाभ न उठायें तो यह उनका कसूर है । × × मुसलमान ग्रगर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन ग्रौर नागरी-प्रचारिसी सभा के विनम्र परिश्रम के फलों का उपयोग न करें, तो यह उनका कसूर है। 🗙 🗙 यह मैं जानता हूं कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस वात का सपना देख रहे हैं कि यहां ख़ाली उर्दू या ख़ाली हिंदी ही रहेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि यह अपवित्र सपना है, श्रीर सदा सपना ही रहेगा । इस्लाम की त्रपनी ख़ास संस्कृति है, इसी तरह हिंदू-धर्म की भी ग्रपनी संस्कृति है। भावी भारत में इन दोनों संस्कृतियों का पूर्ण ऋौर सुखद सिम्मश्रग रहेगा। जन वह शुभ दिन त्र्यायेगा, तव हिंदू-मुसलमानों की सामान्य भाषा हिंदुस्तानी होगी। लेकिन उर्दू फिर भी ऋरवी-फारसी शब्दों की बहुलता के साथ फूलती-फलती रहेगी स्रौर हिंदी ऋपने संस्कृत शब्दों के भारी भएडार के साथ फूले-फलेगी। शिवली ने जिस भाषा में लिखा है वह मर नहीं सकती। लेकिन उन दोनों की श्रन्छाइयां हिंदुस्तानी जवान में विलकुल घुलमिल जायंगी।" गांघीजी के ये शब्द उर्दू नालों के लिए उनके तमाम शक ख्रीर शुवह को दूर कर देने वाले होने चाहिएं।

त्रीर, मैं तो समभता हूँ, राष्ट्रभाषा का एक प्रमुख त्राधार वन जाने से उर्दू का महत्व बढ़ेगा ही। जहाँ तक 'टेकनिकल' शन्दों का सवाल है अरबी क्रीर संस्कृत दोनों इस च्रेत्र में धनी हैं। एक सामान्य राष्ट्र-भाषा दोनों में से किसी एक पर ही पूर्णतः निर्मर नहीं रह सकती। यदि अरबी को एक विदेशी भाषा मान कर हम उसकी अवहेलना करें तो संस्कृत भी तो जन-साधारण में कभी भी प्रचलित नहीं है और कोई भी जो बोलचाल की हिंदी से परिचित है इस बात को जानता है कि जितने संस्कृत के शब्द इस भाषा में आये हैं वे सव धीरे-धीरे काफी परिचर्तित होते गये हैं और इसका कारण यही था कि उनका

मुसल्मानों के द्वारा नहीं, जनसाधारण के द्वारा भी श्रासानी से उच्चारण नहीं किया जा सकता था। ग्राम श्रीर वर्ष जैसे छोटे-छोटे शब्द भी गाँव श्रीर वरस बन गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि हिंदुस्तानी केवल संस्कृत पर निर्भर नहीं रह सकती।

सच तो यह है कि संस्कृत उसका मुख्य त्र्याधार तक न हो सकेगी। जो लोग बोलचाल के साधारण शब्दों का प्रयोग उनके मूल संस्कृत रूप में करने लगे हैं, वे चाहे कुछ चाहते हों, पर यह स्पष्ट है कि एक जीवित, जनसाधारण में प्रचलित भाषा के प्रचार की चिंता उन्हें नहीं है। गांधीजी भी हिंदुस्तानी में संस्कृत पद्म को प्रधानता देना जरूरी नहीं समभते । श्रादिल साहिव के एक पत्र का उत्तर देते हुए श्रीयुत मुन्शी ने लिखा था कि "गुजराती, महाराष्ट्री, बंगाली श्रीर केरलों ने श्रपनी साहित्यिक प्रवृत्तियां बनाली हैं, जिनमें शुद्ध उर्दू तत्वों का प्रायः प्रभाव है। यदि हम हिंदी को स्वीकार करते हैं तो स्वभावतः ही हम संस्कृतमयी हिंदी को स्वीकार करेंगे।" इसके सम्बन्ध में गांधीजी ने लिखा है, ''पहली बात तो यह है कि मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि गुजराती मराठी श्रीर बंगला सभी भाषात्रों में फ़ारसी के शब्द भी काफ़ी संख्या में हैं, न्त्रीर मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि गुजरात न्त्रीर बंगाल के हिंदुन्त्रों को एक-दूसरे के तथा मुसल्मानों के सम्पर्क में त्राने के लिए त्रपनी भाषा को संस्कृतमयी वनाना ज़रूरी हो । इसके त्रालावा हमें शुद्ध उद् तत्वों से कोई वास्ता नहीं है, हमें तो उत्तर भारत की जीवित भाषा ख्रौर उसके मुहावरों से मतलव है। यदि इस जीवित भाषा को राष्ट्र-भाषा का त्राधार बना लिया जाय तो उसमें मुसल्मान ऋच्छी तरह हमसे सहयोग कर सकते हैं। संस्कृत की ऋोर लौट जाने का मतलव यह होगा कि हम उनकी हिंदी, वंगला श्रौर गुजराती के प्रति कीगई सेवात्रों को भुला देना चाहते हैं। इस प्रकार की शतों पर सहयोग की मांग करना त्रात्म-हत्या में सहयोग की मांग से कम नहीं है।"

जवाहरलालजी लिख़ते हैं, ''हमें इस नये जीवन का, जो हिंदी श्रोर उर्दू दोनों के जेत्रों में प्रवाहर्शील है, स्वागत ही करना चाहिए, यद्यपि वह कुछ समय तक के लिए खाई को श्रिधिक चौड़ा बना देगा । हिंदी श्रीर उर्दू दोनों ही श्राज श्रपने को श्राधिनक वैज्ञानिक, राजनीतिक, श्रायिक, व्यापारिक श्रोर कभी-कभी, सांस्कृतिक विचारों की ठीक-ठीक श्रिमिव्यिक के श्रनुपयुक्त पाती हैं श्रीर इसीलिए श्रपने को श्राधिनक समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के योग्य वना रही हैं श्रीर इसमें उन्हें सफलता भी मिलो है।

 नहीं है जब तक हम हिंदी श्रीर उर्दू शब्दों को श्रपने वातावरण के उपयुक्त न होने के कारण कुचलने की कोशिश करते रहेंगे । हमें तो दोनों की जरूरत है श्रीर दोनों को ही मंजूर करना होगा । हमें इस वात को समभ लेना चाहिए कि हिंदी के विकास का श्रर्थ उर्दू का विकास भी है श्रीर उर्दू के विकास से हिंदी की वृद्धि होगी । दोनों का एक-दूसरे पर बड़ा शिक्तशाली प्रभाव पड़ेगा श्रीर दोनों के शब्द-कोप तथा विचारों में वृद्धि होगी।"

यह मुमिकन है कि बहुत दूर जाकर उर्दू ग्रापनी स्वतन्त्र स्थिति को क्रायम न रख सके ग्रोर एक विकसित राष्ट्र-भाषा में ग्रपने को रंग दे, पर यह तभी संभव है जब राष्ट्रभाषा उर्दू के समस्त सौन्दर्य ग्रोर वैभव को ग्रात्मसात् करने की च्रमता रखती हो। उस समय उर्दू ग्रपना काम कर चुकी होगी। मैं मानता हूं कि उर्दू ने हिंदुस्तान में इस्लाम की संस्कृति की रच्ना करने का महान् कार्य किया है;वह उस संस्कृति से इतनी निकटता से हिलमिल गई है कि जब तक उस संस्कृति को मिटा नहीं दिया जाता या पूरा ग्रपना नहीं लिया जाता उर्दू को मिटाया नहीं जा सकता। इस्लाम से हमने पहले बहुत कुछ सीखा है, ग्राज भी बहुत-कुछ सीखना बाकी है। मैं तो समभता हूं कि हमें एक बहुत बड़ी निधि देने के लिए ही मुस्लिम संस्कृति की एक ग्रलग धारा ग्राज हिंदुस्तान में मौजूद है। जिस दिन इम उसे मुक्त इदय से भारतवर्ष की भावी संस्कृति में मिला सकेंगे, इस विन उसकी ग्रलहदा स्थिति ग्रनावश्यक हो जायगी। मेरे मन में इस संबंध में तिनक भी संदेह नहीं है कि वह दिन दूर नहीं है। हिंदू ग्रीर मुस्लिम संस्कृतियों के संपर्क से एक महान संस्कृति को जन्म लेना है। इस महान् समन्वय की दिशा में काम करने वाली संस्कृतियां इतनी ज़बर्दस्त हैं कि वे व्यिक्तयों द्वारा रोकी नहीं जा सकतीं।

राष्ट्र-भाषा के विकास से प्रांतीय भाषात्रों को तो श्रीर भी कम ख़तरा है। उद् के समान वे हिंदी की ही रूपांतर नहीं हैं। उनका विकास हिंदी से खतन्त्र रूप से हुआ है, श्रीर उस विकास के पीछे बहुत बड़े कारण काम करते रहे हैं। भारतवर्ष इतना बड़ा देश है कि उसमें सर्वत्र एक ही भाषा का व्यवहार श्रसम्भव है। उसमें तो एक-दूसरे से मिली-जुली श्रनेक भाषाएं होंगी, सदा रही भी हैं। उनका मिटाया जाना श्रेयस्कर नहीं; उनकी समृद्धि राष्ट्र की समृद्धि है, पर इस श्रनेकता में लाभ तभी है जब उसके पीछे भारतीय संस्कृति की एकता के सूत्र को देश श्रीर पकड़ सके। श्री मुंशी के शब्दों में, "भारत का साहित्य एक है क्योंकि उसके संस्कार कुछ श्रलग-श्रलग नहीं हैं। जिस तरह श्राकाश के श्रनगिनती तारे गिनने की उतावली में श्रज्ञानी लोग उनकी ताल पर सधी हुई चाल की परीद्या नहीं कर सकते, उसी तरह विशाल श्रन्तर, विभिन्न लिपियों श्रीर भाषाश्रों के भेद

की वजह से भारतीय साहित्य की असली एकता को भी नहीं देख सकते।"

राष्ट्र-भाषा में हम इस राष्ट्रीय एकता की एक दिल्य भांकी देखेंगे, परन्तु भारतीय संस्कृति का बहुमुखी विकास तब भी रुकेगा नहीं, राष्ट्र-भाषा के निकट संपर्क से, और उसका माध्यम लेकर अन्य प्रांतीय भाषाओं के संपर्क से, उसे प्रोत्साहन ही मिलेगा । संस्कृति आपसी सम्पर्कों में ही आगे वढ़ा करती है । राष्ट्र-भाषा के सम्बन्ध में श्री मुंशी ने ठीक ही लिखा है, "यह भाषा तो पढ़े-लिखों की सौतेली मां है । इन भाषाओं को बोलने वालों का जीवन-व्यवहार उनकी मातृभाषा द्वारा ही होगा । उनकी साहित्य-प्रवृत्ति उन्हींकी भाषा के द्वारा विक-सित्त होगी । पर जैसे-जैसे राष्ट्र-भाव बढ़ता जायगा, जैसे-जैसे विज्ञान हिंदुस्तान के भिन्न-भिन्न भागों को एक दूसरे के पास लाता जायगा, जैसे-जैसे सारे देश के संस्कार और जीवन एक-धार होते जायंगे, वैसे-वैसे यह भाषा जीवन-तत्व को प्राप्त करेगी । पर, जहां तक दृष्टि पहुंचती है,वहां तक प्रांतों की देश-भाषाओं का स्थान यह कभी नहीं ले सकती ।"

पर, सबसे श्राश्चर्य की बात तो यह है कि इस भाषा के विकास से हिंदी भी । श्राज कुछ सशंकित-सी दिखाई देती है । हिंदी में एक ऐसा दल जोर पकड़ता जारहा है जो समभता है कि हिंदुस्तानी का स्वागत करने से हिंदी का सर्वनाश होजायगा, श्रोर हिंदू-संस्कृति ख़त्म हो जायगी। हिंदू-संस्कृति इतनी निःशक्त नहीं। पांच सौ वधों के मुस्लिम-शासन में वह ख़त्म नहीं हो सकी तो फ़ारसी श्ररवी के कुछ प्रचलित शब्दों को श्रपनाने से वह मिट नहीं जायगी। रहा हिंदी के सींदर्य का सवाल। सो, मैं तो समभता हूं कि हिंदुस्तानी के रूप में उसका सींदर्य निख-रेगा ही, वह प्रीढ़ श्रोर धनी बनेगी, सारे हिन्दुस्तान के सांस्कृतिक बैभव की छलछलाती हुई धाराएं उसके किनारे पर उछलेंगी, श्रीर उसके चरणों में श्रपनी विनम्र में ट चढ़ाएंगी, श्रीर उससे प्रेरणा प्राप्त कर श्रपने प्रांतों के सांस्कृतिक जीवन के पुनर्निर्माण में व्यस्त होंगी।

साहित्य का परिवर्तित दृष्टिकोण

श्राज हमें श्रपने साहित्य के दृष्टिकीण को भी वदलना है—श्रीर उसके साथ-साथ भाषा का रूप श्रपने श्राप ही वदलता जायगा। उस सव साहित्य को हम ख़ैरवाद कहें, जिसमें परियों के किस्ते श्रीर राजाश्रों की कहानियां हैं। हमें कलाकार के मानसिक चितिज को श्रिधिक व्यापक बनाना होगा। जब तक उसकी सहानुभूति श्रिधिक-से-श्रिधिक व्यापक न होगी, उसको कला में गहराई श्रीर स्थायित्व न पा सकेंगे। प्रजातन्त्र श्रीर साम्यवाद के इस युग में ऊंचे साहित्य श्रीर जन-साधारण के साहित्य की वीच को दीवारों को गिरा देना होगा। हिन्दी

उनको हिन्दुस्तानी में ले लेना चाहिए श्रौर उनके श्रलावा भी नये लफ्ज़ों का वहिष्कार इसलिए ही नहीं होना चाहिए कि वह किसी ख़ास ज़वान से लिये गए हैं, बिल्क इसमें यह देखना चाहिए कि वह कहां तक जल्द लोगों में चल गए हैं या चल जायंगे।" मैं इससे पूर्णवः सहमत हूं।

हां, इस वात पर ख्रालग से ज़ोर देने की ज़रूरत भी है कि 'फ़ारसी ख्रीर ख्रारवी से जो शब्द लिये जायं वे हिन्दुस्तानी के व्याकरण का नियंत्रण मानें । दूसरी भाषाख्रों के शब्द तो ख्रापने ख्राप ढल जाते हैं, पर उर्दू की वाक्य-रचना प्रायः हिन्दुस्तानी से मिलती-ज़ुलती होने के कारण उससे ख्राने वाले शब्द कभी कभी ख्रापने उलमे हुए रूप में ख्रा जाते हैं। 'सल्तनते वरतानियां' हिन्दुस्तानी नहीं है, 'ब्रिटेन की सल्तनत' हो सकता है। हिन्दुस्तानी में हम 'ख्राव' नहीं ले सकते क्योंकि हमारा पानी ख्रच्छा-खासा है, यद्यपि एक विशेष ख्रर्थ में, जैसे 'मोती की ख्राव' में हम उसे स्वीकार कर सकते हैं, पर ख्रावे-हयात हर्गिज़ नहों।

४. हमें प्रांतीय भाषात्रों से भी शब्द लेने पड़ेंगे। यह सच है कि उर्दू को छोड़ कर दूसरी प्रांतीय भाषात्रों का त्राधार या तो संस्कृत रहा है या संस्कृत का उन पर काफ़ी प्रभाव रहा है, त्रौर इस कारण लिपि त्रौर वाक्य-रचना के किया, कियापद त्रादि को हटा दिया जाय तो उनका शब्द भएडार बहुत कुछ हिन्दी से भिलता-जुलता है, पर फिर भी कई सौ वपों के स्वतन्त्र विकास में उन्होंने बहुत से नये शब्द गढ़े हैं या त्रासपास से प्राप्त किये हैं। उनमें से बहुत से शब्दों की ज़रूरत हमें त्रपनी राष्ट्र-भाषा को धनी बनाने में होगी।

गुजरावियों ने आंख की कोमलवा प्रगट करने के लिए एक वड़ा श्रच्छा शब्द 'श्रंखड़ली' बना लिया है। Summing-up के लिए हिन्दीमें कोई श्रच्छा शब्द नहीं हैं—परिशिष्ट, उपसंहार आदि में वह बात नहीं हैं, मराठी के 'समारोप' से वड़े मज़े में काम चल सकता है।

५. इस सब के बाद भी विदेशी भाषात्रों—विशेषकर श्रंभेज़ी—पर हमें निर्भर रहना ही होगा । श्रंभेज़ों के साथ 'रेल' श्राई है, उसके टहरने के लिए 'स्टेशन' वने हैं, जिन पर 'प्लैट-फॉर्म' हैं, कौंसिलें हैं, एसेंवली हैं, श्रीर भी बहुत-श्रमिनत लफ्ज़ हैं, इन सब की श्रंभेज़ों के साथ जहाज़ पर लाद कर वापिस भेजना भी हम क्यों चाहें ! ये सब तो हमारे श्रपने बन ही गए हैं, पर श्रभी तो हम पश्चिम के संपर्क में गुलाम श्रीर मालिक के संबंध में ही श्राये हैं, इसलिए कुछ मामूली जरूरतों की चीज़ें हमें उनसे मिल गई ६, जिनके लिए हम उन्हें धन्यवाद दें श्रीर खुश रहें, पर एक श्राज़ाद हिन्दुस्तान—वह जब कभी भी श्राये, श्रीर मैं समभता हं, जल्दी ही श्रायेगा—पश्चिम के नज़दीक वरावरी से वैटेंगा, श्रीर

तत्र जहां हम उसे बहुत कुछ देंगे, वहां बहुत कुछ सीखेंगे भी ।पश्चिम के विज्ञान को चाहे वह राजनैतिक हो, चाहे आर्थिक या सांस्कृतिक, हमें निकट से अध्ययन करना ही पड़ेगा।

विज्ञान के च्रेत्र में तो हम जितने ज्यादा शब्द पश्चिम से ले सकें, हमें सुभीता रहेगा। भाषा का ऋन्तर होते हुए भी प्रायः सभी यूरोपियन देश, विज्ञान के च्रेत्र में, एक दूसरे से मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग ही करते हैं।

ऊपर दिये गए सुभाव भाषा की शुद्धता के समर्थकों को ज़रूर चौंका देंगे। वह कहेंगे कि इस तरह से तो हमारी भाषा खिचड़ी बन जायगी, श्रीर ऐसी खिचड़ी भाषा में साहित्य का विकसित होना भी ऋसंभव होगा । भाषा में ऊपर से स्वेच्छाचारी दीखने वाले परिवर्तनों से उन्हें डर है कि उनकी संस्कृति भी ख़तरे में पड़ जायगी । उर्दू ऋौर हिन्दी दोनों में भाषा की शुद्धता के समर्थकों का जो दल है उन्हें यही डर है। वे ऋपनी छोटी-छोटी, संकुचित, साम्प्रदायिक या प्रांतीय संस्कृतियों को, जो vested interest की तरह वन गई हैं, क़ायम रखना चाहते हैं। वे इस ग़लतफ़हमी के शिकार हैं कि भाषा श्रीर संस्कृति एक दूसरे में ऐसी गुंथी हुई हैं कि उन्हें ऋलहदा नहीं किया जा सकता। मुसल्मान उर्दू को भारतीय इस्लाम का प्रतीक मानते हैं स्त्रीर उसे इस्लाम के सिद्धान्तों को श्रभिन्यक करने वाली दूसरी भाषात्रों-फारसी, श्ररबी श्रादि-के निकटतम संपर्क में ले जाना चाहते हैं। वह समभते हैं कि उसे सादा बनाने से उनकी संस्कृति को धक्का लगेगा। उधर, हिन्दू दिन-पर-दिन हिन्दी को श्रपनी संस्कृति का द्वार-रत्तृक बनाने में प्रयत्नशील हैं। परन्तु वारीकी से देखा जाय तो संस्कृति ऋौर भाषा ऐसी ऋविन्छित्र नहीं हैं, जैसा कि उन्हें मान लिया गया है। यूरोप में कुछ त्रंशों तक सांस्कृतिक एकता के मौजूद होते हुए भी प्रायः प्रत्येक देश की भाषा ऋलहदा है, बल्कि छोटे-छोटे देशों में भी कई भाषाएं प्रचलित हैं। स्वीज़रलैंड में चार भाषाएं हैं, कनाडा श्रौर दिच्ण श्रफीका में सरकारी काम-काज में भी, दो भाषाएं काम में आती हैं। हमारे पड़ोसी अफ़ग़ानिस्तान में, संस्कृति की एकता के बावजूद भी, दो भाषाएं प्रचलित हैं।

संस्कृति को यदि हम उसके संकुचित रूप में न लें तो जैसे उसकी रहा के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि एक गोत्र में ही शादी की जाय, वैसे ही भाषा को अपने में ही सीमित और शुद्ध रखना उसकी संस्कारिता की दृष्टि से वहुत आवश्यक नहीं है। समाज और भाषा दोनों ही स्त्रेंत्रों में इस प्रकार के आंदोलन उदारता के योतक नहीं हैं, और उनसे किसी का लाभ नहीं हो सकता। भाषा में कट्टरता से काम नहीं चला करता। ऐसा किया गया तो उसकी निर्मल स्वच्छ-धारा

कटरता की मक्स्थली में ही छितर कर नष्ट हो जायगी। संस्कृत के साथ तो हुआ भी ऐसा ही। भाषाएं, और संस्कृतियां भी, विविध संपकों का परिणाम ही हुआ करती हैं। किसी में वाहरी प्रभाव ज्यादा होता है, किसी में कम। संस्कृत आयों की शुद्ध वाणी नहीं है, उसमें द्राविड़ शब्द भी प्रचुर-मात्रा में हैं। अरबी, यूनानी, फ़ारसी और इवरानी लफ्ज़ों का मजमृत्रा है। और हिन्दी ही कहां की शुद्ध भाषा है? उसने जहां एक और संस्कृत से अपनी जहों को सींचा है, वहां फ़ारसी और अरबी की कहीं में भी उसकी शाख़ें लहलहा उटी हैं और उसके पत्तों ने अपनी नसों में एक नये जीवन का अनुभव किया है। अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन आदि दुनिया की सभी सभ्य भाषाओं का यही हाल है। वूसरी भाषाओं के शब्दों को लेने से कोई भाषा विगड़ती नहीं, धनवान ही होती है, सशक्त वनती है। उन शब्दों को निकाल दिया जाय तो वह कमज़ोर होकर लड़खड़ाने लगेगी। भाषा में बेढंगापन तो तब आता है जब लिखने वाला अनमेल शब्दों को एक दूसरे में गूंथने की भदी कोशिश करता है। मेल वहीं अञ्छा लगता है, जहां एकरसता हो, जहां सभी स्वर मिलकर एक लय वनाते हों।

सच पूंछा जाय तो, न तो भाषा ही स्थिर होती है, श्रौर न संस्कृति ही। दोनों में निरंतर परिवर्त्तन चलते रहते हैं। हवा के हर भोंके के साथ कुछ न-कुछ परिवर्त्तन होता रहता है। श्राज तो हमारा राष्ट्र श्रौर भी गहरे परिवर्त्तनों में से गुज़र रहा है। हमारी संस्कृति पर पश्चिम की प्रतिक्रिया, श्रौर पश्चिम के प्रति हमारा विद्रोह, दोनों एक साथ ही, जंगल की श्राग के समान, तेज़ी से श्रपनी लपटें ऊंची किये श्रागे वढ़ रहे हैं। हमारे सामने श्राज विनाश भी है, श्रौर निर्माण भी, हकड़े कर देने वाली प्रवृत्तियां हैं श्रौर उनकी तेज धारों के पीछे एकता की मज़बृत फ़ौलाद भी। इन सब प्रवृत्तियों का हमारी भाषा श्रौर संस्कृति पर निरंतर प्रभाव पड़ता जा रहा है। हम में से जो समस्दार हैं वे एक बड़ी मशीन के छोटे-छोटे पहियों से,जिनमें से कुछ एक श्रोर घूम रहे हों,श्रौर कुछ दूसरी श्रोर, श्रपनी नज़र हटाकर मशीन के उस बड़े पहिये पर नज़र जमा सकते हैं जो उसकी गति का निर्देश करता है, श्रौर उसे श्रौर भी तेज़ी के साथ श्रागे की श्रोर श्रम सकते हैं।

भाषा के संबंध में देशी श्रौर विदेशी का सवाल भी नहीं उठना चाहिए। डा॰ ज़ाकिर हुसैन के शब्दों में, ''वाहर से कुछ हवायें ऐसी श्राती हैं जिन से ज़िन्दगी की खेती मुर्मा जाती है, तो कुछ ऐसी भी श्राती हैं जिनसे मुर्माई खेती लहलहाने लगती है। दोनों को एक जानना श्रौर उनके फ़र्क को न सममना बड़ी ही भूल श्रौर नादानी है। × × क्या वह लफ्ज, जिनका चलन इस वह.

हमारी हिन्दुस्तानी ज़वान में है, वस वातचीत करने श्रीर किस्से कहानियां लिखने के श्रागे श्रीर काम भी दे सकते हैं ? दुनिया रोज़ श्रागे वढ़ रही है, नित नयी चीजें वन रही हैं, नित नयी वातें कहनी होती हैं, नये नये ख्याल फैलते हैं । इन नई चीज़ों, नये ख्यालों के लिए नये लफ्ज़, चाहिएं। क्या हम यह ठान लें कि हम जो लफ्ज़ वरत रहे हैं, वस उन्हीं से काम चलायें, उन्हीं को हेरफेर कर नई वातें कहने की कोशिश करें, या नये लफ्ज़ गढ़ें या श्रीर कहीं से उधार लें ? मैं समभता हूं कि ज़वान को वन्द कर देने का हक किसी को नहीं। नयी वातें कहनी होंगीं, तो नये लफ्ज चाहिये ही होंगे।" पर शर्च यही है कि ये लफ्ज़ चाहे जहां से श्रायें, श्रनमेल या बेजोड़ न हों। ऐसे हों कि खप जायं।

एक संगठित योजना की आवश्यकता

इस वात के लिए एक वाकायदा कोशिश (planned effort) की ज़रूरत होगी । हिन्दी, उर्दू ऋौर देश की दूसरी भाषात्रों के विद्वानों को ऋपना सहयोग, विना किसी संकोच श्रीर मानसिक िक्किक के, एक दूसरे को देना होगा। एक केन्द्रीय संस्था की भी ज़रूरत होगी ही, जो सारे काम की दिशा निर्देश करेगी । ऋभी तक इस दिशा में जो हुन्ना है, वह बहुत थोड़ा है। इलाहाबाद की हिन्दुस्तानी एकाडेमी का चेत्र मर्यादित केवल हिन्दी और उर्द को एक दूसरे के नज़दीक लाने का --था। वह उसमें भी सफल नहीं हुई। उसकी कितावें और त्रैमासिक पत्रिका तक आज भी इन दो ज़वानों में अलहदा-अलहदा छुपती हैं। उसने उद् श्रीर हिन्दी में थोड़ा-सा साहित्य भले ही दिया हो, पर हिन्दुस्तानी जैसी कोई चीज़ पैदा नहीं की । उसकी ऋसफलता का मुख्य कारण यह था कि उसने ऊपर से खींचतान कर इन दोनों भाषात्रों को एक दूसरे से मिलाना चाहा । सरकारी सहारा पाकर यह प्रयत्न एकाडेमी के उत्साही प्रधान मन्त्री डा॰ ताराचन्द के हाथों में किसी स्कूलमास्टर के ज्ञापस में लड़ने वाले दो उद्धत लड़कों का सिर एक दूसरे से टकरा देने के समान हो गया। इसे एके के त्रालावा कुछ भी नाम दिया जा सकता है। एकाडेमी ने हिन्दी न्त्रीर उर्द को उनके स्रोत, जनसाधारण की भाषा, तक ले जाने का कोई प्रयत्न नहीं किया त्रीर केवल यही इन दोनों भाषात्रों को एक दूसरे के नज़दीक लाने का सच्चा प्रयत्न हो सकता था । विहार उद्ं कमेटी की मीटिंग के सम्दन्ध में न्नगस्त १६३७ में जब राजेन्द्र बाबू न्त्रीर मौलवी न्नब्दुलहक्क मिले तब उन्होंने एक सम्मिलित योजना तैयार की जिसमें उर्दू और हिन्दी के विद्वानों के सहयोग से हिन्दस्तानी लफ्ज़ों का एक मूल कोष वैयार करने की बाव थी। इस ग्राधार पर एक हिन्दुस्तानी कमेटी का निर्माण हुन्ना, पर जहां तक मैं जानता हूं, उसने

इमारी राजनैतिक समस्याएं

े भी जनता रूपी जो सन्न इन दोनों भाषात्रों को जोड़ता है उस तक पहुंचने का कोई प्रयत्न नहीं किया । ऊपर जिन प्रयत्नों का ज़िक किया गया है, वे सव हिंदी ग्रीर उर्दू से ही संबंध रखते हैं, ग्रन्य प्रान्तीय भाषात्रों से उन्हें कोई सरोकार नहीं।

इस दिशा में एक वड़ा प्रयत्न भारतीय साहित्य परिपद् की स्थापना थी। यह परिपद्, १६३५ में इन्दोर में कायम हुई थी, श्रीर दो या तीन साल काफ़ी जोरदार काम करने के वाद ख़त्म हो गई। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रान्तों में साहित्य का ग्राधार लेकर जो सांस्कृतिक एकता विकास पा रही है, उस पर जोर देना था। इसका प्रमुख उद्देश्य साहित्यिक विकास था: भाषा गीण थी। पर भाषा के दलदल में ही एक प्रकार से इस संस्था की श्रान्त्येष्टि हुई। इसका विश्वास संस्कृत प्रधान भाषा में था—श्रायं संस्कृति के पुनरोत्थान की जो धारा हमारे हिन्दू जीवन में काम कर रही है, यह उससे श्रपने को श्रालहदा काट नहीं सकी। इसीसे मुसलमानों में इसके संबंध में गलतफ़हिम्यां हुई। मुसलमानों के विरोध में समस्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता के लिए काम करने वाली यह संस्था जीवित नहीं रह सकती थी। इसलिए उसे ख़त्म हो जाना पड़ा। श्रीयुत मुंशी ने कहीं लिखा था कि देश इस प्रकार के महान प्रयत्न के लिए तैयार नहीं था। यह श्रपने समय के बहुत पहिले हाथ में ले लिया गथा था। मैं तो मानता हूं कि समय के मुख्य स्त्न, शुद्ध राष्ट्रीयता, को जिसमें हिन्दू श्रीर मुसलमान दोनों हंसी-खुशी से हिस्सा ले सकें न पकड़ पाने के कारण ही इस संस्था का श्रंत हुश्रा।

जो विद्वान राष्ट्र-भाषा के विकास के इस संगठित प्रयत्न में भाग तें उन्हें राजनीति ग्रीर संप्रदायवाद से दूर हटकर, ग्रीर छोटी-छोटी संस्कृतियों, तहज़ीवों के भूंठे मोह से ग्रपने की मुक्त करके, ही ग्रागे ग्राना होगा। यह प्रयत्न तो सांस्कृतिक समन्वय का प्रयत्न होगा, जिसमें प्रत्येक छोटी संस्कृति को कुछ देना होगा, ग्रीर वहुत कुछ पाकर वह ग्रपने को समुद्ध भी बना सकेगी। राष्ट्रीयता में उनका कहर-विश्वास होना चाहिए। इसके ग्रालावा किसी ग्रन्य देवता में उनकी श्रद्धा न हो। इस कमेटी के जो सदस्य हों वे वज़नदार तो हों ही, पर यह मानते हों कि हिंदुस्तान की किस्मत में हिंदू ग्रीर मुसल्मान दोनों समाज ताने ग्रीर वाने के समान एक-दूसरे में उलके हुए हैं, ग्रीर उन्हें देश में दूर-दूर तक फैले हुए उन करोड़ों रारीविकिसान ग्रीर मज़दूरों की—चाहे वे हिंदू हों या मुसल्मान—भाषा के द्वारा एक-दूसरे के ग्रीर भी नज़दीक गूंथ देना ही उनका उद्देश्य है। गांधीजी ने लिखा था, ''हमारे ज़माने की हिंदुस्तानी तहज़ीव ग्रभी वन रही है। हममें से कई इस वात में प्रयत्नशील हैं कि सव संस्कृतियों के, जो ग्राज एक-

दूसरे से संघर्ष करती दिखाई देती हैं, मेल से एक नयी संस्कृति पैदा की जाय। कोई भी संस्कृति जो अपने को अलहदा काट लेना चाहती है ज़िन्दा नहीं रह सकती। हिंदुस्तान में आज शुद्ध आर्थ-संस्कृति नाम की कोई चीज़ नहीं है।" नई संस्कृति और उसके मूल-तत्वों—इसमें जो लोग विश्वास करते हों, उन्हीं को इस कमेटी में काम करना चाहिए।

काम की दिशा

यह कमेटी क्या करेगी ! इस प्रश्न का उत्तर मेरे बूते के वाहर की बात हो सकती है। शायद वह हिन्दुस्तानी का एक कोष तो तैयार करेगी ही। कीष के सम्बन्ध में कई योजनाएं सामने ऋाई हैं। इनमें से दो योजनाऋों की एक संचिप्त रूपरेखा यहां दी जाती है-क्योंकि ये दो विभिन्न मनोवृत्तियों की द्योतक हैं। एक का विश्वास भाषा के classical grandeur में है, दूसरी उसे जन-साधारण के सम्पर्क में ले जाना चाहती है। एक के प्रवर्तक ऋंज्रमने त(क्क़ी-ए-उर्द के ऋध्यत्त मौलवी ऋब्दुल हक्क हैं; ऋौर दूसरी के मोहम्मददीन तासीर । मौलवी ऋब्दुलहक चाहते हैं कि एक ऐसा कोष तैयार किया जाय जिसमें एक स्रोर तो फ़ारसी, स्ररबी स्रौर उर्दू के वे शब्द हों जो हिन्दी भाषा में प्रचलित होगए हैं, स्त्रीर दूसरी स्त्रोर संस्कृत स्त्रीर हिन्दी के वे सब शब्द हों जिन्हें उर्द ने अपना लिया है : इस कोष को हिन्दी श्रीर उर्द के लेखकों के एक प्रतिनिधि मण्डल के सामने पेश किया जाय, श्रौर उनकी स्वीकृति के वाद इसे, एक सामान्य भाषा के भावी विकास के आधार के रूप में, प्रकाशित कर दिया जाय। मौलवी साहिब चाहते हैं कि कोष के प्रकाशित होजाने के बाद भी यह कमेटी काम करती रहे, ऋौर समय-समय पर उक्त कोष में हिन्दी ऋौर उर्दू के ऐसे शब्द श्रोर मुहावरे जोड़ती रहे जिनसे भाषा के विकास श्रीर नये विचारों की अभिन्यिक में सहायता मिलती हो । मोहम्मददीन तासीर का सुकाव है कि इस कमेटी में केवल नये दृष्टिकोण के लेखक ग्रीर भाषा के विद्वान हों, ग्रीर वे पहिले ऐसे मूल (basic) शब्दों की एक लिस्ट बनालें जो हमारे काम-काज के लिए विल्कुल ज़रूरी हों। तब हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से वीन उद् जानने वाले ऐसे सदस्य, जो हिन्दी विल्कुल भी न जानते हों, परन्तु, ग्रापने गांवों की भाषा से खुब परिचित हों, फ़ारसी के ग्रालावा ऐसे सब शब्दों की सूची बनावें जिन्हें वे समभ सकते हों, श्रीर इसी प्रकार से हिन्दी जानने वाले सदस्य संस्कृत के त्रालावा शब्दों की सूची बनावें । तव इन सूचियों का मुक़ाविला 'टेसिक' शब्दों की लिस्ट से किया जाय । जहां मूल-भावों को व्यक्त करने के लिए हिन्दी श्रथवा उद् में शब्द न हों, वहां उसके लिए दोनों भाषाश्रों से शब्द ले लिये

हमारी राजनैतिक समस्याएं

जायं। इस प्रकार एक 'वेसिक' कोप तैयार होगा, जिसका विकास वाद में प्रामीण साहित्य की भापा से व ऊंचे साहित्य की भापा से शब्दों को लेकर किया जा सकता है। वाद में 'टेकिनिकल' वातों ग्रौर राजनैतिक विचार-धाराग्रों को व्यक्त करने वाले शब्दों का एक संग्रह तैयार किया जा सकता है, लेकिन तरीक्षा वही होना चाहिए; यानी दोनों भापाग्रों के शब्दों को लिया जाय, उनका जन-साधारण के प्रयोग में ग्राने वाले शब्दों से मुक्काविला किया जाय, ग्रौर यदि वहां उसके लिए उपयुक्त शब्द न मिले, तव हिंदी ग्रौर उर्दू दोनों शब्दों को रख लिया जाय। राजेन्द्र वावू शायद इन दोनों योजनाग्रों का समन्वय कर देना चाहते थे, जब कि उन्होंने यह सुक्काव उपस्थित किया कि इस कोप में संस्कृत, क्वारसी ग्रौर ग्रस्ती के उन शब्दों का ग्रर्थ दिया जाना चाहिए जो हिन्दुस्तानी में प्रयोग में ग्राते हैं ग्रौर इनमें से २ या ३ हज़ार ग्रधिक प्रचलित ग्रौर सुगम शब्दों को छांट लेना चाहिए ग्रौर स्कृल ग्रौर कॉलेज की शिक्ता में उन्हें ही व्यवहार में लाना चाहिए।

'वेसिक' हिन्दुस्तानी का आंदोलन

'वेसिक' हिंदुस्तानी के आंदोलन को बहुत बड़ा समर्थन जवाहरलालजी के द्वारा मिला है। जवाहरलाल जी वेसिक अंग्रेज़ी के आन्दोलन से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। वेसिक अंग्रेज़ी में, वैज्ञानिक, टेकनिकल और व्यापारिक शब्दों को छोड़कर, एक हज़ार से कुछ कम शब्द हैं। इन्हें सीख कर साधारण वोलचाल की अंग्रेज़ी में प्रवेश किया जा सकता है। हिन्दुस्तानी में भी यदि इस प्रकार के एक हज़ार शब्द दुन लिये जायं, उसके व्याकरण को सादा वना दिया जाय, वो देश भर में इसका प्रचार बड़ी आसानी से हो सकता है। ये शब्द आंख मींचकर उठा लेने से काम नहीं चलेगा। अंग्रेज़ी के समान इस काम में भी एक बड़ी संख्या में विद्वानों को जुट जाना पड़ेगा, और ऐसे शब्दों को ही जुनना पड़ेगा जो अधिक-से-अधिक प्रचलित हों। वेसिक हिन्दुस्तानी के बन जाने से राष्ट्र-भाषा के प्रचार के रास्ते में बड़ी सहुलियत हो जायगी।

में समभता हूं कि यह काम दो या इससे भी ज्यादा मंज़िलों में होगा। पिहला काम तो हिन्दी श्रीर उद्क के बीच समन्वय स्थापित करने का है। इसके लिए हिन्दी श्रीर उद्क के राष्ट्रीय, प्रगतिशील (प्रगतिवादी हों यह ज़रूरी नहीं) श्रीर हो सके तो तक्या (जिनके पास प्रतिभा के साथ काम की शिक्त श्रीर समय भी हो) साहित्यिकों की एक कमेटी वना देना चाहिए। इस कमेटी में भाषा के विभागों की दृष्टि से प्रांतीय प्रतिनिधित्य होना चाहिए, उर्दू के प्रतिनिधि लाहीर, दिल्ली श्रीर ईदरावाद से लिये जायं, हिन्दी के विहार, पूर्वी यू० पी०, पश्चिमी

यू० पी० ग्रौर मध्य भारत से (जिसमें राजस्थान ग्रौर मध्य-प्रांत दोनों शामिल हों) लिए जायं । ये सातों व्यक्ति ऐसे होने चाहिएं जिनका संपर्क गांवों से हो, न्त्रीर जो त्रपने त्रास-पास के गांवों की भाषा जानते हों। ये लोग मिलकर हिन्दु-स्तानी की एक वेसिक, काम-चलाऊ डिक्शनरी तैयार करें जिसे सीखकर वह हिन्दु-स्तानी भी, जिसकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है, हिन्दी में श्रपनी दैनिक ज़रूरतों को व्यक्त कर सके। पर यह काम यहीं रुक नहीं जाना चाहिए। एक आगे वढता हुआ राष्ट्र, जिसके सामने नयी कल्पनाएं हैं ऋौर नये सपने जिसकी स्रांखों में जगमगा रहे हों, नयी श्राकांचाएं जिसके प्राणों को उद्देखित करती हों, एक हज़ार शब्दों में अपने जीवन की ऊंचाई और गहराई व्यक्त नहीं कर सकता । वेसिक श्रंग्रेज़ी का श्रान्दोलन भी, मैं समभता हूं, वहुत सफल नहीं हो पाया है। यह वेसिक हिन्दुस्तानी हमारे स्कूल के छोटे दनों के लिए श्रीर देश भर के उन लोगों के लिए जो राष्ट्र-भाषा के पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं, निहायत ज़रूरी है, पर वह हमारे काम का-जो राष्ट्र-भाषा का पुनर्निर्माण करने का है, केवल पाया हो सकता है। इसके बाद इस कमेटी में दूसरे प्रांतों की भाषात्रों के प्रति-निधियों को लेना होगा। तीन प्रतिनिधि बंगाल, गुजरात श्रौर महाराष्ट्र से लिये जायंगे, चार दिवाण भारत से । ये लोग मिल कर एक हज़ार ऐसे शब्द चुनेंगे जो इमारे दैनिक जीवन में भी काम में त्राते हैं त्रीर समस्त पांतीय भाषात्रों में सामान्य-रूप से जिनका प्रयोग होता है।

यह हुई काम की दूसरी मंज़िल। इस मंज़िल पर पहुंचते-पहुंचते काम का दायरा वहुत ज़्यादा वढ़ जायगा। ऋव इन विद्वानों को इस प्रकार की वेसिक हिन्दुस्तानी में, जो केवल हिन्दी ऋौर उद् की ही सामान्य-भूमि का स्पर्श न करती होगी, परन्तु देश की समस्त भाषाऋों का ऋाधार होगी, जनता को पत्र पत्रिकाऋं और पुस्तकों द्वारा शिव्तित करना होगा।

इसके साथ ही उन्हें विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के कुछ श्रन्य विद्वानों को शामिल करके कई छोटी-छोटी कमेटियां वना देनी पहेंगी, जो इन शास्त्रों के (technical) शब्दों की डिक्शनिरयां तैयार करेंगी। इस वड़ी कमेटी का समर्थन पाकर ही वे प्रकाशित की जा सकेंगी, और यह कोशिश करना पड़ेगी कि इन कोषों को सब प्रांतीय भाषाओं वाले मान लें। संभव है कि इन कोषों में वहुत अधिक विदेशी शब्दों को रखना पड़े।

इस सारे काम में हमें किसानों, मज़दूरों श्रौर कारीगरों के संपर्क में वो रहना ही होगा । परन्तु, हमें भाषा की संस्कारिता पर भी वरावर नज़र रखना होगी । भाषा सादा वने, पर उसकी श्रिभिव्यिक्त को भी खूव व्यापक वनाना

हमारी राजनैतिक समस्याएं

होगा । श्री मुन्शी के शब्दों में "हरएक भाषा के दो रूप होते हैं, एक रूप तो जीवन में व्यवहार के लिए होता है, श्रौर दूसरा कल्पना के विलास श्रौर विचार की व्यक्त करने के लिए। भाषा का पहिला रूप ऐसा होना चाहिए, जो सबके लिए सुलभ हो, श्रौर दूसरा रूप भी ऐसा हो जो विचार श्रौर उड़ान को व्यक्त करे श्रौर घोषित करे।" हमारी राष्ट्र-भाषा को इतना व्यापक होना होगा, उसमें इतनी लोच होगी कि एक श्रोर तो वह लोक-साहित्य के काम श्रा सके, श्रौर दूसरी श्रोर शिष्ट-साहित्य के लिए सुगम-साध्य हो, एक श्रोर उसमें गांव वाला श्रपनी दैनिक श्राव-श्यकता व्यक्त कर सके श्रौर दूसरी श्रोर वहें-से-बड़ा वैज्ञानिक श्रपनी मानिसक खोज की कथा उसके द्वारा दूसरों तक पहुंचा सके। किसी भी प्रथम श्रेणी की भाषा में यह लोच elasticity होना जरूरी है। इन सबके होते हुए भी हमारी श्राज की भाषा का जो श्राधार सौंदर्य श्रौर संस्कारिता है, वह वैसी ही श्रज्ञुएण रहनी चाहिए। यह काम को कठिन ज़रूर वना देगा, पर वहें काम श्रासान कब होते हैं ?

परिशिष्ट

कांग्रेस की कार्य-समिति द्वारा ११ दिसम्बर १९४५ को स्वीकृत चुनाव उद्घोषणा-पत्र के कुछ त्रावश्यक प्रश्न नीचे दिये जा रहे हैं:--

"कांग्रेस ने भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए—चाहे वह पुरुष हो या स्त्री— समान अधिकार का समर्थन किया है । उसने सब सम्प्रदायों और धार्मिक दलों में एकता और पारस्परिक सहिष्णुता की भावना देखनी चाही है । उसकी सदा यह इच्छा रही है कि लोगों को समन्वित रूप से अपनी व्यक्तिगत इच्छा और प्रेरणा के अनुकृल विकास प्राप्त करने का पूर्ण अवसर मिले । साथ-ही-साथ, वह यह भी चाहती रही है कि देश के प्रत्येक दल और घटक को राष्ट्र की वृहत्तर सीमा के भीतर रह कर अपने निजी जीवन और संस्कृति की उन्नित करने की स्व-तन्त्रता है । इस सम्बन्ध में उसने यह भी कहा है कि इस प्रकार के घटकों और प्रांतों की स्थापना जहां तक हो सके, भाषा और संस्कृति के आधार पर होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, कांग्रेस ने उन सब व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन किया है, जो सामाजिक अत्याचार और अन्याय के शिकार रहे हैं, और कहा है कि समान अधिकार में स्कावट डालने वाले सभी प्रतिवन्ध उन पर से हटा दिये जाने चाहिए।

''कांग्रेस ने सदा एक ऐसे स्वतन्त्र श्रीर प्रजावादी राज्य की स्थापना चाही है जिसके विधान में समस्त जनता के बुनियादी श्रिषकारों श्रीर स्वतंत्रवाश्रों की रत्ता की न्यवस्था की गई हो । कांग्रेस की राय में यह विधान संघ के ढंग का होना चाहिए, जिसके सभी भिन्न-भिन्न घटकों को स्वशासन का श्रिषकार प्राप्त हो श्रीर जिसकी धारा-सभाश्रों का चुनाव सभी प्रीढ़-न्यिक्तयों के मत पर श्राश्रित हो।

"भारत का संघ निश्चय ही अपने भिन्न-भिन्न भागों की स्वेन्द्रित एकता का प्रतिरूप होना चाहिए। घटकों को अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता देने के लिए संघ संबंधी सामान्य और आवश्यक विषयों की एक ऐसी छोटी-से-छोटी स्वी बनायी जा सकती है जिसका सब में प्रयोग हो सके। इसके अविरिक्त, सामान्य दिएयों की एक वैकल्पिक स्वी भी होनी चाहिए, जिसे जो लोग चाहें मानें और जो न चाहें, न मानें।

हमारी राजनैतिक समस्याएं

हमारे वुनियादी श्रधिकार

"विधान में बुनियादी ऋधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनमें निम्न-लिखित ऋधिकार भी सम्मिलित हों :—

- १. भारत के प्रत्येक नागिरक को, किसी ऐसे काम के लिए जो कान्न छौर नैतिकता के विरुद्ध न हो, स्वतंत्र रूप से अपनी सम्मित प्रकट करने, मिलने-जुलने और शांति-पूर्वक तथा विना हथियार लिये सभा-सम्मेलन करने का अधिकार है।
- २. प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वर्तत्रता होगी और सार्वजनिक शांति तथा नैतिकता को दृष्टि में रखते हुए स्वर्तत्रता पूर्वक अपने धर्म का प्रचार और पालन करने का अधिकार होगा।
- ३. ग्रल्पसंख्यक जातियों श्रीर भाषा के श्राधार पर वनाये गए विभिन्न घटकों की संस्कृति, भाषा श्रीर लिपि की रक्षा की जायगी।
- ४. कानून की दृष्टि में सभी नागरिक एक समान होंगे, चाहे उनका कोई भी धर्म, कोई भी जाति श्रीर कोई भी धर्म क्यों न हो, श्रीर चाहे वे स्त्री हों या पुरुष ।
- ५. कोई भी स्त्री या पुरुष ख्रंपने धर्म, जाति या वर्ग के कारण नौकरियों, ऊंचे ख्रोहदों ख्रीर व्यापार ख्रादि के लिए ख्रयोग्य न समभा जायगा।
- ६. सब नागरिकों का उन कुन्नों, तालावों, सहकों, स्कूलों, न्नौर सार्वजनिक स्थानों पर समान न्राधिकार है जो या तो सरकारी या स्थानीय कोष से चल रहे हैं या सार्वजनिक प्रयोग के लिए विशेष व्यक्तियों द्वारा वनाये गये हैं।
- ७. प्रत्येक नागरिक को शास्त्र संबंधी क्वानूनों की सीमा में रहकर शस्त्र रखने श्रोर धारण करने का श्राधकार है।
- कि. क्रानृत के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकेगा और उसके मकान या सम्पत्ति को न कोई ज़ब्त कर सकेगा न उसमें अवेश ही कर सकेगा।
 - ६. समी घमों के प्रति सरकार तटस्थता की नीति बरतेगी।
 - १०. मत देने का अधिकार सब भौढ़ व्यक्तियों को होगा।
- १२. सरकार की ओर से 'सुफ्त और अनिवार्य वुनियादी शिक्षा की व्यवस्था की जायगी।
- १२. प्रत्येक नांगरिक को इस बात की आज़ादी है कि वह समस्त भारतवर्ष में जहां चाहे जाय, किसी भी भाग में ठहरें और रहे, कोई भी व्यापार धंधा करे, और क़ानृती दर्ख या रहा के संबंध में भारतवर्ष के सभी हिस्सों में समान व्यवहार प्राप्त करे।

इसके ऋतिरिक्त, शासन-संस्था की ऋोर से पिछड़ी हुई या दिलत जातियों की रचा ऋौर उन्नित के लिए ऋावश्यक प्रवन्ध किये जायंगे ताकि वे शीघतापूर्वक उन्नित कर सकें ऋौर राष्ट्रीय जीवन में पूरा ऋौर समान माग ले सकें। विशेष रूप से कवीले वालों को ऋपनी योग्यता के ऋनुसार उन्नित करने ऋौर परिगणित जातियों को शिच्चा सम्बन्धी ऋौर सामाजिक तथा ऋार्थिक विकास प्राप्त करने में सहायता दी जायगी।

विपदा की कहानी

"पिछुले १५० वधों से भी श्राधिक समय से विदेशों राज्य होने के कारण देश की उन्नित कक गई है श्रीर हमारे सामने ऐसी श्रमंख्य समस्याएं श्रा खड़ी हुई हैं जिन्हें शीघ-से-शीघ हल करने की श्रावश्यकता है। इतने दिनों से भारत श्रीर भारतीयों का जो व्यापक-शोषण होता रहा है उससे विपदा का पारावार नहीं रहा है श्रीर जनता को भूखों मरना पड़ रहा है। हमारा देश न केवल राजनैतिक दृष्टि से ही दासता की जंजीरों में जकड़ा श्रीर श्रपमानित किया गया है विल्क उसे श्राधिक सामाजिक, सांस्कृतिक श्रीर श्रात्मिक श्रधोगित का भी सामना करना पड़ा है।

"भारतीय हितों श्रीर मतों की पूर्ण उपेक्षा करते हुए इस प्रकार उत्तरदायित्व-हीन श्रिधकारियों द्वारा शोषण का किया जाना श्रीर शासन व्यवस्था की श्रयोग्यता लड़ाई के दिनों में इतनी श्रिधक बढ़ गई कि उससे भयंकर दुर्भिक् श्रीर व्यापक-विपदा का विस्तार हुआ । इनमें से एक भी समस्या विना स्वतन्त्रता प्राप्त किये हल नहीं की जा सकती । राजनैतिक श्राजादी के साथ-ही-साथ श्राधिक श्रीर सामाजिक स्वाधीनता भी प्राप्त होनी चाहिए।

हमारी समस्याएं श्रीर उनका हल

"जनता पर से दारिद्रय का श्राप किस प्रकार हटाया जाय श्रौर उसका जीवन-माप किस प्रकार ऊंचा उठाया जाय, यही भारतवर्ष की सब से मुख्य श्रौर श्रावश्यक समस्या है। इसी जनता के कल्याण के लिए कांग्रेस श्रपना विशेष ध्यान देती रही है श्रौर उसी के लिए रचनात्मक कार्य भी करती रही है। उसी के हित श्रौर विकास की कसौटी पर उसने सारे प्रस्तावों श्रौर परिवर्तनों को कसा है श्रौर यह घोषित किया है कि जो कुछ भी देश की उन्नति में वाधक सिद्ध हो उसे रास्ते से हटा दिया जाय।

'देश के धन-धान्य में वृद्धि करने के लिए श्रीर उत्ते दूसरी पर निर्मर रहे दिना ही स्वतः विकसित होने की समता प्रदान करने के लिए उद्योगधंघों, कृषि श्रीर सामाजिक तथा सार्वजनिक लाभ के साधनों, श्रादि को प्रोत्साहन देना, उन्हें नये ढंगमें ढालना चाहिए श्रीर तीव गति के साथ फैलाना चाहिए। किन्तु ये सब काम ्रजनता को लाभ पहुंचाने, उसके ग्राथिक, सांस्कृतिक ग्रीर ग्रात्मिकस्तर को ऊंचा उठाने, बेकारी दूर करने ग्रीर व्यक्तिगत मान को बढ़ाने के ऊदेश्य से ही किये जाने चाहिएं।

"इस कार्य के लिए यह त्रावरयक है कि सभी भिन्न-भिन्न चोतों में सामाजिक उन्नित की योजना बनाई जाय और उसका संगठन किया जाय; किसी एक व्यक्ति ग्रीर दल के पास धन ग्रीर ग्रिधिकार को केन्द्रित न होने दिया जाय। समाज के विरोधियों को बढ़ने से रोका जाय ग्रीर धातु ग्रीर यातायात के साधनों पर ग्रीर भूमि, उद्योग तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम के सभी दूसरे चेत्रों में उत्पादन ग्रीर वितरण की मुख्य प्रणालियों पर सामाजिक प्रभुत्व प्राप्त किया जाय, ताकि स्वतन्त्र भारत सहकारिता की प्रणाली का उपनिवेश बन सके।

''इसलिए शासन-संस्था को सभी बुनियादी श्रीर मुख्य उद्योगों श्रीर नौकरियों, धातु सम्बन्धी साधनों, रेल के रास्तों, समुद्री रास्तों श्रीर जहाजों तथा यातायात के दूसरे साधनों पर श्राधिपत्य या श्रिधिकार प्राप्त करना चाहिए। मुद्रा, विनिमय, वैंक श्रीर वीमा को राष्ट्रीय हित के श्रमुकूल संगठित करना चाहिए।

''वैसे तो दरिद्रता सारे भारतवर्ष में है परन्तु इसकी समस्या मुख्यतः गांवों में है। दिखता का प्रधान कारण भूमि की कमी और दूसरे धनोत्पादक कायों का स्रभाव है । ब्रिटिश ऋधिकार में रहते हुए भारतवर्ष कमशः एक ग्रामीण देश बना दिया गया है, उसके कारवार के छानेक रास्ते बंद कर दिये गए हैं छौर एक विशाल जनसमुदाय खेती पर त्र्याश्रित छोड़ दिया गया है। खेतों के लगातार टुकड़े किये जाते रहे हैं,यहां तक कि अब अधिकांश खेत आर्थिक दृष्टि से अलाभकर होगए हैं। इसलिए यह त्र्यावश्यक है कि भूमि संबंधी समस्या पर सभी पहलुत्रों से ध्यान दिया जाय। कृषि को वैज्ञानिक ढंग से उन्नत वनाने स्त्रीर उद्योग को उसके . वड़े, मभोले श्रीर छोटे सभी रूपों में बढाने की श्रावश्यकता है , ताकि केवल धन का ही उत्पादन न हो सके विल्क कृषि पर ब्राश्रित रहने वाले व्यक्ति भी उनमें खपाय जा सकें। गृह-उद्योगों को पूर्ण श्रीर श्रांशिक दोनों पेशों के रूप में विशेष रूप से प्रोत्साहन देना प्रयोजनीय है। यह त्रावश्यक है कि उद्योगों की रूपरेखा वनाने ग्रौर उसे विकसित करने में जहां एक ग्रोर ग्रधिक-से-ग्रधिक धन के उत्पादन का ध्यान रखा जाय वहां दूसरी ब्रोर यह भी याद रखा जाय कि ऐसा करने से नई वेकारी न पैदा हो जाय । योजना के वनने से ऋधिक-से-श्रधिक लोगों को श्रीर निस्तंदेह सभी पुष्ट व्यक्तियों को काम मिलना चाहिए। जिन लोगों के पास खेत नहीं हैं, उन्हें काम करने का अवसर प्रदान करना चाहिए ग्रौर उद्योगों या खेती में खपा लेना चाहिए । भूमि संबंधी सुधार के

लिए, जिसकी भारतवर्ष में घोर श्रावश्यकता है, किसानों श्रीर शासन-संस्था के बीच के (मध्यस्थ) व्यक्तियों को हटा देना चाहिए श्रीर उनके श्राधकारों को वरावर का मुश्रावज़ा देकर खरीद लेना चाहिए।

"व्यक्तिगत खेती श्रोर किसानों की मिल्कियत की प्रथा चलती रहनी चाहिए। लेकिन उन्नतिशील कृषि श्रोर नयी सामाजिक प्रेरणाश्रों श्रादि के निर्माण के लिए मारतीय स्थितियों के श्रनुकृल सहकारिता ढंग की खेती की कोई प्रणाली होनी चाहिए। ये परिवर्तन कृषकों की सहमित श्रोर सहानुभृति से ही होने चाहिएं।

"इसिलिए यह वांछिनीय है कि सरकार की सहायता से भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में प्रयोग रूप से सहकारिता की प्रणाली पर फ़ारम खोले जांय। प्रदर्शन श्रौर प्रयोग के कार्य के लिए बड़े-बड़े सरकारी फ़ारम भी होने चाहिएं।

"कृषि श्रौर उद्योग के विकास के लिए ग्रामीण श्रौर नागरिक श्रर्थ-व्यवसायों में समुचित संगठन श्रौर संतुलन होना चाहिए। श्रव तक ग्रामीणों को श्रार्थिक चित्त ही उठानी पड़ी है श्रौर उनसे लाम उठा कर नगरों श्रौर कस्वों वालों ने उन्नित की है। इस स्थित में संशोधन की श्रावश्यकता है। देहातों तथा कस्वों के निवासियों के जीवन-माप को यथासाध्य वरावर करने की चेष्टा करनी चाहिए। उद्योगों का किसी एक प्रांत में केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए ताकि सभी प्रांतों की श्रार्थिक-स्थिति में संतुलन स्थापित किया जा सके। श्रकेन्द्रीकरण करते समय इस न्रात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक संभव हो किसी की विशेषता पर श्राधात न पहुंचे।

"कृषि श्रीर उद्योग दोनों के विकास के लिए श्रीर साथ-ही-साथ जनता के स्वास्थ्य तथा हित के लिए भी हमें उस महान् शिक्त पर श्रिषकार करना श्रीर उसका उचित प्रयोग करना चाहिए जो हमें भारत की विश्णल निर्यों के रूप में उपलब्ध है श्रीर जो श्रिषकतः न केवल वरवाद ही जाती है बिलक भूमि के लिए श्रीर भूमि पर निवास करने वालों के लिए बहुधा चित का कारण वनती है। इस काम को करने के लिए निर्यों से संबंध रखनेवाले कमीशन बनाये जाने चाहिएं, ताकि वे सिंचाई के काम को प्रोत्साहन प्रदान कर सकें श्रीर इस वात की व्यवस्था कर सकें कि लोगों को सिंचाई के लिए लगातार श्रीर समान-रूप से पानी मिलता रहे। इसके श्रितिक उनका काम संहारक वाद को रोकने श्रीर जमीन को करने से बचाने का भी होना चाहिए। उन्हें मलेरिया को रोकने, जल-विद्युत शिक्त को बढ़ाने श्रीर दूसरी युक्तियों द्वारा विशेषतः शामवानियों के जीवन-माप को बढ़ाने का काम सौंपना चाहिए। उद्योग श्रीर कृष के विद्यान

हमारी राजनैतिक समस्याएं

के लिए त्र्यावश्यक त्र्याधार प्रदान करने के त्र्याभिप्राय से इस देश के शक्तिदायक साधनों की हर रूप से वढाना प्रयोजनीय है।

"जर्नता के बौद्धिक, ऋार्थिक, सांस्कृतिक छोर नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छोर उसे अपने सामने छाने वाले नये कामों छोर व्यवसायों के योग्य बनाने के लिए शिद्धा का पर्योप्त प्रबंध होना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य के कामों की, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक हैं, ऋधिक-से-ऋधिक व्यवस्था होनी चाहिए छोर इस बात में, दूसरी बातों की तरह ही, आमीणों की आवश्यक-ताछों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनमें प्रस्ति छोर शिशुपालन संबंधी विशेष व्यवस्थाएं भी सम्मिलित होनी चाहिए।

"इस प्रकार हमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिएं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति को हर राष्ट्रीय कार्य-च्रेन में उन्नति करने का समान अवसर मिले और सबके लिए सामाजिक सुरचा का प्रवंध हो।

वैज्ञानिक विकास की श्रावश्यकता

"विज्ञान श्रपने श्रसंख्य कार्य-चेत्रों में मनुष्य-जीवन को प्रभावित श्रीर परि-वर्तित करने में सबसे श्रिधकाधिक भाग लेता रहा है, श्रीर भविष्य में भी इससे श्रिधक मात्रा में भाग लेता रहेगा। श्रीद्योगिक, कृषि-सम्बन्धी श्रीर सांस्कृतिक उन्नति यहां तक कि राष्ट्री-रत्त्रण का कार्य भी इसी पर निर्भर है। श्रतः वैज्ञानिक श्रम्वेषण का कार्य शासन-संस्था का बुनियादी श्रीर श्रावश्यक कार्य है श्रीर उसको व्यापक से व्यापक रूप में सङ्गठित श्रीर प्रोत्साहित करना चाहिए।

"जहां तक मज़दूरों का सवाल है, शासन-संस्था श्रीद्योगिक श्रमजीवियों के हितों की रक्षा करेगी श्रीर इस बात की व्यवस्था करेगी कि उन्हें एक निश्चित सीमा से कम मज़दूरी न मिले, देश की श्रार्थिक श्रवस्था को दृष्ट में रखते हुए जहां तक सम्भव हो, उनके जीवन का माप श्रंतर्राष्ट्रीय माप की तुलना में उचित हो। उनके लिए रहने का यथेष्ट प्रवन्ध हो श्रीर काम के घएटे और मज़दूरी की शर्तें भी ठीक हों। इसके श्रितिरक्त शासन संस्था मज़दूरों श्रीर मालिकों के भगड़ों को तथ करने श्रीर मज़दूरों को बुढ़ापा,वीमारी तथा वेकारीके श्रार्थिक दुष्परिणामों से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करेगी। मज़दूरों को श्रपने हित की रक्षा के लिए संघ बनाने का श्रिधकार होगा।

''श्रृण ने किसानों को कुचल रक्खा है श्रौर यद्यपि विभिन्न कारणों से पिछले दिनों उनके श्रृण का बोभ कुछ हल्का होगया है तथापि वह श्रृब भी है श्रौर उसे दूर करना श्रावश्यक है। इसके लिए किसानों को सहकारिता-संस्थाश्रों द्वारा कम दर पर रूपया उधार दिलवाना चाहिए। "सहकारिता-संस्थात्रों का दूसरे कामों के लिए भी गांवों त्रौर शहरों — दोनों स्थानों में निर्माण होना चाहिए। त्रौद्योगिक सहकारिता-संस्थात्रों को विशेष रूप से प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि प्रजावादी त्राधार पर छोटे-छोटे उद्योगों के विकास के लिए वे विशेष-रूप से उपयोगी होती हैं।

''यद्यपि यह सत्य है कि भारतवर्ष की तत्कालीन श्रौर श्रावश्यक समस्याश्रों का दल राजनैतिक, श्रार्थिक, कृषि-सम्बन्धी, श्रौद्योगिक श्रौर सामाजिक सभी दिशाश्रों से एक साथ सम्मिलित प्रयत्न करने पर ही हो सकेगा, तथापि कुछ श्रावश्यकताएं श्राज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सरकार की निपट श्रयोग्यता श्रौर दुर्व्यवस्था के कारण भारतीय जनता पर विपदा का पहाड़-सा टूट पड़ा है। लाखों लोग भूखों मर चुके हैं, श्रौर श्रव्न तथा कपड़े का श्राज भी न्यापक श्रमाव है। सभी नौकरियों में श्रौर जीवन सम्बन्धी सभी श्रावश्यक पदाथों के नियंत्रण श्रादि के मामलों में बड़ी वेईमानी श्रौर घूसखोरी चल रही है जो हमारे लिए श्रसहा हो गई है। इन श्रावश्यक समस्याश्रों पर फौरन ही ध्यान देना श्रावश्यक है।

"जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का संबंध है, कांग्रेस स्वतन्त्र राष्ट्रों का एक विश्व-संघ स्थापित करने के पक्ष में है। जब तक कि यह संघ क्रियात्मक रूप ग्रह्ण कर सके, भारतवर्ष को सभी राष्ट्रों, विशेषतः अपने पड़ोसियों, से मैत्री के संबंध स्थापित करने चाहिएं। सुदूरपूर्व, दिच्चण-पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया से भारतवर्षका पिछले हज़ारों वर्षों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है और यह अतिवार्य है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ-ही-साथ वह इस संबंध को भी पुनर्जीवित और विकसित करे। संरक्षा की भावना और व्यापार के भावी भुकाव को देखते हुए भी इन चेत्रों से घनिष्टतर सम्पर्क रखना आवश्यक है।

"भारतवर्ष, जो श्रिहिंसा के श्राधार पर श्रपनी स्वतंत्रता की लड़ाई श्राप लड़ता रहा है, इस विश्वव्यापी शांति श्रीर सहयोग का ही पत्त ग्रहण करेगा । वह दूसरे दास-देशों की भी स्वतन्त्रता का समर्थन करेगा क्योंकि इसी स्वतंत्रता के श्राधार पर श्रीर साम्राज्यशाही को सब जगहों से हटा कर ही विश्व-शांति की स्थापना हो सकेगी !"